

राजनीति विज्ञान मानक ग्रन्थ शृङ्खला—5

संपादन हरगोविन्द पत

अंतर्राष्ट्रीय सबंध अधुनातन परिवेश में

लेखन

हरगोविन्द पत रमेश दाधीच
दामोदर शर्मा बी के अरोडा

राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर-302004 (राजस्थान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विश्वविद्यालय
मेतृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित

शीपक अन्तर्राष्ट्रीय सबष अधुन त्तन परिवेस मे
कॉपी राइट राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 302004

प्रथम संस्करण 1982

मूल्य 25 00

मुद्रक भारत प्रकाशन,
के-20/6, नवीन शाहदरा,
दिल्ली 110032,

विषय क्रम

पृष्ठ

- | | |
|--|---------|
| 1 सत्सार व्यापी महासमर की पूव वेला मे
तीन नई बातें, तीन नये विकास, साम्राज्यवाद, साम्राज्य
विरोधी शक्तिया, सोवियत शक्ति | 1—22 |
| 2 युद्ध कालीन घोषणायें, वार्ताएँ एवं सम्मेलन
एटलाटिक घोषणा, मास्को वार्ता, तेहरान, याल्टा मोरक्को,
काहिरा, क्यूबा, ब्रिटनबुडस, डाबटन ओवस, पोट्सडम | 23—64 |
| 3 रूसरे नाटक का भी अंत—स मवादी जापान की
कपाल क्रिया
परमाणु बम, जापान की पराजय, परराष्ट्र मंत्री सम्मेलन,
पेरिस सम्मेलन, शांति सम्मेलन, शांति संधिया, जमनी,
आस्ट्रिया और जापान | 65—95 |
| 4 समुक्त राष्ट्र युद्धकालीन साहचर्य और सहयोग का
एक और सफल प्रयोग
संगठन, सविधान उद्देश्य और सिद्धांत, समुक्त राष्ट्र के
अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक
परिषद, आयोग, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
महासचिव | 96—173 |
| 5 नई सढाई की शुरुआत एक ठण्डी सढाई शीत युद्ध
नई दुनिया, नये सदस्य, शीतयुद्ध का नजरिया | I—XI |
| 5 A शीत युद्ध और अमरीका सोवियत संबंधों का अंतद्वन्द्व
एक प्रारूप, विश्लेषण, युद्धोत्तर काल, प्रथम चरण, द्वितीय
चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, अमरीकी नीति, नई
भूमिका, महाशक्तिम , प्रतिद्विदिता एशियाई सदस्य,
सोवियत प्रति प्रयास, अफ्रीकी मंच, ईरान, अफगानिस्तान,
पोलैण्ड, पश्चिम एशिया शिक्षा मोघ एक सिद्धान्तकन | 174—232 |

- 6 महाशक्ति समीकरण और चीन विश्व राजनीति का त्रिकोण 233—277
 प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चीन का विश्व दृष्टिकोण, तृतीय चरण, चीन-सोवियत संबंध, चीन अमेरिका संबंध
- 7 एशिया की जागृति 278—291
 परिचय—सोवियत, पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम जागृति के कारण, एशिया की समस्याएँ, प्रवृत्तियाँ व परिणाम, सकारात्मक और नकारात्मक भविष्य
- 8 अफ्रीका का अभ्युदय 292—310
 परिचय—औपनिवेशिक पष्ठभूमि, अभ्युदय के कारण, समस्याएँ, महाशक्तियों का हस्तक्षेप, अभ्युदय के परिणाम, अफ्रीकी आतत्त्ववाद, बाहुग एफोएशियन सालिडेरिटी, आक्रा मोशी, अफ्रीकी एकता सम्मेलन
- 9 भारत के परराष्ट्र संबंध 311—349
 परराष्ट्र नीति की दिशा, प्रमुख निर्धारक तत्व नीति का विकास, नहरू युग, इंदिरा युग, जनता सरकार की परराष्ट्र नीति पुन इंदिरा युग—अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंद महासागर भारत चीन रीगन प्रशासन, भारत व चीन अंतर्राष्ट्रीय नव व्यवस्था, भारत पाक संबंध, भारत पाक तनाव बिंदु महाशक्ति प्रतिस्पर्धा
- 10 बिलग्नता या गठनरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया का एक विकल्प 350^r—367
 ऐतिहासिक सद्भव, समय और पहल, अफ्रीका एशिया की एकता, सत्ता की खोज, आंदोलन का स्वरूप प्रवृत्तियाँ और विकास
- 11 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधुनातन समस्याएँ एवं तनाव क्षेत्र 368—399
 पश्चिम एशिया और अरब इजरायल विवाद, स्वेज संकट, मित्र इजरायल संधि, सादात और कम्प डेविड समझौता, ईरान ईराक संधि, कम्पूचिया की समस्या रंग भेद का कलक और नामीबिया स्वायत्तता का स्वातंत्र्य संधि, अंगोला पर दक्षिण अफ्रीका का आक्रमण, नामीबिया का अवैध निर्वाचन

आमुख

राजस्थान विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग हमारे देश के एक संकटा-
से अधिक विश्वविद्यालयों के ऐसे ही राजनीति विज्ञान विभागों में एक विशिष्ट
स्थान प्राप्त कर चुका है। यह उन गिने-चुने विभागों में से एक है जिन्हें विश्व
विद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम (यू एल पी)
चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले तीन वर्षों से यह कार्यक्रम विभाग में चल
रहा है। इस सीढ़ी पर चढ़कर हमारा विभाग आशावित है कि उसे दीर्घ ही
मायता प्राप्त होगी, कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 'विशिष्ट सहायता'
प्राप्त करने के योग्य मान लिया गया है। इस मायता को प्राप्त कर वह राष्ट्रीय
स्तर का राजनीति विज्ञान केंद्र हो सकेगा।

तीन वर्ष से चल रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग ने अनेक शैक्षणिक एवं
शोधपूर्ण कार्य सम्पन्न किये हैं और पिछले 6 महीने के अंदर इस दिशा में द्रुत
गति से प्रगति हुई है। सेमिनार, वक्तृता, विद्वत्तया के ज्ञानयधक भाषण,
सुपाठ्य व सरल भाषा में अधिकारी विद्वानों की कृतियों के अनुवाद इत्यादि
सम्पन्न हुए हैं जिसने इस कार्यक्रम की छवि निखारने में बड़ा काम किया है।
परंतु इन सारे कार्यक्रमों में अनेक ज्ञात व अज्ञात कारणों वश इस नेतृत्व के अंतर्गत
दो गई दो 'पद' खाली रह गये। एक 'विजिटिंग' प्रोफेसर का जिस पर कुछ दिनों
तो दो सज्जन आए और कुछ काम हुआ फिर यह पद रिक्त ही रह गया। रीडर
का पद भरा ही नहीं जा सका। अतः हमने यह निणय लिया कि विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग से निवेदन किया जाए कि इन पदों के लिए निर्धारित रकम हमें
स्नातक स्तर के पांच विषयों की पांच अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखवाने और सम्बद्ध
कालेजों में उन्हें बटवाने की अनुमति मिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से
सह्य हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वस्तुतः यह हमारा सुखद अनुभव रहा है
कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयीय विभागों की अकादमिक
स्थिति सुधारने और उनकी आय विधि से सहायता कर पाने के लिए सदैव तत्पर
और उत्सुक रहा है जो भी प्रगति के राह में झगड़े टटे उठते हैं, वि० वि० अनु-

दान आयोग की ओर से न होकर, अधिकांश विश्वविद्यालयों के खुद के समर्थन-स्टे होते हैं। इसमें भी हमें वर्तमान कुलपति और रजिस्ट्रार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

पर इतनी सारी कृपा और अनुकंपा निष्पक्ष ही हो गई होती यदि मुझे विभाग के अपने सभी सहयोगियों से निर्बाध हार्दिक समर्थन और सहयोग न मिला होता। गुरु से आखिर तक आज के युग में जो देव दुलभ हो गया, ऐसा सह-कर्मियों के पग पग पर समयन और सहयोग ने ही वास्तव में यह सारी सरचना संभव बनायी जिसके लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा। यश और कीर्ति जो मिले, उसके वे ही अधिकारी हैं, श्रुतियाँ अवश्य मेरे जिम्मे की जानी चाहिए।

हमारे विभाग के सभी कर्मचारी यू एल पी कार्यक्रमों में उत्साह और लगन से भाग लेते रहे हैं। इनकी तकनीकी मदद ने हम लोगों के बौद्धिक श्रम को प्रयोग के रूप में प्रकट होने में जो मदद की है, उनके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमारे भूतपूर्व छात्रों सबकी नवसिंह, सत्य-देव एवं महादेव का जो सहयोग मिला है उसके लिए भी हम उनके हृदय से आभारी हैं।

असत में अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से भारत प्रकाशन के श्री भारत भूषण जी की भूरि भूरि प्रशंसा करना और उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा जो हम लोगों के सहृदय, कर्मठ और निष्कपट मुद्रक के रूप में तो मिले ही, एक मित्र की तरह उन्होंने स्थल-स्थल पर हमें इस कार्यक्रम को सुचिपूण ढंग से सफल करने में मूल्यवान सहयोग दिया।

30 जून, 1982

जयपुर

हरमोहिब पंत

निदेशक व अध्यक्ष

सम्पादकीय

राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के अतमत्त विश्व-विद्यालयी नेतृत्व कार्यक्रम की पाठमाला का यह पाचवा पुष्प है जिसकी रचना में प्रस्तुत पक्तियों के लेखक के अलावा, तीन अन्य प्रतिभावान और अनुभवी अध्यापकों ने भाग लिया है। इस ग्रन्थ के प्रणयन में हमें विश्वविद्यालय के सहयोगियों का सहयोग तो मिला ही, खुशी की एक बात यह भी रही कि डॉ० वी० के० अरोड़ा के रूप में हम एक प्रतिभाशाली व अनुभवी कालेज अध्यापक का सहयोग भी प्राप्त कर सके हैं। डॉ० अरोड़ा एक अनुभवी व विद्वान अध्यापक तो है ही, वे एक लेखक के रूप में भी शिक्षा जगत में सुविख्यात रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ के आरम्भ के पांच अध्याय इन पक्तियों के लेखक ने, 5A, छठा और दसवा अध्याय श्री रमेश दाधीच ने, सातवा और आठवा डॉ० अरोड़ा ने तथा नौवा और ग्यारहवा अध्याय श्री दामोदर शर्मा ने लिखा है जो पिछले कुछ वर्षों से विभाग में एक अध्यवसायी और प्रतिभावान युवा अध्यापक के रूप में जाने जाते थे और अब अध्यापन क्षेत्र को छोड़कर प्रशासनिक सेवा में एक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं।

हमारे विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में जिन कुछ बातों में पहल की है, उसमें एक बात यह शामिल है, कि 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' के अध्ययन को सभी स्तरों पर यथोचित सम्मान दिया गया है। स्नातकोत्तर स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषयक 'पेपर' अनिवार्यता से पढ़ाया ही जाता है, स्नातक स्तर पर भी इसे अनिवार्य पाचवे पपर के रूप में मान्यता मिली है, जो अंतिम वर्ष में विद्यार्थियों को लेना पड़ता है। यह पिछले दो दशकों से चल रहा है और इसी कारण 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' का अध्ययन अध्यापन कुछ कुछ सुगठित हो गया है। प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत इस ग्रन्थमाला को आयोजित किया गया है, इस परंपरागत अध्ययन की ओर पुष्ट और सम्पन्न करेगा, यह आशा करनी चाहिए।

ये भी 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' विषयक अध्ययन को अभी तक एक दो विश्व विद्यालयों को छोड़कर (यथा जवाहरपुर व जवाहरनाल नेहरू विश्वविद्यालय)

अयन कही भी स्वतन्त्र विभाग के रूप में गठित नहीं किया जा सका है। एक स्वायत्त 'अनुशासन' के रूप में इसे मायता नहीं मिल पायी है जिसकी वजह से इस 'अनुशासन' का बहुआयामी विकास अव्यक्त है। या तो यह राजनीति विभाग की एक जिम्मेदारी बना हुआ है जिसे जैसे कैसे निभाया जाता है। या फिर इतिहास विभाग में 'आधुनिक दुनिया' की जानकारी का एक पक्ष के तौर पर पढ़ा कर छूटो कर दी जाती है। अभी इसके उचित नामकरण की समस्या भी बनी हुई है। स्नातक स्तर पर हम इसे 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' के नाम से जानते हैं पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक उच्च वैचारिक धरातल पर इस अध्ययन को संगठित करके हम इसे 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' के रूप में पढ़ाते हैं। 'जागतिक राजनीति' के रूप में इसको अध्ययन का विषय बना पाने में तो अभी संभव ही बहुत विलम्ब है।

वस्तुतः जब इस समस्या का हम वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि अयन भी, विदेशों में इस प्रकार के अध्ययन की शुद्धता अभी कुछ दशकों पूर्व ही हुई है। यों तो हम इस अध्ययन की जड़ें सुदूर अतीत में खोज सकते हैं, प्राचीन भारत में, यूनान में, रोम में जब राज्यों के 'पारस्परिक' संबंधों पर विचार किया गया था। सम्बन्धों के कुछ नियम-धर्म, कुछ मर्यादाओं की स्थापित करने का प्रयत्न हुआ था पर सुव्यवस्थित चिन्तन का अभाव तो था ही। वैसे एक तथ्य पर तब भी जोर दिया ही जाता था। वह यह कि 'राज्य' को एक संगठित 'बल' के रूप में, अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाना चाहिए—विजिगीषु के रूप में स्थित 'राज्य' 'मण्डल' सिद्धान्त के अनुसार राज्य सम्बन्ध बनायें। जो है उसे संगठित करता, और जो नहीं है उसे अपने अधिकार में लाना राजनीतिक कर्तव्य ठहराया गया। राज्यों के आपसी सम्बन्ध तय करते समय यह विचार लाना चाहिए कि पड़ोसी तो स्वभावतः 'शत्रु' है। इसी प्रकार उसका शत्रु अपना स्वभावतः मित्र है इत्यादि—इस आधार पर 'मंडल' निर्मित होता है जिसके केंद्र में ही विजिगीषु—विजय की इच्छा रखने वाला राजा। युद्ध के सम्बन्ध में, दूतों के सम्बन्ध में उनका क्या गुण होना चाहिए, क्या मान मर्यादा रखनी चाहिए, इस पर खूब विचार हुआ है।

पर 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' का आज का अध्ययन तात्त्विक रूप से भिन्न हो चला है। वह इतना 'सरल' और तरल नहीं रह गया है। यूरोप में भी पुराने यूनान और रोम के युग के 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' वाले विचार घले ही पृष्ठभूमि की तरह काम दें, पर वे भूलतः आज की बातों से भिन्न हैं। उसका एक स्पष्ट कारण है कि आज के राज्य ही भूलतः उन राज्या से भिन्न हैं, स्वरूप में, गठन में, अंतर्भूत में, जो प्राचीन राजनीति का आधार थे। यूरोप में सामंतीय युग का अन्त होते होते 'राष्ट्रीय राज्यों' का गठन हुआ जिसने यूरोप की उस

“मध्यवासीन वातावरण” से बाहर निकास। जिसमें राजनीति चर्चा की ‘दासी’ बनी हुई थी। मैकयावेलि, जा बोदों, हाब्स प्रभृति लेखक चिन्तक इस ‘दमघोटू’ वातावरण से ‘राजनीतिक अध्ययन’ को उबारने वाले लेखक माने गए—एक स्वामत्त अनुशासन के रूप में राजनीति के अध्ययन का सिलसिला शुरू हुआ जिसका केन्द्र ये ‘राष्ट्रीय राज्य’। राष्ट्र के रूप में निश्चित सीमा के अन्दर, निश्चित ‘प्रभु’ के तत्त्व में, प्रभुता सम्पन्न ‘राज्यो’ के निर्माण का यह सिलसिला प्रथम महायुद्ध तक यूरोप में और उसके बाद सं एशिया और अफ्रीका में चलता ही जा रहा है। ‘राष्ट्रो के मध्य राजनीति’ ‘राष्ट्र का सघ’ और इन सबका मिलाजुला रूप ‘अंतर्राष्ट्रीय राजनीति’। कहने का मतलब यह कि पूरे इस अध्ययन वृत्त का जानाभि क्षेत्र है, वह प्रभुता सम्पन्न ‘राष्ट्र’ का विचार है, जिसे आधुनिक राज्य कहते हैं। इसी से यह विचार पनपता है कि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूलतः एक ही बात है—‘शक्ति के लिए सघप’—जो पिण्ड में वही ब्रह्माण्ड में।

समाज के अतगत लोगान ‘राज्य’ के रूप में संगठित बल’ का निर्माण कर लिया और ‘अराजक’ स्थिति से—मात्स्य ‘याय’ से मुक्ति पाली पर राज्यो के सत्तार में मात्स्य ‘याय’ से छुट्टी नहीं वहां जैसा हाब्स ने चिन्तित किया या पुराने भारतीय जैन, बौद्ध व वैदिक आख्यान में आता है मात्स्य ‘याय’ ही सर्वत्र विद्यमान है। ‘अंतर्राष्ट्रीय राजनीति’ का यह अजीब द्वंद्व है कि जा ‘राज्य’ राज्यान्तगत व्यवस्था बनाये हुए हैं नीति धर्म के संस्थापक हैं, व सीमा के बाहर खुद अराजक स्थिति में आचरण विचरण करते हैं और ‘बलाबल’ के आधार पर अपने पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। इन सबको का देखने परखने की सही दृष्टि क्या मानी जाए इसे लेखक अनेक सम्प्रदाय बन गये हैं।

यूरोप में सबसे पुराना विचार यह रहा है कि राज्य एक जैविक इकाई है जिसका मूल तत्त्व बल या शक्ति है। जैविक जगत में अस्तित्व के लिए जैसा अहर्निश सघप चलता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वही हाल है। राज्य एक दूसरे के विरुद्ध जिस शक्ति सघप में लगे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों का वही मर्म है। इस जैविक सम्प्रदाय की आधार शिला गम्प्लोविज ने रखी और इसका निखार—हाब्स और उनके परवर्तियों की रचनाओं में हुआ। इसे आज के युग में एक सम्प्रदाय के रूप में संगठित करने का श्रेय मुख्यतः मारगे थाऊ और उनके साथियों को दिया जाना चाहिए जो अपने आपको एक यथायवादी सम्प्रदाय कहते हैं। स्मरणीय यह है कि ‘बल’ पर आधारित इस सम्प्रदाय का विकास यूरोपीय ऐतिहासिक विकास के उस बिंदु से होना शुरू हुआ, जहाँ से सामंतीय आच्छादन को तोड़ती फोडती हुई एक ऐसी नुजुआ जाति का सिल-

सिला भी चलता है जा आदम औद्योगिक व्यापारिक क्रांति के सहारे, नय सपके सूत्रों को खोलती हुई बाग बढती चली जाती है। यूरोप के इस बुजुर्ग आ वर्ग ने, अपन घर म राज्य सत्ता पर अपना वचस्व स्थापित कर, जब यूरोप के बाहर एशिया अफ्रीका और पश्चिमी गोलाद्ध मे अपना अधिपत्य जमाया तब इस रक्त रजित प्रक्रिया म पहली बार समूची दुनिया एक् सूत्र म बधन लगी। एक दृष्टि म गेतिहासिक विकास की इग प्रक्रिया म हम अंतर्राष्ट्रीय सबधों की गहरी नीव पढत देखत है। उस और छल के सहारे पूरी दुनिया एक् सूत्र म जोड़ी जा रही थी। बड उड साम्राज्यों का गठन हुआ एशिया, अफ्रीका व लातीन अमरीका क ढीने ढाल राज्यों और उनकी समूची सामाजिक संरचनाओं के उत्पन्न-पुनरुत्पन्न का नम शुरू हुआ। साम्राज्यों के निर्माण के इस रक्तस्नात क्रम म यूरोपीय सत्ताओं न अंतर्राष्ट्रीय नीति और व्यवहार के कानून और धर्म के ज्ञात अनात सभी तरह की मर्यादाओं को एशिया अफ्रीका और अमरीका म रौंद कर रख दिया। बल ही एक सीमा निर्धारक तत्व रहा है परंतु आपस म 'अंतर्राष्ट्रीय सबध और कानून को एक सुनिश्चित धरातल पर रखने के प्रयत्न ढीले नहीं किए गए। एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और कानून एशिया अफ्रीका के लोगों के लिए तय था दूसरा अपने लोगों के लिए। ऐसा ही जसा यूनान के स्वामियों के आपसी रिश्ते और स्वामी और दास के रिश्ते अलग अलग तय होते थे।

इस यथाथ म अंतर्राष्ट्रीय सबध के अध्ययन म ऐसी ऐसी अनगल दुष्टियों का भी अवधण किया जसी गोरे लोगों का इतिहास द्वारा निर्णीत सम्प बनाने का अभियान नस्लवाद पर आधारित सजनशील और केवल बास ढोने वाली नस्ल का वर्गीकरण और गोरे या 'आर्य नस्ल का नियति बद्ध आधिपत्य का अधिकार। इससे जमनी ब्रिटेन और अमरीका म 'भू राजनीति की बहु शाखा भी निकली जो 'भौगोलिक आधार पर राजनीतिक वचस्व व पराधीनता की व्याख्या पर जोर देने लगी। राटजेस, मैकिन्डर, हासपुर प्रभृति इस प्रकार की भाषी 'भू राजनीति को वैज्ञानिकता का आवरण पहनाने लगे। दूसरी ओर यूरोप के जाग्रत और संघर्षशील मजदूर वर्ग के सजग पक्षधरों ने साम्राज्यवाद के असली रूप को उतने भीषण शोषण की समूची प्रक्रिया को उघाडना शुरू किया और एक नई अन्तर्राष्ट्रीयता के निर्माण की मांग उठाई और इसके लिए जाग्रत मजदूर वर्ग के नेतृत्व मे 'राज्य क्रान्तियों का आह्वान किया। मार्क्स लेनिन, हासन इस वैचारिक आंदोलन के सूत्रधार बन। राज्य सत्ता का मम राज्यान्तगत उत्पादन के साधन और उत्पादन के सबधों के द्वातामक विकास में छिपा था और पूजीवादी विकास की चरम परणति साम्राज्यवाद के रूप म हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय सबधों का स्वरूप भी इसी साम्राज्यवादी विकास द्वारा

निर्धारित हो रहा था। इसके विनाश के बाद ही 'अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध' की सही दिशा खुलने वाली थी।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि प्रथम महायुद्ध के पड़ते पड़ते तीन तरह की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के त्वरित विकास ने जहाँ एक ओर पुरानी दुनिया को नष्ट करना शुरू किया, वहीं उनके घात प्रतिघात ने नई दुनिया की नींव रखनी भी शुरू की। ये तीन विकास प्रक्रियाएँ थी साम्राज्यों का आपसी अन्तर्द्वन्द्व जिसकी चरम परणति प्रथम महायुद्ध के विस्फोट में हुई, साम्राज्यों के अन्दर सामाजिक क्रांति का विकास जिसकी चिंगारी तो पूरे यूरोप में फैली, पर जिसे सफलता लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति में मिली, तीसरी विकास प्रक्रिया का संबंध साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध पराधीन राष्ट्रों के मुक्ति आंदोलन के विकास में थी जिसकी परणति एक के बाद दूसरे साम्राज्यों के विघटन के सिलसिले में द्रुतगति से चलने लगी और द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के सम्पूर्ण उन्मूलन के रूप में उद्घाटित होती जा रही है। इस समग्र विकास क्रम ने पुरानी दुनिया ही उसल दी और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को नई आधार शिला ही नहीं दी बल्कि नई समझ का विकास किया। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों का अध्ययन एक नया महत्व पाने लगा।

'साम्राज्यवादी देशों में' प्रथम महायुद्ध के बाद एक और अमरीकी नेतृत्व में एक आदर्शवादी सम्प्रदाय खड़ा किया गया जो 'राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार', समता का अधिकार, और समता और बहुत्व के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और कानून के निर्माण की बात करता था जिसने, युद्धों को खत्म करने के लिए, लोकतन्त्र के लिए 'युद्ध' लड़ने की बात की थी, पर यह सब बातें यूरोप और अमरीका के साम्राज्यीय देशों तक ही सीमित थी—एशिया के राष्ट्रों की मुक्ति, उनके साथ समता का व्यवहार, उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और कानून में हिस्सेदारी इस दायरे के बाहर की बात थी। इतना ही नहीं 'अक्टूबर क्रांति' और उसके पूर्व मैक्सिको' ये ही आदर्शवादी अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन अपने सिद्धांतों को बलाए ताक रख रहे थे। दूसरी ओर एक नई अन्तर्राष्ट्रीयता के पक्षधर बने अक्टूबर क्रांति के पहलू जो बाद में स्टालिन के नेतृत्व में इस मार्क्सवादी वठमुल्लेपन पर उतर आये कि 'अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को भी केवल उत्पादन के सम्बंध या आर्थिक सम्बंध ही निर्णीत करते हैं।

इसके अलावा जब पूँजीवादी सकट के दौर में इटली और जर्मनी में विशेषतः हिटलर के आगमन पर युद्धोन्मुख राष्ट्रवाद सहर्ष लेने लगा तो 'युद्ध, हिंसा, विग्रह' को लेकर भीड़ और जातियों के मनोविज्ञान के रास्ते अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ प्राप्त करने के प्रयत्न हुए। जैसे व्यक्ति के मनोविज्ञान का अध्य-

यन किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का, उसका सवर्गों, भावनाओं और व्यक्तित्व के अनन्य पक्षों का, इसी तरह राष्ट्र और मस्ती का भी अध्ययन हो सकता है। हिटलर के व्यक्तित्व के अध्ययन से, जर्मन जाति के गुण-दुगुणों के अध्ययन से हम जर्मन परराष्ट्र नीति की समझ या सबूत हैं, ऐसी दृष्टि विरसित की जाने लगी। युद्ध और शांति के प्रश्नों को मानव व्यवहार के, समूहों के व्यवहार स्वभाव के रास्ते समझने का प्रयास हुआ।

इस प्रकार व्यवहारवाद, मनोविज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सगठन वाले पक्षों पर बस देने वाले सम्प्रदायों ने जोर पकड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय सबूतों का समझने का एक सम्प्रदायपरक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ—सम्प्रदायों उदित होती हैं बढ़ती हैं, उनका पतन होता है—पश्चिमी सम्प्रदाय का यह पतन काल है स्पेगलर ने कहा। इस तरह की दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीय सगुणों को देखा गया—अकदमर जाति और उसके परिणाम पर सम्प्रदायपरक इस दृष्टि से निष्कर्ष निकाले जाने लगे।

हमारे महायुद्ध के बाद विकास की उच्च प्रक्रिया और भी स्वरित गति से आगे बढ़ने लगी। साम्राज्यों का समूल विघटन एक यथायवादी घटनाक्रम बन गया, समाजवादी राज्यों का एक समूह उठ खड़ा हुआ, सामाजिक जाति और साम्राज्य विरोधी जाति का संगम जगह-जगह बनने लगा। एक नई दुनिया तेजी से उभरने लगी जिस समझने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह पूर्वकालीन सम्प्रदाय नहीं दे पा रहे थे। उनके सहारे विकास को समझना मुश्किल बन गया था। न जविक रूप में 'राज्य' के तथ्या को मानवर चेतन से न मनोवैज्ञानिक ढंग से 'नस्ली और राष्ट्रों और उनके नेताओं के व्यक्तित्वों का विश्लेषण करने बात समझ आ रही थी और न इसे नस्ली और सम्प्रदायों के 'आलोचन विलोचन उनके उत्थान पतन की कहानी के रूप में बात समझाई जा सकती थी। स्वतन्त्र राष्ट्रों के इस विकासशील समुदाय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सगठन में सब की हिस्सेदारी अब मागन की बात न होकर अधिकार की बात हो गई थी। शक्ति के लिए समझ का मैदान अब इस कदर घुसा नहीं रह गया था कि 'उत्तम सबल राष्ट्र' जब चाह जहाँ चाहे धमाचौकड़ी मचा सके। पुरानी दुनिया अभी भी नष्ट नहीं हुई है, पुराना साम्राज्यी मन अभी भी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है सभी वियतनाम में चिली में, साल्वादोर में लेबनान में अमरीकी और इजरायली पागलपन मानवता को झेलना पड़ता है। पर हथियार और बल निर्णायक हाथ तो वियतनाम और फिलीस्तीनी जनता और नेतृत्व मानवता की अस्मिता व स्वाधीनता की उद्दाम चेतना और उसकी अजेयता का गौरवपूर्ण दृष्टांत नहीं बनत।

अन्तर्राष्ट्रीय सबूतों की सही समझ दुर्भाग्यवश दूसरे शिविर में भी नहीं

विकसित हो पा रही है। मानव इतिहास के विकासक्रम में राष्ट्रो का निर्माण हुआ, देशों की रचना हुई, यह विकास की लम्बी प्रक्रिया के फलस्वरूप है। मानसवादी समझ के अनुसार जैसे राज्यों के अन्तर्गत विकास क्रम को समझा जाता है उसका यत्नवत प्रयोग 'अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों' को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगा बल्कि समझ गलत हो जाएगी। उत्पादन के साधन और सबंध, नींव और ऊपरी ढांचा और उनके आपसी द्विद्वात्मक सबंध राज्य के स्वरूप को निर्णीत करते हैं, पर 'अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र' में न कोई एक नींव है, न उसका ऊपरी ढांचा जो एक इकाई के रूप में अपने अन्तर्द्वन्द्वों के सहारे विकसित हो रहा हो। यहाँ राज्य के माध्यम से ही 'अन्तर्राष्ट्रीय सबंध' विकसित होते रहते हैं। इसलिए सही मानसवादी दृष्टि जहाँ एक ओर 'मनोवैज्ञानिक' तौर तरीके, जबकि दृष्टि तकनीक, विचार या नैतिकता पर आधारित सिद्धांतों को इस अर्थ में अस्वीकार करती है, कि ये निर्णायक हैं, वहाँ यत्नवत मानसवाद की इस प्रस्थापना का भी त्यागना होगा कि राज्यों के आपसी सबंधों को 'आर्थिक तत्त्व' के आधार पर ही देखा जाए।

मानसवाद की सबसे बड़ी देन यह है कि वह हम गतिशील विकास को द्विद्वात्मक तरीके से उभरते हुए दृष्टम की दृष्टि देता है जबकि अन्य सम्प्रदाय यह मानकर चलते हैं कि दुनिया ज्यों की त्यों स्थिर है और सघषरत वर्गों और राष्ट्रों के हिता और स्वार्थों में तालमेल बढाने के तरीके की खोज करनी चाहिए। मानसवाद का मुख्य सदेश है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह सदुल्लन, सामंजस्य और स्थायित्व के गुणों वाली दुनिया नहीं है बल्कि सघष परिघटन क्रांति की निरंतरता के गुण वाली दुनिया है, पर अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों की इस सतत प्रवाहवान् दुनिया के रहस्यों को समझाने के लिए हम उन माध्यमों पर भी दृष्टि रखनी होगी, जिनके सहारे यह विकास क्रम कभी धीमे धीमे, कभी छलांग मारता हुआ चलता है। वे माध्यम हैं, वे तमाम सामाजिक संरचनाएँ जैसे राष्ट्र वर्ग, दल, नेतृत्व, व्यक्ति, उनके आपसी सबंध और द्विद्वात्मक रिश्ते और इस तरह के राष्ट्रों का परिवार और उनके बीच द्विद्वात्मक सबंधों का कभी न टूटने वाला विकास क्रम, एक दूसरे को प्रभावित करने का अतर्हीन सिलसिला। इसी समग्र दृष्टि के सहारे अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों का सही अध्ययन हो सकता है। तभी समझ में आता है कि अपने को समाजवादी मानते हुए भी सोवियत और जनवादी चीन के बीच क्या सघष है और उसकी क्या सीमा है, लोकतन्त्री अमेरिका भारत के लोकतन्त्र के दृजाय पाकिस्तानी सैनिक तत्त्व को क्यों सहारा देता है, और अफगानिस्तान और कम्पूचिया के मामले में भारत सोवियत और वियतनाम के साथ क्या व्यवहार नहीं करता जसा चीन करता है और इंदिरा गांधी की सरकार भारत की सीमा के बाहर साम्यवादी सरकारों

को जमा सम्पत्ति और उनके प्रति दोस्ताने का रुख रखती है, वैसा भारत के अन्दर चल रही कम्युनिस्ट सरकारों के लिए नहीं और जिन वामपंथी सरकार की पूँजीवादी-सामन्तवादी नीतियों की भारत के कम्युनिस्ट आये दिन भर्त्सना करते हैं, उस सरकार की परराष्ट्रनीति का वे खुद ही समर्थन करते हैं। तात्पर्य यह कि परराष्ट्र संबंध और घर के अन्दर के संबंध में घना संघर्ष है जरूर, ये अयोध्याधित भी है, पर इस ढंग से नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाँच अरब रुपये लेते ही भारत की परराष्ट्रनीति और संबंध इन ऋणदाताओं के गिरपत में आ गये। इसके बाद भी इंदिरा गांधी ने अमरीका में ही और मारि शस में भी नियागो गांसिया, पाकिस्तान को शस्त्र देते और लेबनान में इजरायली नरसंहार के लिए अमरीका की भर्त्सना करने में कोई कौताही नहीं की।

ससार व्यापी महासमर की पूर्व वेला में

हम यह प्रारंभ में ही स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस अध्याय में हमारा लक्ष्य द्वितीय महासमर के उपरांत की दुनिया की विवेचना करना है, क्योंकि हम उस महासमर की पूर्व पीठिका की चर्चा अत्यन्त भी कर चुके हैं जिसने सितम्बर 1939 से यूरोप के दक्षिणाली देशों को अपनी लपेट में लेकर अगले वर्षों के अंदर समूचे यूरोप को अपनी विभीषिका का शिकार बना लिया। यह महासमर केवल यूरोपीय महाद्वीप तक फैली लड़ाई नहीं रह गई। एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन और अथ एशियाई प्रदशों को अपने-अपने क्षेत्र में लेने की प्रतिस्पर्धा में पर्ल-हार्वर की वमबारी के बाद अमेरिका और जापान के बीच जबदस्त भिड़त हुई और युद्ध अब केवल चीन जापान के बीच बसा आ रहा साम्राज्यवादी युद्ध मात्र ही नहीं रह गया। महासमर की विकराल लपेटों में अब यूरोप और एशिया के विशाल जन समुदाय झुलसने और मृनने लगे, तब यह स्वाभाविक ही था कि दुनिया के अथ लण्डा तक इनकी विनगारिया फैलने लगे। इस प्रकार यह महासमर सही मायने में एक ससार व्यापी महाभारत बन गया।

केवल युद्ध के फैलाव की वजह से ही नहीं, अथ कारणों से भी यह महासमर पूर्ववर्ती प्रथम महायुद्ध से भिन्न लगने लगा बल्कि, ऐसा कहा जाना चाहिये कि यही युद्ध वस्तुतः पहला ससारव्यापी युद्ध था जो प्रारंभ तो हुआ था एशियाई और यूरोपीय देशों में आपसी गृह युद्ध के रूप में पर तेजी से इसका फैलाव बढ़ता गया। इस युद्ध की दो विशेषताएँ दृष्टव्य हैं। प्रथम यह कि यूरोप और एशिया में टकरा रही विरोधी ताकतें आपस में एक दूसरे से सहयोग कर अपनी लड़ाई के दायरे में पूरी दुनिया को ला रही थी। ब्रिटेन व अमेरिका यूरोप में जर्मनी और इटली से, इसी तरह एशिया में जापान से भिड़ रहे थे, ऐसी कुछ स्थिति सोवियत संघ की भी थी। उसमें एक फक यह था कि जापान के साथ उसकी अनाक्रमण संधि महायुद्ध के अंतिम चरण तक बरकरार रही जिससे उसे यूरोपीय मोर्चे में ही लड़ना पड़ा। दूसरी ओर जापान, जर्मनी तथा इटली ने यूरोप और एशिया-अफ्रीका में ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका को चुनौती दी। इस दृष्टि से जापान को भी सोवियत

मोर्चे का सामना युद्ध के अन्तिम चरण के कुछ पूर्व तक नहीं करना पड़ा। जर्मनी और इटली को भी भिन्न राष्ट्रीय शक्ति का सामना यूरोप व अफ्रीका के रणरंगत पर ही करना पड़ा। दूसरी बड़ी बात यह थी कि महायुद्ध में जूझ रही व महा शक्तियाँ अपनी अपनी लड़ाइयाँ दुनिया के नक्शे को अपने सामने रखकर लड़ रही थी। अंग्रेजों फ्रांसिसिया और उनके मित्र अमेरिकियों को जबकि अपने अपने साम्राज्य और अधिकार क्षेत्रों को बचाने की फिक्र पड़ रही थी, तब लड़ाई में जूझ रही इन ताकतों को, जो घुरी राष्ट्राँ के नाम से एकजुट हो रही थी, दुनिया का साम्राज्यवादी नरेशा अपने पक्ष में बदलने का दृढ़ संकल्प युद्धोन्मुख बनाय हुआ था। इन घुरी राष्ट्राँ में कम से कम जर्मनी के नात्सी नेता तो अपने इस संकल्प को बारम्बार दुहरा रहे थे कि पूरी दुनिया को जीतना है और उस अपने अनुकूल बनाना है और इस प्रकार इतिहास में जो अब तक "असंभव बना हुआ था, उसे संभव बनाने में जर्मन नात्सी अपना पूरा दम खम लगा रहे थे।" इस दृष्टि से भी, इरादे या मसूवे के हिसाब से भी, यह युद्ध एक विश्व युद्ध का रूप ले रहा था। पहले महायुद्ध में किसी शक्ति ने अपने संकल्पा की ऐसी घोषणा न की थी, न उनकी रणनीति का यह लक्ष्य था।

युद्धरत शक्तियों के इरादे और मसूवों में इस प्रकार गुणात्मक परिवर्तन के होते हुए भी यह महायुद्ध गत महायुद्ध का क्रमिक विकास ही था। यह महायुद्ध अनिवार्य और अभिन्न रूप से प्रथम महायुद्ध से जुड़ा हुआ था। बहुत सारी व्यवस्थाएँ, प्रबंध, निणय और संधियाँ जो बनी या बिगड़ी थी वे सब जैसा जीवत होकर मचलती हुई पुनः अपने अन्तिम समाधान के लिए रणमंच पर आ गई थी इससे ऐसा लग रहा था कि जो गत हो चुका मान लिया गया था वह ऐसा हुआ नहीं जो अतीत बन गया था वही जैसे वर्तमान बनकर लगभग ज्यों का त्यों, दिखता हुआ, पुनः इतिहास के मंच पर आ गया हो।

तीन नई बातें, तीन नये विकास

पर प्रथम महायुद्ध के बाद जिस प्रकार दुनिया भर में घटनाचक्र घूम रहा था उसको परखते हुए कहना ठीक न होगा कि इतिहास केवल अपने को दुहरा रहा था अर्थात् जो कुछ हो रहा था, वह लगभग ऐसा ही था जैसा पहले हुआ था। वस्तुतः नई ऐतिहासिक शक्तियाँ ने जन्म ले लिया था और नये विकास नई रूढ़ान नई बातें तेजी से इतिहास के रणमंच को घेर रही थी। ऐसी तीन नई बातें हमारा ध्यान खींचती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनमें पहली बात पुराने साम्राज्यों के बारे में थी।

(1) साम्राज्यवाद के दुर्गं टूटने बिखरने लगे सक्रांति का भीषण दौर

प्रथम महायुद्ध में जो शक्तियाँ आपस में टकराई थीं उनमें मित्र राष्ट्रों के नाम से जाने वाले देश विजयी हुए, जर्मनी और उसके साथी आस्ट्रिया-हंगरी, तुर्की आदि पराजित हुए। रूस की जारशाही हारते हारते खुद मिट गई और एक नई व्यवस्था के उसका स्थान ले लिया। पर महायुद्ध खतम होने के बाद विजयी और पराजित दोनों ही तरह की ताकतों फिर से अपनी घरेलू सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को पुराने ढर्रे पर न ला सकी। जिस पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये दोनों तरह की शक्तियाँ युद्धपूर्व सज-घज कर रणस्थल पर आई थी वह पूँजीवादी व्यवस्था टूटने बिखरने लगी, जो हारे थे उनके लिए पुराने आधार पर समझना तो मुश्किल बन ही रहा था, जो जीते थे अंग्रेज, फ्रांसिसी आदि, वे भी पुरानी व्यवस्था पर पैबंद लगाते लगाते हाफ रहे थे। महायुद्ध ने दुनिया भर में फली पूँजीवादी व्यवस्था के अगले विकास के लिए ऐसे अंतर्विरोध खड़े कर दिये थे जिन्होंने जो उसके विकास का माँग अवरोध कर रहे थे। एक तो पूरा का पूरा जारशाही वाला रूसी साम्राज्य इस व्यवस्था से बाहर निकल चुका था। दूसरा जर्मनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसकी नोच लसोट जारी थी। हम अद्यत् भी पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कर चुके हैं कि दुनिया भर में फली पूँजीवादी व्यवस्था में प्रथम महायुद्ध के पूर्व जर्मनी औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस से बाजी मारकर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश बन चुका था। अपने लिए साम्राज्यी व्यवस्था कर पाने के अभियान में महायुद्ध में फसकर वह अपनी इस उपलब्धि को खो बैठा और टूटकर उत्पादन के निम्न धरातल पर आ गिरा। यही हालत जर्मनी के अन्य युद्धकालीन मित्रों की हुई। हारे हुए उभर ही नहीं पा रहे थे, पर जीते हुए भी अपना पुराना ढर्रा नहीं लौटा पा रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इनके सानी देश पूँजीवादी व्यवस्था को बचाये रखकर भी उसके अंतर्गत युद्धपूर्व के उत्पादन के कीर्तिमान को पुनः अर्जित नहीं कर पा रहे थे और न सामाजिक तौर पर युद्धपूर्व की स्थिति लौटा पा रहे थे। जर्मनी से भारी क्षतिपूर्ति व अन्य नोच खसोट व लूट के बावजूद युद्ध की समाप्ति के बाद दस वर्ष भी चैन से गुजारे नहीं जा सके थे कि सन् 1929 की महामंदी की लपेट में रहा सहा भी गवा बठे। प्रथम महायुद्ध और उसके बाद पैदा हुई असंतुलन और अव्यवस्था ने महामंदी के रूप में पूँजीवादी व्यवस्था के कमजोर हुए स्तंभों को बुरी तरह झकझोर दिया और उसकी प्रगति तो रुक ही गई उल्टा उत्पादन का पुराना कीर्तिमान छू पाना ही उसके लिए दुष्कर काय हो गया। यूरोप तो युद्ध की चोट से टूटा हुआ था, पर अमेरिका युद्ध के अंतिम चरण में शामिल होकर युद्ध से आहत नहीं हुआ था। पर यूरोप की टूट फूट के दौरान

पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे में जब महामदी के रूप में अमेरिका की उत्पादन व्यवस्था को चीट पहुँची तब पूँजीवाद के इस सुदृढ़ विघ्नरहित दुग में भी दरारें पड़ने लगीं। अमेरिका के मदी ने उसकी उत्पादन व्यवस्था को नीचे खींचना शुरू कर दिया। एवं के बाद दूसरे संकट में अस्त हो रही पूँजीवादी व्यवस्था का हाल द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने के पूर्व तक यह रहा कि प्रथम महायुद्ध और महामदी के संकट को दूर नहीं किया जा सकता। अगर हम सन 1929 को आधारवर्ष मानकर सोवियत संघ को छोड़कर अन्यत्र ससार व्यापी पूँजीवादी औद्योगिक उत्पादन का स्वरूप देखें तो यह कुछ इस प्रकार बनता है।

जर्मन और उद्योगों में (1929-100)

वर्ष	दुनिया का उत्पादन (सोवियत संघ को छोड़कर)
1934	77 7
1935	86
1936	96 4
1937	10 37
1938	93

इसमें स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवादी दुनिया प्रथम महायुद्ध और महामदी की घातक योजना में उभर नहीं पा रही थी। उसका उत्पादन घोडा बहुत ठीक हुआ तो वह भी सन् 1937 में जब हिटलर ने सत्ता सम्हालते ही "मुद्रो-मुनी अर्थ-व्यवस्था" की स्थापना कर सर्वाधिकारवादी राज्य सत्ता की स्थापना कर दी थी और उसकी पुनोत्थिता का सामना करने के लिए पश्चिम के साम्राज्यवादी नतुरथ ने भी उत्पादन के संकट में उमंग की ठानी।

युद्ध के विराम में ब्रिटेन और फ्रांस इस गहराते हुए संकट का योग्य प्रयत्न उप दिशा पर योजनात्मक और सन् 1935 तक ब्रिटेन ने उत्पादन का सन् 1929 का स्तर प्राप्त कर लिया और आग दिशा में सन् 1937 में 20 प्रतिशत और सन् 1938 में 15 % अधिक उत्पादन का स्तर प्राप्ति कर लिया पर फ्रांस को ऐसी सफलता नहीं मिली। सन् 1933 में उसका उत्पादन स्तर सन् 1929 के मुद्रांक के बराबर रहा था। और सन् 1938 में यह 23 9 प्रतिशत नीचे था। करने का कारण यह है कि प्रथम महायुद्ध के पूर्व की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की प्रत्यक्ष पुनर्स्थापना नहीं की जा सकी। प्रथम महायुद्ध और तदुत्तरांत महामदी का कारण ब्रिटेन में और पश्चिम के अन्य देशों के सामाजिक

जीवन में जो उथल पुथल मचा दी—बेरोजगारों की बढ़ती कतार, मूल्य वृद्धि, सामाजिक तनाव व असुनलन, और ऐसे ही अनेक अंतर विरोधों की शृंखला ने राजनीतिक व्यवस्था को अकड़ लिया। इसका अलग अलग देश में अलग अलग प्रभाव पड़ा पर सभी जगह एक बात सामान्य तौर पर घटित हुई और वह यह थी कि राज्य सत्ता के द्वारा जन जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभावी हस्तक्षेप की प्रवृत्ति में अपूर्व बढ़ाव। यह सभी जगह देखने को मिला, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या अमेरिका या जर्मनी व इटली।

इसका सबसे एक सा प्रभाव यह हुआ कि उदारवादी नरमदली पूँजीवादी दलान का सोप हो गया, ब्रिटेन में अनुत्तर दल बनपा यहाँ लेबर दल संगठित होता गया पर लिबरल दिग्गज हो गए, फ्रांस में अनुदार व प्रतिक्रियावादी तत्वों की साख घटी और आमपथी लोकप्रिय होते गए यद्यपि वे समय का लाभ उठाकर एकजुट नहीं हो सके और यही जर्मनी में भी हुआ जहाँ समाजवादी व साम्यवादी दलों की आपसी लड़ाई और फूट का हिटलर के नात्सी दलों ने लाभ उठाया और सर्वाधिकारवादी सत्ता जर्मन पर थाप दी जो इटली के फासिस्टों की तरह सवर्गशील सत्ता थी।

पूँजीवादी व्यवस्था के अतगत ढूँढे गए “जर्मन समाधान” की अपनी विशेषताएँ दृष्टव्य रही। पहले मजदूरों के संगठनों तथा राजनीतिक दलों को नेस्तनाबूत किया गया, फिर उदार पूँजीवादी दलों की धामत आई और उन्हें भी मिटाया गया पर पूँजीवाद को नहीं। पूँजीवाद के विकास के चारों ओर नात्सी लक्ष्मण रेखा खींच दी गई और एक युद्धो-मुखी अर्थव्यवस्था तथा आतंकवादी और विस्तारवादी आक्रामक परराष्ट्र नीति से उसका गठबंधन कर दिया गया। इस कायवाही ने तात्कालिक पूँजीवादी व्यवस्था के बढ़ते हुए संकट का—बढ़ती बेरोजगारी और उभरती सामाजिक अराजकता को राज्य सत्ता की छत्रछाया में एक संगठित अराजकता के सहारे रोक दिया गया पर जिस नात्सी चीते पर जर्मन सत्ताधारी सवार हो गए थे और अपने साथ जर्मन पूँजीपतियों को भी बैठा लिया था, उसके बाद उनके लिए लूटमार, आतंक, युद्ध के जलावा दूसरा रास्ता और क्या अपनाया जाता। युद्धो-मुखी अर्थव्यवस्था ने सैनिक तानाशाही को हथियारों की कमी नहीं रहने दी, उधर नात्सी पागल नेता के विश्व विजय की सनक को चरिताथ करने के अभियान में सैनिक तानाशाही ने अपनी ओर संकसर नहीं छोड़ी जिसका परिणाम हुआ एक और घनघोर महायुद्ध। पर युद्ध पूर्व इस युद्धो-मुखी अर्थव्यवस्था ने पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे में रहकर एक अभिनव प्रयोग तब किया जबकि नात्सी राज्य को सीधे-सीधे पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे में अंदर रहकर पूरा का पूरा विदेशी व्यापार सीधे-सीधे संभाल लिया, उससे संबंधित उद्योगों को नियंत्रण में ले लिया और पूँजी नियोजन की दिशा में होगी, इसका नियमन भी अपने हाथों में

लिया।¹³ इसे व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए राज्य ने मजदूरी और कीमतों दोनों पर अपनी जकड़ मजबूत की।¹⁴

यह इस अर्थ में तो नई बात नहीं थी कि पहले कभी इस ढंग का कुछ हुआ नहीं था। प्रथम महायुद्ध के दौरान पूँजीवादी व्यवस्था ने एक बड़े पैमाने पर राज्य निर्देशित योजना और संयोजित अर्थव्यवस्था का जायजा लिया था पर नई बात इस बार यह थी कि सर्वाधिकारी राज्य की जकड़ शान्तिवाद में ही शुरू हो गई थी और यह जकड़ उस ढंग के राज्य के हाथों में रही थी जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट डाला था। मजदूर संगठनों और उनके दलों को विनष्ट कर उन्होंने उनका बग नेतृत्व तो खतम कर दिया पर युद्धोन्मुखी अर्थव्यवस्था के सहारे बेरोजगारी मेंट कर उनके असंतोष के ज्वालामुखी को ठंडा कर दिया। पर यह तो हुआ कि सर्वाधिकारी और शीघ्र ही उत्पादन का स्तर 1929 से आगे निकल गया पर बहुत सा था। मजदूर कभी भी दिल से इसके साथ नहीं रहे जो इस बात से स्पष्ट था कि नाजी व्यवस्था के चरमराते ही वे फिर अपने पुराने सपने के नीचे दीड़कर आने लगे।

युद्धोन्मुख अर्थव्यवस्था की प्रगति ज्यों ज्यों हुई, जर्मन सैनिक तानाशाही आतंक और आनमण की नीति अपना कर हस्तक्षेप की कायबाही में जुट गई। मित्र राष्ट्र चाहते तो शुरू शुरू में नात्सी जर्मनी का बढ़ना और जमना रोक सकते थे, पर वे हिटलर को फुसलाने व बहलाने की नीति अपनाने लग गए।

ताकि उसका सैनिक अभियान पूर्वाभिमुख अर्थात् सोवियत संघ की ओर से हो जिस प्रकार साम्यवादी और समाजवादी दलों का उसने कठोर दमन किया था उससे उन्हें भरोसा जम रहा था कि हिटलरी शक्ति भस्मासुरी शक्ति नहीं बनेगी। यह साम्यवादी व समाजवादी विचार और व्यवहार को रोक रखने वाली कम से कम चीन की दीवार तो बनेगी ही।

पर नात्सी सफलता ने इद गिद लोकतंत्र विरोधी और सर्वाधिकारवादी ताकतों को नात्सी झंडे के नीचे एकजुट करना शुरू कर दिया। हिटलर ने पहले आस्ट्रिया फिर चेकोस्लोवाकिया और बाद में पोलैण्ड को आत्मसात किया तब जानर पश्चिमी राष्ट्रों की कुभकर्णी निद्रा टूटी।

जर्मनी के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार का बदला लेने का ही सक्त्प लेकर जारी हो, ऐसा नात्सी शक्ति का स्वभाव नहीं था। वह तो जर्मन शक्ति को, नात्सी शक्ति का एक विश्व साम्राज्य का केन्द्र बनाने के लिए उत्सुक हो रही थी। उसक सपन दुनिया को जीत लेने के थे और इसी दृष्टि से वह यूरोप में इटली और पूर्व में जापान से हाथ मिलाकर एक विश्व-व्यापी अभियान चलाने की अभियोजना बना कर चल रही थी।

जापानी गठजोड़

जापान की सैनिक तानाशाही ने तो नात्सी दल के सत्ता में आने के बहुत पहले से ही साम्राज्यवादी विस्तार के लिए सैनिक कायवाही छेड़ रखी थी। जमनी में तो पहले युद्धो-मुखी अथव्यवस्था जमाई गई फिर लड़ाई छेड़ी गई पर जापान में युद्धो-मुखी अथव्यवस्था के निर्माण और सैनिक अभियान के बीच का अंतराल बहुत छोटा था। सन् 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण करके सैनिक अभियान को छेड़ा गया और महासमर के शुरू होने तक जापान इस प्रकार की आक्रामक कायवाहियों में निरंतर जुड़ा ही रहा। जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर यहाँ उद्योग धंधे जमाकर, इसे अपने युद्धो-मुखी अथव्यवस्था की कुडली में फसा लिया जिसने सैनिक तानाशाही जापान की उत्पादन व्यवस्था की क्षमता को बड़ा दिया जो कुछ मायने में नात्सी जमनी से भी आगे बढ़ गई। सन् 1929 के वष को आधार मानकर चलें तो जापान का औद्योगिक उत्पादन इस प्रकार बढ़ता ही चला जा रहा था।

इस प्रकार युद्ध के समार व्यापी स्वरूप ग्रहण करने के पूर्व हम पाते हैं कि नात्सी जमनी फासी इटली, सैनिक तानाशाही जापान ये सभी धुरी शक्तियाँ अपने अधीन अथव्यवस्था को युद्धो मुखी बनाकर उत्पादन की शक्तियों को काफी आगे बढ़ा ले आये थे। यद्यपि यह तथ्य भी स्मरणीय है कि युद्धो-मुखी होने के नाते उत्पादन का वही क्षेत्र तेजी से और प्रभावशाली ढंग से विकसित किया गया था, जिसकी युद्ध की आवश्यकताओं से घना और निकट का सम्बन्ध था। इस प्रकार के विकास में युद्ध के बीजों का तेजी से पनपना स्वाभाविक था। युद्धो-मुखी अथव्यवस्था युद्ध ही छिड़वा सकती थी और वही इन धुरी शक्तियों ने किया।

अमेरिकी अथव्यवस्था का सामर्थ्य

जहाँ यूरोप के मित्र राष्ट्र सन् 1929 कि महामंदी की मार से घायल अथव्यवस्था को पुनः ठीक से खड़ा करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे वहाँ धीमे धीमे ही के अपने उपनिवेशों पर भारी बोझ फेंकते हुए पर खुद भी बेरोजगारी तनाव व उत्पादन की आर्थिक क्षमता का ही उपयोग कर, हाफते हाफते धीमे धीमे युद्धो-मुखी नात्सी फासी व जापानी सैनिक तानाशाही की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आए। पश्चिमी यूरोप के मित्र देश जब लड़ाई में कूदे, तब उनकी उत्पादन क्षमता नात्सी व फासी शक्तियों की तुलना में कम ही थी। वस्तुतः जमन तेज आक्रमण का फास थोड़ी देर भी सामना नहीं कर पाया उधर पूर्व में पोलैण्ड तक का प्रदेश जमन बूटो के नीचे रौंद दिया गया। पश्चिमी में अकेले अंग्रेज बचे और पूर्व में सोवियत संघ अन्यथा सारे पश्चिमी यूरोप में नात्सी फासी

एठवधन के आगे घुटने टेक लिए। अंग्रेज बहादुरी दिखा रहे थे पर अकेला चना क्या भाड़ तोड़ता। अगर एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ लड़ाई में न ले आए गए होते (जो मित्र राष्ट्रों की एकता और अपूर्व क्षमता और शीघ्र के दृढ़ स्तम्भ बनें) तो युद्ध का रंग ही कुछ और होता।

अमेरिकी मित्रता घरदान बन गई

अमेरिका प्रथम महायुद्ध के अंतिम चरण में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में भाग लेकर महायुद्ध में भाग्य का निपटारा भी मित्र राष्ट्रों के ही पक्ष में कर दिया था पर युद्ध के बाद शांति संधियों सम्पन्न कराने के बाद और राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद वे खुद उन प्रबन्धों से दूर हटकर अपनी लिचड़ी पकाने लगे। वह तब भी सम्पन्न एवं क्षमतावान देश बन गया था। प्रथम महायुद्ध में अमेरिका यूरोपीय देशों की तरह युद्ध का अखाड़ा नहीं बना था। उसकी उत्पादन व्यवस्था दिन दूनी बढ़ती गई। हम इस ग्रन्थ के पहले खण्ड^१ में बता चुके हैं कि किस प्रकार प्रथम महायुद्ध के पूर्व अमेरिका औद्योगिक उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया जिसके बाद जर्मनी का ही नम्बर आता था पर जहां युद्ध ने जमनी की नमर तोड़ दी, अमेरिका आगे बढ़ता ही गया और अगले दस वर्ष में अर्थात् महामदी के पूर्व उसका औद्योगिक उत्पादन सन् 1919 की तुलना में दुगुना हो गया। महामदी ने इस उत्पादन स्तर को एक दम आधा कर दिया। यह महामदी का सक्क ऐसे देश में कहर ढा रहा था। जहां न तो पश्चिम में यूरोप के देशों की तरह कोई जबर-दस्त समाजवादी या काय प्रभावशाली मजदूर आन्दोलन था और न राज्य की केन्द्रीय सत्ता यूरोप के समान विकसित थी। वस्तुतः यूरोप में सभी देशों के पास अच्छी-खासी सेनायें थी, और अनिवार्य सैन्य सेवा की परम्परा थी जो केन्द्रीय राज्य सत्ता की सुदृढ़ता की अनिवार्य बात थी। पर अमेरिका में यूरोप की तुलना में यह सब बहुत नगण्य था। इसलिए जबकि महामदी का सामना करने के लिए यूरोपीय देशों के पास सुदृढ़ केंद्र वाली राज्य सत्ता थी, अमेरिका की राज्य सत्ता के पास इतने तीखे व तेज तर्रार दात नाखून भी न थे। अमेरिका में औद्योगिक क्षेत्र ही अपितु अविभाज्य अंग बनकर था, जिसकी उत्पादन क्षमता इतनी विकसित हो चुकी थी कि न केवल अपने लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य वस्तुएं पैदा की जाती थी बल्कि, अतिरिक्त उत्पादन होता था जिसका बाहर निर्यात होता था।

ऐसी सुदृढ़ और अनोखी ढंग की पूँजीवादी व्यवस्था पर महामदी ने जो चोट की, वह महायुद्ध से अधिक घातक सिद्ध हुई। इसे सभालने में अमेरिका को समय मिला। राज्य के नेतृत्व में 'नए प्रबन्ध' ('न्यू डील') ने एक नए युग का ही शुभारम्भ किया जिसके अंतर्गत पहली बार अमेरिका में राज्य सत्ता के सुदृढ़ आधार तैयार किए गए और राज्य सत्ता के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन

के नियमन के लिए राज्य के हस्तक्षेप का सिलसिला शुरू हुआ जिसने वैश्वीय शासन की क्षमता को बढ़ाने का नया दौर ही शुरू कर दिया। पर इस नये प्रबन्ध के अन्तर्गत न तो नात्सी जर्मनी की तरह किसी सुनियोजित अर्थव्यवस्था को उभारने की चेष्टा हुई और न ही शान्तिकरण के लिए आवश्यक व उसके अनुरूप अर्थव्यवस्था ढालने का प्रयत्न हुआ। जब महामदी शुरू हुई तब तक अमेरिका में सैनिक व्यय अमेरिका की समूची राष्ट्रीय आय का केवल एक प्रतिशत भाग मात्र था। इसके बाद भी इसमें कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई—सन 1933-38 में भी इस मद में खर्च नगण्य ही रहा और न यहाँ जर्मनी की तरह विदेशी व्यापार के राजकीय नियन्त्रण में लाने की कोशिश हुई।

अमेरिका से वस्तुओं का निर्यात तुलना-औद्योगिक उत्पादन

(1903-1925 औसत 100)		वर्ष	जर्मनी 1929	अमेरिका 1935-1939 औसत 100
सालाना औसत	कुल मात्रा			
1926-30	122	1929	100	110
1931-35	76	1934	79.8	75
1936	82	1935	94	87
1937	105	1936	106.3	103
1938	103	1937	117.2	113
1939	110	1938	126.2	89

इस प्रकार देखें तो हम पाते हैं कि हिटलरी जर्मनी की तुलना में अमेरिका अपने सन् 1929 के स्तर को प्राप्त करने और उससे आगे निकलने में सफल नहीं हो रहा था।

औद्योगिक उत्पादन जो सन् 1928 के बाद आधा हो गया था वह केवल 1937 में आगे बढ़ा लेकिन 1938 में फिर नीचे गिर गया। महामदी से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उलट फेर किए गए ताकि, अधिकांश कामगारों की क्रय शक्ति बढ़े, बेरोजगारी कम हो, कृषि क्षेत्र की कीमतें बनीं रहे कृषि उत्पादन पर नियन्त्रण रहे और उन्हें मुआयजा मिलता रहे। सावजनिक ऋण में वृद्धि होने दी गई है। इसके साथ ही साथ जहाँ पर एक ओर राज्य की भूमिका में और बढ़ोत्तरी हुई, राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रोत्साहन से ट्रेड यूनियनों की स्थिति व प्रभाव में वृद्धि हुई और पश्चिम यूरोप के पैमाने पर इसके प्रभाव का विस्तार होने लगा और दूसरी सामाजिक कल्याण की नीति का

अधिकाधिक क्रिया-बयन होने लगा। इतना होते हुए भी 1933-1938 के बीच बेरोजगारी कुल श्रम शक्ति का औसतन 19 प्रतिशत बनी रही।

पर इस सारे क्षण ने बड़े बड़े उद्योगों के मालिकों को नहीं हुआ वे महामंदी के सकट का मजे में खेल सकें—केवल उनके बीच के छूट मय्ये उड़ गये। जब युद्ध छिड़ गया, तब रूजवेल्ट को इन पर लगे (यास विरोधी अभिनियम) थोड़े बहुत प्रतिबंध भी हटाने पड़े, सभी युद्ध सामग्री के उत्पादन में पूरा सहयोग मिलना संभव हुआ।

कुल मिलाकर इन सारे प्रबंधों के बावजूद अमेरिका की उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया जा सका और बेरोजगारी 19 20 प्रतिशत बनी रही। फिर भी अमेरिका दुनिया का तब भी अ-यो से अधिक धनाढ्य देश था जिसका जीवन स्तर सबसे ऊँचा था और जहाँ किसी समाजवादी ढंग का एक विकसित आंदोलन का अभाव ही रहा पर इसमें राज्य के द्वारा जन जीवन में विशेषतः आर्थिक क्षेत्र के नियमन के लिए रास्ता जरूर बना दिया जिसकी कोई परम्परा इसके पूर्व नहीं थी।

पर जब एक बार यूरोप में युद्ध छिड़ गया उसके बाद तेजी से अमेरिका में भी उत्पादन के स्तर में सुधार होता गया और शास्त्रास्त्रों के तथा युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री के उत्पादन में तेजी से बढ़ि होने लगी और कुछ ही समय में युद्ध सामग्री के उत्पादन वाला क्षेत्र खूब फल फूल गया पर अ-य वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में सामान्यतर विकास बना ही रहा। परंतु हाबर पर जापानी हमले के बाद तो अमेरिका का महा दुग मित्र राष्ट्रों के लिए न केवल 'शास्त्रागार' बन गया बल्कि, प्रायः हर प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने का बड़ा उत्पादक क्षेत्र हो गया। अमेरिका में मिलकर ब्रिटेन, व सोवियत संघ की सम्मिलित शक्ति और उत्पादन क्षमता घुरी राष्ट्रों की सम्मिलित सैनिक, औद्योगिक व तकनीकी शक्ति से आगे निकल गई। पर मित्र राष्ट्रों की जीत तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाई जब तक कि मित्र राष्ट्रों ने एकजुट होकर घुरी राष्ट्रों की सामना करने की नहीं ठान ली।

दूसरा नया विकास साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का जबरदस्त उभार

पहले महायुद्ध के दौरान साम्राज्यवादी सत्ताधारी सभी जगह अपने गुलामों को लेकर इन चिंतित न थे कि उन्हें कोई बड़ी बगावत का डर घटाये। छिटपुट विद्रोह की बिगारिया इधर उधर उठ रही थी। पर जगल की आग भी बन सकती है ऐसा कोई डर नहीं था। गुलाम रणरुटा की मजे में भर्ती हो रही थी, साम्राज्यवादियों को डर था तो यह कि कहीं ये लोग हथियार चलाना सीखने के

बाद लौटकर गड़बड़ी न करें। इसमें इन्हे नीचे ही नीचे ओहदा तक ही बढ़ने दिया गया। न केवल साधारण रगरूट बल्कि जाने माने 'नेतागण' भी साम्राज्यवादी सत्ता से झगड़ने के मूढ़ में न थे। 'केसरहिन्द' तमगे के विजेता मोहनदास करमचन्द गांधी रगरूटों की भरती के विरोध न कर, मन्द ही बर रहे थे। गरमदली लोकमाय तिलक तक कुछ दार्तों पर खुले आम अंग्रेजों की मदद के लिए तैयार थे।⁶ कहने का तात्पर्य यह था कि जैसे अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में तथा साम्राज्य के अन्य भागों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी वैसे ही फ्रांसिसी जर्मन, आदि को भी अपने अपने गुलामों की बफादारी का खूब भरोसा था।⁷ उपनिवेशों के सुधारवादी और अधिकतर क्रांतिकारी माने जाने वाले नेतागण भी साम्राज्यी प्रभुओं का साथ देकर, युद्ध के बाद कुछ सुधार के तौर पर कुछ पा जान की आशा रखते थे।

यह सब युद्ध के बाद एक भ्रम' मात्र सिद्ध हुआ। पहले महायुद्ध से दूसरे महायुद्ध के अंतराल में साम्राज्यवाद विरोधी जादालना का ताता लग गया। चारों तरफ एक के बाद दूसरे पराधीन देशों में विद्रोह की चिंगारिया फल गईं और जन आक्रोश आग का गोला बनकर बरसने लगा। राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का दावा नल तेजी से एशिया व अफ्रीका के पराधीन देशों में फैल गया जिसकी आच में साम्राज्यवादी सत्ताधारी झुलसने लगे।

अमेरिकियों के व्यवहार से क्षुब्ध हाकर नेहरू ने अगस्त सन 1942 में निम्नांकित उद्गार व्यक्त किये—

‘उहाने (अमेरिकिया) ने अच्छी मोटर कारें बनायी है और बना रहे हैं। अमेरिका ने चीन और भारत के भव्य उपलब्धियों को मुसा दिया है ये चीन और भारत हैं जिन्होंने युग के अनुभव के आधार पर केवल मौलिक उपलब्धियों के आधार के बिना भी अच्छी तरह जीवन जीने की कला सीखी है।

‘यदि मैं आदरपूर्वक अमेरिकिया के महान लोगों का मुखा सकू तो मैं कहूंगा कि वे भारत, चीन और पूरे एशिया के ही बारे में गलत ढग स सोधत हैं। आप हिन्दुस्तान को ब्रिटेन के पिछलग्गू की तरह लेत हैं और एशिया को यूरोप व अमेरिका का आश्रित मान बठे हैं—जिसमें जातीय वरिष्ठता का भाव रहता है। आप लोग ने मशीनी युग के अविष्कारों की वजह से अपन आपका हमसे अधिक अच्छी हालत में मान लिया है और हमें यह मानत हैं कि हम अधकार प्रस्त पिछड़े हुए लोग हैं लेकिन एशिया के लोग अब इस तरह के वर्ताव को स्वीकार करन नहीं आ रहे हैं।

(नेहरू ने कहा) कि पश्चिम के नेता युद्ध को एक बहुत ही सकुचित सैनिक दष्टि से देखत हैं और वे यह समय पान में बिपन्न रहे हैं कि युद्ध उस महान क्रान्ति का अग्रदूत सिद्ध होगा जो पूरी दुनिया पर छा जायेगी। उहाने मानवता के अत स्तल से नि सृत सहज भावा की प्रचंड बाढ को अनदखा करना चाहा है।⁸

महान अक्टूबर क्रांति की प्रेरणा

प्रथम महायुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने रूस की जारशाही को उखाड़ फेंका और दुनिया के इतिहास में पहली समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कर मजदूर और किसानों का अभूतपूर्व राज्य सत्ता स्थापित की। लेनिन और स्टालिन दोनों के हस्ताक्षर से मुक्त रूस की जनता के अधिकारों की घोषणा ने रूसी लोगों की समानता और प्रभुसत्ता की घोषणा ने तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के स्वतंत्र विकास के अधिकार के उद्घाप ने पूरे पूरब में, एशिया की संघघरत पराधीन देशों के जन समुदायों के उदास मन में प्रकाश की एक जगह दस्त बाढ़ सी ला दी। उनकी धमनियां में बिजली की तेजी सरगत का संचार हो चला। अगले दशकों में “राष्ट्रों से आत्मनिर्णय के अधिकार” के गौरवशाली सोवियत सिद्धान्त और उतने ही वेदांग व्यवहार ने एशिया की जाग्रति में महान योगदान किया। जन्मते ही सोवियत सत्ता महान लेनिन के नेतृत्व में भारत, चीन हिंदोशिया, हिंद चीन की राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष की एक प्रबल हिमायती और सहारा बन गयी। यह कोई कोरी नारवाजी न थी क्योंकि लेनिन की मार्क्सवादी व्यवस्था का निचोड़ इसमें था कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद की अंतिम अवस्था है जिसमें इन पराधीन देशों के बुजुर्गों राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध को संगठित करने, उनके हाथों साम्राज्यवादियों को परास्त करने के अभियान में मार्क्सवादी क्रांति कारियों व उनके अग्रिम दस्ते बोल्शेविकों, की बेहिचक और जोरदार मदद करना उनका फज है। क्रांतिकारी सोवियत सत्ता की उपस्थिति मात्र ही सभी एशियाई देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की प्रेरणा बनी।⁹

अक्टूबर क्रांति की अजस्र प्रेरणा से, एशिया में जगह जगह साम्यवादी दल संगठित हुए यथा चीन में भारत में, इंडोनेशिया में हिंद चीन आदि में। जगह जगह राष्ट्रीय आंदोलनों से क्रांतिकारी सोवियत सत्ता और साम्यवादी अन्तर-राष्ट्रीय संगठन से सम्पर्क सूत्र जुड़े और उसने साम्राज्यवादियों की जान के लिए एक नई और बड़ी आफत पदा कर दी।¹⁰ अक्टूबर क्रांति ने साम्राज्य विरोधी संघर्ष को एक संघर्ष सही और नई दिशा देकर एक संघर्ष नये सुनहरे युग के बद कपाट खोल दिये। इसके बाद साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलनों का एक नया और निसमर्थक दौर चल पड़ा।

इन प्रकार इन महायुद्धों के बीच के काल में चीन में, भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में एशियाई जन समूह अपनी नियति को अपने हाथों में लेने के लिए उठ खड़े हुए। व अब अपने इतिहास के खुद रचयिता बनने का सारल्य धारण करने लगे। साम्राज्यवादी शक्तियां यथा भारत में ब्रिटेन, सुधारों के रास्ते उनकी उपद्रता को ठण्डा करने की दुरभिसंधि रचकर, उनमें फूट डलवाकर

अहिंसक आंदोलन को भी हिंसा पूर्वक कुचलकर, दिशाहीन बनाने की खूब चेष्टा करती रही। वैसे महामंदी का सकट शुरू हो रहा था पर भारत मंत्री लाड वरकेनहेड अपना यह ख्याल लाड सभा में प्रकट कर रहे थे।

“इस सभा में ऐसा कौन है जो यह कह सकता है कि वह एक पीढ़ी में, दो पीढ़ियों में, सो वर्षों में भी ऐसी सम्भावना के बारे में सोच सकता है जब कि भारत के लोग सेना, नौ सेना लोक भवा, पर खुद नियंत्रण कर सकेंगे, और एक ऐसा गवर्नर जनरल ला सकेंगे जो भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हो, न कि इस देश (ब्रिटेन) की किसी सत्ता के प्रति।”¹²

साम्राज्यवादी तब भी ऐसा साच रहे थे (जबकि आंदोलन के बाद सन 1935 के सुधारों के अंतर्गत सन् 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने ग्यारह में आठ प्रांता में भारी बहुमत प्राप्त किया था) कि कांग्रेस केवल एक ‘अल्पमत’ का ही प्रतिनिधित्व करती थी जब सन् 1939 में भारत की ओर से ऐसा फैसला क्या और किस अधिकार से कर लिया और सत्तापञ्चक जवाब के न आने पर तुरंत कांग्रेसी लोकप्रिय मंत्री मण्डली ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस असहयोग के रास्ते पर चलने लगी वे तब भी ऐसा ही सोचते थे। कांग्रेस ने फासीवाद व नात्सीवादी सत्ताओं की भत्सना की, और नाजी आक्रमण का सामना करने में ब्रिटेन का पक्ष लेने का भरोसा दिलाया बशर्ते कि भारत एक मित्र की तरह एक समान भागीदार की तरह आमंत्रित हो, न कि एक उपनिवेश की तरह। सहयोग बराबर वालों के बीच आपसी सहमति से एक ऐसे आदस के लिए होता है जिसके प्रति दोनों ही समर्पण का भाव रखें। लेकिन, कांग्रेस ने अपनी घोषणा में स्पष्ट किया कि यदि युद्ध साम्राज्य के विशेषाधिकारों की यथा स्थिति की बचाये रखने के लिए हैं तो भारत का उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यदि प्रश्न लोकतंत्र का है और एक ऐसी सत्तार व्यापी व्यवस्था का जो लोकतंत्र पर आधारित हो, तो भारत की उसमें गहरी दिलचस्पी है।

आजादी का विगुल बजने लगा। ‘कैसे रहे हिंद’ तमगे वाला महात्मा गांधी अब अंग्रेजों के लिए रगरूट भरती करने में मदद करने को तैयार न था। अब तो स्वतंत्र भारत के लिए ही रगरूटों की भरती हो सकती थी। कसमकस बढ़ती गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ब्रिटेन पर जोर डाला कि—‘गुप्तो सुलभे’—क्रिप्स साहब आए। बातें हुई। पर लाड वरकेनहेड के सपनों का भारत गायब हो चुका था। कांग्रेस ने खुली उगावत छेड़ दी “अंग्रेजों भारत छोड़ो” आंदोलन सारे देश में फैल गया। अहिंसक स्थिति बनी रह गई। तोड़ फोड़ भी हुई पर कांग्रेस ने नेतृत्व ने “भारत छोड़ो” मार्ग को सशस्त्र संघर्ष का सहारा न देकर जेल यात्रा को हज या बंदीनाथ केदारनाथ आदि की सी तीर्थ यात्रा बनाकर भविष्य में आजादी ‘पुण्य’ लाभ करने की व्यवस्था कर ली। पर सभी ऐसे पुण्यनाथ के

को भी तैयार न थे कांग्रेसी समाजवादी दल के लोग ने कुछ तोड़ फोड़ की काम वाही संगठित की। उससे अधिक—बारमार ढग ने, और बहुत पहले से सुभाष बोस ने पहले गांधी की नीतियाँ और कायगैली असहमत होकर फारवर्ड ब्लॉक बनाकर संध छेड़ा और फिर अंग्रेजी निगरानी संध निबल कर देश के बाहर सशस्त्र क्रांति की लो को एक बार पुनः सुलगाया और स्वाधीन भारत ब होने के पहले ही “भारतीय राष्ट्रीय सना” गठित कर घुरी शक्तियों से मिल जुलकर, भारत को ब्रितानी साम्राज्य स मुक्त करन की एक असफल पर बड़ी रोमांचक और स्मरणीय चेष्टा की।

बाहर छिड़ रहे मित्र राष्ट्रा और घुरी राष्ट्रा के बीच घनघोर महासमर ने भारत के साम्यवादी दल का कुछ और ढग स प्रभावित किया। सोवियत संध के इस महासमर म शामिल होने के पूर्व तक तो सुभाष बास क फारवर्ड ब्लॉक व साम्यवादी दल, कांग्रेसी अहिंसक ‘व्यक्तिगत सत्याग्रह’ को उभारने और गमनि की कोशिश म निरंतर लगे रहे व इस संध मे जेल जाने म जुटे। पर सोवियत संध पर नात्सी जमनी का हमला होते ही साम्यवादी दल अपनी रीति-नीति की लेनिनवादी ढग स व्यवस्थित नहीं कर पाया। सोवियत संध के सकट म भारत की जनता की ओर स यह भी क्या किसी मतलब का साथक योगदान रहा कि साम्राज्य विरोधी आंदोलन को धीमा कर दिया जाएगा। लोक युद्ध ‘के नार के नीचे दबा दिया जाये। भारतीय पूँजीपतियों की रहनुमा पार्टी तो अपने बग के अनुसार ऐसा मायावी युद्ध लड़ रही थी कि नात्सी विरोधी अंग्रेज के साथ भी थी और जाजादी के नाम पर न होने का भी उपक्रम रचती रही थी। कांग्रेसी साम्यवादिया स अधिक चालाक निकले। जनता की साम्राज्य विरोधी चेतना को उभारने म तो आगे-आगे रहे पर जब जबरदस्त विस्फोट होने लगा तो वही भी सशस्त्र संध को गठित नहीं किया। शालीनता से अंग्रेजा की जेल भर दी और वहा जनता के संधों से दूर होकर युद्ध का मुजरा लेने नगें और युद्ध के उतार चढ़ाव पर अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने अपन जेल म पाले गए शोक का जायका लेते रह। जेल मे रहकर कोई उन पर यह इलजाम भला कैसे लगा पता कि वे अंग्रेजो के साथ हैं यद्यपि वे युद्ध के कमर तोड़ बोझ म दबती कुचलती शोषण के दमघोटू वातावरण म जीवन मरण संध मे जूझनी, भारतीय जनता के कष्टों को जेल मे रहकर कुल मिलाकर वे मूक दशक मात्र ही साम्राज्य विरोधी प्रतिरोध संगठित करते। वे कान म तेल डालकर मानो यो सो गये कि महायुद्ध जसे ही निपटेगा, तब आगे देख लेंगे।

इस ऐतिहासिक चातुर्य ने बाद म मौका दिया कि जेल से निकलकर वे जेल की सजा भोगे स्वतंत्रता के योद्धाओं के अनुरूप दूसरे जेल से बाहर “लोक युद्ध” के मंच से महायुद्ध के आशीर्वाद बने कम्युनिस्टों के देश प्रेम व निष्ठा पर जमकर

प्रहार करें। जिस एक अप्रतिहत साहस और विशुद्ध साम्राज्य विरोधी व देश भक्त नेतृत्व में हर सूरत में देश की सशस्त्र 'क्रांति' के द्वारा मुक्त करने का बीड़ा उठाया, उस मुझाव व उनके साथियों को इस बात के लिए बरसा नहीं, कि वे महायुद्ध में सही पक्ष को चुनने में गलती कर गए। अंग्रेजों के प्रति गहरी साम्राज्यविरोधी घृणा और प्रचण्ड सात्त्विक आक्रोश ने उन्हें बौटिल्य के इस साधारण सूत्र पर चलवा दिया कि शत्रु का शत्रु नैसर्गिक मित्र होता है। सुभाष बोस ने राजनीति विशारद माओ त्से तुंग के और न ही चिह्न मिला, इस कमी ने उनके अभियान को विफल तो कर दिया था किंतु उन्होंने भारत की कोटि कोटि जनता के मन में अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो और कोई न छोड़ पाया। पर इससे उनके नेतृत्व में चलाए गए देशभक्ति पूर्ण सशस्त्र युद्ध का महत्व तो कम नहीं होता। वह भारतीय जनता की सघष गाथा का वह एक छोटा ही सही पर बड़ा ही प्रखर व शीघ्र पूर्ण जीवित प्रेरणादायी अध्याय था जिसकी गूज महायुद्ध समाप्त होने के वर्षों बाद तक गूजती रही और अनेक अनेक साधारण स्त्री पुरुष यह मानने से अब तक इन्कार करते हैं कि उनके राष्ट्रीय सघष का सबश्रेष्ठ थोड़ा इस प्रकार काल-कलवित हो गया। अमर राष्ट्रीय चेतना व अजैम जन शक्ति के सबसे जीवित प्रतीक बन गए उसी तरह जैसे चीन के माओत्से तुंग बने और हिंद चीन में हो चिह्नमिला जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति के साम्राज्य विरोधी सघष को समाजवादी आंदोलन से जट्टूट रिश्ते में जोड़कर सामाजिक, क्रांति को गहराई दे दी। वह भारतीय साम्यवादी नेतृत्व की समझ वृष्ण के बलवृत्ते की बात नहीं रही। सोवियत क्रांति की रक्षा पक्षित इससे मजबूत न हुई वह हुई चीन व हिंद चीन तथा ऐसी अन्य साम्यवादी दलों के आंदोलन से जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति की धारा को जनवादी समाजवादी क्रांति के धारा से पूरी तरह मिला जुला दिया।

सोवियत क्रांति का अप्रतिम युग प्रवर्तक महासमर

तीसरी और बहुत मूल्यवान बात जो दो महायुद्धों के बीच का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विकास माना जाना चाहिये वह था नास्ती फासी 'गकिनया' के विरुद्ध एक महान व अतुलनीय सघष की सोवियत गाथा। सोवियत सघ रूसी जारगाही का कोई नया संस्करण मात्र न था। एक महान युग प्रवर्तक क्रांति का शुभारंभ अग्रिम दस्ते की विजय यात्रा का श्रीगणेश था। वह रूसी साम्राज्य में बसने वाली सघष-शील जनता का केवल ऊपरी कायावपल ही न था बल्कि, जनजीवन में एक आमूल-चूल रूपांतरण की अविरल प्रक्रिया का समारंभ था। लेनिन व उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में यह सोवियत सत्ता तेजी से पहले तो समाजवादी राज्य की राजनीतिक नींव मजबूत करती गई। फिर औद्योगीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समुचित सामाजिक क्रांति के सदम में ठीक-ठाक स्थित कर नव निर्माण

का कार्य शुरू किया गया जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में उत्पादन का स्तर तेजी से बढ़ने लगा जो निम्नांकित आकड़ा से पता चलेगा। शुरू से ही सोवियत शक्ति के संस्थापकों का यह सवरूप रहा कि वे सोवियत संघ को मिली औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन को विरासत में उत्पादन व्यवस्था की नींव डालेंगे जिस पर तेजी से एक समृद्धिशाली, एक महान् औद्योगिक राज्य की रचना हो सके और जो आधुनिकतम तकनीक एवं विज्ञान की उपलब्धियों का अधिकारी बन सके। केवल उद्योग व तकनीक ही नहीं, सोवियत सत्ताधारी सोवियत कृषि का भी पूरी तरह पुनर्गठन करने पर जुट गए। उत्पादन के सभी साधनों को समूचे समाज की मिलिक्रियत बनाकर, उन्होंने उत्पादन के सबधों को सबध नये, एवं प्रातिकारो साचे में ढाल दिया और एक योजनाबद्ध विकास क पथ पर सा खड़ा किया जिसका फल एक दशक में ही देखने लायक हो गया।

उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में सोवियत उत्पादन

	1913	1929	1939
इस्पात (लाख टन में)	42	49	69
रोल्ल इस्पात	35	39	51
कायला	291	401	763
तेल	92	138	225
लोहा	12	80	144
रेल इंजिन	418	602	941
सामान लादने के ट्रक	14 8	15 9	182
मोटर कार	—	1 4	49 7
बिजली	19	62	164
पिग लोह	42	40	71
ताबा	—	35 5	44 5
अल्मूनियम	—	—	7
सीमेण्ट	15	22	27
सूती वस्त्र (लाख मीटर)	22270	30680	24220
ऊनी वस्त्र	950	1006	861
जूते (लाख जोड़ी)	—	488	803
कच्ची शक्कर (हजार टन)	1290	1283	995
धातु और इंजीनियरी	1466	3054	10822
उद्योग (रुबल के हिसाब)			

दृष्टव्य है कि जिन दिनों महामदी की चपेट में सारे पूँजीवादी देशों में उत्पादन तेजी से घटा, सोवियत संघ में उत्पादन घटा नहीं, बढ़ता ही गया जिसमें पूँजीवादी सरकार से अपनी अलग एक आकषक सत्ता की मजबूत नींव डाल पाने में सफलता की घोषणा अपने आप ही हो गई। सोवियत संघ एक ऐसा अवलोकन बन गया जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था के नियम कानून लागू नहीं होते थे। शांतिकाल में भारी उत्पादन करना, बेरोजगारी का नामोनिशान मिटा देना तथा इसके साथ साथ अनिवार्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करते हुए सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण की एक पड़ोसियों के साथ अच्छे पड़ोसी के संबंध बनाने वाली पर राष्ट्रीयता को अभिन्न रूप से जोड़ देना एक कमाल की बात थी जो सभी को अत्यंत आश्चर्य में डाल रही थी। कहा अमेरिका को मिलाकर सभी पश्चिमी पूँजीवादी देशों का, गिरता उत्पादन व गहराता हुआ आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक संकट और कहा सोवियत संघ में उत्पादन की शक्त का निरंतर एवं तीव्र गति से हो रहा विकास—वह 'भी' अर्थव्यवस्था को मुद्धो मुल्ली एवं पराश्रित बनाये बगैर। इसका नतीजा सामने था कि जर्मनी के पूर्व का एक नगण्य औद्योगिक शक्ति के रूप में जाना पहिचाना जा रहा ही रूस का पूरी तरह कायाकल्प होकर सोवियत शक्ति के रूप में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उद्योग प्रधान देश बन जाना।

विश्व उत्पादन में प्रमुख शक्तियों का योगदान

देश	1928
अमेरिका	44.8
जर्मनी	11.6
ब्रिटेन	9.3
सोवियत संघ	4.7

और महामदी की चोट लगते ही सन् 1932 में इन औद्योगिक 'बड़ा' की स्थिति में निम्नांकित स्तर पर बदलाव आ गया।

देश	1932 के मध्य में
अमेरिका	34.4
सोवियत संघ	15.1
ब्रिटेन	11.3
जर्मनी	8.3

इस प्रकार जबकि जा रहा ही के जमाने में विश्व औद्योगिक उत्पादन में रूसी साम्राज्य का योगदान केवल 4 प्रतिशत रहा, सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत वह

बढ़कर करीब 12 प्रतिशत हो गया और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था वाली दुनिया दूसरे महासमर के छिड़ने तक मुश्किल से सन् 1929 के स्तर का छू पा रही थी, सोवियत अर्थव्यवस्था सन् 1919 के आधार पर से कहीं आगे निकल गई थी।

स्टालिन के नेतृत्व में इस प्रकार सोवियत संघ में न केवल शांति की आर्थिक नींव गहरी की जा रही थी, बल्कि, परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व साहस और दूरदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए समुचित वातावरण निर्मित करने के लिए पहल बढ़ाई की जा रही थी। सोवियत संघ की ओर से पूर्ण निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव रखे गये। पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समानता और अहस्तक्षेप की नीति अपनाकर जारशाही साम्राज्यवादी नीति को पूर्णतः तिलाजलि दी गई, पर पश्चिम की साम्राज्यवादों ताकतों ने इस सोवियत संघ की कमजोर स्थिति का प्रमाण माना और पहले वहिष्कार और घेराव, फिर इसे ढीला कर असहयोग और उपेक्षा की नीति अपनाई। यूरोप में नात्सी ताकतों का खतरा बढ़ने पर फिर सोवियत संघ के साथ आंशिक सहयोग की नीति तो अपना ली, पर ब्रिटेन व फ्रांस दोनों में ही सत्ताधारी वर्ग ऐसा व्यवहार करने लगे जिससे नात्सी व फ्रांसीसी शक्तियाँ को बढ़ावा मिलने लगा और वर्साई की व्यवस्था खड़-खड़ होती गई। सोवियत नेतृत्व में अनेक बार समय रहते नात्सी फ्रांसीसी गठ-बंधन को निःप्रभ और निस्तब्ध करने के लिए समुक्त मोर्चा बनाने की पेशकश की पर कोई नतीजा नहीं निकला म्यूनिख के पूर्व और उसके दौरान अपने पूर्व के मित्रों के रक्षा फ्रांस को उचित कायवाही करने में पर्याप्त मदद देने का खुला निमंत्रण देने पर भी सोवियत संघ के नेतृत्व ने यह पाया कि ब्रिटेन और फ्रांस नात्सी फ्रांसीसी ताकतों को बाधने में दिलचस्पी लेने के बजाय उन्हें पूर्व की ओर बढ़ने को उकसाने में लग गए हैं। सोवियत की ऐसा ही अनुभव म्यूनिख समझौते के बाद हुआ जबकि ब्रिटानी सरकार ने सोवियत संघ से बातचीत चलाई भी तो उस ऊँचे व महत्वपूर्ण मोर्चे पर से जाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस घेरुखी ने सोवियत नेताओं को बाध्यता कर दिया कि वे अपने स्वाभाविक शत्रु नात्सी जर्मनी से अवश्यभावी दिखने वाली लड़ाई के लिए कमर बंधने की कोशिश में जितना भी समय खरीद सके, खरीद लें। सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि विरुद्ध होकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए उठाया गया 'समय खरीदने वाला ऐसा ही एक कदम था।' इन अल्प वर्षों में भी सोवियत नेताओं ने अपनी रक्षा पंक्ति को सुदृढ़ करने, अपने अग्रतंत्र को और पुष्ट करने तथा उस एगिप्टाई प्रदेश में विकसित करने, तथा राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र को प्राप्ति पारी रूप में सुसंस्थापित करने में श्रम दिया ताकि, आसन्न संकट का अकेले ही रूटकर मुकाबला किया जा सके। स्वाभाविक है कि अक्टूबर प्राप्ति के बाद अपने

अथतः को दिन दिन मजबूत करके, उसकी उत्पादन क्षमता को अमृतपूर्व ढंग से उच्च स्तर पर ले जाने के बावजूद बाहर की आक्रमण परिस्थितियों ने सोवियत रचनाकारों को ऐसा मौका नहीं दिया कि वे समाजवादी नींव पर खड़ी हो रही व्यवस्था के जरिए जनसाधारण के जीवन स्तर को उतनी ही तेजी से ऊंचा उठाते चले जाएं। सोवियत उत्पादन व्यवस्था अधिकांश रक्षा की इस्पाती नींव के निर्माण में खपने लगा। सोवियत जनता ने अपने पसीने और खून की एक एक बूंद से जिस ढंग से सोवित समाजवादी व्यवस्था की नींव डाली, तथा निर्माण किया और उसकी रक्षा में महान उत्साह का ऐतिहासिक दृष्टांत रखा वह हमारी इस सदी में "न भूतो, न भविष्यति।"

जब हिटलर ने अतंतु सोवियत सघ से लोहा लेने की ठानी और आक्रमण कर दिया, तब सोवियत सघ ने लड़ाई में अपने आप को अकेला नहीं पाया। चर्चिल के ब्रिटेन ने बिना मागे और बिना शर्त सोवियत सघ के प्रति अपना खुला समर्थन व्यक्त किया। अलग धलग पड़ा, नात्सी आक्रमण को झेलते हुए ब्रिटेन का, सोवियत सघ की युद्ध में अपना भागीदार पाकर उत्साह बढ़ा। यह एक अच्छी शुरुआत थी क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका से कुछ सहायता और समर्थन पा रहा था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि पल हार्बर ने दिसम्बर 7, 1941 के जापानी हमले में अमेरिका को भी युद्ध में घसीट लिया और इस प्रकार "मित्र राष्ट्र" के बीच, समान शत्रुओं के विरुद्ध समानधर्मी गठबंधन को जन्म मिला जो दूसरे महासागर की "धुरी शक्तियाँ" के गठबंधन का उतना ही जोरदार जवाब बनकर उभरा। यो भी भौतिक धरातल पर मित्र राष्ट्रों का गठबंधन धुरी राष्ट्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन गया था क्योंकि तीन बड़ों की युद्धोन्मुखी अथ व्यवस्था की उत्पादन क्षमता धुरी राष्ट्रों की सम्मिलित क्षमता से बढ़कर थी, उनके साधन स्रोत हथियारों का उत्पादन और वितरण, सैन्य शक्ति सभी प्रकार की, जल, धल नभ की धुरी राष्ट्रों की तुलना में, मात्रा के हिसाब से अधिक थी। लड़ने वाले सैनिक और उनकी सहायता में जुटे— औद्योगिक तकनीकी कौशल युक्त असैनिक कृषि और व्यापार में लगे असैनिक अधिक थे। बस लड़ने का हौसला, मरने मारने के लिए उद्यत सैनिक जोश खरोश, एक युद्धानुकूल हवा को भयकर तूफान में परिणित होने की कसर थी जो धुरी शक्तियों से टकरा टकरा कर खौफनाक बनती गई।

आणविक युद्ध किस लिए लड़ रहे हैं

मित्र राष्ट्रों में अग्रज सबसे प्रथम, पर अमेरिकी सबसे बाद युद्ध में शामिल हुए। इन दोनों काल बिंदुओं के बीच सोवियत सघ की तब विवश होकर युद्ध करना पड़ा जब हिटलर ने जून 1941 में उन पर अचानक आक्रमण कर लिया।

इस प्रकार अमेरिका को ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, इन तीनों के मुकाबल अधिक समय और अवसर मिला कि वे युद्ध के लिए तैयार हो सकें। स्मरणीय यह भी है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही पोलैण्ड पर जमन हमले के तुरंत बाद युद्ध में कूद पड़े पर युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा उस तरफ से भी थी। इसी को लक्ष्य कर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जोरदार मांग उठायी थी कि भारत का हार्दिक सहयोग चाहता है तो ब्रिटेन अपने युद्ध के लक्ष्यों को स्पष्टतः घोषित करे। आखिर किस लिए लड़ रहे हैं।

तत्काल, न केवल साम्राज्यवादी ब्रिटेन व फ्रांस, बल्कि अमेरिका में भी युद्ध के लक्ष्यों के बारे में कोई निश्चित घोषणा नहीं की। तब वे इसकी शायद जहरत ही महसूस नहीं कर रहे थे। पर यूरोप में युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका में एतद विषयक राष्ट्रीय चर्चा छिटपुट ढंग से छिड़ गई। बहस छिड़ने के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जनवरी 6, 1941 को घोषणा की कि अमेरिका धुरी राष्ट्रों के विरोध में लड़ रहे उन राष्ट्रों की सहायता देगा जिनका युद्ध लक्ष्य चार स्वतंत्रताएँ स्थापित करना हो अर्थात्, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा उपासना की स्वतंत्रता, अभाव से मुक्ति अर्थात् युद्ध के लक्ष्यों की घोषणा के नाम पर एक अमृत लक्ष्यों की ओर इंगित करना मात्र था। पर यो सिलसिले के तौर पर शुरू तो हुआ।

सोवियत संघ की पहल

इस दिशा में सोवियत संघ ने पहल की और स्पष्ट तौर पर युद्ध के लक्ष्यों की घोषणा की। आक्रमण होने के एक हफ्ते के बाद सोवियत संघ के कम्युनिस्ट दल की केन्द्रीय समिति ने सोगा को आह्वान किया कि वे तन मन धन से शत्रु को नष्ट करने में जुट जायें।

केन्द्रीय समिति ने जर्मनी और उनके सहयोगियों के विरुद्ध की फासी विरोधी युद्ध की सज्ञा दी और इसे मुक्ति का संघर्ष कहा। इसने यह घोषणा की कि युद्ध सभी यूरोपीय राष्ट्रों के भाग्य का निपटारा करेगा और सोवियत की जनता को वेस अपने देश की रक्षा के लिए आगे आये बलि, फासीवाद के जुएँ स सभी पराधीन राष्ट्रों को मुक्ति दिलाए। केन्द्रीय समिति और सोवियत सरकार ने इस बान पर जोर दिया कि यूरोप के मुक्त हुए सोगा को बिना किसी बाहरी दबाव के अपने-अपने देशों की सामाजिक एवम् राजनीतिक ढाँचे के बारे में खुद नियंत्रण करने का अधिकार मिलेगा। स्टालिन ने इस वायव्य की मुख्य बातों की घोषणा जुलाई 3, 1941 को अपने रेडियो प्रसारण में की।¹²

सोवियत संघ की इस एतिहासिक घोषणा का यूरोप व अमेरिका में जगह जगह स्वागत हुआ। एक भाग की विरुद्ध युद्ध के घटाटोप वादना के बीच में मिस

उठी। इस घोषणा का यह असर हुआ कि ब्रिटेन व अमेरिका ने भी अपनी अपनी ओर से युद्ध के लक्ष्य की घोषणा करने में तत्परता दिखाई। जगस्त 14 1941 को हस्ताक्षरित अतलांतिक घोषणा पत्र इस ओर उठाया गया पहला कदम था।

संदर्भ

- 1 देखिये लेखक की कृति "अंतर्राष्ट्रीय सन्ध", प्रथम खण्ड, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 1980।
- 2 देखिये लेखक द्वारा रचित अंतर्राष्ट्रीय सन्ध—1919-19 प्रथम खण्ड
- 3 वही
- 4 वही,
- 5 देखिये लेखक की कृति, 'अंतर्राष्ट्रीय सन्ध' (प्रथम खण्ड)
- 6 भारत में ही गांधीजी और तिलक अपनी शर्तों पर रक्खटों को भरती कराने में योग देने के लिए तैयार थे।
- 7 यही स्थिति अत्यन्त थी।
- 8 दि हिन्दू 9 अगस्त, 1942।
- 9 एशिया ऐण्ड वस्टन डामिनेस के० एम० पण्णीकर प० 251।
- 10 सन् 1927 का ससेल्स में हुआ यह सम्मेलन ऐतिहासिक बन गया जहाँ साम्राज्यवाद विरोधी लीग के नेतृत्व में एशिया, अफ्रीका व यूरोप के करीब 175 लोग शामिल हुए जिसमें जवाहरलाल नेहरू, हो चिंह मिह, रोम्या रोला, अलबर्ट आइस्टीन आदि प्रमुख थे।
- 11 देखिए लॉड सभा में हुए बहसों।
- 12 सितम्बर 2, 1940, ब्रिटेन के साथ अमेरिका ने पहला युद्धकालीन समझौता 50 पुराने विध्वंसक इस क्षत पर दिए कि ब्रिटेन यू फाउंड लेण्ड और ब्रितानी गायना के बीच के आठ ब्रितानी अड्डे, 99 साल के पट्टे पर अमेरिका का दगा। अप्रैल में अमेरिकी फौजें ग्रीन लेण्ड में भेजी गईं और सोवियत संघ पर हमला होने के बाद अमेरिका में आइसलेण्ड में अपनी फौजें भेजी। घोर घोर अमेरिका ब्रिटेन व सोवियत के पक्ष की ओर मुड़ रहा था। आगे बढ़कर रूजवेल्ट की सरकार ने जून 24, 1941 को उधार पट्टे की मदद सोवियत संघ को भी देने का वायदा किया और नवम्बर 7, 1941 को औपचारिक तौर पर ऐसी मदद की स्वीकृति दे दी जो वष की समाप्ति तक 5 लाख पैतालीस डालर तक पहुँच गई। इस प्रकार सितम्बर 1939

०।२ सन्धर 1941 के बीच अमेरिका तटस्थता की नीति से आगे बढ़ते बढ़ते ब्रिटेन व सोवियत के साथ मंत्री गठबंधन में वधता चला गया यद्यपि हथियारों की मदद मिलनी अभी बाकी थी।

जून 1941 में हिटलर ने सोवियत पर आक्रमण किया था, कुछ समय के बाद दिसम्बर 7 को पल हाबर के हमले ने अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया वह अब मित्र राष्ट्रों के गठबंधन में अग्रणी पक्ष में खड़ा था।

- 13 देखिए एन० सिवाचयोग व ई—याजकोव, कृत हिस्ट्री ऑव यू० एस० ए० सि स वर्ल्ड वार फस्ट, प० 162।

युद्ध कालीन घोषणाएँ, वार्ताएँ एवं सम्मेलन

हमने पिछले अध्याय में उम्र सदम को स्पष्ट करने की चेष्टा की है जिसमें महासमर छिड़ा और मित्र राष्ट्रों के बीच सहयोग और साहचर्य के पुलों की स्थापना हुई। युद्ध छिड़ गया था पर ब्रिटेन और फ्रांस की ओर युद्ध के उद्देश्यों की कोई प्रेरणाप्रद घोषणा नहीं हुई थी। इस दृष्टि से सोवियत नेनाआ ने पहल की और एक बार सोवियत संघ की ओर से फासी विरोधी युद्ध का ऐलान इस घोषणा के साथ हुआ कि सोवियत सेनाओं का यह लक्ष्य होगा कि वह न केवल अपनी सीमाओं को आजातता से खाली कराएँ और उनकी रक्षा करें बल्कि, आगे बढ़कर पराधीन देशों को नात्सी फासी शक्तियों के चंगुल से मुक्त कराये और आत्म निर्णय के सिद्धांत के अनुसार अपने भाग्य का खुद निपटारा कराने का अवसर प्राप्त करायें। जून सन 1941 में इस ऐलान के बाद ही ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रीय नेताओं ने इस दिशा में अगला कदम उठाया।

एटलांटिक घोषणा पत्र

(अगस्त 14, सन 1941)

अमेरिका अभी भी युद्ध में नहीं कूदा था पर ब्रिटेन को जर्मनी से लड़ते हुए लगभग 2 वर्ष बीत रहे थे और सोवियत संघ युद्ध में शामिल हो चुका था। अमेरिका में अभी भी इस बात को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ था कि अमेरिका तटस्थ रहे या मित्रों की ओर से युद्ध में फासी नात्सी सर्वाधिकारवादियों के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़े। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार धीरे-धीरे मित्र राष्ट्रों के पक्ष में खुलकर आती जा रही थी और जब अगस्त 14, 1941 का राष्ट्रपति सजवेट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल 'यूफाउडलैण्ड' के तट पर मिले तब उन्होंने आपस में बातचीत की ओर कुछ ऐसी सिद्धांतों की घोषणा की जिनके अनुसार अपनी-अपनी राष्ट्रीय नीतियों को कायम रखेंगे। ये निम्नांकित सिद्धांत घोषित किये गए।¹

(1) य दाना देश किसी प्रकार के प्रादेशिक या अन्य प्रकार के विस्तार के

आवासी नहीं हैं।

(2) य दोना राष्ट्र किसी ऐसे प्रादेशिक बटवारे या काट छाट के आवासी नहीं है जो उस प्रदेश की जाति की स्वतंत्र इच्छा के प्रतिकूल हो।

(3) ये सब लोगो के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वे अपनी इच्छा के अनुकूल अपनी अनी शासन व्यवस्था चुनें, साथ ही अमेरिका व ब्रिटेन की इच्छा यह भी है कि जिन लोगो की इस अधिकार से वंचित किया गया है उन्हें यह अधिकार फिर से दिलवाया जाए।

(4) वे दोनों इस बात के लिए प्रयत्नशील होंगे कि चाहे विजेता हो या विजित सभी छोटे बड़े राष्ट्रों को अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार व कच्चे माल प्राप्त करने की सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हों।

(5) ये चाहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में सभी देशों के बीच अधिकाधिक सहयोग बढ़े ताकि श्रमिका की दशा में सुधार हो सके और आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक सुरक्षा को संभव बनाया जा सके।

(6) ये आशा करते हैं कि नात्सी अत्याचारों का अंत होते ही सार देश अपनी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में सुरक्षा पूर्ण रहते हुए भय और दरिद्रता से मुक्त होकर अपनी जीवन बिता सकेंगे।

(7) इन दोनों देशों का विश्वास है कि इस प्रकार की शांति की स्थापना के होते सभी लोगों को महासागरों एवं सागरों पर निर्वाण आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी।

(8) ये यह विश्वास करते हैं कि दुनिया के सभी देश, आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही कारणों के वश होकर बल प्रयोग करना छोड़ेंगे। उनका यह भी विश्वास है कि निशस्त्रीकरण का होना अनिवार्य है। वे चाहेंगे कि उन सभी सम्भव कार्यों को उनका सहारा मिले और प्रेरणा मिले जो शांति प्रिय लोगों को शस्त्रों के कमर तान बोल को हटाने की दिशा में किए जाएं।

उपर्युक्त आठ सिद्धांतों से युक्त इस सम्मिलित रूप से की गई घोषणा में इन दोनों साम्राज्यवादी मित्रों के बीच सम्बन्धों की कमजोरी और ताकत दोनों की झलक मिलती है। अमेरिकी साम्राज्यवाद उठान पर था जबकि ब्रिटेन का सकट गस्त, एक का सकट दूसरे के लिए अवसर द्वार खोल रहा था। इसी दृष्टि से दृष्टव्य है चौथा और सातवा सिद्धांत। अमेरिका अब किसी भी ऐसे क्षेत्र को जो ब्रिटेन के अधीन हो अपने लिए 'प्रतिबंधित' मानने को तैयार न था। निर्वाण आवागमन की सुविधा उसे चाहिए थी जिसे ब्रिटेन अब नहीं रोक पा रहा था, न अमेरिका अब नौ सेना के विस्तार में किसी प्रकार की ब्रितानी रोकथाम या विक्रम की ब्रिटेन द्वारा खींची सीमा रोक मानने को तैयार था—कुछ समय से सागरों पर बचस्व के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा में ब्रिटेन का पिछड़ना शुरू हो चला

था। सबसे स्मरणीय बात यह थी कि वे “स्वतंत्रताएँ अपनी सरकार या शासन व्यवस्था खुद निश्चित करने का अधिकार आदि।” यह यूरोप के उन देशों के सदस्य में कहा जा रहा था जो नात्सी फासी ताकतों द्वारा पद दलित हो चुके थे। इस स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाने के लिए एशिया व अफ्रीका के लोग अभी भी इनकी नजर में योग्य न थे। जैसा सोवियत घोषणा यूरोप के सदस्य में की गई थी, वही हाल इन साम्राज्यवादियों की घोषणा का भी था। पर चूँकि सोवियत सत्ता के अधीन कोई उपनिवेश न थे इसलिए उनके द्वारा उपनिवेशों की आजादी की बात न उठाना कुछ समझ में आ सकता है, या साम्राज्यवादियों से घर आगन में जिस पराधीन हुई जनता के लिए आठ आठ आसू बहाये जा रहे थे, वह एशिया व अफ्रीका की जनता न थी, वह यूरोप की जनता थी जिसकी मुसीबत ब्रिटेन व अमेरिका को दुख दे रही थी। अपने साम्राज्य के लोगों के लिए “एटलांटिक चाटूर” न था, जैसा भारत के सदस्य में चर्चिल ने स्पष्ट भी किया था। बाद में रूजवेल्ट के दबाव पर जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं से वार्ता भी चलाई गई तो हार्दिक सहयोग को प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं किए गए और जब वार्ता टूट गई तब स्पष्ट हुई रूजवेल्ट विल्सन के नए संस्करण के अलावा और कुछ न थे।¹ पर चर्चिल तो अपने गुरू सॉयड जाज से दो कदम और पीछे रहने वाले टोरी नेता सिद्ध हो रहे थे।

युद्ध के इन उद्देश्यों या सिद्धांतों को उन परवर्ती घोषणाओं और वाताओं ने पुष्ट किया जो तीन बड़ों के बीच ससय समय पर युद्धकाल में होती रही। पर इसमें दो सिद्धांत भी स्थापना की गई जिस पर इन तीन बड़ा और इनके सहयोगियों में पूर्ण सहमति थी कि (1) उपलब्ध सारे साधनों के सहारे युद्ध लड़ा जाए और (2) यह कि पूर्ण विजय प्राप्त होने तक युद्ध लड़ा जाए और अलग से कोई राष्ट्र घुरी शक्तिता से संधि नहीं करेगा। इस संयुक्त राष्ट्रा की घोषणा पर 21 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए जिनमें गुलाम भारत भी शामिल किया गया था।²

महासागर के पूरे काल में मित्र राष्ट्रों के बीच समय समय पर वार्ता हुई तथा जो सम्मेलन हुए उन्हें चार भागों में बांट सकते हैं। ये हैं (पहला) अमेरिका—सोवियत—ब्रिटेन के बीच त्रिपदीय सम्मेलन, दूसरी कोटि में, ब्रिटेन व अमेरिका के बीच हुई अनेक वार्ताएँ तीसरी कोटि में अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच हुई वार्ताएँ और अंत में एक बड़ मंच में युद्धकाल के सभी मित्र राष्ट्रों के बीच बहते वार्ता।

(1) तीन बड़ों के बीच में

तीन बड़ा के बीच में युद्धकालीन जो भी वार्ताएँ हुई वे उन्होंने युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई—इस कोटि में आती हैं—(1) सितंबर 1941 में

मास्को सम्मेलन, अक्टूबर सन 1943 में मास्को में ही पर राष्ट्र मंत्रियों के बीच वार्ताएँ, नवम्बर व दिसम्बर सन 1943 की तेहरान वार्ता जिसमें तीनों राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए फिर अक्टूबर व सितम्बर 1944 को डायटन ओक्स में हुआ सम्मेलन जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान मुद्दे तय हुए फरवरी सन 1945 वाल्टा सम्मेलन और अन्त में जुलाई व अगस्त सन् 1945 का पोट्सडम सम्मेलन ।

(2) दो बड़े साम्राज्यवादियों के बीच

ये वार्ताएँ सन् 1939-1945 के बीच रूजवेल्ट और चर्चिल के मध्य समय-समय पर भी, यथा एटलांटिक चार्टर की घोषणा जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसी तरह कासालबाका में, दो बार न्यूवेक, वाहिरा में तथा दोना देशों के परराष्ट्र मंत्रियों और सैनिक स्टाफ के बीच समय-समय पर ।

(3) सोवियत व अमेरिका के बीच

सोवियत व अमेरिकी अधिकारियों के मध्य वार्ताएँ तीसरे ढंग की थी जो महत्व के हिसाब से अ-वल दर्जे की मानी जाएगी । इस दृष्टि से हेरी हापकिंस का वार्ता के लिए दो बार मास्को जागमन (सन 1941 के ग्रीष्म में तथा मई जून 1945 में), सन 1942-11 जून की सोवियत अमेरिकी समझौता । इन सिद्धांतों की स्थापना के लिए जिनके आधार पर आक्रमण के विरुद्ध युद्ध संचालित किया जायेगा । जून 12 सन 1942 में सोवियत वरिष्ठ नेता मोलोटोव की अमेरिकी यात्रा, दूसरे मोर्चे खोलने के अवसर ।

(4) "युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण" बृहत्तर मंच पर

चौथे ढंग की वार्ताओं का दायरा और भागीदार बृहत्तर आधार पर आयोजित की गई जिसका उद्देश्य था युद्धोत्तर दुनिया में सुरक्षा व्यवस्था और प्रगति के लिए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आधार शिला का बनाव जिसका श्री गणेश 1 जनवरी सन 1942 के संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा से शुरू होकर अप्रैल जून सन 1945 में सम्पन्न हुए सान फ्रांसिस्को सम्मेलन तक फला रहा ।

(अ) तीन बड़ों के बीच कूटनीतिक वार्ताएँ (1) सितंबर 1941 की मास्को वार्ता

अगस्त सन् 1941 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपस में वार्ता करके "एटलांटिक घोषणा" की थी जिसमें उन्होंने युद्ध के लक्ष्यों को स्पष्ट किया था और अपना यह दृढ़ निश्चय व्यक्त किया था कि नात्सी अत्याचार का विनाश हो जाने के बाद एक ऐसी शांति की स्थापना का प्रयत्न होगा

जिसमें सभी राष्ट्र सुरक्षित अनुभव करते हुए भय और अभाव से मुक्त होकर जीवन का निर्वाह कर सकेंगे और यह कि वे सभी लोग वा अपने ढंग की अपनी सरकार चुनने के अधिकार को मानते हैं, यद्यपि घोषणा के बाद चर्चिल ने बार-बार इस स्पष्ट किया कि 'अपने देश में अपना राज' स्थापित करने के अधिकार को वे एशिया व अफ्रीका के लोगों के लिए लागू करने का तयार न थे—यह सारी घोषणा के बावजूद यूरोप के उन देशों के निमित्त थे जो नात्सी फ्रांसी आक्रमण के शिकार हुए थे।

जून : सोवियत संघ पर हिटलर का आक्रमण हो चुका था। हमला हात ही ब्रिटेन ने तुरंत सोवियत संघ के प्रति अपनी सहानुभूति और मित्रता का हाथ बढ़ाया। अमेरिका अभी भी युद्ध में शामिल न था पर उसकी पक्षधरता धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी, जैसा एटलांटिक घोषणा में स्पष्ट था अमेरिका के हरी हापकिंस सोवियत संघ जाकर अपनी आत्मा से रूसी मार्च की हालत देखकर आए थे। उनकी स्टालिन से बातें भी हुई।⁴ हापकिंस मास्को में आवश्यक सूचनाएं तथा स्टालिन के प्रति एक सम्मान का भाव लेकर सीटों और सीधे यू फाउंडलंड गए जहां चर्चिल और रूजवेल्ट एटलांटिक घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे (9 अगस्त 1941) वहां ब्रिटानी और अमेरिकी सैन्य अधिकारी इस बात पर विचार करते रहे कि स चीजा और हथियारों की खेप ब्रिटेन में रखी जाए या सीधे रूसियों को दे दी जाए। अमेरिकी अधिकारी हथियारों को सीधे रूसियों के पास भेजना चाहते थे जबकि ब्रिटानी अधिकारी अमेरिकी सप्लाय ब्रिटेन में ही रखना बहुत मान रहे थे। तय हुआ कि रूस की मदद के सिलसिले में एक मिलाजुला शिफ्ट मण्डल मास्को भेजा जाए तदनुसार अमेरिका के एबरेल हेंगरीमैन तथा ब्रिटेन के लार्ड वेबर द्वाक मास्को गए और वहां स्टालिन से उनकी तीन बैठकें हुई (28 सितंबर से बैठक चली) जिसमें मूलतः उन वस्तुओं और हथियारों की सूची बनाई गई जो सोवियत संघ को भेजा जाना तय हुआ तथा जिसके अनुसार अमेरिका ने 1 अक्टूबर 1941 से जुलाई 1942 के बीच एक अरब डॉलर की वस्तुओं की सप्लाय देने का वायदा किया इस प्रकार सोवियत संघ और पश्चिम के बीच एक सैनिक भागीदारी शुरू हुई जो घुरी शक्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने तक चलती रही।⁵

(2) मास्को में ही परराष्ट्र मंत्रियों का सम्मेलन

(अक्टूबर 1930 से 1943)

यह सम्मेलन उस ऐतिहासिक मोड़ के बाद बुलाया गया जब सोवियत की बहादुर फौजों के अप्रूप शौर्य और बलिदान के बल पर हिटलर की आक्रांता फौजों को न केवल स्टालिनग्राद के बाहर धाम लिया बल्कि, दुश्मनों के नाकों चने चबा दिए और युद्ध का पासा पलटने लगा। अगस्त में सोवियत समाचार पत्रों ने सुझाव

दिया कि चूँकि मित्र राष्ट्रों के राज्यध्यक्ष मिल नहीं पा रहे हैं तो उनके परराष्ट्र मित्रों की ही बैठक हो जाए। यह सुझाव माना गया और अक्टूबर 19 से 30 तक मास्को में ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री ए. ए. बेकन, अमेरिका के वाइस हंस व मोलोतोव तथा स्टालिन के बीच बातचीत हुई जिसमें चीनी राजदूत 'फू पिंग शु' भी शामिल हुए और बातों का परिणाम निम्नसा एक समुक्त विज्ञापित के रूप में जो ब्रिटेन अमेरिका के साथियत के बीच युद्ध संबंधों आपसी समझदारी की सबप्रथम अभिव्यक्ति थी। इसके पहले भी सहयोग और पारस्परिक वार्ताएँ हुई थी, परराष्ट्र मंत्रियों के स्तर पर यह पहला महत्वपूर्ण विचार विमर्श था जिसमें अनेक युद्ध संबंधों प्रश्नों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें इन बातों पर सहमति हुई कि—(1) हर ऐसा प्रयत्न किए जाए ताकि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके और इस दृष्टि से मित्र राष्ट्रों के बीच घना से घना सहयोग और साहचर्य हो। (2) युद्धकालीन सहयोग की भावना और व्यवहार को युद्ध के बाद भी बनाए रखने के उपाय किए जाए ताकि शांति की मजबूत स्थापना हो सके। और जन साधारण का राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण सम्पादित हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसमें छोटे या बड़े सभी शांति प्रिय देशों को शामिल करने की बात तय हुई।¹⁸

इस सम्मेलन में एक ऐसी सस्था के निर्माण की बात भी तय हुई जो युद्धकाल में यूरोपीय देशों के प्रश्नों पर विचार विमर्श करती रहने के लिए तीनों देशों के बीच घने सहयोग की स्थापना करने का यत्न करें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन ने लंदन में एक यूरोपीय परामर्शदायी आयोग की स्थापना करने का निश्चय किया जो इन प्रश्नों पर विचार करे और अपनी समुक्त सन्तुष्टि तीनों सरकारों को दे।

इस सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि इटली संबंधी मामलों के लिए एक परामर्शदायी समिति बनाई जाए। तीनों परराष्ट्र मंत्रियों ने एक घोषणा के द्वारा इटली में लोकतन्त्र की पुनः स्थापना के लिए मित्रराष्ट्रों के हस्त को स्पष्ट करने का निश्चय किया। इस प्रकार तीनों परराष्ट्र मंत्रियों ने अपनी सरकारों की ओर स आस्ट्रिया की स्वाधीनता की पुनः स्थापना का मन्त्र्य दुहराया और इस चेतावनी को भी दुहराया कि पराजित जर्मनी को जब भी 'युद्धविराम' स्वीकृति दी जायगी, तब उन जर्मन सैनिक अधिकारियों और नात्सी अधिकारियों को उनके अत्याचारों के लिए उन उन दण्ड में दण्डित किए जाने के लिए ले जाया जायगा जहाँ उ हाने से जुल्म ढाये हैं और उनके देशों के कानून के अनुसार दण्डित किया जायगा।

इस सम्मेलन में चार बड़े राष्ट्रों की ओर से एक सप्त सिद्धांतीय घोषणा की गई जिसमें शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए युद्धकालीन सहयोग को शांति

काल मे भी बनाये रखने, शत्रु से आत्म समर्पण कराने और निशस्त्र करने के लिए एक जुट रहने शीघ्र ही एक ऐसे अंतराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए प्रयत्न करने जिसमें सभी शांतिप्रिय देशों की प्रमुखता सवधी समानताओं का आदर मिलेगा, तथा जिसके द्वार छोट-बड़े सभी राज्यों के लिए खुले रहेंगे, तथा युद्धावस्थात कोई भी दूसरे राज्यों के प्रदक्ष के अतगत अपनी सनाओं को सिद्धाय उम सूरत में जो इसमें दो गई है और जो परस्पर विचार विमर्श के बाद तय किया जाए, कभी तैनात नहीं करने तथा युद्धोत्तर काल में सन्तान के नियमन के लिए आपस में विचार विमर्श करने और सहयोग करने का सकल्प लिया गया ताकि, एक सवमाय समन्वित हो सके ।

इस प्रकार यह सम्मेलन युद्ध सत्तासन एव युद्धोपरात एक अंतराष्ट्रीय संगठन और व्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, यद्यपि यह बात स्मरणीय है कि इस समय तक सोवियत संघ के बार बार आग्रह करने पर भी दूसरा मोर्चा न खोलने की वजह में मित्र राष्ट्रों के बीच कुछ मन मुटाव भी शुरू हो गया था । समूचे सन् 1942 के वर्ष में हिटलरी राक्षसी सना के 280 सना के डिवीजना का पूरा का पूरा दबाव अकेले ही सोवियत संघ की झेलना पड़ा जिसमें उसे अपनी बहादुर सना, जन धन का भारी बलिदान करना पड़ा ।

इस बीच अफ्रीका में लडाई का मोर्चा खालकर हिटलर को कुछ परेशानी पहुंचायी गयी । पर जहां एक ओर इस बीच 'दूसरा मोर्चा' खालने की ब्रिटेन और अमरिका कोई जल्दी न थी और व दिक्कत होमें की सूचना व रह थे, वहीं स्टालिन से यह अनुरोध करने से भी अमरीका नहीं चूक रहा था कि अकेले ही हिटलर के 280 डिवीजना का सामना करते हुए भी, वे जापान के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने में दिलचस्पी लें ।

सन् 1943 शुरू हो गया पर दूसरा मोर्चा खोलने का निश्चय अभी भी टाला ही जा रहा था । चर्चित की अडगेबाजी खतम ही नहीं हो पा रही थी जिसके आगे अमेरिका भी लाचार हो जात । यहां तक कि चर्चित व एक मित्र दक्षिण अफ्रीका के जेन स्मट्स भी चर्चित की टालमटूल नीति के औचित्य पर सदेह प्रकट करने लगे । एक पत्र में उ होन युद्धकाल में उस सदम की चर्चा की जिसके अ तगत बाद में मास्को में यह सम्मेलन हुआ, जो द्रष्टव्य है । जेन स्मट्स ने लिखा था

‘स्थल पर हमारी तुलनात्मक नायबाहिया महत्वहीन रही और उनकी गति बहुत असंतोषजनक ।’ साधारण लोगो का तो ऐसा लगगा कि यह रूस है जा युद्ध जीत रहा है । यदि ऐसी ही छाप बनी रही तो रूस की तुलना में युद्धोत्तर ससार में हमारी क्या नूरत बनेंगी । हमारी विश्वस्तरीय स्थिति में भारी परिवर्तन हो जायगा और इससे रूस समूची दुनिया का राजनयिक स्वामी बनकर उभर चुकगा । यह बात अवश्यभावी है और अवाछनीय भी पर जब तक हम युद्ध से बराबरी के

आधार पर न तिवल्ले, हमारी स्थिति असुविधापूर्ण बन जायगी और सतरनाक भी।'

(3) तेहरान का सम्मेलन

(22-25 नवम्बर सन 1943)

यद्यपि 'दूसरा मोर्चा' अभी भी दूर था, पर तेहरान में पहली बार एक होकर तीन बड़ी शक्तियाँ के राष्ट्राध्यक्षा ने मित्र राष्ट्रीय एकता और सहयोग के भाव को पारस्परिक विश्वास और सौहार्द के योग से परिपुष्ट करने में सफलता पाई। तेहरान में पहली बार ये तीन बड़े मिल रहे थे और वह भी उस तेहरान में जो उस राज्य की राजधानी थी जिसमें होकर सोवियत संघ की सप्लाई 'पहुँचाई' जा रही थी। वह युद्धकाल तक एक ओर ब्रिटेन तो दूसरी ओर सोवियत संघ के अधीन बना रहा। वहाँ के तत्कालीन शासक को हटाकर (जिसके बारे में यह शक था कि उसकी सहानुभूति जर्मनी के प्रति थी) उसके अल्पव्यस्क पुत्र को मोहम्मद रजाशाह पहलवी की गद्दी पर बैठाया गया था।

तीन बड़े ने परस्पर विचारों का आदान प्रदान किया। कुछ महत्वपूर्ण निणय किये गये युद्ध के बारे में ईरान के बारे में, युद्धोत्तर व्यवस्था की रूपरत्ना के संबंध में। इनमें से कुछ निणय प्रकट किए गए, कुछ गुप्त रखे गए जो बाद में सन 1947 में ही प्रकट हुए। सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि तीन बड़े ने दिल खोलकर बातों की और एक दूसरे का सदभाव और विश्वास प्राप्त किया। सम्मेलन के बाद तीन शक्तियाँ की घोषणा ने अपनी विजयि में अंत में कहा कि हम यहाँ आशावान और सकल्पवान होकर आए थे और अब भावना और उद्देश्य की दृष्टि से हम वस्तुतः मित्र बनकर लौट रहे हैं।

इस सम्मेलन में तीनों मित्र देशों के सेनाध्यक्षा की वे योजनाएँ प्रस्तुत की गई थीं। इस पर विचार हुआ और पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में जर्मनी पर आक्रमण करने की योजना पर मतैक्य स्थापित किया गया। इस सम्मेलन में युद्धोत्तर शांति की स्थापना की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया।

ईरान के संबंध में

ईरान के बारे में तेहरान सम्मेलन के द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की गई और जिस प्रकार की आर्थिक कठिनाइयाँ ईरान को भोगनी पड़ रही हैं उनके प्रति वृत्तज्ञता और आभार प्रकट किया और वचन दिया कि युद्धोपरांत ईरान की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि तीन बड़े राष्ट्र ईरान की स्वाधीनता प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता को बनाए रखेंगे और वे यह भरोसा करते हैं कि ईरान

भी अ य शांति प्रिय राष्ट्रों की तरह युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सम्पन्नता की स्थापना के लिए एटलांटिक घोषणा के सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करेगा

गुप्त सम्मेलन

तीन बड़ी न अपनी पहली बैठक में कुछ समझौते होने भी किए जिसे उन्होंने तत्काल गुप्त रखने का निश्चय किया गया वे निम्न थे

(1) युगोस्लाविया के स्वाधीनता सैनिकों की शस्त्रास्त्रा और साज सामान की सप्लाई भेजकर हर प्रकार की मदद दी जायेगी।

(2) यह तय हुआ कि सैनिक दृष्टि से यह वाछनीय था कि तुर्की को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में लाया जाए।

(3) स्टालिन के इस वक्तव्य को नोट किया गया कि यदि तुर्की युद्ध में शामिल हो जाए और उसके फलस्वरूप बलगारिया तुर्की के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दे तो सोवियत संघ तुरंत बलगारिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ देगा। तुर्की का युद्ध में आमंत्रित करने के लिए इस महत्वपूर्ण सूचना का उपयोग किया जाए।

(4) यह नोट किया गया कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा (ओवर लांड अभियान) मई सन 1944 के दौरान खोला जाएगा। सम्मेलन ने स्टालिन का यह आश्वासन भी नोट किया कि यदि ऐसा दूसरा मोर्चा खोला गया तो सोवियत सेनाएँ उस समय ऐसा जवदस्त सैनिक अभियान छेड़ेंगी जिसका लक्ष्य होगा कि जर्मनी अपनी पौर्बे पूव से पश्चिमी मोर्चों की ओर न लगा पायें

(5) यह तय हुआ कि तीनों शक्तियाँ के सैनिक अधिकारी परस्पर संपर्क बनाये रखेंगे और दुश्मन को धोखे में रखने और छानने के लिए एक गुप्त योजना कार्यान्वित की जायेगी।

इस सम्मेलन में तीन बड़ी के दिल आपस में मिल गए, यह एक बड़ी बात थी जिसका श्रेय स्टालिन और रूजवेल्ट को जाता है। चर्चिल का दूसरा मोर्चा को टालने की दुर्नीति चलती रही और ऐसी कोशिशें भी की जिसमें लगे कि सोवियत संघ के विरुद्ध एक आम्ल अमेरिकी मोर्चा अन्तर ही अंदर बना हुआ है पर रूजवेल्ट ने अपने निष्कपट और निष्पक्ष व्यावहार का भरोसा बचा कर इस प्रकार के दुष्प्रभाव को रोका।⁹ स्टालिन का स्मरणीय नेतृत्व इस सम्मेलन में बेजोड़ रहा। उस समय अथात नवंबर सन 1943 में 320 जर्मन डिवीजनों में से 206 डिवीजनों सन 1944 में आखिर में पुरा तो स्टालिन में सदा की भांति अपना बायदा सच कर दिखाया, उस समय भी हिटलर के 157 डिवीजन पूव में लड़ रहे थे जबकि (जनवरी में) ब्रिटेन व खिल्लाफ कुल 50 डिवीजन थे—अप्रैल 14 सन् 1944 में अनुमान था कि 199 जर्मन डिवीजन पूर्वी मोर्चों में तैनात थे और 137 अयत्र

जिसमें फ्रांस और निम्नस्थ प्रत्या 51, 1 सितम्बर में भी जर्मन केवल 52 डिवीजन मेना की पश्चिमी मोर्चे में जुटाए हुए थे लेकिन इसमें ॥ बहुत सी डिवीजनों नाम मात्र की थी। जनवरी सन 1945 में रूसी सेना 133 जर्मन डिवीजनों से भिड़ रही थी जो समूची जर्मन घल सेना का आधार थी और अन्य भिन्न 100 डिवीजनों का सामना कर रहे थे जिनमें 76 पश्चिम में थी और 24 इटली में।^{१०}

य आंकड़े इस तथ्य का अच्छी तरह उजागर करते हैं कि यूरोप में युद्ध का महान केन्द्रीय सैनिक तथ्य या तालसेना की शक्ति। दूसरे महायुद्ध को लेकर जो अनेक मिथ्या बने चल आ रहे हैं वे इस नियमन विचार धारणा की उपेक्षा करके चलते हैं। इस माह के समय में जबकि युगोस्लाविया के स्वाधीनता सनानी अपनी जान लेवा मुक्ति सघर्ष में लगे थे, तब उनके लिए मित्र राष्ट्रों की ओर से सब प्रकार की सहायता का प्रबंध भी जिन हाथों ने किया, वे स्टालिन के इस्पाती हाथ ही थे, जिनकी मुटठी मुटठी सहायता सब मुक्ति सघर्ष के लिए मिलजुल कर तय किया वलिक, युद्धोत्तरकाल के लिए भी बंदोबस्त करने का यत्न किया। मास्को के परराष्ट्र मंत्रियों के पहले सम्मेलन में ही युद्धोत्तर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था इसके बाद भी समय समय पर ये प्रश्न उठाये गए पर जब सन 1942-43 के बाद मित्र राष्ट्रों की विजय के आसार प्रकट होने लगे तब इस पर और विचार विमर्श चला। डब्लुटन ओक्स सम्मेलन इस दिशा में उठाया गया पहला पुस्तक कदम था जिसमें वार्ताओं का दौर दो चरणों में तय हुआ। पहले चरण में तीन बड़ी शक्तियाँ क बीच वार्ताओं का दौर चला और दूसरे चरण में चीन ने दो बड़ा— ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बात चीत के जोर सोवियत सघ इससे असंग रहा। इन डब्लुटन ओक्स की प्रथम चरण की वार्ता में तीन बड़ों के बीच सोवियत सघ अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य बहुत सारी बातों में मतभेद रहा। यथा ये सभी राष्ट्र नये अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबंधी चार आधारभूत तत्वों के बारे में पूर्णतः अहमत रहे। ये सहमत थे कि

(1) ऐसी एक सामान्य सभा हो जिसमें सभी राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व मिले।

(2) ऐसी एक सुरक्षा परिषद हो जिसमें सभी बड़ी ताकतों को स्थायी तौर पर सदस्यता मिले और कुछ दूसरे प्रतिनिधि भी इसमें रहें जो छोटे देशों का प्रतिनिधित्व करें और समय समय पर सामान्य सभा के द्वारा चुने जायें।

(3) एक सचिवालय हो।

(4) एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो।

यह भी तय हुआ कि इस नये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र सघ ही रखा जाए। यह भी इसने बीच तय हुआ कि न तो सुरक्षा परिषद में और न सामान्य सभा में निर्विरोध नियम की विवक्षता रहे अर्थात् सार नियम निर्विरोध

ही हो। एक सामांय सहमति थी कि सुरक्षा की व्यवस्था करे और बड़ी शक्तियों को इसमें स्थायी तौर पर सदस्यता मिले।¹¹

मतभेद कुछ अंश में महत्वपूर्ण मुद्दों पर उठे। पहला मतभेद तो सुरक्षा परिषद की इस अधिकार के बारे में था कि वह किसी मामले को निपटाने की शर्तें थोप सके। अमेरिका सुरक्षा परिषद को ऐसा अधिकार देना चाहता था। पर यह प्रस्ताव न तो ब्रिटेन को मान्य था और न सोवियत संघ को ही।¹²

इसी प्रकार अमेरिका का प्रस्ताव था कि ब्राजील को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिले पर ब्रिटेन और सोवियत ने इसका विरोध किया, मतभेद इसको लेकर भी था कि सुरक्षा परिषद में नियंत्रण लेते वक्त किसी प्रक्रिया अपनायी जायेगी अर्थात् किसी विवाद में संबंधित बड़ी शक्तियाँ भी मत दे सकेंगी या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति का आग्रह था कि अमेरिकी संघ की तरह ही यदि बड़ी शक्ति किसी मामले में फँसी हो तो वह नियंत्रणकारी मतदान के वक्त तटस्थ रहे। लेकिन सोवियत संघ निर्विरोध नियंत्रण के तरीके छोड़ने को तैयार न थे अर्थात् ऐसे मामलों में बड़ी ताकतों के बीच पूर्ण मतभेद की नितांत आवश्यकता पर बल दिया। वे खूब महसूस कर रहे थे कि पूँजीवादी संसार के लिए ये कणधार अपने बहुमत के सहारे 'कहर' डालेंगे इसलिए वे निर्विरोध नियंत्रण की बात को कतई छोड़ने को तैयार न थे। राष्ट्र संघ के अपने कटु अनुभव सोवियत नेताओं का भूलें न थे और न वे उन्हें 'भुलाने' के लिए तैयार थे। इस प्रकार यह बात तय नहीं हो पाई।

अमेरिकी आयोजक खुद तो अपने लिए तो जापानी अड्डे पर कब्जा करना चाहते थे पर सोवियत संघ की सुरक्षा की जरूरतों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार न थे। सोवियत संघ का प्रस्ताव था कि¹⁴ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जो सुरक्षा परिषद के निर्देश पर मिनट भर में कामवाही करने को तैयार हो जाए और¹⁵ जो छोटे देश सुरक्षा परिषद की अपनी सैन्य शक्ति का सहारा न दे पाये, तो अपने प्रदेश परिषद के उपयोग के लिए भेंट करने का उद्घत रहे। अमेरिकी उसके लिए तैयार न थे। ब्रिटेन एक सैन्य स्टाफ बनाने के पक्ष में था।¹⁶ सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना खड़ी की जाए पर उन्होंने यह प्रस्ताव वापिस ले लिया।

इसी प्रकार सामांय सभा के अधिकारों के बारे में भी पूर्ण सहमति न थी। जबकि सोवियत चाहते थे कि शांति और सुरक्षा के मामले सामांय सभा तय करे पर सुरक्षा परिषद की अनुमति के बाद लेकिन अमेरिका व ब्रिटेन की राय थी कि स्वतंत्र रूप से ही सामांय सभा को यह अधिकार मिले अर्थात् चाहे उस मामले में सुरक्षा परिषद की अनुमति हो या न हो। यह विचार कि सुरक्षा के प्रश्न प्रभावित सुरक्षा परिषद का उत्तरदायित्व होंगे सभी को मान्य था। ऐसा ही झगड़ा सदस्यता

के प्रश्न को लेकर चल पड़ा। अमेरिका चाहता था कि समुक्त राष्ट्र के रूप में घोषणा करने वाले सभी सदस्य माने जायें। ब्रिटेन के साथ अमेरिका चाहता था कि 'सहयोगी राष्ट्र भी इस संगठन में शामिल करा' के लिए आमंत्रित किए जायें। जिन्होंने समुक्त राष्ट्र के आध्यात्मिक सम्मेलन का नियंत्रण स्वीकार किया था पर समुक्त राष्ट्रों के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थी। आठ ऐसे देश थे जिनमें 6 लातिनी अमेरिकी देश थे। सोवियत संघ नया संगठन इसलिए बनाने के पक्ष में था कि मुख्यतः (यदि पुनः न भी होता तो) जर्मन और जापानी आक्रमण का पुनः उभार न हो सके और इसी दृष्टि से वे सैनिक सैन्य संगठन को आग बलाते रहना चाहते थे जिसका अर्थ था उन देशों को बाहर ही रखना जिन्होंने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया पर जब अमेरिका उन्हें शामिल किए जाने के लिए जोर देने लगा तो सोवियत संघ ने यह मांग की कि उसके सोलह के सोलह गणराज्यों को अलग अलग से इसमें प्रतिनिधित्व मिले। इसने विवाद को विस्फोटक रूप देना शुरू कर दिया। बात फिलहाल टाल दी गई।

चीन के साथ ब्रिटेन व अमेरिका का विचार विमर्श

दूसरे कारण में दो बड़ा ने—अमेरिका व ब्रिटेन—चीन के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। पर चीन की ओर से कोई खास प्रस्ताव नहीं सुझाया गया और इसी से डम्बटन ओक्स प्रस्ताव में इस ओर से कुछ नया जोड़ा गया। चीनी प्रतिनिधि मण्डल के द्वारा पेश किए गये तीन सुझावों को ब्रिटेन व अमेरिका ने अपनी स्वीकृति दी और बाद में सोवियत संघ ने भी अपनी सहमति प्रकट की कि उन सुझावों को सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में रखा जाए। ये तीन सुझाव थे : (1) समुक्त राष्ट्र संघ के विधान में यह बंदोबस्त हो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हो (2) अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और नियमों के संशोधन और परिवर्धन के बारे में विचार करने तथा सुझाव देने की पहल करने की जिम्मेदारी सामान्य सभा की हो तथा राष्ट्रों के बीच, (3) औसतिक एवं अन्य सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ा देने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद बंदोबस्त करे।

याट्टा सम्मेलन के पूर्व दो बड़ों के बीच वार्ताएँ

बड़ी शक्तियों के बीच युद्धकाल में जितने भी सम्मेलन व आपसी वार्ताएँ हुई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन याट्टा में हुआ जहाँ सन 1945 की फरवरी 4 से 11 तक तीन बड़ी शक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच महत्वपूर्ण वार्ताएँ हुईं और उसी बोटि के महत्वपूर्ण निष्पत्ति हुए जिनमें कुछ निष्पत्ति तत्काल आयों से गुप्त रखे गए और जब उनका भेद खुला तब वे काफी विवादास्पद सिद्ध हुए। याट्टा

सम्मेलन पर विचार करने के पहले यह अच्छा होगा कि हम उस सदन में (एफ्ट) क्यों जिसमें यह सम्मेलन सम्पादित हुआ था। तभी हम इसके निणयों का सही मूल्यांकन कर सकेंगे।

हम याददाश्त के बतिये महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों का जिक्र कर चुके हैं। उन वार्ताओं का जिक्र अब तक नहीं हुआ है जो एटलांटिक चाटर की परम्परा को आगे बढ़ाने वाला थे अर्थात् द्विपक्षीय वार्ताएँ जिसमें तीन बड़ा-की जगह दो बड़ा-के बीच ही बातचीत हुई, तथा ब्रिटेन व अमेरिका के बीच, या ब्रिटेन व सोवियत संघ के बीच। इन द्विपक्षीय वार्ताओं का उल्लेख कर हम याददाश्त के पूर्व की स्थिति को सही तरह से रक्त सकेंगे।

मोरक्को के फासाल्बाका में सम्मेलन

(14 फरवरी से 24 फरवरी तक सन् 1847)

यह सम्मेलन अमेरिका व ब्रिटेन के बीच हुआ और इसमें ब्रिटेन में 'शरण पाय' मुक्त फ्रांस' के नेता दगाल को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में दूसरे मोर्चे को टालते हुए यह तय किया गया कि उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण करने के पूर्व इटली पर हमला कर धुरी शक्तियों को पछाड़ा जाय। चर्चिल अपना पक्ष रूजवेल्ट के आगे मजबूत करना चाहते थे और कि उनकी यह रणनीति मानी जाए। इसलिए इस रणनीति को पुष्ट करने के लिए वे अपने साथ दगाल को ले गए जिनके प्रति रूजवेल्ट का कुछ खास झुकाव न था।

काहिरा सम्मेलन

(22 नवम्बर 1943 से 25 नवम्बर तक)

इसी प्रकार ब्रिटेन व अमेरिका के मध्य काहिरा में भी महत्त्वपूर्ण वार्ता हुई जिसमें फ्रांस की तरह इस बार चीन को शामिल किया गया चूँकि जिन समस्याओं पर बातचीत हुई वे मुख्यतः पूर्वी एशिया से संबंधित थी। इसमें चीन को आश्वस्त करते हुए यह निणय लिया गया कि जापान ने प्रथम महायुद्ध के समय जो प्रदेश चीन से छीने थे, वे उसे वापस मिलेंगे। यहाँ रूजवेल्ट ने सोवियत संघ की ओर से "जल से निक्कासी" की सहूलियत की माँग से च्यांग को परिचित कराया था अर्थात् पोर्ट जायर और डेरियन के सबंध में मागी गई। सुविधाओं के बारे में सूचना दी और आपस में विचार किया।¹⁸

इस प्रकार चर्चिल धीरे धीरे फ्रांस को लंदन स्थित टूटे फूटे 'मुक्त फ्रांसिसी' दल को आगे लाकर बड़े राष्ट्रों की पंक्ति में बैठाने लग्ये, और यही अमेरिका चीन के लिए कर रहा था। "तीन बड़ों" की पंक्ति में, कालांतर में ये "दो बड़ों" की भी शामिल किया जाना था।

यूबेक सम्मेलन

(11 सितम्बर से 15 तक, 1944)

कनाडा की राजधानी क्यूबेक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन व उसके राष्ट्रमण्डल के सदस्यों—कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूजीलण्ड से वार्ता की जिसमें जर्मनी की जिस प्रकार उसकी पराजय के बाद अलग अलग “अधिवृत्त क्षेत्रों” के तौर पर बांटा जायेगा, उस पर विचार किया गया और आम सहमति प्राप्त की गई। यही अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने आपस में तय किया कि ‘मार्गो-याऊ योजना’ के अनुसार जर्मनी का ‘अनौद्योगीकरण’ किया जाय जो अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री हल को पसन्द न था।

जिससे बाद में अमेरिकी कैबिनेट ने संशोधित किया और रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी ट्रुमैन ने जिस योजना का परित्याग कर दिया।

ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन

(जुलाई 21, 1944)

21 जुलाई सन 1944 को संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स में हुआ जिसमें 44 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें युद्धोपरांत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विकास के निमित्त पृथिव्यादी व्यवस्था के अनुकूल हो, एक पुनर्गठन एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बक तथा अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करने का निश्चय किया गया। एटलांटिक चार्टर का उद्देश्य आखिर इसी विकास क्रम की दिशा को अपने अनुकूल बनाना था।

अमेरिकी व सोवियत के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं

(हेरी हापकिंस की मास्को यात्रा मई जून, 1941)

हम अग्यन इस यात्रा का जिक्र कर चुके हैं। हापकिंस लंदन से होते हुए मास्को गए थे जहां उन्होंने स्टालिन से खुलकर बातें की और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जिसके अनुसार सोवियत शक्ति जब लड़ाई के मदान में उतरी तो उसने 24 हजार टैंक थे जिसमें 4 हजार बड़े टैंक थे जबकि जर्मनी के पास तीस हजार थे। सोवियत सभ एक हजार टैंक प्रति माह निर्मित कर रहे थे और 1800 सौ हवाई जहाज। जल्दी ही उनकी तादाद बढ़कर 2500 हो जाने वाली थी। लड़ाई शुरू होते समय नात्सी जर्मनी और सोवियत सभ दोनों के 175 डिविजन सैनिकों के सहारे सड़ रहे थे।¹⁹

हापकिंस सोवियत सभ व उसके नेता स्टालिन के साहस, शौर्य और दबदब सक्त्प वाले व्यक्तित्व में बहुत प्रभावित होकर लौटे। हापकिंस बीरपट से रूज

वेल्ट को इस बात के लिए उत्साहित किया कि वे सोवियत सघ की मदद के लिए आगे आ गए। इसके बाद अमेरिका के एवरल हैरीमेन व ब्रिटेन के लाड वेवर ब्रुक उधार पट्टे के अतृप्त सहायता देने का प्रस्ताव लेकर स्टालिन से मिलने गए और तब सहायता सामग्री की सूचि तय हुआ कि। अक्टूबर 1941 स। जुलाई सन 1942 तक एक अरब डालर राशि की सहायता सोवियत सघ को प्रदान की जायेगी। यही से सोवियत सघ की ओर पश्चिम के मित्र राष्ट्रा के मध्य सैनिक सापेदारी की शुरुआत होती है।

एन्थोनी ईडन की महत्वपूर्ण यात्रा (मास्को बैठक)

रूसी सैनिक एक ऐतिहासिक 'महाभारत' लड़ रहे थे। लाखों सैनिकों की लाम बंदी हुआ जो शीघ्र ही एक करोड़ की संख्या तक पहुंच गई। जर्मन नात्सी पूरी बबरता दिखा रहे थे। हमलावर बढ़ते ही जा रहे थे और सोवियत सघ ने सन 1939 के बाद जो प्रदेश अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अधिकार में ले लिये थे, उन पर जमन बज्जा हो गया। जगह जगह नात्सी जमना की लाठ फोड़ की काय बाही व विनाश लीला चल रही थी और लेनिनग्राड और मास्को के निकट जमन बबर सना ने घेरा डाल दिया। एक एक इंच जमीन पर सोवियत रण बाकुरे अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहे थे और सोवियत के इन बहादुर योद्धाओं ने स्टालिन ग्राह पर हिटलर की फौजों को न केवल रोक दिया बल्कि उन पर भारी चोट पहुंचाकर युद्ध का पासा ही पलट दिया।

इस गाढ़े समय में भी सोवियत नेताओं ने चाहा कि ब्रिटेन से युद्धोत्तर प्रबध के बारे में अभी समझौता हो जाए तो निश्चित होकर और जमकर साथ साथ युद्ध लड़ा जाए। ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री इसी माहौल में दिसंबर 7 की मास्को पधारे। पर दिसंबर 5 की ब्रितानी सरकार की रूजवेल्ट का इस आशय का पत्र मिल चुका था कि अमेरिका की ओर से युद्धोत्तर प्रबध की दिशा एटलांटिक चाटर में निश्चित है। यदि तीनों सरकारों में स कोई भी सरकार इसके आगे जान का तय करेगी तो अमेरिका इसे दुर्भाग्य पूर्ण बात मानेगा। "सबसे मुख्य बात यह कि कोई गुप्त समझौता नहीं होना चाहिए और जिस साविधानिक सीमा से अमेरिका की सरकार बंधी हुई है उसे ध्यान में रखा ही जाना चाहिए।"²⁰

रूसी नेता उस समय ब्रिटेन से यह चाहते थे कि अपनी सन 1940 की सीमाओं को वह मान ले। पर ईडन इसके लिए तैयार न थे। स्टालिन ने यह प्रस्ताव रखा कि 22 जून सन 1941 की रूस की सीमा को नाप लिया जाए तथा स्लोवाकिया, युगोस्लाविया, आस्ट्रेलिया एवं अल्बानिया की पुनः स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा, पूर्वी प्रशा पोलेण्ड को दे दिया जाय तथा पश्चिम में जमनी से

राइनलैण्ड और सभ्य हो तो बबरिया असंग करायी जाए और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसे मायता दे दी जाए स्टालिन इसके लिए तैयार थे कि बदले में वे ब्रिटेन को फ्रांस को मिलाकर समूचे पश्चिमी यूरोपीय देशों में, वही भी अड़्डे देने के प्रस्ताव को समतन देंगे।

इन प्रस्तावों को अमेरिका ने नामजूर कर दिया। उनका ख्याल था कि बाल्टिक देशों का रूसी अधिग्रहण नहीं मजूर किया जा सकता है तथा पूर्वी पोलैंड रूस को नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सारी मांगें रूस अपनी उस कमजोर स्थिति को ध्यान में रखकर पेश कर रहा है जो युद्ध के बाद उसकी हानि जाने का उमे भय है। इस प्रकार ब्रिटेन व अमेरिका ऐसे किसी समझौते के लिए तैयार न थे जो सोवियत संघ की युद्ध पूरा की सीमाओं को मायता प्रदान कर दे। सोवियत संघ की पश्चिमी सीमाओं को मायता प्रदान कर दे। सोवियत संघ की पश्चिमी सीमाओं का मामला एक खुला विषय बनी रही जो युद्ध के परिणाम पर निर्भर करा दी गई। पर स्टालिन ने ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री ईडन को तब भी स्पष्ट कर दिया था कि दिसम्बर सन 1941 में चूँकि अतीत में पिछले 35 वर्षों में तीन बार रूस को पूर्वी यूरोप के आक्रमण कारियों का सामना करना पड़ा है और भारी बलिदान करना पड़ा है, इसलिए अब वे इस प्रदेश को विरोधियों के हाथों नहीं पड़ने देंगे। यह लक्ष्य जैसा कि ल्फेमिंग ने उचित ही कहा है सोवियत नेताओं की ओर से युद्ध का प्रथम लक्ष्य, जिसने टलने का प्रश्न ही नहीं उठना था।

अप्रैल 1942 में ब्रिटेन ने इस दिशा में फिर से कुछ समझौता वार्ता चलानी चाही, पर अमेरिकी विरोध के आगे ब्रिटेन की चली नहीं और मई 1942 में जो समझौता सोवियत संघ से हुआ उसमें प्रादेशिक प्रबंध की चर्चा भी नहीं थी जिसका अर्थ था कि कुर्यात म्यूनिस समझौता भी उमो का त्याग बना रहा। वह कलक अगस्त सन 1942 में तभी मिट पाया जब स्पेकोस्लावाकिया के नेता बेंज का जोरदार दबाव ब्रिटेन पर पड़ा।

यूरोप की लड़ाई मुख्यतः रूसी लाल सेना के दम खम पर लड़ी जा रही थी पर मित्र राष्ट्रों की ओर मित्रता का कैसा ठिटूरा देने वाला प्रथम परिचय रूस को मिल रहा था उस समय जब कि वे जीवन मरण के अपने ऐतिहासिक संघर्ष में जूझ रहे थे।²³

युद्धकाल में ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एकदूसरी महत्वपूर्ण वार्ता 1944 की चर्चिल स्टालिन वार्ता

याल्टा सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व चर्चिल ने मास्को जाकर रूसी नेता स्टालिन से महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता की और गुप्तचुप समझौता भी कर लिया पर

तब युद्ध का सदम कुछ का कुछ बन चुका था। युद्ध के प्रारम्भ में सोवियत संघ को उत्तरी सीमाओं के बारे में किसी प्रकार की माँगता न देकर भी दूसरा मोर्चा खोलते-खोलते विलम्ब कर देने के बाद भी जब सोवियत की लाल सेनाओं ने अपना जोर कर दिखाया और न केवल अपनी सीमाओं से बर जर्मन आक्राताओं को खदेड़ दिया बल्कि, उनका पीछा करते हुए पड़ोसी देशों से भी उनका सफाया करते हुए रूसी सेना अपनी अजेय वीरता का परिचय देती आगे बढ़ने लगी और बुल्गारिया, पर अधिकार कर यूनान और तुर्की की ओर बढ़ चली—अक्टूबर सन 1944 में लाल सेना हमरी और युगोस्लाविया में थी और तब ब्रितानी फौजें यूनान में उतरी ही थी जहाँ साम्यवादी नेतृत्व में भारी संख्या में भुक्ति युद्ध के योद्धा उनका स्वागत न कर, उनके विरोध पर आमादा थे उस समय ब्रितानी नेता चर्चिल ने मास्को जाकर ऐसा समझौता करना चाहा जो उह यूनान में 'निर्वाण अधिकार' की छूट दे दे क्योंकि यदि लाल सेना यूनान के साम्यवादी छापामारों को मदद देना तय कर लेती, तो ब्रिटेन के लिए ये संभव न रहा जाता कि वे आसानी से यूनान में घुसपठ कर सकें और अपने राजतन्त्रीय समर्थकों को पुन गद्दी पर बिठा सकें।

ब्रिटेन ने अमेरिका को सूचना दी कि वह सोवियत संघ से ऐसा समझौता करने का इच्छुक है जो सोवियत संघ को रमानिया में प्रभाव क्षेत्र बनाने द ताकि बदले में ब्रिटेन यूनान को अपना प्रभाव क्षेत्र बना ले। अमेरिका का बताया गया कि यह प्रभाव क्षेत्र की बात नहीं बल्कि, यह कि रूसी रमानिया का और ब्रिटेन यूनान व युगोस्लाविया का मामला सभाले। अमेरिकी सरकार ने अपनी सहमति न दी और यह सुझाव रखा कि बाल्कन प्रदेशों के लिए एक परामशदात्री समिति बनाई जाए जिसके माध्यम से मामले तय हों। पर चर्चिल अपनी जिद पर अड़े और अपने प्रस्ताव को एक ऐसे प्रयोग के रूप में मनवाने का आग्रह करने लगे जिसे तीन महीने तो चलाया जाए।

सोवियत संघ ने भी अपनी ओर से चर्चिल के इस सलाह मसबरे की सूचना अमेरिका को दी ताकि मित्र राष्ट्रों की मित्रता में किसी तरह की खटाई न पड़े। रूजवेल्ट की ओर से सूचना दी गई कि ब्रितानी प्रस्ताव को एक विशुद्धत अस्थायी प्रबंध के रूप में माना जा रहा है। पर भविष्य का प्रबंध बाद में ही होगा। ब्रिटेन के नेता अपने ढंग से चलते रहे और अक्टूबर सन 1944 में चर्चिल और ईडन ने मास्को जाकर न केवल अपने समझौते पर रूसी मुहर लगवा ली बल्कि, रूसी नेता स्टालिन के साथ इस बाल्कन प्रदेश के बारे में अपने अपने प्रभाव की मात्रा प्रतिशत के रूप में भी तय करवा ली।

चर्चिल व ही शब्दों में यह समझौता इस तरह हुआ कि उसने रूस के लिए 90 प्रतिशत प्राधान्य रमानिया में माना और यही प्रतिशत ब्रिटेन का यूनान में

रहा। यूगोस्लाविया में दोनों का पचास पचास प्रतिशत तय माना गया। चर्चिल के अनुसार उन्होंने एक कागज पर इन पांचो बाल्कन प्रदेशों में ब्रिटेन व सोवियत संघ के वचस्व का प्रतिशत लिख दिया, यथा, रूमानिया में सोवियत का 90 प्रतिशत पचास पचास प्रतिशत दोनों का वचस्व बुल्गारिया में सोवियत का 75 प्रतिशत वचस्व तथा अ य का 25 प्रतिशत। स्टालिन ने इस कागज को देखा और उस पर एक बड़ा सा नीला सही का निशान बना दिया और कागज चर्चिल को ही लौटा दिया। सब कुछ झटपट ही तय हो गया था। वह समझौते वाला कागज टेबल पर पड़ा था। साम्राज्यवादी चर्चिल के मन का चोर जाग गया कि यदि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े मामले जिनसे लाखों लोगों के भाग्य जुड़े हैं इस चल ताक ढंग से तय हो गए। चर्चिल की राय थी इस कागज को जिसमें पांच बाल्कन राष्ट्रा की भाग्य रेखा निश्चित कर दी गयी थी जला दिया जाए। लेनिन के महान शिष्य व साम्यवादी नेता स्टालिन ने जारशाही के सहजे में फरमाया नहीं इसे आप ही रख लें। मसमजा दोप गुण भर्त्ता साम्राज्यवादियों की सगत कुछ रगत तो लाकर ही रहेगी।

याल्टा सम्मेलन

(4 फरवरी सन 1945 से 11 फरवरी 1945 तक)

महासमर निर्णायक दौर में पहुंच चुका था। दूसरा मोर्चा पश्चिम में खुल था चुका था जिसकी वजह से जर्मन नात्सी सैन्य शक्ति को तोड़ना और भी आसान होता जा रहा था। पर दूसरा मोर्चा खोलने में देर लगाकर पश्चिमी मित्र राष्ट्रा ने सोवियत की लाल सना के कंधों पर ही सारा बोझ टिका दिया था। वे अपनी सीमाओं में जर्मन नात्सी सैन्य शक्ति को खदेड़ कर पड़ीसी दशों को नात्सी आतंक से मुक्त करने के लिए आगे बढ़ते गये और तब चर्चिल और उनके मित्रों को भविष्य की एक नापसंद तस्वीर उभरती दिखाई देने लगी। इस उभार के समय रहते जितना भी रोक सके उतना रोक लेने के लिए चर्चिल ने वह दोढ़धूप मास्को जाकर की जिसका हम जिक्र कर चुके हैं और घटनाचक्र को कुछ थोड़ा सा अपने अनुकूल मोड़ पाने में सफलता प्राप्त कर ली। फिनलैण्ड पर आक्रमण करने अपनी रक्षा पकित दुरस्त करने वाले सोवियत नेताओं ने साम्राज्यवादियों का यह 'वजित पल' खल लिया और यूनान व यूगोस्लाविया के मुक्त सैनिकों को उनके साथ लाल सना पड़ीस के उस समूचे प्रदेश को नात्सी और उनके सहायक जहरीले तत्वों से मुक्त कराने की अभियान में आगे बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने चर्चिल से यह ठजोड़ न किया होता तो यूनान यूगोस्लाविया व भूमध्य सागर का भविष्य ही कुछ

और बनता, पर स्टालिनी नेतृत्व ब्रितानी व अमेरिकी साम्राज्यवादियों में मिल-जुलकर चलने की नीति अपना रहा था। यूरोप की लड़ाई का अंत साफ नजर आ रहा था, पर इससे अमेरिका को पूरी तरह निश्चितता नहीं प्राप्त हो रही थी, अमेरिका की "बड़ी लड़ाई" तो अभी बाकी थी—वह लड़ाई जिसने वस्तुतः अमेरिका को महासमर में ला पटका था अर्थात् अमेरिका का जापान के विरुद्ध महायुद्ध। इस युद्ध में अमेरिका को अब दूसरे मोर्चे की जरूरत थी और वह दूसरा मोर्चा केवल सोवियत की लाल सेना खोल सकती थी। स्मरणीय है कि सोवियत व जापान के बीच अनाक्रमण संधि का अब तक अच्छे तरह निर्वाह दोनों पक्षा की ओर में हो रहा था। जापान के विरुद्ध जब तक सोवियत लाल सेना न आए इस मोर्चे का बोझ अमेरिकी कंधे पर ही था। इस मोर्चे के सैनिक कमांडर सोवियत लाल सेना की आर याचना भरी दृष्टि से देख रहे थे।

अमेरिका के एक तथाकथित महान सेना नायक ने जो बाद में जापान पर सैनिक अधिकार कर, अमेरिकी सत्ता की ओर से जापान के कुछ समय के लिए सर्वेसर्वा बन गए थे, सोवियत सना के बारे में निम्नांकित उद्गार फरवरी 23, 1942 को प्रकट किये थे।

“इस समय की दुनिया की स्थिति यह है कि साहसी रूसी सेनाओं के योग्य शत्रु पर सम्पत्ता की आशा टिकी हुई है। मैंने अपन जीवन में अनक युद्धों में भाग लिया है और जनक का दशक रहा हूँ, तथा अतीत के महान सैनिक नेताओं के अभियानों के ब्यौरों का अध्ययन रहा हूँ मैंने इसमें से किसी लड़ाई में अब तक के अविजित शत्रु की भारी चोटों का प्रभावशाली ढंग से प्रतिरोध करते हुए किसी शत्रु को वैसा नहीं पाया, जैसा सोवियत सना ने किया है जिन्होंने जबकी हमले पर दुश्मनों को उनके घर लौटने के लिए खदेड़ना शुरू कर दिया है। जिसे पैमान पर और जिस शान से यह महान प्रयास सम्पादित किया जा रहा है, उसने इस समूचे इतिहास की सबसे महान सैनिक उपलब्धि बना दी है।”

सन् 1944 तक तो यह गौरवशाली अभियान पर चार चांद टाके जा चुके थे। याल्टा सम्मेलन में इस अपूर्व विजय वाहिनी का मुख जापान के विरुद्ध भी मोड़ने की महत्वाकांक्षा लेकर रुज्वेल्ट महोदय याल्टा पधारे थे। याल्टा सम्मेलन में विचार विमर्श के पीछे अमेरिका का यह एक इरादा बड़ा प्रेरक तत्व बना हुआ था। क्रीमिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर तीन बड़े, अपन अपने परामर्श दाताओं और सैनिक कमांडरों के साथ इकट्ठे हुए और बातचीत की। यहाँ अनेक मसलों पर विचार हुआ यथा संयुक्त राष्ट्र संधि की बनावट के बारे में यूरोप के भावी स्वरूप के बारे में जर्मनी तथा पूर्वी एशिया के सबंध में जो भर कर चर्चा हुई और निणय लिए गये। कुछ तत्काल ही प्रकट कर दिए गए। और कुछ महत्व पूर्ण निणय 'गुप्त' रखे गये जिनका रहस्योद्घाटन बाद में हुआ। य गुप्ता समझौते

पूर्वी एशिया संबंधी थे। और इस प्रकार थे।

- 1 बाह्य मंगोलिया की स्वाधीनता को मायता दी गई अर्थात् उस चीन से अलग एवं राज्य का दर्जा दिया गाना माना लिया गया। यह कोई एहसान न था क्योंकि पिछले बीस वर्षों से 'बाह्य मंगोलिया' चीन से अलग होकर एक समाजवादी गणतंत्र की तरह अस्तित्व में रहकर तदनुकूल आचरण करता रहा। यह एक यथाथ का मिली मायता थी।
- 2 सलालीन के लंबे द्वीप के दक्षिणी भाग का सोवियत संघ का लौटाया जाना। स्टालिनवादी नेतृत्व पुराने जारशाही के दाव को अपनी विरासत मानकर चल रहा था। सन 1905 में ये द्वीप जापान ने जारशाही को युद्ध में हराकर छीन लिए थे।
- 3 कुराइल द्वीप समूह जिन पर सुरक्षा के हित के नाम पर स्टालिनवादी रुस ने दावा किया। यह दावा भी रूजवेल्ट ने और त्रिटैन ने मान लिया।
- 4 सोवियत संघ को 'प्रशांत महासागर' में, एक गरम बंदरगाह की जरूरत थी। उसमें अपने बंदरगाह अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते थे। रूजवेल्ट ने यह जरूरत की बात कहिरा में फ्याम कार्ड से की थी और तेहरान में भी इस पर पुनर्चर्चा चली थी। डेरियन के बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीयकरण और वहां सोवियत संघ का विशेष सुविधा देने का प्रबंध तय हुआ।
- 5 सोवियत संघ चीन के दक्षिणी और पूर्वी मचूरिया के रेल मातायात में हिस्से दारी चाहता था तथा चाहता था कि पोर्ट आथर उसे नौनैतिक अड्डा बनाने के लिए 'लीज' में दिया जाए। यह भी स्टालिन को सेंट में दिया गया दक्षिण फ्याम कार्ड गैर से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेनदेन का वहां पुराना साम्राज्यवादी तरीका भ्रष्ट में चलामा जा रहा था। चीन के समूह में अमेरिका त्रिटैन जा देने वाले थे सोवियत संघ दावदार था और लेने वाला लेकिन भारत सारा का सारा चीन का था। लेनिन का अक्टूबर क्रांति के तत्काल बाद की गई "क्रांतिकारी घोषणा", जिसने समूचे एशिया में विजली की बोध की तरह 'प्रकाश' फमा दिया था बीत दिना की एक सुभावनी याद बनकर रह गई थी।

क्रांतिकारी स्टालिन जिसने राष्ट्रीय के आत्म नियंत्रण के अधिकार का सभी सिंहनाद किया था, हिटलर और मुसोलिनी के मरने के पहले ही मर चुका था। यह स्टालिनी तो पीटर महान और जार निकालम का उत्तराधिकारी था जो सम्राटों की पुरानी बहिया खोल खोलकर अपना दावा मनचाहा चल रहा था। अमेरिका सब मानने को तयार था बशर्ते कि स्टालिन जापान के विरुद्ध जंग में कूदने को तयार हो जाए और उनका काम अपने बहादुर सैनिकों की जिदगियों की कीमत पर पूरा कर दे। महाजन अमेरिका कम खर्च पर अधिक से अधिक लाभ

पाने के चक्कर में था। रूस की ओर स याल्टा में एक ही मांग थी कि इतना बड़ा उत्सर्ग कर चुकने के बाद आखिर स्टालिन रूसी जनता से और अधिक से कुर्बानी के लिए कहें तो कैसे कहें, अगर वह उन्हें यह आश्वासन न दिला सकें कि ऐसी कुर्बानी करके उन्हें कुछ उपलब्ध होगा अर्थात् दूसरों की जमीन और जानमाल पर अबाध अधिकार मिलेगा। उन्होंने अपनी मांग रखी कि डेरियन और पोट आयर पर पूरा अधिकार और मचूरियाई रेलवे लाइन का स्वामित्व, लेकिन सौदा पटा इस पर डेरियन बदरगाह का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जायेगा, पोट आयर 'लीज' पर दे दिया जायेगा। और मचूरिया की रेलवे लाइन पर रूस चीन का साक्षात् रहेगा। अमेरिका व ब्रिटेन राजी हो गये। तत्काल छिपाकर रखना इसलिए जरूरी बताया गया कि क्याग फाई शेक के यहाँ बात छुप रह पायेगी इसका भरोसा न था। बाद में उन्हें बताया गया और उन्होंने क्याग फाई शेक को भी राजी कर लिया।⁸ और ये बातें अगस्त सन 1945 के चीन रूस संधि में दर्ज हो गईं। अमेरिका लेखक जो याल्टा सम्मेलन के पक्षपाती हैं आसानी से यह तक देते हैं कि इस समझौते में चीन को यह मोना मिला कि वह सोवियत के अधिग्रहण का इस प्रकार सीमाबद्ध और लिपिबद्ध कर सके नहीं तो बाद में सोवियत सत्ता आती तो अपनी मनमर्जी से इलाके हथियाती। ऐसी सूरत में गिरत पड़ते चीन के लिए यह किना बड़ा सहारा था।⁹ जो इस समझौते में नाराज है उनकी नाराजगी यह नहीं है कि अमेरिका ब्रिटेन को क्या हक था कि वे चीन की जनता की सम्पत्ति और अधिकार को जुटाते फिरे, बल्कि उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि जो अपना हो सकता था उसे रूसिया को क्यों दिया गया।

इस सदन में यह स्मरणीय है कि याल्टा के इस समझौते को क्याग फाई शेक ने तो मान लिया पर चीनी कम्युनिस्टा न जो मचूरियाई हिस्से में लड़ रहे थे, इसके विरुद्ध आवाज उठाई तभी यह तय हो गया था कि चीनी जनता किसके साथ है जिस तथ्य पर बाद में यह युद्ध न मुहर लगा दी।¹⁰

पर तत्क्षण इतनी सुविधाओं के उपलब्ध किये जाने का आश्वासन पाकर रुजवेल्ट के अनुरोध पर स्टालिन ने वचन दिया कि यूरोपीय क्षेत्र में युद्ध समाप्त हो जाने के तीन महीने के भीतर सोवियत संघ जापान के विरुद्ध युद्ध छेड़ देगा।

जर्मनी और पोलैण्ड के सबंध में

याल्टा सम्मेलन सारत युद्ध सबंधी निणर्णों का सम्मेलन था मिन राइट्रो के ध्यान का मुख्य केन्द्र जर्मनी था जिसकी पराजय अब बहुत नजदीक आती दिख रही थी। सम्मेलन में शुरू शुरू में यह विचार जोर पकड़ता रहा कि जर्मनी को अनेक राज्या में विखंडित कर दिया जाए, पर बाद में यह विचार पीछे धकेल दिया गया। युद्ध का मुआवजा जर्मनी से वसूल करने का विचार भी बना। इसमें रूसियो

का जोर ज्यादा था और वे अपनी शक्ति को ध्यान में रख, जमनी से भारी हर्जाना वसूल करना चाहते थे और और चाहते थे कि 80 प्रतिशत जमनी के भारी उद्योग आसानी से जमनी से हटाए जाकर हर्जाने के तौर पर रूस को दिए जा सकते थे। उनका दबाव था कि हर्जाने की राशि 20 अरब डॉलर तक की होनी चाहिए जिसका कम से कम आधा सोवियत मध्य को मिलना चाहिए अमेरिका तयार हो गया कि यह प्रश्न रूसी मुझाव का आधार बनाकर मुझावजा आयाग को विचाराम सौंप दिया जाए पर अग्रज इसमें सहमत न थे। इसलिए यह निश्चय किया गया कि जमनी को निश्चय दिया जाए। जमन सैन्य संगठन को नष्ट किया जाए ताकि, दुबारा जमन सैन्यवाद सिर न उठा सके। तथा सार नात्सी संगठन नष्ट किए जाए। तभी मुझ में कूरता बरतने वाल जमन सैनिक व असन्निव अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए और दण्डित किया जाए। आवश्यक जाच तथा समय का निणय तीन बजे पर राष्ट्र मंत्रिया की समिति तय करें।

पोलेण्ड के सम्बन्ध में

माल्टा सम्मेलन के शुरू होते होते, रूजवेल्ट ने अपनी वह पुरानी नीति बदल दी कि शांति सम्मेलन होने के पूर्व तक रूस की पश्चिमी सीमा के द्वार में चर्चा नहीं की जाए। दूसरा मोर्चा खोलने में देरी करके मित्र राष्ट्रों ने रूस को विश्वास कर दिया था कि वह सन् 1941 की सीमाओं को मित्र राष्ट्रों के मनवान का काम अपनी बहादुर सेनाओं के द्वारा पूरा करा ने। जो सन् 1941 ने मांगा जा रहा था, वह माल्टा सम्मेलन के समय का यथाथ बन गया था। यथाथवादी रूजवेल्ट और चर्चिल पोलैंड की कजन रेखा को मान रहे थे—यद्यपि सोवियत मध्य अपने अनुकूल निर्धारित हुई इस सीमा को कजन के नाम से जोड़ने पर आपत्ति कर रहे थे यह उनकी नजर में नई सीमा रेखा थी जो चर्चिल के लिए कजन रेखा का ही सशोधन था। सोवियत की यह भी भाव थी कि पोलैंड की सीमा पश्चिम की ओर बढ़ा दी जाए और पूर्वी दिशा और साइलेसिया ही नहीं अपितु पोमरेनिया और वे-डनवग की छोटी की जमनी से खाली करा दिया जाये और बदले में पोलैंड को जमनी के भाग दिए गए।²¹

पोलेण्ड के द्वार में यह भी तय हुआ कि बहुत राष्ट्रीय एन्तर की अस्थायी सरकार शीघ्र स्थापित की जाएगी। अभी भी पश्चिम के मित्रों का ख्याल था कि पूर्वी यूरोप रूसी सेनाओं की उपस्थिति के बावजूद उनके अपने निकट से बाहर न हो पायेगा अर्थात् पूजीवादी दुनिया का अंग बना रहेगा। पोलैंड में सोवियत सम पित लुबालिन सरकार गठित हो चुकी थी, पर अग्रज सदन में एक प्रतिद्वंद्वी पोलीय सरकार बनाया बैठे थे। अग्रज अपने शरणाधियों को बेसहारा करने की तैयार न थे। बहुत जद्दजहद के बाद यह तय हुआ कि पोलीय सरकार पुन गठित की

जाए। जिसमें पोलैंड के अंदर और बाहर, दोनों तरफ के पोल नेता उसमें शामिल हो और जैसा ही संभव हो सके, एक निर्वाध चुनाव पूर्ण व्यवस्था मताधिकार के आधार पर कराया जाए। इस चुनाव में सभी लोकतंत्री और नात्सी विरोधी दलों को चुनाव प्रचार करने का अधिकार मिले और गुप्त मतदान की प्रणाली अपनाई जाए।

या कुर्यात म्युनिख सम्मेलन पर ब्रिटेन जो हमेशा के लिए छोड़ चुका था, उसे पुनः हथियान की चप्टा चलती रही। स्तालिन की भाग थी कि पोलैंड की सीमा नीस ओडर नदी-तट तक लाई जाए ताकि न केवल पूर्वी दिशा बल्कि समूचा साइबेरिया, तथा पामेरिनयन और ब्रे-डनवग का सिरा इसमें शामिल हो सके जिसमें स्टेटिन भी पोलैंड के पास रहें।

पोलैंड के बारे में स्तालिन ने बड़े मामूली ढंग से कहा "रूसी लोगों के लिए पोलैंड का प्रश्न केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं रहा है, बल्कि वह सुरक्षा का प्रश्न रहा है। समूचे इतिहास में पोलैंड के गलियारों से होकर ही शत्रुता ने रूस पर घाई की है। पिछले तीस वर्षों में दो बार, हमारे दुश्मनों ने, जर्मनों ने इसी गलियारे का इस्तेमाल किया है। यह रूस के हित में होगा कि पोलैंड सुदृढ़ और शक्तिशाली हो, उसमें ऐसी समझ हो कि अपने बलवृत्त पर गलियारे बंद रख सके—यह आवश्यक है कि पोलैंड मुक्त और अपनी सत्ता में स्वाधीन हो। इसलिए सोवियत राज्य के लिए केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है बल्कि, जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।"

पोलैंड का मामला बर्चिल के लिए अहम सवाल बन गया था आखिर म्युनिख सम्मेलन करने के बाद पोलैंड को लेकर ही तो अंग्रेज लड़ाई में कूद थे पर उधर स्तालिन का भी जबदस्त आग्रह था कि अतीत में सदा पोलैंड वह गलियारा रहा है जहाँ से आक्राता रूस पर हमला करने आये थे। पिछले तीस वर्षों में दो बार पोलैंड के रास्ते रूस पर हमला हुआ था। वह अब किसी भारी आक्राता को

पोलैंड के रास्ते" से आगे न आने देने के लिए कटिबद्ध थे और इसके लिए वे दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि पोलैंड स्वाधीन रहेगा, मजबूत रहेगा पर ऐसा ही रह सकेगा जो सोवियत के दुश्मन और सोवियत के लिए सदा ही भिन्न रहने वाला देश। सोवियत नेता अब सुरक्षा के इस प्रश्न पर किसी तरह की गफलत में पड़ने का तैयार न थे।

मुक्त यूरोपीय क्षेत्रों के संबंध में

यही बात और भी खुलकर उन यूरोपीय क्षेत्रों में लागू हुई जिन्हें रूसी लाल सेना मुक्त कर चुकी थी या मुक्त करने की प्रक्रिया में थी। याल्टा में यह तय हुआ कि इन क्षेत्रों में नात्सी फासी शक्तियाँ समूल नष्ट की जायेंगी और एटलांटिक

चाटर के अनुसार यहा नात्सी विरोधी तथा लोकतन्त्री शक्तियो का मजबूत किया जाएगा और लोकतन्त्र की स्थापना की जायगी। ब्रिटेन व अमेरिका एक ओर, सोवियत संघ दूसरी ओर, लोकतन्त्र की अपनी अपनी परिभाषा अपन पास ही रखे रह, जो जब इन क्षेत्रों में व्यवहार में उतारी जान लगी तो विवाद उठ पड़े हुए। इसका मुख्य कारण यह रहा कि पश्चिमी मित्र राष्ट्र लोकतन्त्र के नाम पर अपने ढंग की पूँजीवादी व्यवस्था और उसको पनपान वाला उठारवाली संसदीय लोकतन्त्री व्यवस्था को यहा जमान की मंगा रखता था। इस प्रकार की व्यवस्था यहा, चेकोस्लावकिया को छाड़कर अन्य जगहों पर कही पहले भी न थी, न अब बच रही थी। पर याल्टा में अभी भी लोकतन्त्र की स्थापित करने की उम्मीद अभी भी बांधे रहा।

युगोस्लाविया के संघर्ष में

यहा माशल टिटो की मुक्तिवाहिनी नात्सी सत्ता का जमकर मुकाबला कर रही थी तेहरान सम्मेलन में स्टालिन ने टिटो को मित्र राष्ट्रों की और सहायता पहुँचाने का आग्रह किया था अब सच्चाई निर्णायक दौर में पहुँच चुकी थी। यहा यह तय हुआ कि टिटो और सुवासिच के बीच सम्पन्न हुए समझौते के अनुसार नई सरकार का गठन किया जाए। स्टालिन एवं चर्चिल के बीच 50/50 प्रतिशत प्रभाव की मात्रा के बंटवारे का यह पहला फल था।

यूरोप अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के बारे में सोवियत के तीन सदस्य व तीन मत

याल्टा में तीन बड़ों ने युद्ध के बाद वैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ढाली जाए इस पर मुरझाते चिन्तन मनन किया। डायटन ओक्स में बातें पहले हो चुकी थी। उन्हीं सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए यह तय हुआ कि सोवियत संघ के दो गणराज्यों को—यूक्रेन और बाइसोरेस्त्रा को को अलग से सदस्यता दे दी जाए—यद्यपि स्टालिन लिथुआनिया को भी सदस्य बनवाना चाहते थे। सोवियत नेता संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना घजन बढ़ाना चाहते थे। अमेरिका इस मानने से हिचक रहा था पर ब्रिटेन हिंदुस्तान और अपने उपनिवेशों को ध्यान में रख इस माना बढ़ि का समर्थक बन गया जिससे सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ में तीन 'मत' प्राप्त हो गए, इसी प्रकार ब्रिटेन को अपने उपनिवेश व डोमोनियनों के अमेरिका ने भी तीन मत मंगे। स्टालिन इसके लिए राजी थे पर अमेरिका ने इस मांग को छोड़ दिया। उनके पास लातिनी अमेरिका के 21 राज्यों के अधिकांश मत पहले से ही जेब में थे।

निर्णायक अधिकार

अमेरिका याल्टा में संयुक्त राष्ट्र संघ के संघर्ष में अंतिम रूप से समझौता

चाहता था। पर संयुक्त राष्ट्र सभ के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा निषेधाधिकार को लेकर उठ रही थी। डावटन ओक्स में सोवियत सभ ने जोर देकर कहा था कि निषेधाधिकार की शक्ति पूरी तरह से और निर्वाचन रूप से रहनी चाहिये अर्थात् सोवियत सभ या पांच में से किसी भी बड़ी शक्ति के हित के विरुद्ध कोई भी कार्य वाही संयुक्त राष्ट्रसभ के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। पर संयुक्त राष्ट्र सभ के मंच से बड़ी शक्ति के विरुद्ध बारंबार पर निषेध मान लिया गया, यह नहीं माना गया कि 'बड़ी शक्ति' के सबब में चर्चा पर ही निषेध लगा दिया जाए जैसा सोवियत चाहते थे।

याल्टा में यह निश्चय हुआ कि 25 अप्रैल सन 1945 को सान फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाए और इसमें वे सभी राष्ट्र आमंत्रित किए गए जिन्होंने 1 मार्च सन 1945 तक जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी हो।

याल्टा सम्मेलन एक अध्याय का अन्त

बड़ी शक्तियों के मध्य वार्ता के क्रम का रास्ता याल्टा से सीधे सान फ्रांसिस्को पहुँचा जहाँ संयुक्त राष्ट्र सभ के विधान के बारे में विचार विमर्श का अंतिम दौर चला। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के शुरू होने के पूर्व एक दुघटना घट गई और वह दुघटना थी अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति रूजवेल्ट का 13 अप्रैल सन 1945 को निधन होना। यह एक ऐसी क्षति थी जिसकी युद्धोत्तर काल में फिर क्षतिपूर्ति न हो सकी और जिसकी वजह से मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध काल में निमित्त आपसी सौहार्द, विश्वास एवं सहयोग का माहौल ज्यादा देर तक टिका न रह सका। अमेरिका में रूजवेल्ट के उत्तराधिकारी के तौर ट्रूमैन ने राष्ट्रपति पद का भार संभाला। उप राष्ट्रपति बनने के पूर्व व. सिनेट में डेमोक्रेटिक दल के नेता थे। युद्धोत्तरकाल की समस्याओं से निबटने के लिए सिनेट से सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्होंने ट्रूमैन को अपना साथी चुना था ताकि ट्रूमैन के सिनेट्रीय नेतृत्व के अनुभव का पूरा लाभ उठाकर सिनेट के हाथों राष्ट्रपति विस्सन वाले दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार को बचा ले जाए। पर ट्रूमैन एक दूसरे ही ढंग के नेता थे, स्वभाव की दृष्टि से भी, शैली और नेतृत्व की क्षमता की दृष्टि से भी। सिनेट के एक नेता की हैसियत से सोवियत के विरुद्ध युद्ध छिड़ते ही उन्होंने सुझाया था।

'यदि हम यह पाये कि जर्मनी लड़ाई जीत रहा है, तब हमें रूस की मदद करनी चाहिए और यदि रूस जीत रहा हो, तब हमें जर्मनी की मदद करनी चाहिए और इस ढंग से व. एक दूसरे को जितना मार सकें हम उन्हें करने दें।' 13

यही महाज्ञानी सिनेटर महोदय रूजवेल्ट ने उत्तराधिकारी बन पर तब तक रूस और जर्मनी के बीच का महायुद्ध निष्पादन दौर पर पहुँच चुका था और पिटी

पितायी जर्मन नात्सी शक्ति को मदद कर सतुलन बनाने का सपना हवा हो चुका था। उल्टा रूस जीत रहा था, और ट्रूमैन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि सीमित क्षमतावाले इस नेता को विश्वास में लेकर रुजवेल्ट युद्धकाल की मित्रराष्ट्रीय उपलब्धियों और एकता और सहयोग की समस्याओं से अवगत नहीं करा सक। उनका नया कार्यकाल शुरू ही हुआ था कि वे चल बसे। रुजवेल्ट के हाथों प्रशिक्षण के अभाव में अपन स्वभाव और बौद्धिक क्षमता की सीमाओं के अतगत, भारी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ते ही, युद्धकालीन और युद्धोत्तर समस्याओं की पेचीदमियों और दारिक्रियों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के बजाय ट्रूमैन को जो सहज रूप सह ही सूझा वह था। युद्धकाल के अपने मित्र और सहयोगी सोवियत संघ के विरुद्ध मुठठी तान लेना। वे स्टालिन के बरिष्ठ सहयोगी मोलोटोव को इस नए रुझे अमेरिकी नेतृत्व का स्वाद चखाने से तब बाज नहीं आये। मोलोटोव मास्को से सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचते ही ट्रूमैन के प्रति अपना रुझाव प्रकट करने के लिए उनसे मिले। अपनी इस पहली मुलाकात में ही पोलैंड के प्रश्न को लेकर मोलोटोव को बुरी तरह झटाने की घटना को ट्रूमैन ने बड़े मिश्र मसाले के साथ अपने सस्मरण में याद किया है।¹⁰⁴ स्पष्ट है कि मोलोटोव इस झटके को सुनने के लिए नहीं आए थे।

ट्रूमैन ने मोलोटोव से अमेरिका की ओर से यह आरोप लगाते हुए नाराजी प्रकट की कि वे (रूसी) पोलैंड के बने में हुए याल्टा सम्झौता को फिर से लागू नहीं कर रहे हैं। बात जिस ढंग में कही गई वह ढंग कोटि के राजनयिक नेताओं के बीच कभी नहीं अपनाया जाता जिसमें 'क्षिष्टता और मददता का कतई लेप ही नहीं था।¹⁰⁵

यह अशिष्ट "झाड़ झड़प" 23 अप्रैल 1945 को घटी थी। अमेरिका अभी भी गरजमंद था कि सोवियत संघ यूरोप की लड़ाई खतम होते ही जापान के विरुद्ध युद्ध में फूट पड़े। बात यही नहीं रुकी। गरम मिजाजी के दौर में आगे चल कर तुरंत ही 'उधार पट्टे' की बही बंद करा दी। प्रशासक ट्रूमैन के पास इस आग्रह की आदेश का प्रारूप लाए और उन्होंने बिना उसे पढ़े तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए युद्धवास से चली आ रही 'उधार' की जाने वाली यह मदद तुरंत रूस और यूरोप के मित्रों को बंद कर दी गई। बाद में यूरोप के मित्रों के विरोध पर इस आदेश को रद्द कर दिया गया और ट्रूमैन का इस सिलसिले में अपना बयान यह रहा कि यह आदेश रुजवेल्ट के समय में ही तैयार हो चुके थे और उन्होंने ठीक वैसे ही बिना इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे।¹⁰⁶ उधार पट्टा फिर से कुछ समय के लिए चालू हो गया पर भावनात्मक ढंग से जो चोट पड़नी थी वह युद्धकालीन मित्रता पर पड़ ही गयी।¹⁰⁷

इस प्रकार याल्टा सम्मेलन समाप्त हुआ। यह युद्धकालीन अंतिम सम्मेलन की

तुलना मे अधिक महत्त्वपूर्ण एव अधिक मफस सम्मेलन रहा। समय की बात है कि उन तीन बड़े राष्ट्राध्यक्षों के मध्य यह अंतिम सम्मेलन सिद्ध हुआ जिन्होंने पिछले चार वर्षों में मिलजुलकर सहयोग और सौहार्द्र तथा सौमनस्य के नये कीर्तिमान स्थापित किये। इसमें गुप्त भेंटनायें हुई, गुप्त समझौते हुए और मतभेद और शकाए सदेहा को दूर करने की कुल मिलाकर सफल प्रयत्न हुए। यह सम्मेलन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के जीवन काल का अंतिम सम्मेलन सिद्ध हुआ क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनके उत्तराधिकारी उप-राष्ट्रपति ट्रूमेन ने ली।

घाल्टा समझौते की आलोचना (बिन्नो तारी कितनी मोवली)

कालान्तर में जिन प्रकार सौहार्द्र और सौमनीयता का वातावरण लक्षित हुआ और "ग्रीनयुद्ध" भड़क उठा उस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को उठाते हैं कि यदि रूजवेल्ट की इस प्रकार दुनिया के रंगमंच से बिदाई न हो गई होती तो मित्र राष्ट्रा व ग्रीन सौहार्द्र और सौमनस्य के पुल इस तरह टूटते नहीं और मित्र राष्ट्रों के बीच चला आ रहा युद्धवासीन महामाज जारी रहता। वगैरे तो यह प्रश्न दुनिया भर के इतिहास में उठे, "यदि ऐसा हुआ हो तो" कोटि का प्रश्न है और इस अर्थ में निष्पक्ष है, पर यदि इस प्रश्न से कल्पना अगत में उलझा ही जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह अनुमान अज्ञात ही सही घटना। राष्ट्रपति रूजवेल्ट एक अत्यंत प्रभावशाली राष्ट्रपति थे जिन्होंने तीन बार चुनाव जीतकर एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया था (इसी वजह से वहां संविधान में संशोधन की यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति दो बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है) वे युद्धकाल में ही तीसरी बार चुन लिए गए थे इसलिए वे सन् 1949 तक राष्ट्रपति पद पर होते। वे अत्यंत व्यग्रता से युद्ध और राजनीतिक तौर पर दक्ष नेता थे इसलिए युद्धोत्तर परीक्षा का गुलनाम भी सकते थे। पर सवाल यह है कि क्या कोई भी नेता, जय ही वह रूजवेल्ट हो, या स्टालिन हो, अपनी समाज व्यवस्था अपने प्रतिपक्ष के द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं का अनिवार्य रूप से अनुसरण कर सकता है। रूजवेल्ट अपने अन्तर्गत समाज और उसके वर्गों की अपनी सहज सीमाओं को आगे की गतिशीलता में रखा। यह युद्धकाल में कहा जा सकता है। युद्ध में युद्ध के पहलू आगे की गतिशीलता के दृष्टिकोण से, युद्ध से बटकर चलने की नीति में, निरन्तरता और गतिशीलता के बीच आजादी के मामले में युद्ध युद्ध के पहलू में ही आजादी के पहलू में उठाने कहा ऐसा बहस उठाना आजादी के पहलू में आजादी के पहलू में उठाने कहा जा सकता है। या तो यह आजादी के पहलू में आजादी के पहलू में उठाने कहा जा सकता है।

मेंट किए थे। इतना ही नहीं, वे चर्चिल के साम्राज्यवादी हिता की भी आघात पहुँचाने को तैयार न थे। वस्तुतः बहुत कुछ वे उनसे सुरताल बैठाकर ही चलते रहे। उल्टा यह कि पूर्वी यूरोप के मसला को निबटाने, उसके वार में चर्चिल, स्टालिन के बीच समझौते के वे विरोधी रहे। पोलैंड का मसाला हो, या जर्मनी का उसमें वह कोई समझौतापरस्त नीति के हामी न थे। पर लफ़ेमिंग के इस कथन से सहमति प्रकट करने में हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि यदि राष्ट्रपति रूजवेल्ट युद्धोत्तर समस्याओं को सुलझाने के लिए उपस्थित होते तो अन्य पक्षों की ओर से एक दूसरे के प्रति इस सावधानी के साथ व्यवहार किया जाता और सम्भवतः शीतयुद्ध भड़क पड़ता। कहा जा सकता है कि कम से कम उसका यह स्वरूप तो न बनता जो टूमेन के हाथों हुआ।

यह एक बेकार की अमेरिकी बकवास है कि रूजवेल्ट याल्टा के दिनांकण थे। इस कारण याल्टा के समझौते इस प्रकार हुए और अमेरिकी हित सट्टाई में पड़ गए। रूजवेल्ट हो या चर्चिल, यह कोई युवा नेता न थे, ऐसा न था कि युद्ध के पूर्व बहुत 'स्वस्थ' रहे हो, युद्ध के दौरान, खासकर याल्टा में बीमार पड़ गए हों, और कमजोरी की हासत में इस प्रकार नासमझी दिखा गए हों। अगर याल्टा पहले के समझौते नासमझी के दृष्टांत न थे तो याल्टा के समझौते तो अमेरिकी साम्राज्यवादी हितों की दृष्टि से कतई नुकसानदेह समझौते न थे। वस्तुतः इससे अधिक लाभप्रद समझौते और हो ही क्या सकते थे, उस समय जबकि सोवियत संघ संकट की विचराल घड़ी को ठेल कर पोलैंड तक आ गया था और जर्मनी की घेरावदी शुरू हो चुकी थी। दूसरा मोर्चा खोलने में विलम्ब करने सोवियत सत्ता की और अधिक बुर्जुानी के लिए बाधक किया जा सकता था पर सोवियत सालेनेना ता एक अजेय शक्ति की तरह बढ़ती ही जाती और यूरोप का मानचित्र कुछ और दूसरा भी हो सकता था। यूनान में कम्युनिस्ट कमजोर न थे। याल्टा का समझौता द्वारा स्टालिन ने यूनान की भेंट चढ़ा दी थी और अग्नेजों की भूमध्य सागर और उसके रास्ते अपने अधीन रखने का अवसर सौंप दिया था। फिर जब तक जापान सोवियत अनाक्रमण संधि बरकरार थी, अगर आग्ल-अमेरिकी युद्ध बनता और हिटलर के उत्तराधिकारियों से साठ-गाठ कर 'दूसरे मोर्चे' की जगह कुछ दूसरे प्रकार की दुरभि-संधि सम्पन्न होती, तो सोवियत का गठबन्धन जापान को अमेरिका के आगे घुटने टेकने न देता। अमेरिका का मुख्य स्वाय पूर्वो एशिया में था यूरोप में उतना नहीं जापान ने ही अमेरिका का युद्ध में सा पसीदा था।

सारांश यह कि याल्टा समझौता की युद्धोत्तर अमेरिकी आलोचना बेमानी और शीतयुद्ध की तिरदाजी मात्र है। याल्टा का पूर्व के मित्र राष्ट्रों के युद्धकालीन साहचर्य और सहयोग का वह महज परिणाम था। वह इसलिए सहज रूप से घटा चूक, उमड़-पूब का घटनाचक्र इसी विश्वास में महयोग को मोड़ रहा था। जैसा

ल्फोमिंग ने ठीक ही लिखा है कि याल्टा के आलोचक उस मित्र को "आज की हालत में पीछे मुड़कर देखते हुए गड़बड़ा देते हैं और उन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते जिनके अधीन याल्टा में एकत्र हुए समर साधियों ने बातचीत और समझौते किये थे।³⁹ 25 जुलाई सन् 1945 को अर्थात् अणुबम फेंके जाने से कुछ ही पूर्व और याल्टा के बाद, विसकोसिन के अमेरिकी सेनेटर अनेकजेंडर विली ने अपने एक भाषण में इस से मार्मिक अपील करते हुए कहा, "लाखों अमेरिकी घरों में, मातायें, पिता और प्रेमी युगल बेसब्री से इस क इरादें बताने वाली खबर का इंतजार कर रहे हैं। वे यह जानते हैं कि यदि इस न युद्ध छेड़ दिया (जापान के विरुद्ध), यदि उसके बमबर्षक युद्धपात ब्लाडीवास्टक से जापान के विरुद्ध घबराकर बाहर निकल आयेंगे, तो ये कायवाहिया जापान का घुटने टेक देने के लिए अंतिम कायवाहिया सिद्ध होगी। इस प्रकार इस के निणय पर अनगिनत अमेरिकियों के जीवन टग हुए हैं। जब हम यह चाहते हैं कि सुदूरपूर्व में इस अपना युद्ध भार उठाये, तब हम नहीं चाहते कि कोई यह कह कि हम उसके धरलू मामला में दखल दे रहे हैं—मैं एक अमेरिकी सेनेटर होने के नाते रतव्य च्युत होने का दोषी ठहराया जाऊंगा, यदि पूरे विनय के साथ अपनी सारी ताकत के साथ लाखों अमेरिकियों के दिल की इस आशा को बुरा न करूँ कि प्रशांत में इस कृपया अपनी भूमिका अदा करे।"⁴⁰

स्टालिन के इस ने अपना याल्टा का वचन निभाया। यूरोप में लड़ाई खतम होने के तीन महीने के अंदर जापान सोवियत अनाक्रमण संधि को समाप्त कर जापान पर हमला कर अपनी मित्र राष्ट्रीय पक्षधरता का सुदृढ प्रमाण प्रस्तुत किया।

सारा झगडा, ऐसा कहा जाता है कि पोलैंड और दूसरे क्षेत्रों में युद्धोत्तर "लोकतन्त्रीय व्यवस्था" की स्थापना को लेकर उठ रहा था। स्थिति यह थी कि पूर्वी यूरोप में लाल सेना भारी कुर्बानी देकर प्रभावशाली ढंग से उपस्थित थी। स्टालिन को विश्वास था कि मित्र राष्ट्र फासी व नात्सी तत्वों को समूल नष्ट करने में उनके साथ हैं। उनको यह आशा थी कि वे गैर साम्यवादी तत्व जिन्होंने फासी व नात्सी दमनचक्र को साम्यवादियों के साथ साथ फेला है, वे युद्धोत्तर व्यवस्था में साथ रहेंगे। एन एच प्रयोग के लिए स्टालिन व उनके साथी तैयार थे। यही "जनता के लोकतन्त्र" का उनके लिए अर्थ था, पर यह सब सहयोग के आधार पर ही सम्भव था। अमेरिका व उनके साम्राज्यवादी साथी, वह बाजी लोकतन्त्र की पश्चिमी शैली के माध्यम से जीतना चाहते थे जिसे वह म्यूनिख तथा युद्ध में पहले ही हार चुके थे। "लोकतन्त्री" चुनाव के नाम पर इसी लाल सेना एक सजी सजायी तबतरी में उह पूर्वी यूरोप फिर से मेंट कर दें, यह मांग एन उभर रहे माहौल का सकेत द रही थी जिसमें युद्धकालीन मेत मिलाप

य विद्वत्ताओं को दफनाते की तैयारी हो चुकी थी और स्ट्रॉसबर्ग के विद्वत्ता व धर्म प्रवक्ता किंग गार्ड "सेनबधु" की कायवाहिया की जमीन हिलाई जा रही थी।

डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन अगस्त 21, 1944 स सान फ्रांसिस्को (25 अप्रैल सन् 1945-26 जून सन् 1945) समुक्त राष्ट्र का निर्माण—

युद्धकाल के दौरान, युद्धसंचालन के साथ साथ जो सबसे बड़ा रचनात्मक काम मिन राइटो में शुरू किया था वह था समुक्त राष्ट्र के रूप में एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नींव डालना ताकि, युद्ध समाप्त होत ही, वह मृत राष्ट्रमण्डल का स्थानापन्न बन सके और उसके उन दोषों और निबलताओं से मुक्त हो, जिसके कारण राष्ट्रसंघ जनमते ही पगु बन गए थे और अपने पूरे कार्यकाल में सभी लोकप्रिय नहीं बन सके थे। जाहिर है कि एक मजबूत और सम्पूर्ण बड़े राष्ट्र के रूप में अमेरिका में इसकी सख्त काफी विचार मयन चल रहा था पर ऐसा संगठन की नितान आवश्यकता की अनुभूति सबत्र थी। मोक्षियत सभ में बन्मुनिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भग कर दिया था और वे भी ऐम एक सबप्रिय और सब सेवी संगठन के पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने शुरू से ही इन सम्मेलनों में रुचि पूर्वक भाग लिया। जब अगस्त 21 1944 को डम्बर्टन ओक्स में यह सम्मेलन हुआ, तो अमेरिकी सभी और प्रितानीय तीना बड़े देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से मतविवाद रखे और खुलकर बहस में भाग लिया और आदाजनक बात यह थी कि इन तीनों में कोई गंभीर और तात्त्विक मतभेद न था। रूस की ओर से यह भाव की गई कि उसके सोलह के सोलह जातियाँ की सहायता दी जाए जिस पर आपत्ति हुई पर एक नये आधार स्तम्भ की तरह, समुक्त राष्ट्र की कायवाहिया में भागीदार होने के पूर्व रूस अपनी स्थिति को समुक्त राष्ट्र की लोक व्यवस्था में पहल से ही कमजोर करके नहीं चलना चाहता था विशेषतः ऐसी स्थिति में जहाँ बहुसंख्यक समुक्त राष्ट्र के भावी सदस्य पूँजीवादी देशों के प्रतिनिधि होने वाले थे। इसी बात को लक्ष्य कर निषेधाधिकार का प्रश्न भी उठा यास्टा में यह मान लिया गया था कि तीन बड़े के विरुद्ध कोई कायवाही की बात हो तो उसे रोकने के लिए निषेध का अधिकार बड़े को मिलेगा पर अगो के साथ विवाद से ऐसा अधिकार नहीं रहेगा। यह सुझाव मान लिया गया।

डम्बर्टन ओक्स के बाद इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था सान फ्रांसिस्को सम्मेलन जो 25 अप्रैल सन् 1945 से शुरू होकर 26 जून 1945 तक चलता रहा। इस सम्मेलन में शुरू होने के 13 दिन पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई जिसने युद्धकालीन सहयोग और सौहार्द की निरंतरता पर कुछ व्याघात डाला कुछ शकाएँ, कुछ सदह जो दब गए थे, सिर उठाने लगे, कुछ नयी पेचीदगियाँ दिखाई देने लगी। फिर भी यह सम्मेलन पूर्व निश्चित ढंग से सम्पन्न हुआ।

इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के 'चाटर' का निर्माण और उसकी स्थापना का कार्य सम्पन्न करना था। इसमें भाग लेने के लिए 46 देशों को आमन्त्रित किया गया जिनकी ओर से 850 प्रतिनिधि शामिल हुए। बाद में 4 राज्यों को और आमन्त्रित किया गया बाद में इसमें पोलैण्ड को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार 51 राज्यां न सम्मेलन में हिस्सेदारी की रूसी और अमेरिकी नेता काडल हस व विरोध के बावजूद फासी अर्जेन्टाइना को सदस्य बना दिया गया—मतदान के बाद सम्मेलन में मुख्यतः तीन बड़ी ताकतों का दबदबा रहा और सम्मेलन से पारित हुए 'चाटर' पर इन तीन बड़ों के प्रभाव की छाप स्पष्ट थी। चाटर के प्रावधानों पर खूब बहस हुई, विवाद उठे, समाधान सुझाये गये और अन्ततः 'चाटर' सब सम्मति से स्वीकृत हुआ जिस पर 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर मित्र राष्ट्रों की युद्धकालीन मित्रता सहयोग और परस्पर विश्वास और आशा को संयुक्त राष्ट्र की रचना के रूप में सारूप कर दिया।⁴⁰ ऐसा लग रहा था कि मानवता के इतिहास में एक स्वस्थ अध्याय जुड़ने जा रहा है और अब से युद्ध फिर कभी न होंगे।

मई का महीना आ रहा था। दुर्दांत जर्मन नात्सी सेना ने मित्र राष्ट्रों के आगे घुटन टेक दिए। सोवियत की ओर से जनरल जुकोव व आगस्त अमेरिकी पक्ष से जनरल आइसन हावर ने मित्र राष्ट्रों के सेनापति की हैसियत से जर्मन सेना का समपण स्वीकार किया। यूरोप में युद्ध का अंत हो गया।

पोट्सडम सम्मेलन युद्धोत्तर यूरोप के निर्माण की ओर (17 जुलाई 1945—2 अगस्त 1945)

नात्सी जर्मनी ने हार मान ली। आत्म समर्पण कर दिया। यूरोप में महायुद्ध खतम हो गया। महायुद्ध बच रहा। एशिया में सैन्यवादी जापान के विरुद्ध अमेरिका के लिए कहीं विकट युद्ध था। अमेरिका को इस महायुद्ध में घसीट लाने वाली लड़ाई थी ही जापान के विरुद्ध छेड़ी गई लड़ाई नहीं तो अमेरिका तो मजे से 'इस हाथ डॉलर दो उस हाथ हथियार लो' की नीति पर चल रहा था। इस बीच जहाँ यूरोप की लड़ाई खतम हो चुकी थी, और सोवियत सत्ता भारी कुबानी के बावजूद अब अभूतपूर्व हर्षोल्लास से नात्सी फासी शक्तियों पर विजय का पर्व मना रही थी अमेरिकी सत्ता की चिन्ता का अभी भी अंत नहीं हुआ था। ऊपर से नेतृत्व का एक संकट भी पैदा हो गया था—रुजवेल्ट की मृत्यु के कारण। ट्रूमैन ने उनकी जगह भर तो दी पर वे बहुत मायने में नौसिखब थे और रीतिनीति में तथा सोच विचार में भूतपूर्व राष्ट्रपति से बहुत कम मिलते जुलते थे। जैसे-जैसे समय बीता यह बात स्पष्टतर होती गई और इस विवाद को जन्म दे बैठी कि यदि रुजवेल्ट इस प्रकार असमय में ही काल नवलित न हुए होते तो "शीत युद्ध"

के रूप में जो घटा, वह था तो घटता ही नहीं था बहुत बितबग घटता। पान्ग म स्टालिन ने कहा था 'व सभी यह जाना है कि जब तक व सीता त्रिग रहेंगे कोई भी उन्हें आक्रामक कारवाइया में नहीं डालेगा। वेबिन हम बगैर बाद शायद उनमें से कोई 1 रह पाएगा। एक मई पीढ़ी उपजगी त्रिग युद्ध की विभिन्नता का कोई अंदाज ही न होगा। इंगलैंड यह उारी अपनी जिम्मेदारी है कि वह ऐसा संगठन बनाय जो कम से कम पचास वर्ष के लिए शांति का गुराणित कर लेंगे।' ॥

कम से कम पचास वर्ष की शांति व्यवस्था

इस प्रकार की शांति व्यवस्था जो कम से कम पचास वर्ष चल सके—नई पीढ़ी के लिए बनाने का उपजम संपुक्त राष्ट्र के निमाण के रूप में हुआ और युद्ध समाप्त होते ही पोद्सडम के सम्मेलन में युद्धोत्तर यूरोप का नक्का पसा दिये इसके बारे में विमर्श हुआ। आपसी झगड़े छुट-पुट हो रहे थे पर हम तो पहले भी चले। आज की दृष्टि से न दगें, तो तब ऐसा नहीं लग रहा था कि मित्र राष्ट्रों में कोई दरार पड़ने जा रही है। तीन सुपरिणित बड़ा में एक उठ गया जो बत्रया स्टालिन और चर्चिल के बीच सम्म्यस्यता करता था और 'जिसके बडप्पन का दोना ह्याल करते थे। पर जब जमनी के पोद्सडम में फिर भी तीन बड़ा व बीच बातचीत हुई तो रुजवेल्ट के उत्तराधिकारी की पावर स्टालिन को ऐसा कुछ नहीं लगा कि रुजवेल्ट का अभाव कोई बड़ी आपत्ति को निमगण दे रहा है बल्कि जल्दी ही दोनों एक दूसरे को पसंद आ गये, ऐसा कुछ आभास हुआ।

जब सम्मेलन शुरू हुआ तो इस एक बात पर तो तुरत रजामदी ही गई कि (1) बड़ी दक्षिणियों के परराष्ट्र मंत्रियों की एक परिषद निर्मित की जाए जिसके जिम्मे शांति संधियों की रचना आदि काम छोड़ दिया जाए। इसके बारे में सहमति हो जाने के बाद फिर शतरज के दावपव की तरह बातें गुरु हुई। शुभभात हुई अमेरिकी प्रतिनिधियों की ओर से जिन्होंने आरोप लगाया कि बुलगारिया या रूमानिया के मसले में सीना बड़ा की सम्मिलित कायवाही की जो बात याल्टा में सय हुई थी वह नहीं निभाई जा रही है। रूस की बारस उत्तर तैयार था कि यूनान में इकनरफा कायवाही अप्रेज करते ही जा रहे हैं और बड़ी ज्यादातिया कहा हो रही हैं और इटली के मामलों में तो सोवियत संध को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। बात सच यह थी कि जहा जिसकी सेना काबिज था, वहा दूसर को हिस्सा देने का सवाल ही नहीं उठता था, याल्टा में हुआ हो, दो और बातों पर मतमुटाव हुआ। पहली बात थी रूमानिया में जो अमेरिकी तथा ब्रितानी सम्पत्ति के रूप में जा उछाम थे, उन्हें रूसिया ने जमना की सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होने के नाते, अधिग्रहण कर लिया और उसे लौटाने का सवाल ही रूसियों की नजर ॥

नहीं उठता था। दूसरी बात थी रूसियों की ओर स माग की कि उपनिवेशों की बदरबाट में उन्हें भी हिस्सा मिले। अफीका में इटली के एक उपनिवेश को यास के रूप में चाहते थे। कैंसी बिडम्बना थी कि महान लेनिन के रूस को जिसन फिन लेण्ड लौटा दिया था, अबटूबर त्राति के उस रूस को जारशाही के सहजे में बाँटें करते मुनना जो राष्ट्रा के आत्म निणय का और मानवता की अंतिम भुक्ति का स्वर बुलंद किए रहा। युद्धोत्तर उभरे समाजवादी खेमे के द्वारा दिया जा रहा अपना पहला और नया युद्धोत्तर परिषय मह भी था। चीन के प्रदक्ष प्राप्त करने की गुप्त समझौते वाली घृणित साम्राज्यवादी दुर्नीति की कैंसी युद्धोत्तर परिणिति थी यह। यह सोवियत सत्ता के लिए अच्छा ही हुआ कि आग्ल अमेरिकी गुट ने शीत युद्ध छेड़ दिया और सावियत सत्ता फिर त्राति के बोस बोलने लगी, अथवा अगर चर्चिल ट्रूमैन स्तालिन को बगलगीर बनाकर बदर बाट में हिस्सा लेने को तैयार हो जाते, तो कामरड स्तालिन को हम जार "स्टालिन" के नय सस्करण में देख पाते। रूसियों ने तुर्की से दा प्राप्त लौटान की माग रखी। स्तालिन साहिब उस जमीन का चप्पा चप्पा वापस ले आना चाहते थे जो कभी जारशाही की शान था।

शांतिप्रिय अमेरिकी लेखक अपने नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि इतना अच्छा अवसर अवसर लेनिन के शिष्य को राजी करने का और शांति की व्यवस्था करने का उन्होंने अपने हाथों गवा दिया। इटली के एक उपनिवेश दे देने पर, तथा भूमध्य सागर में रूस को आ जाने देने से क्या बिगड़ जाता। बात शायद बन जाती और मिली भगत का युग चल पड़ता।⁴³

इस बीच ब्रिटेन में नये चुनाव की बात आ गई। युद्धकालीन मिलीजुली सरकार को चर्चिल यूरोप में युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ दिना और चलाना चाहते थे, पर लेबर दल राजी न हुआ इसलिए युद्ध खतम होत ही चुनाव कराने पड़े। पोट्सडम की वार्ता कुछ समय के लिए स्थगित रही। ब्रिटेन के चुनावों में चर्चिल का दल हार गया और लेबर दल न भारी विजय प्राप्त कर सरकार बनाने का अवसर प्राप्त कर लिया। चर्चिल इस प्रकार पोट्सडम नहीं लौट पाय। पोट्सडम सम्मेलन में यह दूसरी अनुपस्थिति थी, पर ब्रितानी नीति में ज्यादा परिवर्तन इसलिए नहीं आया चूँकि, नये परराष्ट्रमन्त्री अर्नेस्ट बेदिन युद्धकाल में भी परराष्ट्र मामलों में चर्चिल के एक प्रकार से हमराही ही थे। यही सिद्ध भी हुआ वस्तिक, उनका मिजाज रूसियों के खिलाफ चर्चिल से कुछ ज्यादा ही गरम रहा करता था। इस प्रकार अकेले स्तालिन युद्धकालीन सहयोग और सौहार्द्र की भावना के साक्षी, उत्तराधिकारी तो दो नये 'बड़े' आ गये थे जिनसे साक्षात्कार पहली बार ही हो रहा था और जिन्हें एसा लग रहा था कि रूसी नेता स्तालिन तो 'विजय' का सपना देख रहे हैं।⁴⁴

सैन्य नियंत्रण में ले चुके थे।

(2) जर्मनी के साथ अंतिम रूप में शांति संधि सम्पन्न करने के पूर्व उसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इसके बारे में कुछ राजनीतिक सिद्धांतों कुछ आर्थिक सिद्धांतों, ऐसे ही क्षतिपूर्ति विषयक कुछ सिद्धांतों तथा जर्मन नौ सेना के बटवारे के बारे में तथा जर्मनी के व्यापारिक जहाजों के बटवारों के कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया गया।¹

यूरोप से ही चीन को यूरोप के इन मामलों से दूर रखा गया। यूरोप के “भाग्य नियता” एशिया के मामलों में दखल देने का पूरा अधिकार रखते थे, विजयी राष्ट्रा की पक्ष में शामिल किए जाने के बाद भी चीन इसका अधिकारी न बन पाया कि वह यूरोप के समाधानों में अपना योगदान कर सके।

राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी को वास्तव में तीन, पर व्यवहार में चार क्षेत्रों में बांटा गया—अमेरिकी, ब्रितानी, रूसी और फ्रांसीसी फ्रांस “लुजपुज” था, फ्रांसीसी सैनिकों की बर्दों और हथियार भी आपल अमेरिकी मित्रों की उतारने थे, पर चर्चिल फ्रांस का हक दिला रहा, भले ही फ्रांस का इलाका, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी और अमेरिकी इलाकों में क्षेत्रों लेकर बना दिया गया। इसके नियंत्रण के लिए चार महाशक्तियों के प्रतिनिधियों की एक परिषद की स्थापना की गई।

(3) यह भी निश्चित किया गया कि युद्धोत्तर जर्मनी को पूर्णतः निःशुल्क और सत्ता विहीन किया जायगा और नात्सी समूहों और उनके वानूना को समूल नष्ट किया जायगा। यह तय किया गया कि जर्मनी में लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति स्थापित की जायगी और नागरिक स्वतंत्रताएँ की जायेंगी। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण निणय लिया गया कि उन जर्मनों पर मुकदमा चलाया जायगा जिन्होंने युद्ध में क्रूर और अमानुषिक घातनायें पहुँचायी हैं।

आर्थिक क्षेत्र में जहाँ एक ओर यह तय किया गया कि जर्मनी में शस्त्रास्त्र तथा युद्ध सामग्री के उत्पादन पर रोक लगा दी जायेगी वहाँ यह भी तय किया गया कि उसकी अर्थ-व्यवस्था को एक विकेंद्रीकृत कायव्यवस्था बनाया जायगा और कृषि एवं शांतिकालीन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा। महत्वपूर्ण निणय यह था कि सम्पूर्ण जर्मनी का एक इकाई मानकर चला जायगा, भले ही कब्जा घोर बड़े राष्ट्रों का बना रहे। जहाँ हज़ारों के बारे में यह तय किया गया कि जर्मनी से युद्ध का हर्जाना लिया जायेगा वहाँ यह भी निणय लिया गया कि वह हर्जाना इतना ही कि बिना बाहरी मदद के जर्मनी की अर्थव्यवस्था चलती चले। हर्जाने की रकम के बारे में यह तय हुआ कि सोवियत अधिकृत क्षेत्र में साक्षित मघ हर्जाना ले और बाहरी पूँजी का अधिग्रहण कर ले तथा अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देश पश्चिमी क्षेत्र तथा बाहरी पूँजी से वसूल लें। इनके अलावा यह भी तय किया गया कि शांति कालीन जर्मन अर्थव्यवस्था के लिए अनावश्यक कारखानों से

ट्रूमैन के सस्मरणों से स्पष्ट हो जाता है कि रूजवेल्ट यूगोस्लाविया के युद्धपूर्वक की जाने वाली कूटनीतिक वार्ताओं का जिनमें पर्याप्त मात्रा में शिष्टाचार का निर्वाह किया जाता था, अब गये जमाने की बातें हो चुकी थी। बात बात में ट्रूमैन अपना घबराहट से बोल रहे थे। बस जो बात, जो लिहाज थोड़ा बहुत अभी स्टालिन के लिए बचा था, वह इसलिए बचा था कि रूस को जापान के विरुद्ध "युद्ध का मैदान में उतारना" था। इसने लिए अमेरिकी सैनिक अधिकारी जोर दे रहे थे, पर ट्रूमैन ने अपना मन बना लिया था कि जापान की विजय में रूसियों का योगदान तो होना चाहिये पर "विजय की सूट" में हिस्सा बतई नहीं मिलेगा।¹³

पोट्सडम के समझौते

पोट्सडम के उपर्युक्त महौल में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। सस्मरणों में चाहे जो लिखा हो, पर दो बातें शुरू से ही स्पष्ट थी कि अमेरिकी रूस को जापान के विरुद्ध लाने के लिए चेतावनी दे और रूसिया ने ठीक उस दिन से जिस दिन अतल नात्सी जर्मनी ने धूमने डेक दिए, जापान के साथ हुए समझौते का तोड़ने के लिए कदम रखा। बर्लिन विजय के दूसरे दिन अप्रैल 1945 में मित्र राष्ट्रों की विजय का ऐतिहासिक समाचार छाप—रूसी इस केवल रूस की विजय का रूप में नहीं मना रहे थे, और साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से भी जापान को "समर्पण" करने की चेतावनी भी छपी जिससे यूरोपीय विजय के दूसरे दिन ही जापान के विरुद्ध रूसिया के मन की बात खोली जा रही थी। यकदम इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि रूसी नेता मित्र राष्ट्रों की युद्धकालीन एकता और सहयोग को जारी रखने के पक्ष में थे और अपनी ओर सह्य शांति की स्थापना में अपना योगदान करने में दिलचस्पी रखते थे। जिस तरह से उन्होंने पोट्सडम में "हर्जाने" की मांग पर जिद की और "उधार पट्टे" की समाप्ति पर वेदना प्रकट की उसे देखते हुए कोई 'बेखचिल्ली' ही हो सकता है, जो ट्रूमैन की इस दुराग्रही धारणा को स्वीकार कर पायगा कि रूसी विश्व विजय का सपना देखने वाले इस युग के नये सिकंदर बन रहे थे। पोट्सडम में यह तय हुआ कि —

(1) पांच बड़ों के परराष्ट्र मंत्रियों की एक परिषद स्थापित की जाये— अर्थात् अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, एवं चीन जिसका कार्यालय लंदन में ही स्थापित किया जाए। इस परिषद की पहली बैठक 1 सितम्बर सन् 1945 का लंदन में की जाए। बाद की बैठकें आपसी सहमति से अन्य राजधानियों में भी हो सकती हैं। इस परिषद का काम था कि वह इटली, रूमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और फिनलैण्ड के साथ शांति संधियाँ का मसविदा तैयार करे और प्रादेशिक प्रश्नों को निबटारे। साथ ही इस उस जर्मनी के साथ की जाने वाली संधि का प्रारूप तैयार करने का काम भी दिया गया जिस तीनों बड़े मिलजुल कर अपने

सैन्य नियंत्रण में ले चुके थे।

(2) जर्मनी के साथ अंतिम रूप से शांति संधि सम्पन्न करने के पूर्व उसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इसके बारे में कुछ राजनीतिक सिद्धांत कुछ आर्थिक सिद्धांतों, ऐसे ही क्षतिपूर्ति विषयक कुछ सिद्धांतों तथा जर्मन नौ सेना के बटवार के बारे में तथा जर्मनी के व्यापारिक जहाजों के बटवारे के कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया गया।⁴

शुरू से ही चीन को यूरोप के इन मामलों में दूर रखा गया। यूरोप के “भाग्य नियता” एशिया के मामलों में दखल देने का पूरा अधिकार रखते थे, विजयी राष्ट्रों की पक्ष में शामिल किए जाने के बाद भी चीन इसका अधिकारी न बन पाया कि वह यूरोप के समाधानों में अपना योगदान कर सके।

राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी को वास्तव में तीन, पर व्यवहार में चार क्षेत्रों में बांटा गया—अमेरिकी, ब्रितानी, रूसी और फ्रांसिसी फ्रांस “लुजपुज” था, फ्रांसिसी सैनिकों की बर्दी और हथियार भी जास्त अमेरिकी मित्रों की उतारन” थे, पर चर्चिल फ्रांस का हक दिलवा रहे, भले ही फ्रांस का इलाका, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी और अमेरिकी इलाका से क्षेत्रांश लेकर बना दिया गया। इसके नियंत्रण के लिए चार महाशक्तियों के प्रतिनिधियों की एक परिपद की स्थापना की गई।

(3) यह भी निश्चित किया गया कि युद्धोत्तर जर्मनी को पूर्णतः निःशुल्क और सत्ता विहीन किया जायेगा और नात्सी संगठन और उनके वानूना को समूल नष्ट किया जायेगा। यह तय किया गया कि जर्मनी में लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति स्थापित की जायेगी और नागरिक स्वतन्त्रताएँ की जायेंगी। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण निणय लिया गया कि उन जर्मनों पर मुकदमा चलाया जायेगा जिन्होंने युद्ध में क्रूर और अमानुषिक मातनार्थें पहुँचायी हैं।

आर्थिक क्षेत्र में जहाँ एक ओर यह तय किया गया कि जर्मनी में शस्त्रास्त्र तथा युद्ध सामग्री के उत्पादन पर रोक लगा दी जायेगी वहाँ यह भी तय किया गया कि उसकी अर्थ-व्यवस्था का एक विकेंद्रीकृत कामव्यवस्था बनाया जायेगा और कृषि एवं शान्तिकालीन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। महत्वपूर्ण निणय यह था कि सम्पूर्ण जर्मनी को एक इकाई मानकर चला जायेगा, भले ही वज्राचार वहाँ राष्ट्रों का बना रहे। जहाँ जर्मन के बारे में यह तय किया गया कि जर्मनी से युद्ध का हर्जाना लिया जायेगा वहाँ यह भी निणय लिया गया कि वह तजाना इतना ही कि बिना बाहरी मदद के जर्मनी की अर्थव्यवस्था चलती चले। हर्जाने की रकम ५ बरस में यह तय हुआ कि सोवियत अधिभूत क्षेत्र में सावियत मध्य हर्जाना से और बाहरी पूँजी का अधिग्रहण कर ले तथा अमेरिका, ब्रिटन तथा अन्य देश पश्चिमी क्षेत्र तथा बाहरी पूँजी से वसूल लें। इसका अलावा यह भी तय किया गया कि शांति कालीन जर्मन अर्थव्यवस्था के लिए अनावश्यक कारखानों का

10 प्रतिशत मशीनें और सामग्री पश्चिमी क्षेत्र से सोवियत संघ को दी जायें और इसके अलावा 15 प्रतिशत औद्योगिक सामग्री, पूर्वी क्षेत्र से उतनी मूल्य का वस्त्र, कोयला, पोटैश, इमारती लकड़ी आदि देकर ले सकता था।

विजयी दावेदारों ने एक दूसरे के हारों पर अपने दावे छोड़े अर्थात् सोवियत संघ ने पश्चिम जर्मनी के वारखानों और स्वर्ण कोष अपने दावें हटा लिए, इसी तरह ब्रिटेन, अमेरिका फ्रांस ने पूर्वी जर्मनी के क्षेत्र के कारखानों पर अपने अपने दावे छोड़ दिये। जर्मनी की नीमेना के बारे में यह निणय लिया गया कि अधिकांश जर्मन पनडुब्बियों को डुबो दिया जायेगा केवल 30 प्रतिशत पनडुब्बियाँ तीनों बड़े देशों में बराबर बराबर बांट दी जायेंगी। व्यापारिक जहाजों को समान रूप से आपस में बांट लिया गया। कोर्सिक्स बग का नगर और आस पास का इलाका सोवियत संघ को देने का निश्चय किया गया।

(4) पोलैण्ड के बारे में वाल्टा निश्चयों को पुनराया गया कि सावजनिक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया जायेगा और लोकतान्त्रिक सरकार की स्थापना की जायेगी। पोलैण्ड की अस्थायी सीमा पर सीमा भी निश्चित की गई जिसके अनुसार पूर्व में बाल्टिक में स्वीन मुहाने तक तथा पश्चिम में ओडर और नीश नदियों के साथ साथ नैब सीमाओं तक रहेगी।

(5) यह भी तय किया गया कि इटली, बुल्गारिया फिनलैण्ड और हंगरी के साथ शांति संधियाँ सम्पन्न की जायें और इन शत्रु राष्ट्रों को समुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान की जायें।

(6) ताजिकस्तान का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बना दिया जाए। तब तय हुआ कि आस्ट्रिया के बारे में सोवियत प्रस्ताव पर विचार हो जब आग्ल अमेरिकी सेना का वहा प्रवेश हो जाए। आस्ट्रिया में क्षतिपूर्ति की राशि वसूल न की जाए।

(7) ईरान में मिन राष्ट्रा की सन्तानें स्थिति थी। इसके संबंध में निणय लिया गया कि ईरान के इलाके खाली करा दिये जायें ताकि ईरान पर यह अस्थायी गिरावणी खत्म हो और वह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पुनः स्थित हो।

(8) काला सागर जल डमरूमध्य के बारे में मातुरे के अभिसरणों पर पुनः विचार हो क्योंकि व अब आग की हाथों के अनुकूल नहीं रह गये।

(9) प्रादेशिक यावों के बारे में परिषद ने सोवियत प्रस्ताव पर विचार किया और यह तय हुआ कि इटली के उपनिवेशों के बारे में इटली संबंधित शांति संधि में विचार हो और उसे अगले सितंबर की परिषद की बैठक पर विचार के लिए रखा जाये। इतिहास के मजे मजाये साम्राज्यवादी नेता अपनी पगल में स्टालिन को बैठाने को सैयार नहीं थे।

दृष्ट-य है कि पोट्सडम सम्मेलन में अभी भी मिलजुल कर महत्त्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे। माहीन में कुछ नयापन था पर वह तीता या कसैला नहीं लग

रहा था। कुछ भेदभरी नजरें इधर उधर पड़ रही थी, पर उनमें सदेह के विपरीत बीज छिपे नहीं लग रहे थे। कुल मिलाकर अभी भी युद्धकालीन एकता और सहयोग की भावना बरकरार मालूम दे रहा थी यद्यपि बहुत बारीक खरोच के से निशान कहीं कहीं दिखाई पढ़न की हानत में उभर रहे थे। पर जापान का भय अभी भी अमेरिकी युद्ध विचारदा के मन पर हावी था और उनके दबाव के आगे ट्रूमैन के मतत्व में अमेरिकी राजनेतागण युद्धोत्तर राजनीति को नई हवा देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अभी उनके मन की उनके मन में ही थी। वह वाणी का परिधान पहनकर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।

जापान के बारे में

मुख्य मुद्दे की बात अमेरिकिया की नजर में जापान सवधी नियंत्रण थे जिसने अकेला पड़ जाने के बावजूद अभी तक 'समपण' का रुख नहीं दिखाया था। पाट-सदम में मित्र राष्ट्रों ने तय किया कि—

- 1 जापान के वे सैनिक तत्वों को निमूल किया जायेगा जिन्होंने जापान को विश्व विजय के अभियान में लगाया और बबरता पूर्वक युद्ध चलाया।
- 2 जब तक जापान से इन सैनिक तत्वों का सफाया नहीं हो जाता मित्र राष्ट्र जापान पर अपना नियंत्रण बनाय रखेंगे।
- 3 जापान की प्रमुखता, काहिरा सम्मेलन के निष्पत्तिनुसार केवल होशू, होकाइडो, क्युशु, शिकोकू, तथा तीना बड़ी शक्तियाँ द्वारा निर्णीत ऐसे अन्य छोटे टापुओं तक ही सीमित मानी जायेगी।
- 4 (जमनी की तरह ही) जापानी सेनाओं को पूर्णतः निशस्त्र किया जायेगा।
- 5 जापान के युद्ध अपराधियों को दण्डित किया जायेगा और
- 6 जापान की युद्धोत्तर सरकार को लोकतन्त्र के आधार पर गठित किया जायेगा तथा जापानी समाज में वाणी लेखन धर्म और विचारों की स्वतन्त्रता तथा अन्य मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जायेगी तथा।
- 7 युद्धोत्तर जापान में स्मृत्यु चुनावों के आधार पर जब उत्तरदायी सरकार स्थापित कर ली जायेगी तभी मित्र राष्ट्र अपनी सेना वहाँ से हटाएंगे।

जापान को चेतावनी दी गई कि वह बिना शर्त आत्म समपण कर दे अन्यथा उसे दीर्घ ही नष्ट कर दिया जायेगा। चेतावनी दी गई अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की आर में सोवियत संघ को इसकी सूचना भेज दी गई। राष्ट्रों के इस व्यवहार पर जब मोलोटोव ने आपत्ति की तो उन्हें बताया गया कि यह तो इसलिए किया गया था कि सोवियत संघ ने अभी विधिवत जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी और वह पुरानी संधि से बंधा हुआ था।

इस प्रसंग में दो बातें दृष्टव्य हैं। पहली बात यह कि जापान के विरुद्ध

वाही अभी भी सम्मिलित तौर पर करने का मकसद तो लिया जा रहा था और उस पर जमनी की तरह ही सभी का बन्ना स्थापित करने की धारणा स्पष्ट का जा रही थी पर सोवियत संघ का जापानी मामलों में ब्रता रखने की दुरमि सधि चलने लगी थी यद्यपि उनमें अपेक्षा की जा रही थी कि वे जापान के विरुद्ध मोर्चे में आ उठेंगे और उनका बचनानुसार यूरोपीय युद्ध की समाप्ति के 3 महीने के अंदर वे जापान के विरोध में युद्ध की घोषणा करने वाले थे। 8 मई को युद्ध समाप्त हुआ तो इस हिसाब से 8 अगस्त तक उनके युद्ध में कूद पड़ने का भरोसा था।

परमाणु युग का पर्दा उठा

इस बीच अमेरिका में एक युवा-तरकामी वैज्ञानिक आविष्कार का सफल प्रयोग रीन जा रहा था। कुछ वर्षों से आत्म अमेरिकी सहयोग से दोनो देशों के वैज्ञानिक जिन्हें विशेषतः आइंस्टीन के ऑपिन हेमर ऐसी वैज्ञानिकों पतिभागों का असुरक्षित सहयोग प्राप्त हो गया था परमाणु विखंडन प्रक्रिया का सफल प्रयोग करने में जुटे हुए थे। वह प्रक्रिया पूरी तरह सफल हुई और अमेरिका ने उस तक नीचे पर अचिपत्य हासिल कर लिया पोटसडम में जब बैठक चल रही थी तब ट्रूमैन को परमाणु बम के सफल परीक्षण की सूचना ट्रूमैन ने चर्चिल का तो वे ही पर स्टालिन से इस गुप्त ही रखा गया उ हे केवल यह सूचना दी गई कि अमेरिका ने एक शीघ्र अग्न के निर्माण में सफलता अर्जित कर ली है। स्टालिन का उत्तर था कि उन्हें आशा है कि इसका प्रभावशाली उपयोग जापान के विरुद्ध होगा।¹⁴ उन्होंने यह उत्सुकता नहीं प्रकट की कि आगिर वह क्या अस्त्र है किस प्रकार का अस्त्र है। इसकी उन्हें तभी जानकारी मिली जब 6 अगस्त को यह बम-हिराशिमा को आग की सपटा में भून गया और दलत दलत 70 हजार लोग कालवर्धित हो गए और हजारों घर नष्ट हो गये। एक अभूतपूर्व विनाशालीला का लोमहर्षक दृश्य उपस्थित हुआ गया। उसके दो दिन बाद अर्थात् 8 अगस्त को, तीन महीने का निर्णित अवधि में सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

सावित्रत संघ की छोड़कर अब तीन मिन गण्टा न 27 जुलाई को अति-मेतमम' ने रखा था जिसे तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री ने ठुकरा दिया था और अमेरिकी नीति निर्माता 'परमाणु बम से जापान का सहार करने को तैयार हुआ गया। फेंक जाने के लिए बम 31 जुलाई को ही तैयार था पर त्वराव सोमम ने 5 दिन की मुहलत दे दी। 6 अगस्त को अर्थात् पोटसडम से वाशिगटन लौटाने के पहले अमेरिकी नेताओं ने परमाणु बम से सहार करने की ठान ली और य ब्रह्मास्त्र छाड़ दिया और हिराशिमा में मृत्यु का ताडक नृत्य शुरू हो गया। अतः भीषण अस्त्र की जापानिया पर फेंकन का निणय लेकर ट्रूमैन ने डाक-

जनी के इतिहास के उस अध्याय की चरम परिणति ला दी थी, जो शताब्दी पूर्व के अमेरिकी बमादर पेरी की जोर जबदस्ती से जापानी बमादरगाह खुलवाने के लिए गोलाबारी करके धुरी की गई थी।⁴⁸ इसके दो दिन बाद अर्थात् 8 अगस्त को सोवियत संघ भी जापान के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में आ गया, यद्यपि जापान सोवियत संघ से मध्यस्थता करने के लिए अनुरोध कर रहा था जिसकी खबर स्टालिन ने ट्रूमैन को दे दी और यह भी कह दिया था कि इस प्रस्ताव को उहाने ठुकरा दिया है जिसकी दाद तब ट्रूमैन ने भी दी थी।

नौ अगस्त को दूसरा बम ऐसा ही भीषण नागासाकी के नगर पर छोड़ा गया। 10 अगस्त को जापानी सरकार आत्म समर्पण के लिए घुटने टेकने लगी। शर्तें 14 अगस्त तक तय हो गईं और 2 सितंबर को जापान ने आत्म समर्पण कर दिया। एशिया की एक मान साम्राज्यवादी शक्ति जो यूरोपीय और अमेरिका साम्राज्यवाद से जमकर लोहा ल रही थी और बराबरी का दावा मजूर करवाने में जुटी थी, जिसने एक एशियायी शक्ति के रूप में यूरोप के तबके कदम पर चलते हुए यूरोप की एक बड़ी शक्ति को 1905 में पछाड़ा था और बाद में उनसे बराबरी मनवा ली थी, जिसने पल हवा पर अमेरिका पर जबदस्त हमला कर अमेरिका औद्योगिक और सामरिक दृष्टि से ठुकरा कर दिए थे। जिसकी उदीयमान औद्योगिक और सामरिक क्षमता के आगे आग्ल अमेरिकी गुट त्रस्त था और जर्मन नात्सी और फासी इटली के साथ मिलकर पूरी दुनिया को आपस में बांट लेने के स्वप्न में वसुध होकर साम्राज्यवादी सरकार में व्यस्त रही अततो गत्वा एशिया के अल्प पुरातन राष्ट्रों की तरह धूलधूसरित और पद दलित होकर ही रही। उगते सूर्य के देश में सूरज को तेजी से डूबते पाया और अधिकार की धनी पत के बिछते ही उगते सूरज का देश अपनी कलक कालिमा में कुछ समय के लिए खो गया।

पर परमाणु बम के प्रयोग ने, अपने धमाके से मिन राष्ट्रों के युद्धकालीन पठ बधन का भी अंत ला दिया और एक नई युद्धोत्तर दुनिया अपनी तमाम उमचुम और भूडोल के झटके के साथ उभर आई। यूरोप में युद्ध बंद हुआ तो लगा कि बात कुछ नहीं बनी पर इस एशियाई 'सहारा लीला' ने पलक झपकते ही उभरती दुनिया की एक त्रासदायक झलक दिखा दी।⁴⁹

सदभ

1. नेहरू ने एटलांटिक घोषणा को एक अस्पष्ट और पुलपुली घोषणा कहा। उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं से अनुरोध किया कि वे एक दूसरी घोषणा भी प्रसारित करें जिसमें सभी जातियों के लोगों को समान व्यवहार

- 20 शेरवुड, पृ० 401-402
- 21 कारडेल हल, मैमाअस, खण्ड 2, पृ० 1167 70
- 22 स्फेमिंग, वही, पृ० 147
- 23 चर्विल, युद्ध के सम्मरण, खण्ड 5, पृ० 227-8
- 25 स्फेमिंग वही प० 193-94
- 26 शेरवुड, पृ० 497 ।
- 27 देखिए वतमान गथ के प०
- 28 देखिए स्फेमिंग, वही, प० 196
- 29 देखिए, स्फेमिंग, वही पृ० 195-97
- 30 थियोडोर एच, ह्वाट, फायर इन द एशेज, प० 343
- 31 याल्टा पेपस, पृ० 679 81
- 32 जेम्स वायरलीज स्पीकिंग फॉकली, पृ० 31-2, चर्विल, खंड 6वा, पृ० 369
- 33 "यूयाक टाइम्स, जुलाई 24, 1941 (स्फेमिंग से उद्धृत प० 135)
- 34 देखिये ट्रूमेन के सम्मरण, खण्ड-1, प० 221 2 तथा स्फेमिंग, वही, प० 268 69
- 35 वही, प० 221-2
- 36 वही, प० 221-2
- 37 एडवर्ड स्टेटिनियस, रुजवेल्ट एण्ड दि रस स, पृ० 318 19
- 38 स्फेमिंग, वही, पृ०
- 39 स्फेमिंग, वही, पृ० 195
- 40 मैकार्थर हिग्विग्स, भाग 3, प० 206, स्फेमिंग कृत "द कोल्ड वार से उद्धृत" प० 196
अमेरिका के युद्धविशारद जैसे उनके बड़े जनरल मैकार्थर, सचिव फोरेस्टल
रूस की जापान के विरुद्ध युद्ध में भागीदारी को एक बड़ी, लगभग निर्णायक
बात मान रहे थे—देखिए स्फेमिंग, याल्टा सम्मेलन सबंधी अध्याय 8,
पृ० 188 218
- 40 "सम्मेलन का रिवाज, यूयाक टाइम्स ने लिखा, यह स्पष्ट करता है, कि
रूस ने दस बार सहूलियतें देकर डम्ब्रटन ओक्स के प्रस्तावों बहुत कुछ
नरम बनाने में योगदान दिया ।" स्फेमिंग, पृ 286 वही,
- 41 याल्टा पेपस, पृ 665 ■
- 42 जान सी कैम्पबेल, दि यूनाइटेड स्टेट्स इन वल्ट अफेअस, 1945-47,
पृ 54,
- 43 देखिये स्फेमिंग, वही पृ 290 92,
- 44 ट्रूमेन ने अपने सम्मरण में लिखा है कि उन्हें ऐसा आभास हो गया था कि

दूसरे नाटक का भी अंत : सैन्यवादी जापान की कपाल क्रिया—अमेरिका का परमाणु (ब्रह्मास्त्र) और सोवियत संघ का अंतिम युद्ध

महायुद्ध अपने अंतिम क्षरण में पहुँच गया था। दूसरा मोर्चा खुल गया था। नात्सी जर्मनी पर दोनों ओर से प्रहार पर प्रहार हो रहा था। जर्मनी लड़खड़ाते लगा था कि दुर्भाग्यवश अमेरिका के अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रपति रूजवेल्ट का अचानक निधन हो गया। उत्तराधिकारी थे राष्ट्रपति हेरी एस ट्रूमैन जिन्होंने तुरंत राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली और वामवाज समझने की कोशिश में जुट गये। ट्रूमैन का दिल और दिमाग रूजवेल्ट की तरह न था। वे कुछ असंग ही तरह के व्यक्तित्व के धनी थे और उनके आग्रह व पूर्वग्रह भी अपने ढंग के थे। पर युद्ध के बीच घोंघे भते ही बदल गये हो, युद्ध की दिशा थोड़ी बदली जा सकती थी। युद्ध जारी रहा और नात्सी जर्मनी का कचूमर निवाल कर ही यूरोप में उसका अंत हुआ। पर अमेरिका के लिए अभी युद्ध का कहीं अधिक महत्वपूर्ण मोर्चा जारी था। उसके जल्दी धमने की आशा नहीं दिख रही। वह युद्ध था सैन्यवादी जापान के विरुद्ध जिसने वस्तुतः अमेरिका को युद्ध में ला धसीटा था।

इस माहौल में बर्लिन के पास पोट्सडम में एक बार फिर तीन बड़ों का सम्मेलन गठित हुआ। ट्रूमैन पहली बार अपने समकालीन तथा स्वर्गीय रूजवेल्ट के पुराने मित्रों से महत्वपूर्ण वार्ता के लिए रवाना हुए। वे जब उगाटा नामक जहाज से यूरोप आ रहे थे, तब जहाज पर अक्सर यह कहा करते कि मैं सबसे अधिक यह बात चाहता हूँ कि रूस के हवाई अड्डों का इस्तेमाल हो सके ताकि वहाँ से जापान और उसके विजित प्रदेशों पर हमला हो सके। उनके सैनिक अधिकारी बेताबी से रूस को जापान के विरुद्ध लाने के लिए अनुरोध करने के हिमायती थे। 9 अगस्त, 1945 को जब नागासाकी में दूसरा परमाणु बम फेंका जा चुका था, एसोसियेटेड प्रेस के एक सवाददाता ने 'यूयार्क टाइम्स' में लिखा (यह

संवाददाता ट्रूमैन के साथ पोट्सडम गया था) कि अब यह बात खोली जा सकती है कि जापान के विरुद्ध रूस को युद्ध में लाना यह समझौता करने का मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए ट्रूमैन ने पोट्सडम की यात्रा की थी। 24 जुलाई तक जो रूस की मदद निहायत जरूरी लग रही थी एक घटना घटते ही वह बेमानी हो गई। वह घटना क्या थी ?

सफल "परमाणु" परीक्षण

परमाणु अस्त्र ने अमेरिकी विभाग फेर दिया

जमनी में सन 1938 तक वैज्ञानिक इस प्रयत्न में जुटे हुए थे कि वे परमाणु विस्फोटन का तरीका खोज निकालें पर वहां सफलता नहीं मिली। इसी दिशा में अमेरिकी जिन्हें नात्सी उत्पीड़न के कारण दश स भागें एस महान वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन का सहयोग मिला, और इस दिशा में जोर शोरो से काम चलता रहा पर यूरोप में युद्ध खतम होने तक सफलता हाथ नहीं लगी। काम फिर भी जारी रहा। जब पोट्सडम में ट्रूमैन विचार विमर्श में भागलू थे, उस समय जुलाई 16 को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अन्तः परमाणु परीक्षण में सफलता प्राप्त कर ली थी और वह वैज्ञानिक उपलब्धि सुरत ही एक भीषण संहारक अस्त्र की उत्पत्ति का कारण बनी। ट्रूमैन की एंशो का ठिकाना न रहा पर उन्होंने इस "गुप्त" उपलब्धि को जग जाहिर नहीं होने दिया। चर्चित को तो सभी कुछ बताया गया पर 24 जुलाई को ट्रूमैन के द्वारा स्टालिन का केवल यह खबर दी गई कि एक "विशाल अस्त्र ने निर्माण में अमेरिका को सफलता मिल गई है। स्टालिन ने आधा प्रवृत्त की कि इसका उपयोग मित्र राष्ट्रों के दुश्मनों के खिलाफ होगा। इसके आगे रहस्य पर पर्दा पड़ा रहा।

पर्दा तब भी पड़ा रहा जब स्टालिन के बिना ही 26 जुलाई, 1945 को जापान को अन्तिम चेतावनी दी गई अर्थात् "पोट्सडम" की घोषणा कर दी गई तीन बड़ा वे नाम पर जिसमें सोवियत संघ की जगह "चीन" को शामिल किया गया था। जापान के विरुद्ध घोषित युद्ध लड़ रहे थे, सोवियत संघ को औपचारिक तौर पर अभी युद्ध की घोषणा करनी थी। सोवियत संघ को जापान के विरुद्ध सहाई स उत्पन्न होने वाली विजयप्री में बाहर रखने का प्रयत्न शुरू हो गया था। मोलोटोव को पोट्सडम घोषणा की एक प्रति भिजवा दी गई। तब उन्होंने यह अनुरोध किया कि इसे दो तीन दिनों के लिए रोक लिया जाये पर अब अमेरिकी मित्रों को सोवियत के साथ "योगदान" में हिस्सेदारी नहीं रह गई थी। वे अपने दूसरी ही उद्योग बुन में लग हुए थे।

जापान ने पोट्सडम की चेतावनी ठुकरा दी। अमेरिकी नेता ट्रूमैन यही चाहते थे। उन्हें पहले यह भी मताह दी गई थी कि बिना चेतावनी दिए

परमाणु बम की मार की जाय पर अधिकांश सत्ताहकारों का जिनमें कुछ नामी वैज्ञानिक भी थे, यह जोर था कि चेतावनी तो दी ही जाये। 28 जुलाई को जापानी प्रधानमंत्री मुजुकी ने चेतावनी ठुकराई और 31 जुलाई को बम अग्निवर्षण के लिए तैयार था। स्त्राब मोसम ने पांच दिन और दिए। 5 अगस्त को पोट्सडम से ट्रूमैन घर को खाना हुआ और 6 अगस्त को सुबह 8 45 मिनट पर हिरोशिमा नगर पर यह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया।

मिनटों में 80 हजार आदमी बालकबलित हो गये और इतने ही बुरी तरह से घायल। बम की आग ने 4 4 बगमोल के घेरे को भस्मसात कर दिया जैसे आग का तूफान फट पड़ा हो। लगभग 60 62 हजार इमारतें देखते-देखते धराशायी हो गईं, बाकी टूट फूट गईं। ऐसा विनाश पहले भी हो रहा था, पर ऐसे विनाश को लाने के लिए सैकड़ों ब्यां हजारों हवाई जहाजों और कुछ लाख टन बमों की जरूरत होती रही। एक बम ऐसी विनाश लीला उगलेगा, यह पहली बार देखने को मिला, जो मौत से बच गये, उनके रोगों से खड़े हो गये। तीन दिन के बाद जापान के दूसरे घनी आबादी वाले नगर नागासाकी की शामत आई। परमाणु बम उस पर फँका गया। इस अपूर्व विनाश लीला के बाद जापान ने घुटने टेक दिए। औपचारिक तौर पर आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर सितंबर में हस्ताक्षर हुए।

आखिर परमाणु बम ऐसे सहारक अस्त्र का प्रयोग इतने आनन फानन से अमेरिका ने क्या किया, विशेषतः तब जबकि घुरी राष्ट्रों में तब अकेले जापान ही युद्ध क्षेत्र में रह गया था और यूरोपीय मंच के मित्रराष्ट्र छुट्टी पा गये थे। इतने भारी जन जीवन की कीमत पर यह विजय अभिमान क्या संगठित हुआ ?

इस सबब में चार बातें या तर्क अमेरिकी नेताओं और लेखकों के द्वारा दिए गए हैं (1) प्रथम यह कि अमेरिकी सैनिकों का जीवन बचाने के लिए, (2) दूसरा यह कि लड़ाई जल्द खतम हो जाये, लबी न खिंचे (3) तीसरा यह कि यहां ढंग से परमाणु युग के आगमन की घोषणा हो और (4) अंततः कि पूर्वी एशिया में रूसी प्रभाव के विस्तार को न्यूनतम कर दिया था उसे सीमित कर दिया जाए।

राष्ट्रपति ट्रूमैन ने पहला व दूसरा तर्क सावजनिक रूप से इस्तेमाल में लिया पर लोगो को यह बात इस कारण जैची नहीं कि जापान की हालत तब बहुत खस्ता हो चुकी थी। उनमें जवाबी हमला करने की क्षमता जा चुकी थी। अमेरिकी बम वर्षक महीनों से तबाही किये जा रहे थे और जवाब में जापान कुछ नहीं कर पा रहा था।⁵ जापान ने रूसी नेताओं से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव भी रखा था जिसकी खबर स्टालिन ने ट्रूमैन को दे दी थी। लड़ाई बिना परमाणु बम के इस्तेमाल के भी बसे ही खतम होन जा रही थी क्योंकि सोवियत संध के जापान के विरुद्ध घोषणा के बाद जापान के लिए मुक्ति के सारे द्वार बंद हो चुके थे। दो

बमो की लोमहर्षक सहार लीला ने वावजूद जापानी सैनिक बर्मान ने घोषणा की थी कि हम इन बमो से कोई घबड़ाहट नहीं हुई है और हम बदले की कारवाही करने जा रहे हैं।¹⁶ पर सोवियत संघ के युद्ध में आते ही युद्ध का पासा पलट गया जसा अमेरिकी एडमिरल लीही और चर्चिल ने खुद स्वीकार किया है कि परमाणु बम की वजह से जापान न घुटने नहीं टेके।¹⁷

एक दृष्टि से द्वितीय महायुद्ध के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विकास था अमेरिका का न केवल औद्योगिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में उभरना बल्कि, एक सबसे अधिक सम्पन्न व पुष्ट सैनिक शक्ति के रूप में उभरना। जहाँ तक औद्योगिक जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहण करने की बात थी, जसा हम अपने प्रथम खण्ड में बता चुके हैं यह प्रशिया द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के पहले ही उस बिंदु पर पहुँच चुकी थी। अमेरिका ब्रिटेन को बंब का पछाड़ चुका था। पर सैन्य शक्ति के रूप में प्रथम महायुद्ध केवलतम हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक अमेरिका की स्थिति प्रकटत इंग्लैंड फ्रांस व जर्मनी के बाद भी मानी जाती थी। दो नौसेना की दृष्टि से असबत्ता अमेरिकी ब्रिटेन की होड में आगे बढ़ता जा रहा था और द्वितीय महायुद्ध शुरू होने के पूर्व तक आगे निकल चुका था।

सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक शक्ति का सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हो जाना एक स्वाभाविक प्रशिया थी। पर अगर महायुद्ध में अमेरिका न पसीटा गया होता तो सम्भवतः इस स्वाभाविक प्रक्रिया को प्रतिफलित होने में कुछ देर लगती। अमेरिका मजे से एक बजोड औद्योगिक और व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर रहा था उसके पास सना का जवाब उसके अनुरूप न था। जहाज रानी और नाविक शक्ति के बारे में अमेरिकी शासक बग सचेत थे और उसकी जरूरत न थी जसी पल हावर के बाद तुरत ही महसूस होने लगी। शुरू शुरू में उनकी नीति यूरोप के झगड में न पडने की थी। नवदी दो ओर ले जाओ की नीति चलाकर वे तटस्थ भी रहे। ब्रिटेन के साथ सहानुभूति रखते हुए अटलांटिक घाटर के बाद भी वे समुद्री जलमार्गों के बरोकटोक आवाजाही की बातों में अधिक दिलचस्पी लेते रहे। प्रथम महायुद्ध के दौरान भी अमरीका को युद्ध में लाने में विल्सन को बड़ी महनत करनी पड़ी थी तब जाकर सन 1917 में अमेरिका यूरोप की झगड में शामिल हुआ था। अमेरिकी जनमत इस सडार्ई में भी नहीं पड़ना चाहता था न यूरोप में और न पूव एशिया में। पर पल हावर और जर्मनी की अपनी नावेबंदी की कायवाही ने अमेरिका को युद्ध में सावर ही मना और एक बार अमेरिका सन् 1941 के वष के समाप्त होते होते युद्ध में पसीटा लिया गया तब एक विशाल सैनिक शक्ति के रूप में भी अमेरिका का उभर जाना दृष्टवर्ति से होने वाली एक सहज प्रशिया के रूप में हुआ जिसका अमेरिकी जनजीवन और आणविक राजनीति दोनों पर गभीर और बहुत टिकाऊ प्रभाव पडा और जिसका

विकृत रूप हमें युद्ध के अंतिम दिनों से ही देखने को मिलने लगा। परमाणु शक्ति का सफल परीक्षण और इस अपूर्व संहारक शस्त्र से एशिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र पर भीषण प्रहार, इस विकृत हो रही मन स्थिति का पहला विस्फोट था जो अनावश्यक होते हुए भी लाखों अमेरिकी नागरिकों को बिना पूर्व सूचना के बात की बात में परमाणु बम की "नारकीय भट्ठी" में झोंकने के बाद सुख की नींद सोने का द्विद्वारा पीटता है।¹⁸ अमेरिकी नौसेना के कमांडर पेरी ने अपनी तोपों से गोले दाग कर जापान से कुछ बदरगाह खुलवाने की जिद की थी। कमांडर प्रेसीडेंट ट्रूमैन ने भी ऐसी ही जिद हिरोशिमा और नागासाकी में, बिना सूचना के, और अनावश्यक तौर पर परमाणु बम बरसा कर लाखों लाखों अमेरिकियों को मिनटों में हताहत कर पूरी की। परमाणु बम के द्वारा संहार करने के पूर्व ही जापानी सैन्य शक्ति नाहिमाम करती शरणागत होने को व्यग्र थी पर 'पेरी मनोवृत्ति' भला ऐसे कैसे मानती। हथियार हैं तो हथियार चलाये जायेंगे वह भी एशियाई रणस्थल में, भले ही वह परमाणु बम हो।

युद्धकाल में सैन्य कार्यों के मद में लगभग 315 अरब डॉलर व्यय किए गए और यदि हम युद्ध ऋण और अवकाश प्राप्त सैनिकों के कल्याणार्थ हुए खर्च को भी जोड़ लें तो यह खर्च लगभग 425 अरब डॉलर बैठेगा। इस भारी सैन्य व्यय भार ने औद्योगिक विकास को ऊँचे सोपान पर ला खड़ा किया। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी औद्योगिक उत्पादन में हुई। अगर हम 1947-49 के वर्ष को आधार मान-कर चलें (100) तो उत्पादन जहाँ 1939 में 57 तो वहाँ 1941 में 88 और 1943 में 133 हो गया। इसी प्रकार जी० एन० पी० (कुल राष्ट्रीय उत्पादन) के आंकड़े बताते हैं कि—सन् 1929 में जहाँ जी० एन० पी० 104 अरब डॉलर था।

-1939 में लगभग	100 अरब से कम रहा
1940 में लगभग	100 अरब
1941 में लगभग	125.8 अरब
1942 में लगभग	159.1 अरब (इस समय की कीमतों के आधार पर)
1943 में लगभग	192.5 अरब
1944 में लगभग	211.5 अरब
1945 में लगभग	213.6 अरब

इसके साथ साथ सरकारी व्यय का औसत भी बढ़ता गया। जहाँ 1932 में 'कु रा उ' का 7 प्रतिशत रहा, वहाँ 1944 में यह "कु रा उ" का 50 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि युद्धकाल में जहाँ एक ओर अमेरिका में उत्पादन की शक्तियाँ ना अभूतपूर्व विस्तार हुआ और उत्पादन की मात्रा में

वर्द्धि हुई, वहा सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप तथा सरकार के द्वारा 'सरीद' व्यय की मात्रा का अनुपात भी तेजी से बढ़ता गया। विवास के इस स्वरूप ने सरकारी केन्द्रीकरण की तो प्रोत्साहित किया ही, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विशाल व्यापारिक औद्योगिक संस्थाओं की अद्यतन पर जबड़ की भी मजबूत कर दिया। घडाघड करोडो अरबों के ठेके उन्हें मिलने लगे जिससे वे तो फलते फूलते गये पर छोटे छोटे व्यापारिक फर्म टूट फूट गये। सन 1940 के जून महीने से लेकर सितंबर 1964 तक करीब 175 अरब डॉलर के ठेके कोई 18 539 संस्थानों को दिए गए पर 67 प्रतिशत, यं ठेके करीब 100 प्रतिष्ठानों के हाथों में आए और 117 अरब डॉलर का हिस्सा था। हुआ यह कि यह हिस्सा इन बड़े संस्थानों का 67 से 75 प्रतिशत के बीच की बना रहा। युद्ध समाप्त होते ही इन विनाश युद्ध काल में तेजी से विकसित पल्लवित हुआ युद्धो-मुख अद्यतन। युद्ध क्षतम होते ही विपरीत दिशा में जाने वाली शांतिकालीन संभावनाओं का अंत करने का संकल्प अब इन विशाल संस्थाओं के मालिकों की बुरी तरह घसने लगा और वे उसकी तैयारी में लगे।

विवास पथ पर आरूढ़ अद्यतन के इस स्वरूप पर ध्यान रखें तो हम पाते हैं कि इन औद्योगिक व्यापारिक संस्थाओं तथा रईस किसानों के बग का शासन तंत्र पर आधिपत्य युद्धकाल में काफी मजबूत हो गया था। अपने अंतिम चुनाव के दिनों रजवेल्ट ने शांतिकाल में उठने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर इन मजबूत वर्गों के प्रतिनिधियों की पूरी तरह अपने पक्ष में रखने की नीति अपना ली थी जिसका परिणाम था कि उन्होंने अपने विश्वासपात्र और जनसाधारण में 'लोक प्रिय' हेनरी वेलस को उप राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की जगह हेरी एस ट्रूमेन को यह उम्मीदवारी दे दी। इसी तरह उन्होंने सिनेटर वेडनबग तथा जान फास्टर डलेस' ऐसे कुख्यात साम्राज्यवादी और रिपब्लिकन को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनाया ताकि वे सैन फ्रांसिस्को संधि का संविधान तैयार करावें। इस तरह के लोग अमेरिकी राज्य नीति निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ाये जा रहे थे जिनकी यह दुइ मायता थी कि अमेरिका अब इस नई उभरती युद्धोत्तर दुनिया के अनायास्य का एक मात्र 'ट्रस्टी' है या अमेरिकी साम्राज्यिक 'टाईम' के संपादक हेनरी सुई के शब्दों में अब मानव इतिहास की अमेरिकी शताब्दी प्रारंभ हो गई है।

सारी दुनिया की अपने पग तले घसीट साने की महत्वाकांक्षा इतिहास में अनेक सिरफिरे आक्राताओं के मन में डल चुकी थी। अभी अभी हिल्टर, मुसो लिनी और जापानी संयुवादी इस जहर की मार से गुप्तो की मौत मर चुके थे, पर अब यह जहर यहाँ से हटकर अमेरिकी शासन बग के माँ पर उतरने लगा

या और उतर रहा था परमाणु अस्त्र के सहारे धीरे-धीरे। वह एक चीज थी जो उनके पास है और अर्थ के पास नहीं थी। उससे बचाव करने के लिए कदम भी नहीं है। ऐसी जहरबुझी भावना उनके साथियों के मन में घर करने लगी।

युद्धकालीन मंत्री का अन्त

पिछले पन्थों में उस सम्मेलन की चर्चा की जा चुकी है जो महायुद्ध की समाप्ति के पूर्व आयोजित किया गया था और जिसमें सोवियत संघ के नेता स्तालिन तथा रुजवेल्ट के उत्तराधिकारी अमेरिका के नये राष्ट्रपति ट्रूमैन पहली बार एक दूसरे से मिले। पोर्ट्सडम का यह सम्मेलन महायुद्ध की समाप्ति के पूर्व का अंतिम महत्वपूर्ण बड़ा सम्मेलन था। इस बातचीत के पूर्व ट्रूमैन ने अपने मंत्रिमंडल में भारी रव दोबदल कर दिया था। रुजवेल्टकालीन दम मंत्रियों में से 6 हटाए गये थे। बाकी 4 में 2 सन् 1945 के अंत तक और शेष 2 सन् 1946 के अंत तक बिदा हो गए।¹⁰ इन हटाए गए मंत्रियों में एक थे हेनरी मारगेथाऊ जूनियर, जो कोष विभाग के मंत्री थे और जिन्होंने जर्मनी के वि-औद्योगीकरण की वह योजना बनाई थी जिसे पिछले सितम्बर में चर्चिल और रुजवेल्ट का समर्थन मिला था। तब आग्ल-अमेरिकी योजना थी कि युद्ध के बाद जर्मनी का औद्योगिक ढांचा तोड़ मरोड़ दिया जाए और कड़ाई से उद्योग प्रधान जर्मनी की औद्योगिक रीढ़ तोड़ दी जाए। यह इस बात का सूचक था कि अमेरिका का रूल सोवियत संघ के बारे में बदल रहा था।¹¹ इन तमाम नियुक्तियों में एक सर्वाधिक महत्व की नियुक्ति थी जेम्स एफ बाइरनीज की जो परराष्ट्र मंत्री बनाये गए। ट्रूमैन तब उन्हें इस पद के लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति मानते थे पर शीघ्र ही उनके विचार बदलने लगे।

जैसे ही पोर्ट्सडम सम्मेलन शुरू हुआ, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दो प्रस्ताव सम्मेलन के सम्मुख रखे। पहला था परराष्ट्र मंत्रियों की परिषद की स्थापना के सवध में और इसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। दूसरा प्रस्ताव बाइरनीज के शब्दों में ही "हमारा मतबिदा साफ कह रहा था कि याल्टा घोषणा के दायित्वों को ठीक तरह से निभाया नहीं जा रहा है।" और यह सुझाया गया कि, "बुल्गारिया और रूमानिया की सरकारों के पुनर्गठन के लिए मिलजुल कर कायवाही की जाय ताकि, सभी लोकतंत्री गुट भागीदार बन सकें।" इस दूसरे प्रस्ताव का रूसियों ने तुरंत ही यह आरोप लगाते हुए विरोध किया कि अग्रेजों ने यूनान में अवैध हस्तक्षेप किया है और मनमाने ढंग से "चुनाव" संगठित किए हैं। मोलोटोव के शब्दों में "यूनान में जो अतिवादी कायवाहिया हुई हैं उनकी तुलना में रूमानिया या बुल्गारिया में हुई कारवाइया नगण्य हैं।" इस प्रकार जैसा हम अग्रेज भी बता चुके हैं, पोर्ट्सडम सम्मेलन की शुरुआत से ही आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला दोनों

तरफ म इस ढंग से चमना शुरू हुआ जो पुराने मंत्री सबका के सटार्ड में पढ़ने की सूचना दे रहा था। रूजवेल्ट बाल को अमेरिकी परराष्ट्र का अन्त समीप ला गया था। सुमनरवल्स न (जो रूजवेल्ट के उप-परराष्ट्रमंत्री थे) ठीक ही कहा है अमेरिकी नीति का दिशा निर्देश दूसरे हाथों में चला गया। इसने अमेरिकी सोवियत संबंधों में जो भारी परिवर्तन ला दिया वह पोटसडम सम्मेलन में उपस्थित सभी निष्पक्ष पक्षों को स्पष्ट हो गया था।¹³ पर इस सम्मेलन में उप-परराष्ट्र मंत्रियों के परिषद की स्थापना हो गई थी जिनके जिम्मे यह महत्वपूर्ण काम सौंपा गया कि वे युद्धोत्तर मधिया और व्यवस्था के मसविदे तैयार करें। इस परिषद की पहली बैठक स'दन में 11 सितम्बर को बुलाई गई पर इस की उपयुक्त अनबन के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएँ पेट चुकी थी। पोटसडम सम्मेलन शुरू हो जाने का था कि अमेरिका में सबसे पातक "परमाणु बम" का सफल परीक्षण हो चुका था और अमेरिकी शासकों की नीयत सोवियत संघ को दूर रखकर, समूच जापान पर कब्जा करने की बन चुकी थी ताकि, सोवियतों को उसमें हिस्सेदारी न मिल सके और याल्टा समझौता का पातन करने की जरूरत भी न पड़े।¹² जब अमेरिका ने महाअस्त्र को चलाने का निणय कर लिया था, उस समय तक जापानी साम्राजिया का मनोबल बहुत नीचे गिर चुका था और सोवियत संघ के समक्ष तथा अमेरिकियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जापान आत्म समर्पण के लिए तयार है उस पर परमाणु बम की मार करने की कतई जरूरत न थी।¹⁴ पर अमेरिकी शासकों ने परमाणु बम चला देने का निश्चय किया और दो ऐसे सहारक बम उनका दो जनसकुल नगरा हिरोशिमा और नागासाकी में छोड़े। इसने उस जापान को तुरंत घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, जो इसके बिना भी पहले से आत्म समर्पण के लिए उचित सहारे की खोज कर रहा था। अमेरिकी शासकों ने यह विध्वंसक परमाणु बम के एक मात्र धारक होने की सूचना दे दी और यह भी बतावनी दे दी कि अपने स्वायत्तों की पूर्ति के लिए परमाणु बमों की बर्पा करके मनुष्य मात्र के जीवन को अंतिम सनक की दिशा में डबेले देने का बेशम दुसाहस टूमेन में पाते हैं। मसोमत होकर चंचल ने कहा था मानवीय मामलों में एक नये सबल तत्व के सामने हम अपने को पाते हैं हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई जो अबाध है भविष्य के बारे में हमारा दस बिल्कुल बदल गया है।¹⁵

बदले हुए माहौल में शांति वार्ता

इस बदले हुए माहौल में शांति वार्ता के प्रयास हुए और वे प्रयास बहुत कुछ सफल रहे। जमनी के साथ 7 मई 1945 को और जापान के साथ 5 सितम्बर, 1945 को युद्धविराम की संधि हो जाने के बाद तो युद्ध समाप्त हो गया पर उसके

साथ युद्धकालीन मंत्रीपूर्ण वातावरण भी सामग्य नमाप्त सा हो गया था। रुज-वेल्ट की असमय में ही मृत्यु हो जाने से युद्धोत्तर वार्ताजों और समझौता पर बड़ा असर पड़ा। इंग्लैण्ड में चुनाव हुए और चर्चिल का दल हार गया। सेवरदल के नेता के रूप में एटली और परराष्ट्रमंत्री बेविन ने युद्धोत्तर व्यवस्था के निर्माण में हिस्सा लिया। युद्धकाल के तीन बड़ों में सबसे स्टातिन ही सत्ता में थे। पुराना माहौल पुराने लोगों के साथ जाता रहा। इसने शांति स्थापना के काम को कठिन बना दिया था। भीषण क्षति से ग्रस्त पश्चिम यूरोप अपने पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह आश्रित हो रहा था, उधर पूर्वी यूरोप के वे देश जिन्हें सोवियत की साल सेना ने फासियो और नारिस्तियो से मुक्त किया था, सोवियत सत्ता के बश-वर्ती बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यूरोप दो भागों में बंट चुका है और यह विभाजन रेखा सोवियत की साल सेना और आंग्ल-अमेरिकी सेनाओं के द्वारा अधिकृत क्षेत्रों के विभाजन की रेखा के आधार पर अपने आप ही तीखी और गहरी होती चली जा रही है।

भूमिका बन चुकी थी पर काम कठिन हो गया प्रारम्भिक कठिनाइयाँ

यों तो प्रथम महायुद्ध की तुलना में द्वितीय महायुद्ध के बाद शांति स्थापना का काम सरल हो जाना चाहिए था। मित्र राष्ट्र शुरू से ही भविष्य में युद्धोत्तर व्यवस्था के निर्माण के बारे में चिंतित रहे हैं और प्रयत्नशील रहे हैं कि कम से कम युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के बारे में अधिकाधिक सहमति से कुछ मूलभूत सिद्धांत तय कर लें ताकि युद्धोत्तर शांति स्थापना का कार्य सरल हो जाए। ऐसी दूर-दर्शिता युद्धकाल में उनकी मंत्री की प्रगट करने में भी सहायक रही है। इसी को ध्यान में रखकर सन् 1941 में चर्चिल और रुजवेल्ट ने अपने एटलांटिक घोषणा पत्र में युद्धोत्तर शांति व्यवस्था के बारे में कुछ सिद्धांतों की उद्घोषण की थी। इसी प्रकार सन् 1943 के नवम्बर में काहिरा सम्मेलन में जापान के साथ संधि करने की शर्तों के बारे में विचार हुआ था। इसी वर्ष पोलेण्ड की सीमा व ईरान की प्रादेशिक अखण्डता के बारे में भी कुछ निणय लिए गए थे। इस दिशा में, फरवरी सन् 1945 में याल्टा सम्मेलन में तय हुई बातें उल्लेखनीय रही जिनमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत निधारित किए गए तथा पोलेण्ड की सीमाओं, जापान के अधिकार में, कुछ प्रदेशों को सोवियत संघ को दिए जाने का निश्चय तथा विजेताओं के बीच जर्मनी के अस्थायी विभाजन का भी निर्णय लिया गया। इसी समय चर्चिल और स्टातिन के बीच पूर्वी यूरोप के राज्यों को लेकर 'प्रभाव क्षेत्रों' का बटवारा भी हुआ।

सबसे महत्व की बात यह थी कि युद्ध समाप्त होने के पहले ही राष्ट्र संघ की रास पर नये जागतिक महत्व के समुक्त राष्ट्र संघ की इमारत की सड़ा

दैन्य की तरह समुद्रपार करवटें बदल रहा था। लेकिन इस बिगड़ते हुए माहौल में भी सोवियत संघ के साथ मिलकर अर्ध मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर ली थी और उस जगत व्यापी संगठन ने अपना काम शुरू कर दिया था और अब लड़ते झगड़ते हुए भी मित्रराष्ट्र पराजित शत्रु देशों के साथ शांति संधियां करने की योजना बना रहे थे। इस बदले हुए वातावरण में आगल अमेरिकी नेतृत्व में ऐसे प्रयत्न चल रहे थे कि जितना कुछ हो सके, याल्टा और पोट्सडम के समझौतों से, विशेषतः उन समझौतों से जिनमें सोवियत संघ को कुछ विशेष सुविधाएं तथा अनुग्रह दिए गए थे, वचनिकलें ताकि, सोवियत संघ ने जिन प्रदेशों को अपने बाहुबल से "मुक्त" कराकर अपने अनुकूल राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न शुरू कर दिया था, वहां सोवियत के प्रति मंत्रीभाव रखने वाली सरकारें नहीं संगठित हो सकें। उन प्रदशा पर सोवियत की जकड़ डीली की जा सके और यदि "खुले" चुनाव के जरिए सोवियत विरोधी व उनसे स्वतंत्र पर पश्चिमो-मुखी तत्वा, यथा पुराने उद्योगपतियों, जमींदारों, बकरो तथा अर्ध युद्ध पूव के शासक वर्गों को संगठित किया जा सके, तो ऐसा किया जाए। इस तरह की कायवाहियों का नतीजा उल्टा ही हुआ। सोवियत शासकों के मन में पश्चिमी देशों के शासकों के इन अर्धनीपूण कृत्यों और वक्तव्यों ने कोई अच्छी छाप नहीं छोड़ी, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोवियत नेता, इस प्रकार के व्यवहार से क्षुब्ध जरूर हुए पर उन्होंने बहुत दूर तक 'सहयोग और सौहार्द वाला अपना युद्धकालीन रुख त्यागा नहीं बल्कि, ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना-चक्र से सतप्त रहते हुए भी, (यथा 20 सितम्बर, 1945 में अपने एक सम्पादकीय में सोवियत मुखपत्र इजवेस्तिया ने लिखा कि "पश्चिमी गुट पश्चिम में इसी विश्वास को समाप्त करने पर तुल हुए हैं।") उन्होंने परराष्ट्र मंत्रि परिषद की बैठकों में यह चेष्टा जारी रखी कि पराजित शत्रु देशों से शांति संधि सम्पन्न हो जाए। इस पराश्रम में आशिक सफलता हा मिल पाई क्योंकि युद्धकाल की सबसे बड़ी समस्याएं—जर्मनी व जापान से शांति संधियां कर पाना—तत्काल सुलभ नहीं पाई। केवल उही देशों से संधि सम्पन्न हो सकी जहां सोवियत या आगल अमेरिकी संघ का एकाधिकार बना हुआ था। ये देश थे इटली, रूमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और फिनलैण्ड। इनके बारे में संधि के प्रारूप तय हो सके और उसमें भी लगभग दो वष लग गए पर जर्मनी, आस्ट्रिया और जापान के साथ संधि सम्पन्न कर पाना तत्काल कठिन ही नहीं बन गया बल्कि तत्काल ऐसा लगने लगा कि यह काय असंभव बन गया है। पर जिन देशों के साथ सन 1947 तक संधि की शर्तें तय हो गईं, उनसे संबंधित प्रश्नों पर परराष्ट्रमंत्रि परिषद की बैठकों में काफी वाद विवाद छिड़ा, अनेक प्रश्नों पर मतभेद और असहमति के दौर चले और अंततोगत्वा शांति संधि के प्रारूप तय हो पाये जिनमें तत्कालीन "यथास्थिति" का

गया। सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का 'चाटर' (अधिकार पत्र) सविधान) तैयार कर लिया गया जो मित्र राष्ट्रों के युद्धांशहीन सहयोग, साहचर्य और सहोदाय का सर्वोत्तम फल था। इन सबके साथ साथ पोट्सडम सम्मेलन में उस कायविधि का बारे में भी निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत शांति रचना की जानी थी। इसके अनुसार यह तय हुआ कि प्रथम महायुद्ध के उपरान्त जसा शांति सम्मेलन बुलाया गया था, उस तरह का आयोजन न करके, पांच बड़े राष्ट्रों-संयुक्त राज्य, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन के परराष्ट्र मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे सन्तराष्ट्र के साथ संधि के मसविदा तैयार करें।

इतनी देर सारी तयारियाँ के बावजूद यदि शांति स्थापना का काम अन्त तोगत्वा ठंडा हो गया तो इसका मुख्य कारण या नये अमेरिकी शासकों का बर्ताव हुआ हल। ट्रूमेन शासन के लेबर और अदालत बदल चुके थे और अंग्रेज छत्र भङ्गिया बने उनकी हा ही में हा नहीं मिलाते जा रहे थे—बल्कि, उन्हें उकसाते बत रहे थे ताकि सोवियत संघ व विरुद्ध एक सुदृढ़ मोर्चा अमेरिका से बनवा कर अमरीकी परराष्ट्र नीति को यूरोप के घरेलू मामला में अच्छी तरह उलसा दें, इतना कि वे यूरोप की व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था के पुनर्निर्माण में पूरी दिलचस्पी से काम करें और अपनी परंपरागत "तटस्थतावादी" नीति की ओर न लौट पड़ें जिसका खतरा युद्ध खतम होते ही उस जबदस्त अमेरिकी अभियान के चलते चलते बढ रहा था जिसके अंतर्गत यह लोकप्रिय मांग अमेरिका की बस्ती-बस्ती में उठ रही थी कि "हमारे बच्चों को घर वापस बुलाओ।" चर्चित और उनके साथी लेबरदल के नेता तथा उनके यूरोपीय पिछलग्गू इस खतरे को भली भाँति भाव रहे थे और आसन्न विपदा को टालने के उपाय सोचने में लग गए। शीत युद्ध का अस्त इसी 'शीतान के कारखाने' की उपज था। उस युद्ध की विगुल बजे, इसके पहले यह मांग पश्चिमी देशों के जिम्मेदार हलकों में उठायी जाने लगी कि सोवियत संघ से युद्ध का खतरा बढ रहा है और पश्चिम इस युद्ध के लिए तयार रहे।¹⁶ यह कहा जाने लगा कि सोवियत बम्बे के बाहर यूरोप का जो भाग बचा हुआ है उसे संगठित किया जाए एक संयुक्त राज्य या इकाई की तरह और मजबूत किया जाए। फ्रांस, इटली व बेल्जियम तथा अन्य भी साम्यवादी दल एक संशक्त दल की तरह उभरे थे और पूँजीवादी व्यवस्था के पोषक तत्व नास्ती व फासिस्त ताकतों से साठ गाँठ कर बहुत बदनाम हो चुके थे तथा जनसाधारण के मन में उनकी साथ बहुत नीचे गिर चुकी थी। चर्च का हाल भी बहुत उजला बेदाग न था पर कुछ भी हो पश्चिम यूरोप को "सोवियत पंजों में पड़ने देने से रोकना जरूरी था। यह ब्रिटेन के शासकों की चिंता ही न थी बल्कि, यूरोप के समाजवादियों तथा चर्चवादियों का भी आंदोलन बन गया।¹⁷ जबदस्त आसन्न था परमाणु आयुधधारी, डॉक्टर सम्पन्न अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो अकेला महा

दत्त की तरह समुद्रपार करवटें बदल रहा था। लेकिन इस बिगड़त हुए माहौल में भी सोवियत संघ के साथ मिलकर अर्ध मित्र राष्ट्रों ने समुक्त राष्ट्र की स्थापना कर ली थी और उस जगत व्यापी संगठन ने अपना काम शुरू कर दिया था और अब सड़ते पगड़ते हुए भी मित्रराष्ट्र पराजित शत्रु देशों के साथ शांति संधियां करने की योजना बना रहे थे। इस बदले हुए वातावरण में आग्ल अमेरिकी नेतृत्व में ऐसे प्रयत्न चल रहे थे कि जितना कुछ हो सके, याल्टा और पोतस्डम के समझौते से, विशेषतः उन समझौतों से जिनमें सोवियत संघ को कुछ विशेष सुविधाएं तथा अनुग्रह दिए गए थे, वचनबद्धता कि, सोवियत सेना न जिन प्रदेशों को अपने बाहुयत्न से “मुक्त” कराकर अपने अनुकूल राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न शुरू कर दिया था, वहां सोवियत के प्रति मैत्रीभाव रखने वाली सरकारें नहीं संगठित हों सकें। उन प्रदेशों पर सोवियत की जकड़ ढीली की जा सके और यदि “तुले” चुनाव के जरिए सोवियत विरोधी व उनमें स्वतंत्र पर पश्चिमोन्मुखी तत्वा, यथा पुराने उद्योगपतियों, जमींदारों, बैंकों तथा अर्ध युद्ध पूर्व के शासक वर्गों को संगठित किया जा सके, तो ऐसा किया जाए। इस तरह की कायबाहियां वां नतीजा उल्टा ही हुआ। सोवियत शासकों के मन में पश्चिमी देशों के शासकों के इन अमर्त्यपूर्ण कृत्यों और वक्तव्यों ने कोई अच्छी छाप नहीं छोड़ी, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोवियत नेता, इस प्रकार के व्यवहार से क्षुब्ध जरूर हुए पर उन्होंने बहुत देर तक “सहयोग और सौहार्द वाला अपना युद्धकालीन रुख त्यागा नहीं बल्कि, वे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना-चक्र से सतप्त रहते हुए भी, (यथा 20 सितम्बर, 1945 में अपने एक सम्पादकीय में सोवियत मुखपत्र इजवस्तिया ने लिखा कि “पश्चिमी गुट पश्चिम में उसी विश्वास को समाप्त करने पर तुले हुए है।”) उन्होंने परराष्ट्र मंत्रि परिषद की बैठकों में यह चेष्टा जारी रखी कि पराजित शत्रु देशों से शांति संधि सम्पन्न हो जाए। इस पराक्रम में आशिक सफलता हा मिल पाई क्योंकि युद्धकाल की सबसे बड़ी समस्याएँ—जर्मनी व जापान से शांति संधियां कर पाना—तत्काल सुलझ नहीं पाई। केवल उही देशों से संधि सम्पन्न हो सकी जहां सोवियत या आग्ल-अमेरिकी सेना का एकाधिकार बना हुआ था। ये देश थे इटली, रूमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और फिनलैण्ड। इनके बारे में संधि के प्रारूप तय हो सके और उसमें भी लगभग दो वष लग गए पर जर्मनी, आस्ट्रिया और जापान के साथ संधि सम्पन्न कर पाना तत्काल कठिन ही नहीं बन गया बल्कि, तत्काल ऐसा लगने लगा कि यह कार्य असम्भव बन गया है। पर जिन देशों के साथ सन् 1947 तक संधि की शर्तें तय हो गईं, उनसे संचित प्रश्नों पर परराष्ट्रमंत्रि परिषद की बैठकों में काफी वाद विवाद छिड़ा, अनेक प्रश्नों पर मतभेद और असहमति के दौर चले और अंततोगत्वा शांति संधि के प्रारूप तय हो पाये जिनमें तत्कालीन “यथास्थिति” को

स्वीकार करने के अलावा और कुछ चारा न था। यह सिलसिला निम्नांकित ढंग से चला।

लंदन में परराष्ट्रमन्त्री परिषद की प्रथम बैठक (सितम्बर, 1945)

परराष्ट्रमन्त्री इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले लंदन में सितम्बर 11, 1945 को मिले। बैठक में "पाच बड़ों" के परराष्ट्र मन्त्री शामिल हुए—अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बैठक 11 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चली। शुरू से ही ब्रिटेन और अमेरिका तीन बड़ों के अलावा किसी चौथे को लाने में हिचक रहे थे। अमेरिका जिस "चौथी" ताकत को लाना चाहता था, वह चीन था पर ब्रिटेन उसे नहीं चाहता था। ब्रिटेन फ्रांस को चौथा सवार बना कर लाना चाहता था जिसे अमेरिका और सोवियत दोनों ही नापसंद कर रहे थे क्योंकि "फ्रांस" के वास्तविक शासक माशल पेटा तो हिटलर के सहयोगी बन बैठे थे। लंदन में बचे खूबे फ्रांसिसियों के नेता "द गाल" यो तो अपने को स्वतंत्र फ्रांसिसियों के नेता घोषित किए बैठे थे, पर ये पूर्णतः चर्चिल पर आश्रित। स्टालिन और रुजवेल्ट दोनों ही इस चौथे सवार के पक्ष में न थे। स्टालिन चौथे सवार के रूप में क्याग कोई शेक वाले चीन के पक्ष में भी नहीं थे। पर अतर्क चर्चिल ने अपनी बात मनवा ली। इधर फ्रांस उधर चीन चौथे और पाचवें सवार बना दिए गए। यह युद्ध के अंतिम दिनों की बात थी जब संयुक्त राष्ट्र का ढांचा तैयार होने को था और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की नींव डाली जा रही थी। अथ शांति संधियों की रचना की बात शुरू हुई तो यह तय हुआ कि शांति संधियों पर विचार तो पांच परराष्ट्र मन्त्री इस परिषद में बैठकर करेंगे पर संधि रचना के लिए केवल उन्हीं देशों के मन्त्री उत्तरदायी होंगे जिन्होंने विराम संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार तीन बड़ों ने दो छुटमंडियों को विचार विमर्श में तो शामिल कर लिया पर उन्हें संधियों के बारे में फैसला करने का अधिकार नहीं दिया गया। वे इसमें मतदान नहीं कर सकते थे। इस प्रकार यूरोपीय शांति संधियों से 'एशियाई' एकमात्र शक्ति जिसे पांच पक्षों में एक माना गया था अलग कर दी गई। फ्रांस भी अलग हो गया, पर उसके हितों की देखभाल तो ब्रिटेन कर ही रहा था। सोवियत नेता इस संकुचित यूरोपवाद के खुद शिकार हो गए थे पर यह सिद्धांत कि जो विराम संधि में नहीं शामिल हैं, वे संधि नियम से भी बाहर रहेंगे, उनके विरुद्ध ही जाने वाला था, जब सुदूरपूर्व के बारे में फैसला करने की बात उठनी थी। स्मरणीय है कि इस सम्मेलन की शुरुआत होने के पहले फ्रांस ने दगाल ने एक बखर्ब्य में कहा कि पश्चिमी देशों का एक मजबूत गुट बनाया जाना चाहिये जिसका सोवियत संघ ने विरोध किया। इसके अलावा इस बैठक में इतालवी

घाति संधि पर चर्चा हुई पर सफलता नहीं मिली। मुख्य टकराव सोवियत और दो अन्य बड़ों, अमेरिका व ब्रिटेन के हितों के बीच हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका सोवियत संधि को इटली के मामले में वही भी कोई सहूलियत देने को तैयार न था। यह प्रदेश "पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र" का एक प्रमुख भाग था। सोवियत संधि के नेताओं की मांग थी कि—

(1) ट्रीस्ट और फ्यूम के बदरगाहों के साथ साथ जूलियन माच का इलाका यूगोस्लाविया को दे दिया जाए, चूंकि उस पर यूगोस्लाविया का दावा तक सगत है।

पर इस मामले में ब्रिटेन और अमेरिका का रुख कुछ दूसरे ढंग का था। वे ट्रीस्ट के बदरगाह का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे और जूलियन माच को भाषा तथा संस्कृति के आधार पर यूगोस्लाविया और इटली के बीच बांट देना चाहते थे। इस प्रश्न पर असहमति हो जाने के कारण यह मामला उप परराष्ट्र मंत्रियों को सौंप दिया गया।

(2) ऐसी ही कठिनाई क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर हुई। सोवियत संधि की मांग थी कि इटली से 60 करोड़ डॉलर हर्जाने के तौर पर वसूल किए जाए और उसका अधिकांश सोवियत संधि को इसलिए दिया जाए चूंकि, महायुद्ध में सबसे अधिक क्षति सोवियत संधि की ही हुई है। ब्रिटेन और अमेरिका इस मांग का समयन करने को तैयार न थे क्योंकि, उनकी दृष्टि में इटली इस क्षतिपूर्ति के बोझ को सभाल नहीं सकता है तथा उन्होंने ही इटली को युद्ध पूर्व भारी मात्रा में उधार की रकम दे रखी थी, जिसे वसूल कर पाना इन्हीं के लिए कठिन था। फ्रांसीसी इटली इनका ही तो पाला पोसा "साठ" था जो अक्टूबर क्रांति के माहौल में हुडदग मचाने के लिए खूब खिला पिला कर मोटा किया गया था।

(3) सोवियत संधि के नेता साम्राज्यवादियों की पचायत में बैठकर इस जघन्य अपराध के भी दोषी बन गए, जब उन्होंने उपनिवेशों की "बदरबाट" में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। इतिहास का यह क्रूर व्यर्थ देखिए कि लेनिन के उत्तराधिकारी उपनिवेशवाद को समूल नष्ट करने के बजाय साम्राज्यवादियों से इस 'बदरबाट' में हिस्सा मांग बैठे। उन्होंने मांग की कि ट्रिपो लिटानिया पर उन्हें यास स्थापित करने का अधिकार दिया जाए। पर मजे हुए अपराधकर्मियों के बीच उनकी दाल गलन वाली न थी। ब्रिटेन और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे सोवियत संधि को इस प्रदेश पर यास देकर भूमध्य सागर के रास्ते को अपने एकाधिकार से मुक्त नहीं करना चाहते थे और न इसके लिए तैयार हुए कि महा सोवियत के पजे मड़ने दें ताकि उन अरब देशों पर जो पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र में थे, सोवियतों की छाया न पड़े।

(4) यही बात सोवियत संधि की उस मांग पर हुई कि उसे इटली की नौ

गना जहाजों में हिस्सा मिले। ब्रिटेन व अमेरिका इटली के मामले में सोवियत संघ को किसी प्रकार की हिस्मदारी देने को तैयार न थे। व इटली को दृढ़तापूर्वक अपने प्रभाव क्षेत्र का अंग मानते थे। उनकी रूचि न तो "लेन देन" में थी और न य सोवियत संघ को अपने प्रभाव विस्तार के लिए कोई भी ऐसा मौका हाथ नहीं लगने देना चाहते थे जो बाद में उनके लिए सिर दब बन। उनकी रूचि उन प्रदेशों में अपनी घुसपैठ करने की थी, जो तब सोवियत संघ के वरिष्ठ में आ चुके थे, वे प्रदर्श जो लाल सेना के कब्जे में थे।

इन प्रश्नों पर यथा जव सोवियत मंत्री मोलोटोव ने बुलगारिया और रूमानिया की तत्काल सगठित की गई सरकारों को मायता देने का प्रश्न उठाया, ब्रिटेन व अमेरिका के प्रतिनिधियों ने अपना विरोध यह कहकर प्रकट किया कि ये सरकारें सही माने में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें नहीं हैं, अतएव इन्हें मायता देने का प्रश्न ही नहीं उठना। अमेरिका ने हंगरी, बुलगारिया और रूमानिया के संबंध में सधिया के प्रारूप प्रस्तुत किये।¹⁸

इस प्रकार सभी विचाराधीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उग्र मतभेद उभर आए और परिषद का यह पहला सम्मेलन इस अर्थ में तो विफल रहा कि बात सुलह की हो नहीं पायी पर इस अर्थ में यह सफल भी रहा कि मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने एक दूसरे के सामने बंदरबाट के अपने सौदों की "तर्ज" रख दी और एक दूसरे को जानकारी दे दी तथा यह सिलसिला शुरू कर दिया कि जो हमारे पास है उसमें तो दूसरों को कुछ देना नहीं लेकिन जो दूसरों के पास है उसमें से कुछ मिले तो ले लिया जाए। स्पष्ट था कि सनिको ने जो फैसला कर दिया था उसके आगे न सोवियत संघ और न पश्चिमी 'बड़े' एक इंच भी आगे बढ़ने को तैयार थे। युद्धकाल का मंत्री सगठन ऐसा टूट रहा था कि अब फिर से जुड़ने की उम्मीद तिरोहित होती दिख रही थी। पर बातचीत का सिलसिला अभी टूटनेवाला न था।

तनाव बढ़ता गया

इधर उधर केवल बाता का ही जमा खच नहीं हो रहा था। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम की ताकतें सुदूरपूर्व में अपने नव अजित प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में जुटी रही। उनके इशारों पर दक्षिण कोरिया के प्रदेश में सिधमरी के नेतृत्व में एक अमेरिका परस्त तथा सोवियत विरोधी सरकार गठित हो गई जिसके फलस्वरूप उत्तरी कोरिया में सोवियत प्रभाव को सुदृढ़ करना सोवियत संघ के लिए आवश्यक बन गया। सोवियत संघ ने मंचूरिया में भी अपनी सैनिक स्थिति सुदृढ़ करनी शुरू कर दी जिसका अर्थ था चीनी और कोरियायी साम्यवादियों की स्थिति को पुष्ट करना। लंदन सम्मेलन की विफलता न यूगोस्लाविया के नेताओं को नी

मामलो में फिर से दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया जिसका फल यह हुआ कि यूनान में साम्यवादिया के प्रभाव में कुछ उफान आने लगा। स्मरणीय है कि यूनान के "द्वितानी प्रभाव क्षेत्र" में स्टालिन ने भाग लिया था और वे आगे बढ़कर यूनानी कम्युनिस्टों को सहारा देने की नीति त्याग चुके थे। इटली के मामले में समझौता हो जाता तो यूगोस्लाविया भी ढीला पड़ जाता। यूनान में स्थिति पूरी तरह ब्रिटेन के पक्ष में आयी भी नहीं थी। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया का सहारा मिलने पर वाजी अभी भी पलटी जा सकती थी। लंदन सम्मेलन के बाद यूनान में कम्युनिस्टों के प्रभाव में बढ़ोत्तरी हुई और मिन राष्ट्रो के बीच तनाव बढ़ने लगा।

सर्वाधिक महत्व का प्रश्न परमाणु आयुध सबधी रहस्य का क्या हो

हर उदीयमान राष्ट्र के जीवन में कभी कभी एकाध बार ऐसा ऐतिहासिक अवसर आते हैं जब उसका वरण करने के लिए महानता स्वयं दरवाजे पर दस्तक देती है। अमेरिका के जीवन में दूसरी बार ऐसा अवसर उपस्थित हो रहा था, जब एक महान अमेरिका की दृढ़ नींव ढाली जा सकती थी।¹⁹ यह अवसर माग कर रहा था कि अमेरिका अपनी भीषण विध्वंस शक्ति "परमाणु आयुध" के रहस्यों की जानकारी अरबों के लिए सुलभ कर, उस रहस्य पर से परदे उठाकर "परमाणु शक्ति" के दोहन को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में दे दें ताकि, इस महती शक्ति का रचनात्मक उपयोग जनसाधारण के व्यापक हित में किया जा सके और छोटे बड़े सभी राष्ट्र इस क्षेत्र में कमर तोड़ प्रतियोगिता के चक्कर में पड़ने से बच जायें। इसका परिणाम यह भी होता कि संयुक्त राष्ट्र की जड़ें बहुत मजबूत हो जाती, निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव व योजनायें पाखंड बनकर न रह जाती। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस मुहूर्त के महत्व का ध्यान में रखते ही एक अजीब पछतावा होता है। कितना विपुल धन, और कितनी अकूत मानवीय शक्ति का इस "परमाणु विध्वंस" की साज सज्जा में, बड़े राष्ट्रों की आपसी होड़ में तथा छोटे अधमरे देशों के "परमाणु शक्ति" बनकर एक झूठी महत्ता अर्जित करने की चाह में नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका के तत्कालीन मदाघ शासको ने "परमाणु शक्ति" के रहस्य को अपने एकाधिकार में रखने की दुरमि सधि रची यद्यपि उनमें श्रेष्ठ वैज्ञानिक तथा दूरभूत के मंत्रिमंडल के बहुसंख्यक सदस्यों ने तब इस 'परमाणु रहस्य' के क्षेत्र में सोवियत सत्ता के साथ साझादारी करने का प्रस्ताव रखा था।²⁰ अमरीका दूसरी ओर मुड़ गया और उससे शासको ने यह कोशिश की कि 'परमाणु शक्ति' के रहस्य अमेरिका की मुट्ठी में ही बंद रहें। अमेरिकी शासको ने अपने आपको और अपनी अमेरिकी जनता को भुलावे में रख पाने की ऐसी अदभुत क्षमता है, जैसी किसी अन्य शासक के पास नहीं है। पर एमें दूरदर्शी व

साहसी अमेरिकी भी थे जो प्रोफेसर हैरॉल्ड मेउरे की तरह एक बहुत बड़ परमाणु वैज्ञानिक जो यह चेतावनी देने से नहीं घूबे कि "हम बम बना रहे हैं और उन्हें सजो रहे हैं और इस प्रकार दूसरे दशा के लिए खतरा बन गए हैं। ज्ञान और हथियारों की होड़ शुरू करने के अपराधी हैं।"²²

यों परमाणु बम का रहस्य गुप्त रख लिया गया और परमाणु बम चलाने की घमकी खुलकर दी जाने लगी। चर्चित बर्ट्रैंड रसेल से लेकर सिनेटर जानसन तक सभी के लिए "परमाणु बम" के द्वारा अंतिम फैसला करवा देने की घमकी देना आम बात हो गई। इस प्रकार शांति की मुख्यवस्था स्थापित करने के बजाय ट्रूमेन व उनके सहयोगी युद्ध का नगाड़ा बजाने लगे मानो सोवियत संघ उनका मित्र राष्ट्र न होकर हिटलरी जर्मनी और फासी इटली का स्थानापन्न शत्रु राष्ट्र हो जिससे घमकी के बल पर ही "सीदा" किया जा सकता हो।

परराष्ट्र मंत्रियों का मास्को सम्मेलन (दिसम्बर 1945)

युद्ध की समाप्ति का वष समाप्त होने जा रहा था। शांति के कपोतो पर ऐसा पहराव अमेरिका ब्रिटेन की ओर से हो रहा था कि वे महु लुहान हो रहे थे, पर युद्धोत्तर समझौते की आशा अभी खतम नहीं हुई थी। यह तय हुआ था कि परराष्ट्र मंत्री हर तीसरे महीने मिला करेंगे। अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री ने मास्को से सम्पर्क किया और तुरत ही बैठक के लिए उन्हें आमन्त्रित किया गया। मास्को में वाशरनीज और स्तालिन के बीच तीन बैठकें हुईं और बहुत सारे मसलों में सहमति हो गई। इस सम्मेलन में फ्रांस और चीन के परराष्ट्र मंत्री नहीं बुलाये गये। वाशरनीज की भी यही सलाह थी।

मुख्य मसला था पांच शत्रु राज्यों के साथ संधियों के प्राख्य पर विचार करना तथा रूमानिया और बुल्गारिया की सरकारों को मायता देने के प्रश्न को तय करना। इसके साथ ही परमाणु शक्ति के नियंत्रण की समस्या पर भी विचार करना तय हुआ था। सुदूरपूर्व अर्थात् जापान एवं कोरिया के प्रश्न तथा ईरान से मित्र राष्ट्रों की फौजों को हटाना और उसकी प्रभुसत्ता को पुन प्रतिष्ठा ऐसे प्रश्न थे जो मुह बाये खड़े थे।

सम्मेलन की कार्यवाही ठीक से शुरू हो गई। पहली समस्या के बारे में यह तय हो गया कि संधियों के प्राख्य उन राज्यों के द्वारा तैयार किए जायेंगे जिन्होंने विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। केवल इटली वाले प्राख्य के संबंध में फ्रांस को जोड़ दिया जायेगा। फिनलैण्ड के मसल में सोवियत संघ और ब्रिटेन हिस्सा लेंगे। बाल्कन राज्यों के बारे में "तीन बड़े संधि की रचना करेंगे। जब सारे प्राख्य तैयार हो जायेंगे, तब 21 राज्यों के एक सम्मेलन के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत किया

बने। जिन्होंने देवकी देव अन्तिम होने दिखते दुरोध को धुनि में लहरों में डालने के लिए किया है। दुरोधों ने जिन्हें और अमेरिका के सदस्य भारत (पराधीन) अन्तिम में लड़ने के लिए छोड़ा है। ईसाईयों को भी शामिल किया गया। इन प्रकार के सम्मेलन में विचार-विमर्श होने के बाद सदस्यों के अन्तिम प्राप्ति वाली शक्तियों के द्वारा तब कि जबकि जिन्होंने इन प्राप्ति की रचना की थी। अन्तिम मानने में वे प्राप्ति उन सभी राज्यों के सम्मुख रखे जायेंगे जिन्होंने युद्ध की घोषणा की थी लेकिन वे अभी लाइ माने जायेंगे जबकि इनकी संपूर्णता सभी देशों के द्वारा हो जायेंगे जिन्होंने विचार सचि पर हस्ताक्षर किये हैं पर्याप्त चीन दंड और पराजित शत्रु राष्ट्र। इस समझौते में सोवियत संघ का यह अधिकार बना कि "या कि संधियों का मानता चीन दंड ही तब करे भले ही उस पर तब चीन" की नीति से सी जाए जो परिचयी "दंडों" का पट्टा रहा। भारत ने भी इन की सोवियत सचि संधियों को मान बहस का विषय नहीं बनाया पाएँगे। या तो बर्तों पुनर्पुनः तौर पर न्य हो जायें या दंडों की छोटी बैठक में। इस सम्मेलन में यह भी तब हुआ कि संधि होते ही मित्र राष्ट्र इन देशों से अपनी सेनाएँ हटा लें। इसमें एक अपवाद मान लिया गया कि सोवियत ने तब एगरी और रुमा निना में तब तक अपनी सेनाएँ रखा रखा, जब तक जोरिद्वारा के साथ संधि सम्मेलन न हो जायें।

इस सम्मेलन ने एक सुदूरपूर्व आयोग की भी स्थापना की जिसका मुख्यालय अफ़्गानिस्तान में रखा गया और जिसके जिम्मे यह काम सौंपा गया कि यह आपात के हांग संधि दायित्वों को पूरा करने के सबंध में नीतियाँ और स्तर तय करें और जो जनरल मेकायर, सर्वोच्च सेनापति के नीति निर्देशों की परीक्षा कर सकें। इसमें सोवियत सचि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, हासलैण्ड, बनावडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिजीपीन्स तथा भारत (पराधीन) को स्थान दिया गया। इसमें अलावा जापान के लिए मित्र राष्ट्रों की एक परिषद भी बनायी गयी जिसमें अमेरिका, सोवियत सचि, ब्रिटेन और चीन को ही सदस्यता दी गयी। इस परिषद की अध्यक्षता प्रान्त महासागर में मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति को सौंपी गयी और उसका प्रमुख के दालय टोकियो में स्थापित किया गया।

इसके अतिरिक्त (1) एक सोवियत अमेरिकी सम्मेलन जो पोरिया में प्रशा पर विचार करें और एक ऐसा समुक्त आयोग जो पोरिया में काम पताऊ सोव-तीय सरकार की स्थापना की योजना बनाये, बनाये गये (2) यह भी तय हुआ कि चीन से सोवियत और अमेरिकी नेताओं को तुरत वापस बुला लिया जाए तथा (3) एक तिसदसीय आयोग रूमानीया के लिए बनाया जाय जो रूमानीया जाये और राजा माइनेल को इसमें मदद करें कि राष्ट्रीय किसान दल का एक सदस्य और एक सदस्य उदार दल का कैबिनेट में शामिल किया जाय ताकि उन्मुख गेते मातामण्ड

म त्रिगम, त्रैम, भाग्य और ममाका 1 की वगैरहो, खुदाय कराये जा सकें तथा (4) सावित्र गण का 1- त्रिगमारी मोरी ममा कि व- माकाकाय मुटो व दो प्रतिनिधियों को बुलगाविया की वधिभट 11 कादिम कराय 1 यह लय हुतादि न सारे वदम उठा दिद जाने के बाद ही कमानिया और बुलगाविया की ममाका 11 परिपथी सावित्रा मायगा देगी ।

अतिस महत्व का भाग परमाणु आयोग की स्थापना के संबंध में सी। बदा मीज ने तो पाठा था कि सम्मेलन में सबन पहुँ 1 दुगक बार व तय हो पर माने मोय ने इस विषय गूथी 11 अतः म रग निया । मोमोताव ने अमेरिका के उस मुताब का पहुँ तो विरोध किया त्रिगम अनुसार इगमत 1 को मीही दर सीही 11 वगमा पा पर बाद में व मान मय । 15 नवम्बर का वाकिमपटा परमाणु समझौता स्वी बार कर लिया गया त्रिगम गुग्गा परिषद व अधिकार सुरक्षा कर न्दिये दद । कसिया न परमाणु यम की पचा ही नह । की । बैठक 16 मितबर 11 चलकर 27 दिसबर को समाप्त हो गई ।

मास्को सम्मेलन में इस तथ्य को अच्छी तरह उद्घाटित कर दिया था कि सोवियत सभ मुद्रवासीन मत्री को तोडा व कोई दिसपस्ती नही रसता वरन् व समझौताबादी रुग बनाय दूण है और सभी मसला पर मिल जुल कर चलन को तैयार है । लेकिन जब अमेरिकी परराष्ट्र मत्री सम्मेलन समाप्त कर घर लौटे तो उह भी यह दावर रोदपूण विस्मय हुआ कि अमरीकी 'ग्रेम' का एक मुगर अग मास्को समझौते को 'सुष्कीकरण का वदम ठहरा रहा है । दुभाग्य इमने बडा यह था कि राष्ट्रपति ट्रुमेन आग बबूसा हो रह थे कि बायरनीज ने वाता के दोरान उता सपन नहीं रगा और जितनी सगरी के पाहते थे, उतनी सखी के माय व कसिया स पेस नही आण । ईरान के मसल म कसी बारवादयो का उहोने विरोध नहीं किया । ट्रुमेन ने बायरनीज को जो पत्र भेजा उसमे उहोने लिता

‘ मेरे मन में थोडा भी सदेह नहीं है कि रूस तुर्की पर हमसा करना चाहता है और बाले सागर में और भूमध्य सागर में उसके इसाका को छीनलेगा चाहता है । यदि रूस का सामना तनी मुठटिया तथा कडी भाषा के साथ न किया गया तो दूसरी सडाई अन्दर ही अन्दर पकती रहेगी । वे बेवत एव ही भाषा समझते हैं— तुम्हारे पास मना की टुकडिया कितनी हैं ?

मैं नहीं सोचता कि अब आगे कोई समझौते की बात हो । जब तक वे हमारी वातें न मानें, हमे कमानिया और बुलगाविया को मायता नहीं देनी चाहिए हम रूस स अपने जहाजा की वापसी पर जोर देना चाहिए और रूस को दिया गया उधार पट्टे का हिसाब चुकता नरन के लिए जोर देना चाहिए । मैं सोचि यतो को पालने में खुलाते खुलाते पक गया हूँ ।²²

रूस से तुरत हिसाब नहीं हो सका पर बायरनीज का हिसाब तुरत चुकता

कर दिया गया। बहटा दिए गए। टूमेन के ये लिपिबद्ध उद्गार, जैसा उन्होंने अपने सस्मरण में खुद कहा है अमेरिकी परराष्ट्र नीति में एक नये मोड़ के सूचक हैं।⁴ टूमेन की उम्र मन स्थिति के निर्माण की प्रक्रिया का यहाँ आभास मिल रहा था जो अपने पूरे विस्फोटक रूप में साल-सवा साल के बाद 'टूमेन सिद्धांत' की घोषणा के रूप में 'शीत युद्ध' की शख्श्वनि करने वाली थी। आम लोग समझ रहे थे कि मित्र राष्ट्र मिल जुल कर युद्धोत्तर मामले निबटा रहे हैं पर आग्ल अमेरिकी शासक अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहे थे जिस पर रखा ठकना थोड़ा सा हटते ही इतनी गरम भाप छोड़ गया था। वायरनीज ने कोई बड़ी बात न कर केवल इतना ही स्वीकारा था कि जो जहाँ अपनी मेना के छाये गया है, वहाँ की सधि का प्रारूप वह तय कर ले। उन्होंने रूसिया को घमकाने डराने की दुर्नीति का सहारा जरूर नहीं लिया।

पेरिस का उप परराष्ट्र मंत्री सम्मेलन

लंदन में परराष्ट्र मंत्रियों की परिषद ने जैसा तय किया था उसी के अनुसार जनवरी सन् 1946 में उप-परराष्ट्र मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसकी बैठकों में इन उप मंत्रियों ने सधियों के प्रारूप तैयार करने के प्रयास किये। ये बैठकें 12 जुलाई तक चलती रही, और इनमें पांच शांति सधियों के प्रारूप तैयार किए गए।

इन बैठकों में सबसे बड़ी अड़चन इटली और यूगोस्लाविया की सीमाओं को लेकर पैदा हो रही थी। प्रश्न 'ट्रीस्ट' प्रदेश के बारे में था कि यह यूगोस्लाविया को मिले या इटली को या कोई अन्य व्यवस्था की जाय। इस प्रदेश में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने भी प्रवेश किया था और यूगोस्लाव सैनिक भी थे। तब दोना के बीच यह समझौता हुआ था कि ट्रीस्ट नगर को दो भागों में बांट दिया जाय। पेरिस सम्मेलन में सोवियत ने जूलियन माच के इलाके को भाषा और संस्कृति के आधार पर यूगोस्लाविया को देने का अनुरोध किया। पर ब्रिटेन और अमेरिकी ने इस तक को नहीं माना। वे इन आधारों पर दोनों का दावा मान रहे थे। सोवियत सध ट्रिपोलिटानिया पर अपना दावा छोड़ने को सहमत थे बशर्ते कि यूगोस्लाविया को ट्रीस्ट दे दिया जाए पर दो बड़े राजी नहीं हुए। अंत में फ्रांसिसी मंत्री विदो के सुझाव पर इस नगर के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को मान लिया गया। 29 जून को विदो ने एक सात सूत्री कार्यक्रम सुझाया जिसके अनुसार 10 वर्षों तक ट्रीस्ट को स्वतंत्र नगर बना कर रखा जाय और उसका प्रशासन में सोवियत सध अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूगोस्लाविया को शामिल किया जाय। इसमें सुरक्षा परिषद और इसके निवासियों को भी हिस्सेदारी मिले तथा प्राथमिक असंख्यता बनाये रखने का भार सुरक्षा परिषद को सौंपा जाए। जूलियन माच के बारे में बाद को यह तय किया गया कि इसका अधिकांश यूगोस्लाविया को दे दिया

जाण । स्वतंत्र नगर व वार म एवं सविधान की रचना भी हुई जा दृष्टी से की जान वाली संधि में जाह दिया गया ।

द्वितीय शीतयुद्ध की तैयारी, उपर सम्मेलन

शांति संधिवा वाला मसला पेरिस के सम्मेलन में अतत निबटे इस परन्तु शीतयुद्ध के गोले दागे जान लग । अमेरिकी शासकों का मिजाज बिगड़ रहा था । वे अब साविधता के साथ हंस बोल कर युद्धोत्तर पुनरुपना में दिलचस्पी लेने को बतई तयार नहीं थे । जितना कुछ घोंस घमकी स छुड़ा सकें, उतना सोविधता में छुड़ा लें पर जो घब रहा है, पूजीवादी दुनिया का जो भाग एशिया अफ्रीका में तब भी बरफ़ार था और बलिन व पार का पश्चिमी यूरोप उसे सगठित करें और सोविधता का कमजोर बनाकर कासातर में पूर्वी यूरोप को भी हथिया लें, एना योजना उन पश्चिमी देशों के शासक बग व मन को बचन परन लगी जिनकी बसा अमेरिकी राष्ट्रपति अपन हाथ में लिए हुए थे । वे परमाणु बम घारी तो थे ही । इस ध्यान में रखकर उधार पट्टे की बात सतम कर दी गई थी । अमेरिकी राष्ट्रपति के सभापतित्व में फ्ल्टन म चर्चिस का वह दहसान वाला भाषण दिया जा चुका था जिसमें 'लाह आवरण' में पनपने वाली रूसी तानाशाही को सलकारा गया था । बुनौती रूसी शासकों को सभी मोर्चे पर दी जा रही था और सोविधत संध का एक ऐसी दुर्दांत शक्ति के रूप में पेश किया जा रहा था जो पश्चिमी सम्मिता के लिए एन ऐसा भारी खतरा हो जिससे भिड़ने के लिए ध्वसा बनेप फासी और नाज़ी शक्तियों को यथा पुतगाल और स्पेन को तथा पश्चिम में लुके छिपे नाजिया को गले लगाए बिना पश्चिम का काम नहीं चलने का हो । मुददे की बात यह थी अमेरिकी त्रितानी साम्राज्यवाद का गठबधन अपनी दृष्टी फूटती दुनिया को और अधिक दृढ़ करने के लिए कमर कस रहे थे । युद्धोन्माद फैलाने से बढकर और उपाय ही क्या था जब पूजीवाद की कलई पूरी तरह यूरोप में खूल चुकी थी, पहले हिटलर भुसोलिनी के हाथा और बाद में सोविधत शक्ति के सामने । एशिया और अफ्रीका के पददलित लोग ने अपनी आखों के आगे 'अजेय यूरोपीय शक्ति को एशियायी 'जापानी' सैनिक दाहो के आगे घुटने टेकते देख लिया था और उनकी 'अजेयता' का बुलबुला देखते ही देखते फूट गया था । जगह जगह आवाज बुलंद हो रही थी 'एशिया छोड़ो ! अफ्रीका छोड़ो !'

उभरते हुए इस साम्राज्य विरोधी एशिया अफ्रीका व्यापी अभिमान के दौरान आग्ल अमेरिका गठबधन की मुरय चिन्ता का विषय था कि किस प्रकार दृष्टी गिरती हुई साम्राज्यवादी पूजीवादी व्यवस्था को फिर से पायेदार बनाया जाय और सोविधत संध और विश्वपत उनके प्रभावक्षेत्र में आए इलाकों को जमने न दिया जाय तथा पुननिर्माण के कार्यों में शांतिपूर्वक उन्हें जुटने का अवसर प्राप्त

न होन दिया जाय। पर इस तरह का माहौल बनाना आसान न था। कल ही तो सोवियत की लाल सेना के तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, उनकी मित्रता और सोहाद्र की चचा जोरा पर थी, उन पर भरोसा करने की बात जनसाधारण की जुबान पर ला दी गई थी। इतनी जल्दी सोवियतता के बारे में हल कैसे पसंदा जा सकता था। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ा जा रहा था। सोवियत नेता भी तुर्कों व तुर्कों इन चाला का जबाब दे रहे थे पर समझौतावादी हल बनाये हुए थे, जसा मास्को सम्मेलन ने दिखाया। व अगले सम्मेलन में यह धारणा पुष्ट करने चल रहे थे कि सोवियत व्यवस्था पूँजीवाद से लड़ना नहीं चाहती, उसके साथ मिलजुल कर चलना चाहती है। मिलजुल कर उसने संयुक्त राष्ट्र बनाया है, शांति सधिया रच रहे हैं और भी आगे बहुत भारी बाता में सहयोग हो सकता है। व फुल्टन भाषण ऐसी बातों से भी इतने उत्तेजित नहीं हो रहे थे कि सहयोग और सोहाद्र के सार पुल ही तोड़ दें। विरोध करते जड़ते, आपत्ति करते पर अतंत सुलह के लिए प्रस्तुत हो जाते। महायुद्ध में सबसे भारी बलि उनके ही जनधन की थी, इतनी कि जिसका अर्थो का अंदाज लगाना कठिन हो रहा था। इस स्थिति में शांति का कोई भी विवर्त्य सोवियत के मन में, किसी भी नागरिक में, घासक दल के सदस्य के मन में अराजक रूप से आ ही कस सकता था। अमरीका और ब्रिटेन के सत्ताधारी इस खूब जानते थे।

पेरिस के शांति सम्मेलन की पूर्व पीठिका

इस उभ चूब वाले वातावरण में पेरिस में 25 अप्रैल 1946 में परराष्ट्र मंत्रियों का फिर से सम्मेलन हुआ। इस बार मोलातोव इस बात के लिए राजी हो गए कि फ्रांसिसी प्रतिनिधि भी भाग ले। मोलातोव ने अमेरिका द्वारा प्रस्तुत जमनी से संबंधित संधि प्रारूप तो यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इससे काम नहीं चलेगा। आस्ट्रिया के बारे में बातें करने से इन्कार कर दिया। इटली के उपनिवेशों का क्या हो, इस पर विवाद बना रहा—ऐस ही विवादग्रस्त ट्रीस्ट और बोडेलेनीज के मामले बने रहे। यही हथ उस प्रस्ताव का हुआ जिसे दिसंबर सन 1945 में वायरनीज ने स्टालिन के सामने रखा था कि जमनी को निःशस्त्र बनाये रखने की एक पच्चीसवर्षीय संधि की जाय जिसमें अनुसार रूस की सुरक्षा का एक और प्रबंध हो दूसरी ओर रूस की लाल सेना जमनी से वापस चली जाय। पर फुल्टन भाषण के बाद दूसरा अवसर पश्चिम ने, खो दिया था। ट्रूमेन से डाढ़ छाये हुए वायरनीज कर्म फूक फूक कर रख रहे थे और राष्ट्रपति के लहजे में लाल-पील होकर सोवियतों की घमकी दते जा रहे थे और सारा दोष सोवियत संध पर मढ़ रहे थे। एक बात हो गई थी जिसे रूजवेल्ट ने हमेशा बचाने की कोशिश की थी—आग्ल अमेरिकी गठबन्धन की हर मामल में एक गुट बनाकर सोवियत के

विरुद्ध मोर्चाबंदी अब खुले रूप में हो रही थी। इसमें अमेरिका के उन तत्त्वों को जरूर खुश कर दिया था जो ट्रूमैन के नेतृत्व में रुस से बड़ा इस पेशेवान के हिमायती थे।

पश्चिमी गोलाद्ध की प्रयोगशाला

अमेरिकी शासक वर्ग की अपनी भावी योजना की एक चालक पश्चिमी गोलाद्ध की प्रयोगशाला में देखने को मिल रही थी। पश्चिमी गोलाद्ध अमेरिका का अपना घर आगमन था। सबसे पहला कदम वहाँ ही उठाना लाजिमी था। ट्रूमैन ने 7 मई सन् 1946 में पश्चिमी गोलाद्ध के अपने किले की अस्त्र शस्त्रों में सुसज्जित करने का प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मुख रखा। डॉलर और हथियार इस गोलाद्ध के देशों में बरसने लगे और चार वर्षों के अन्दर ही लाखों डालर की कीमत वाले हथियार ही नहीं आये बल्कि, यहाँ के सैनिक तत्त्वों को इस हद तक पुष्ट किया जाने लगा कि एक के बाद दूसरी सोवियत सत्ता को उलटती चली गई और सैनिक तानाशाहिया स्थापित होती चली गई। अमेरिका की 'सौहार्द्रपूर्ण पद्धति' ध्वजा जगह जगह फहराने लगी। यह अमेरिकी जागतिक शक्ति की परराष्ट्र नीति का एक पूर्वाभ्यास सिद्ध हुआ जिसकी सपेट में शीघ्र ही बाकी पूँजीवादी दुनिया के क्षेत्र भी घसीटे गए। इसी तूफानी अभियान में फामोस स्पेन, पुर्तगाल व अर्जेंटीना मित्र बना लिए गए।

पेरिस सम्मेलन का दूसरा दौर

पेरिस में पुनः जून 1946 में परराष्ट्र मंत्रियों की बैठक हुई। मोलोटोव ने गतिरोध दूर करत हुए यह मान लिया कि बोडेलेनीज द्वीप यूनान को दे दिए जाए। अमेरिका का यह प्रस्ताव भी उठाने मान लिया कि साल भर के लिए इटली के उपनिवेशों के भविष्य की चर्चा टाल दी जाए। अगर आगल अमेरिकी गठबन्धन को यह डर था कि रुसी भूमध्य सागर में घुसपैठ करना चाहते हैं तो रुमिया ने इस भय को निर्मूल बना दिया। मोलोटोव ने यह भी मान लिया कि गति सम्मेलन 29 जुलाई से मुलाया जाए। तब वहाँ आगल अमेरिकी गुट ने सोवियतों की यह मांग मानी कि उन्हें इटली में दस करोड़ डालर ऋजनि के दिलवाये जाए और यह इटली के अतिरिक्त औद्योगिक साज सामान्य, तथा बाल्कन प्रदेशों में इटली की पूँजी व सम्पत्ति में और बाकी इटली के उत्पादन से बसूला जाए जिसके लिए बच्चा माल रुमी देंगे।

ट्रीस्ट के बारे में फ्रांसीसी प्रस्ताव द्वारा सुझायी गई वह विभाजन रेखा मान ली गई जो इटली और यूगोस्लाविया की सीमाओं को बाटेगी। ट्रीस्ट को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया, तपसील में बात बाद में तय होनी थी।

एक और प्रश्न पर विवाद था। मोलोटोव रूस का निषेधाधिकार उस प्रक्रिया के सबंध में भी चाहते थे जिसके अनुसार शांति सम्मेलन चलाया जाना था। इस पर भी समझौता हो गया। इस प्रकार फ्रांस के सहयोग और सोवियतता के समझौता परस्त रुढ़ ने शांति सम्मेलन की संभावना को सफलता के करीब ला दिया।

पेरिस का शांति सम्मेलन

(29 जुलाई सन् 1946 से अक्टूबर 15, 1946)

अतः वह घड़ी भी आई जब पेरिस में शांति सम्मेलन जुलाई 29, सन् 1946 का शुरु हुआ। इस सम्मेलन में 29 राज्यों के प्रतिनिधि जुटे और उन्होंने परराष्ट्र मंत्रियों द्वारा तैयार किए गए संधियों के प्रारूप पर विचार किया और अपनी अनुसारायें प्रस्तुत की। इसमें कुल 1385 प्रतिनिधि तथा लगभग दो हजार पत्रकारों ने भाग लिया। चार बड़ा ने प्रस्ताव रखा कि मामले दो तिहाई बहुमत से तय किए जायें छोटे देशों ने बहुमत से निषेध करने का प्रस्ताव रखा। समझौता यह हुआ कि परराष्ट्रमंत्रियों की परिषद को जो अनुसारायें भेजी जायें वे दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होने के बाद भेजी जायें तब साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव भी विचारायें भेज दिए जायें। सम्मेलन ने अपना सारा काम पांच आयोगों के माध्यम से तथा 4 समितियों के जरिये किया (सैनिक, कानूनी तथा दो आर्थिक समितियाँ) शान्ति देशों के प्रतिनिधियों को अपनी बातें रखने का मौका दिया गया परंतु मत देने का अधिकार न था।

नवंबर 4 से दिसंबर 12, सन् 1946 तक, फिर यूरोप में परराष्ट्र मंत्रियों की परिषद की बैठकें हुईं जिसमें पांच संधियों का अंतिम रूप दिया गया। इन संधियों पर पांच शान्ति देशों के प्रतिनिधियों तथा युद्ध में भागीदार सभी मित्र राष्ट्रों के हस्ताक्षर करवरी 10, सन् 1947 को हो गये जिसने युद्धोत्तर व्यवस्था निर्माण के कार्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा कर दिया।

इटली के साथ संधि

इस संधि में 10 धाराएं तथा 17 अनुक्रमणिकाएँ थीं इस संधि के अनुसार निम्नांकित क्षेत्रीय प्रबंध किए गए

(अ) क्षेत्रीय प्रबंध इस संधि के अंतर्गत इटली की सीमाओं में फेर को गई जिसके अनुसार फ्रांस को इटली वह पुराना भाग दिया गया जो लिटिल सेंट बर्नार्ड का दर्रा था मॉन्टेनापोर, चेवरतान माट नेनिस, टॉडा और ग्रीगा के नाम से जाना जाते थे। यूगोस्लाविया को इटली के जारा, पेलागोसा, सगोस्ता और डान-मेतो तट के दूसरे टापू दिए गए। इस्ट्रीया प्रायद्वीप तथा वनजिया मूलतः प्रात का अधिकांश टीस्ट को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया गया जिस प्रशासन के लिए सुरक्षा

परिपद में अंतर्गत रखा गया। यूनान को रोड्स तथा डोडेकनीज़ द्वीप दिए गए।

अल्बानिया में इटली के जा भी उपनिवेशों में उन्हें त्यागना पड़ा और यह तय हुआ कि सामंभर के अंदर चार बड़े तय करेंगे कि उनका क्या हो और तय न कर पाने की मरत में, यह मामला संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा को सौंप दिया जाएगा।

अल्बानिया को मुक्त कर दिया गया और इसी प्रकार इथियोपिया की स्वतंत्रता का मांगता दी गई। दिसंबर 1949 में महामभा तक लीबिया को स्वतंत्र कर दिया जाए। इतालवी सोमालीलैंड को दस वर्ष तक इटली के संरक्षण में रखा गया तथा इरीट्रिया को मई 1954 तक संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रखा गया।

निःशस्त्रीकरण

फ्रांस और युगोस्लाविया से लगने वाली इटली की सीमाओं का विसर्पीकरण किया गया। परमाणु आयुध, प्रक्षेपास्त्र, 30 कि० मी० से दूर कार करने वाले बंदूकें विध्वंसक, विमानवाहक पनडुब्बियां तथा वमवयक जहाज, की मनाही कर दी गई। बड़े और मझोले 200 टैंकों के रखने तक की इजाजत मिली, इसी प्रकार नौसेना में दो युद्धपोत तथा अन्य श्रेणी के जहाज 67500 टन तक के रखने की अनुमति मिली तथा नौसेना में 25000 अफसर और सैनिक, इसी प्रकार स्थल सेना की सरया 2 50,000 तथा वायुमना में 200 लड़ाकू जहाज तथा 150 भार वाहक जहाज रखने की इजाजत मिली।

1 क्षतिपूर्ति की व्यवस्था

इटली को युद्ध प्रारंभ करने का अपराधी ठहराया गया। अतएव यह तय हुआ कि युद्ध घोषित करने वाले देश की हैसियत से उस मित्र राष्ट्रों को 36 करोड़ डॉलर हर्जान में देने पड़ेंगे जिसे वह 7 वर्ष की अवधि में चुका सकेगा। इस हर्जान की रकम से सोवियत संघ को 10 करोड़ डॉलर, युगोस्लाविया को साढ़े बारह करोड़ डॉलर, यूनान को साढ़े दस करोड़ डॉलर, इथियोपिया को ढाई करोड़ डॉलर तथा अल्बानिया का 50 लाख डॉलर देने पड़ेगे।

2 बुल्गारिया के साथ संधि

बुल्गारिया के साथ जो संधि सम्पन्न हुई उसके अनुसार यह तय हुआ कि उसकी सीमा वह रहेगी जो जनवरी सन 1941 में थी। उसे कोई प्रादेशिक क्षति नहीं हुई बल्कि, रूमानिया से दक्षिणी दोब्रुजा का प्रदक्ष मिला।

बुल्गारिया की सैनिक क्षति की सीमा बांधी गई यथा उसकी स्थल सेना का 55 हजार नौसेना के साढ़े तीन हजार तथा वायुमना को पांच हजार दो सौ

सैनिकों तक सीमित कर दिया गया इटली की तरह अस्त्र शस्त्रा व मामलों में प्रतिबंधित कर दिया गया और विद्यमान व जलयानों की संख्या सीमित कर दी गई ।

यह भी तय किया गया कि वह यूनान की सीमा पर किलबंदिया नहीं करेगा ।

क्षतिपूर्ति के रूप में उसे साढ़े चार करोड़ डालर यूनान को तथा ढाई करोड़ डॉलर यूगोस्लाविया को 8 वर्ष की अवधि में चुकाने थे ।

3 हंगरी के साथ संधि

हंगरी के साथ जो संधि सम्पन्न हुई, उसमें निम्नांकित व्यवस्था की गई

आस्ट्रिया और यूगोस्लाविया से उसकी वह सीमा पुन स्थापित की गई जो पहली जनवरी सन् 1938 में थी । ऐसा ही सीमा निर्धारण चेकोस्लावाकिया के संबंध में हुआ (केवल चेकोस्लोवाकिया का डे-यूव के पश्चिम के तीन गांव तथा प्रातिस्लाव का दक्षिणी भाग दे दिया गया । सन 1938 के नवंबर 2 का वियना का फैसला रद्द कर दिया गया जिसमें फलस्वरूप रुमानिया को टा मलबेनिया मिल गया ।

सैनिक शक्ति को यहां भी प्रतिबंधित किया गया जिसके अनुसार स्थल सेना की अधिकतम सीमा 65 हजार, हवाई सेना की पांच हजार (तथा 10 जहाज) निर्धारित की गई । अथ अस्त्र शस्त्रों के बारे में वैसे ही प्रतिबंध लगाये गये जैसे इटली के साथ लगाये गये थे ।

क्षतिपूर्ति की रकम हंगरी का भी चुकानी थी । इसमें 20 करोड़ डॉलर की लागत का माल सोवियत संघ को तथा पांच करोड़ की लागत का यूगोस्लाविया को और 5 करोड़ की लागत का माल चेकोस्लोवाकिया को चुकाना था ।

4 रुमानिया के साथ संधि

रुमानिया के साथ जो संधि सम्पन्न हुई, उसकी धाराओं के अनुसार निम्नांकित व्यवस्था की गई

(1) पहली जनवरी सन 1941 की सीमाओं की पुन स्थापना की गई । केवल इसमें यह अपवाद रखा गया कि जो सोवियत रुमानिया समझौता सीमाओं के बारे में 28 जून सन् 1940 में हुआ था और सोवियत चेक समझौता 29 जून 1945 में हुआ था, उसको ध्यान में रखकर सीमा निर्धारण किया जायेगा ।

सैनिक शक्ति पर प्रतिबंध यह लगाया गया कि स्थल सेना की सीमा एक लाख बीस हजार सैनिक हवाई मारक तोपखाना पांच हजार तक, नौसेना 5 हजार सैनिकों तक तथा 15 हजार टन के जहाजों तक तथा वायुसेना हजार सैनिक और एक सौ पचास हवाई जहाजों तक रहेगी इटली की तरह ही अथ अस्त्र शस्त्रों

पर प्रतिवध रहेगा।

युद्ध की क्षतिपूर्ति रूमानिया को भी करनी थी। इससे अनुसार तौस करोड़ न लागत की सामग्री सोवियत सघ को आठ वष की अवधि तक पहुचानी थी।

अंतर्राष्ट्रीय सबष

5 फिनलेण्ड के साथ सधि

फिनलेण्ड वह आखिरी देश था जिसके साथ सन 1947 का मित्र राष्ट्रा ने सधि सम्पन्न कर ली। इस सधि के प्रावधानों में निम्नांकित व्यवस्था थी

(1) पहली जनवरी सन 1941 के समय की सीमाओं को पुन स्थापना की जायेगी। अपवाद एक यह था कि पेट्सामो प्रांत सोवियत सघ को दे दिया जायेगा। 12 मार्च सन् 1940 को सम्पन्न सावियत फिन शांति सधि की पुन स्थापना की गई पर इतना अंतर डाला गया कि सोवियत सघ ने हाया पर अपनी 'लीज' का दावा समाप्त कर दिया और 50 वर्षों की 'लीज' पर वह क्षेत्र प्राप्त किया जिसके लिए 50 लाख फिन मार्क सालाना चुकाने का समझौता हुआ और जो पोरक्कल उप के प्रदेश में है ताकि उस सोवियत नौ सेना का अड्डा बनाया जा सके।

सैनिक शक्ति पर प्रतिवध लगाय गये जिससे अनुसार सेना में अधिक से अधिक 34 हजार चार सौ नौ सेना में साने चार हजार सैनिक और 10 हजार टन का जहाज तथा हवाई सेना में 3000 सैनिक तथा 60 जहाज रखे जा सकें। फिनलेण्ड का भी युद्ध की क्षतिपूर्ति करनी थी इससे लिए उसे सोवियत सघ का 30 करोड़ की लागत की सामग्री 2 वर्षों की अवधि के अंतगत चुकानी थी।

शांति सधि रचना की प्रक्रिया यही थम गई

इन उपयुक्त पाठ पराजित शत्रु राष्ट्रा ने साथ शांति सधियाँ सार शयदा और मुसीबतों के बाद सम्पन्न हो ही गईं। इसका आगे यह प्रक्रिया चलनी पुष्कर हो गई यद्यपि प्रयत्न जारी रह कि आस्ट्रिया और जर्मनी तथा जापान के साथ भी युद्ध की स्थिति समाप्त होकर शांति सधियाँ सम्पन्न हो जाये। आस्ट्रिया और जर्मनी का मसाला यूरोप में सम्बंध रखता था। जापान सुदूरपूर्व एशिया का बड़ा प्रश्न था। पर इन समस्याओं का हल निवासना आसान नहीं था क्योंकि इन मामलों में पश्चिमी ताकतों की स्थिति अधिक मजबूत थी और उनका इरादा भी कुछ और ही थे।

जर्मनी और आस्ट्रिया सबकी सधि-वार्ताएँ, जो सफल नहीं रही द्वितीय महायुद्ध में घुरी राष्ट्रों का गठन मुख्यतः जर्मनी, इटली और जापान

को लेकर हुआ। घुरी राष्ट्रों की निर्मूर्ति इनको लेकर बनी थी, जैसे मित्र राष्ट्रों के तीन बड़े थे अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटन। विजेताओं की निर्मूर्ति ने युद्ध जीतने के बाद इटली और चार अन्य छूटभइय शत्रु दलों से तो शांति संधियां कर लीं। यह अपेक्षाकृत आसान मिट्ट हुआ क्योंकि पूर्वी यूरोप में लाल सना ने और इटली में आग्ल अमेरिकी सनाओं के एकाधिपत्य ने सैनिक हल पहल ही निकाल लिया था। उस पर राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाने की जरूरत थी। वह इन शांति संधियां ने जैसे तैम फितहाल पूरी कर दी। जर्मनी और आस्ट्रिया का मसला पेचीदा था क्योंकि यहा लाल सना भी स्थित थी और आग्ल अमेरिकी सेनायें भी अपना कब्जा जमाये बैठी थी। बाकायदा इ हान अपने अपने अलग सेनाधिकृत क्षेत्र बना रखे थे। ये समस्यायें तो मिल जुल कर, आपसी लेन देन के द्वारा ही, सहयोग और सौहार्द की भावनाओं के बल पर ही तय हो सकती थी जिससे स्रोत सूख खले थे। उल्टे पहले पश्चिम से धमकी और धुंढकिया भरे वक्तव्य दागे जाने लगे तो इनके जवाब में सोवियतों की आवाज भी तीखी और तल्लभरी हो गई। पुराने वायदों पर धूल पड़ने लगी। पुराने वाग्रदे क्या थे ?

पुराने वायदे और संकल्प आस्ट्रिया के साथ थे

आस्ट्रिया और जर्मनी के बारे में युद्धकाल में मित्र राष्ट्रों की ओर से मार-गर्भित अनुरोधों का समय पर हुई थी। उदाहरण के लिए आस्ट्रिया के बारे में युद्धकाल में ही नवम्बर में 1943 में मास्को में परराष्ट्र मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद आस्ट्रिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी जायेगी और यह घोषणा की गई कि जर्मनी के द्वारा बलपूर्वक आस्ट्रिया को जर्मनी में मिला देने की कारवाई एक अवैध और अमान्य ठहराई गई कारवाई थी नात्सी विरोधी आस्ट्रिया ने जितना प्रतिरोध कर सकता था, उतना किया पर हिटलर और उसके दलालों के आगे उसका बग नहीं लला यो तो माणस पैतृ ने भी फ्रांस को मित्र राष्ट्रों की सनाओं ने मुक्त कराया था। पर फ्रांस बड़ा में शामिल हो गया था आस्ट्रिया अपनी मुक्ति के लिए तीन बड़ा की सेनाओं की ओर ताकता रहा जो उसके क्षेत्र पर कब्जा किए रही। इस प्रकार उसके साथ जो कारवाई की जा रहा थी, वह अनुचित और विधि सम्मत न थी। आस्ट्रिया उस अर्थ में शत्रु देश न था। पर चाह न चाह, आस्ट्रिया का युद्धोत्तर भाग भी जर्मनी से जुड़ा ही रहा और क्योंकि उन मुल-क्षाना मुश्किल हो गया। कई बार परराष्ट्र मंत्रियों के सम्मेलन में आस्ट्रिया का प्रश्न उठा पर पश्चिम के दो बड़े और सोवियत संघ के बीच गहरा मतभेद बने रहे। जून जुलाई सन् 1946 में सम्मेलन की दूसरी बैठक में अमेरिका ने आस्ट्रिया से विदेशी सेनाओं हटाने का प्रस्ताव रखा पर वह सोवियत संघ का मंजूर नहीं था

क्याकि वह इसक लिए तैयार न था कि 'जर्मन समस्या' से इसे अलग कर हल करने का यत्न विचारणीय है। पश्चिम के देशों में 'शीत युद्ध' का पूर्वाभ्यास चल चुका था और पश्चिम जर्मनी का एक पश्चिम समर्थित पिछलग्गु राज्य के रूप में दालने का काफिरा शुरू हो गई थी। आस्ट्रियाई समस्या को इस युद्धोत्पत्ति को मनावृत्ति न निगल लिया। आस्ट्रिया इटली में मिला हुआ इलाका था, न युद्धोत्तर इटली था और न जर्मनी कि वहां केवल एक ही देश की सेना का आधिपत्य हो वह तो तभी अपनी समस्या का समाधान पा सकता था जब उभय पक्ष मिल बैठ कर हल निकालने की कोशिश करते। उस प्रकार की कोशिश के बदले अब माहौल विरोध व आरोप व प्रत्यारोप का तथा ऐसे वैमनस्य का बन रहा था, जो कभी भी नय युद्ध का विस्फोटक वागद बन सकता था।

अंततोगत्वा आस्ट्रिया की तत्कालीन समस्या सुलभी पर उस सुलझने में इस वष लग गये और जब कि नया युग शुरू हुआ जिसमें बातचीत द्वारा आपसी समस्याएँ सुलझाने के लिए नय मोड़ियत नेतृ व ने पहले की। नय सावियन नतत्व ने एक बार फिर जर्मनी की उबलन समस्या को हल करने के लिए पहले युद्ध की और उसी का पहला नतीजा था आस्ट्रिया के मामले का इस आधार पर तय करने की पदावधि कि आस्ट्रिया एक तटस्थ राज्य बन रहने का निर्णय करे। स्ट्रुइस्व इस प्रकार 'पश्चिम जर्मनी' के सम्मुख एक आक्षेप दृष्टांत पेश करना चाहते थे कि यदि जर्मनी भी तटस्थ होना तय कर ले और 'उत्तर अटलांटिक संधि संगठन' में शामिल न हो तो उसका 'एकीकरण' पर विचार संभव हो सकता है। आस्ट्रिया की तरह वह भी एकीकृत पर तटस्थ राज्य बन कर उभर सकता है। आस्ट्रिया के युजवा नतत्व ने समस्यादारी दिखाई स्ट्रुइस्व का आमंत्रण स्वीकार किया तटस्थता का स्वरूप लिया और समझौता हो गया। 27 जुलाई सन् 1955 को आस्ट्रिया स्वाधीन प्रमुता सम्पन्न और एकीकृत राज्य बन गया। संधि होने ही मित्र राष्ट्रों की पीछे हट गई और 15 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका, साक्षिमत संधि ब्रिटेन तथा आस्ट्रिया ने संधि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि के द्वारा आस्ट्रिया ने मध्य के लिए तटस्थ रहने की घोषणा की और उसकी संसद ने ऐसा स्वरूप पारित किया। इस संधि के द्वारा जर्मनी और आस्ट्रिया का क्लियर हमला के लिए निषिद्ध हुआ और आस्ट्रिया की वहां सीमा मान ली गई जो पहली जनवरी सन् 1938 की थी।

जापान के साथ शांति संधि सुदूरपूर्व के हल

पश्चिम की सबसे बड़ी और एकमात्र साम्राज्यवादी शक्ति जापान ने जब मित्र राष्ट्रों व आग घुटने टक किए तब पराजित एवं अधिभूत जापान का स्थिति जर्मनी की तरह ही होकर इटली की तरह बनी अर्थात् मित्र राष्ट्रों में विलीन

अमेरिकी फौजों ने पूरे जापान पर कब्जा किया। वस्तुतः जैसा हम अग्रिम बता चुके हैं, सोवियत संघ के साथ साझेदारी न करने का मन बनाकर ही अमेरिका ने अनेक कारणों के साथ इस कारण से भी दो परमाणु बम जापान में छोड़े थे ताकि, युद्ध का फैसला शीघ्रातिशीघ्र हो जाये और उह सोवियत की लाल सेना के साथ उस तरह की भागीदारी न करनी पड़े जैसी जर्मनी में हो गयी थी। पर जापान पर तो अमेरिकी फौजी दस्तों ने एकाधिकार कर लिया। तत्कालीन जापानी 'साम्राज्य' के संपूर्ण भाग पर वे काबिज न हो सके। कोरिया के आधे भाग पर, तथा चीन के मंचूरिया प्रदेश और उन प्रदेशों पर जिन्हें युद्धकाल में सोवियतों को मँट करना सय हो चुका था, यथा कुरील द्वीप एवं सखालीन द्वीप समूह, पोर्ट आयर तथा पोट डेरियन आदि पर सोवियत की लाल सेना ने कब्जा कर लिया।

मित्र राष्ट्रों के बीच जो युद्धकालीन समझौते जापान के सम्बन्ध में हुए थे, यथा काहिरा में, याल्टा में तथा पोट्सडम में, उनके अनुसार यह तय हुआ था कि जापान की प्रभुसत्ता चार बड़े तथा कुछ छोटे राष्ट्रों तक सीमित की जायगी, कोरिया का एक स्वाधीन राज्य बनाया जायेगा सोवियतों को वे सारे प्रदेश वापस सौटाये जायेंगे जो जारशाही रुस से सन 1904 में छीने गए थे तथा जापानी सैन्यवाद का उन्मूलन किया जायगा।

संदर्भ

- 1 फ्लेमिंग वही, पृ 305
- 2 फ्लेमिंग, वही, पृ 197-980
- 3 ऐसा ही चर्चिल का मन हो गया था। उन्होंने मिक्वोलाजाइव से 15 जून को कहा 'हमें अब इसकी परवाह नहीं कि स्टालिन जापान के विरुद्ध युद्ध में आता है या नहीं। हमें अब उसकी जरूरत भी नहीं है।' फ्लेमिंग, वही से उद्धृत।
- 4 कुछ ऐसे विवेकशील वज्ञानिक भी थे, जो परमाणु बम के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, राल्फ०ए० वाड और डॉ लियो सिलार्ड-देखिये, फ्लेमिंग, वही, 300 302
- 5 ब्रिटेन के एडमिरल वाइकाउट कनिंघम ने अपने भाषण में कहा कि उह इसका हमेशा खेद रहेगा कि बम डाला गया जिसकी ऐसी कोई जरूरत न थी बल्कि, इसकी वजह से परमाणु शक्ति का अयथा शांतिमय प्रयोग की बात दब गई—फ्लेमिंग, पृ० 306

- 6 इनकियो, सी तथा अग कृत आधुनिक जापान का इतिहास देखिये
- 7 यह मेरी राय है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर इन बर अस्त्रों के प्रयोग ने जापान के विरुद्ध हमारी लड़ाई पर कोई बड़ा भारी फल नहीं डाला" एडमिरल विलियम सीही (ब्राइ वाज देयर, लंदन 1950, प० 515)
—' यह सोचना गलत होगा कि जापान के—2
- 8 प० 90—
भाष्य का फैसला परमाणु दमन न किया-वर्चिल, दि सैकंड वर्ल्ड वार, पण्ड 5, प० 643
- 9 प्रेसीडेंट ट्रूमेन सम्मरण, वही, पृ०
- 10 इतना ही नहीं, "125 महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर जो अगले 12 वर्षों में नियुक्तियां हुईं, उनमें से 49 बकर, उद्योगपति व व्यापारी थे, 31 सेना से संबंधित और 17 वकील जिनके व्यापारिक सस्थानों से अच्छे संबंध थे।" देखिये—हावर्ड के स्मिथ कृत मे "स्टेट ऑफ यूरोप", 1949, प० 83 तथा प० 95
- 11 विरोधत सोवियत संघ की जमनी से हजनि की मांग और अरबा डालर उधार देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार शुरू हो गया था देखिये—जार्ज अल्प रोविज "एटामिक डिप्लोमेसी हिरोशिमा ऐण्ड पोद्सहम", पृ० 159
- 12 सुमनर वेल्स 'व्हेयर आर वी हेडिंग' 1946, पृ० 375 91
- 13 देखिए अल्पाबोरिज, पृ० 29-30, जॉन स्तेल कृत "दि मीनिंग आव वाल्टा" पृ० 129, पी० एम० एस० वेल्कट "मिलिटरी ऐण्ड पॉलिटिकल कासी क्वे-मेस आव एटामिक वेप-स।
- 14 देखिए, फीरेन्टल डायरीज, फेलिमिंग—"दि कोल्ड वार", डेविड हारोवित्ज काम वाल्टा दु वियतनाम", सीसरा अध्याय, प० 51-57, पीछे उद्धृत
- 15 वर्चिल का बबनव्य, "यूनाक टाइम्स, 17 अगस्त 1945
- 16 फेलिमिंग, 'दि कोल्ड वार' खण्ड प्रथम, पृ० 281 85
- 17 10 अगस्त सन 1945 को फ्रांसिस्सी समाजवादी दल के विपक्ष ने सोवियत विरोधी वक्तव्य में ऐसी ही बात कही थी।
- 18 इन प्रारूपों में अमेरिका ने स्पष्ट किया था कि ये प्रारूप सैद्धांतिक तौर पर ही प्रस्तुत किए जा रहे थे क्योंकि तब तक शांति संधि सम्पन्न नहीं हो सकनी जब तक यहाँ की सरकारें नियंत्रण में युक्त न हों। ये इन तीनों प्रारूपों में इसका जिक्र था कि सारी विदेशी सेनाएँ संधि समापन होते ही हटा ली जायें।
मोमोनोव ने आरोप लगाया कि रूस विरोधी सरकारें स्थापित करने की

योजना बना रहे ह जबकि वायरलीज ने निजी बातचीत में भरोसा दिलाया था कि उनकी मर्चा है कि इस के प्रति मैत्रीभाव रखनेवाली तथा सभी तत्वा का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की स्थापना हो ।

19 पत्रमिंग, वही, प 319 20

20 वही, प 330, तथा सिनेटर जानसन का वक्तव्य जो उन्होंने नवंबर 28, 1945 को सिनेट में दिया, "अतएव फिलीपीन में असास्का तक हवाई अड्डा की सामरिक महत्व की उपस्थिति के साथ, हम क्षणभर की सूचना पर दुनिया के किसी भी सतह पर स्थित जगह पर परमाणु बम गिरा सकते और अपने अड्डे को लौट सकते हैं ।"

21 नवम्बर 29, 1945 को दिय गये उनके वक्तव्य का अंश, स्फेमिंग, वही, प 331

22 ट्रूमैन सत्स्मरण, 11 भाग पृ० 552

23 वही,

24 जुलाई में 'यूमाक टाइम्स में क्रुक्स एटकिंसन ने सोवियत संघ की यात्रा करने के बाद लिखा कि " सोवियत नेता सटाई नहीं चाहते ।" वे युद्ध की विभीषिका के बारे में हमसे अधिक जानते हैं । वे इस समय विषय जनमत का विरोध भी नहीं करना चाहते, जैसा ईरान और तुर्की से हटकर उन्होंने सिद्ध किया ' पलेमिंग, वही, प० 362

अध्याय-4

संयुक्त राष्ट्र युद्धकालीन साहचर्य और सहयोग का एक और सफल प्रयोग

द्विजने महायुद्ध की भीषण लपटों ने और कुछ नष्ट किया हो न किया हो पर राष्ट्र संघ की तो राख बर ही दिया। उससे बाहर नो बड़ी शक्तियाँ ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने जब विजय हावर युद्ध करने की ठानी, तब उनके लिए यह समझ न था कि वे आपसी श्रीचनान में जिसका दम ही निकला जा रहा था उस राष्ट्र संघ के झूठे वे नीचे हो। उसके दो सदस्यों के साथ उनके प्रतिपक्ष दो अन्य भूतपूर्व सदस्यों जर्मनी और इटली के विरुद्ध सहने का निश्चय करते। इसकी जगह उन्होंने एक नये संघ का नाम से सडाई का मिगुल बजाया और यह घोषणा की नये संयुक्त राष्ट्र के नाम से। यह नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सुनाया था और इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1 जनवरी सन 1942 में हुआ था। जब 26 संयुक्त राष्ट्रों की ओर से यह घोषणा की गई थी कि वे घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध एक जुट होकर लड़ेंगे।

एकजुटता का यह त्रम समय का साथ बढ़ता और गहरा होता गया। जैसे जैसे महायुद्ध गहराने लगा, संयुक्त राष्ट्रों का एका भी इस्पाती शक्ल लेता गया, इन मित्र राष्ट्रों की परस्पर विश्वास, सौहाद्र सहानुभूति और मित्रता के डोर एक दूसरे को बांधते और निजट भात गये। युद्ध ने एक दूसरे के प्रति अजनबीपन की बहुत कुछ दूर कर दिया, और आत्मीयता के भाव बढ़ाने शुरू कर दिये। मित्र राष्ट्र अपने इसी एकता और सहकार भाव के बलवृत्ते पर घुरी राष्ट्रों पर एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करत गए और मिल-जुलकर मानव इतिहास के इस भीषणतम युद्ध में विजयी हुए। जैसे जैंग के जीतते जाते, वे युद्ध लड़ते लड़ते तब नये अंतरा राष्ट्रीय समठन की नाव क पत्थर रखते जा रहे थे। यह नीव भरने का काम अंतराष्ट्रीय समठन का सबसे म बुलाए गए उस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पूरा हुआ जो सन. फ्रांसिसको में 25 अप्रैल से 26 जून सन 1945 के बीच तक चला। इससे पूर्व अगस्त में अक्टूबर मन् 1944 तक डम्बर्टन ओक्स में चार बड़ा ने चीन

सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस अंतर्राष्ट्रीय संघ का प्रारूप तय किया। बहुत सी बातें इनके बीच बहती थीं।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का संविधान बनाया गया और उस पर 26 जून, 1945 को हस्ताक्षर हुए। पालेड सम्मेलन में, भाग नहीं ले सका। उसकी ओर से बाद में दस्तखत हुए। ब्रिटेन के ताज की छाया में भारत गुलाम होते हुए भी इसका संस्थापक सदस्य बना। इस प्रकार 51 संस्थापक सदस्यों की मदद से संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945, को अस्तित्व में आया जबकि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अमेरिका ने 'चार्टर' या संविधान को औपचारिक तौर पर मान्यता दी और इनके अलावा बहुसंख्यक राज्यों ने इसे स्वीकार किया। तब से 24 अक्टूबर 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है।

इस प्रकार महादेशों (अर्थात् तीन बड़े—अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के) के मध्य महायुद्ध के दौरान एक दूसरे के प्रति जितनी आत्मीयता, सहोदरता, विश्वास और मिलजुलकर भविष्य के लिए कुछ 'रचना' करने की प्रतिभा और इच्छा थी, उसका पुजीभूत प्रतिफल संयुक्त राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ। अस्तित्व में आ जाने के बाद, छोटे मझोले राष्ट्रों ने इस गाड़ी के पहिए बनकर इस धीमे धीमे ही सही आगे ठेलते ले चलने का काम किया और इसके अस्तित्व की रक्षा पकिन की लड़ाई ही नहीं किया बल्कि, उस ऐसी गहराई भी दी, जो 'महादेश' के आपसी वैमनस्य और संघर्ष में तनाव के फलस्वरूप उपजी वैधैर्य की क्षमता रखती थी। इस सबका परिणाम यह रहा है कि समय की प्रवाह के साथ साथ 'संयुक्त राष्ट्र' और कुछ नहीं तो सबकी 'चौपाल' के रूप में तोड़ल ही गया है जहाँ जहाँ लोग निभय होकर, बिना लाग सपेट के अपनी बातें एक दूसरे के साथ मिलकर किसी तीसरे से भी कह सकते हैं और कहते हैं। वे 'सत्य' पारित करते हैं कि अमुक के विरुद्ध अमुक ढंग की कारवाई की और सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के रूप में संपूर्ण मानवता की एक उत्कृष्टतम अंतरात्मा ही वह दुबस विकासशील लोग अपनी रचनाशीलता की पहिचान बनाती चली जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण इस तथ्य को अच्छी तरह प्रकट करता है कि शान्ति संघर्ष के अलावा इस क्षेत्र में भी राष्ट्रों की युद्ध काल में उपजी और गहराई मित्रता युद्ध समाप्त होते ही, निष्फल नहीं हो गई बल्कि, उसकी सज्जनशीलता उभार पर थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण और उसकी आज उपस्थिति इस तथ्य का भली भाँति प्रमाणित करती है।

संयुक्त राष्ट्र का संगठन

संयुक्त राष्ट्रों के इस संगठन का विधान जिसे 'चार्टर' कहते हैं, यह स्पष्ट करता

हे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी एक ढीला ढाला संघीय गठन है, न कि पूर्णतः एकीकृत एक वैश्वीय संगठन। अभी तक यह प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्रों की एक मजबूत गोष्ठी मात्र ही बना हुआ है जो पूरी तरह उन राष्ट्रों की मर्जी पर टिका है जिन पर दो बड़ी शक्तियाँ और उनके नेतृत्व में बने गुट छाये हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएँ हैं, जबकि पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ के विधान में मात्र 26 धाराएँ थी।

उद्देश्य और सिद्धान्त

(1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना,

(2) राष्ट्रों में परस्पर मैत्री संबंध बढ़ाना,

(3) संसार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य मानवीय समस्याओं को वह हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, लिंग भाषा तथा वर्ग भेद के बिना मानव मान के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना, तथा

(4) चौथा और अंतिम उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रों के प्रयत्नों में तारतम्य स्थापित करना तथा इस रचनात्मक कार्यक्रम का एक प्रभावशाली केन्द्र बन कर कार्य सम्पादित करना है।

स्पष्ट है कि जो प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का माना गया है, वह है शांति के निमित्त राष्ट्रों के एक प्रभावशाली केन्द्र के रूप में काम करना। संक्षेप में, इसके अन्य उद्देश्य हैं—

(क) राष्ट्रों में मैत्री सम्बंध प्रगाढ़ करना,

(ख) आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक तथा मानवीय विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा,

(ग) इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्यों के आपसी सम्बंधों में तालमेल बैठाना है।

संयुक्त राष्ट्र का संविधान तथा उसके मूलभूत सिद्धांत

चार्टर के अनुच्छेद 2 में संघ के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि संघ और उसके सदस्य अनुच्छेद 1 में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नांकित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे

(1) सभी सदस्यों की सावधोक्त समानता का सिद्धांत पाया गया है। स्मरणीय है कि यह सिद्धांत उन 5 बड़े राज्यों के जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं विशेषाधिकार से अनुबद्धित है।

(2) यह सिद्धांत माना गया है कि सदस्य राष्ट्र 'चार्टर' के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभायेंगे।

(3) सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगडा को शांतिपूर्ण तरीको मे ही सुलवायेंगे।

(4) कोई भी सदस्य राष्ट्र अपन पारस्परिक संवधा मे न तो शक्ति प्रयोग की धमकी ही देंगे और न शक्ति का प्रयोग करेंगे।

(5) कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी ऐसे राज्य को सहायता नहीं देगा जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिरोधक अथवा अनुरोधक कार्यवाही कर रहा हो।

(6) संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रयत्न करेगा कि जो राज्य इसके सदस्य नहीं है व भी वहा तक इन सिद्धांतों का पालन करेंगे जहा तक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की स्थापना के लिए आवश्यक हो।

(7) अतः, संयुक्त राष्ट्र संघ उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो कि राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

इस सदन में यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान में इस मत को स्पष्टतः माना मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से प्रमुखता का उत्पन्न नहीं होता है, अपितु प्रमुखता के द्वारा ही इन दायित्वों का वहन संभव हो पाता है।

संविधान के अंतर्गत घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं प्राप्त है परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ को अनेक कार्यवाहियों पर एक दृष्टि डालने पर यह पता चलता है कि

(क) सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी देश की सरकार और उसका प्रशासन घरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है परंतु जैसा यूनान चेकोस्लोवाकिया व चीन तथा बांग्लादेश के मामले में हुआ—ऐसे प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाये जाते रहे हैं और प्रश्न उठाने वालों ने इसे हस्तक्षेप नहीं माना। यद्यपि जब उनका अपना मामला आया तब जैसा फ्रांस ने अल्जीरिया में व ब्रिटेन ने रोडेसिया में—इस तरह के हस्तक्षेप को पसंद नहीं किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

नये संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का पक्का इरादा कर लेने के बाद मित्र राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता के प्रश्न पर भी विचार किया। और डब्लुवटन ओक्स सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि इसमें (1) वे सभी राष्ट्र शामिल किये जायेंगे जिन्होंने ऐटलांटिक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये थे।

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का श्रीमण्डल एवं निरर्थक प्रस्तावना से होता है जो अमेरिका प्रतिनिधि के जोर देने पर इस रूप में जोड़ा गया था। इस प्रस्तावना का प्रारम्भ “हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग—” ऐसी शब्दावली से होता

है जिस से ऐसा भ्रम सहज में ही उभरता है कि 'चाटर किसी राज्य के एक सविधान की तरह बनाया गया है जो समस्त संसार के लोगों की महत्वाकांक्षाओं और हार्थिक भावनाओं का न केवल प्रतिनिधित्व करता है बल्कि उनके प्रति समर्पित है। इस में बड़ा गया था हमारी सरकारों अपने प्रतिनिधियों के रूप में सान फ्रांसिस्को नगर में एकत्र हुई हैं। इन प्रतिनिधियों में संयुक्त राष्ट्र के इस चाटर को स्वीकार किया है। परन्तु यथायथ यह 'चाटर' कोई सविधान नहीं है। न सत्ता की दृष्टि से और न सामर्थ्य की दृष्टि से ही यह एक सांविधानिक दस्तावेज के समक्ष ठहरता है। यह वास्तव में एक सविधान मात्र है जो राज्यों के बीच सम्पन्न हुआ। इसका सम्बन्ध में गुमा न ठीक ही लिखा है कि 'संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रसंघ से अनेक बातों में भिन्न होने के बावजूद उसका ही एक छद्म रूप है।'

फिर भी प्रस्तावना का अपना महत्व है क्योंकि वह इस संधि पत्र का एक प्रारम्भिक और अविभाज्य अंग है। इसके साथ ही संघ के उद्देश्य और सिद्धांत भी दिये गये हैं। उद्देश्य के रूप में उन सामान्य हिता की घोषणा की गई है जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का विचार टिका हुआ है। सिद्धांतों के द्वारा उन प्रक्रियाओं और तकालन सूत्रों को निर्धारित किया गया है जिनके आधार पर अपने सामान्य हिता की पूर्ति के लिए राज्य घटके तथा उनका यह संघ आवरण करेगा।

(2) इसके अलावा इसकी सदस्यता के द्वारा सभी शांति प्रिय राष्ट्रों के लिए खोल दिये जायेंगे। इस प्रावधान का सम्बन्ध सन् 1943 की मित्र राष्ट्रों की उस घोषणा में था जिसमें शांतिप्रिय राज्यों की एक संस्था बनाने का निश्चय किया गया था। शांति प्रियता पर इतना जोर देने का कारण यह भी था कि इस आधार पर पराजित सैनिक युद्ध के सदस्य तथा स्पेन का फासी फकी सरकार व ऐसी अन्य सरकारें भी जो युद्ध में मित्र राष्ट्रों के दुरमना के साथ भागीदार न बन कर भी उन्हें सहयोग देने के अपराधी थे उन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से दूर रखा जा सके।

अनुच्छेद 3 में संस्थापक राज्यों का विवरण दिया गया है। इसमें 51 सदस्य राष्ट्र शामिल नियत हैं जिनमें भारत व पिसीफाइन् ऐस पराधीन देश भी थे। इसके अलावा नए सदस्यों के प्रवेश का भी प्रबंध किया गया था पर उनके लिए यह बात सार्वभौमिक (1) व मान प्रिय (2) वर्तमान सविधान में उल्लिखित दायित्वों का स्वीकार करने का है—इतना ही नहीं अपितु (3) संघ के मतानुसार इन दायित्वों को निभा पाने की उनमें क्षमता भी हो (4) सुरक्षा परिषद में तथा सामान्य सभा में 2/3 बहुमत में प्रवेश के प्रश्न पर उन्हें अनुमोदन प्राप्त हो।

इस प्रकार यो तो संयुक्त राष्ट्रसंघ में नए सदस्यों का प्रवेश एक सरल बात मालूम पड़ती है परंतु व्यवहार में अनेक बार यह बहुत जटिल सिद्ध हुई यथा मंगोलिया, श्रीलंका, साम्यवादी चीन दोनों जमनी जो अब शामिल हो चुके हैं तथा दोनों कोरिया जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं।

पर इन क्षणों के बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ का परिवार बढ़ता गया है। और आज साम्यवादी चीन तथा दोनों जमनी पश्चिमी जमनी और पूर्वी जमनी को मिलाकर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता सराया 155 हो गयी है। अब स्वतंत्र राष्ट्रों की पंक्ति में केवल दोना कोरिया व स्विटजरलैंड ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की चहार-दीवारी के बाहर हैं। जिस दीध कालीन संघर्ष के बाद साम्यवादी चीन को तथा दोनों जमनी राष्ट्रों को तथा एकीकृत वियतनाम को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल पाई है वह एक स्मरणीय प्रसंग बन गया है।

(1) संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन का प्रवेश

जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव डाली गई थी तब चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के पांच बड़े निर्माताओं की वोटिंग में रखा गया था। चीन को तब एशिया के सबसे बड़े तथा दुनिया की पांच बड़ी ताकतों में शामिल किया गया था। चीन को पंच परमेश्वरों के बीच आसीन कराने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका ने किया था। रूजवेल्ट का अमेरिका चीन को अपने साथ रख कर तब अपनी प्रशासनी नीति में एक नया मोड़ ला रहा था। पराजित जापान का अंत हो रहा था और अमेरिका समर्थित चांगकाई शेक के चीन का उदय हो रहा था जो पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में था। स्मरणीय है कि याल्टा सम्मेलन में सोवियत संघ को जापान के खिलाफ युद्ध में लाने के लिए जो शुभ समझौता हुआ था उसमें रूजवेल्ट ने चीनी नेताओं से पूछे बिना ही कुछ महत्वपूर्ण सहूलियतें सोवियत संघ को मँट कर दी थी और यह वचन दिया था कि वे चांगकाई शेक से ये सहूलियतें दिलवाने की गारंटी लेते हैं।

चांगकाई शेक वाले चीन के अंदर ही अंदर एक त्रातिकारी साम्यवादी आंदोलन पनप रहा था। उस साम्यवादी सत्ता ने कुओमिन्तांग के साथ संयुक्त मोर्चा बना कर जापान के खिलाफ युद्ध में शानदार भूमिका निभायी थी और युद्ध के अंत होते होते तक इस शानदार भूमिका न उन्हें चीनी सत्ता में बराबर का भागीदार बन दिया था परंतु चांगकाई शेक इस मायता देने के पक्ष में नहीं था। कोरवो की तरह वे साम्यवादियों को बिना युद्ध सुई की नोक बराबर जमीन देने का तैयार नहीं था। इस सदन में स्मरणीय है कि अमेरिका कुओमिन्तांग और साम्यवादियों के बीच मायस्थता कर युद्ध नानन के पक्ष में था परन्तु जब रांग की जिद पर गह-युद्ध छिड़ ही गया तब अमेरिका ने चांग के पक्ष को भरपूर मदद की।

है जिस से ऐसा भ्रम सहज में ही उभरता है कि 'चाटर' किसी राज्य के एक सविधानिक तरह बनाया गया है जो समस्त ससार के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की दृष्टि भावनाओं का न केवल प्रतिनिधित्व करता है बल्कि, उनके प्रति समानता है। इस में कहा गया था 'हमारी सरकारें अपने प्रतिनिधियों के रूप में सार्वभौमिक नगर में एकत्र हुई हैं। इन प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के इस 'चाटर' को स्वीकार किया है। पर यथाथ में यह 'चाटर' कोई सविधान नहीं है। न सार्वभौमिक दृष्टि से और न स. मर्याद की दृष्टि से ही यह एक सविधानिक दस्तावेज के समक्ष ठहरता है। यह वास्तव में एक सविधान पत्र मात्र है जो राज्यों के बीच सम्पन्न हुआ। इसके सम्बन्ध में शूमा ने ठीक ही लिखा है कि 'संयुक्त राष्ट्र सच अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रसंघ से अनेक बातों में भिन्न होने के बावजूद उसका ही एक छत्र रूप है।'

फिर भी प्रस्तावना का अपना महत्व है क्योंकि वह इस संधि पत्र का एक प्रारम्भिक और अधिभाष्य अंश है। उसके साथ ही संधि के उद्देश्य और सिद्धांत भी दिये गए हैं। उद्देश्य के रूप में उन सामान्य हितों की घोषणा की गई है जिन पर संयुक्त राष्ट्र संधि के निर्माण का विचार टिका हुआ है। सिद्धांतों के द्वारा उक्त प्रक्रियाओं और संचालन सूत्रों को निर्धारित किया गया है। इनके आधार पर अपने सामान्य हितों की पूर्ति के लिए राज्य घटक तथा उनका यह संधि आचरण करेगा।

(2) इसका अलावा इसकी सदस्यता के द्वारा सभी शांति प्रिय राष्ट्रों के लिए खोल दिया जावेगा। इस प्रावधान का सम्बन्ध सन 1943 की मित्र राष्ट्रों की उस घोषणा में था जिसमें शांतिप्रिय राज्यों की एक संस्था बनाने का निश्चय किया गया था। शांति प्रियता पर इतना जोर देने का कारण यह भी था कि इस आधार पर पराजित सैनिक गुट के सदस्य तथा स्पेन के फासी फ्रोंटो सरकार के ऐसी अन्य सरकारें भी जो युद्ध में मित्र राष्ट्रों के दुश्मनों के साथ भागीदार न बन कर भी उन्हें सहयोग देने के अपराधी थे उन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से दूर रखा जा सके।

'नवम्बर 3 में संस्थापक राज्यों का विवरण दिया गया है। इसमें 51 सदस्य राष्ट्रों में 15 मित्र प्रिय गणध्वजिनों में भारत व फिलीपीन्स ऐसे पराधीन देश भी थे।¹ इसके अलावा नव सदस्यों के प्रवेश का भी प्रबंध किया गया था पर उनके लिए यह बात तर्क है कि (1) वे गण प्रिय हों (2) वर्तमान सविधान में उल्लिखित दायित्वों को स्वीकार करने वातावरण—इतना ही नहीं अपितु (3) संधि में अनुसार इन दायित्वों को निभा पाने की उनमें क्षमता भी हो, (4) गुरुता परिपक्वता तथा सामान्य सभा के 2/3 बहुमत से प्रवेश के प्रश्न पर उन्हें अनुमोदन प्राप्त हो।

संयुक्त राष्ट्र युद्धकालीन साहचर्य

इस प्रकार यो तो संयुक्त राष्ट्रसंघ में नए सदस्यों का प्रवेश एक सरल बात मालूम पड़ती है पर तु व्यवहार में अनेक बाध यह बहुत जटिल सिद्ध हुईं यथा मंगोलिया, श्रीलंका, साम्यवादी चीन दोनों जगनी जो अब शामिल हो चुके हैं तथा दोनों कोरिया जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं।

पर इन झगड़ों के बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ का परिवार बढ़ता गया है। और जात्र साम्यवादी चीन तथा दोनों जगनी पश्चिमी जगनी और पूर्वी जगनी को मिलाकर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता सरया 155 हो गयी है। अब स्वतंत्र राष्ट्रों की पंक्ति में केवल दोनो कोरिया व स्विट्जरलैंड ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की बहार-दीवारी के बाहर हैं। जिस दोष कालीन संघ के बाद साम्यवादी चीन को तय दोनो जगनी राष्ट्रों को तथा एकीकृत वियतनाम को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल पाई है वह एक स्मरणीय प्रसंग बन गया है।

(1) संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन का प्रवेश

जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव डाली गई थी तब चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के पांच बड़े निर्माताओं की कौटि में रखा गया था। चीन को तब एशिया के सबसे बड़े तथा दुनिया की पांच बड़ी ताकतों में शामिल किया गया था। चीन को पंच परमेश्वरों के बीच आसीन कराने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका ने किया था। रूजवेल्ट का अमेरिका चीन को अपने साथ रख कर तब अपनी प्रशासनीति में एक नया मोड़ ला रहा था। पराजित जापान का अंत हो रहा था और अमेरिका के समर्थित चांगकाई शेक के चीन का उदय हो रहा था जो पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में था। स्मरणीय है कि याल्टा सम्मेलन में सोवियत संघ को जापान के खिलाफ युद्ध में लाने के लिए जो शुप्त समझौता हुआ था उसमें रूजवेल्ट ने चीनी नेताओं से पूछे बिना ही कुछ महत्वपूर्ण सहूलियतें सोवियत संघ को मँट कर दी थी और यह वचन दिया था कि वे चांगकाई शेक न ये सहूलियतें दिलवान की गारंटी लेते हैं।

चांगकाई शेक वाले चीन के अंदर ही अंदर ग्य क्रांतिकारी साम्यवादी आंदोलन पनप रहा था। उस साम्यवादी सत्ता ने कुओमिन्तांग के साथ संयुक्त मोर्चा बना कर जापान के खिलाफ युद्ध में शानदार भूमिका निभायी थी और युद्ध के अंत होते होते तक इस शानदार भूमिका ने उन्हें चीनी सत्ता में बराबर का भागीदार बन दिया था परंतु चांगकाई शेक इस भावना देने के पक्ष में नहीं था। कौरवों की तरह वे साम्यवादियों को बिना युद्ध सुई की नोक बराबर जमीन देने का तैयार नहीं थे। इस सदम में स्मरणीय है कि अमेरिका कुओमिन्तांग और साम्यवादियों के बीच मध्यस्थता कर युद्ध नानन के पक्ष में था परंतु जब रांग की जिद पर गृह-युद्ध छिड़ ही गया तब अमेरिका ने चांगकाई शेक को भरपूर मदद की।

है जिस से ऐसा भ्रम सहज में ही उभरता है कि 'चाटर' किसी राज्य के एक संविधान की तरह बनाया गया है जो समस्त संसार के लोगों की महत्वाकांक्षाओं और हार्थिक भावनाओं का न केवल प्रतिनिधित्व करता है बल्कि, उनके प्रति समर्पित है। इस में कहा गया था "हमारी सरकारें अपने प्रतिनिधियों के रूप में सान फ्रांसिस्को नगर में एकत्र हुई हैं। इन प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के इस 'चाटर' को स्वीकार किया है। पर यथाथ में यह 'चाटर' कोई संविधान नहीं है। न सत्ता की दृष्टि से और न सामर्थ्य की दृष्टि से ही यह एक संविधानिक दस्तावेज के समक्ष ठहरता है। यह वास्तव में एक संविदा पत्र मात्र है जो राज्यों के बीच सम्पन्न हुआ। इसके सम्बन्ध में शुमा ने ठीक ही लिखा है कि 'संयुक्त राष्ट्र संघ अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रसंघ से अनेक बातों में भिन्न होने के बावजूद उसका ही एक छद्म रूप है।'

फिर भी प्रस्तावना का धपना महत्व है क्योंकि वह इस संधि-पत्र का एक प्रारम्भिक और अविभाज्य अंग है। इसके साथ ही संघ के उद्देश्य और सिद्धांत भी दिये गये हैं। उद्देश्य के रूप में उन सामान्य हिता की घोषणा की गई है जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का विचार टिका हुआ है। सिद्धांतों के द्वारा उन प्रक्रियाओं और संचालन सूत्रों को निर्धारित किया गया है जिनका आधार पर अपने सामान्य हितों की पूर्ति के लिए राज्य घटक तथा उनका यह संघ आचरण करेगा।¹³

(2) इसके अलावा इसकी सदस्यता के द्वारा सभी शांति प्रिय राष्ट्रों के लिए खोल दिया जाएगा। इस प्रावधान का सम्बन्ध सन् 1943 की मित्र राष्ट्रों की उस घोषणा से था जिसमें शांतिप्रिय राज्यों की एक संस्था बनाने का निश्चय किया गया था। शांति प्रियता पर इतना जोर देने का कारण यह भी था कि इस आधार पर पराजित सैनिक गुट के सदस्य तथा स्पेन का फासी फ्रोंटो सरकार व ऐसी अन्य सरकारें भी जो युद्ध में मित्र राष्ट्रों के दुश्मनों के साथ भागीदार न बन कर भी उन्हें महयोग देने के अपराधी थे, उन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से दूर रखा जा सके।

अनुच्छेद 3 में संस्थापक राज्यों का विवरण दिया गया है। इसमें 51 सदस्य राष्ट्र शामिल किये गये थे जिनमें भारत व फिलीपाइन ऐसे पराधीन देश भी थे।¹⁵

इसके अलावा नए सदस्यों के प्रवेश का भी प्रवन्ध किया गया था पर उनके लिए यह शर्त लगाई कि (1) वे शांति प्रिय हों (2) वर्तमान संविधान में उल्लिखित दायित्वों को स्वीकार करने वाले हों—इतना ही नहीं अपितु, (3) संघ के मतानुसार इन दायित्वों को निभा पाने की उनमें क्षमता भी हो, (4) सुरक्षा परिषद से तथा सामान्य सभा के 2/3 बहुमत से प्रवेश के प्रश्न पर उन्हें अनुमोदन प्राप्त हो।

इस प्रकार यो तो संयुक्त राष्ट्रसंघ में नए सदस्यों का प्रवेश एक सरल बात मालूम पड़ती है परन्तु व्यवहार में अनेक बार यह बहुत जटिल सिद्ध हुई यथा मंगोलिया, श्रीलंका, साम्यवादी चीन, दोना जमनी जो अब शामिल हो चुके हैं तथा दोनो कोरिया जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं।

पर इन झगड़ों के बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ का परिवार बढ़ता गया है। और आज साम्यवादी चीन तथा दोनो जमनी-पश्चिमी जमनी और पूर्वी जमनी को मिलाकर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता संख्या 155 हो गयी है। अब स्वतंत्र राष्ट्रों की पंक्ति में केवल दोना कोरिया व स्विट्जरलैंड ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की चहार-दीवारी के बाहर हैं। जिस दीघ कालीन संघर्ष के बाद साम्यवादी चीन को तथा दोनो जमनी राष्ट्रों को तथा एकीकृत वियतनाम को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल पाई है वह एक स्मरणीय प्रसंग बन गया है।

(1) संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन का प्रवेश

जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव डाली गई थी तब चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के पांच बड़े निमित्तों की शक्ति में रखा गया था। चीन को तब एशिया के सबसे बड़े तथा बुनियादी पांच बड़ी ताकतों में शामिल किया गया था। चीन को पंच परमेश्वरों के बीच आसीन कराने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका ने किया था। रूजवेल्ट का अमेरिका चीन को अपने साथ रख कर तब अपनी प्रशासनीय नीति में एक नया मोड़ ला रहा था। पराजित जापान का अंत हो रहा था और अमेरिका समर्थित चांगकाई शक्ति के चीन का उदय हो रहा था जो पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में था। स्मरणीय है कि यांटा सम्मेलन में सोवियत संघ को जापान के खिलाफ युद्ध में लाने के लिए जो गुप्त समझौता हुआ था उसमें रूजवेल्ट ने चीनी नेताओं से पूछे बिना ही कुछ महत्वपूर्ण सहूलियतें सोवियत संघ को भेंट कर दी थी और यह वचन दिया था कि वे चांगकाई शक्ति से ये सहूलियतें दिलवाने की गारंटी लेते हैं।

चांगकाई शक्ति वाले चीन के अंदर ही अंदर एक क्रांतिकारी साम्यवादी आंदोलन बन रहा था। उस साम्यवादी सत्ता ने कुओमिन्तांग के साथ संयुक्त मोर्चा बना कर जापान के खिलाफ युद्ध में शानदार भूमिका निभायी थी और युद्ध के अंत होत-होते तक इस शानदार भूमिका ने उन्हें चीनी सत्ता में बराबर का भागीदार बन दिया था परन्तु चांगकाई शक्ति इसे मायता देने के पक्ष में नहीं था। कौरवों की तरह वे साम्यवादियों को बिना युद्ध सुई की नोक बराबर जमीन देने को तैयार नहीं थे। इस संदर्भ में स्मरणीय है कि अमेरिका कुओमिन्तांग और साम्यवादियों के बीच मध्यस्थता कर युद्ध चलाने के पक्ष में था परन्तु जब चीन की जिद पर यह युद्ध छिड़ ही गया तब अमेरिका ने चांग के पक्ष को भरपूर मदद की।

पर इस भीषण गृह युद्ध में साम्यवादियों का ही पलड़ा भारी रहा और वे विजयी हुए। यह तथ्य ध्यान में रखने लायक है कि तब तक यूरोप में अमेरिका के नेतृत्व में शीत युद्ध पूरी तरह छिड़ चुका था और इधर कम्युनिस्ट चीन की स्थापना हो रही थी तो उधर पश्चिम यूरोप ने एक बृहद् और अपूर्व शक्ति कालीन सैनिक संगठन 'नाटो' जन्म ले रहा था जिसकी बागडोर अमेरिकी मुट्ठि में थी। चांग की पराजय को अमेरिका ने अपनी जबदस्त पराजय के रूप में लिया और उसकी यह मायता बनी कि साम्यवादी चीन के उदय का अर्थ था सोवियत साम्यवादी सत्ता का विस्तार होना।¹⁶ (शूमा) साम्यवादी हो चुके चीन को अब समुक्त राष्ट्र संधि में घुसने न देने की साजिश अमेरिका ने शुरू की और अपने सहायियों और पिछले गुप्तों को इस नीति के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी गुट ने साम्यवादी चीन के प्रवेश के प्रश्न को बहुत विवाद ग्रस्त बना दिया।

यह प्रश्न सन्धसम्मेलन 1949 में महासभा के समक्ष उपस्थित हुआ। घर में घुरी तरह पिट कर जब चांगकाई शेक की सरकार ने अमेरिकी संरक्षण पाकर ताई-वान में शरण ले ली उसके बाद भी चांग के प्रतिनिधि ही दीघकाल तक चीन के प्रतिनिधि के रूप में समुक्त राष्ट्र संधि में बैठते रहे। सन् 1950 में सोवियत संध पूर्व यूरोप के साम्यवादी देश तथा एशिया की विलम्ब शक्तियाँ यथा भारत, इण्डोनेशिया ने इस प्रश्न को महासभा में उठाया कि चांग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अवध है।

प्रश्न यह नहीं था कि चीन को सदस्यता प्रदान की जाए। चूंकि, चीन स्थायी सदस्य था, वरन् प्रश्न यह था कि साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए, न कि अपदस्थ सरकार के। कोरिया की सहाई में जब चीन को भाग लेना पड़ा तब इसका बहाना बना कर सन् 1951 में एक प्रस्ताव के द्वारा चीन को आक्राता ठहरा कर उसकी भर्त्सना अमेरिका ने करवाई और इस तथ्य को भी चीन के प्रवेश के प्रश्न के साथ जोड़ दिया और चीन को सदस्यता से वंचित रखने का आधार बनाया गया। पर प्रश्न यह था ही नहीं। साम्यवादी चीन समुक्त राष्ट्र संधि में नए सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं चाह रहा था। वह तो स्थायी सदस्य के रूप में अपने अधिकारों का दावेदार था। मांग यह थी कि चीन के सही प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। तबसे लगातार चीन की वास्तविक सदस्यता और प्रतिनिधित्व का प्रश्न महासभा के सामने लाया गया पर 1961 तक यह प्रश्न महासभा की कार्य सूची में नहीं रखा जा सका। सन् 1962 के बाद जब भी यह कार्यसूची में रखा गया, बहुत वर्षों तक यथेष्ट बहुमत के अभाव में यह पारित नहीं हो सका।

सन् 1964-65 के बार सावियत चीन के बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे

होने लगे और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सभ में प्रवेश के बारे में एक ओर सोवियत सभ और उसके साथियों का खुजा समथन उतना उत्साहपूर्ण नहीं रहा। साम्यवादी पक्ष की ओर से चीन की वकासत अल्बानिया के द्वारा ही होती रही तो दूसरी ओर चीन की ओर से इस क्षेत्र में दिलचस्पी और प्रवेश पाने के प्रयास बढ़ने लगे। सांस्कृतिक क्रांति ने इस प्रश्न को चीन में पूरी तरह उभरने नहीं दिया फिर भी सन् 1967 में जब यह प्रश्न महासभा में आया तो 45 के विरुद्ध 58 मतों से ही यह पराजित हो पाया (18 राष्ट्रा ने मतदान में भाग नहीं लिया)। इस अधिवेशन में वेल्जियम, इटली, लक्समबर्ग, हासैण्ड तथा बिली ने यह सुझाव रखा कि चीन के प्रतिनिधित्व से संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की जाए परंतु 32 के विरुद्ध 57 मतों से यह अस्वीकृत हो गया तथा 39 राष्ट्रो ने मतदान में भाग ही नहीं लिया।

साम्यवादी चीन को महासभा का समयन कुछ थोड़ी घटा बढी के साथ लगा सार मिलता ही गया और ज्वा ज्यो सोवियत चीन के आपसी सघष में तेजी आती गई चीन की ओर अमेरिका का रत्न भी बदलने लगा। निक्सन के पदासीन होने के बाद चीन सबधी 'नया रुख' खुलने लगा। सन 1970 में 'पिंग पांग' कूटनीति का प्रारंभ हुआ। टोक्यो आई एक अमेरिकी टेबुल टेनिस टीम को बीजिंग आने का आमन्त्रण मिला और एक नया अध्याय चीन अमेरिका के सघषा में जुड़ने लगा।

एक ऐतिहासिक मोड़

इस प्रकार के घटनाक्रम ने चीन के संयुक्त राष्ट्र सभ में प्रवेश को एक आसान प्रनिया बना दिया। जब 1971 में महासभा का अधिवेशन शुरू हुआ, तब तक यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि चीन को प्रवेश मिल ही जायेगा। इस बीच किसिगर की गुप्त वार्ता बीजिंग में सम्पन्न हो चुकी थी और निक्सन को चीन आने का निमन्त्रण मिल चुका था। महासभा में चीन के प्रवेश के प्रश्न को लेकर मुख्यतः दो प्रस्ताव थे। अमेरिकी प्रस्ताव के अंतर्गत भी यह कहा गया था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र सभ में प्रतिनिधित्व तो मिले परंतु साथ ही साथ अध्याय काइ शेष की सरनार को भी संयुक्त राष्ट्र सभ में सदस्यता प्राप्त हो। अल्बानिया ने दूसरा प्रस्ताव रखा जिसके अंतर्गत साम्यवादी चीन की सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि वही मात्र चीन की प्रतिनिधि सरकार है अतः उस ही मात्र प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और ताईवान को पूर्णतया निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

जब महासभा में इस बार मतदान हुआ तब ऐतिहासिक निणय हुआ जिसमें अल्बानिया के प्रस्ताव ने पक्ष में 76 मत पड़े (केवल 17 सदस्य अनुपस्थित रहे) और अमेरिकी प्रस्ताव को केवल 5 मत मिले। अल्बानिया के प्रस्ताव को 2/3 से

भी अधिक मत मिले। इतनी जबदस्त हार के लिए अमेरिका भी तैयार न था, और न चीन के मित्र ही इतना अधिक आशावित थे। यह बात तो बहस के दौरान ही स्पष्ट हो रही थी कि इस बार चीन को प्रवेश मिल कर रहेगा। एक के बाद दूसरे प्रतिनिधि चीन के पक्ष में बोलते गये पर अमेरिका, जापान व फिलीपाइन फिर भी आशावित थे कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 'दो चीन का प्रस्ताव' मान्यता प्राप्त कर लेगा। पर आशातीत सफलता चीन के पक्ष को प्राप्त हुई और सोवियत, समाजवादी, तथा भारत ऐसी सभी विजयवादी राष्ट्रों ने, यूरोप व लैटिनो अमेरिका के देशों के साथ चीन को अभूतपूर्व समर्थन देकर विजयी बनाया और 22 वर्षों के अमेरिकी दुराग्रह पर खड़ी नीति चक्काचूर हो गई। ताईवान को विद्रोह सत्ता से निष्कासित कर दिया गया।

अमेरिका की सामंजस्य भेद की अपनी नीति के कहीं कोई कोर बसर नहीं रह गई थी। काफी झोड़ भाग रही। किसी को उत्कोच दिया गया तो किसी को व्यापारिक हितों की याद दिलाई गई, किसी को विशेष विमान से 'यूयाक' लाने का (मासी के प्रतिनिधि को) प्रयत्न हुआ पर इन सबका कुछ असर नहीं हुआ। यह देखकर कि अमेरिका खुद नये चीन के साथ अपना नया ताना बाना बुनने की धुन में समझदारा के लिए यह इशारा काफी था। साम्यवादी चीन अतंत सयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य बन गया और एक बार फिर इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बुनावट पुराने ढंग की हो गई।

सदस्यता से निष्कासन

'चाटर' में इस का भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सदस्य निरंतर सभ के सिद्धांतों की अवहेलना करे तो उस सभ की सदस्यता स हटाया जा सकता है। यह बाधवाही महा सभा सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर कर सकती है। चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः महासभा का निर्णय 2/3 मत से लिया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि निरंतर अवहेलना करने पर ही अर्थात् गम्भीर मामलों में ही यह बाधवाही की जायेगी। गुठरिन एंड हेमरो' के अनुसार 'चाटर' के प्रावधानों की अवहेलना अनुच्छेद 2 की अवहेलना की ओर संकेत करती है।

सदस्यता से प्रत्याहार

राष्ट्रसभ के संविधान में यह प्रावधान था कि बाद भी सदस्य दो वर्ष का 'नोटिस' देकर प्रत्याहार कर सकता था। जापान, जर्मनी, इटली ने ऐसा ही किया। ड्यूरेन जीवम के प्रस्ताव में प्रत्याहार का कोई प्रावधान नहीं था। सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में इस प्रश्न को लेकर प्रतिनिधियों में आपस में काफी मतभेद था। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद आयोग ने (1) यह उद्घोषणा स्वीकृत की कि

‘चाटर’ में प्रत्याहार के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न रखा जाय। समिति के दृष्टि-कोण में मदस्या का यह महानतम महत्त्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना में संधि के सहयोग प्रदान करें। किंतु यदि किंही विशेष परिस्थितियों में कोई सदस्य संधि से प्रत्याहार करना आवश्यक समझता है तो यह संधि का उद्देश्य नहीं है कि उसे सदस्य बने रहने के लिए बाध्य करें। सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में आयोग की इस व्याख्यात्मक घोषणा को स्वीकार किया। इस संबंध में गुडरिच एवं हमरों का मत है कि जिस ढंग से यह स्वीकार हुई है उसमें यह निष्कर्ष निकालना ठीक होगा कि यह ‘चाटर’ की भांति बाध्यात्मक रूप में प्रभावशाली है।¹⁰

अमेरिकी सेनेट में बिडन वग⁹ ने यह निश्चार व्यक्त किया था कि प्रत्येक सदस्य का एच्छिक प्रत्याहार का अधिकार प्राप्त है और स्मरणीय है कि इसी प्रकार आयोग के समक्ष किसी प्रतिनिधि ने यह मत व्यक्त किया था कि यदि कोई राष्ट्र किंही विशेष परिस्थितियों के कारण संधि की सदस्यता का प्रत्याहार करना चाहे तो ऐसा कर सकता है क्योंकि यह अधिकार उसकी प्रमुखता का चोत्कर्ष है।¹⁰ बिडन वग का ख्याल था कि प्रत्याहार करने वाले राष्ट्र को अपने कारणों को स्पष्ट करना होगा अन्यथा वह सदस्य राष्ट्रों की नैतिक भत्सना का पात्र होगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा काय औचित्यपूर्ण नहीं लगता तो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र उसे समझाने का अधिकार रखते हैं किंतु उसे न तो रोक सकते हैं और न उसके खिलाफ कायवाही कर सकते हैं। किंतु यदि वह इसके साथ शांति भंग करने की कोई कायवाही करता है या ऐसा करने की धमकी देता है तो वह सभी कायवाहियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ कर सकता है जो उसके सदस्यता के समय की जा सकती थी।¹¹

पर इस प्रकार की कायवाही का प्रावधान अनुच्छेद 2 (6) में किया हुआ है जो गर सदस्यों के सम्बंध में की जा सकती है।

इंडोनेशिया ने 1, मार्च, 1965 को संयुक्त राष्ट्रसंघ से प्रत्याहार करने की घोषणा की। अन्य कारणों के साथ प्रत्याहार करने का इंडोनेशिया का यह कदम इस कारण भी उठाया गया था कि उसके तत्कालीन शत्रु मलेशिया की सुरक्षा परिषद के लिए राष्ट्रसंघ के प्रावधानों की उपेक्षा करके चयन किया गया था। इंडोनेशिया की मांग थी कि राष्ट्र व महत्त्व तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखने में योगदान को ध्यान में रखकर ऐसा चुनाव किया जाना चाहिए था। प्रत्याहार करते समय इंडोनेशिया ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सबंधी ‘चाटर’ के उद्देश्यों का पालन करती रहगी। संधि के महासचिव ने प्रत्याहार पत्र को संधि के सभी सदस्यों को भेजा। इंडो-नेशिया का यह कदम संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी।

इंडोनेशिया ने न केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपना सम्पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर लिया बल्कि राष्ट्रपति सुकर्णो ने एक नये अंतराष्ट्रीय सङ्गठन के निर्माण की योजना की भी सूचना दी। उस उद्घोषणा से यह लगा कि शायद राष्ट्रपति सुकर्णो चीन, पाकिस्तान व अन्य अपने सहयोगी राष्ट्रों की मदद से एक समानांतर अंतराष्ट्रीय सङ्गठन बनाने का प्रयत्न करें। 1965 के सितंबर में पाकिस्तान ने भी ऐसी धमकी दी कि वह राष्ट्रसंघ छोड़ देगा पर इंडोनेशिया की तरह संघ छोड़ने की उसे हिम्मत नहीं हुई। कालांतर में इंडोनेशिया में एक जबदस्त प्रतिक्रांति हुई जिसमें साम्यवादियों का धार दमन हुआ और राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी अपनी सत्ता खो दी नहीं सैनिक सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में पुनः सदस्यता स्वीकार करने की इच्छा प्रच्छा प्रकट की और 20, दिसंबर 1966 को इंडोनेशिया फिर संघ में शामिल हो गया।

कुछ अन्य बातें

यह शांतव्य है कि 'चार्टर' में सदस्यता समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं जैसा राष्ट्रसंघ के विधान में था। चार्टर के उल्लंघन करने पर सदस्य राष्ट्र को संघ से निकाला जा सकता है या उस सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। सभी सदस्यों को अपनी संधियाँ और समझौतों को सचिवालय में दर्ज करना पड़ता है। राष्ट्रसंघ की तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमदनी भी सदस्य राष्ट्रों के ऋदे पर निर्भर करती है। जहाँ तक 'चार्टर' में सशोधन का सबंध है। उसके लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है पर इस में सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी बड़े सदस्यों की सहमति आवश्यक है।¹

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग

संयुक्त राष्ट्रसंघ का ढाँचा राष्ट्रसंघ के समान ही बनाया गया है। उसमें अंतर केवल इतना है कि दो नई परिषदें संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग के रूप में जोड़ दी गई हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अंगों की संख्या 11 हो गई है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (जो एक सवर्षा नवीन प्रयोग है), संरक्षण परिषद (जो राष्ट्रसंघ के स्थायी संरक्षण आयोग से मिलती जुलती चीज है), अंतराष्ट्रीय न्यायालय (राष्ट्रसंघ का अंतराष्ट्रीय न्यायालय उसका मुख्य अंग नहीं था), एवं सचिवालय। इन अंगों का सङ्गठन और कार्य विधि का व्योरा नीचे दिया जा रहा है। अनुच्छेद 7 (2) के मुख्य अंगों के कार्य निर्वाह में सुविधा की दृष्टि से इन अंगों को सहायक अंग स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का कार्यकारी कार्य सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में बाँट दिया गया है तथा न्याय परिषद व सचिवालय महासभा

के अधिकार क्षेत्र में रख दिये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद-57 के अंतर्गत स्थापित विशिष्ट अधिकरण सभ के अंग नहीं माने गये हैं और न ही अभ्यास आठ के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय प्रवर्धन सस्याए भी संयुक्त राष्ट्रसभ का अंग मानी गई हैं भले ही इनके सारे सदस्य संयुक्त राष्ट्रसभ के ही सदस्य हों।

यद्यपि मुख्य अंगों के जिम्मे अलग अलग ढंग के काम सौंपे गये हैं फिर भी काफी हद तक वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसी स्थल पर एक मुख्य अंग को दूसरे पर आश्रित किया गया है तो कहीं दूसरा पहले के और किसी किसी स्थल पर दो अंगों के कार्य सामूहिक रूप में हैं। यथा आर्थिक एवं सामाजिक परिपद तथा यास परिपद अनुच्छेद 60 और 85 के अंतर्गत प्रमश महासभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करती है और महासभा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सुरक्षा परिपद के अधिकार क्षेत्र में प्रभावित है। नये सदस्यों के प्रवेश, 'चाटर' के संशोधन या महासचिव की नियुक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में महासभा और सुरक्षा परिपद मिल जुल कर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इस बात का भी प्रवर्धन किया गया है कि एक मुख्य अंग दूसरे को सहयोग दें यथा आर्थिक एवं सामाजिक परिपद (अनु० 65) तथा यास परिपद महासभा को (अनु० 85) सहयोग देती रहेंगी। कुछ मामला में यथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विषय में दोनों ही मुख्य अंगों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यद्यपि सुरक्षा परिपद का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाये रखे। परन्तु यह दायित्व उस तक ही सीमित नहीं है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'चाटर' के अंतर्गत कोई कठोर कार्य विभाजन का प्रवर्धन नहीं किया गया है बल्कि, जो भी कार्य विभाजन है वह सगठन को अच्छी तरह से चलाने के लिए है।

महासभा—संयुक्त राष्ट्रसभ की सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक सस्या उसकी महासभा है। संयुक्त राष्ट्रसभ के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। इस महासभा का गठन बड़े लोकतन्त्रात्मक ढंग से किया गया है। प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट प्राप्त है यद्यपि व अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि सभा में भेज सकते हैं। सनटर वेडन अंग ने इसे ससार की एक नगर सभा कहा था। भूतपूर्व महासचिव हमर-शोल्ड का कथन था कि इसका स्वरूप संसदीय सम्मेलन जैसा बन गया है।¹² ऐसा भगता है जैसे यह राष्ट्रों की संसद हो। पर संयुक्त राष्ट्रसभ कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार के रूप में गठित नहीं की गई है। इसलिए महासभा एक संसद की तरह विधायी का सगठन नहीं है। यहां सदस्यों के बीच विचार विनिमय होना है और सभा संस्तुति कर सकती है। कोई बाध्यकारी कानून का निमाण नहीं कर सकती है। इसलिए गुड स्पीड का यह कथन सही है कि यह कूटनीति का सम्मेलन की तरह है।¹³ अनुच्छेद 11 में महासभा को 'चाटर' के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने का अधिकार सौंपा गया

है। तथा एक अन्तर्-अनुच्छेद में ऐसे विषयों एवं परिस्थितियों के सम्बन्ध में इन्हीं सुरक्षा परिपद का ध्यान आवृष्ट करने का अधिकार दिया गया है जिन से अन्तराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के भंग होने का खतरा हो।

अधिवेशन यह व्यवस्था की गई है कि महासभा के वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से होंगे और आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाये जा सकते हैं। ऐसे विशेष अधिवेशन या तो सुरक्षा परिपद की प्राथना पर या संयुक्त राष्ट्रसंघ के बहुसंख्यक सदस्यों की मांग पर महासचिव के द्वारा बुलाये जा सकते हैं।¹⁵ वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष के सितंबर मास के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। यह अधिवेशन सब के मुख्यालय में आयोजित किये जाते हैं परन्तु यदि महासभा का बहुमत तो चाहें वह अन्यत्र भी किया जा सकता है यथा महासभा का तीसरा वार्षिक सम्मेलन पेरिस में किया गया था। इसी प्रकार यदि सदस्य चाहे तो अधिवेशन स्थगित भी किया जा सकता है यथा 1964 में बहुसंख्यक सदस्यों की राय पर दो बार ऐसा स्थगित किया गया। ऐसी परम्परा भी बन गयी है कि महासभा का अधिवेशन कई भागों में बांट दिया जाता और इन भागों की बैठकों के बीच मई-महीनों अंतर भी पड़ सकता है। यद्यपि 'चाटर' में किसी आपात्कालीन विशेष अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है तथापि महासभा के शांति के लिए संगठन नामक 30 नवम्बर, 1950 को पारित प्रस्ताव 377 (5) खण्ड अ पैरा 1 अनुसार 24 घंटे का सूचना पर ऐसा आपात्कालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यह अधिवेशन सुरक्षा परिपद के 7 सदस्यों के अनुरोध पर या महासभा के किसी सदस्य के अनुरोध पर जिस बहुमत की स्वीकृति प्राप्त हो बुलाया जा सकता है। अब इस प्रकार के पांच अधिवेशन हो चुके हैं। पहले दो अधिवेशन 1956 में स्वेज नहर के संकट पर विचार करने के लिए, तीसरा 1958 में लेबनान की संकटपूर्ण स्थिति पर, चौथा 1960 में कांगों के प्रश्न पर और पांचवा 1967 में इजरायल के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर सोवियत संघ के अनुरोध पर जिसे बहुसंख्यक सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त था। अतः इस प्रकार के कुल पांच अधिवेशन हुए ?

अध्यक्ष महासभा अनुच्छेद 21 में दिये अधिकार के तहत अपनी कार्यप्रणाली व नियमावली का स्वयं ही निर्धारण करती है। अधिवेशन का सबसे पहला काम अपने अध्यक्ष का चुनना होता है—यह एक परम्परा भी बन गई है कि अध्यक्ष बड़ी शक्तियों का निवासी नहीं होता है। इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। अध्यक्ष के पद को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यद्यपि उसके पास कोई विधि अधिकार नहीं है वह सभापति की तरह ही कार्य करता है परन्तु अधिवेशन का काम ठीक संचालन के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के हित को महासभा के अन्तर् की गुटवदियों व दुष्प्रभाव से मुक्त रखने में वह बहुत कुछ योगदान कर रहा होता है। वह महासभा की बैठक को स्थगित करने या किसी विषय पर हो रहे

बाद विवाद को स्थगित करना या निलंबित करने का सुझाव दे सकता है पर यह मतदान में भाग नहीं ले सकता है।

महासभा के नियमानुसार अध्यास के अतिरिक्त 17 उपाध्यक्षा और 7 समिति के समाप्तियों के चुनावों की भी व्यवस्था है। उपाध्यक्षा व चुनाव में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन में जहां तक सम्भव हो 7 व्यक्ति एशियाई अफ्रीकी तथा अन्य पूर्वी यूरोप सहित पश्चिमी यूरोप सहित लातिनी अमेरिका सहित तथा दोप अफ्रीका सहित (बेनडा, आस्ट्रेलिया 'न्यूजिलैंड') शामिल जाय। इससे अगवाया सुरक्षा परिषद के पास स्थायी सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या 18 हो जाती है। परंतु जिस क्षेत्र में अध्यास चुना जाता है उसकी एक संख्या कम कर दी जाती है। यह भी व्यवस्था की गई है कि कम से कम एक उपाध्यक्ष पद एशिया अफ्रीका क्षेत्रों में से या पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्यों में से या अध्यास पद या महापति पदों में से एक राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रों के सदस्यों को दिया जाय। स्पष्ट है कि महासभा में प्रादेशिक तथा अन्य आधार पर स्थित महासभा के अंदर की गुटबन्धियों को इस प्रकार मायता प्रदान की है।

मतदान जगह कहा जा चुका है महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक मत होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा अपने 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है। इनमें निम्नांकित प्रश्न शामिल किये गये हैं —

- (1) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए सन्तुष्टियां,
- (2) सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा स्वास्थ्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन,
- (3) राज्यों का सघन प्रवेश (सदस्य के रूप में) सदस्यों का सघन निष्कासन तथा सदस्यता व अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का विलम्बन,
- (4) स्वास्थ्य परिषद के संचालन सम्बन्धी प्रश्न,
- (5) आय-व्यय सम्बन्धी प्रश्न,
- (6) तथा वे प्रश्न भी जिन्हें महासभा महत्वपूर्ण धारित करे।

समितियां एवं सहायक अंग महासभा अपना काम समितियों के जरिए करती है। इस दृष्टि से अनुच्छेद 21 में इसे अधिकार प्रदान किये गये हैं। ऐसी समितियों के बिना महासभा के लिए अच्छी तरह विचार करना संभव नहीं है। अतः महासभा कार्य-सूची के प्रत्येक विषय को विचाराय तत् सम्बन्धी समिति को सौंप देती है। और उनकी सत्कृति के अनुसार फिर निर्णय करती है। प्रमुख समिति निम्नांकित हैं —

प्रथम समिति राजनीति एवं सुरक्षा समिति कही जाती है जो इस सम्बन्ध के मामलों पर विचार करती है,

द्वितीय समिति—आर्थिक एवं वित्तीय समिति है जो संघ के आर्थिक और वित्तीय सवाल पर विचार करती है,

तृतीय समिति—सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति है जो संघ के ऐतद विषय प्रश्न पर विचार करती है,

चतुर्थ—यास समिति है जो महासभा को यास परिपद सम्बन्धी कामों में मदद करती है।

पंचम समिति—शासक एवं आय-व्यय समिति है जो संघ के सचिवालय के शासनात्मक एवं बजट सम्बन्धी मामलों पर विचार करती है।

षष्ठम समिति विधि समिति है जो संघ के कानूनी मामला तथा अभिमत आदि तैयार करने में मदद करती है,

सप्तम समिति विशेष राजनीतिक समिति

ये समितियाँ अपने अध्यक्ष खुद चुनती हैं और इन्हें उप समितियाँ बनाने का भी अधिकार है। इसके अलावा दो प्रकार की और प्रक्रिया सम्बन्धी समितियाँ हैं—

सामान्य समिति या साधारण समिति—इसमें महासभा के अध्यक्ष, 17 उपाध्यक्ष और मुख्य समितियों के सभापति होते हैं। यह समिति महासभा को कार्य संचालन समिति कहली जा सकती है। इस समिति का काम कार्य-सूत्री निश्चित करना विचार विमर्श की प्राथमिकता तय करना तथा 7 स्थायी समितियों के कार्यों का समन्वय करना। समिति का कार्य परामर्श देना है।

परिषद् समिति इसमें 9 सदस्य होते हैं जो अधिवेशन में चुने जाते हैं यह समिति सदस्यों के परिषद् पत्रों की जांच करती है। इस समिति का कार्य भी परामर्शदायी है। इसके अतिरिक्त दो स्थायी समितियाँ भी हैं—

प्रशासनिक एवं आय-व्यय परामर्श समिति इस में महासभा द्वारा निर्वाचित 9 सदस्य होते हैं।

अनुदान समिति इसमें महासभा द्वारा निर्वाचित 10 सदस्य होते हैं यह समिति सदस्यों को दिया जाने वाला अनुदान निर्धारित करने में सलाह देती है। इन दोनों समितियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

इन उपयुक्त समितियों के अलावा महासभा में अनेक ऐतद समितियों की स्थापना की है जिनमें निम्नांकित मुख्य हैं—

(1) स्थायी प्रधान कार्यालय समिति (2) फिनंस्तीन समझौता समिति, (3) अणुशक्ति व शांति कार्यो वाली समिति, (4) विशेष बालबचन समिति, इत्यादि।

इन ऐतद समितियों के अलावा महासभा ने समय-समय पर अन्य सहायक अंगों की भी स्थापना की है यथा (1) अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (2) समुक्त

राष्ट्रीय प्रशासनात्मक आयोग, (3) शांति निरीक्षण समिति, (4) अतिरम समिति।

महासभा न सघ के प्रारम्भिक काल में जब सोवियत और अमेरिका के बीच शीत युद्ध छिड़ गया जिसके फलस्वरूप सुरक्षा परिषद का ठीक से काम चलना मुश्किल हो गया, उस समय महासभा ने 13 नवम्बर 1947 के एक प्रस्ताव के अनुसार एक अतिरम समिति नामक संस्था गठित की। इसी समिति की छोटी 'असम्बली' या छोटी सभा भी कहा जाता है। सघ प्रथम यह एक वर्ष के लिए गठित की गई थी। यह तय किया गया कि जब साधारण सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तब उपर्युक्त सभा महासभा के रूप में कार्य करती रहेगी। यह सुरक्षा परिषद के दायित्वों पर भी नज़र रखती थी। इसमें महासभा के सदस्यों के एक एक प्रतिनिधि रहते थे। सन 1948 में इसका कार्यकाल एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। सन 1949 में इसकी अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। परन्तु सन् 1952 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई और इस प्रकार यह एक निष्क्रिय परिषद हो गयी सन् 1947 में कोरिया सम्बन्धी अस्थायी कोरिया आयोग तथा बालकाल सम्बन्धी विशेष समिति के साथ परामर्श के लिए व जांच का काम इसे सौंपा गया था। सन् 1948 में इसे अन्तर्राष्ट्रीय मायालय की परामर्श समिति मागने का अधिकार दिया गया। इसको मास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन पर महासभा को रिपोर्ट देने का भी काम सौंपा गया।

सन 1950 में जब कोरिया में युद्ध शुरू होने के कारण सुरक्षा परिषद का काम चलने में कठिनाई हो गई तब पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी परिस्थिति में जबकि सुरक्षा परिषद शांति स्थापना सम्बन्धी निणय न ले सके तब महासभा को विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाय। महासभा में वीटो की कोई व्यवस्था नहीं है अतः 2/3 बहुमत से कोई भी महत्वपूर्ण निणय लिया जा सकता है। सघ में यह आवश्यक है प्रस्ताव पारित हो गया जिसके अनुसार सुरक्षा परिषद के साधारण 7 मतों से अथवा महासभा के सदस्यों के बहुमत से 24 घंटे का 'नोटिस' देकर आवश्यक विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यदि विशेषाधिकार के प्रयोग से सुरक्षा परिषद अपना कार्य न कर सके तो साधारण सभा इस पर तुरन्त विचार कर कर सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकती है।

महासभा का कार्यक्षेत्र महासभा की 'चाटर' ने एवं सर्वाधिक शक्तिशाली अंग के रूप में रखने की योजना नहीं की थी। महासभा में संयुक्त राष्ट्र सघ का लोकतन्त्रात्मक और प्रतिनिधि मूलक स्वरूप सुरक्षित है पर कालांतर में महासभा ने कार्य और अधिकार क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। वैसे भी 'चाटर'

ने महासभा को एक विस्तृत क्षेत्राधिकार दिया था। महासभा को न केवल विचार विमर्श एवं सस्तुतियात्मक कार्य ही नहीं सौंपे गये थे बल्कि, उसे पर्यवेक्षण, वित्तीय नियंत्रण एवं अन्य अंगों के निर्माण काय भूमिका भी सौंपी गयी थी। महासभा के दायों व अधिकारों के क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नांकित शीर्षकों के द्वारा दर्शाया जा सकता है — (1) विचार विमर्श एवं सस्तुतियात्मक कार्य — महासभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मामले में जो 'चाटर' व अंतर्गत या चाटर के अधिनस्थ संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अंग के अधिकार या कार्य से सम्बंधित है विचार कर सकती है। इस प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत महासभा का कार्य कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों के मामले महासभा में पेश हो सकते हैं। महासभा सदस्यों का तथा सुरक्षा परिषद को अपनी सस्तुति प्रेषित कर सकती है। इसी विधान के अंतर्गत ऐसे मामलों जहाँ में उठाया गया जैसे 2 अप्रैल, 1947 को घिटेन के प्रति निर्धारित महासभा के विचाराधीन फिलिस्तीन का मामला रखा। इसी तरह 9 फरवरी, 1946 को महासभा ने स्पेन के मामले में यह प्रस्ताव पारित किया कि सदस्य सेन फ्रांसिसको एवं पोर्टोसो सम्मेलनों के प्रस्तावों को अनुमति देकर (जिस में सदस्यों ने यह अनुरोध किया गया था कि वे स्पेन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सन्तुष्टता प्राप्त करने में मदद नहीं करें) ऐसी ही स्थिति में यूनान के प्रश्न पर हुई जबकि सुरक्षा परिषद की असमर्थता के कारण यूनान के प्राप्ति अमेरिका प्रतिनिधि की सहायता से अक्टूबर 1947 में महासभा के सामने रखी गयी। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत महासभा को अधिकार दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए राजनीतिक सहयोग सम्बंधी किसी प्रश्न पर विचार कर सदस्यों, सुरक्षा परिषद अथवा दोनों को सस्तुति कर सकती है। महासभा को यह भी अधिकार मिला है कि वह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास कर सकती तथा वह राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बंधों पर प्रभाव डालने वाली किसी भी स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सस्तुति कर सकती है।¹⁶

महासभा का निरीक्षणात्मक अधिकार अनुच्छेद 15 में महासभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह सुरक्षा परिषद से वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन प्राप्त करे। इन प्रतिवेदनों में सुरक्षा परिषद अपने उन निष्कर्षों तथा कार्यवाहियों का विवरण उपस्थिति करती है जिस अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के निमित्त उठाया गया है। इसी तरह वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों से भी इस प्रकार के प्रतिवेदन प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार महासभा को अन्य अंगों के कार्य व्यापार पर विमर्श करने तथा अपनी राय देने का अधिकार देकर 'चाटर' ने महासभा को एक महत्वपूर्ण निरीक्षक अंग बना दिया है।

सुरक्षा परिषद अपने नियमित अधिवेशन के अंत में महा सभा को वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करती है। किंतु महा सभा ने कभी उस पर अपनी सहमति या असहमति प्रकट नहीं की। औपचारिक रूप से वह एक प्रस्ताव पास करती है कि "महा सभा ने सुरक्षा परिषद का प्रतिवेदन प्राप्त कर उस पर विचार विमर्श किया और काय अब काय सूची के अगले विषय पर विचार करने हेतु अग्रसर होती है।

अनुच्छेद 98 में महा सचिव की यह जिम्मेदारी मानी गयी है कि वह सभ के काय-कलापो के सम्बन्ध में महासभा को एक वार्षिक प्रतिवेदन करता रहेगा। आर्थिक एवं सामाजिक तथा 'याय' परिषदों के इस प्रकार के वार्षिक प्रतिवेदन का या तो श्रावधान नहीं है लेकिन यह महा सभा के अधिकार क्षेत्र में है कि वह उन से प्रतिवेदन माग ले। व्यवहार में ये परिषदें सदैव नियमित प्रतिवेदन महा सभा को भेजती रही हैं। महा सभा परिषदों के कार्यों की आलोचना कर सकती है। सुझाव दे सकती है और सुधार एवं विस्तार के लिए निर्देश दे सकती है। यदि वह असंतुष्ट है तो अपन असंतोष को सन्तुष्टि के रूप में प्रकट कर सकती है।

वित्तीय काय महासभा इसके अंतर्गत सभ के बजट पर विचार करती है तथा उसे स्वीकार करती है तथा वह सदस्यों के अशदान को निर्धारित करती है। महा सभा को विशिष्ट अधिकरणों के आय व्यय सम्बन्धी प्रबन्धों के अनुमोदन करने और प्रशासकीय आय व्यय का निरीक्षण करने तथा सन्तुष्टि करने का अधिकार है।

निर्वाचन सम्बन्धी काय यह महा सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो उसे संयुक्त राष्ट्र सभ का केन्द्र सा बना देती है क्योंकि उसकी सहायता से ही दूसरे अंग अपने सदस्यों का चुनाव करते हैं।

महा सभा सुरक्षा परिषद के अस्थायी असदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों तथा 'याय' परिषद के कुछ सदस्यों का निर्वाचन करती है। महा सभा सुरक्षा परिषद के साथ मिल कर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा 'याय'-धीशा का निर्वाचन करती है तथा सुरक्षा परिषद की सन्तुष्टि पर महा सचिव की नियुक्ति का भी उसे अधिकार है।

इन कार्यों के अतिरिक्त महा सभा किसी भी वैधानिक प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की परामर्शीय सम्पत्ति प्राप्त कर सकती है। महामभा 'चाटर' के सशोधन को अपनी स्वीकृति देती है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सभ की महा सभा एक विस्तृत अधिकार वाली परिषद मालूम पड़ती है। परन्तु यह ध्यान रखने लायक है कि इस के अधिकार असीमित नहीं। यह प्रमुत्ता सम्पन्न मन्द रहती है। 'चाटर' ने इस अधिकार को प्रतिबंधित कर रखा है। इसके अन्तर्गत सभ में विचार विमर्श कर सकते हैं समस्याओं का अध्ययन प्रारम्भ कर सकते हैं, प्रस्ताव स्वीकार

करते हैं और सन्तुष्टियां पैदा कर सकते हैं। पर वे कोई ऐसा कानून बना सकते जिसे राज्यों को बाध्य होकर मानना पड़े। वे शांति और सुरक्षा परिषद के सामने पैदा हो तब तक उस पर कोई विचार नहीं कर सकती जब तक स्वयं सुरक्षा परिषद उस के लिए प्रायना न करे।

शांति के लिए सगठन संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना के कुछ समय पश्चात् ही मित्र राष्ट्रों के बीच फूट पड़ गयी और सोवियत संधि एव अमेरिका गुट के बीच शीत युद्ध छिड़ गया जिस से सुरक्षा परिषद को कायवाही ठण्ठ पड़ने लगी। सन् 1946 में ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं के सीरिया और लेबनान के सम्बन्ध में तथा 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी के समय सुरक्षा परिषद एक निष्क्रिय एवं निस्तेज परिषद बन कर रह गई। इस से संयुक्त राष्ट्र संधि शांति और सुरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा सका। इस समस्या से निपटने के लिए 13 नवम्बर, 1947 को महासभा ने एक अन्तरिम समिति गठित की जिस का वर्णन ऊपर कर चुके हैं। सन् 1950 में जब कोरिया में युद्ध छिड़ गया तब सुरक्षा परिषद के लिए इस विषय पर स्थिति का सामना करना पड़ना ही हुआ। सोवियत संधि लगातार अपना 'वीटो' इस्तेमाल करने लगे। ऐसी स्थिति में पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से 3 नवम्बर, 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा के समक्ष रखा गया जिसे उस ने पारित किया। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत यह प्रवृत्ति किया गया कि यदि किसी कारणवश शांति एवं सुरक्षा की कायवाही में सुरक्षा परिषद अपने को असमर्थ पाती है तब महासभा इस कृतव्य को वहन कर सकती है। तथा आवश्यक कायवाही करने का उसे अधिकार है। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नांकित हैं —

(1) सुरक्षा परिषद के शांति एवं सुरक्षा की कायवाही में असमर्थ रहने पर उसने 7 सदस्यों या महासभा के बहुमत के अनुरोध पर महासभा की विशेष आपातकालीन अधिवेशन 24 घण्टे के अन्दर बुलाया जा सकता है।

(2) 14 सदस्यों के एक शांति पर्यवेक्षक दल का निर्माण करना जिसमें सुरक्षा परिषद के पांचो स्थायी सदस्य भी रहेंगे तथा जिस का कार्य शांति भंग के खतरे वाले क्षेत्र में पर्यवेक्षकों को भेजना है ताकि, वे स्थिति को बिगड़ने से रोकें।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के साधनों का अध्ययन करने के लिए एक 14 सदसीय सामूहिक सुरक्षा समिति का गठन करना,

(4) यह सन्तुष्टि की गई कि सदस्य अपने साधनों का सर्वेक्षण करें कि वे शांति व सुरक्षा के लिए महासभा को कितनी सहायता दे सकते हैं। वे अपनी सैनिक टुकड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे तथा शस्त्रास्त्रों में 'लैश' रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे उपलब्ध हो सकें। महासचिव को सैनिक विशेषज्ञों की एक सूची तैयार

संयुक्त राष्ट्र युद्धवालीन साहचय

करने का अधिकार दिया गया जो राज्यों के अनुरोध पर उन्हें तकनीकी परामश देंगे।

115

सामूहिक सुरक्षा समिति ने 1951-52 और 1954 में आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक अनुसंस्थितों सम्बन्धी कई प्रतिवेदन महासभा के सामने प्रस्तुत किये।

सामूहिक शांति रक्षा की कायवाही के अन्तर्गत महासभा ने 1956 में पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की रक्षा के लिए सेनाएं भेजी। 1960 में कांगो तथा 1964 में साइप्रस में सेनाएं एवं 1963 में यमन में निरीक्षक दल भेजे। ऐसे ही अभी अभी पश्चिम एशिया में अरब इजरायली युद्ध विराम के रक्षा के लिए भेजा है। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि सदस्य राष्ट्र शांति रक्षा की इस तरह की कायवाही में किये गये व्यय को सध का व्यय नहीं मानते हैं। तथा उस देने को तैयार नहीं हैं। यमन और साइप्रस की कायवाहिया स्वेच्छिक अशदान द्वारा पूरी की जा रही हैं। कांगो की कायवाही में किये गये व्यय की कोई जिम्मेदारी सोवियत सध व उसके साथी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। सोवियत सध सदैव स ऐसे प्रस्ताव का विरोधी रहा है और इस उसने असाविधानिक माना है।

अनुच्छेद 19 संयुक्त राष्ट्र सध के ऐसे सदस्य को जिसने सध को अपना आर्थिक अनुदान न दिया हो महासभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उसकी बकाया रकम पिछले दो वर्षों के अनुदान के बराबर अथवा अधिक होगी। महासभा ऐसे सदस्य को मतदान की आज्ञा दे सकती है। यदि उस इस बात से सतोष हो जाय कि रकम न चुका सकने के ऐसे कारण थे जिन पर सदस्य का नियन्त्रण नहीं था। ऐसे मतधिकार से बचिन करने का ऐसा अधिकार सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा यास परिषद को प्राप्त नहीं है।

जब स्वेज और कांगो में संयुक्त राष्ट्र सध की सेना के व्यय का भार बहन करने के लिए रूस और फ्रांस तथा कुछ अन्य राष्ट्र तैयार नहीं हुए और उनकी बकाया धनराशि दो वर्ष के अनुदान से अधिक हो गयी तब 1964 में अमेरिका ने इन राष्ट्रों के विरुद्ध ऐसा एक प्रस्ताव रखा। किन्तु बहुमत को अपने पक्ष में न पाकर अमेरिकी प्रतिनिधि ने उसे मतदान के लिए नहीं सौंपा। फलस्वरूप इस प्रस्ताव पर अमल नहीं हो सका।¹⁷ इसके अलावा महासभा ने एक अन्य महत्व पूर्ण काय भी किया है यथा महासभा ने फिलस्तीन के बटवारे की योजना बनाई थी और इजरायल के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार स्वतंत्र कोरिया के निर्माण का प्रयास भी किया गया। यद्यपि वह दक्षिण कोरिया से आगे नहीं बढ़ सका। सन् 1967 में दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के संरक्षित प्रदेश की सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक 12 सदस्यी की समिति गठित की गयी। इसी प्रकार बांग्ला देश की मायता का प्रश्न भी आजकल महासभा के सम्मुख है।

महासभा का बदलता हुआ स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संधि के निर्माताओं ने जिस रूप में महासभा की कल्पना की थी आज महासभा का स्वरूप और महत्व उससे काफी बदला हुआ है। 'चाटर' के निर्माताओं ने महासभा को संयुक्त राष्ट्रसंधि का एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ बनाया था पर शांति और सुरक्षा के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद को महासभा से अधिक शक्तिशाली और उत्तरदायी बनाया था। वस्तुतः जिस प्रकार सुरक्षा परिषद का संगठन किया गया था उसमें शांति और सुरक्षा के लिए पांच बड़े स्थायी सदस्यों को विशेषतः विश्व शांति व सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गए थे पर छोटे युद्ध की सपेट में आकर सुरक्षा परिषद पांच बड़ों की आपसी सझाई का शिकार हुआ और एक प्रभावशाली परिषद नहीं बन सकी। इस कमी को महासभा ने बहुत कुछ पूरा करने की चेष्टा की। शांति के लिए एतता के प्रस्ताव के बाद महासभा विचार विमर्श और बाद विवाद मात्र करने वाली परिषद ही नहीं रह गई बल्कि, शांति और सुरक्षा के मामले में सुरक्षा परिषद के समाधान न निकाल पाने पर एक महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग भी बन गयी है। महासभा के महत्व और शक्ति में निरंतर बढ़ि हुई है। यह केवल इस एकता के प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप ही नहीं बल्कि, अन्य कारणों से भी महासभा का स्वरूप कुछ का कुछ हो गया है। एक प्रमुख कारण यह है कि महासभा की सदस्यता के दायरे में आज लगभग पूरे ससार के स्वतंत्र राष्ट्र आ रहे हैं। प्रारम्भिक काल में जब केवल 51 संस्थापक राज्य इस के सदस्य थे तब महासभा 21 लातिनी अमेरिकी राज्यों के दबदबे में थी जिसका लाभ अमेरिकी नेतृत्व उठाता था। लातिनी अमेरिकी देश उनका नेता अमेरिका, केनडा, पश्चिम यूरोप के पुराने साम्राज्यवादी देश इनको मिलाने आम्स अमेरिकी गुट का वचस्व सहज की स्थापित हो जाता था पर जैसे-जैसे नये सदस्य राष्ट्रों का प्रवेश हुआ और सन 1955 के बाद विशेषतः जब एशिया अफ्रिका के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र इसके सदस्य बनते गए तब महासभा के अंदर का शक्ति सतुलन बिल्कुल ही बदल गया और यह ससार की वास्तविक प्रतिनिधि सस्था के रूप में ढलने लगी जिसमें बहुसंख्यक सदस्य विश्व जनमत का प्रतिनिधित्व करने का दावा ठोस आधार पर कर सकते हैं। इसी के फलस्वरूप आज बड़े राष्ट्रों की दादागिरी महासभा में नहीं दिखाई पड़ती जब कि सुरक्षा परिषद ही ऐसी परिषद रह गई है जिसमें वे अपनी दादागिरी आजमा सकते हैं। आज इस के सदस्यों की संख्या 155 तक पहुच गयी है और अब ससार के लगभग आधा दर्जन देश ही इसकी सदस्यता से वंचित रह गए हैं। इस अर्थ में महासभा का स्वरूप अब मानव समाज के सदस्य की तरह बन गया है आज यदि शांति और सुरक्षा के प्रश्नों का समाधान विश्व जनमत के सहारे शांतिपूर्ण ढंग से आपसी विचार विमर्श के बाद निकालना सम्भव हो सका है तो उस में महासभा के इस बदलते रूप में एक अच्छा खासा योगदान

किया है। महासभा के इस प्रतिनिधि मूलक स्वरूप के कारण आज छोटे मोटे राष्ट्रों की भी हिम्मत और आत्म विश्वास बढ़ गया है और वे बड़े राष्ट्रों का वचस्व और दबदबे को महासभा की ढाल बनाकर बहुत कुछ रोक पाने में समर्थ हो रहे हैं। इस महासभा में संसार की सभी समस्याओं पर विचार होते रहते हैं और यह उल्लेखनीय है कि महासभा ने शांति और सुरक्षा के अनेक मसलों को सुलझाने में सहायनीय प्रयत्न किया है।

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संधि के 'चाटर' के निर्माताओं ने महासभा की एक विचार विमर्श करने वाली परिषद के रूप में बनाया था और संयुक्त राष्ट्र संधि की कार्याकारिणी की तरह तीन अथवा अग्रा का निर्मित किया था। वे तीन अंग हैं 'रास या संरक्षण परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तथा सुरक्षा परिषद। इनमें सुरक्षा परिषद को शांति और सुरक्षा के मामलों के लिए जिम्मेदार एक प्रभावशाली कार्याकारी अंग के रूप में ढाला गया था। इस के सदस्यों की संख्या को भी 'चाटर' के द्वारा निर्धारित किया गया था जबकि पुराने राष्ट्रसंघ की 'काउंसिल' की कोई निश्चित सदस्यता नहीं थी। 'चाटर' ने इसे अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार एक ग्यारह सदस्यों वाली परिषद के रूप में बनाया था जिनमें पांच बड़े राष्ट्रों को स्थायी रूप से सदस्यता सौंपी गयी थी। वे पांच थे सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। बाकी छ सदस्य अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिए महासभा के 2/3 मतों से निर्वाचित होते थे। जब संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्य संख्या निरंतर बढ़ती गई और एशिया अफ्रीका के अनेक नवोदित राष्ट्र इसके सदस्य बनते गए तब सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाने की भी मांग उठी। इसके फलस्वरूप अगस्त 1965 में 'चाटर' के इस भाग का संशोधन किया गया जिसके अनुसार अस्थायी सदस्यों की संख्या छ की जगह 10 कर दी गई। महासभा ने यह निर्णय किया कि 10 अस्थायी सदस्यों में से पांच एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से लिए जाय, एक पूर्वी यूरोप में से, दो लातिनी अमेरिकी राज्यों में से व दो पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से लिए जाए। 'चाटर' में यह कहा गया कि दो वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने पर किसी सदस्य राष्ट्र को तुरंत ही दुबारा निर्वाचन के लिए खड़े होने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार सन 1965 के संशोधन से अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो गई है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद में भी एफो एशियाई तथा लातिनी अमेरिकी देशों का प्रभाव बढ़ा है तथापि यह उल्लेखनीय है कि स्थायी सदस्यों की संख्या ज्यों की त्यों ही बनी रह गई है। यद्यपि संसार के अन्य देशों में इन 5 बड़े राष्ट्रों की तुलना में जापान, जर्मनी, भारतवर्ष ऐसे राष्ट्रों का महत्त्व इन 5 बड़े राष्ट्रों से विशेषतः फ्रांस, ब्रिटेन और चीन से कुछ कम नहीं है तथापि, ये अस्थायी सदस्यता ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चाटर के इस संशोधन ने सदस्यता

ये इस पहलु को भी उदघाटित कर दिया है।

सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को या तो वक्ता एवं मत देने का अधिकार है। परिषद के प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर 9 मत से निर्णय लिया जाता है लेकिन प्रक्रिया के अलावा अन्य विषयों पर इन 9 मतों में 5 स्थायी सदस्यों के मतों का होना भी आवश्यक है। यदि इन पांचों में से एक भी बड़े राष्ट्र का मत विपक्ष में या विरोध में हो तो वह प्रस्ताव किसी भी प्रकार के बहुमत के बावजूद अस्वीकृत हो जाएगा। पांच बड़े राष्ट्रों में प्रत्येक के मतों को मिल दूँ, इस व्यवस्था को ही निषेध का अधिकार कहते हैं। इस प्रकार सुरक्षा परिषद में प्रस्तावों के पास होने के उनके अमल में लाये जाने के लिए यह नितांत जरूरी है कि न केवल 9 मत उसके पक्ष में गिर सकें, एक-एक पांच बड़े राष्ट्र उस प्रस्ताव से अपनी सहमति प्रकट करें जिस का अर्थ यह होता है कि यदि एक भी बड़ा राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यवाही का विरोधी हो तो वह उस सारी कार्यवाही को ही खत्म कर सकता है। अरनाल फास्टर ने ठीक ही लिखा है 'निषेधाधिकार का भय सम्पूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के घरीर में ही पड़ावात है। यह उस 'कार' के समान है जिसका 'स्टार्टर' किसी भी समय उस की यंत्र व्यवस्था में गड़बड़ करके उसके इंजिन को रोक सकता है।'

सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली व अधिकार क्षेत्र

सुरक्षा परिषद का इस तरह गठन किया गया है कि यह सदैव कार्यरत रहने वाली परिषद बन गयी है। इस के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि मुख्यालय में रहता है। इस कारण सुरक्षा परिषद के बैठकें आवश्यकतानुसार तुरन्त ही बुलाई जा सकती हैं और सुरक्षा परिषद उन के माध्यम से तुरन्त कार्यवाही कर सकता है। जैसे सामान्यतः सुरक्षा परिषद की बैठकें प्रत्येक पसबाड़े में होती हैं अर्थात् दो बैठकों के बीच 14 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस परिषद की बैठकें अध्यक्ष आमन्त्रित करता है अध्यक्ष निम्नांकित परिस्थितियों में परिषद की बैठक आमन्त्रित करता है।

- 1 सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य राष्ट्र की प्रायना पर,
- 2 सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति की ओर 'चाटर' के अनुच्छेद 11 (3) अथवा अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित किए जाने पर,
- 3 यदि महासभा अनुच्छेद 11 (2) के अन्तर्गत परिषद का ध्यान किसी प्रश्न या विवाद की ओर आकर्षित करती है अथवा इस अनुच्छेद के अन्तर्गत परिषद की बैठक की सिफारिश करती है,
- 4 यदि महासभा का महासचिव अनुच्छेद 99 के अन्तर्गत परिषद के अध्यक्ष को

सूचना देता है कि किसी कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है,

इसके अलावा अनुच्छेद 28 (2) के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद की सामूहिक बैठकों के बुलाये जाने का भी प्रबंध किया गया है जिसमें साधारण प्रतिनिधि के स्थान पर विशेष मनोनीत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया नियमावली में इस तरह की बैठकें साल में दो बार की जा सकती हैं। इस प्रबंध को कार्यान्वित करने के लिए 1950 व 1955 में महासचिव ने सुझाव दिये थे। सन 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन में महासचिव यू. थाट ने भी इस के उपयोग का सुझाव दिया था ताकि इस प्रकार की बैठकों में परिषद के सदस्यों को उच्च स्तरीय वार्ता का अवसर मिल जाता है। महासभा और सुरक्षा परिषद ने भी समय समय पर ऐसा सुझाव दिया।

सुरक्षा परिषद अपने अध्यक्ष का स्वयं चुनाव करती है। परिषद का अध्यक्ष प्रति मास राष्ट्रों के अग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में चुना जाता है। अध्यक्ष का काम परिषद की बैठकों को नियमानुसार बुलाना व उस का संचालन करना है। अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण का निणय करने तथा अन्य निर्देश देने का अधिकार है। लेकिन परिषद अध्यक्ष के निर्देश के विरुद्ध भी निणय कर सकता है। अध्यक्ष महासचिव द्वारा निर्धारित प्रारम्भिक कार्य सूची को तैयार करता है। उन विवादों में जो ऐम. राउस से सम्बन्धित हों जहाँ का अध्यक्ष नागरिक है, उस स्थिति में वह अध्यक्षता नहीं करता। इसके अलावा अध्यक्ष अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर कभी कभी निषेधाधिकार का प्रयोग करने के लिए आपसी विचार-विमर्श द्वारा सदस्यों का अभिमत जानने का प्रयत्न करता है जसा बास्मोर और वियतनाम के मामले में किया गया।

यह ध्यान देने योग्य है कि परिषद को यह भी अधिकार है कि जब यह किसी ऐसे मामले पर विचार कर रही है जिस से सम्बन्धित पक्ष परिषद में उपस्थित न हो तब भी वह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य हो या न हो उस बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर सकती है पर एम. सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होगा। यथा 1962 क्यूबा संकट की घटना में क्यूबा को आमन्त्रित किया गया था तथा 1964 में टाबिन गाड़ी की घटना के संबंध में उत्तरी वियतनाम को आमन्त्रित किया गया।

सुरक्षा परिषद को अपनी प्रक्रिया नियमावली बनाने का अधिकार है।

समितिओं व आयोग

सुरक्षा परिषद ने अपने काम को सुचारु रूप में चलायें व निरंतर समितिओं व आयोगों का गठन किया है।

(1) सैनिक बग समिति यह समिति अनुच्छेद 47 के अधीन स्थापित की गयी है। यह समिति सुरक्षा परिषद की सहाय्य सैनिक भाष्यवाही, सहाय्य सनाओ के संचालन, सना सम्बन्धी आवश्यकताओ, सहाय्य की व्यवस्था एवं निरासत्रीकरण आदि के विषयों में सहायता और सलाह देती है। इस समिति के सदस्य परिषद के स्थायी सदस्यों के सनापति अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते हैं। यह समिति रूस तथा अन्य स्थायी सदस्यों के बीच गहरे मतभेद के कारण कार्यशील नहीं हो सकती।

(2) अणु शक्ति आयोग अनुच्छेद 29 के अंतर्गत महासभा के 24 जनवरी, 1946 के प्रस्ताव के आधार पर अणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई। इसका कार्य परमाणु शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सम्बन्ध में परिषद को परामर्श देना तथा परमाणु शक्ति का शांति के कार्यों के लिए प्रयोग करने में मदद देना है। इसमें सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के अलावा केनडा है।

(3) विध्वंसक हथियारों का आयोग इस आयोग की स्थापना 13 फरवरी, 1947 में हुई इसका काम महासभा के 14 दिसम्बर, 1946 के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का है जिसके अंतर्गत हथियारों के नियंत्रण और उनमें कटौती करने के बारे में परिषद का काम देना है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य इसमें सदस्य हैं। इसके अलावा परिषद की दो स्थायी समितियाँ भी जिनमें परिषद के सभी सदस्य रहते हैं (1) नए सदस्यों के प्रवेश की समिति यह समिति उन प्रायनामों पर विचार करती है और अपनी सन्तुष्टि देती है जो नए सदस्य समुक्त राष्ट्र सभ में प्रवेश पाने के लिए प्रस्तुत करते हैं (2) विशेषज्ञों की समिति यह परिषद की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में नियमों एवं प्राविधिक मामलों में परिषद को अपनी सलाह देती है।

इसके अलावा परिषद समय समय पर आयोगों एवं एतद्घ समितियों का निर्माण करती रहती है यथा इण्डोनेशिया के सम्बन्ध में राष्ट्र सभ आयोग (25 अगस्त, 1947) भारत के लिए राष्ट्र सभ आयोग (20 जनवरी 1948) यूनान के मामले में आयोग तथा फिलिस्तीन के मामले में राष्ट्र सभ आयोग।

अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा

सुरक्षा परिषद का काम क्षेत्र 'चाटर' के अनुसार सुरक्षा परिषद समुक्त राष्ट्र सभ का वह कार्यकारी अंग है जिसके जिम्मे विश्व में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना है। 'चाटर' के अनुच्छेद 29 के अनुसार सुरक्षा परिषद के अधिकारों व कार्यों का निर्धारण किया गया है। चाटर के अनुसार सुरक्षा परिषद के प्राथमिक दायित्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का भार उस पर सौंपा गया है। यह उल्लेखनीय है कि चाटर सुरक्षा परिषद को प्राथमिकता प्रदान करता है न कि

सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जो केवल संधि में निहित है 'चाटर' की 33-38 अनुच्छेद तक अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में शांतिपूर्ण निपटारे के सम्बन्ध में तथा 39 से 51 अनुच्छेद तक अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरों में डालने से इसे भंग करने या आक्रमण को रोकने की कायवाही के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। सुरक्षा परिषद को अपने शांति और सुरक्षा की स्थापना के उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए अध्याय 6, 7, 8, और 12 के अंतर्गत कायवाही करने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 के द्वारा राष्ट्र संधि के सदस्यों का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वे परिषद के निर्णयों को स्वीकार करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करेंगे। जब कभी अंतर्राष्ट्रीय शांति के भंग होने का खतरा हो या ऐसी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाय तब (1) महासभा के द्वारा (2) अथवा महासचिव के द्वारा या (3) परिषद का कोई भी सदस्य ऐसी विस्फोटक स्थिति की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं परंतु सुरक्षा परिषद स्वयं यह निश्चय करती है कि अमुक परिस्थिति में तथाकथित आक्रामक कायवाही या धमकी किस हद तक नीति भंग करने वाली मानी जाय। क्योंकि अन्ततः अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की पुनः स्थापना के लिए कायवाही करने का उसे अधिकार है। ऐसा करने के पूर्व परिषद उक्त विवाद से सम्बन्धित राज्यों को निर्देश दे सकती है कि वे तनाव को दूर करने के लिए अंतिम हल तय होने से पूर्व कुछ अस्थायी व्यवस्था स्थापित कर लें।

यदि स्थिति नहीं सभलती तो परिषद अपने निर्णयों को लागू करने के लिए तथा शांति स्थापना के लिए दो तरह की कायवाही कर सकती है। (1) ऐसी कायवाही जिसमें शक्ति का प्रयोग न हो यथा परिषद सदस्यों को आदेश दे सकती है कि सदस्यगण आक्रामक के साथ अपना आर्थिक सम्बन्ध पूर्णतः या अंशतः विच्छेद कर दें। या ऐसे आक्रामक को यातायात, डाक व तार व व्यापार की अन्य सुविधाओं से वंचित कर दें एवं उसकी कूटनीतिक मायता रद्द कर दें।

(2) जल, थल एवं वायु सेना के द्वारा सशस्त्र कायवाही हालांकि बिगड़ने पर परिषद नानेबंदी वायु थल एवं नौसेना के द्वारा सैनिक कायवाही भी कर सकती है। 'चाटर' के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संधि के सभी सदस्यों ने परिषद की ऐसी सुरक्षात्मक कायवाही के लिए सैनिक सहायता देने का वचन दिया है इसी प्रकार उन्हें संयुक्त राष्ट्र संधि की सेना को आवागमन की सुविधा देनी होगी यह परिषद तय करेगी कि इस तरह की सैनिक कार्यवाही में सभी सदस्य राज्यों का भाग लेना अनिवार्य है या नहीं। यदि कोई राज्य आक्रमण की स्थिति में अपनी सुरक्षात्मक कदम उठाता है तब इसकी सूचना तुरंत ही सुरक्षा परिषद को देनी होगी।

(2) विवादों का निपटारा चाटर के अध्याय 6 में सुरक्षा परिषद को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वह विवादों का शांतिपूर्ण हल निकाले। 33 में यह दिया है कि यदि दो पक्षों के बीच कोई ऐसा विवाद उठ

जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाने की आशका है तो उस विवाद को वार्ता, जांच मध्यस्थता, सराधन (कंसोलिडेशन) विवाचन (आरबिट्रेशन) 'यायिक निणय' क्षेत्रीय प्रबंध' इत्यादि अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से हल निकालें। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि यदि पक्ष अपने विवाद को इस तरह सुलझाने में सफल नहीं होते तो उन्हें इसे सुरक्षा परिषद को सौंप देना चाहिए। बर्लिन की नाकेबंदी का सवाल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में सुरक्षा परिषद के सामने यह कह कर ही रखा दिया था कि शांतिपूर्ण तरीकों से इसका हल सम्भव नहीं है। अतः यह शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। इस पर किसी विरोध के बावजूद इस सवाल ने सुरक्षा परिषद की कार्य सूची में स्थान पा लिया था। इस सम्बंध में यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 34 के अन्तर्गत यदि सुरक्षा परिषद किसी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने वाला माने तो वह विवाद या स्थिति की जांच करवा सकते हैं। यूनान और भारत-पाकिस्तान विवादों में अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जांच आयोग की स्थापना की गयी है। इस बारे में मतभेद है कि यह जांच की कार्यवाही प्रक्रिया सम्बंधी प्रश्न है या महत्वपूर्ण प्रश्न माना है और बेकौन्लोवाकिया के प्रश्न पर निपेधाधिकार का प्रयोग किया।

(3) अन्य काम सदस्यता सम्बंधी नये सदस्यों का प्रवेश, उनका निलम्बन तथा निलम्बन की समाप्ति और उनका निष्कासन सुरक्षा परिषद के सहमति के बिना सम्भव नहीं।

'यास प्रशासन' कुछ 'यान प्रशासन' में कुछ क्षेत्र 'सामरिक' महत्व के निर्धारित किये गये हैं। ये क्षेत्र प्रज्ञात महासागरीय द्वीप समूह हैं (माशल आइलैंड) इनके प्रशासन का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर डाला गया है। जो यास समझौता को स्विकार करती है और अपने निरीक्षणात्मक अधिकार के अंतर्गत सालाना रिपोर्ट प्राप्त करती है।

निर्भूत सम्बंधी अंतर्राष्ट्रीय 'यायालयों के 'यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संसुति पर महासभा के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार सुरक्षा परिषद की संसुति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है।

सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण मामलों में अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय से परामर्श मूलक सम्मति ले सकती है और यदि कोई पक्ष 'यायालय के निणय से अपने दायित्व का पालन नहीं करता तो परिषद उस मनवाने के लिए उचित कार्यवाही कर सकती है।

सुरक्षा परिषद विवादों के शांतिपूर्ण हल तथा प्रवृत्तात्मक कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय प्रबंध के अन्तर्गत संयोजित संगठनों का उपयोग कर सकती है। इस सम्बंध

मे यह माना गया है कि ऐसे संगठन शांति और सुरक्षा के निहित जो भी कायवाही करेंगे उसकी सूचना सुरक्षा परिषद को देना आवश्यक है।

अतः मे, सुरक्षा परिषद पर यह तय करने की जिम्मेदारी छोड़ी गयी है कि यदि कोई राज्य जिसने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान पर अपनी सहमति नहीं है वह यहाँ मुकदमा लाना चाहे तो किन परिस्थितियों में ला सकता है।

सुरक्षा परिषद के निणय और निषेधाधिकार का प्रश्न

संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माताओं ने सुरक्षा परिषद को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली अंग के रूप में निर्मित किया था। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के बीच संयुक्त राष्ट्रसंघ के ये निर्माता एक ऐसी युद्धोत्तर व्यवस्था बनाने के लिए कृत संकल्प थे जो विश्व शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ आधारों पर टिका दे और युद्ध की सम्भावनाओं को समाप्त प्रायः कर दे। वे सभी दिलोजाना से ऐसी योजना बनाने में जुटे और उसका ही प्रतिफल सुरक्षा परिषद का संगठन था। जिस मूलभूत विचार पर सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ वह यह था कि दुनिया की वास्तविक बड़ी शक्तियों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही ससार की शांति और सुरक्षा की व्यवस्था निर्मित की जा सकती है। युद्ध की सम्भावना उस स्थिति में पैदा हो जाती है और बढ़ जाती है जबकि कुछ बड़ी ताकतें अथवा बड़ी ताकत के विरुद्ध ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रयोग में लाती हैं। जिन संगठनों के जन्मे शांति और व्यवस्था सौंपी गयी है राष्ट्रसंघ का कटु अनुभव यही शिक्षा दे रहा था कि जब ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्रसंघ को अथवा शक्तियों के विरुद्ध हथियार बनाना शुरू किया और दूसरी ताकत ने राष्ट्रसंघ से बाहर निकल कर या उससे निष्कासित होकर उसके प्रति वैमनस्यता और उदासीनता तो राष्ट्रसंघ का भी ढेर हो गया और युद्ध जनक स्थितियाँ बढ़ती चली गयीं। इसलिए इस बार युद्धोत्तर व्यवस्था में शांति और सुरक्षा की मूलभूत जिम्मेदारी पाँच बड़ी शक्तियों की पचायत पर छोड़ दी गयी थी और यह प्रबंध किया गया कि इन पाँचों बड़ी शक्तियों का न केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति रहेगी बल्कि इनमें एक एक भी अगर सुरक्षा परिषद द्वारा सुझायी गयी कायवाही का विरोध करे तो वह कायवाही नहीं की जा सकेगी। अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघ रूपी अस्त्र का प्रयोग इन पाँच पक्षों के सहयोग से तो किया जा सकता है। इनमें से एक की भी असहयोग करने पर यह अस्त्र बेकार हो जायेगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माताओं का यह विचार था कि ससार की शांति और व्यवस्था सामर्थ्यवान और शक्तिवान राष्ट्रों के भरोसे ही सफल हो सकती है अथवा नहीं। जिस समय राष्ट्रसंघ का निर्माण हो रहा था उस समय तीन बड़े देश, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन का वचस्व सभी को मान्य था। अमेरिका

के राष्ट्रपति रुजवेल्ट के जोर दबाव पर चीन को इन बडों में शामिल किया गया तो ब्रिटेन के ऐसे ही दबाव पर फ्रांस को भी इस शिविर में ले लिया गया और इस प्रकार ये पांच बडों "ताकतें" सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बना दी गयी और उन्हें वह अधिकार दे दिया गया जिस नियेधाधिकार कहा जान लया । सारांश यह कि सुरक्षा परिषद वाली सम्पूर्ण व्यवस्था इस विचार पर आधारित की गयी कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से शांति और सुरक्षा के नाम पर जो भी कायवाही हो वह केवल इसलिए न हो कि सदस्य राष्ट्रों के बहुमत में वैसे इच्छा प्रकट की है बल्कि, वह, तभी हो जब महा शक्तियां वा पूरा समर्थन और सहयोग उसे प्राप्त हो क्योंकि वास्तव में तभी वह स्थायी ढंग की व्यवस्था हो सकती है । रुजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल तीनों इसी मत के थे और इसी मत को संयुक्त राष्ट्रसंघ में मायता मिल गयी ।

युद्धोत्तर परिस्थितियों में तत्काल यह विचार बड़ा आकर्षक लगा । इस भारी टूटफूट के बाद वास्तव में दो ही शक्तियां समर्थ शक्तियों के रूप में दिख रही थीं । उनके नेताओं के हृदय सौहार्द और मित्रता के भावों से भरे हुए थे । युद्ध काल में ये नेतागण एक दूसरे के काफी निकट आ चुके थे और सम्बन्धों में पुराना अनजाना पन बहुत कुछ खत्म हो चुका था । अनेक युद्धकालीन नियम तथा युद्धोत्तर योजनाओं के निर्माण में विचार विमर्श के दौरान एक दूसरे के पक्ष को समझन और अपने आप्रहो पर बल न देकर दूसरे पक्ष से समझौता करने के अनेक प्रमाण मिल चुके थे । वस्तुतः सुरक्षा परिषद की कल्पना में तीन राष्ट्रों के नेताओं की सहमति इसका एक ज्वलंत प्रमाण थी । यह विचार वैसे भी व्यावहारिक दृष्टि से उचित मालूम पड़ता था कि सुरक्षा व्यवस्था में उसकी भूमिका मुख्य और निर्णायक होनी चाहिए जिसके पास सुरक्षा और शांति स्थापित करने की शक्ति यदि छोटे राष्ट्र किसी ऐसी कार्यवाही करने का नियम ले लें जो बड़े राष्ट्रों को पसंद नहीं या किसी एक बड़े राष्ट्र को पसंद नहीं तो बिना इन बड़े राष्ट्रों के सहयोग से कायवाही कैसे हो सकती है । चूंकि सुरक्षा परिषद के पास न कोई अपनी सेना है और न शस्त्रास्त्र । किसी भी नियम को अमल में लाने के लिए जिस शस्त्र बल की आवश्यकता होगी वह बड़े राष्ट्रों से ही प्राप्त हो सकता था बड़े राष्ट्रों के विरुद्ध नहीं । इसी तरह यदि बड़े राष्ट्र आपस में लड़ने को उद्यत हो ही जाएं तो बहुसंख्यक होकर भी छोटे राष्ट्र अपने सार संकल्पों के बावजूद इस लड़ाई को रोक कैसे सकते थे । इस प्रकार किसी भी व्यावहारिक दृष्टि से सुरक्षा और शांति की व्यवस्था पर विचार करने पर यही उचित मालूम पड़ता था कि शांति और सुरक्षा को जिम्मेदारी महा शक्तियों की पूरा सहमति और सहयोग पर आधारित की जाय । इसी विचार ने सुरक्षा परिषद के संगठन के रूप में जन्म लिया ।

पर युद्ध समाप्त होने और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के कुछ ही समय बाद

महा शक्तियाँ, विशेषतः सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्धकालीन सोहाद और सहयोग की भावना तेजी से तिरोहित होने लगी और उनके बीच अपने-प्रभाव क्षेत्रों को सगठित करने और बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। ब्रिटेन के कूटनीतियों से प्रेरित टूमेन का अमेरिकी प्रशासन, सोवियत संघ और उसके द्वारा मुक्त किए गये पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों के विरुद्ध लगातार सैनिक और आर्थिक दबाव बनाने की नीति अपनायी गयी और आंग्ल-अमेरिकी गुट के पक्ष में विश्व का शक्ति संतुलन स्थापित करने का अभियान अमेरिकी नेतृत्व में चलाया गया। इसे ही बाद में शीत युद्ध की शुरुआत मानी गयी जिसके अंतर्गत अमेरिकी नेतृत्व में सैनिक और आर्थिक संगठनों का निमाण पश्चिम यूरोप में तेजी से किया जाने लगा। और अंततः भी इस शीत युद्ध में सत्तार को दो गुटों में बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसी विपरीत स्थिति में सुरक्षा परिषद एक विफल परिषद के रूप में प्रकट होने लगी। सुरक्षा परिषद ने जब-जब सोवियत संघ या उनके मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव आता तब तब सोवियत संघ अपने निषेधाधिकार का प्रयोग का प्रयोग कर उस निष्फल कर देता। संयुक्त राष्ट्र संघ में चूँकि आंग्ल-अमेरिकी गुट के सदस्यों का बहुमत था इसलिए सोवियत संघ को अनेक बार इसे निषेधाधिकार का प्रयोग करना पड़ा। सोवियत विरोधी वातावरण में सुरक्षा परिषद केवल एक बहस करने वाली पर बकार परिषद सिद्ध होने लगी और इससे यह विवाद उठने लगा कि निषेधाधिकार की वजह से सारे संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था ही ठप्प पड़ गयी पर बात वास्तव में ऐसी थी नहीं। जैसा हम ऊपर बता चुके हैं सुरक्षा परिषद के मूल में जो विचार था वह यह नहीं था कि सुरक्षा परिषद का अस्तित्व कभी भी किसी बड़ी ताकत के विरुद्ध इस्तेमाल हो, बल्कि, सुरक्षा परिषद की सारी बुनावट की ही ऐसी गयी थी कि वह महा शक्तियों की मदद से न कि उनके विरोध में इस्तेमाल की जाय। वह ऐसे तत्वों से बनी ही नहीं थी और न इस इरादे से बनाई गयी थी कि कभी उसका इस्तेमाल किसी भी एक बड़ी ताकत के खिलाफ हो सके। इसलिए सोवियत संघ के द्वारा बार-बार निषेधाधिकार के इस्तेमाल के खिलाफ जो हो हल्ला मचाया गया वह संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई पूरी समझ की जमा पूँजी के बाहर की बात थी। वस्तुतः जसा ए० ई० इस्टीवेंस ने लिखा था 'निषेधाधिकार हमारी कठिनाइयों का आधार भूत का कारण नहीं है। यह रूस के लोगों के साथ हमारे दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदों का प्रतिबिम्ब मात्र ही है।' यदि हम सच से बचना चाहते हैं तो हमें उन मतभेदों को तय करना चाहिए। केवल मतभेदों की विधि को बदलना पर्याप्त न होगा। मतभेदों के नियम का जन्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं से हुआ है। यदि पाँच महान् राज्य किसी मामले पर राजी नहीं होते तो उनमें से किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग एक बड़े युद्ध का जन्म देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना

इसी सम्भावना से बचने के लिए हुई थी।¹⁸

आर्थिक और सामाजिक परिपद

प्रथम महायुद्ध के बाद जिम अंतर्राष्ट्रीय कहे जाने वाले राष्ट्र सन्ध की स्थापना की गयी थी उमके सविदा म ऐम किसी अग की स्थापना नहीं की गयी थी जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मदद करे। केवल व्यापार में उचित तरीके अपनाये जाए उसका ही जिक्र था पर धीरे धीरे राष्ट्र सन्ध से सम्बन्ध रखने वाले करीबन सात आठ सौ शासकीय व अशासकीय संस्थायें अस्तित्व में आ गई थी। वैसे राष्ट्र सन्ध के जीवन के प्रारम्भिक काल में तीन तकनीकी संगठनों का गठन किया गया था — स्वास्थ्य संगठन। वित्तीय तथा आर्थिक संगठन तथा संचार और यतायात संगठन। स्मरणीय है कि मई 1923 तक स्थायी स्वास्थ्य की योजना ही नहीं बनायी जा सकी। उस वर्ष सितम्बर में राष्ट्र सन्ध की महासभा ने उसका अनुमोदन किया। इसी प्रकार आर्थिक संगठना का हाल रहा।¹⁹ संचार व यतायात के बारे में भी पहला सम्मेलन मार्च 1921 में हुआ और उसके प्रति चार वर्ष बाद उसकी सभायें होती रही। इसी प्रकार राष्ट्र सन्ध ने श्रमिका की समस्याओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सन्ध का गठन किया, अथवा ऐस ही संगठन समय समय पर बने यथा विस्थापित से संबंधित (1921) या 1926 में स्थापित एक बुद्धिजीवी सहयोग संस्थान।

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक कार्य

इस उपयुक्त पृष्ठभूमि में द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सन्ध के तत्वाधान में ही राष्ट्रों के आपसी आर्थिक व सामाजिक प्रगति को व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में चाटर की 61वीं स 72वीं धाराओं में आर्थिक तथा सामाजिक परिपद की व्यवस्था की गयी है। संयुक्त राष्ट्र सन्ध के चाटर का निमाण करने वाले सान फ्रांसिस्को के सम्मेलन के गठन के समय तक कुछ विशेष संस्थायें बन चुकी थी और कुछ प्रम्प्टिट हो रही थी। अतः चाटर में इस तथ्य का भावना दी कि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा देने तथा तत्संबंधी कार्यों को संपादित करने के लिए जो विशिष्ट संस्थायें पल्लवित व अकुरित होगी वे अपने कार्यवाहों के लिए बहुत हद तक स्वतंत्र होगी। 'चाटर' ने इन विशिष्ट संगठनों व उनकी कार्यवाहियों के समन्वय के लिए सन्ध के प्राधिकारों की विशेष रूप से व्याख्या की गई और यह भी प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त सदस्यों की पूर्ति के लिए जहां उपयुक्त एवं आवश्यक होगा सन्ध नई विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रों से वार्ता करेगा। यह भी 'चाटर' में स्पष्ट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति से स्थापित इन विशेषज्ञ

संस्थाओं (विशिष्ट अधिकरणों) के अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की व्याख्या उनके अपने सविदा पत्रों में होगी और वे संघ से संबंधित होंगी। संघ उनकी नीतियों व कार्यवाहियों को समन्वय के करने के लिए सन्तुष्टि करेगा। और इन उत्तरदायित्वों को निभाने का वाकाम महासभा को सौंपा गया और उसकी निगरानी के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में निहित किया गया है।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद

संगठन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का संगठन उन 18 सदस्यों से होता था जो महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से चुने जाते थे इसमें प्रत्येक सदस्य तीन वष के लिए चुना जाता है और उसमें पुनर्निर्वाचन में कोई बाधा नहीं है। ध्यान देने योग्य है कि पांच बड़े राष्ट्रों को न तो इसमें कोई विशेष स्थान है या अधिकार प्राप्त हैं न ही उनकी स्थायी सदस्यता या नियेदाधिकार प्राप्त है। वैसे सदस्यों की योग्यता आदि के बारे में कोई निर्देश नहीं है तथा महासभा भौगोलिक आधार पर समान वितरण का ध्यान रखती है। 1965 में 'चाटर' में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गयी और इस प्रकार बड़े हुए नौ स्थानों का बंटवारा भौगोलिक आधार पर या कर किया गया—7 सीटें एशिया अफ्रीकी देशों के लिए एक लातिनी अमेरिकी देशों को और एक पश्चिम यूरोपीय देशों को दी गयी।

कार्य और अधिकार आर्थिक और सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्वावधान में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा विविध नये कार्यों को सम्पन्न करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। (1) यह परिषद इससे संबंधित विषयों का अध्ययन करती है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। तथा इन विषयों के संबंध में अपनी सन्तुष्टि महासभा को या संघ के सदस्यों या विशिष्ट अधिकरणों को देती है। (2) महासभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों के संबंध में महासभा के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले सविदा या समझौतों के प्राहणों एवं आलेखों को तैयार करती है। (3) महासभा को सन्तुष्टियों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कार्यवाही करती है (4) महासभा के अनुमोदन पर संघ के सदस्यों तथा विशिष्ट अधिकरणों की प्रायना पर सेवाओं का सम्पादन करती है। (5) सुरक्षा परिषद को उसकी प्रायना पर सहायता प्रदान करती है एवं वांछित सूचनाएं देती है। (6) वह मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के पालनाथ एवं उसके प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए सन्तुष्टियां करती है। () वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर संघ द्वारा नियमित निणयों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आमन्त्रित करती है। (8) वह विशिष्ट अधिकरणों की कार्यवाही में परामर्श देकर या उन्हें महासभा और संघ के

सदस्यों को अपनी सस्तुति देकर समर्थन करती है (9) अनुच्छेद 57 के अन्तर्गत वह किसी भी अधिकरण के साथ समझौता कर सकती है तथा उन शर्तों को निर्धारित करती है जिसके अन्तर्गत वे अधिकरण समुक्त राष्ट्र सघ से संबंधित हों। पर इन समझौतों का महासभा की स्वीकृति पाना आवश्यक है। (10) विशिष्ट अधिकरणों से प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है तथा महासभा और अपनी सस्तुतियों को कार्यान्वित करने के लिए उठाये गये नये कदमों के संबंध में उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करती है और उस प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी के साथ महासभा को भेज सकती है (11) अतः, वह ऐसे भी कार्य सम्पादित करती है जो 'चाटर' के अन्तर्गत महासभा उस सौंप देती है या 'चाटर' में कहीं अन्यत्र दिये गये हैं।

परिषद की कार्यवाही परिषद का प्रथम अधिवेशन सदन में 23 जनवरी से 26 फरवरी 1946 तक हुआ था।

परिषद की प्रक्रिया नियमावली में यह व्यवस्था की कि वष में कम से कम तीन अधिवेशन किये जायेंगे पर बाद में इनकी संख्या घटा कर दो कर दी गयी। परिषद के बहुसंख्यक सदस्य महासभा एवं सुरक्षा परिषद की मांग पर अभी भी विशेष अधिवेशन 30 दिन के नोटिस पर आमंत्रित कर सकते हैं। सामान्य अधिवेशन महासभा के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व तथा शरद ऋतु में होता है। अधिवेशन 4 से 6 हफ्ते तक चलते हैं और इनकी बैठकें आम होती हैं अर्थात् जन-साधारण के लिए खुली होती हैं। लेकिन जब भी परिषद चाहे वे बैठकें गुप्त हो सकती हैं।

अधिवेशन के प्रारम्भ में परिषद अपने अध्यक्ष तथा पहले और दूसरे उपाध्यक्ष को चुनती है। आम तौर से अध्यक्ष के पद के लिए छोटे राष्ट्रों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके पुनर्निर्वाचित होने का भी अधिकार है। परिषद अपने नियमों की खुद निर्मात्री है और अध्यक्ष परिषद के नियमों का पालन कराता है। परिषद 'एजेन्डे' या कार्य सूची के लिए समुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य, अथवा महासचिव या विशिष्ट अधिकरण या अन्य संगठन विषय प्रस्तुत करते हैं। परिषद अनेक स्रोतों से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए और सस्तुति करने के लिए सदस्यों की समिति या गठित करती है। अधिवेशनों का अधिक समय इस विभिन्न अधिकरणों और सहयोगी निकायों के प्रतिवेदन सुनने में लग जाता है।

सहायक अथवा 'चाटर' ने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समुचित रूप से कार्य संचालन के लिए आयोग तथा मानव-अधिकार आयोग की स्थापना का अधिकार दिया तदनुसार, परिषद ने निम्नांकित आयोगों की स्थापना की जिनमें कुछ क्षेत्रीय आयोग हैं। पांच विशेष निकायों तथा समय समय पर एतदर्थ समितियों का निर्माण भी किया गया।

आयोग आर्थिक एवं सेवा योजना, (2) यातायात तथा संचार आयोग,

(15 सदस्य) (3) सांख्यिकीय आयोग (15 सदस्य) महिलाओं के अधिकार संबंधी आयोग (18 सदस्य) 'मानव अधिकार आयोग (18 सदस्य), मादक द्रव्य संबंधी आयोग (18 सदस्य), अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार आयोग (18 सदस्य) जनसंख्या आयोग (15 सदस्य) सामाजिक आयोग (18 सदस्य)। जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय आयोग हैं, वे इस प्रकार हैं — (1) यूरोपीय आर्थिक आयोग, (2) एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग, (3) लातिनी अमेरिकी आर्थिक आयोग, (4) मध्य-पूर्व के लिए आयोग, (5) अफ्रीका संबंधी आयोग।

इन आयोगों की सदस्यता 18 से 21 तक होती है और इनका कार्यकाल 2 से 4 वर्ष तक का होता है। 1946 में परिषद ने यह निर्णय लिया था कि इसके सदस्य विशेषज्ञ न होकर राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। इनका चुनाव परिषद करती है—केवल मादक पदार्थ संबंधित आयोग के प्रतिनिधियों को, जो उही राष्ट्रों से आते हैं जो या तो उत्पादक हैं या निर्माता या जहाँ इन वस्तुओं का अवैध व्यापार होता है, सीधे सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

इस परिषद के द्वारा एक उप आयोग भी गठित किया गया है जिसका काम है भेदभाव की रोकथाम करना। इसका नाम ही भेदभाव की रोकथाम एवं अल्प संख्यक सुरक्षा संबंधी आयोग है।

इन आयोगों पर एक दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि ये आयोग तीन प्रकार के हैं (1) कुछ ऐसे हैं जिनका मुख्य कार्य समस्याओं का अध्ययन करना और परिषद के लिए प्राविधिक सूचनाएँ एकत्रित करना है यथा सांख्यिकीय, जनसंख्या, तथा अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार आयोग, (2) कुछ ऐसे आयोग हैं जो सामाजिक समस्याओं के बारे में परामर्श देते हैं और सन्तुष्टियाँ उपस्थित करते हैं यथा मानव अधिकार और महिलाओं के स्तर सम्बन्धी आयोग,

(3) ऐसे आयोग हैं जिनका काम न केवल परामर्श देना है बल्कि, निरीक्षण करना भी है यथा मादक द्रव्य आयोग।

इन आयोगों में परिषद की तरह ही कार्य होता है अर्थात् प्रतिवर्ष अध्ययन, उपाध्यक्ष का चयन होता है और निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। कुछ आयोगों की बैठकें दो वर्ष में एक बार होती हैं यथा मानव अधिकार सहयोग, मादक आयोग इत्यादि।

जहाँ तक क्षेत्रीय आर्थिक आयोगों का सम्बन्ध है, यह ज्ञातव्य है कि यूरोपीय आर्थिक आयोग तथा एशिया और सुदूर पूर्व आयोग का निर्माण सन् 1947 में हुआ था। लातिनी अमेरिकी आयोग सन् 1948 में गठित किया गया था और अफ्रीका आयोग की स्थापना सन् 1958 में की गई थी। इन विभिन्न आर्थिक आयोगों की सदस्यता पर भी एक दृष्टि डालने पर कुछ मनोरंजक तथ्य उभरते हैं यथा सदस्यता इस प्रकार है—

(1) यूरोपीय आर्थिक आयोग—यूरोप के राष्ट्रों के अलावा अमेरिका भी इसका सदस्य है,

(2) एशिया और सुदूर पूर्व में यहाँ के सदस्यों के अलावा (जब चीन भी शामिल हो गया है) आस्ट्रेलिया, यूजीनेड, फ्रांस, नीदरलैंड, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका भी सदस्य हैं।

(3) लातिनी अमेरिकी आयोग में अमेरिकी गोलाबद्ध के सदस्य राष्ट्रों के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड भी सदस्य हैं।

(4) इसी प्रकार अफ्रीकी आयोग में अफ्रीकी सदस्यों के अलावा स्पेन, फ्रांस व ब्रिटेन हैं। पुर्तगाल को 1963 में परिषद द्वारा सदस्यता के अलग कर दिया था और इसी प्रकार जाति भेद की कुत्सित नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका को भी जो इसका सदस्य था निलंबित कर दिया।

यह आयोग भी अपने सहयोगी अगो, समितियों और सम्मेलनों के माध्यम से काम करते हैं।

परिषद ने इसके अलावा पांच स्थायी समितियों की स्थापना की है। ये इस प्रकार हैं—

(1) अराजकीय संगठन समिति यह समिति अराजकीय संगठनों के बारे में सचिवालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं पर विचार कर परिषद को अपनी सिफारिशें देती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं।

(2) उद्योग विकास समिति इसमें परिषद के सभी सदस्यों के अतिरिक्त 12 और सदस्य होते हैं। यह समिति अविकसित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास का बढ़ावा देने के बारे में सलाह देती है। यह औद्योगिकरण की नई विधियाँ नये बाजार और वित्तीय वितरण के बारे में गोप्यता संगठित करती है और सूचनाएँ एकत्रित करती है,

(3) गृह और आयोजन समिति—यह गृह निर्माण योजना तथा ऐसी अन्य सुविधाओं के विषय में अपना प्रतिवेदन सामाजिक आयोग के माध्यम से देती रहती है। इसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी और इसमें 18 सदस्य हैं।

(4) वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परामर्श सम्बन्धी समिति इसका काम भी विकास के वैज्ञानिक एवं प्राविधिक सूचनाओं को एकत्रित एवं वितरित करना है। यह वैज्ञानिक एवं प्राविधिक संस्थाओं के प्रयत्नों को बढ़ावा देती है और उनके कार्यों को समन्वित करती है। अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए भी सहयोग प्रदान करने में यह प्राथमिकता का ध्यान रखती है।

इस का गठन सन 1963 में किया गया था। इनमें 18 सदस्य होते हैं जिन्हें महासचिव न केवल उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चयन करता है बल्कि, भौगोलिक वितरण की समानता का भी ध्यान रखता है,

(5) सम्मेलन के कार्यक्रम सम्बन्धी अंतरिम समिति इसमें चार सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति परिषद का अध्यक्ष करता है। यह सम्मेलन के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए महासचिव से सलाह माँगकर करती रहती है।

इन स्थायी समितियों का अलावा परिषद ने अपने काम को ठीक से चलाने के लिए कुछ निकायों की भी स्थापना की है यथा अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निकाय जो 1965 में स्थापित हुआ। इसमें 10 सदस्य होते हैं जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नामांकित व्यक्तियों में से चुने जाते हैं और 8 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों व अन्य अभिकरणों के द्वारा। मादक द्रव्य औषधि आयोग इसका नीति निर्धारक अंग है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि इसकी स्थापना दिसम्बर 1946 को हुई। इसका उद्देश्य शिशु कल्याण के विविध कार्यों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शोषण के कार्यक्रमों को चलाना है। सन 1964-65 में प्राविधिक माग निवेशन कार्यक्रम के अंतर्गत इसने स्कूलों को सहायता तथा औद्योगिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया था।

सामान्य रूप से निधि के द्वारा साजोसामान और अन्य वस्तुओं के रूप में सहायता दी जाती है। यह निधि अपने आर्थिक कार्यों के अंशुदान तथा व्यक्तियों के व्यक्तिगत दान पर निर्भर करती है।

इस निधि का एक कार्यकारी निदेशक होता है। यह कार्यकारी निदेशक एक 30 सदस्यीय कार्यकारी निकाय की सहायता से निधि का प्रशासन करता है। परिषद इस कार्यकारी निकाय के सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए करती है जिस में वह अंशुदान देने वाले व्यक्तियों तथा सदस्य राष्ट्रों और उनका भौगोलिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखती है।

विस्थापित उच्चायुक्त कार्यालय — द्वितीय महायुद्ध के दौरान और उसके बाद जो अनेक स्थानों में विस्थापितों के रूप में मानव समुद्र में प्रकट हुए उनकी खोज और पुनर्वास के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय विस्थापित उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना सन 1950 में की गई। इस कार्यालय के जिम्मे यह काम सौंपा गया कि यह विस्थापितों की समस्या का कोई स्थायी हल निकाले। एक 25 सदस्यीय कार्यकारी समिति के अधीन यह कार्यालय काम करता है जो जिनेवा स्थिति उच्चायुक्त को उसके कार्य में सहायता देती है। सन 1946 में महासभा ने उच्चायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया है। इसका प्रशासकीय खर्चा तो संयुक्त राष्ट्र चलाता है पर अन्य कार्यों के लिए निजी ऐच्छिक दानों के सहारे काम चलाया जाता है। बांग्ला देश के सिलसिले में उच्चायुक्त प्रिंस सदस्यीय भारत और बांग्ला देश गये थे जहाँ कोई खास सहायता विस्थापितों को नहीं मिली।

संयुक्त राष्ट्र सच विकास कार्यक्रम 1965 में परिषद ने महासभा की सस्तुति पर एक संयुक्त राष्ट्र सघीय विकास कार्यक्रम की भी स्थापना की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राविधिक सहायता तथा 1958 में स्थापित विशेष निधि के कार्यक्रमों को एक में मिला दिया गया था। इसका एक अपना परामर्शदात्री निकाय है और एक 36 सदस्यों की शासकीय परिषद जिसमें 19 विकसित देशों के और 17 विकासशील देशों के प्रतिनिधि हैं। इन निकाय में उन विशिष्ट अभिकरणों के प्रधान भी होते हैं जिनका इस कार्यक्रम में सम्बन्ध है। सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उसका नीति निर्देशन करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं।

विशिष्ट अभिकरण आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य उसके द्वारा स्थापित विशिष्ट अभिकरणों के जरिए होता है। निम्नांकित विशिष्ट एजेंसियों का संयुक्त राष्ट्रसच से सम्बन्ध हुआ है। ये अभिकरण उस प्रकार के संगठन हैं जिनकी स्थापना अन्त शासकीय अनुबन्धों के द्वारा हुई है। ये अनुबन्ध महासभा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं सम्बन्ध संस्थाओं के द्वारा अलग अलग स्वीकार किए जाते हैं। तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इन कार्यक्रमों और नीतियों का समन्वय करती रहती है। जैसा ऊपर बताया चुक है ये अभिकरण संयुक्त राष्ट्रसच की विस्तृत प्राविधिक सहायता योजना में भाग लते हैं और परिषद की प्राविधिक सहायता परिषद में इनकी प्रतिनिधित्व मिला है। इन की संख्या 12 है

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण,
- (3) विश्व डाक सच,
- (4) विश्व स्वास्थ्य संगठन,
- (5) खाद्य एवं कृषि संगठन,
- (6) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन,
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
- (8) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम
- (9) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक,
- (10) विश्व ऋतु विज्ञान संगठन
- (11) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार सच,
- (12) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन।

इसके अलावा एक अन्त शासकीय सामुद्रिक परामर्शदाता संगठन की स्थापना भी की गई है और जैसा बताया जा चुका है—एक मानव अधिकार सहयोग गुरु से ही काम कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्गठन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ से सम्बन्धित यह अभिकरण वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र सङ्घ से कहीं अधिक पुराना सङ्गठन है। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गयी थी और इसे तब राष्ट्र सङ्घ अर्थात् 'लीग' ऑफ नेशन्स से जोड़ दिया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन के सबन्ध में यह ज्ञातव्य है कि यह सङ्गठन प्रथम महायुद्ध के पूर्व यूरोप के पूँजीवादी देशों की सत्ताधारियों के द्वारा समाजवादी एवं श्रमिक आन्दोलन के बीच हुए निरन्तर भीषण अतद्वन्द्व को रोकने के लिए किये गये पूँजीवादियों एवं सशोधनवादियों के युद्ध पूर्व के प्रयासों की परिणति इस रूप में हुई। श्रमिकों के निम्न शोषण पर सुधारवाद का लेबिल चिपकाने के प्रयत्न श्रमिकों की समस्याओं से सम्बन्धित सम्मेलनों के रूप में हुए यथा 1890 में बर्लिन में फिर 1906 में बर्न में सम्मेलन हुए। इसी प्रकार 1905 और 1913 में प्राविधिक सम्मेलन में भी कुछ समझौतों के प्रारूप तैयार किये। 1916 में लस्डस के श्रमिक सङ्घों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। व 1917 में एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्घ काग्रेस बर्न में बुलाई गई और। 1918 के एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम तथा समाजवादी सम्मेलन बुलाया गया जिसके ओर स सरकारों की अपील भेजी गई कि वे शांति संधियों में ऐसी व्यवस्था करें जिससे श्रमिक वर्ग को भी अपने सङ्गठन बनाने तथा लोक कल्याण के कार्य जैसे सामाजिक बीमा, उचित काम के घंटे स्वास्थ्य रक्षा व अन्य ऐसे ही मजदूरों की दशा सुधारने वाले प्रयास किये जा सकें। रूस में हुई अपूर्व सोवियत क्रांति ने जिसकी चिनगारियों यूरोप भर में फैल गई थी, इन श्रमिक सुधारकों को ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन की जल्दी से जल्दी स्थापित करने के लिए बाध्य किया ताकि, इस सुधारवादी मुखौटे को ओढ़कर वे सोवियत क्रांति चिनगारियों में पूँजीवाद के लडखलहाते सङ्गठन को नष्ट होने से रोक सकें तदनुसार पेरिस के शांति सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विधान पर एक आयोग बनाया जिसने दो माह के अन्दर इस श्रमिक सङ्घ के विधान को बना दिया जो बर्साय संधि के 13वें भाग के रूप में सम्मिलित हो गया। फलस्वरूप संधि की धारा 392 में यह प्रबन्ध किया गया कि एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय राष्ट्र सङ्घ के मुख्यालय पर राष्ट्र सङ्घ के एक अंग के रूप में स्थापित किया जाय। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्घ से सम्बन्धित पर एक स्वायत्तता पूर्ण अंग के रूप में स्थापित किया गया।

यह श्रम सङ्घ 1921 से 1939 तक जेनेवा में कार्य करता रहा। फिर यूरोप में युद्ध की आशंका के निरन्तर बढ़ने पर सन 1940 में इसका कार्यालय वेनिस के मानट्रियल शहर में भेज दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद सन 1944 में फिलाडेल्फिया में इसका एक सामान्य सम्मेलन बुलाया गया जिसमें इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों की घोषणा की गई जिसे फिलाडेल्फिया 'चाटर' भी कहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया गया था कि 'चाटर'

श्रम संगठन को ऐसे अभिकरण के रूप में जगह दी जाय जो श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का मुख्यतः सुधारने के लिए उत्तरदायी संस्था है। सम्मेलन में इसके स्वायत्त रूप को बनाय रखने की सिफारिश की गई। परिवर्तित संविधान में संगठन को समुक्त राष्ट्र संध में सम्मिलित किया गया और इसके सम्बन्ध में राज्यों के दायित्वों का विस्तार किया गया। इस प्रकार सिद्धांत रूप में यह अभिकरण प्रायः उसी रूप में है जिस रूप में वह 1919 में स्थापित किया गया था। पर यह ज्ञातव्य है कि यह समुक्त राष्ट्र संध से जोड़ा जाने वाला पहला अभिकरण है। (14 दिसम्बर 1946) पहले की अपेक्षा व्यवहार में इसने कामकाज काफी बदल और बढ़ गया है।

इस अभिकरण के निम्नांकित सिद्धांत बताये जाते हैं

- 1 श्रम कोई नया विषय की वस्तु नहीं है अर्थात् यह सिद्धांत माना गया कि वस्तुओं का उत्पादन एक सामाजिक कृतित्व है,
- 2 अभाव और दरिद्रता सभी देशों की समृद्धि के लिए बाधक है,
- 3 अतः अभाव और दरिद्रता को सर्वत्र दूर करने के लिए सभी को कटिबद्ध होना चाहिए,
- 4 पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगपतियों, श्रमिकों व सरकारी प्रतिनिधियों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर इसे लोकतांत्रिक ढंग में खुले विचार विनिमय के आधार पर नय करना चाहिए।

उद्देश्य इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं

- 1 श्रमिकों के लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था और उनके जीवन-यापन के स्तर को ऊँचा किया जाय,
- 2 श्रमिकों की स्वच्छतापूर्वक ऐसे कामों में लगाना जहाँ उनके श्रम का उचित उपयोग हो,
- 3 श्रमिकों के प्रशिक्षण, स्थानांतरण और संस्थापन की पूरी गारंटी दिलवाना,
- 4 काम के घट्टे, मजदूरी और काम के सम्बन्ध में दूसरी शर्तों की समुचित व्यवस्था करना ताकि, उन्हें अपना उचित योगदान का अंश प्राप्त हो सके। और न्यूनतम जीवनोपयोगी वतन मिल सके,
- 5 सामूहिक सौदबाजी के अधिकार को मायता मिल और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने तथा सामाजिक और आर्थिक नीतियों में मालिकों और मजदूरों का पारस्परिक सहयोग मिल सके,
- 6 प्रत्येक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा रोगी और घायल श्रमिकों की चिकित्सा की व्यवस्था करना,
- 7 बाल विवास तथा शिशु और माता की सुरक्षा की व्यवस्था करना,
- 8 श्रमिकों को पोषणदायी भोजन आवास, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के साधनों

को उपलब्ध कराना,

- 9 सच इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार को तकनीकी सहायता देता है तथा श्रमिक समस्याओं के बारे में पत्रिकाएँ निकाले, औद्योगिक एवं मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन कर और प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

संगठन अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सच के तीन प्रमुख अंग हैं

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन,
- (2) शासन निकाय तथा
- (3) श्रम कार्यालय।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यह सच का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसका संगठन अपने ढंग से होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 4 प्रतिनिधि भेजते हैं जिसमें सरकारी की ओर से दो प्रतिनिधि होते हैं राज्य के उद्योगपतियों और मालिकों की ओर से एक प्रतिनिधि होता है और श्रमिक संगठनों की ओर से एक प्रतिनिधि। हमारे देश के मजदूर प्रतिनिधियों में राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सत्ताधारी दल की राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। प्रत्येक सदस्य के साथ दो परामशदाता भी भेजे जाते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य कार्य ससमयों की स्थापना करना है (कनवन्शन्स) और सन्सुतियाँ भेजना हैं।

(2) शासन निकाय यह एक कार्यकारी परिपद है जिसमें 48 सदस्य होते हैं। जिसमें 24 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 12 उद्योगपतियाँ और मिल मालिकों के तथा 12 श्रमिक सच के प्रतिनिधि होते हैं। 24 सरकारी प्रतिनिधियों में 12 ऐसे राज्यों के प्रतिनिधि स्थायी सदस्यों के रूप में होते हैं जो औद्योगिक महत्त्व के माने गये हैं। ये राज्य हैं अमेरिका, सोवियत सच, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान इटली, चीन और भारत। ये तीन बच क लिए चुने जाते हैं। (अस्थायी सदस्य)।

यह निकाय महानिदेशक की नियुक्ति करती है तथा अनेक समितियाँ व आयोगों तथा श्रम कार्यालय के कामों की देखभाल करती है तथा श्रम सम्मेलन के लिए कार्य सूची बनाती है तथा उसकी बैठकें बुलाती है। आय व्यय का ब्योरा तैयार करती है तथा सदस्यों का अशदान निर्धारित करती है, व समस्याओं के अध्ययनाथ समितियाँ इत्यादि गठित करती है।

(3) श्रम कार्यालय पहले का ही तरह श्रम संगठन का मुख्य कार्यालय जिनेवा में है। इसकी शाखाएँ यूयाक, बेंगलूर, मध्य पूर्व स्ताम्बूल मैक्सिको, लीमा (पेरू) तथा यूरोप और एशिया के अन्य देशों के स्थित हैं। जैसा बताया चुके हैं इसका प्रधान प्रशासक महानिदेशक होता है। वही इसके कार्य व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है। वह कार्य सूची के विषयों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों को सदस्यों को भेजता है। वह सन्सुतियों और ससमयों में अध्यक्ष के साथ-साथ हस्ताक्षर करता है। वह शासन निकाय द्वारा नियुक्त समितियों एवं आयोगों के प्रतिवेदनों

को शासन नियंत्रण की भेजता रहता है। इस कार्यक्षेत्र का काम श्रम सम्बंधी समस्याओं के लिए सूचनाएँ इकट्ठा करना उन्हें वितरित करना और उन पर विचार बरधा कर उन्हें ससमय निर्माण में मदद करना है।

सदस्यता में कुछ महत्वपूर्ण ससमय कोई भी राज्य इस संधि का सदस्य हो सकता है। वे सार राज्य जो एक नवम्बर 1945 को इससे सदस्य थे इसमें शामिल कर लिए गये। इसके अलावा 2/3 बहुमत से तथा 2/3 सरकारों के प्रतिनिधियों के बहुमत से कोई भी राज्य इसका सदस्य स्वीकार किया जा सकता है। इसमें यह जरूरी नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संधि का सदस्य ही इसका सदस्य बन सके यथा संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्यता पान के पहले ही पश्चिम जर्मनी को इसकी स्थायी सदस्यता प्राप्त थी। इसी प्रकार कोई भी सदस्य दो वर्ष की नोटिस देकर इससे अलग हो सकता है। 1964 में सम्मेलन ने यह सलाह स्वीकार किया कि कोई भी ऐसा सदस्य राष्ट्र जो जाति भेद की नीति अपनाये, इसकी सदस्यता से निलंबित या रिक्तकामित किया जा सकता है। इस पर दक्षिण अफ्रीका ने सदस्यता छोड़नी चाही परन्तु महानिदेशक ने इस दो वर्षे वाली शर्त के आधार पर उसे अलग नहीं किया। सन् 1961 में श्रीमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है तथा मार्च 1963 में श्रीमिकों को विदेश प्राविधिक और औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गयी। बहुत से ऐसे क्षेत्रीय परामशदात्री 'मिशन' स्थापित किये गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संहिता सम्बंधी लगभग 150 ससमयों अर्थात् बनवन शान्त अपनाये जा चुके हैं। और लगभग इतनी ही सन्तुष्टियाँ (रिकमेन्डेशन) श्रम सम्मेलनों ने भेज रखी हैं। इन सभी को लगभग 1500 सन्तुष्टियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। अब तक अपनाये गये कुछ महत्वपूर्ण 'कनवे' श'स' इस प्रकार रहे हैं

- (1) 1919 उद्योगों के कार्यों के घटे सम्बंधी शक्ति में महिलाओं से काम चलाने के बारे में तथा युवकों से भी ऐसा काम न लेने के बारे में,
- (2) 1921 सामूहिक व्यापार में लगे युवकों की डॉक्टरी जांच के बारे में,
- (3) 1927 बेगार सम्बंधी, 1917 उद्योगों में बीमारी बीमा नियोजन
- (4) 1933 बुढ़ावस्था पेणन,
- (5) 1934 बेरोजगारी सम्बंधी,
- (6) 1946 समुद्री व्यापार में लगे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना,
- (7) 1949 श्रम निरिक्षण योजना सेवा सविदा समिति,
- (8) 1948 संगठन निर्माण की स्वतंत्रता और संगठन आयोजित करने सुरक्षा,
- (9) 1949 सावजनिक सविदा में श्रम सम्बंधी प्रावधानों को स्थान देना,

(10) 1952 बेगार सम्बन्धी 'वनवेशन'।

इसी प्रकार सम्मेलन ने सौ से भी अधिक सस्तुतियां स्वीकार की हैं जो सेवा दुष्टता, मालिका द्वारा सेवाओं से हटाये जाने का प्रावधान, औद्योगिक दुष्टताओं को रोकना एवं श्रम निरीक्षण आदि प्रावधान सम्बन्धी हैं।

ये सस्तुतियां 2/3 बहुमत से स्वीकृत होती हैं। इसके बाद सम्मेलन के अध्यक्ष तथा महानिर्देशक उस पर हस्ताक्षर करने हैं फिर ये सदस्य राष्ट्रों को उनकी सांविधानिक प्रक्रिया द्वारा सत्पुष्ट होने के लिए भेज दिये जाते हैं। सत्पुष्ट हो जाने पर राज्यों का यह वक्तव्य हो जाता है कि वे उनको कार्यान्वित करें। धारा 26 के अन्तर्गत किसी ससमय को सत्पुष्ट करने वाला राष्ट्र यदि उसका पालन सतोष जनक रूप से नहीं करता है तो इस सगठन के किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह इसकी शिकायत श्रम कार्यालय का भेजे जहां शासन निकाय कामवाही करता है और आवश्यकता पड़ती है तो जांच के लिए आयोग को भेज सकता है। यथा सन 1962 में घाना ने पुर्तगाल के विरुद्ध शिकायत की थी कि वह बेगार को समाप्त करने वाले ससमय का पालन नहीं कर रहा था। दूसरे में पुर्तगाल ने ऐसी ही शिकायत लीबिया के बारे में धारा 24 के अन्तर्गत उद्योगपति या श्रमिक के सगठन शासन निकाय को सरकार के विरुद्ध शिकायत के रूप में भेज सकते हैं कि वे सत्पुष्ट किये जाने के बाद भी ससमयों का पालन नहीं कर रहे हैं।

इस प्रावधान का भी सात बार उपयोग किया गया है। श्रम सगठन की एक समिति है जो प्रतिवेदनो पर विचार करती है और अपना मत साधारण सम्मेलन को भेजती है और जो सदस्य राष्ट्रों से सस्तुतियां व ससमयों पर कायवाही न करने के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है। सन 1964 में समिति ने 63 राज्यों से इस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा था जबकि एक वर्ष पूर्व ऐसे 73 मामले उनके सामने आए। अब तक लगभग 300 शिकायतें सुनी जा चुकी हैं। इस प्रकार श्रम सगठन भरसक सघ के सदस्यों की दिशा में की जा रही उपेक्षा, गैरजिम्मेदारी व दुर्व्यवहार को रोकने या कम करने के प्रयत्न में लगा ही रहता है।

सारांश यह है कि पूँजीवादी दायरे के अंदर प्रारम्भिक वर्षों में पुराने साम्राज्यवादियों व तथाकथित लोकतन्त्रवादियों के नेतृत्व में यह सस्था श्रमिकों की दशा सुधारने में, यत्किंचित् योगदान करती रही। जब से एशिया अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र इस के सदस्य बने हैं तब से इसकी गति में कुछ तेजी आ गई और आजकल की परिस्थितियों में सोवियत सघ तथा उस के समर्थक राष्ट्रों की ओर से होने वाला विरोध और उपेक्षा बहुत कुछ कम हो गई है। जैसे राष्ट्रीय सीमा के अंदर वैसे ही इस अखाड़े में भी पूँजीपति वर्ग व सशोषणवादी मजदूर नेतृत्व एवं समझौतावादी नीति अपना कर इसका महत्व बढ़ाते रहे हैं।

इस सस्था का मुख्य उद्देश्य अणु शक्ति के शांति पूण वायों के लिए उपयोग को बढ़ावा देना है, उस की खोज करना है तथा इसका समस्त ससार की शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए विस्तृत प्रयोग करना है। इस सस्था के दो अंग हैं ?

- (1) साधारण सभा,
- (2) इसका अधिसामी निकाय।

संगठन इसके तीन प्रमुख अंग हैं—

- (1) विश्व डाक परिषद या सघ,
- (2) कायकारिणी या सम्पक समिति,
- (3) अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो।

कायकारिणी एवं सम्पक समिति में 20 सदस्य होते हैं जो विश्व डाक परिषद द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। फरवरी 1964 को इस की सदस्य सख्या 27 कर दी गई।

अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो इस प्रकार प्रधान महानिदेशक होता है तथा वह स्वयं सरकार की दलरेख में काम करता है। वह डाक सनसमयों के अंतर्गत विवादा के सुलझाने में मध्यस्थता करता है। 1964 में इस सघ की सदस्य सरया 126 थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रसंघ के कायकाल में रोगों विशेष कर महामारियों व छुआछूत के रोगों की रोकथाम के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीयस्वीय स्वास्थ्य सस्थान की स्थापना हुई थी। इसी क्रम की द्वितीय महायुद्ध के बाद सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में सुविस्तृत और सुसंगठित करने का विचार किया गया और फलस्वरूप एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। सामाजिक और आर्थिक परिपद ने एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन बुलाकर (जिस में 61 सदस्यों ने भाग लिया) इस संगठन के समिधान्तर्गत स्थापना कर दी गयी और 10 जुलाई, 1948 का निर्माण किया और 7 अप्रैल, 1948 को इस संयुक्त राष्ट्रसंघ से जोड़ दिया गया।

संगठन इस सस्था का काय तीन अंगों की सहायता से चलाया जाता है—

- 1 विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन,
- 2 सम्मेलन द्वारा चुने गये 18 व्यक्तियों का एक कार्यकारी निकाय, तथा
- 3 सचिवालय।

इस संगठन के अंतर्गत अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रादेशिक संगठन भी बनाये गये हैं। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में है जिसका प्रमुख महानिर्देशक होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य दुनिया की और मानव मात्र का शारीरिक, मानसिक और सामाजिकदृष्टि से स्वास्थ्य उपलब्ध करना है और व्याधियां से

भुक्त रखना है। इस उद्देश्य से, संस्था निम्नांकित कार्य करती है—

- (1) स्वास्थ्य के क्षेत्र में अथ समूहों राज्यों के स्वास्थ्य संगठनों तथा चिकित्सक समूहों से सहयोग प्राप्त करना।
- (2) महामारियों व बीमारियों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को संगठित करना
- (3) स्थानीय वातावरण के अनुकूल स्वास्थ्य, भोजन, आवास एवं स्वच्छता की दशाओं को बढ़ावा देना,
- (4) शिशुओं एवं माताओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यों को प्रोत्साहित करना,
- (5) इस संस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसंधान को दुनिया के अनेक भागों में अनुसंधान शालाओं को स्थापित कर बढ़ाया है और इस में कृसर और हृदय रोग पर विशेष बल दिया जा रहा है,
- (6) खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के सम्बन्ध में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने में प्रयत्नशील है।
- (7) इसी प्रकार चिकित्सा सम्बन्धी मानदण्ड स्थापित करने में प्रयत्नशील है,
- (8) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान कर रही है,
- (9) सदस्यों के अनुरोध पर उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयत्न करती है।

प्रतिवर्ष इसका एक बार नियमित अधिवेशन होता है। 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में एक नई दिल्ली में स्थिति है। (दक्षिण पूर्व एशिया का)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को यद्यपि बड़े और समथ देशों का हार्दिक सहयोग नहीं मिला है तथापि इसने विकासशील देशों के हित में कुछ उल्लेखनीय कार्य किये हैं यथा छुआछूत से फैलने वाली बीमारियाँ और महामारियों की रोकथाम में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है यथा मलेरिया उन्मूलन के अन्तर्गत इसने भारत, श्री लंका, इत्रायल, जाह्न, लेबनान, सीरिया, यूनान इत्यादि 40 देशों में कार्य किया है और अनेक जगहों में इस उल्लेखनीय सफलता मिली है। इसी प्रकार इफ़ुलजा के लिए लंदन, एटलाटा, जार्जिया में इस संगठन के द्वारा वे 'द अच्छा काम कर रहे हैं। क्षय या टी बी रोग के निवारण के लिए इस संगठन ने अनेक देशों की बड़ी सहायता की है। अकेले भारत में ही 55 क्षय निरोधक दवाओं की प्रशिक्षण देकर तथा इसकी सहायता से भारत के राष्ट्रीय क्षय संस्थान से लगभग 600 डॉक्टर प्रशिक्षण पा चुके हैं। 'ट्रकोमा' के लिए टीके के अनुसंधान तथा अथ औषधियों के अनुसंधान में यह संगठन पर्याप्त रुचि लेता है और कार्य करता है। सन 1964 में इसका 118 सदस्य थे (सोवियत संघ, बुल्गारिया, रूमानिया और हंगरी इसके

सहायक सदस्य के रूप में ही बने रहे) ।

साथ और कृषि सगठन साथ और कृषि सगठन की स्थापना का बीजानु-
'एटसाटिक' घोषणा पत्र में प्रकट होता है। वस्तुतः इस सगठन के निर्माण के
प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है। जब आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि ने इस तरह के एक
साथ और कृषि क्षेत्र के प्राविधिक आयोग की स्थापना का सुझाव अक्टूबर 1942
में ब्रिटेन, अमेरिका व केनडा को दिया। रजिस्ट्रार के द्वारा इस सुझाव में काफी
रुचि ली गई। और स्वयं ने एक दीयकालीन योजना प्रस्तुत की। तत्नुसार वर्ष
1943 में साथ और कृषि पर एक सम्मेलन अमेरिका में हुआ और इस सम्मेलन
ने ऐसे एक सगठन के विधान के निर्माण के लिए एक आयोग की स्थापना के
सिफारिश की जो जुलाई में बना। उसके आधार पर इस सगठन का निर्माण 16
अक्टूबर, 1945 को हुआ। यह संस्थान राष्ट्रसंघ के एक विशिष्ट अभिवरण के
रूप में 14 दिसम्बर, 1943 को जोड़ दिया गया।

साथ और कृषि सगठन के तीन प्रमुख अंग हैं—

- (1) सभा अथवा सम्मेलन
- (2) परिषद
- (3) सचिवालय।

उद्देश्य इस सगठन के निम्नांकित उद्देश्य बताये गये हैं

- (1) साधनों वनस्पति वन सम्पत्ति तथा मछलियों के उत्पादन में अभि-
वृद्धि करना और इनके त्रय विक्रय का प्रबन्ध करना।
- (2) जीवन यापन एवं आहार के स्तर को बढ़ाने तथा उसके सम्बन्ध में
वैज्ञानिक प्राविधिक सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर शोध करना।
- (3) अपने कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देना।
- (4) प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करना।
- (5) भूमि धारण व्यवस्था की विभिन्न पद्धतियों का सुधार करना एवं
कृषि के लिए साख की व्यवस्था करना।
- (6) वितरण की उचित व्यवस्था में सहायता करना।

कार्य

इस सगठन के निम्न कार्य हैं

- (1) भूमि तथा जल के स्रोतों के विकास में सहायता प्रदान करना।
- (2) उत्पादक वस्तुओं के लिए सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए
प्रोत्साहित करना।
- (3) साथ एवं कृषि सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित करना एवं उन्हें
प्रकाशित करना।

(4) प्रतिवर्ष विश्व खाद्यान्नों का सर्वेक्षण करना ।

(5) वृषि सम्बन्धी समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करना ।

(6) खाद्य एवं वृषि की प्रत्येक समस्या पर देशों को प्राविधिक सहायता एवं परामर्श देना ।

(7) अल्पविकसित देशों की राष्ट्रीय विकास योजनाओं में सहायता देने के लिए विशेषज्ञ भेजना ।

(8) भूमि रक्षा, पशुओं की बीमारी पर नियंत्रण एवं मछली पालन आदि समस्याओं का विशेष अध्ययन करना ।

(9) सदस्य राष्ट्रों या अन्य राष्ट्रों के अनुरोध पर प्राविधिक सहायता प्रदान करना ।

(10) नये ढंग के पौधों को एक देश से दूसरे देश में भेजने की प्रोत्साहित करना ।

(11) उपयुक्त पद्धतियों का समस्त संचार में प्रचार करना ।

संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)

यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का सर्वाधिक उपयोगी और लोकप्रिय संगठन बन गया है। इस संगठन के त्रिया कलाप दुनिया के प्रायः सभी देशों के सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्य क्रमों में योगदान देते आ रहे हैं। इस संगठन की स्थापना 4 नवम्बर 1946 को लंदन में हुए नवम्बर 1945 के सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किये विधान के अनुसार की गई और इसे 14 दिसम्बर 1946 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ जोड़ दिया गया। शुरू शुरू में इसके लगभग 20 सदस्य थे लेकिन आज यह सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था सिद्ध हुई है और इसकी सदस्य संख्या 130 में भी अधिक पहुँच गयी है।

उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के 'चाटर' में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना दुनिया के सभी लोगों को मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये। इसके संविधान में तदनुसार इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, एवं संस्कृति के माध्यम से न्याय, कानून के शासन, मौलिक अधिकार एवं स्वतन्त्रताओं के प्रति सभी लोगों में जाति, धर्म और लिंग के भेद भाव व बिना आदर की भावना उपजाना है। इसके संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि 'युद्ध मनुष्य के अस्तित्व में जनम लेता है। इसलिए शांति को सुरक्षित रखने की आधार शिलाएँ भी मनुष्य के अस्तित्व में बनाई जानी चाहिए।' अतः यह संस्था इसी उद्देश्य को लेकर अपने अस्तित्व को न्याय-संगत ठहराती है। यह संस्था शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के

बीच में जोल बढ़ाने इस प्रकार शांति और सुरक्षा की स्थायी नींव डालने का प्रयत्न करती है।

संगठन यह तीन अग्रा वाली संस्था है जो क्रमशः

- (1) साधारण सभा या सामान्य सम्मेलन,
- (2) प्रशासन निकाय या कार्यकारी तथा
- (3) सचिवालय।

सामान्य सभा या सम्मेलन में प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रतिनिधि रहता है।

इसकी बैठक साल में एक बार होती है। यह सभ की नीति निर्धारित करती है, उसका बजट स्वीकार करती है तथा प्रशासन निकाय का निर्धारण करती है। प्रशासन निकाय में सम्मेलन के द्वारा चुने गये 24 सदस्य होते हैं और इस चुनाव में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे ही व्यक्ति चुने जाय जो शिक्षा, समाज सेवा विज्ञान एवं कला में निपुण हों और उन्हें इस क्षेत्र में सभाओं का अनुभव हो और दक्षता प्राप्त हो ताकि वे यूनेस्को के कामों का ठीक से कर सके पर इसका साथ ही विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सांस्कृतिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी हो। प्रधान को छोड़कर किसी राष्ट्र के दो सदस्य निकाय में नहीं रहे जा सकते। निकाय यूनेस्को के कार्यक्रमों को लागू करती है और वर्ष में इसकी दो बार बैठकें होती हैं। इसका एक सचिवालय है जो पेरिस में स्थित है और जिसकी अध्यक्षता एक महासचिव करता है।

कार्यक्रम यह संस्था अपने समूचे कार्यक्रम को छ भागों में बांट कर चलाती है। वे छ प्रकार के कार्य इस प्रकार हैं

- (1) शिक्षा (2) प्राकृतिक विज्ञान (3) सामाजिक विज्ञान (4) सांस्कृतिक
- कार्य (5) सामूहिक शिक्षा एवं प्रचार के साधन (6) प्राविधिक सहायता।

शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में 'यू०एन०ओ०' ने अपना उद्देश्य शिक्षा का प्रसार उसका उद्देश्य और विश्व समाज के निर्माण व विश्व नागरिकता को बढ़ाने वाली शिक्षा। इसमें 'यूनेस्को' ने साक्षरता और प्रौढ शिक्षा पर बल दिया है। अनेक कार्यक्रम अपनाये गये हैं यथा 1964 में 8 चुने हुए दशों में शिक्षा-प्रचार के लिए 'पाइलट प्रोजेक्ट' तैयार किये गये तथा दो क्षेत्रीय सम्मेलन किये गये (एक आरबिड जन, दूसरा बाहिरा में) प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में सेनेगल में ऐसा ही पाइलट प्रोजेक्ट चलाया गया। अफ्रीका में माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्था स्थापित की गई तथा एक शोध केन्द्र अकारा में खोला गया। पाठ्य पुस्तकों के बारे में केम्ब्रिज में एक केन्द्र स्थापित किया गया तथा सूडान में विद्यालय भवन का निर्माण केन्द्र खोला गया। इसी प्रकार 66 विशेषज्ञों का एक दल बागो भेजा गया। शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना बैंगल तथा फिलीपाइन्स में खोला गया जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। यह स्मरणीय है कि सामू

हिक शिक्षा तथा अनिवार्य नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था पर 'यूनेस्को' ने बड़ा बल दिया और अपना मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उन सारी प्रवृत्तियों से लड़ना और उन्हें दूर करना निश्चित किया है जो युद्धों को भड़काती हैं या पनपाती हैं यथा जातीय द्वेष और साम्प्रदायिक विष बमन। लेकिन यह ज्ञातव्य है कि युद्धों का मूल कारण साम्राज्यवाद और पूँजीवाद का शोषण इसके सौम्य जकड़ से बाहर की बात है।

प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान इस क्षेत्र में भी 'यूनेस्को' ने उल्लेखनीय कार्य किया और मुख्यतः अपना ध्यान विकासशील देशों की समस्याओं पर लगाया है यथा सन् 1963 में विकासशील देशों के विज्ञान और प्राविधिक ज्ञान के उपयोग के लिए जिनेवा में एक सम्मेलन सम्पन्न किया गया और दो विभागों की स्थापना की गई। इसी प्रकार सागोस में एक बैठक में यह योजना बनाई गई कि 15 वर्षों में वैज्ञानिकों की संख्या अफ्रीका में 15 गुनी की जाय। इसी प्रकार पेरिस की एक बैठक में ज्वालामुखी एवं भूकम्प आभयत्रण सम्बन्धी योजना बनाई तथा विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्रों का नक्शा बनाने प्रतिस्थापित शोध-शालाओं की और सबल बनाने एवं भूकम्पीय क्षेत्रों में ऐसे भवन-निर्माण करने जिन पर उनका असर न हो। इस सम्बन्ध के शोध की योजना स्वीकार की।

सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 18 राष्ट्रों के विशेषज्ञों का एक सम्मेलन मास्को में जातिवाद के प्रकार तथा जाति भेदों पर शरीर विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए सम्पन्न किया गया (सन् 1964 में) इसी प्रकार यह संस्था विचार गोष्ठियों को आयोजित करती है और साहित्य प्रकाशित करती है। और एक अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक परिषद का सन् 1964 में गठन किया जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक सम्पत्ति की रक्षा करना है यह संस्था एक अन्तर्राष्ट्रीय समाज, विज्ञान बुलेटिन निकालती है।

सांस्कृतिक एवं सामूहिक शिक्षा व प्राविधिक सहायता के क्षेत्र में ही इसने सराहनीय कार्य किया है। सामाजिक संचार के साधनों व विकास और इनकी स्थापना के लिए प्रशिक्षण फेलोशिप तथा क्षेत्रीय गोष्ठियाँ आयोजित कर सहायता देकर अनेक देशों में रेडियो, टेलिविजन, प्रेस सर्विस, समाचार-पत्र सेवा तथा सूचना सेवाओं आदि की स्थापना में यह सहायता देती रहती है और इस सम्बन्ध की गोष्ठियाँ आयोजित करती रहती हैं यथा रेडियो पत्रकारिता की गोष्ठी सन् 1964 में फ्रांस में की गई तथा 10 सप्ताह का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया जिसमें 12 देशों के 84 विचारियों ने भाग लिया।

इस प्रकार यह समूह शिक्षा विज्ञान व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व सहायता के कार्य क्रमादि का कार्य निर्वहण कर महत्वपूर्ण योगदान करता है। लेकिन यह ज्ञातव्य है कि 'यूनेस्को' की गतिविधियाँ विकासशील देशों की भी

प्रभावित करने वाली गतिविधियाँ हैं और चाहे वह तकनीकी सहायता हो व अथ सांस्कृतिक व सामाजिक वायव्य सन्ध ही विवसित और विकासशील देशों के बीच दाता और गगता का सम्बन्ध है ।

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय सगठन द्वितीय महायुद्ध के दौरान पूजीवाद व साम्राज्यवाद के सगठक नेता अमेरिका ब्रिटेन को राजनीतिक नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था व सम्मन्धों को अपने अनुकूल बनाय रखने के लिए सर्वाधिक रूप से चिंतित था । उन्हें अपनी दृष्टि से सुरक्षा और शांति की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण रूप दुनिया की पूजीवादी व्यवस्था और उपनिवेशवादी व्यवस्था को अपने अधीन रखना ही था क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ युद्ध में सहयोग कर रहे थे इसलिए वे युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय गठन में सोवियत संघ के सहयोग की अपेक्षा रखते थे । फलस्वरूप वे ऐसे आर्थिक सन्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील रह जो यथायथ वे उनकी पूजीवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था को यथावत बनाये रख कर भी अपने स्वरूप में लोक-कल्याणकारी लगे तदनुसार 3-4 ऐसे अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के रूप में बनाय गये और वे संयुक्त राष्ट्रसंघ से जोड़ दिय गये । ऐसे सगठनों में प्रमुख निम्नांकित हैं

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सगठन,
- (3) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम,
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस कोष की स्थापना 27 सितम्बर, 1945 (दिसम्बर ?) की गई व इस 15 नवम्बर 1947 को संयुक्त राष्ट्रसंघ से जोड़ दिया गया ।

इस मुद्रा कोष की स्थापना की प्रक्रिया का प्रारम्भ तब से हुआ जब अमेरिकी गणतन्त्रों के विदेश मंत्रियों ने जनवरी सन 1942 में रिओडीजनरो में अपने एक सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया कि एक मुद्रा स्थिरता सन्ध बनाया जाय ताकि मुद्रा सम्बन्धी संकट का सामना किया जाय । उसी वर्ष अगस्त में ब्रिटेन में एक अन्तर्राष्ट्रीय समा शोधन संघ की स्थापना के प्रस्थापना के प्रस्ताव का प्रारूप अमेरिका को भेजा और इस प्रकार इन प्रकार इन दोनों पूजीवाद के नेताओं के बीच पारस्परिक विचार विमर्श हुआ साथ ही इन्होंने सोवियत संघ, केनडा, चीन तथा अन्य सरकारों से विचारों का आदान प्रदान किया । अगले वर्ष वाशिंगटन में एक बैठक बुलाई गई पर ब्रिटेन और अमेरिका आपस में सहमत न हो पाये फिर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने व्हेटनबुल्स नामक स्थान पर राष्ट्रों की एक सम्मेलन बुलाया जिसकी बैठक जुलाई 1, 1944 से 22 जुलाई, 1944 तक चली जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का स्वरूप किया गया जो ब्रिटेन और

अमेरिका के प्रस्तावों के मेल का परिणाम था। यह निश्चय किया गया कि कोप को 80 प्रतिशत साधन देने वाले राष्ट्र के द्वारा संपुष्ट किये जाने पर इसकी स्थापना की जाय। 27 सितम्बर, 1945 को 29 राष्ट्रों ने ऐसी संपुष्टि कर दी। इस प्रकार कोप के 80 प्रतिशत भाग के जमा हो जाने के बाद इसकी स्थापना हो गई और इस संयुक्त राष्ट्रसंघ से जोड़ दिया गया। जून 1966 को इस कोप की सम्पत्ति 3585 लाख डॉलर (स्वण में), 866 लाख डॉलर (चंद में) तथा 19960 लाख डॉलर राष्ट्रीय मुद्रा में थी।

उद्देश्य इस मुद्रा कोप के निम्नांकित उद्देश्य बताये जाते हैं

(1) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी सवालों पर सलाह देना व सहयोग बढ़ाना,

(2) स्वतंत्र विश्व व्यापार के समुचित एवं विस्तृत विकास की सुविधाओं को सगठित करना,

(3) अन्तराष्ट्रीय मुद्रातान में जो कृत्रिम रुकावटें आ जाती हैं, उनको हटाना और नियोजित विनिमय को बढ़ाने तथा विनिमय सम्बन्धी प्रतियोगिता को रोकना।

(4) सदस्यों को विदेशी मुद्रा के आदान प्रदान में सहायता करना तथा आर्थिक विकास के लिए व जीवन स्तर को उठाने के लिए किए जाने वाले आर्थिक प्रयत्नों में मदद करना।

(5) यह कोप सदस्यों की विदेशी मुद्रा की देय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहायता देता है।

इस प्रकार यह कोप विदेशी मुद्रा के विनिमय सम्बन्धी सवालों पर विचार करने और ब्रिटेन अमेरिका के नेतृत्व में उनका समाधान खोजने का एक मंच है। इसका सभी सदस्य यह स्वीकार कर चलते हैं कि वे अपनी मुद्रा का विनिमय मूल्य कोप के द्वारा सहमति प्राप्त कर चलेंगे और उसे बनाये रखेंगे। तथा 10 प्रतिशत मूल्य में अधिक का परिवर्तन करने पर कोप से पूछेंगे। सदस्यमण मुद्राभाषकों अपने स्वण तथा विदेशी मुद्रा अन्तराष्ट्रीय व्यापार, विनिमय एवं मूल्य, राष्ट्रीय आय तथा मूल्यो इत्यादि के संबंध में सूचनाएं दत्त रहते हैं। मुद्रा विनिमय में व समस्या के समाधान में बड़ों को आसानी रहे। कोप की स्थापना विदेशी मुद्रा के रूप में दी जाती है और सदस्य राष्ट्र अपनी मुद्रा को कोप में बदलवाना चाहें वह उतने ही मूल्य की अपनी मुद्रा को कोप में बदलेंगे और कोप को आगे की जाती है कि 3 साल या अधिक में कोप को बदलने की स्वयं या पुन डॉलर या कोप की मुद्रा को बदलेंगे। इस धनराशि पर कुछ और मुद्रा को बदलेंगे व जितने समय के लिए सी जाय

जाता है कि इस कोष से निवाली गई मुद्रा का प्रयोग सैनिक खर्च के लिए या आर्थिक विकास के लिए न होकर भुगतान की कठिनाइयाँ को दूर करना होगा। पर विकासशील देशों को कभी कभी यह छूट दी जाती है कि वे अपनी अस्थायी भुगतान की कठिनाइयाँ के कारण इसका प्रयोग आर्थिक विकास के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कोष के वायव्य निम्नांकित हैं

- (1) विदेशी मुद्रा एवं स्वर्ण को व्यापार के लिए सदस्यों को देचना,
- (2) विदेशी विनिमय की बाधाओं को दूर करने वाले वित्तीय एवं कोष सम्बंधी उपाय बतलाना,
- (3) मुद्रा सम्बंधी समस्याओं के बारे में सलाह देना,
- (4) मुद्रा स्थिति को रोकने के प्रयत्न में मदद करना,
- (5) आर्थिक समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों का प्रबंध करना,
- (6) विश्व की वित्तीय स्थिति के बारे में (पूँजीवादी विश्व की) सदस्यों को सूचना देते रहना एवं
- (7) प्राविधिक सहायता का प्रबंध करना।

कोष का प्रत्येक सदस्य अपना पैदा जो निर्धारित कर दिया जाता है और जिस वह अक्षत स्वर्ण व अक्षत मुद्रा में देता है निविष्ट किया जाता है और इसी धनराशि के आधार पर उसके मतदान की शक्ति व विदेशी विनिमय की रकम जो वह निकाल सकता है तय की जाती है।

संगठन इस मुद्रा कोष के संगठन में तीन अंग इस प्रकार हैं

- (1) अधिशासी मंडल या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स,
- (2) अधिशासी निदेशक
- (3) प्रबंधकारी निदेशक व,
- (4) सचिवालय।

अधिशासी मंडल कोष को सर्वोच्च अधिकारी है। इसमें प्रत्येक सदस्य के द्वारा नियुक्त एक अधिशासी व एक वैकल्पिक अधिशासी होता है। इसे ही कोष के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। निम्नांकित विषयों में केवल अधिशासी मंडल ही अधिकार का प्रयोग करता है बाकी वह अधिशासी निर्देशकों को सौंप सकता है।

- (1) सदस्यों में प्रवेश या उन्हें अलग करना,
- (2) कोष की आय के वितरण करने,
- (3) सदस्यों की मुद्रा के मूल्य में एक समान परिवर्तन एवं नियत राशि की स्वीकृति देना,
- (4) कोष को समाप्त करने का निणय,

अधिशासी निर्देशकों की कुल संख्या 20 है जिसमें पांच सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और भारतवर्ष हैं। जिनका कोषदान सबसे अधिक है। शेष

15 अधिशासियों का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका एक प्रबंध निर्देशक है व उसकी सहायता के लिए उप प्रबंध निर्देशक है। अधिशासी निर्देशकों की बैठक जिसमें प्रबंध निर्देशक या उप प्रबंध निर्देशक सम्मति का आसन ग्रहण करते हैं अधिशासी मण्डल कहलाता है। अधिशासी निर्देशकों की पहली बैठक मई 6 1 46 में हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है। 30 जून, 1966 तक 83 सदस्यों में से 61 सदस्यों ने इस मुद्रा कोष में 12 265 लाख डालर की धनराशि अपने अपने देशों की मुद्रा में निवासी। इसी प्रकार जनवरी 1962 में कोष में औद्योगिक देशों के 6 अरब डॉलर ऋण देन की सिफारिश की और इसकी अवधि चार वर्ष तक बढ़ा दी गई। वृद्धा सदस्यों की विदेशी विनिमय देय शक्ति को मजबूत बनाने के लिए 72 घण्टे की सूचना पर सहायता दी गई। कोष भामागत आगामी एक वर्ष के लिए दी जाने वाली सहायता की सूचना देता है।

कोष का एक कार्य प्राविधिक सहायता देना भी है। एतदर्थ वे सदस्य राष्ट्रों के बैंकिंग संस्थानों को उनके आर्थिक और बजट सम्बन्धी समस्याओं को सुधारन व आर्थिक सूचनाएँ इकट्ठा करने में सहायता देने हेतु विशेषज्ञ भेजता है। मई 1954 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य या प्राविधिक सहायता के रूप में सदस्यों (राष्ट्रों) के हित में वित्त मंत्रालयों व बैंक के कमचारियों को प्रशिक्षण देना। यह कोष समय समय पर साहित्य प्रकाशित करता है जिसमें महत्वपूर्ण साहित्य है वार्षिक प्रतिबदन विनिमय प्रतिबंधों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिबदन तथा द्वा मासिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय सूचनाएँ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के सहयोग से कुछ अन्य पत्रिकाएँ भी निबालता है।

(कोष की समस्याएँ मुख्यतः यह रही हैं कि अमेरिकी व ब्रितानी, फ्रांसीसी तथा जर्मन साम्राज्यवादी इस कोष के सहारे अपनी इच्छा व अनुकूल विनिमय दरों को इस प्रकार निश्चित करना चाहते रहे हैं कि विकासशील देशों को अधिक से अधिक लूट सकें जिसका विकासशील देशों विरोध करते आ रहे हैं। इस प्रकार प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता भी भावना आड़े आई है। ऐसा कहा जाता है कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा योजना और सम्पत्ति के स्वामित्व पर अधिकाधिक अधिकार करने की भावना में भी कोष के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा डाली)

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ब्रिटेन बुद्धस 'म जो उपयुक्त संयुक्त राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आर्थिक सम्मेलन बुलाया गया था उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस संगठन की बनाने का सुझाव सुनाया। यह प्रस्ताव जब 29 राष्ट्रों के द्वारा संपुष्ट हो गया तब 27 दिसम्बर 1945 को इसकी स्थापना की गई और 15 नवम्बर, 1947 को इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ दिया गया। इस संस्था की संख्या 106 के लगभग है।

संगठन विषय बैंक का कार्य चलाने के लिए तीन अंगों की स्थापना की गई।

- (1) अधिशासी मण्डल,
- (2) अधिशासी निदेशक,
- (3) सचिवालय एवं अध्यक्ष।

अधिशासी मण्डल में प्रत्येक देश द्वारा नियुक्त एक अधिशासी तथा एक वैकल्पिक सदस्य होता है। बैंक की सारी शक्तियाँ इसी मण्डल को प्राप्त हैं। प्रत्येक राष्ट्र को उससे अशदान के अनुपात से मतदान का अधिकार है। इसका नियमित अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। अधिशासी निदेशक 20 होते हैं जिनमें पांच सर्वाधिक अशदान देने वाले राष्ट्रों द्वारा नियुक्त होते हैं। तथा शेष 15 अन्य राष्ट्रों के अधिशासियों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

कार्यालय का प्रधान अधिशासी निदेशक के द्वारा चुना जाता है। वह अधिशासी निदेशकों का अध्यक्ष होता है तथा बैंक के कार्यों का प्रधान होता है। बैंक के संचालन की जिम्मेदारी उस मिल्ती होती है और वही कार्यालय अधिकाधिकारियों की नियुक्ति करता है व उन्हें हटाता है। अमेरिका के भूतपूर्व रक्षामन्त्री मैकनामरा इससे वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है।

उद्देश्य एवं कार्य इस बैंक के निम्नांकित उद्देश्य एवं कार्य उल्लेखनीय हैं।

- (1) उत्पादक कार्यों के लिए सदस्य राष्ट्रों को पूँजी उपलब्ध कराता है।
- (2) विदेशों में निजी पूँजी लगाने में सहायता देता है।
- (3) विश्व व्यापार में संतुलन स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय योग को बढ़ावा देता है।

इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

- (1) यह निजी उद्योगों को सहायता देता है एवं प्राविधिक सहायता प्रस्तुत करता है।
- (2) अपनी शक्तों पर यह विकास कार्यों के लिए ऋण देता है तथा,
- (3) विश्व में ऋण ग्राहिता (ऋण देने वाले और ऋण लेने वालों के हितों) में सामंजस्य पैदा करता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के सदस्यों ने 14 मई 1955 को इस अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिस 24 जुलाई 1956 को स्थापित कर दिया गया और 20 फरवरी 1950 को यह संयुक्त राष्ट्र संघ से जोड़ दिया गया। यह संस्था विश्व बैंक के सभी राष्ट्रों के लिए खुली है। इसकी वर्तमान सदस्यता 80 के करीब है।

संगठन यह निगम 3 अंगों में बंटा है (1) अधिशासी निकाय, (2) निदेशक निकाय, (3) सचिवालय। इस निगम के समस्त अधिकार संचालक परिषद के पास हैं अर्थात् निदेशक निकाय में हैं।

प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक सचालक एवं एक वैकल्पिक सदस्य भेजता है। इसके अधिकार और कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समान हैं और इसका अधिवेशन विश्व बैंक के साथ साथ होता है। सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी प्रबंधनिर्देशक होता है और इसका स्थायी सचिवालय वाशिंगटन में है।

उद्देश्य व कार्य इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों विशेष कर विकासशील देशों की निजी पूँजी को बढ़ावा देना और उसका संरक्षण व पोषण करना है। इसने लिए यह सदस्य राष्ट्रों को आसान दर पर पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराती है। वह स्वयं पूँजी लगाती है ऋण नहीं देता है। निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत निजी पूँजी (विदेश एवं उस देश की अपनी) पूँजी के लिए शमा शोधन (क्लीयरिंग हाऊस) का काम करती है।

दिसम्बर 1965 में इस संस्थाने 34 देशों के निजी क्षेत्रों की 12 योजनाओं में 150 लाख डॉलर की पूँजी लगाई। इसकी अधिकृत पूँजी 150 लाख डॉलर है। निगम सम्पूर्ण योजना व्यय की आधी पूँजी लगाता है एवं एक लाख से दो लाख डॉलर के बीच देता है और यह पूँजी अमेरिकी डॉलर में दी जाती है। (सन् 1967 तक इसने 36 राज्यों की 108 कंपनियों में 20 करोड़ डॉलर की पूँजी लगा रखी थी और यह पूँजी मुख्यतः स्पात, लोहा, कागज कपड़ा व खाद्य निर्माण उद्योग में थी। आयोग की सदस्यता 84 राज्यों ने स्वीकार की)।

अंतर्राष्ट्रीय विकास सगठन यह विश्व बैंक की एक सहायक संस्था है। इस की स्थापना 1960 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देना है। ऐसा कहा जाता है कि यह सगठन बैंक विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में मदद देता है। इस सगठन द्वारा दिये गए ऋण 50 वर्षों में अदा किये जाते हैं जिसमें प्रथम 10 वर्षों में कोई अदायगी नहीं होती और न ही व्याज लिया जाता है। दूसरे 10 वर्षों में एक प्रतिशत व्याज लिया जाता है तथा शेष 30 वर्षों में मूल धन पर 3 प्रतिशत व्याज लिया जाता है। इस प्रकार इस सगठन के अनेक विकासशील देशों में अपनी पूँजी लगाई तथा दिसम्बर, 1965 तक 30 राष्ट्रों को 7॥ विकास ऋणों के रूप में 112 लाख डॉलर दिये और 1968 तक यह राशि 750 करोड़ डॉलर तक बढ़ गई। इस रकम की तीन चौथाई अकेले एशिया और मध्य पूर्व के राज्यों में लगी हुई है। बाकी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी राज्यों में लगी हुई है। इसकी सदस्य संख्या 99 है।

न्यास परिषद या संरक्षण परिषद तथा पराधीन क्षेत्र

संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा महत्वपूर्ण अंग न्यास परिषद या संरक्षण परिषद है। जिसके सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव रिग्वेली ने कहा था

कि सत्तार में यह पहला अवसर है कि सार्वकारी प्रतिनिधियों की एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय समिति बक्स पिछड़े लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। एक माने में यह संरक्षण परिषद एक सचवा गया प्रयोग है और वह इस मान में कि यह सत्तया सयुक्त राष्ट्र सभ की एक प्रमुख अंग के रूप में मठिा बा गई सत्तया है। लेकिन दूगर अथ में यह उस प्रयोग का भी विकास मात्र है जो प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्र सभ के अंतगत मंडेट प्रणाली या समवेत प्रणाली के रूप में सार्ई गई थी और जिसके अंतगत प्रथम महायुद्ध में हार हुए साम्राज्यवादिया न उपनिवेशों को राष्ट्र सभ में माध्यम से जीते हुए साम्राज्यवादिया न हथिया लिया था और अपने शोषण व्यवस्था के अंतगत रण लिया था। आज की व्यवस्था में यह अंतर है कि द्वितीय महायुद्ध के उपरांत इन्ही पराधीन क्षेत्रों को पूरी तरह सयुक्त राष्ट्र सभ की निगरानी में रखा दिया गया था यद्यपि ये पास क्षेत्र अलग अलग साम्राज्यवादियों के हाथ में रहने दिए गये थे। दूसरा महत्वपूर्ण भेद यह था कि इस बार सयुक्त राष्ट्र सभ के अंतगत इन पराधीन क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य माना गया कि वे कालांतर में स्वाधीन बनाये जायेंगे और प्रथम में सभी पराधीन क्षेत्र आज स्वाधीन कर दिए गये हैं। इस प्रकार पुराने साम्राज्यवादी स्वरूप पर एक मुलम्मा चढ़ाया गया था और इस पुरानी साम्राज्यवादी समस्या को इस बार इस सिद्धांत के रूप में पेश किया गया कि आज के सत्तार में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके निवासी अविकसित और पिछड़े हुए हैं तथा उनकी जनति तब तक सम्भव नहीं है जब तक सम्यक् जनत देश उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर न उठाये। और इस तरह ये सम्यक् जन जनत देश इन् अविकसित लोगों के हितों को ध्यान में रख एक 'यासी (ट्रस्टी)' की तरह देखभाल करते रहे जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े होने लायक न हो जाए। यह सिद्धांत कुछ कुछ गांधीजी के उस 'ट्रस्टीशिप सिद्धांत' की तरह है जो वे राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में लागू करना चाहते थे।

'पास व्यवस्था का प्रारम्भिक विचार' पास व्यवस्था के विचार का सूत्रपात अमेरिकी के द्वारा सन 1942 में तब हुआ जब अमेरिकी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। अमेरिकी नेतृत्व यह चाहता था कि पराधीन उपनिवेश जो उसके मित्रों के हाथ में थे वे नहीं जर्मन नासियों व जापानी से व दासकों के शिकार न बने। इस दुषटना को रोकने के लिए एक आकषक योजना अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण परिषद के रूप में एक प्राविधिक समिति के द्वारा सन् 1942 में तयार की गई जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी सचिव वेल्स ने की। इसकी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह योजना सारे भर स्वायत्तता शासी क्षेत्रों पर लागू होनी थी और इसका नियम सयुक्त राष्ट्र सभ पर छोड़ा जाना था कि कौन सा क्षेत्र कब स्वाधीनता के लिए उपयुक्त हो गया है और उस कब ऐसी स्वायत्तता दी जाय। जापानी सरकार के द्वारा पश्चिमी उपनिवेशवाद व विरुद्ध जो जहर उमला जा रहा था और जिस

तरह जापानी अधिनायकवादी अपने आपका एशिया का मुक्तिदाता घोषित कर रहे थे उससे अमेरिकी साम्राज्यवादी बहुत चिंतित थे। जापान एक के बाद दूसरी जगहों पर कब्जा किये चला जा रहा था और ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि बिना एशियाई लोगों के हादिक सहयोग के जापानी बाढ़ को रोकना असंभव होगा इसलिए अमेरिकी साम्राज्यवादी इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन को अपने पक्ष में करना चाहते थे। 'एटलांटिक चार्टर' में इसीलिए पहले भी इस बात की घोषणा की गई थी कि मित्र राष्ट्र किसी प्रकार का क्षेत्रीय विस्तार नहीं चाहते हैं पर अंग्रेज साम्राज्यवादी यद्यपि 'एटलांटिक चार्टर' की इस घोषणा से तो सहमत थे वह आगे और कोई प्रवेश नहीं चाहते पर वे साथ ही यह भी नहीं चाहते कि जो कुछ उनके पास है उस उन्हें खोना पड़े यह वह समय था जब कि अमेरिकी दबाव से चर्चिल ने सर स्टेफन डिप्स को भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं से समझौता वार्ता के लिए भेजा था मगर जसा चर्चिल ने स्पष्ट कहा था वे इसलिए प्रधान मंत्री नहीं बने हैं कि वे साम्राज्य के विघटन का नेतृत्व करें। इस प्रकार अमेरिकी साम्राज्यवादी और उनके निकटतम सहयोगी अंग्रेज साम्राज्यवादियों के बीच पूर्ण सहमति नहीं हो पा रही थी। पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट सीमित क्षेत्र में 'यास पद्धति' लागू करने के पक्ष में थे और 14 जुलाई, 1943 को प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अमेरिकी प्रारूप में कहा गया था कि ऐसे सर प्रशासित क्षेत्र जहाँ के लोग अभी स्वतंत्रता पाने में योग्य नहीं हो पाये हैं वहाँ 'यास व्यवस्था' का सिद्धांत लागू किया जायेगा जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मान कर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की देख रेख में इन प्रदेशों को रखा जायेगा और इस प्रबंध का अंतिम लक्ष्य यह होगा कि राजनीतिक परिपक्वता आने पर इन्हें स्वाधीन बना दिया जायेगा। 1944 में इस पर पुनः विचार किया गया। यद्यपि डम्बटन ओक्स की बैठक में इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं हुआ (अमेरिकी सैन्य दल इस प्रबंध में सहमत नहीं था—इसलिए राष्ट्रपति ने डम्बटन ओक्स की कार्यसूची से निकाल दिया) इस प्रश्न पर फिर याल्टा सम्मेलन में विचार किया गया जहाँ तीन बड़े (अमेरिकी, सोवियत और ब्रितानी) राष्ट्रा ने यह तय किया कि सुरक्षा परिषद में पांच बड़े राष्ट्र स्थायी सदस्यता पायेंगे और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पूर्व वे आपस में 'यास पद्धति' के बारे में विचार करेंगे और उनमें यह भी तय हुआ कि यह पद्धति निम्नांकित क्षेत्रों पर लागू की जायेगी—

- (1) राष्ट्र संघ के तत्कालीन समादेशित क्षेत्र,
- (2) पहले की तरह ही इस बार शत्रुओं से छीने जाने वाले प्रदेश और
- (3) ऐसे कोई अन्य प्रदेश जिन्हें मित्र राष्ट्र (साम्राज्यवादी) स्वेच्छापूर्वक इस पद्धति के अंतर्गत सौंपना चाहे।

तदनुसार समुन्नत राष्ट्र सघ के 'पाटर' व अनुच्छेद 77 का इस कर्मन को लागू किया गया— और इन तीन कोटि के पराधीन क्षेत्रों को 'याम पद्धति' व अन्तर्गत रखा गया और अनुच्छेद 78 में इस बात की घोषणा की गई कि पराधीन राष्ट्रों के ये प्रशासन जो समुन्नत राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं उनमें कोई भी क्षेत्र 'याम पद्धति' के अन्तर्गत नहीं नियोज्योगे। यह शास्त्र है कि ये प्रशासन अपने आप ही इस पद्धति के अन्तर्गत नहीं आये बल्कि अनुच्छेद 79 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रसंघ का इस प्रकार का समझौता करना है जो महासभा के द्वारा स्वीकृत होने पर लागू किया जाता है।

पुराने राष्ट्रसंघ के समावेशित प्रशासकों के अन्तर्गत निम्नांकित क्षेत्र आते थे

प्रथम श्रेणी	समावेशक
1 लेबनान	फ्रांस
2 सीरिया	फ्रांस
3 फिलिस्तीन	ब्रिटेन
4 ट्रांस जोर्डन	ब्रिटेन
5 ईराक	ब्रिटेन
द्वितीय श्रेणी	समावेशक
1 टोगोलैंड	फ्रांस
2 टोगोलैंड	बेल्जियम
3 टनगानिका	बेल्जियम
4 कैमरून	बेल्जियम
5 कैमरून	फ्रांस
6 रुअंडा उरुंडी	ब्रिटेन
तृतीय श्रेणी	समावेशक
1 दक्षिण पश्चिमी अफ्रिका	दक्षिण अफ्रिका सघ
2 मैरीनास कारोलीन मार्शल द्वीप समूह	जापान
3 'यू गिनी (उत्तरी भाग) 'यू आयरलैंड	
'यू ब्रिटेन और सोलोमन द्वीप समूह	आस्ट्रेलिया
4 नारू	आस्ट्रेलिया
5 पश्चिमी समाओ	'यूजीलैंड

ईराक 1932 में स्वतंत्र कर दिया गया था। सीरिया व लेबनान 1936 में स्वशासी क्षेत्र घोषित हुआ तथा 13 दिसम्बर, 1945 को पूर्ण स्वतंत्र घोषित

किये गये। ट्रासजोडन 17 जनवरी, 1946 को स्वतंत्र हो गया। फिलस्तीन 1948 में स्वतंत्र हो गया न विभाजित कर समाप्त कर दिया गया।

शेष द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के समादेशित क्षेत्रों में से 10 'यास पद्धति' के अंतर्गत आ गए। वे थे —

क्षेत्र का नाम	श्रेणी	प्रशासक	प्रशासक प्राधिकारी 'यास पद्धति' के अंतर्गत
1 टोगोलैंड	बी	फ्रांस	फ्रांस
2 टोगोलैंड	बी	बेल्जियम	बेल्जियम
3 रुआंडा उरुंडी	बी	ब्रिटेन	ब्रिटेन
4 कैमरून	बी	फ्रांस	फ्रांस
5 कैमरून	बी	ब्रिटेन	ब्रिटेन
6 टांगानिका	बी	ब्रिटेन	ब्रिटेन
7 नारू	सी	'यूजीलैंड'	ब्रिटेन
8 'यूगिनी'	सी	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया
9 पश्चिमी समाओ	सी	'यूजीलैंड'	'यूजीलैंड'
10 नाथ पैसिफिक द्वीप समूह	सी	जापान	अमेरिका

इनमें मेरीयानस माससस और कैरोलीना द्वीप समूह वाला क्षेत्र ऐसा था जो जापान से छीना गया था उसे अमेरिका के प्रशासनात्मक कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 82 के अंतर्गत इसे सामरिक महत्व का घोषित कर दिया जाय अतः 17 फरवरी, 1947 को अमेरिकी ने सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के लिए एक समझौते का प्रारूप रखा और कुछ सरकारों के विरोध के बावजूद सुरक्षा परिषद ने छोटे मोटे परिवर्तन के साथ इस स्वीकार कर लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि इस समझौते में अमेरिकियों को यहां के मूल निवासियों की अपेक्षा आर्थिक मामलों में प्राथमिकता प्राप्त है और यह भी अधिकार मिला हुआ है कि सुरक्षा के हित में वह किसी भी क्षेत्र को निरीक्षण के लिए मना कर सकता है।¹⁹ इस प्रकार चाटर में दो तरह के यासों का प्रावधान हो गया। वे हैं

(1) असैनिक 'यास' क्षेत्र तथा

(2) सैनिक महत्व के 'यास' क्षेत्र।

असैनिक यास क्षेत्रों को महासभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया जबकि सैनिक महत्व के क्षेत्र अर्थात् जो अमेरिकी के शासनात्मक हैं सुरक्षा परिषद के अधीन किये गये हैं ताकि, अमेरिकी अपने हितों की रक्षा के लिए

नियेधाधिकार का प्रयोग कर सके। यह स्मरणीय है कि वैसे इसका प्रबंध रिया गया था कि यदि स्वेच्छा से कोई साम्राज्य अपने अंतर्गत किसी अस्वशासी प्रदेश को 'यास परिपद' के अंतर्गत रखना चाह तो रख सकता है। परन्तु किसी भी साम्राज्य देश ने कोई ऐसा प्रदेश 'यास' व्यवस्था को नहीं सौंपा।²⁰

'यास परिपद' संगठन का काम राष्ट्रसंघ के अंतर्गत जो समावेशित प्रबंध चलता था वह राष्ट्रसंघ को कोई अविभाज्य अंग न था बल्कि, यह एक सहायक अंग के रूप में काम करता था तथा इसमें विशेषज्ञ लोग ही सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते थे जो कबल परामर्श ही द सकते थे। संयुक्त राष्ट्र की यह 'यास' व्यवस्था इस माने में अपनी पूर्ववर्ती व्यवस्था से भिन्न है कि (1) 'यास परिपद' संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक प्रधान अंग है और इसके संगठन की व्यवस्था 'चाटर' के अंतर्गत की गयी है जिसके अनुसार 'यास' सम्भालने वाले राष्ट्रों के बराबर महत्वा के दूसरे राष्ट्र जो महासभा के द्वारा चुने जाते हैं इसके सदस्य होते हैं। इस अपने सारे अधिकारों का प्रयोग महासभा के तत्वावधान में ही करने का अधिकार है। यह परिपद महासभा के निर्देश पर ही कार्य करती है तथा सैनिक महत्व के 'यास' क्षेत्रों के बारे में इस सुझाव परिपद का निर्देश मानना पड़ता है। अनुच्छेद 86 के अनुसार इसमें तीन प्रकार के सदस्य हैं — (1) वे प्रतिनिधि जो 'यास' प्राप्त राज्यों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, (2) सुरक्षा परिपद के वे स्थायी सदस्य जो किसी ऐसे 'यास' क्षेत्र के प्रशासक नहीं हैं, (3) ऐसे अन्य सदस्य जिनकी सख्या उन राष्ट्रों के प्राधिकारी प्रतिनिधियों के बराबर होगी जो 'यास' प्रशासक हैं। ऐसे सदस्य महासभा के द्वारा तीन वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने प्रतिनिधि के साथ साथ एक वैकल्पिक सदस्य और एक सलाहकार भेज सकता है आवश्यकता पड़ने पर ऐसा राष्ट्र भी जो परिपद के सदस्य नहीं है विशेष आमंत्रण पर प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं।

अनुच्छेद 87 के अनुसार महासभा और उसके तत्वावधान में काम करने वाले 'यास परिपद' निम्नांकित कार्य सम्पन्न करती है—

- 1 यह प्रासासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किये गए प्रतिवेदनो पर विचार करती है। एक प्रस्तावनी तैयार की जाती है और उसके आधार पर 'यास' क्षेत्र के प्रशासन के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा इस प्रशासन में सवध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है
- 2 यह उन याचिकाओं को प्राप्त करती है और प्रशासनिक अधिकारों की मदद से उन पर विचार करती है जो याचिकाएं 'यास' प्रशासक के लोगों के द्वारा या वहां के संगठनों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। 1951 में तक इसके सामने 700 याचिकाएं आई थीं पर उनकी सख्या बढ़ती गयी और अगले वर्ष 1959 में परिपद को 1235 ऐसे प्रतिवेदन मिले ,

- 3 'यास परिषद प्रशासनिक अधिकारी द्वारा महत्तम समय पर 'यास क्षेत्र का दौरा भी करती है व मौके पर जाकर निरीक्षण करती है। यह प्रबन्ध है कि प्रत्येक यास प्रदेश में वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य निरीक्षण मण्डल भेजा जाता है।
- 4 इसका अलावा 'यास समझौते के अनुसार वह इन प्रतिवेदनो और याचिकाओ पर कार्यवाही करती है।

'यास परिषद के अ तर्गत इस प्रकार 11 प्रदेश साये गये थे जिनका क्षेत्रफल 907660 वर्ग मील व जनसंख्या 1,74,75,647 थी। आज इन प्रदेशों में से सिधाय प्रदा त महासागरीय द्वीपों को छोड़कर जो अमेरिका के अधीन हैं बाकी सारे क्षेत्र स्वशासन प्राप्त कर चुके हैं और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ का यही एक मात्र ऐसा अंग है जिसने 'चाटर' में उल्लिखित ध्येय की पूर्ति की है और उप निवेशवाद की समाप्ति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सदन में यह उल्लेखनीय है कि अभी भी दुनिया में ऐम क्षेत्र बाकी हैं जो स्वशासन नहीं प्राप्त कर सके यथा पुतगाल के अधीन उपनिवेश अंगोला, मोजम्बिक, पुतगाली गिनी तथा दक्षिण रोडेशिया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रिका। इस सदन में 14 दिसम्बर, 1960 में महासभा के द्वारा पास किया गया वह प्रस्ताव उल्लेखनीय है जिसमें उपनिवेशवाद को समाप्त करने का संकल्प किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस संकल्प ने भी उपनिवेशवाद को 'यास व्यवस्था के अ तर्गत और उसके बाहर भी समाप्त करने में काफी योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि 'यास परिषद ने अपनी उस पद्धति के द्वारा जिसके अ तर्गत याचिकाएँ सुनी जाती थी तथा शिष्ट मंडल भेजे जाते थे अस्वशासित क्षेत्रों के लोगों को काफी कुछ लाभ पहुँचाया। इसी की दृष्टि में रखकर मिश्री प्रतिनिधि मुहम्मद एल० कौली ने यह टिप्पणी की थी कि 'यास पद्धति समादक्षित पद्धति से कहीं ज्यादा सुधरी हुई व्यवस्था है क्योंकि वह शिष्ट मंडल के द्वारा देखभाल का काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। इसके बारे में सन 1947 में शिष्ट मंडल के प्रतिवेदन पर 'यूजीलैंड ने अपने अधीन क्षेत्र समाओ के प्रशासन में संधार किया। ऐसे ही आस्ट्रेलिया ने भी सन 1962 में 'यूगिनी के क्षेत्र में प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका सभा का प्रबन्ध किया। इन शिष्ट मंडलों के द्वारा 'याम परिषद चाहे तो यह सूचना बड़ी अच्छी तरह इकट्ठा कर सकती थी कि राजनीतिक समस्याओं, सांख्यिक सेवाओं उद्योग घरे बगार तथा स्वास्थ्य और कृषि सम्बन्धी बातों में प्रशासनिक राज्य क्या क्या कार्यवाही कर रहे हैं उनकी सूचनाएँ कहा तक विश्वसनीय हों और उनके विरुद्ध शिकायतें कहा तक सही हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इसके अतर्गत जनमत संग्रह भी करवाये यथा ब्रिटिश टोगा लैंड व ब्रिटिश केमरून में जनमत संग्रह का निरीक्षण किया जिससे वहाँ संघ द्वारा मायता प्राप्त टोगोलैंड

तथा गोल्डवोस्ट को मिलाकर घना संधि की स्थापना हुई। इसी प्रकार वे जनमत गणना के द्वारा पश्चिमी सभाओं के लिए नया सविधान स्वीकार किया गया और यह सन् 1962 में स्वतंत्र कर दिया गया। फ्रांसिसी तोगोलंड, रुअंडा और उरुंडा में स्वशासन में पूर्व चुनावों के समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रेक्षक दल भेजे गए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपने सीमित दायरे के अंदर राष्ट्रसंघ के इस अंग ने प्रशंसनीय कार्य किया जिस आंगिक रूप में उपनिवेशवाद की समाप्ति का कार्य कहा जा सकता है क्योंकि उपनिवेशवाद का कोढ़ अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।

समादेशित प्रणाली में यास व्यवस्था—यूना न यास व्यवस्था के बारे में यह मार्क की बात बही थी कि यह पुरानी समादेशित प्रणाली का ही संशोधित रूप है। लेकिन समादेशित प्रणाली और उस व्यवस्था में बहुत कुछ साम्य होते हुए भी कुछ मामलों में यह उससे भिन्न रही है। यह अंतर निम्नांकित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है—

1 यास व्यवस्था अधिक विस्तृत है। सैद्धांतिक रूप में यह व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से अधिक विस्तृत मानी गई थी क्योंकि समादेशित व्यवस्था केवल उन क्षेत्रों और उपनिवेशों में लागू होनी थी जो प्रथम युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी या तुर्की से छीन गए थे जबकि यास व्यवस्था में केवल शत्रु के अधीन प्रदेशों की ही शामिल नहीं किया गया था बल्कि यह व्यवस्था की गई थी यदि उपनिवेशों के स्वामी अपने अधीन अस्वशासित किसी प्रदेश को यास व्यवस्था के अधीन रखना चाहें तो रख सकते हैं। पर ऐसा कोई प्रदेश यास व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आया। इसलिए व्यवहार में दोनों व्यवस्थाओं के बीच कोई अंतर नहीं पड़ा। नई व्यवस्था का विस्तार इस प्रकार क्षेत्र सम्बंधी न होकर अधिकार या सामर्थ्य सम्बंधी है।

यास परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंग के रूप में उभरी

प्रारम्भ से ही इस नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यास परिषद को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में गठित करने की योजना रखी गयी थी। पुरानी समादेशित प्रणाली राष्ट्रसंघ को कोई अभिन्न अंग नहीं थी। बल्कि वह विशेषज्ञ वाला एक स्थायी संरक्षण या समादेशित आयोग के रूप में चलने वाली समिति जैसी था और इस प्रकार वह एक निम्न स्तर का संगठन थी। इस बार यास परिषद के रूप में इस बहुत महत्व दिया गया था और राष्ट्रसंघ के अभिन्न अंग के रूप में रखा गया था जिसमें न केवल निपेदाधिकार प्राप्त पांच बड़े राष्ट्रों को सदस्य बनाया गया था बल्कि यह व्यवस्था की गयी थी कि महासभा के द्वारा चुने हुए सदस्य भी इसमें रहें। इस प्रकार यह एक प्रतिनिधि मूलक और उत्तरदायी संस्था बन गई।

अधिक शक्तिशाली और नियंत्रण निरीक्षण करने वाला अंग

वर्तमान 'यास' परिषद न केवल प्रतिनिधि मूलक और अधिक जिम्मेदारी निभाने वाली परिषद रही है बल्कि, उस अपने पूर्ववर्ती समादेशित आयोग से बड़ी अधिक निरीक्षण नियंत्रण की शक्ति मिली हुई थी। वह आयोग की तरह एक साधारण समिति न थी बल्कि, प्रशासक राज्यों द्वारा रपट मागन वाली, उनकी प्रशासन की छानबीन करने वाली और यथावश्यक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म से सूक्ष्म सूचनाएँ एकत्रित कर सकने वाली परिषद सिद्ध हुई।

इस सदन में यह स्मरणीय है कि राष्ट्रसंघ के अंतर्गत आयोग को अपने आप छान बीन करने का अधिकार न था जबकि वर्तमान 'चाटर' के अंतर्गत यह प्रबंध किया गया है कि 3 वर्ष में कम से कम एक बार 'यास' परिषद के प्रतिनिधि 'यास' प्रदेशों का दौरा अवश्य करेंगे। इस दौरे के बारे में प्रशासक राज्यों को सचेत रहना पड़ता था क्योंकि 'यास' परिषद मौके पर जाकर खुद ही बहुत सारी सूचनाएँ इस तरह प्राप्त कर सकती थी और उसकी रपट महासभा को देती थी।

निश्चित लक्ष्य वाली पुराने राष्ट्रसंघ के अंतर्गत जो संरक्षण व्यवस्था अपनायी गयी थी उसमें संरक्षित प्रदेशों के लिए स्वाधीनता का कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया था और ये प्रदेश वस्तुतः पराक्षर रूप में प्रशासक साम्राज्य के अंग से ही थे जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंतर्गत 'यास' प्रदेशों के लिए यह पहले से ही तय किया गया कि वे प्रदेश स्थायी तौर पर संरक्षित प्रदेश ही नहीं बने रहेंगे बल्कि, संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्देशन में अंतर्गत स्वाशासन पा जायेंगे। और हुआ भी यह जिसके फलस्वरूप आज प्रायः व सारे प्रदेश जो 'यास' व्यवस्था के अंतर्गत रहे गए थे, स्वाशासन प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था अधिक फलदायी सिद्ध हुई और कौरा उपनिवेशवाद का भ्रष्ट स्वरूप नहीं रह गई।

महासभा के प्रति उत्तरदायी पुरानी संरक्षण व्यवस्था राष्ट्रसंघ की परिषद की निगरानी व नियंत्रण में काम करती थी। परंतु 'यास' व्यवस्था पर महासभा का सीधा नियंत्रण है। महासभा स्थायी सदस्यों को और प्रशासक राज्यों के अलावा अपने सदस्यों को चुन कर इसमें भेजती है। महासभा इस 'यास' परिषद पर नियंत्रण रखती है इसकी रपट सुनती है प्रतिवेदनो पर विचार करती है तथा इन प्रदेशों से आई हुई याचिकाओं की सुनवाई करती है और चूंकि, प्रशासक राज्यों की कार्यवाही अपने पूरे व्योरे के साथ महासभा के आगे प्रस्तुत की जाती है इसलिए प्रशासक राज्य भी महासभा की इस कार्यवाही से धवराते रहते हैं और उन पर महासभा एक अकुश का काम करती है।

उपयुक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि 'यास' व्यवस्था यद्यपि कोई

आदशवादी व्यवस्था नहीं थी परंतु वह सरक्षण व्यवस्था का नया संस्करण भी नहीं थी। वह पुरानी सरक्षण व्यवस्था से वही अधिक दूरदर्शी और परिवर्तनवादी सिद्ध हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' राष्ट्रों के बीच समय-समय पर उठने वाले विवादों को निपटाने की समस्या विरवाले में रही है। यूरोप में इस समस्या के सुलझाने के लिए जो प्रयत्न आधुनिक काल में हुए उनकी शुरुआत सन 1899 में हग के अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' की स्थापना से हुई जिसमें विभिन्न देशों के 132 विधिशास्त्रियों के नामों की सूची रहा करती थी। इसके अनुसार हग सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच जब कभी विवाद उठ खड़ा होता तो इस सूची में दिये हुए नामों में से कुछ को चुनकर एक 'यायालय' सा बना दिया जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की वैधता व्याख्या करता तथा यह बताता कि अनुसंधान में क्या सच भग हुआ है या नहीं। विवादोत्पत्ति मामलों में यह निणय नहीं देता था।

दूसरे हग सम्मेलन में जो 1907 में हुआ अमेरिका देशों ने एक अमेरिकी 'यायालय' की स्थापना की जिसे 10 वर्षों के लिए स्थापित किया गया। उसमें 5 'यायाधीश' होते थे तथा प्रत्येक मध्य अमेरिकी राज्य एक 'यायाधीश' की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करता था। इसी सम्मेलन में तय किया कि मध्य अमेरिकी राज्यों के बीच उठने वाले प्रश्नों को इसके सामने रखा जायेगा। इस 'यायालय' ने 1917 तक दस मामलों पर अपना निर्णय दिये थे। प्रथम महायुद्ध के पहले इस प्रकार यूरोप और अमेरिकी देशों में यह 'यायालय' की पूछ-बीछका तैयार हो रही थी। प्रथम महायुद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक 'यायालय' की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो राष्ट्रसंघ की संविदा की धारा 14 में स्थापित हो गया। विचार विमर्श के बाद महासभा के द्वारा सन 1920 के 13 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' वाला प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 1922 को यह स्थायी 'यायालय' हग में विधिवत स्थापित हो गया। समुक्त राष्ट्रसंघ के 'चाटर्' ने इसी 'यायालय' के पुनर्जीवित कर दिया है।

पुराने अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' में प्रारम्भिक वर्षों में 11 'यायाधीश' और 4 उप-यायाधीश होते थे जिनकी संख्या 1921 में 15 कर दी गई। इस 'यायालय' के दोना ही प्रकार के अधिकार क्षेत्र थे। एक ऐच्छिक और दूसरा अनिवार्य। करीब 20 राज्यों ने कुछ मामलों में यथा संधियों की व्याख्या इत्यादि के द्वार में अनिवार्य अधिकार क्षेत्र स्वीकार कर लिया था। अपने 20 वर्ष के कार्य काल में इस 'यायालय' ने करीब 65 मामलों पर विचार किया जिनमें से 32 मामलों में निणय दिये और करीब 27 परमश किये।

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' एक अथवा नया 'यायालय' है चूँकि 18 अप्रैल, 1936 को महासभा के निणयानुसार पुराना

स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समाप्त कर दिया गया तथा नया न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। यह प्रबंध किया गया कि इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र सचय की साधारण सभा और सुरक्षा परिषद करती है। इस न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए उम्मीदवार का न केवल अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए बल्कि, उस अपने राज्य के कानून और अंतर्राष्ट्रीय विधि का जानकार भी होना चाहिए। न्यायाधीशों के निर्वाचन की प्रणाली कुछ इस प्रकार है कि उम्मीदवार उस सूची में से चुने जाते हैं जिस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र बनाते हैं। फिर उसी सूची के उम्मीदवार जिन्हें साधारण सभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत मिलने में हो चुना जाना सम्भव होना है। सामान्यतः सबसे पहले सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति जहरी हो जाती है। वैसे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जहां तक सम्भव हो सकार के सभी विधि व्यवस्थाओं के प्रतिनिधि बुलाये जाए पर किसी एक राज्य के दो न्यायाधीश नहीं होने चाहिए। न्यायालयों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। पर वे पुनः इसी अवधि के लिए चुने जाते हैं। न्यायाधीश मण्डल 3 वर्ष के लिए अपना अध्यक्ष और उपअध्यक्ष का चुनाव करत है तथा अपने अधीन काम करने वाले निबंधक तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति खुद करता है।

न्यायालय का कार्य संचालन इस प्रकार होता है कि सभी न्यायाधीश मिल कर मामले की सुनवाई करते हैं यद्यपि यदि वे चाहें तो मुविषा की दृष्टि से पांच सदस्यों का एक खंडपीठ बना लें। न्यायालय की गणपूर्ति कम से कम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति से बनती है तथा वे नियम या राय देते हैं। जिस देश का मामला पेश होता है उस देश से सम्बन्धित न्यायाधीश भाग नहीं लेता पर यदि किसी ऐसे राज्य का मामला पेश हो जिसका प्रतिनिधित्व न्यायालय में नहीं है तो उस देश के न्यायाधीशों को भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है पर वे नियम में भागीदार नहीं हो सकते हैं।

न्यायालय की भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। यह स्मरणीय है कि न्यायालय के सम्मुख केवल राज्य ही पक्ष हो सकते हैं। तीन कोर्ट के राष्ट्र न्यायालय के सामने पक्ष के रूप में हाजिर हो सकते हैं।

- (1) संयुक्त राष्ट्र सचय के सदस्य जो प्रमश न्यायालय की सविधि के भी सदस्य हो सकते हैं।
- (2) संयुक्त राष्ट्र सचय के जो सदस्य नहीं हैं वे भी उन शर्तों पर सविधि के सदस्य हो सकते हैं जिन्हें महासभा सुरक्षा परिषद की सस्तुति पर निर्धारण करती है। स्विटजरलैण्ड की प्रार्थना पर महासभा ने अपने पहले अधिवेशन में य निम्नांकित शर्तें तय की थी—

(क) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि को स्वीकार करना,

- (स) 'चाटर' के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत राष्ट्र संध के सदस्यता का दायित्वा को स्वीकार करना,
- (ग) महासभा द्वारा निर्दिष्ट यायालय के व्यय के अगदान का देना।
- (3) ऐम राज्य जो सविधि के सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद द्वारा निर्दिष्ट शर्तों व आधार पर एक पक्ष के रूप में उपस्थिति हो सकता है किंतु, उह यह घोषणा करनी पड़ती है कि वे 'यायालय के' नियमों और नियमों का मानेंगे। 'कप्यू चैनल' के मामले में अल्बानिया को इसी रूप में उपस्थिति होने दिया था

अक्टूबर 1946 में सुरक्षा परिषद ने निम्नांकित शर्तें निर्धारण की थी—

- (1) कि एम राज्य पहले 'यायालय के' निबंधन के पास समयक के अनुसार 'यायालय के' अधिक्षेत्र की स्वीकृति की घोषणा करत हैं तथा सदस्यता से 'यायालय के' नियमों तथा ससमय के अनुच्छेद 94 के अनुसार संध का दायित्वा का पालन करना स्वीकार करते हैं।
- (2) यह उदघोषणा सामान्य या विशेष हो सकती है। किन्तु उदघोषणा में किसी विवाद के सम्बन्ध में 'यायालय के' अधिक्षेत्र को स्वीकार किया जाता है जबकि सामान्य में सभी विवादों के लिए इस प्रकार की उदघोषणा की वधता या प्रभाव सम्बन्धी प्रश्नों पर 'यायालय' नियम लेता है।

यायालय का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' का क्षेत्राधिकार काफी व्यापक है और यह अधिकार सम्बन्धी प्रश्नों का खुद ही निर्णायक है। समुक्त राष्ट्रसंघ के भी सदस्य और यदि चाहे तो गर सदस्य भी इस यायालय के सम्मुख अपने मामले ला सकते हैं। निम्नांकित तीन प्रकार के विवादों पर उस नियम का अधिकार प्राप्त है—

- (1) जब सम्बन्धित पक्ष अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' में विवाद को प्रस्तुत किया जाने के लिए आपस में सहमत हो। यह उसका ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है।
- (2) यदि किसी विवाद में सम्बन्धित दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' के अनिवार्य क्षेत्र की मान चुके हैं तो इन पक्षों में से कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' के समक्ष अपना मामला पेश कर सकता है।
- (3) समुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों पर यह अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' कोई अनिवार्य क्षेत्राधिकार नहीं लागू कर सकता। मध्य के सदस्य अपना मामला 'यायालय' में लाने के लिए मजबूर नहीं किये जा सकते परंतु 'चाटर' की धारा 36(2) में यह दिया हुआ है कि चाटर के सदस्य किसी समय भी 'यायालय' के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र को आपस के समक्षों के द्वारा निम्नांकित चार प्रकार के विवादों के सम्बन्ध में स्वी

कार कर सकते हैं।

(1) किसी सधि की व्याख्या करने के सम्बन्ध में,

(2) अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्न को तय करने के लिए।

(3) किसी ऐसी बात के उठने पर जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के भग होने का खतरा हो,

(4) किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के भग हान पर जो मुआवजा देना पड़े उस की मात्रा व स्वरूप को तय करना। इस प्रकार वैकल्पिक धारा के अंतर्गत अनिवार्य अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया है। इससे यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों ने किसी सधि के अंतर्गत अपने मामले स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेजना स्वीकार किया था व सभी मामलों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भेजे दिये जायेंगे।

हमक अलावा यास पद्धति के अंतर्गत हुए समझौते में यह प्रबंध है कि प्रत्येक राज्य और सधि के अंतर्गत सदस्यों के बीच हुए समझौतों की व्याख्या और कार्य निष्पत्ति सम्बन्धी विवाद को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने ऐसे मामले भेजे जायेंगे। यही बात कुछ विशिष्ट अभिकरणों के सम्बन्ध में भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि की धारा 36 (3) में प्रावधान है कि सभी कानूनी विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को फैसले के लिए भेजे जायेंगे। यह स्मरणीय है कि व सारे मामले जो धरेलू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, न्यायालय की परिधि से बाहर हैं।

परामर्श सम्बन्धी अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल फैसला करने वाला ही न्यायालय नहीं है बल्कि 'चाटर' के अंतर्गत उसे संयुक्त राष्ट्र सधि के विविध अंगों को परामर्श देने का अधिकार मिला हुआ है। महासभा और सुरक्षा परिषद किसी भी वैधानिक मामले पर इसकी सलाह मांग सकती है परन्तु संयुक्त राष्ट्र सधि के अंतर्गत उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे ही दूसरे अंग और अभिकरण की सलाह ले सकते हैं।

निर्णय हो जाने पर कोई भी पक्ष निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए सुरक्षा परिषद से कायवाही कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। और सुरक्षा परिषद उसे कार्यान्वित कराने के लिए 'चाटर' के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत आवश्यक कायवाही कर सकती है।

न्यायालय द्वारा तय किए हुए कुछ मामले

(1) न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आय कुछ महत्वपूर्ण

मामले तय किए हैं जिनमें 'कफ्यू चैनल' का मामला, कोलम्बिया पीरू राजनीतिक शरण का मामला, आग्ल नार्वे मछली मारने का मामला, आग्ल ईरान तेल कम्पनी का मामला, बेल्जियम डच सीमा सम्बन्धी प्रमुखता का मामला, हवाई दुपटना सम्बन्धी 27 जुलाई, 1955 का मामला, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का मामला, भारतीय क्षेत्र से यातायात की सुविधा का मामला प्रिय विहार मंदिर का मामला ऐसे मामले हैं।

इसी तरह परामश सम्बन्धी मामले भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तय किये जिनमें प्रमुख है

- (1) राज्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न (17 नवम्बर, 1948)।
- (2) संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में हुए नुकसान के मुश्तान का प्रश्न (दिसम्बर 1948)।
- (3) संघ की सन्म्यता में प्रवेश सम्बन्धी महासभा की क्षमता (22 नवम्बर, 1949)।
- (4) दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति (दिसम्बर 1949)।
- (5) अन्तर राज्य जहाजरानी परामश संघ की जहाजरानी सुरक्षा समिति के गठन का प्रश्न।
- (6) संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना कार्यों पर व्यय (सन 1961)।

इस प्रकार अनेक मामला में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मुख्यतः एक विवाद प्रस्तुत हर तरह की सम्मतिमा दी है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्याय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस न्यायालय ने अब तक लगभग 50 विवादों में स 29 पर अपने निष्पत्ति दिए हैं जो भल ही जन प्रिय न हो पाय हो पर बहुसंख्यक राष्ट्रों में उनका बहुत कुछ समर्थन किया है। यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का विषय है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। क्योंकि विवादी राष्ट्र अपने मामले को तय कराने के लिए इसका सहारा नहीं खोजते।

द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने बड़े बड़े मामले और विवाद उठे, विवादी पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय समूहों के बजाय अन्य राजनीतिक तरीकों से अपने हल खोजने के प्रयत्न किये अनेक विस्फोटक विवादों में क्यूबा संकट घियतनाम सत्र और ऐम ही अन्य विस्फोटक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसका अंग दानव्यान वाली भूमिका भी नहीं निभा सकते। पक्ष विपक्ष में अपना हल खोजने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण नहीं ली। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का महत्व अपने पूर्ववर्ती में भी कम मिट्ट हुआ। एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसने अग्रा द्वारा भी इसका कम ही उपयोग हुआ और

चूँकि राज्यों के अलावा नागरिक अपने मामले स्वयं ममक्ष नहीं कर सकते थे और राज्य सारे महत्वपूर्ण मामलों को अपने घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पसंद करते थे इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास काम करने की क्षमता कम थी। यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ पुराने न्यायालय के निर्माण के बाद ही 44 देशों ने स्वीकार किया था वहाँ इतनी भारी संख्या में राष्ट्रों के स्वीकार होने के बाद भी सन् 1967 तक केवल 43 राष्ट्रों ने ही स्वीकार किया था। फिर यह भी देखा गया कि इन राष्ट्रों में से बहुत से राष्ट्रों को लागू करना इतना आसान सिद्ध नहीं हुआ कि वे इसे लागू करेंगे। विवादों पक्षों ने उसकी भी अपेक्षा की। दफ्तरी कार्य के लिए भी न्यायालय ने अल्पानिया को ब्रिटेन का हुजाना देना शुरू किया। यही स्थिति वागा की सैनिक हस्तक्षेप के तत्काल बाद प्रकाशित हुई। सुरक्षा परिषद द्वारा दिये गये परामर्श पर हुई या शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं को अवहेलना हुई। अधिक तरजीह नहीं दी और जहाँ आवश्यक हो तो सैन्य शक्ति का उपयोग कि मामले को न्यायालय के मूल नियमों के अन्तर्गत लाया जा सके।

मामले तय किए हैं जिनमें 'बर्फ्यू चैनल' का मामला, कोमम्बिया पीरू राजनीतिक शरण का मामला, जंगल नार्वे मछली मारने का मामला, आगल ईरान तेल कम्पनी का मामला, बल्जियम डच सीमा सम्बन्धी प्रभुसत्ता का मामला, हवाई दुर्घटना सम्बन्धी 27 जुलाई 1955 का मामला, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का मामला, भारतीय क्षेत्र से यातायात की सुविधा का मामला, प्रिय विहार मंदिर का मामला ऐसे मामले हैं।

इसी तरह परामश सम्बन्धी मामले भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तय किये जिनमें प्रमुख है

- (1) राज्या के संयुक्त राष्ट्र संधि में प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न (17 नवम्बर, 1948)।
- (2) संयुक्त राष्ट्र संधि की सेवा में हुए नुकसार के भुगतान का प्रश्न (दिसंबर 1948)।
- (3) संधि की सदस्यता में प्रवेश सम्बन्धी महासभा की क्षमता (22 नवम्बर, 1949)।
- (4) दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति (दिसम्बर 1949)।
- (5) अंतर राज्य जहाजरानी परामश संधि की जहाजरानी सुरक्षा समिति के गठन का प्रश्न।
- (6) संयुक्त राष्ट्र संधि के शांति स्थापना कार्या पर ध्यान (सन् 1961)।

इस प्रकार अनेक मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मूल्यवान एवं विवाद प्रसन्न हृदय तरह की सम्मतियाँ दी हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्याय सभ्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस न्यायालय ने अब तक लगभग 50 विवादों में से 29 पर अपने निर्णय दिए हैं जो भले ही जन प्रिय न हो पायें हो पर बहुसंख्यक राष्ट्रीय में उनका बहुत कुछ समयन किया है। यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का विषय है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। क्योंकि विवादों राष्ट्र अपने मामले को तय कराने के लिए इसका महारा नहीं सोजते।

द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने बड़े बड़े मामले और विवाद उठे विवादी पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बजाय अन्य राजनीतिक तरीकों से अपने हल खोजने के प्रयत्न किये अनेक विस्फोटक विवादों में बयूबा सचट, धियानास सचट और ऐंग ही अन्य विस्फोटक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके अंग डार्लाने वाली भूमिका भी नहीं निभा सकते। पक्ष विपक्ष में अपने हल खोजने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण नहीं ली। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का महत्व अपने पूर्ववर्ती में भी कम सिद्ध हुआ। एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके अंगों द्वारा भी इसका कम ही उपयोग हुआ और

चूनि राज्यों के अलावा नागरिक अपने मामले हमने समझ नहीं ला सकते थे और राज्य सारे महत्वपूर्ण मामलों को अपने धरे लु छोपाधिकार के अंतगत रखना पसंद करते थे इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय 'यायालय' का पास काम बहुत धोड़ा रह गया। यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ पुराने 'यायालय' के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र को 44 देशों ने स्वीकार किया था वहाँ इतनी भारी समस्या में स्वतंत्र देशों के गठित होने के बाद भी सन 1967 तक केवल 43 राज्यों ने ही ऐसा अनिवार्य क्षेत्र स्वीकार किया था। फिर यह भी देना पड़ा कि अन्तर्राष्ट्रीय 'यायालय' के नियमों की लागू करना इतना आसान सिद्ध नहीं हुआ जो इस 'यायालय' ने नियमों के विवादों पर न उसको भी अपेक्षा की। यहाँ 'क्याचनल' के नियमों में 'यायालय' ने अलवानिया को ब्रिटेन का हजाना देना तय किया परन्तु अलवानिया ने उस नहीं चुकाया। यही स्थिति मागा की सैनिक कायबाही के तब के प्रदन पर 'यायालय' द्वारा नियमों परामर्श पर हुई या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के मामलों में ऐसी ही अकहेलना हुई। सुरक्षा परिषद और महासभा ने भी बानूनी मामलों में इसको अधिकतर जीह नहीं दी और जहाँ कहीं विवादों छोटे राष्ट्रों ने ऐसा सुझाव दिया कि मामलों को 'यायालय' के सुपुर्द किया जाय वहाँ इसकी उपेक्षा की गई।

सचिवालय पुराने राष्ट्रमण्डल के जिस अंग को लगभग जया का लो रत लिया गया है वह अंग है अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय। चाटर के 15 वें अध्याय में अनुच्छेद 97 से 101 तक इस गठन का वर्णन किया है। अनुच्छेद 7 के अंतगत इस सभ का मुख्य अंग बनाया गया है। इसका गठन इस प्रकार किया जाता है कि यह अपना बहुराष्ट्रीय रूप बनाये रखे। इसका प्रधान प्रशासनिक अधिकार महासचिव है जो सभ का एक बहुत उत्तरदायी प्रशासक है वहीं सभ के समस्त कमचारियों को नियुक्त करता है जिनसे आधा की जाती है कि वे अपने राष्ट्र के नागरिक रहत हुए भी सचिवालय में काम करते समय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के प्रति निष्ठा वान रहेंगे और निष्पक्ष होकर अपना उत्तरदायित्व निभायेंगे।

महासचिव सयुक्त राष्ट्र सभ के 'चाटर' के अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि सचिवालय में एक महासचिव तथा सभ की आवश्यकता के अनुसार अन्य कम चारी होंगे जिन्हें महासचिव नियुक्त करेगा। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा सभ की परम्परा का अनुमोदन किया गया है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि पुराने राष्ट्र सभ के अंतगत महासचिव की जो स्थिति थी उससे कहीं अधिक शक्ति सम्पन्न वर्तमान सयुक्त राष्ट्रसभ का महासचिव है। राष्ट्र सभ की व्यवस्था के अंतगत महासचिव को राजनीतिक कार्यों का अधिकार न था यद्यपि व्यवहार में वह ऐसे कार्य करने लगा था लेकिन जसा प्रथम महासचिव ड्रमंड ने स्वीकार किया था — 'मैं कार्य करने परदे के पीछे रहकर करना पड़ता था। परन्तु नव 'चाटर' के

अतः महासचिव को यह अधिकार दिया गया है कि वे शांति और सुरक्षा के गम्भीर गतर के उपस्थित होने पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकषिप्त कर सकें।

वैस भी जैसा वनामडेस न ठीक ही कहा है कि महा सचिव का पार प्रभासक पार स वही अधिक महत्वपूर्ण है। यह पद इतना प्रभावशाली और महत्व का हो सकता है जितना इसम पदासीन व्यक्तित्व उसे बनाने में समर्थ हो सकें क्योंकि लिखित प्रावधान की सीमायें भले ही निधारित हों लेकिन व्यवहार में उन सीमाओं को फलाया भी जा सकता है।

समुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के बारे में त्रिगवली के नाम की सन्तुति 30 जनवरी, 1946 को सुरक्षा परिषद ने की जिसे महासभा ने 3 मर्तो क विरुद्ध 46 से पास किया पर महासभा साधारण बहुमत से ही इस पास कर सकती थी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि डम्बरटन आक्स के सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव सुचाया था कि महासचिव के पद के लिए छोटे राष्ट्रों से ही उम्मीदवार लिये जाय यद्यपि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया परन्तु व्यवहार में यही परम्परा पड़ गई। त्रिगवली के बाद शीत युद्ध के काल में उन्हें दुबारा कायकाल मिलना अधिक कठिन हो गया और वे अपना दूसरा कायकाल पूरा नहीं कर पाय। और उनकी पुन नियुक्ति न करके उनके कायकाल को 14 राष्ट्रों के प्रस्ताव के अनुसार 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। पर जब ली ने कोरिया युद्ध के दौरान सन 52 में इस्तीफा दे दिया तो उनका उत्तराधिकारी की खोज में तत्काल राष्ट्रों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और तब डाग हेमरशाल्ड को सुरक्षा परिषद ने प्रस्तावित किया जो अपना काय भार अधिक प्रभावशाली ढंग से चला सके और उनकी निष्पक्षता अधिक मान्य ठहरी। फलस्वरूप उनकी पुननियुक्ति की सन्तुति में वह अडचन नहीं पड़ी जो ली के बारे में हुआ था। डाग हेमरशाल्ड काफी सफल महासचिव सिद्ध हुए यद्यपि कांगो कायवाही के दौरान वह रूसी पक्ष में लोकप्रिय नहीं रह गये पर भारत समेत सभी विलग्न और तत्काल राष्ट्रों का उन्हें सदा ही भरपूर सहयोग मिला। उनकी हवाई दुर्घटना में 18 सितम्बर, 1961 को मृत्यु हो गई। तत्काल ही उनके उप महासचिव को कार्यकारी महा सचिव बना दिया गया। यह वह समय था जबकि रूस अपने महासचिव टोइका 'प्रस्ताव पर जोर दे रहा था जिसके अनुसार एक महासचिव की जगह तीन महा सचिवों का मण्डल सुचाया गया था। हेमरशाल्ड की मृत्यु के बाद रूस ने फिर सुझाया कि 4 अनुसचिवों का एक निर्देशक मण्डल नियुक्ति किया जाय जिसमें एक को उसका अध्यक्ष चुन लिया जाय और बारी बारी से वे अपने अध्यक्ष चुनते रहें। इससे नई नियुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पर अन्य सदस्यों ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। फिर रूस और अमेरिका अतिरिक्त नियुक्ति के लिए राजी हो गये और इस प्रवृत्ति के लिए भी सहमत हुए गये कि अतिरिक्त महासचिव

की सहायता के लिए 4 या 5 अनुसचिव नियुक्ति किये जाय जिनसे महासचिव अपनी इच्छानुसार परामर्श कर सकें वर्मा के प्रतिनिधि यू. थाट के नाम पर सहमत हो गयी पर यू. थाट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि पांच अनुसचिव उस तरह से नियुक्त किये जाएँ जैसा रूस अमेरिका ने प्रस्तावित किया है अर्थात् एक-एक अनुसचिव अमेरिका, रूस, लातिनी अमेरिका अफ्रिका का हो और महासचिव एशिया का। अतः मे रूस और अमेरिका इन अनुसचिवों की नियुक्ति यू. थाट पर छोड़ने को राजी हुए और उन्होंने सचिवालय में कार्य करने वाले पांच व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त कर दिया। साथ ही शपथ ग्रहण करने के बाद अपने कार्य में सहयोग के लिए कुछ परामर्श दाताओं के चुनने की बात कही जो सचिवालय के बाहर के भी हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले अमेरिका के राल्फ ब्रूच और रूस के जाज जी, आकदेव नियुक्त हुए। अपने अंतरिम काल को सफलता पूर्वक व प्रभावशाली ढंग से निभाने के बाद उन्हें 3 नवम्बर, 1962 को सुरक्षा परिषद की सत्सुति होने पर 4 वर्ष के लिए महासचिव नियुक्त कर दिया गया। यू. थाट ने अपना कार्यभार हेमरशोल्ड से भी अधिक सफलता के साथ निभाया। वे बहुत ही लोकप्रिय महासचिव सिद्ध हुए। उनकी निष्पक्षता, सरल हृदयता और कार्यकुशलता की घाफ जम गई पर वे दूसरे कार्य काल के लिए अनिच्छुक रहे और ऐसी अनिच्छा उन्होंने पहले ही प्रकट कर दी थी। परन्तु बड़े और छोटे, विलग्न और मलग्न राष्ट्रों के अत्यन्त आग्रह पर यू. थाट पुनः पांच वर्ष के लिए कार्यभार संभालने को राजी हो गये। इस कार्य काल के समाप्त होने पर फिर यह समस्या उठी और उनके उत्तराधिकारी की खोज होने लगी। यह उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों की सूची में प्रायः सभी नाम तटस्थ या विलग्न राष्ट्रों के थे और अतः में, उत्तराधिकारी के रूप में कुतः वालधेम चुने गये जो यूरोप के तटस्थ राज्य आस्ट्रिया के नागरिक हैं। वालधेम यू. थाट के योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हो रहे हैं और उन्होंने अपनी निष्पक्षता निमयता और सहकारिता भावना की एक अच्छी छाप संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों पर छोड़ी है। विद्यतनाम, बांग्लादेश, पश्चिम एशिया में अरब इजरायली युद्ध, ईरान ईराक युद्ध ऐसी अनेक विस्फोटक स्थितियों में वालधेम ने एक प्रभावशाली और सहत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

महासचिव के कार्य संयुक्त राष्ट्र सभ में महासचिव का पद बड़े महत्व का सिद्ध हुआ। प्रारम्भिक आयोग में महासचिव के निम्नांकित कार्य बताये हैं

- (1) सामान्य प्रशासन तथा कार्यकारी कार्य,
- (2) प्राविधिक कार्य,
- (3) वित्तीय कार्य,
- (4) सचिवालय संगठन एवं प्रशासन,
- (5) प्रतिनिधित्व का कार्य,

(6) राजनीतिक काय ।

(1) सामान्य प्रशासन तथा कायकारी काय 'चाटर' के अनुसार महा सचिव समुक्त राष्ट्र सभ का मुख्य प्रशासन अधिकारी है। वही सभ और उसके सदस्यों के बीच सम्पर्क-मूलक का काम करता है। समुक्त राष्ट्र सभ और उसके अंग और अभिवरणों तथा सभ के सदस्यों के बीच सारा पत्र व्यवहार उसने माध्यम से होता है। इस दृष्टि में वह एक सुनहली कड़ी है जो सभ को उसके विविध अभिवरणों में जोड़ती है महा सचिव ही सभ के सभी अंगों के निणयों को कार्यान्वित करने, उन्हें परस्पर समन्वय करने की व्यवस्था करता है। वह सभ के आर्थिक कायक्रमों को विरसित करने में सागु करने के लिए तथा उनमें तालमेल बैठाने के लिए मुख्य भूमिका अदा करता है। पारस्परिक हितों के कारणों के सम्बन्ध में आर्थिक व सामाजिक परिपद के अनुरोध पर उसने एक सहायक समिति गठित कर ली है जिसका वह प्रधान होता है तथा अभिवरणों के प्रशासनिक अधिकारी उसके सदस्य होते हैं।

वह सुरक्षा परिपद की बैठक में महा सचिव की तरह स्वयं भाग लेता है और महासभा की प्रतिया नियमावली के अन्तर्गत वह या उसका प्रतिनिधि महा सभा में भाग ले सकते हैं और लिखित या मौखिक वक्तव्य दे सकते हैं। वह महा सभा को सभ के कार्यों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन या रपट देता है। गुडरिच और हैम्प्री के अनुसार इस अनुच्छेद के अन्तर्गत (97) महा सचिव को इतने विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं कि दूसरे अनुच्छेदों के अन्तर्गत काय भी उसमें समा जाते हैं। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे दो प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं

(1) प्रशासनिक एवं प्राविधिक काय सम्बन्धी ।

(2) वह काय जिन्हें वह अपने विवेकाधीन अधिकारों से करता है।

पहले प्रकार के काय के अन्तर्गत निम्नांकित बातें आती हैं

(1) नियमानुसार विशेष अधिवेशन आमन्त्रित करना,

(2) सदस्यों को सूचनाएं भेजना,

(3) बैठकों की कार्यवाही रखना,

(4) वक्ताओं की नियुक्ति करना और उन्हें काय सम्बन्धी निर्देश देना,

(5) वक्तव्य, प्रतिवेदन, प्रस्ताव, दस्तावेज आदि छपवाना, अनुवाद करवाना तथा उन्हें सभाल कर रखना ।

(6) चाटर के अन्तर्गत अन्य निर्धारित कार्यों को करना तथा महा सभा सुरक्षा परिपद द्वारा घाति एवं सुरक्षा परिपद सम्बन्धी कामवाही करने या उसे सुरक्षा परिपद से हटाये जाने की महा सभा को सूचना देना ।

दूसरे प्रकार के कार्यों के अन्तर्गत वह निम्न काय करता है

(1) महा सभा, सुरक्षा परिषद, यास परिषद तथा आर्थिक व सामाजिक परिषद की अंतरकालीन कार्य सूची तैयार करता है तथा उन सूचनाओं को भी उनमें शामिल कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है।

(2) महा सचिव को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यह प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 99 के अंतर्गत ऐसे मामलों की सूचना सुरक्षा परिषद को देता है या सुरक्षा परिषद का ध्यान उन मामलों की ओर आकृष्ट कर सकता है जिसमें वह अपने विवेकानुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरनाक समझे। ऐसे अधिकार पुराने राष्ट्र संधि के महा सचिव को प्राप्त नहीं थे।

संधि के अग्रा के समक्ष अपने लिखित या मौखिक वक्तव्यों के द्वारा या जिस तरह से वह स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं उसके द्वारा वे राष्ट्र संधि के विविध अंगों की कार्यवाही को प्रभावित करते हैं। महा सचिव का यह भी काम माना जाता है कि वे प्रतिनिधियों के सदस्यता के परिचय पत्रों की जांच करें। चीन की साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद नये प्रतिनिधि की नियुक्ति पर त्रिग्वेली ने सुरक्षा परिषद को अपनी सम्मति से परिचित कराया। सन 1956 में हंगरी और सन 1958 में ईराक के प्रतिनिधि के नियुक्ति के सवाल पर भी महा सचिव ने पहले अडगा लगाया पर फिर स्थिति बदलने पर नई नियुक्तियों का मायता दे दी।

(2) प्राविधिक कार्य महा सचिव इसके अंतर्गत उन सभी सवालों का अध्ययन करवाता है, प्रतिवेदन बनवाता है, टिप्पणियाँ व सर्वेक्षण करवाता है जो महा सभा के समक्ष लाये जाते हैं। महा सचिव संधि के सदस्यों तथा संधि के अग्रा को अपनी विशेषज्ञता की सेवा का लाभ पहुँचाता है। वह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अनुरोध पर विकासशील देशों की आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए समस्याओं का अध्ययन तथा उसके सम्बन्ध में समाधान खोजने का प्रयत्न करता है।

इस परिषद के अनुरोध पर महा सचिव ने सचिवालय के अंदर एक सांख्यिकीय इकाई का गठन कर रखा है जिसका काम है हर तरह की सूचनाएँ इकट्ठी करना, उनकी परीक्षा करना, उनका समीक्षात्मक रूप रखना तथा विशिष्ट अभिवरणों की ऐसी ही सांख्यिकीय कार्यवाहियों का समन्वय करना। सचिवालय का अपना एक सूचना कार्यालय है जिसकी शाखाएँ सप्ताह के लगभग 40 केंद्रों में स्थापित हैं जो सूचनाएँ इकट्ठा करती हैं और वितरित करती हैं। यही कार्यालय संधि के कार्यवाहियों तथा प्रतिवेदनों की छपाई के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय कार्य महा सचिव के जिम्मे वित्तीय प्रशासन भी सौंप गया है। वह महा सभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत तथा उससे सम्बंधित नियमों के अधीन संधि के आय-व्यय तैयार करने, धन के वितरण, खर्च के नियंत्रण, सदस्यों के धन

एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन सेवा का उदघाटन किया गया है। यद्यपि व्यवहार में अनेक बार सदस्य राष्ट्रों के राजनीतिक अध्यक्षों ने सचिवालय में काम कर रहे अपने नागरिक कर्मचारियों को सचिवालय से हटाने में और इस तरह उसमें लगाने में सफल हस्तक्षेप किये हैं।

राजनीतिक कार्य महासचिव केवल एक प्रशासकीय अधिकारी ही नहीं है बल्कि, अनुच्छेद 99 महासचिव को राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करता है। इसीके अंतर्गत वह किसी भी ऐसी विस्फोटक राजनीतिक परिस्थिति की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान कभी भी आकृष्ट कर सकता है जो उसकी दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल रही हो। ऐसा अधिकार पुराने राष्ट्रसंघ के महासचिव का नहीं प्राप्त था। इस अधिकार के अंतर्गत महासचिव का दर्जा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की तरह हो जाता है जो उस अनहोनी स्थिति में जबकि सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी एक विशेष खतरे के बारे में प्रश्न न उठाना चाहे तब अपनी जबदस्त भूमिका निभाते हुए महासचिव उस मामले को सुरक्षा परिषद में ला सकते हैं अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। वैसे महासचिव को ऐसा अधिकार महासभा के बारे में नहीं प्राप्त है। परंतु प्रक्रिया नियमावली के नियम 62 के अंतर्गत वह लिखित वक्तव्य देकर या मौखिक रूप से अपनी ओर स समस्या उठा सकता है तथा अपने वार्षिक प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख कर सकता है यथा सन 1965 से यू.एन. ने वियतनाम की स्थिति के सम्बन्ध में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा था कि वहाँ पर सैनिक कार्यवाही के द्वारा शांति नहीं स्थापित हो सकती है और उस समस्या का समाधान केवल वार्तालाप के द्वारा ही हो सकता है—इत्यादि।²³

महासचिव का बढ़ता हुआ राजनीतिक प्रभाव

वस्तुतः प्रारम्भ से ही महासचिव को राजनीतिक प्रभाव के बढ़ने का द्रम शुरू हो गया था। प्रथम महासचिव त्रिगवेली ने शीत युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति में अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करना शुरू किया था यथा ईरान की शिकायत के बारे में उसे सुरक्षा परिषद की कार्य सूची से हटाए जाने पर उन्होंने एक कानूनी प्रतिवेदन करवाया था जिसमें यह सुझाव था कि सुरक्षा परिषद का यह कदम ग्राह्य-मगत था। इसी प्रकार फिलिस्तीन के मामले को मुलद्दाने में उनका प्रयास चला। 1950 में साम्यवादी चीन को संघ की सदस्यता प्रदान किए जाने के बारे में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ उसे दूर करने में भी उनकी भूमिका यद्यपि सफल नहीं हुई पर उन्होंने प्रभाव डाला।²⁴ उन्होंने यह सुझाया था कि सुरक्षा परिषद इस बात की जांच कराय कि चीन की कौन सी सरकार संघ के दायित्वों के पालन करने में समर्थ है। कोरिया में युद्ध की स्थिति होन पर कोरियाई आयोग

दान की वसूली और सच के धन की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह सच क आय-व्यय की प्रशासकीय एवं आय-व्यय परामर्शीय समिति द्वारा जांच के लिए महा सभा की पंचम समिति को विचाराय सौंपता है और उसके बाद महा सभा की स्वीकृति के लिए सौंपता है। महा सभा में भी वह आय-व्यय को पारित कराने में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। इसी प्रकार विविष्ट अभिकरणों के आय-व्यय के सम्बन्ध में विचार विमर्श करता है और निर्धारित समझौते के अनुसार इस महा सभा के सामन प्रस्तुत करता है (दिसम्बर 1961 में महा सचिव ने स्थायी सदस्यों को सूचित किया कि सच दिवालिया हान जा रहा है और वह अपने वार्य संचालन के लिए 25 वर्षीय 2 प्रतिशत व्याज पर समुक्त राष्ट्र सचय बाड़ा को राष्ट्रीय कार्यलयों एवं राष्ट्रीय बैंकों को बेचने के लिए तैयार है और महा सचिव 200 लाख डॉलर के बांड बेचे जाने के लिए महा सभा को राजी करन में सफल हुए तथा 150 डॉलर मूल्य के बांड उठाने के लिए भी। इस प्रकार आय-व्यय सम्बन्धी कार्यों में महा सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आये हैं। अनेक शांति स्थापना के कार्यों में सच के बारे में जो कठिनाइयाँ समय समय पर उठीं उन्हें हल करने में महासचिव ने अपने प्रभाव का अच्छा उपयोग किया।

सच के प्रतिनिधि के रूप में महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सत्त्वा का प्रतिनिधित्व करता है। वही सच क अतगत सच की ओर स पत्र व्यवहार करता है राजनयिकों का स्वागत करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यायालय में सच का प्रतिनिधित्व करता है सदस्य राष्ट्रों के प्रधान जब कभी समुक्त राष्ट्र सच क मुख्यालय में आते हैं तो वही उनका स्वागत करता है। सच की ओर से राष्ट्रों को बधाई और शोक संवेदना भी उसके ही माध्यम से की जाती है। सच की ओर से सविदाओं पर वही हस्ताक्षर करता है। सच के प्रतिनिधि के रूप में महीने में एक बार वह पत्रकार सम्मेलन बुलवाता है।

सचिवालय संगठन एवं प्रशासन समुक्त राष्ट्र सच के अनुच्छेद 101 में महासचिव को मह अधिकार दिया गया है कि वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन योग्यता दक्षता क्षमता सत्यनिष्ठा तथा विस्तृत भोगों लिक बितरण को ध्यान में रखकर सचिवालय के कमचारियों की नियुक्ति करेंगे। इन नियुक्तियों में सच के अय अगो के कमचारी भी शामिल हैं। ये सारे कमचारी महासचिव के निर्देश में रहते हैं। अनुच्छेद 100 में यह प्रावधान किया है कि महासचिव व उसके कमचारी अपने कर्तव्य के निर्वाह में न तो किसी सत्ता के आदेश को मानेंगे न प्राप्त करेंगे। और न वे ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे उनके अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी होने या केवल सच के प्रति उत्तरदायी होने की भावना पर कोई आघात पहुँचेगा। महासचिव को ही सचिवालय के निर्देशन में संचालन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है और सभी कमचारी उसके अनुशासन रहते हैं। इस तरह

एक वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालन सेवा का उदघाटन किया गया है। यद्यपि व्यवहार में अनेक बार सदस्य राष्ऱ के राजनीतिक अध्यक्षा ने सचिवालय में काम कर रहे अपने नागरिक कर्मचारियों को सचिवालय से हटाने में और इस तरह उसमें नगाने में सफल हस्तक्षेप किये हैं।

राजनीतिक बाध महासचिव केवल एक प्रशासकीय अधिकारी ही नहीं है बल्कि, अनुच्छेद 99 महासचिव को राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करता है। इसीने अतगत यह तिसी भी ऐसी बिस्फोटक राजनीतिक परिस्थिति की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान कभी भी आकृष्ट कर सकता है जो उसकी दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गतरे में डाल रही हो। ऐसा अधिकार पुराने राष्ऱसभ के महासचिव का नहीं प्राप्त था। इस अधिकार के अतगत महासचिव का दर्जा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की तरह हो जाता है जो उस अनहोनी स्थिति में जबकि सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी एक विशेष त्वतरे के बारे में प्रश्न न उठाना चाहे तब अपनी जबदस्त भूमिका निभाते हुए महासचिव उस मामले को सुरक्षा परिषद में ला सकते हैं अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। वैसे महासचिव को ऐसा अधिकार महासभा के बारे में नहीं प्राप्त है। परंतु प्रक्रिया नियमावली के नियम 62 के अतगत वह लिखित वक्तव्य देकर या मौखिक रूप से अपनी ओर से समस्या उठा सकता है तथा अपने वार्षिक प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख कर सकता है यथा सन 1965 संयुक्त राष्ट्र ने बियतनाम की स्थिति के सम्बंध में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा था कि वहां पर सैनिक बाधवाही के द्वारा शांति नहीं स्थापित हो सकती है और उस समस्या का समाधान केवल वार्तालाप के द्वारा ही हो सकता है—इत्यादि।¹²

महासचिव का बढ़ता हुआ राजनीतिक प्रभाव

वस्तुतः प्रारम्भ से ही महासचिव को राजनीतिक प्रभाव के बढ़ने का क्रम शुरू हो गया था। प्रथम महासचिव रिगबेली ने शीत युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति में अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करना शुरू किया था यथा ईरान की शिकायत के बारे में उस सुरक्षा परिषद की कार्य सूची से हटाये जाने पर उन्होंने एक कानूनी प्रतिवेदन करवाया था जिसमें यह सुझाव था कि सुरक्षा परिषद का यह कदम ग्राह्य मंगत था। इसी प्रकार फिलस्तीन के मामले को सुलझाने में उनका प्रयास चला। 1950 में साम्यवादी चीन को सच की सदस्यता प्रदान किय जाने के बारे में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ उसे दूर करने में भी उनकी भूमिका यद्यपि सफल नहीं हुई पर उन्होंने प्रभाव डाला।¹³ उन्होंने यह सुझाव भी कि सुरक्षा परिषद इस बात की जांच कराए कि चीन की कौन सी सरकार सच के दायित्वों के पालन करने में समर्थ है। कोरिया में युद्ध की स्थिति होन पर कोरियाई आयोग

स प्रमाणित करा कर उन्होंने दक्षिण कोरिया पर तथान्वित उत्तर कोरिया के हमले की सूचना सदस्यों में फैलाई (महासभा में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी यह वायदाही अनुच्छेद 99 के अंतर्गत की गई थी) यही स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन के नाक बंदी दूर कराने के बारे में दोनों पक्षों की बातचीत के लिए राजी कराने में उनकी भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति स्थापित करने के सम्बन्ध में उन्होंने एब 10 सूत्रीय 20 वर्षीय कार्यक्रम की भी पोषणा की थी। जिसे महासभा ने अपने पंचम अधिवेशन में 5 के विरुद्ध 51 मतों से स्वीकार किया था और महासचिव के वायदा सराहा था।

हम प्रकार प्रथम महासचिव के कार्यकाल में राजनीतिक महत्व की जिम्मेदारी का दायरा त्रिगुणित ने काफी बढ़ा दिया था पर इस प्रक्रिया में वे शीत युद्ध की राजनीति के शिखार हो गये और उनसे विरुद्ध साविमल नेमों का लगातार विरोध उनके पुनर्निर्वाचन में अवदस्त दीवार बनकर खड़ा हो गया। उनके उत्तराधिकारों स्वीडन के हाग हैमरगोल्ड इस अर्थ में उनसे कहीं अधिक सफल महासचिव सिद्ध हुए क्योंकि जहाँ उन्होंने अपने पूर्ववर्ती की तरह राजनीतिक प्रभाव का काफी उपयोग किया और महासचिव के पद की गरिमा और क्षमता को काफी बढ़ाया वहाँ अपने पूर्ववर्ती से अधिक कूटनीतिक चातुर्य गहरी सूझ बुझ और व्यापक सहानुभूति का परिचय भी दिया। उन्होंने महासचिव के बड़त हुए उत्तरदायित्व और क्षमता के दृढ़ स्तम्भों का निर्माण किया और इन दृढ़ स्तम्भों के निर्माण में उन्होंने तटस्थ और विलग्न राष्ट्रों के योगदान का अधिकाधिक प्रयोग किया। इससे व अल्पकाल में ही एशिया, अफ्रिका के पुराने और नवोदित तटस्थ और विलग्न राष्ट्रों के अल्पकाल में ही भाजन बन गये। इनके ही सहानु के शीत युद्ध के बड़े ताकतों के दाव पैदा से अपने को बचाने में समर्थ बन सके। यह कहा जा सकता है कि महासचिव के तथा सच की अधिशासी वर्तमान शक्ति की उन्होंने ही सही माने में प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी यह धारणा थी किम उन्होंने अपनी 1961 के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकट भी किया था कि जब 'चाटर' का निर्माण हुआ था उस समय संयुक्त राष्ट्र सच का स्वरूप एब अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन रूपों स्थापन की तरह था जो क्रमिक विकास कर अब सचदीय सम्मेलन के रूप में हो गया है। जब 'चाटर' बना था उसमें अधिशासी प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत ही कहा गया था क्योंकि तत्काल सच का संगठन सम्मेलनात्मक भावना पर टिका हुआ था परन्तु बदली हुई परिस्थिति में यदि सच की विश्व जनमत की भावना तथा 'चाटर' में दिये हुए अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य करना है तो सच को अपने अधिशासी प्रणाली को विकसित करना होगा।

सदस्य

- 1 शूमा - इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, प० 207
- 2 देखिए केलसन का लेख जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स 134 59
समिति (1) के अंतर्गत हुए विवचन में यह स्वीकारा गया है कि प्रस्तावना, उद्देश्य (अनुच्छेद 1) और सिद्धांत (अनुच्छेद 2) में स्पष्ट अंतर निर्धारित करना कठिन है।
- 3 इसमें सोवियत संघ के दो गणराज्य बाइको रक्षा तथा यूक्रेन भी शामिल किए गये हैं। फ्रांको स्पेन के प्रवेश में पहले तो बड़ा अड़गा डाला गया लेकिन शीत युद्ध के चलने के बाद फ्रांकोस्पेन अमेरिकी राजनीति का मोहरा बन गया और उसका प्रवेश आगमल अमेरिकी गुट में आसान बना लिया।
- 4 सियांग एडमोशन ऑफ इंडियन स्टेट टु यू एन, 43 अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्टरनेशनल लॉ कहा गया कि यह युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टि में रखकर संस्थापकों (प 133 144, 154) ने पराधीन रहते हुए भी भारत को मूल सदस्यों की सूची में रख लिया।
- 5 शूमा, वही प
- 6 गुडरिच एव हेम्ब्रो (कमेटी ऑन यू० एन० चार्टर 1949, पृ० 41)
- 7 वही, पृ० 144
- 8 हीअरिंग बिफोर दि कमेटी ऑन फारिन रिलेशन ऑन दि यू० एन० चार्टर जुलाई 2 1945, प० 237
- 9 यू० एन० सी० आई० ओ० वरबेटिम मिनिट्स आदि पृ० 8, डाक्यूमेंट 8, पृ० 619
- 10 हीअरिंग बिफोर वही, पृ० 237
- 11 राष्ट्रसंघ के विधान में संशोधन के लिए सभी सदस्य राज्यों की सहमति जरूरी थी।
- 12 सन् 1961 में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में हेमरसोल्ट ने यह कहा।
- 13 गुड स्पीड, नेचर एंड फक्शन ऑफ इन्टरनेशनल आगनाइजेशन 1967
- 14 पान अधिवेशन अब तक बुलाये जा चुके हैं। पहला फिलिस्तीनी समस्या पर सन 1947 में दूसरा इसी समस्या पर सन 1948 में तीसरा हंगरी की स्थिति पर सन 1956 में, चौथा सन 1963 में संघ के आर्थिक सत्र पर, पांचवां मई 1967 में दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सरक्षित प्रदेशों के प्रशासन के हस्तांतरण पर विचार करने के लिए बुलाया।
- 15 राष्ट्र संघ के आर्थिक कार्यक्रमों पर टिप्पणी करते हुए लियोनाड ने लिखा है कि लगभग 20 वर्षों में ही सरकारें अपवाकृत समान आर्थिक व

वित्तीय समस्याओं के दृष्टिकोण से असंग-यलग रहने की नीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अत्यधिक सहयोग की नीति पर आ गए हैं। इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समाज की बाय सूची में इतने अधिक आर्थिक प्रश्न चुगी मदी बच्चे माम की प्राप्ति के साधन—वित्तीय पुनर्निर्माण इत्यादि रसे गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में योजनायें बनायी गई हैं अथवा ठोस नीतियां सामने आई हैं तो भी वह बहुत महत्वपूर्ण था कि उनमें द्वारा स्थापित किये।

16 दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका भी एक समादेशित प्रदेश था जो दक्षिण अफ्रीका के शासनात्मक रखा गया था। 'यास' व्यवस्था बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने इसके सम्बन्ध में समझौता करने से इन्कार कर दिया। महासभा के लगातार आदेशों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका इस सम्बन्ध में विरोध ही करता रहा। अंतर्राष्ट्रीय 'यायालय' को मामला सौंपा गया तो 'यायालय' ने सम्मति दी कि दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न को 'यास' पद्धति में रखने के लिए बाध्य नहीं पर उसका कतम्य है कि वह इस क्षेत्र में सम्बन्ध में बायिक प्रतिवेदन देता रहे और यहाँ के निवासियों की याचिकाएँ महासभा को भेज तथा सयुक्त राष्ट्र सच को इस प्रश्न में निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। 1965 में अपने निणय में 'यायालय' ने महासभा के इस अधिकार को भी माना कि वह मौलिक याचिकाएँ भी सुन सकती हैं। पर दक्षिण अफ्रीका ने इन सबको सुना अनसुना कर दिया।

17 स्वेच्छा से प्राप्त 'यास' प्रबन्ध के मामले में पश्चिमी ईरियान का क्षेत्र कुछ समय के लिए रखा गया था। महासभा के दूसरे अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव रखा था कि अस्वशासी प्रदेश समझौते के द्वारा स्वच्छा पूर्वक 'यास' व्यवस्था के अंतर्गत रखे जाय और यह आशा प्रकट की कि ऐसे प्रदेशों के प्रशासक राष्ट्र उक्त समझौते का प्रारूप प्रस्तुत करेंगे। यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया गया लेकिन बाद में महासभा में यह आपत्ति उठायी गई कि इस दो तिहाई बहुमत से नहीं पास हुआ। बाद में फिर मतदान हुआ और उसमें बराबर बराबर मत पडने से यह प्रस्ताव ना पास हो गया।

18 गुमा -इंटरनेशनल पोलिटिकल लिगवट गुरे के अनुसार यह समादेशित व्यवस्था का एक संशोधित और विकसित रूप है जबकि जनरल स्मट्स ने (दक्षिण अफ्रीका के) इसे समादेशित व्यवस्था से अधिक व्यापक बताया है। सयुक्त राष्ट्रसच के प्रथम महासचिव त्रिगवेली के अनुसार सचारा में यह पहला अवसर था जबकि सरकारी प्रतिनिधियों की एक अंतर्राष्ट्रीय स्थायी समिति केवल पिछड़े हुए लोगों की भलाई के नाय के लिए गठित की गई।

- 19 'यास परिषद के प्रथम अध्यक्ष जी० समरे न कहा था 'जब तक एशिया और अफ्रीका में पिछड़े हुए प्रदेश हैं, हम स्थायी शांति की नींव का अभाव रहेगा 'यास व्यवस्था पिछड़े हुए लोगों में ऐसी क्रांति की प्राप्ति का 'याव हारिक यव प्रदान करती है ।
- 20 सिच वेविल स्टीफेस दि एस० जी० आर्चिडि यू० एन० 1952 प० 19
- 21 प्रथम महासचिव त्रिगवली ने अपने इस राजनीतिक अधिकार का काफी उपयोग व दुरुपयोग किया यथा ईरान की शिवायत के बारे में या फिलस्तीन के प्रश्न को सुधान के लिए व 1950 में साम्यवादी चीन की सघ की सदस्यता के प्रश्न पर जिम में उन्होंने सुझाया—सुरक्षा परिषद इस बात की जांच कराए कि चीन की कौन सी सरकार सदस्यता के दायित्व का पालन करने में समर्थ है । कोरिया के बारे में महासचिव ने अपने राजनीतिक अधिकार का दुरुपयोग करते हुए दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया की तथाकथित आक्रमण की सूचना की पुष्टि कोरियाई आयोग से कराकर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई ।
- 22 'The people of China have a constitutional right under the charter to be represented by the government that has power to be representative there of '
- 23 उस दस सूत्री कार्यक्रम में अनेक प्रमुख बातें थी ।

नई लड़ाई की शुरुआत । एक ठण्डी लड़ाई ; शीत युद्ध

1945 का साल बीतने नहीं पाया कि दूसरा विकराल महायुद्ध समाप्त हो गया । जैसा हम बता चुके हैं, पहले यूरोप के मोर्चे पर नाजी और फासी शक्तियाँ पराजित हुईं, फिर जापान पर दो परमाणु बम के गिरते ही उस मोर्चे में भी लड़ाई खत्म हो गई और जापान ने अमरीकी सेना के आगे घुटने टेक दिए । सभी मोर्चों पर इस प्रकार लड़ाई ठण्डी पड़ गई । कुछ समय तक मित्र राष्ट्रों में युद्धकालीन मंत्री और पारस्परिक सहयोग का भाव बना रहा । इस बीच यूरोप के पराजित देशों (जर्मनी और आस्ट्रिया को छोड़कर) के साथ राष्ट्रों ने सदभावपूर्ण ढंग से सधिया सम्पन्न की और फिर लोगो ने देखा कि मित्र राष्ट्रों के बीच एकता और मैत्री के भावों में जैसे एक झटके में ही दरार पड़ गई हो । मित्रता के स्वर तेजी से अमैत्री और अमंगल सूचनाएँ स्वरो में बदल गये । लड़ाई ठण्डी पड़ी नहीं कि जैसे एक ठण्डे ढंग की लड़ाई का शखानाद सुनाई पड़ने लगा ।

नई दुनिया में सद्भाव

दूसरे महायुद्ध ने मूलाप की कमर तोड़ कर रख दी । वह यूरोप जहाँ से व्यापारी और पादरी व्यापार और धर्मप्रचार के नाम पर समुद्र पार कर एशिया और अफ्रीका तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में पहुँचे थे और जो इनकी विजय बहुत ही बजाता सारी दुनिया की अव्यवस्था और राजनीति का नेत्र बन गया था, अपना ऐतिहासिक वक्षस्व खो बैठा । सरदार पणिकर के शब्दों 'याम्को दिगात्मा' युग का अन्त हो गया, पश्चिमी साम्राज्यवाद का लगभग पूर्ण अवसान ।

मदिरा से चली आ रही निम्न शोषण व्यवस्था अन्तिम महायुद्ध की लड़ाई की भेंट हो गई और अन्तराष्ट्रीय राजनीति का यूरोपीय दृष्टि केन्द्र टूट-टूट कर

खिखरता गया। यह कोई आकस्मिक घटना न थी। विचारवान लोग एशिया व अफ्रीका में इस प्रकार के अत की भविष्यवाणी कर चुके थे, 'भारत छोड़ो' आन्दोलन इसकी ही एक सबल अभिव्यक्ति था। एक संवदनशील भारतीय नेता, जवाहर लाल नेहरू ने अपने ग्रंथ 'विश्व इतिहास की झलक' के अंतिम प्रकरण में लिखा था

'इंग्लैंड जो इतने दिनों से विश्व की अगुआ शक्ति था, अब अपनी पुरानी व सबसे ऊँची हैसियत खो चुका है और जो कुछ बचा है, उसे कायम रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है।'²

वस्तुतः साम्राज्यों के विघटन की प्रक्रिया प्रथम महायुद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी जिसने यूरोपीय साम्राज्यों की चूल्हे हिला दी। तुर्की आस्ट्रीया, हंगरी और जारशाही रूस पूरी तरह विघटित हो गये थे। जर्मनी का साम्राज्य तो नष्ट कर दिया गया और कुछ छीन लिया गया। युद्ध अपराधी ठहरा कर जर्मनों को भारी दण्ड दिया गया, उनके प्रदेश छीन गये और हरजान के लिए बाध्य किया गया जिसने उसकी कमर तोड़ दी और एक भयानक कुवड़े नाजीवाद का जन्म लेन दिया गया।

न केवल यूरोप में साम्राज्यों की ऐसी दुर्गति हुई बल्कि, विजयी और पराजित यूरोपीय साम्राज्यों के उपनिवेशों में भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वाधीनता के आन्दोलनों की आग लग गई। एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता के आन्दोलनों की हलचल न जक्तूबर 1918 के विस्फोट के द्वारा लाय गए भूकम्प के द्वारा हिलाई जा रही साम्राज्यी व्यवस्था का डबाडोल कर दिया।

दो महायुद्धों के अंतराल का समय ही वह समय है जबकि एशिया अफ्रीका के लोगों के मन साम्राज्यवादियों के मायाजास से बाहर निकलने के लिए छटपटान लगे। यही वह समय है जबकि ब्रितानी राजभक्त केसर हिन्द मंडल से विभूषित गांधी जलमयानावाला बाग के नृशंस कांड का खिलाफन सजा कर अपने ढंग का एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर भारत के लोगों को विद्रोह के रास्ते पर लाने की चेष्टा करते हैं। यही वह समय है जबकि पश्चिम के तब तक वे प्रशंसक सुनघात सेन चीन के लोगों का समझता है कि पश्चिमी साम्राज्यवादियों से किसी भी तरह के सद्व्यवहार की आशा करना व्यर्थ है। यही वह समय है जबकि पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी स्वाधीनता के आंदोलन जार पकड़ने लगते हैं और सोवियत क्रांति और समाजवादी विचारों के प्रभाव का विस्तार एशिया में तेजी से होने लगता है और जगह जगह साम्यवादी दलों का गठन राष्ट्रवादी स्वाधीनता आंदोलन के अंदर एक 'घटक' के रूप में और उससे बाहर स्वतंत्र

रूप से भी गठित होकर अपने विषयव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का अंग बनता है।

एशिया में हम इसी अन्तरास में एशिया की एकमात्र साम्राज्यवादी शक्ति जापान का अपने घिनौने साम्राज्यवादी विस्तार के अभियान के द्वारा एशियाई मुक्ति आंदोलन के स्वस्थ वातावरण को गंदसा करते पाते हैं जो परोक्षतः साम्राज्यवाद विरोधी एक बृहत्तर मार्च के निर्माण में और सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वस्तुगत दृष्टि से समझने में एशियाई लोगों को बड़ी मदद देता है। जापान एशिया का होन हुए भी अपना नहीं था, नास्तिकारी रुम और यूरोप का जाघत मजदूर वर्ग एशिया का अंग न हासत हुए भी किन्ना अपना बन गया था, इसकी समय बढ़ रही थी।

इसी वस्तुगत समझ में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की वह जिंदा निर्धारित करने में नेहरू और उनके साथियों की मदद की और दूसरी ओर इसके अभाव में सुभाष और उनके साथियों का मुक्ति आंदोलन से अलग चल पड़ जाने की भूमि तयार कर दी। 'अपने पराये का निणय अब जाति या नस्ल या रंग के आधार पर करना समझदारी की बात नहीं, उसका आधार 'वर्ग' था—चीन में सुनघात सेन और साम्यवादी इसी क्रांतिकारी विचार के बाहुक बन, हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रीय आंदोलन के अन्दर नेहरू के नेतृत्व में तथा उससे बाहर साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन के नेतृत्व के अन्तर्गत उभरने लगे—यह एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रदय के निर्माण की भूमिका बनाने लगा जिसके अन्तर्गत सबसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की समस्याओं की समझने और उन्हें मूलभूत में आसानी हल लगी। यही कारण था कि जब दूसरा युद्ध छिड़ा तब तक गांधी और नेहरू का बैसा ही हाल हो चुका था, जसा प्रथम महायुद्ध के बाद सुनघातसेन का हुआ था। पश्चिम के सभी साम्राज्यवादी और जापान एक ही पैसी के चट्टे-बट्टे तो थे। ब्रिटेन का विरोधी होकर न जर्मन साम्राज्यवाद अपना था, न जापानी साम्राज्यवाद। मुक्ति आंदोलन को यदि कहीं से भी मरिक्चित मदद की आशा बढ़ती थी, और वस्तुगत और मनोगत इस आशा का आधार उभरता दिख रहा था, तो वह यूरोप का एक मात्र बोल्शेविक क्रांति का केन्द्र था और यूरोप में उभरता जनवादी और समाजवादी आन्दोलन था।

अमेरिका की स्थिति फिर भी भिन्न थी

इस परिस्थिति में भी अमेरिका की ओर एशिया और अफ्रीका के जनवादी आन्दोलनों का नेतृत्व आशा भरी दृष्टि से देखत थे। लगता था कि वह यूरोपीय साम्राज्यवाद का जन्म न था। सातौं अमेरिका में वह क्या कर रहा था किसी

पाश्चात्य द्वीप समूह में उसकी क्या भूमिका थी, यह सब यहाँ दृष्टि से ओझल था। उसकी अलग ही राजनीति विकसित हो रही थी, जिसे यूरोपीय साम्राज्यवादी कोढ़ ऐसा लगता था, ने अभी तक छुआ नहीं था। वह राष्ट्रसंघ से अलग बना रहा। साम्राज्यवादी खुली धमाचौकड़ी में शामिल न होता हुआ, अपनी विकासशील औद्योगिक और व्यापारिक क्षमता का वह बढ़ाता चला जा रहा था। हम अत्यन्त स्पष्ट कर चुके हैं कि औद्योगिक शक्ति के रूप कैसे अमेरिका शीघ्र हो चुका था। लाकत व्रत का अभी भी वह एक गढ़ माना जा रहा था। प्रथम महायुद्ध में निर्णायक भूमिका अदा करने के बाद भी, वह नीतिज्ञा को छोड़कर अन्य 'सैनिक तत्व' के आधार को नहीं बना रहा था। 'सैनिक तत्वों' का जिस तरह का आसुरी बढ़ाव हिटलरी जर्मनी और साम्राज्यवादी जापान में उभर चुका था, उसके कारण भी अमेरिका की आरंभिक आशाभरी दृष्टि से देख रहे थे।

रूजवेल्ट का नया नेतृत्व

महामंदी की गहरी चपेट में आए हुए अमेरिका में जब रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति के रूप में 'नया कार्यक्रम' ('यूडीएल') चलाया जिसमें महामंदी से त्रस्त लोगों का कुछ कुछ राहत मिलान लगी, बरोजगारों को राजगार मिलान लगा और ठप्प पड़े बल कारखाने सरकारी मदद पाकर फिर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उठने लगे, इस रूजवेल्टी अमेरिका ने तब अमेरिका का एक नया रूप निखार दिया, एक असैनिक, लोक कल्याण कार्यों में तत्पर, अमेरिका एक ऐसा अमेरिका जो मंडोसिया के लिए भी भय का कारण नहीं रह गया जो घर में और बाहर भी, छोटे तबका, छोटे-छोटे लोगों और उनके समाज को सहारा देने का भरोसा दे रहा था। इस अमेरिका ने सावित्र्य की क्रांति को मायता देकर इस भाव को पुष्टि ही कर दिया कि अमेरिका, 'प्रति क्रांति' का न तो अड़डा था और न साम्राज्यवादी यूरोप का पश्चिम गालादीय विकसित संस्करण। द्वितीय महायुद्ध के शुरू होते समय अमेरिका की 'मलमल साहस वाली' यही भूरत उसे सभी के आकर्षण का केन्द्र बना रही थी। ब्रिटन और उसके साम्राज्यवादी मित्र इस अमेरिका को अपना सहारा मान रहे थे, तो हिटलरी जर्मनी मुसोलिनी की फासी इटली और स्पेन के गणतंत्र का विध्वंसक फ्रांका तक 'नकद दाँ और ले जाओ' नीति के अंतर्गत अमेरिकी शस्त्रागार का शस्त्रास्त्र खरीद रहे थे। अमेरिका इनका भी एक ढग से 'अपना' ही था—दाम चुका कर जा अपना पास नहीं उसे प्राप्त कर ला। यह अमेरिका मोवियत क्रांतिकारियों का भी मित्र बन रहा था। उन्हीं अथवा क्रांति को मायता दे दी थी और उसे अपने उद्योग घड़े विकसित करने में तकनीक और

पूजी की मदद भी देने लग गये। इस अमरीका से एशिया और अफ्रीका के जन-
 वाणी आ दोलन भी आशा लगाये बैठे थे। जापानी साम्राज्यवाद से आक्रांत
 जनवादी चीन अमरीकी सहायता की बात जोहता था तो भारत का राष्ट्रवाणी
 आदोलन भी आशाभरी दृष्टि से उस देखता था। पल हावर के बदरगाह पर अम-
 रीकी नौसना पर जब जापान ने बमबारी कर उस महायुद्ध में घसीट ही लिया
 तो अमरीका की यही नवतुमुखी क्षमता मित राष्ट्रों के लिए बरदान सिद्ध
 हुई। रूजवेल्ट के अमरीका ने विश्व राजनीति में इस तरह इतनी उड़ी साख
 बना ली थी। चीन को जापान के विरुद्ध लड़ाई में एक मन्थगार मिल गया तो
 स्टालिन और चर्चिल को यूरोपीय रणक्षेत्र में हिटलर और मुसोलिनी के विरुद्ध
 एक-जबदस्त सहभागी मिला। हिंदुस्तान के स्वाधीनता आन्दोलन के वरिष्ठ
 नेता भी अमरीका से आशा करने लग कि वह साम्राज्यवादी ब्रिटन पर दबाव
 डालकर उस स्वाधीनता के रास्ते पर ला दगा—फ्रिंस मिशन की पीछे यही
 आशा की किरण फूट रही थी। एक खयाल था कि अमरीकन साम्राज्य-
 बान्धियों पर दबाव डाल कर रूजवेल्ट उपनिवेशवाद को समाप्त करा देंगे।
 वह फिलीपाइन्स पर अमरीकी उपनिवेशवाद को समाप्त करा देंगे।
 चुक थे और फ्रांसिसी साम्राज्यवाद की समाप्ति के बार में भी अपनी यह राय
 व्यक्त कर चुक थे यथा इलियट रूजवेल्ट के शब्दों में—
 'सन 1944 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उस हिंद चीन के हल के लिए सबसे
 अच्छा हल यह बताया था कि वहाँ माय व्यवस्था स्थापित कर दिया जाय और
 साम्राज्यवादी फ्रांस के द्वारा निममता पूर्ण दोहन के लिए उसे लौटाया न
 जाये।' मार्च सन 1943 में रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के पर राष्ट्र में श्री ईडन को भी
 यह सुझाया था कि युद्धोपरांत फ्रांसिसी उपनिवेशवाद को जितान के बजाय
 एक अंतर्राष्ट्रीय माय व्यवस्था के अंतर्गत हिंद चीन को जितान के लिए
 तयार किया जाय।¹ स्पष्ट है कि यह सुझाव अग्रजों का पसंद न था। रूज-
 वेल्ट ने फरवरी सन् 1945 में माल्टा सम्मेलन में कहा भी था कि यदि हिंद
 चीन का आजादी मिली तो उनका अपना साम्राज्य भी वहीं फूट न पड़े चूँकि
 हिंद चीन के स्वाधीन होते ही बर्मी लोग भी इसी रास्ते जा सकते हैं।² हम
 अर्थात् इसका जिक्र कर चुके हैं कि किस प्रकार रूजवेल्ट की पीछे पीछे स्टालिन
 और चर्चिल ने पूर्वी यूरोप और मध्य सागरीय प्रदेश में प्रभाव क्षय आपस
 में बांट लिया था। रूजवेल्ट की इस सहमति न थी। बाद में वह इस नजर-
 से समझाता चीनी हितों की नीमत पर कर लिया और स्टालिन को चीन से
 कुछ सहूलियतें वोट आर्थर और डेरियन के बदरगाह मचूरिया की रत्नवे
 लाइन में हिंसे दिलवान का वायना कर, एक गुप्त समझौता कर लिया, यह

भी उनका दर्जा स्तालिन से नीचे नहीं हान देता। यह कहना कि वे बोरे आदर्शवाणी नहीं थे, दूसरों की नीमत पर अपना लाभ सेना चाहते थे, उनकी भत्सना करना नहीं होगा। वस्तुतः न साम्राज्यवादी ढंग से उद्धान कही भी चंचिल की तरह दूसरा या चीना ढपटने और अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की पहल की, न मोवियत त्नाओ की तरह अपना आन्ध्र स गिरकर ऐसा निदय आचरण किया। उनके पक्ष में यह कहा जा सकता है कि यदि स्तालिन और चंचिल आपस में साठगाठ कर इस तरह के साम्राज्यवादी दाव पेश न लगात तो रूजवेल्ट अपनी आर में बदर घाट के लिए अपने साम्राज्यवादी और समाजवादी मित्रों का इस प्रकार के 'शिक्कर' के लिए आमन्त्रित करने वाले न थे।

उनके रहत ही मित्र राष्ट्रों के मध्य में कुछ ननाव पैदा हान लगे थे पर वे भरमबा वाशिस करते रहे कि ऐसे तनाव मिटें और मित्र राष्ट्रों का सहयोग और माह्वय का आधार भजवूत हाता चले। अपने अंतिम दिना में वे इसी प्रयास में थे। युद्ध की समाप्ति जैसे जम नजनीन आती निख रही थी, वैसे वैसे रूजवेल्ट ने अपने घर की राजनीति का ऐसा माड देना शुरू कर दिया ताकि युद्ध से लौटन पर, उनकी धंसी दुगति न हो, जैसी प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रपति विलसन की हुई थी कि वे अपनी कांग्रेस से युद्ध के बाद की संधियों और राष्ट्रसंघ के सविदा के पत्रा पर सहमति नहीं प्राप्त कर सक। इसी नीति के अंतगत उन्होंने अपने मित्र हनरी वेलस को छोड उस ट्रूमेन का उप राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना जा मिनट में डिमोक्रेटिक दल के नेता थे और उनके डेलीगेशनो और मंचों के लिए प्रतिद्वंदी पार्टी, रिपब्लिकन दल के नेताओं का चुनाव मिनटर में डेनवग और जान फास्टर डलेस ऐसी ही भूतिया थी। पर रूजवेल्ट के निधन होते ही उन तमाम तत्वों और शक्ति के छोटे मोटे के द्रो पर जा रूजवेल्टी शासन की धुरी बन हुए थे, उनकी नीति के विरोधियों का बचस्व स्थापित हो गया जिससे अमरीकी राजनीति की दिशा और शली दोनों में पहले बहुत तजी से ऐसा बदलाव शुरू हुआ जा का तीन वष बीते भी न थे कि सोवियत विरोधी ऐसे मोर्चे में परिणत हो गई जिसका नेतृत्व अमरीका के हाथ में था, पर दिशा बोध उसे अंग्रेज और उनके साथी साम्राज्यवादी दन लगे। चंचिल के लिए जा आसान बात थी कि स्तालिन का साथ छोडकर ट्रूमेन के अमरीका के गले जा मिलें, वही बात स्तालिन के लिए पहल दुप्कर बनी और फिर असभव सी हो गई।

नया रूख

धीमे-धीमे एक नया रूख अमरीका शासकों ने अपनाना शुरू कर दिया जिसका अर्थ था कि महासमर के दौरान रूजवेल्ट के नेतृत्व में विवसित हुई

अमरीकी परराष्ट्र नीति में उत्तरेक शुरु हो गया था। शूमा के शब्दों में 'यद्यपि व दोना एन ही राजनीतिक दल से आए थे, पर रूजवेल्ट व प्रशासन से ट्रूमन व प्रशासन की आर सत्रमण कुछ अर्थों में सन् 1921 में हुए विल्लन प्रशासन से हाटिंग प्रशासन की आर सत्रमण का याद दिलाता था।'⁹

नये राष्ट्रीय नीति में शुरु में बड़े विनम्र और जिगामु रह पर जैसे जैसे उनमें आत्मविश्वास की मात्रा बढ़ती गई, उन्होंने अपना शासन तब बदल दिया और कुछ ही दिनों में व ऐसे सलाहकारों से घिर गए जिनकी और सनिकतत व अधिकारी थे यथा फोरेस्टल जो सुरक्षा सचिव बने, व डिल्लन जो एड कपनी व अध्यक्ष रहे जहां सना के उपसचिव मिस्टर ट्रेपर उपाध्यक्ष थे। हेनरी वलेस के उत्तराधिकारी एवरेल हैरीमन, जो करोड़पति छानदान के थे, शायद प्रदश हैरीमन तथा कम्पनी के सत्पापक थे। इसी प्रकार सहायक सचिव परराष्ट्र विभाग व, चार्ल्स साल्टजमान न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज के उपाध्यक्ष थे। जनवरी सन् 1948 तक उन सार पदा में जिनमें सामान्यतः असैनिक पदाधिकारी होते थे सभी ऐसे लोग नियुक्त हो गए जो युद्धकला के विचारों से। विलियम लीही, परराष्ट्र सचिव साज माथल साल्टजमान सना सचिव कैनन रायल, जमनी क गवर्नर रिस्के, जापान व गवर्नर जनरल मकायर, चीन में राजदूत केडे मयर हस में राजदूत बाल्टरस्मिथ ऐसे अनेक अधिकारी ट्रूमन के शासनकाल में जग बन गए थे।'

युद्ध समाप्त हुए 75 वर्ष नहीं बीते थे कि ट्रूमन का अमरीका युद्धास्त्रों में लगभग 10 अरब डॉलर सालाना खर्च कर रहा था और बढ़ रहा था। जहां तक प्रशासन और कांग्रेस की नीतियां पर किन्हीं वयहिलों के जबदस्त प्रभाव की बात थी, अमरीकी गणतंत्र बड़े बड़े 'पावसायियों और सैनिक विशेषज्ञों के द्वारा अनुशासित हो रहा था।' कहने का तात्पर्य यह कि राज्य की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में आ गई थी जिन्हें 'आदेश देने और अनुशासन स्थापित करने की आदत थी और जिनकी दिमागी हस्तान्तरणों के सैनिक प्रशिक्षण की अभ्यस्त थी—एक ऐसी आदत जो भौतिक बल के प्रयोग करने की आदत थी।' शूमा ने ठीक ही लिखा है कि परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में जो जो घट रहा था यदि अधिकारियों और उद्देश्यों के बारे में जो बदलाव हुआ था उस पर ध्यान न दिया जाए तो वह बलाव समझ में नहीं आ सकेगा।¹⁰

युद्ध का समाप्त हुए साल भर भी नहीं बीते थे कि अमरीका में उच्च अधिकारी इस तरह के वक्तव्य देन लगे तथा जाज बल ने अप्रैल 26 सन् 1946 को अमरीकी जनता का उदबोधन किया

नातिसोयों से कहीं बड़ा खतरा सोवियत रूस है। अमरीका की आत्मरक्षा

क लिए रूस व प्रत्येक कस्बे शहर और गांव को नस्तनाबूत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। (पुन अक्टूबर 10, सन 1947 को) कमालन पर एक अच्छा-सा छाटा परमाणु बम और साठ सोलह करोड़ रूसी लोग बिचड़े बिचड़े होकर इधर-उधर बिखर जायेंगे "11

बात सोवियत हमले की न थी बात कुछ और ही थी

बड़ी चतुराई व माथ एक जबदस्त सोवियत हमले की आज्ञा का होवा खड़ा किया गया। समाज प्रचार माध्यमों के जरिये दशनापूर्वक घर में और बाहर यह फैलाया गया कि सोवियत की लाल सेना बर्लिन से कूचकर पूरे यूरोप का हथियाने और फिर भूमध्य सागरीय इनाका की कब्जे में लेकर एशिया और अफ्रीका की ओर अपने लाख साम्राज्य के विस्तार करने की तैयारी में लगी हुई है। तरह-तरह व 'सत्य' और 'सत्य' गढ़ गए और इस झूठ की सभी के मन के नीचे उतारने के उपाय सोचे गए और उन पर अमल शुरू हो गया। यह प्रचारित किया जान लगा कि वस्तुतः यह सगढ़ा विरोधी यूना मायताओं और समाज व्यवस्था का है, साम्यवादी व्यवस्था और लोकतन्त्री व्यवस्था का। फुल्टन व ट्रूमन के सभापतित्व में जो सभा हुई उसमें चर्चित न अपन भाषण में पहला गोला दागा यह कहकर कि एक अशुभपूर्व साह का पर्दा इस पार में उन पार स्नातन के रूप में डाल दिया है, यह कि व मित्र राष्ट्रों की युद्ध-कालीन मंत्री को नष्ट कर तानाशाही आरोपित कर सोवियत साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं कि उन्होंने पूर्वी यूरोप में लोकतन्त्र की शक्तियों पर दमन चम चला दिया है इत्यादि। इसके बाद ही ट्रूमन ने अपना सिद्धान्त की घोषणा की तथा तुर्की और यूनान की रक्षा व्यवस्था करने के लिए बंदम उठाने की बात कही जिसके अंतर्गत एक अमेरिकी युद्धपोत भूमध्य सागर को खाना किया गया और उसी वर्ष अर्थात् सन 1947 के प्रारम्भ में पश्चिमी यूरोप के जीर्णोद्धार और उन पुन गठित करने के लिए मासल यात्रा की घोषणा की गई। एक ठण्डी सड़ाई का बिगुल इस तरह बजने लगा। ब्रिटेन व फ्रांस के माथ बनक की सधि सम्पन्न कर सैनिक गठबंधन की नींव डालनी शुरू की जिसका दूसरा कदम था ब्रिटेन की सधि जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा अन्य पश्चिमी यूरोप के देश भी लाये गए और इसी वर्ष बर्लिन के गलियार को लेकर जो संकट पैदा हुआ, उसके माथ-साथ शांतिकाल के एक अभूतपूर्व सैनिक गठबंधन की नींव डालते हुए एक "उत्तर अटलांटिक सधि संगठन" खड़ा कर दिया गया जिसके सदस्य अटलांटिक मागर से दूर, उस पार स्थित तुर्की और यूनान ही न थे बल्कि फ्रांस का अल्जीरियाई हिस्सा भी था। सबसे मार्के की बात तो यह हुई कि अमेरीका और ब्रिटेन न (तब फ्रांस तो बस भी पराधीन था)

जमनी ने उन टुकड़ों को जो उनकी सेना के अधीन थे मिलाकर एक 'जरासंध' खड़ा कर लिया — पहले उन क्षेत्रों में मुद्रा परिवर्तन कर जिससे जमनी टुकड़ा की एकता बढ़ाने वाली अथ व्यवस्था को छिनभिन्न कर दिया, फिर अपने अधीन एक 'जमनी गणतन्त्र' की स्थापना कर उस पूरे जमनी का दावेदार बनाकर अपने गठबन्धन का अंग बना लिया। सभी मोर्चों पर रूजवेल्टीय नीति की तोड़ मरोड़ शुरू हो गई — हिंदचीन में फ्रांस की पुनर्वापसी, इदोनेशिया में डचों को और इसी तरह अथ एशियाई भागों में और अफ्रीका में नवोदित स्वाधीन उपनिवेश विरोधी, रंगभेद विरोधी शक्तियों को दबाव कुचलन का अभियान छिड़ गया। हिंदुस्तान भी इस शीत युद्ध की चपट में लाया जा रहा था। वह तात्कालिकता थी कि पड़ोसी देश चीन में जो गह्रयुद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें अमरीका और ब्रिटेन के पुराने मित्र ज़्यागकाई शेख और उनका देश पराजित हो गया और साम्यवादी शक्ति पूरे चीन पर छा गई। इस तथ्य ने जहाँ एक ओर हिंदुस्तान के टूटे हुए पर अब आजाद बन टुकड़ा को अंग्रेजी 'राष्ट्रमंडल' में शामिल करा दिया वहाँ चीन में कम्युनिस्टों की विजय ने भारत के नतत्व वगैरे का शीत युद्ध में बदले समीकरण में अपना महत्व प्राप्त करने के अवसर भी खोल दिए। जहाँ एक ओर ज़्यागकाई शेख की दुर्गति देखकर भारतीय नेता इतिहास का यह ताजा सबक सीख रहे थे कि भारत अमरीकी गठबन्धन उन्हें कैसे खार्ई में ढकेल देगा वहाँ आगल अमरीकी गुट भी सावधानी बरत रहा था कि दबाव भले ही जारी रहे पर सीधे हस्तक्षेप से कुछ का कुछ न हाँ जाए जैसा चीन में हाँ गया था। आगल अमरीकी गुट की यह नीति तब से जारी रही कि दबाव डालना बंद न किया जाए पर इतनी मात्रा और इस प्रकार का दबाव भी न डाला जाय कि बात बिगड़ ही जाय। राष्ट्रमंडल की सदस्यता से दोनों ओर कुछ राहत मिल गई — राष्ट्रमंडल आखिर एक 'गोष्ठी' से बढ़कर तो कुछ था नहीं, कोई समिक गठबन्धन तो था नहीं, जो भारत की स्वतंत्र परराष्ट्र और यह नीति के आड़े आए परसपक साधने का एक निर्दोष सा माध्यम था जहाँ साल भर में एक बार राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री मिल लेते थे, बातचीत कर लेते थे प्रीतिभाज में शामिल हो लेते थे और ऐसे महत्व के वक्तव्य भी गाहबगाहे छपवा लेते थे जैसे सन् 1948 में ब्रूसेल्स गठबन्धन के पत्र में निबाला गया था जब उत्तर एटलांटिक संधि का समयन किया गया था जब कोरियाई युद्ध में समुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जब मोर्चा खुला तब धायलों की भरहम पट्टी करने के लिए भारत की ओर से भी 'समुक्त राष्ट्र' की सहायता के रूप कुछ डाक्टर, नर्स और दवाईयाँ भेजी गई और बाद में जब कोरियाई युद्ध में चीन के कूद पड़ने पर गहराने लगा, तब समुक्त राष्ट्र का साथ छोड़ भारत सुसहनामा कराने के लिए आगे आगे हो लिया।

शीत युद्ध का नजरिया समझौता नहीं भगड़ा बढ़ाया जाए

वात सोवियत हमले के डर की थी ही नहीं। जाज यफ कैनन¹ जो शीत-युद्ध के शुरू के दिनों में इस नीति के बड़े हिमायती थे कि सोवियत शक्ति की रोकथाम की जाए, इस बात से इकार करते हैं कि सोवियत हमले का कोई डर था। सोवियत संघ न युद्ध के लिए तैयार था, न उसके नेता या उनकी मार्क्सवादी समर्थन इसके लिए उन्हें प्रेरित कर रही थी। वास्तविक खतरा, कन्न साहब के अनुसार, यूरोप में क्रांति की समाधान का था जो एक पड़ोसीकारी कल्पितक (कम्प्युनिस्ट दल) के माध्यम से हो सकता था 'जि ह आशा थी कि व अपने राष्ट्रीय दायरों में सत्ता हथिया लेंगे तथा तानाशाही तरीके से उसे कायम रखेंगे। इसीलिए कैनन और उनके जैसे बुद्धिजीवियों ने मासल योजना और पश्चिमी यूरोप की अव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति का समर्थन किया था, न कि 'नाटो' जैसे सैनिक संगठन बनाने का। कैनन के अनुसार 'नाटो' की संरचना के पीछे केवल उही विचारों के लागू हो सकते थे जो इन दिनों में अपना चिंतन दौड़ाते थे कि यूरोप का अच्छा भविष्य तभी बन सकता है जब कि सोवियतों की पूर्ण सामरिक पराजय हो जाय या ऐसा कुछ घट कि भले ही जिसका कारण न बता सकें या जो अभी संभव नहीं लग रहा हो ऐसा सोवियत नेताओं का राजनीतिक संकल्प और इच्छा शक्ति भरभरा कर दह जाए। राष्ट्रपति ट्रुमेन और उनके कुछ निकटस्थ सलाहकार इसी मंडली के नेता और सदस्य थे जो बलपूर्वक हल निकालने को उद्यत हो रहे थे। इनमें चर्चित ऐसे यूरोपीय नेता भी शामिल थे। ट्रुमेन का वह वक्तव्य दृष्टव्य है जो उन्होंने अपने परराष्ट्र मंत्री वायरेजीज को भेजा था

'मेरे दिमाग में जरा भी संशय नहीं है कि रूस टर्की पर आक्रमण और काले सागर की भूमध्य सागर में खुलती खाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। यदि रूस का मुकाबला सौहृद मुठभेड़ और कठोर भाषा से नहीं किया गया तो एक नये युद्ध की शुरुआत हो सकती है मेरी समझ में अब आपका समझौते की नीति पर और अधिक बिलकुल भी नहीं चलना चाहिये हम रूमानिया और बल्गारिया को तब तक मायता नहीं देनी चाहिये जब तक वे हमारी मांगें नहीं मान लेते हम अपनी ईरान की नीति स्पष्ट कर देनी चाहिये हमें लगातार इस भाग पर डटे रहना चाहिये कि कील नहर, राइन डेल्टा जलमार्ग तथा काला सागर की खाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाये और हम जापान तथा प्रशांत महासागर पर पूरा आधिपत्य रखना चाहिये हम 'उधार खाते' वाले ऋण के समझौते के लिए रूस पर दबाव डालना चाहिये—मैं रूस को बच्चों की तरह पालने में झुलाते-झुलाते सग आ गया हूँ।'²

जमनी के उन टुकड़ा को जो उनकी सेना के अधीन थे मिलाकर एक 'जरासय' पड़ा कर लिया — पहले उन क्षेत्रों में मुद्रा परिवर्तन कर जिससे जमनी टुकड़ा की एकात्मता बढ़ाने वाली अर्थ व्यवस्था का छिन्नभिन्न कर दिया फिर अपने अधीन एक 'अमन गणतन्त्र' की स्थापना कर उस पूरे जमनी का दावदार बनाकर अपने गठबंधन का अंग बना लिया। सभी मोर्चों पर रुजवल्लीय नीति की ताड़ मरोड़ शुरू हो गई — हिंदी में फ्रांस की पुनर्वापसी, इंग्लैंड में डच्चा को और इसी तरह अन्य एशियाई भागों में और अफ्रीका में नवोदित स्वाधीन उपनिवेश विरोधी, रंगभेद विरोधी शक्तियों को दबाने का अभियान छिड़ गया। हिंदुस्तान भी इस शीत युद्ध की चपेट में लाया जा रहा था। यह तो गनीमत थी कि पचासी दश चीन में जा गहयुद्ध छिड़ा हुआ था उसमें अमरीका और ब्रिटेन के पुराने मित्र जियांगकाई शेख और उनका दल पराजित हो गया और साम्यवादी शक्ति पूरे चीन पर छा गई। इस तथ्य ने जहां एक ओर हिंदुस्तान के टूटे हुए पर अब आजाद बन टुकड़ा को अंग्रेजी 'राष्ट्रमंडल' में शामिल करा दिया, वहां चीन में कम्युनिस्टों की विजय ने भारत के नवतत्त्व वर्ग को शीत युद्ध के बदले समीकरण में अपना महत्व प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान किए। जहां एक ओर जियांगकाई शेख की दुर्गति देखकर भारतीय नेता इतिहास का यह ताजा सबक सीख रहे थे कि भारत अमरीकी गठबंधन उतह कैसे खाई में डूबके देगा वहां आग्ल अमरीकी गृह भी सावधानी बरत रहा था कि दबाव भले ही जारी रहे पर सीधे हस्तक्षेप से कुछ का कुछ न हो जाए जसा चीन में हो गया था। आग्ल अमरीकी गृह की यह नीति तब से जारी रही कि दबाव डालना बंद न किया जाए पर इतनी मात्रा और इस प्रकार का दबाव भी न डाला जाय कि बात बिगड़ ही जाये। राष्ट्रमंडल की सदस्यता से दोनों ओर कुछ राहत मिल गई — राष्ट्रमंडल आखिर एक गोष्ठी से बढ़कर तो कुछ था नहीं, कोई सैनिक गठबंधन तो था नहीं जो भारत की स्वतंत्र परराष्ट्र और यह नीति के आड़े आए पर सपक साधने का एक निर्दोष सा माध्यम था, जहां साल भर में एक बार राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री मिल लेते थे बातचीत कर लेते थे प्रीतिभोज में शामिल हो लेते थे और ऐसे महत्व के अवसर भी गाढ़ेबाढ़े छपवा लेते थे जैसे सन 1948 में ब्रूसेल्स गठबंधन के पक्ष में निवाला गया था जब उत्तर एटलांटिक संधि का समयन किया गया था जब कोरियाई युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जब मोर्चा खुला, तब घायलों की मरहम पट्टी करने के लिए भारत की ओर से भी 'संयुक्त राष्ट्र' की सहायता के रूप कुछ डाक्टर, नर्स और दवाइयां भेजी गई और बाद में जब कोरियाई युद्ध में चीन के कूद पड़ने पर गहराने लगा, तब संयुक्त राष्ट्र का साथ छोड़ भारत सुलहनामा कराने के लिए आगे आगे हां लिया।

तग वास्तव में साम्राज्य के बाजार हो गये थे

सन्नि जो चीज दायतव में इन्हें तग कर रही थी, वह थी अमरीकी साम्राज्यवादी फलाव में भाग जगह जगह अवरोध हो रहे थे। प्रथम महायुद्ध के बाद सुर्वी और आस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्यों के विघटन के बाद आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर जो पूर्वी यूरोप का नया नक्शा बनाया था और जिसका लक्ष्य नाजो जर्मनी से गगडा बड़ा, प्रिटन, फ्रांस का यह 'प्रभाव क्षेत्र' साविजन्य प्रभाव में आ गया था और वहाँ से पूँजीवादी नीय का सफाया हो गया था। नाजो जर्मनी का एक अच्छा पामा टुकड़ा साविजन्य क्षेत्र में चला गया था और वैसेपुच यूरोप में भी पूँजीवादी शक्तियों का बचस्व लड़खड़ा रहा था। इससे पतरा यह बड़ रहा था कि एशिया अफ्रीका की मुक्ति आन्दोलन की बाढ़ को पामना मुश्किल क्या, असंभव हो जाय—चीन में हिंसा चीन में, इण्डोनेशिया में, मलाया में बर्मा में, पश्चिम एशिया में और भारत में—समाज जगह जबदस्त उथल पुथल थी। इनमें बड़े बाजार कहा जायेंगे। रजिस्ट्र के समय एक दूसरा विकल्प सम्भव बन रहा था कि तेजी से बढ़ रही अमरीकी औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक शक्तें सबके काम आ जायें और अमरीका का एक भलमनसाहत वाला व्यापारी का विश्वव्यापी प्रभाव क्षेत्र बन जाये जो युद्ध-कालीन मित्रराष्ट्रों के साहचर्य और सद्भाव की स्वाभाविक परिणति होती। साविजन्य का हथ अमरीकी पूँजी और उनके नेताओं से सहयोग का ग्य था पश्चिम यूरोप के साम्यवादी दल के नेता जो मिली जुली सरकार में भाग ले रहे थे इस प्रकार के सहयोग के लिये तैयार थे—मासल योजना का स्वागत करने में उन्हें सकोच न होता—वस्तुतः उन दिनों ऐसी सभावना दिख रही थी कि समाजवादी शक्तियों और सकटग्रस्त अस्तव्यस्त पूँजीवादी शक्तियों के बीच बड़ी समझौता हो जाए। टूमेन शासन ने इन सभावना की जान ले ली उनके तेवर और अदाज उस खूनी बाज के तेवर और अन्दाज बन गये जो शांति के कतूबों को निश्चित हाकर इधर उधर उड़त दखकर तग आ गया हो। हिंसा चीन को फामीशी साम्राज्य को न सौटाने का विचार प्रकट करने वाले रजिस्ट्र के अमरीका की जगह अब टूमेन का अमरीका था जिसके अनुसार (अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में 23 दिसम्बर सन् 1949 को दिया गए उद्गार के अनुसार)---

'एशिया ऐसा महत्वपूर्ण कच्चे और अघपक मान का एक बड़ा स्रोत है जिसमें से कुछ मामरिक महत्व है। इसके अलावा अतीत में विस्तृत देशों के पक्के मान का स्रोत है और पक्के मान के लिए पूँजी निवेश से और अन्य प्रयोजनों के लिए पक्के मान का स्रोत रहा है।'

इस पुराने साम्राज्यवादी शोषण के खातो पर नये सिरे से कब्जा करना अमरीकी परराष्ट्र नीति का प्रमुख नक्ष्य हो गया। कुछ ग्रन्थ गोरी सम्पत्ता का भार अब अमरीका के प्रशस्य बघो पर आ पड, था। रुजवेट का अमरीका जा उपनिवेशो के लागो को तरह-तरह से मुक्ति की आशा बघाए हुए था उनके माप ही विलीन हो गया—और एक ऐसा अमरीका एक भयावन दत्य की तरह अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर आ गडा हुआ जिसके तीन लाख नागरिक तो युद्ध की भेंट हुए पर पूरा प्रदेश बमो की ओर से अछना रहा, जिनके कल कारखाने दमियो गुना उत्पादन म रात दिन लगे रहे और फलस्वरूप जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पादन करीब 91 हजार कराड डालर से (सन 1941 म) बढ़कर एक सौ छियासठ करोड डालर (सन 1945 म) तक पहुच गया (91 billion स 166 billion तक) जिमम दूसरा को दिय उधार खात म ही करीब 30 हजार कराड डालर बज था।¹⁵ अतएव द्वितीय महायुद्ध अधिकांश अमरीकियों के लिए न ता बठिनाई और न तकलीफ लेकर आया बल्कि वह उनक लिए बहनर जिदगी ले आया।¹⁶

युद्ध खतम हुआ तो यही बहनर जिदगी खतरे म पडती दिखाई ली। उह डर लगने लगा कि दुनिया के अनेक विशी बाजारो उछोयी और बच्चे माल क खातो म उनकी घुसपट राकन की कोशिश होगी। सोवियत प्रभाव क्षेत्र ता उनके लिये अवरुद्ध होगा ही, त्रितानी और फामीसी भूतपूर्व और तत्कालीन साम्राज्यो के क्षेत्र भी पहुच से बाहर हो सकते थे— इसी 'बघन' को तोडन का मिलसिला ब्रिटन बुडस ममझाते से शुरू होकर, माशल योजना, और उसके आगे तक चलता रहा जिमक अन्तगत ईरान, यूनान, तुर्की, पश्चिम एशिया के क्षेत्र, दक्षिण पूव एशिया के इलाके सभी आ गय जिसम सन्निव राजनीतिक और आर्थिक हर तरह का वचस्व स्थापित करन का अभियान छेड दिया गया जिसका सामूहिक नाम था शीत युद्ध।¹⁷

इस सम्बन्ध मे ट्रूमेन कान के विदेश सचिव डीन अवेसन का निम्नांकित वक्तव्य दृष्टव्य है

"यदि आप अमेरिका के संपूर्ण व्यापार और आमदनी पर नियंत्रण करना चाहत है जिनका अर्थ होगा लोगों की जिन्दगी नियंत्रित करना, तब संभवत आप यह तय करेंगे कि यहाँ (अमेरिका में) जो भी उत्पादन होता है, उसकी खपत भी यही हो लेकिन तब यह बात हमारे सविधान को ही पूरी तरह बदल देगी, हमारे सम्पत्ति के प्रति संवैधानिक, मानवीय स्वतंत्रता तथा कानून की अवधारणा को ही बदल देगी और यह कोई भी नहीं साचता। इसलिए अब यह बात है कि आप दूसरे बाजारों की तरफ नजर डालें और बाजार सारे बाहर है।"¹⁸

यह है अमेरिकी परराष्ट्र नीति के 'घुमे द्वार' या 'अनीपचारिक साम्राज्य' का उद्गम स्थल और इसीलिए अमेरिकी परराष्ट्र नीति के 'विषय को अमेरीका मय कर दो अभियान का मूल इसी में दूढ़ा से मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रूमन के शब्दों में'

"सारी दुनिया का अमेरिकी व्यवस्था अपनानी चाहिए अमेरिकी व्यवस्था अमेरीका में भी तभी टिकी रह सकेगी जब वह सार्वभौमिक व्यवस्था हो जाए"^१ शीत युद्ध छेदन की घुन के पीछे यही मन है।

संदर्भ

- १ देखिए, सरदार के० यम० पतिस्कर इन एशिया एण्ड वेस्टन डामिनेन्स भूमिका
- २ नहरू विश्व इतिहास की सलक पृ 1312
- ३ इलियट रजवेल्ड, 'एज ही सा इट' (यूनाक 1946), पृ 251
- ४ काडल हल, सकरण (यूनाक 1948) खंड 11 पृ 1595 (—) 98
- ५ आधर सिसालिगर जूनियर, द ब्रिटिश हेरिटेज (लंदन 1967) पृ 11
- ६ शूमा, वही, पृ 806
- ७ वही, " " " "
- ८ शूमा, वही, पृ 806
- ९ वही " " "
- १० वही, पृ 807
- ११ वही उदघाटन पृ 807
- १२ जाज, यफ, कनन सन 1946 तक मास्को स्थित अमेरिकी दूतावास में एक अधिकारी थे। तत्पश्चात् वे राष्ट्रपति ट्रूमन के परराष्ट्र मंत्रालय के 'नीति आयोजन स्टाफ' के निदेशक थे—उद्घाटन सन 1965 में जेनेवा स्थिति ग्रेजुएट्स स्टडीयूट आफ इटरनेशनल स्टडीज में भाषण देते हुए ये बातें स्पष्ट कीं। जाज यफ कनन ने उस नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया था जिसके अंतर्गत अमेरीका ने सोवियत शक्ति को रोकथाम के लिए काम उठाया।

- 13 ट्रमेन सस्करण 2 खड, पृ 552
- 14 प्रतिनिधि सभा सशस्त्र सेवाओं की समिति की बैठक, खड 8 पृ 225-64
- 15 देखिए गाढन राइट पृ 265 द यूनाइटेड स्टेट्स बिकम एन एकानामिक ट्रमेन, पब्लिक पेपर्स, जाईंट 1947, पृ 168
- 16 रिचार्ड पोलेनबर्ग, वार एण्ड सोसायटी, द यूनाइटेड स्टेट्स, 1941 45, 1972 पृ 131-2
- 17 देखिए, स्टीफन ई एम्ब्रोज, राइज टू ग्लोबालिस्म अमेरिकन फारेन पालिसी सिस 1938, लंदन 1971 पृ 18
- 18 कौल्का, द पालिटिक्स आफ वार, पृ 254
- 19 एम्ब्रोज, वही, पृ 19

शीत युद्ध और अमेरिका-सोवियत सम्बन्धों का अतर्द्ध्व

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था एक प्रारूप

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और उसकी सहज गतिशीलता का अवसर दो प्रकार के उपागमों से समझा जाता है। प्रथम, बहुप्रचलित स्वरूप में अधिकांशतः विदेश नीतियों के अध्ययन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्पष्ट किया जाता है। इस उपागम में किसी राष्ट्र विशेष को केन्द्र मानकर उसकी विदेश नीति के आधार और अन्य राष्ट्रों के प्रति उसकी नीति का विवेचन किया जाता है। उदाहरणतः भारत की विदेश नीति, सोवियत की विदेश नीति अथवा अमेरिका की विदेश नीति। दूसरी एवं गुणात्मक रूप से भिन्न प्रक्रिया मूलतः विदेशनीति का अध्ययन से हटकर राष्ट्रा के परस्पर सम्बन्धों की अपना 'केन्द्र बिंदु' बनाती है। विश्लेषण का ऐसा दृष्टिकोण कि ही दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्बन्धों की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में उन राष्ट्रा की विदेशी नीति के आधारों का भी परीक्षा समवेश सम्भव हो पाता है। परस्पर सम्बन्धों की स्थितियों को अध्ययन का 'केन्द्र बिंदु' मानने से एक सीधी उपयोगिता के रूप में विषयवस्तु की पुनर्जागृति संभवा जा सकता है वैसे तो आंतरिक राजनीति में भी यह बात खरी उतरती है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलू और उनकी गतिशीलता सजीव रूप से जुड़ी होती है। अतः किसी एक पहलू पर विचार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत पहलुओं का समावेश भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उदाहरणके तौर पर जब हम अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तब अमेरिका और सोवियत के सम्बन्ध जो कि अमेरिका की विदेश नीति के लिए प्राथमिक महत्व के हैं, का अध्ययन भी विस्तार में आवश्यक है।

ऐसे ही जब हम सोवियत की विदेश नीति का पथक अध्ययन करें तो अमेरिका के साथ सम्बन्ध पुनर्जागृत करना होगा लेकिन यदि अध्ययन का आयोजन परस्पर सम्बन्धों के आधार पर ही कर लिया जाए तो ऐसी पुनर्जागृति में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया जा सकता है। जहां तक प्रस्तुत, अध्ययन का प्रश्न है, हम इस प्रकार

दृष्टिकोण की उपादेयता को अधिक साधक मानते हैं। राजनीतिसास्त्र के सैद्धांतिक पक्षों को उभारने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में देखने के लिए, ऐसे दृष्टिकोण के अनेक उपादय आयात हैं।

परस्पर सम्बंधों का अध्ययन एक वाञ्छित विकल्प

अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की राजनीति के अध्ययन में विदेशनीति के अध्ययन की प्रणाली से हटकर राष्ट्रा के परस्पर सम्बंधों को केन्द्र बनाने का दृष्टिकोण निम्न रूप में साधक एवं औचित्यपूर्ण है।

1 विदेशनीति के अध्ययन की प्रणाली में अध्ययन का केन्द्र बिन्दु उस राष्ट्र विशेष की नीति हो जाता है एवं अध्ययन का सारा रुझान और समीक्षा उसी एक केन्द्र पर आश्रित होती है। जबकि यदि राष्ट्रा के परस्पर सम्बंधों पर बल दिया जाये तो अध्ययन की परिधि स्वतः ही विस्तृत हो जाती है और अध्ययन का प्रमुख स्रोत किसी राष्ट्र विशेष पर केन्द्रित न होकर, उन सम्बंधों की पारस्परिकता पर बल देता है।

2 विदेशनीति को केन्द्र बिन्दु मानने में मूल्यांकन और समीक्षा में भी स्वाभाविक अवरोध आता है। किसी नीतिविशेष का सही अथवा गलत होना, साधक अथवा निरर्थक होना—उस राष्ट्र विशेष के सम्बंध में आका जाता है। इसके विपरीत जब हम राष्ट्रा के परस्पर सम्बंधों को केन्द्र बनाते हैं तो उनका मूल्यांकन किसी एक राष्ट्र के हितों के पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो पाता।

3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में तुलनात्मक अध्ययन के प्रारूप को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से भी, परस्पर सम्बंधों के अध्ययन की प्रक्रिया अधिक साधक बनती है। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक सामयिक प्रश्नों पर अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही इन प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित स्वरूप समझा जा सकता है। परस्पर सम्बंधों पर अध्ययन का दृष्टिकोण ऐसे अध्ययन के लिए अधिक सुलभ है।

4 इस सम्बंध में अत्यधिक महत्त्व का जो प्रश्न है वह इस बात से सम्बंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध अनेक आप में एक व्यवस्थित स्वरूप लिए हुए हैं। सतही तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गतिशीलता भ्रामक लगती है, और विभिन्न घटनाओं में किसी भी सततता को रेखांकित कर पाना बहुधा कठिन लगता है। लेकिन अपने बाहरी आचरणों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की राजनीति की अपनी स्वयं की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इस व्यवस्थागत स्वरूप को समझने के लिए और उसका सही विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रों के परस्पर सम्बंधों का दृष्टिकोण अत्यधिक महत्त्व का है।

कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की एक निश्चित व्यवस्था

शीत युद्ध और अमेरिका-सोवियत संबंधों का अतर्द्ध

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था एक प्रारूप

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और उसकी सहज गतिशीलता को अवसर वा प्रकार के उपागमों से समझा जाता है। प्रथम बहुप्रचलित स्वरूप में अधिकांशतः विदेश नीतियों के अध्ययन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्पष्ट किया जाता है। इस उपागम में किसी राष्ट्र विशेष का केन्द्र मानकर उसकी विदेश नीति के आधार और अन्य राष्ट्रों के प्रति उसकी नीति का विवेचन किया जाता है। उदाहरणतः भारत की विदेश नीति सोवियत की विदेश नीति अथवा अमेरिका की विदेश नीति। दूसरी एवं गुणात्मक रूप से भिन्न प्रक्रिया मूलतः विदेशनीति के अन्वयन से हटकर, राष्ट्रा के परस्पर सम्बन्धों को अपना 'केन्द्र बिंदु' बनाती है। विश्लेषण का ऐसा दृष्टिकोण किन्हीं दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्बन्धों की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में उन राष्ट्रों की विदेशी नीति के आधारों का भी परीक्षा समवेश सम्भव हो पाता है। परस्पर सम्बन्धों की स्थितियों को अध्ययन का 'केन्द्र बिंदु' मानने से एक सीधी उपयोगिता के रूप में विषयवस्तु की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है वैसे तो आन्तरिक राजनीति में भी यह बात खरी उतरती है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलू और उनकी गतिशीलता सजीव रूप से जुड़ी होती है। अतः किसी एक पहलू पर विचार करने की प्रक्रिया के अन्य पहलुओं का समावेश भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उदाहरणके तौर पर जब हम अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तब अमेरिका और सोवियत के सम्बन्धों को वि-अमेरिका की विदेश नीति के लिए प्राथमिक महत्व के है, का अध्ययन भी विस्तार में आवश्यक है।

ऐसे ही जब हम सोवियत की विदेश नीति का पृथक् अध्ययन करें तो अमेरिका के साथ संबंध पुनरावृत्त करना होगा। लेकिन यदि अध्ययन का आयोजन परस्पर सम्बन्धों के आधार पर ही कर लिया जाए तो ऐसी पुनरावृत्ति स्पष्ट रूप से मुक्त हुआ जा सकता है। जहां तक प्रस्तुत, अध्ययन का प्रश्न है, हम इस दूसरे

दृष्टिकोण की उपादेयता को अधिक साधक मानते हैं। राजनीतिशास्त्र के सैद्धांतिक पक्षों को उभारने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में देखने के लिए, ऐसे दृष्टिकोण के अनन्त उपादेय आयाम हैं।

परस्पर संबंधों का अध्ययन एक वाछित विकल्प

अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की राजनीति के अध्ययन में विदेशनीति के अध्ययन की प्रणाली से हटकर राष्ट्रा के परस्पर सम्बंधों को केन्द्र बनाने का दृष्टिकोण निम्न रूप से साधक एवं औचित्यपूर्ण है।

1 विदेशनीति के अध्ययन की प्रणाली में अध्ययन का केन्द्र बिन्दु उस राष्ट्र विशेष की नीति हो जाता है एवं अध्ययन का सारा ज्ञान और समीक्षा उसी एक केन्द्र पर आश्रित होती है। जबकि यदि राष्ट्रा के परस्पर सम्बंधों पर बल दिया जाय तो अध्ययन की परिधि स्वतः ही विस्तृत हो जाती है और अध्ययन का प्रमुख स्रोत किसी राष्ट्र विशेष पर केन्द्रित न होकर, उन सम्बंधों की पारस्परिकता पर बल देता है।

2 विदेशनीति को केन्द्र बिन्दु मानने में मूल्यांकन और समीक्षा में भी स्वाभाविक अवरोध आता है। किसी नीतिविशेष का सही अथवा गलत होना, साधक अथवा निरर्थक होना—उस राष्ट्र विशेष के सम्बंध में आका जाता है। इसके विपरीत जब हम राष्ट्रा के परस्पर सम्बंधों का केन्द्र बनाते हैं तो उनका मूल्यांकन किसी एक राष्ट्र के हितों के पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं हो पाता।

3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में तुलनात्मक अध्ययन के प्रारूप की प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से भी, परस्पर सम्बंधों के अध्ययन की प्रक्रिया अधिक साधक बनती है। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनन्त सामयिक प्रश्नों पर अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही इन प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित स्वरूप समझा जा सकता है। परस्पर सम्बंधों पर अध्ययन का दृष्टिकोण ऐसे अध्ययन के लिए अधिक सुलभ है।

4 इस सम्बंध में अत्यधिक महत्व का जो प्रश्न है वह इस बात से सम्बंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध अपने आप में एक व्यवस्थित स्वरूप लिए हुए हैं। सतही तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गतिशीलता भ्रामक लगती है और विभिन्न घटनाओं में किसी भी सततता को रेखांकित कर पाना बहुधा कठिन लगता है। लेकिन अपने बाहरी आचरणों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की राजनीति की अपनी स्वयं की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इस व्यवस्थागत स्वरूप को समझने के लिए और उसका सही विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रा के परस्पर सम्बंधों का दृष्टिकोण अत्यधिक महत्व का है।

कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की एक निश्चित व्यवस्था

1 ध्रुवीय सम्बंध एक सामूहिक अस्तित्व के रूप में सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को निर्धारित करते हैं।

2 महाद्वीपीय सम्बंध प्रत्यक्ष रूप में ध्रुवीय सम्बंधों से निश्चित होते हैं, लेकिन उपमहाद्वीपीय सम्बंधों से भी जुड़े होते हैं।

3 उपमहाद्वीपीय सम्बंधों के निर्धारण में ध्रुवीय एवं महाद्वीपीय समीकरणों का स्पष्ट प्रभाव है जो कि पदसोपान की प्रक्रिया का परिचायक है।

4 व्यवस्था का स्वरूप पद सोपान का होता हुआ भी सम्बंधों की प्रक्रिया एकपक्षीय नहीं है बल्कि उनमें द्वि-द्विआत्मक परस्परता (डाइलेक्टिकल रैस्पोंस) है। अर्थात् एक ओर जहाँ ध्रुवीय एवं महाद्वीपीय सम्बंध उपमहाद्वीपीय सम्बंधों का प्रभावित करते हैं वहीं दूसरी ओर उपमहाद्वीपीय एवं महाद्वीपीय सम्बंध भी ध्रुवीय सम्बंधों के निश्चित समीकरणों को निर्देशित करते हैं।

5 ध्रुवीय सम्बंध सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्व दर्शाते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रत्येक ध्रुवीय शक्ति द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय स्तर पर अन्य राष्ट्रों से भी सलग्न रहती है।

अध्ययन का विश्लेषणात्मक प्रारूप

उपरोक्त विवेचन से कुछ मूलभूत बातें उभरकर सामने आई हैं। यह कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों के अध्ययन में विदेशनीति केन्द्रित दृष्टिकोण की तुलना में परस्पर सम्बंधपरक उपागम अधिक साधक होगा। ऐसे उपागम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों की राजनीति को एक व्यवस्थागत रूप में समझा जा सकेगा जिसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर संबंधों को एक पदसोपान की रूपरेखा में आयोजित करना भी सम्भव हो सकेगा। साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया में एक तुलनात्मक पद्धति का प्रारूप भी उभरेगा।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

विगत में हमने एक वैचारिक परिवेश प्रस्तुत किया है ताकि, हम अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों के जगत में विद्यमान पदसापान-स्थिति के सदृश में इस सारे घटनाक्रम को समझ सकें। हमारा आशय यह है कि जब तक कि हम किसी वैचारिक उपागम की मदद से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा दृष्टिकोण दिशावान नहीं हो पाएगा।

इसी परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए हमने सर्वप्रथम सोवियत अमेरिका संबंधों (विशेषतः शीतयुद्ध के सदृश में) को समझने का प्रयास किया है। स्मरणीय है कि अनेक पाठ्य पुस्तकों में इन्हें पथक पथक विदेश नीतियों में शीपक के अंतर्गत विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है जिनमें कि पिछले पोषण तथा पुनर्विनिर्माण के अलावा नया कुछ भी नहीं होता है और विद्यार्थी भी निरुत्साहित होकर रह जाते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक गुणात्मक ध्रुवीकरण के साथ प्रस्तुत हुई। यह ध्रुवीकरण गुणात्मक और अपूर्व था, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की राजनीति में किसी एकछत्रीय महत्वपूर्ण बदलाव को रक्षान्वित करने को कहा जाये तो, बिना किसी संशय के ध्रुवीकरण की इस प्रक्रिया की ओर ही इंगित करना होगा। इसके राजनीतिक आर्थिक एवं वैचारिक सभी पक्ष प्रबल थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के विकेंद्रीकरण की राजनीति थी। यह सही था कि ब्रिटेन का एक बड़ा साम्राज्य था लेकिन उसमें भी स्पष्ट रूप से दरारे पड़ने लगे थे। यूरोपीय शक्ति के रूप में ब्रिटेन की चुनौती देने वाली शक्तियाँ भी तीव्र रूप से उभरीं। जर्मनी एवं इटली का उदय सबज्ञात है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक शक्ति को एकछत्रीय शक्ति की औपचारिक अथवा अनौपचारिक मान्यता मिल पाना असम्भव था। प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र अपने आप में साम्राज्यवादी बटवारे की होड़ में था। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति इन तमाम उभरते हुए अवरोधों की साक्षी है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नवीन अध्याय है। यूरोपीय राष्ट्रों की आर्थिक शक्ति के आधार ढोलने लगे जिसकी अभिव्यक्ति उनकी राजनीतिक शक्ति पर भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। आर्थिक और राजनीतिक सकट से घिरा यूरोप अब विश्व राजनीति का रममंच नहीं रहा। शक्तिशाली यूरोप को अब सम्बल की आवश्यकता थी। उसे उभारने के लिए और उसके पुनरुत्थान के लिए एक सशक्त नवसाम्राज्यवादी शक्ति का नेतृत्व आवश्यक था। यह नेतृत्व अब तक 'प्रबुद्ध' अन्तर्भाव की नीति अपनाने वाले राष्ट्र अमेरिका ने दिया। साम्राज्यवाद का स्वरूप गुणात्मक परिवर्तन कर चुका था।

राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए अब भौगोलिक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। बदली हुई परिस्थितियों में आवश्यकता प्रभाव क्षेत्रों की थी जिनके माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक उपागमों द्वारा परोक्ष रूप से नियंत्रण हो सके। भौगोलिक क्षेत्रों से हटकर प्रभाव क्षेत्रों की प्रतिद्वंद्विता इस बदलते हुए ध्रुवीकरण का एक अभूतपूर्व आयाम था।

प्रतिद्वंद्वी व्यवस्था एक विचारधारा वाला सोवियत संघ इस नये ध्रुवीकरण की दूसरी धुरी बना। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद दो महाद्वीपों को समेटे हुए इस राष्ट्र में समाजवाद की स्थापना हुई। विश्व का एक मान्य प्रतिद्वंद्वी व्यवस्था वाला राष्ट्र होने के नाते रविवरुस की नीति में प्रारंभिक रूप से एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण बना रहा। वैचारिक रूप में विश्व स्तर पर व्यवस्था बदलाव का पक्षधर होते हुए भी रूस में इस हेतु क्षमता नहीं थी। प्राथमिक आवश्यकता रूस में समाजवाद की स्थापना और उसे साम्राज्यवादी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना था। द्वितीय विश्वयुद्ध और उसमें सांत्वानिक पूर्व की घटनाओं में रूस ने एक गहन राजनीतिक साम्राज्यवाद के उभरते अंतरविरोधों का, अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए फायदा उठाया गया। निर्णयात्मक स्थितियों में, युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय इस सूझबूझ की परीक्षापेठा था।

1945 का सोवियत संघ 1917 के सोवियत संघ के मुकाबिले कहीं अधिक सक्षम था। यूरोपीय द्वार की ओर अब उसकी सहयोगी व्यवस्थायें थी। एशियाई द्वार की ओर चीन में क्रांति की संशक्त सम्भावनायें उत्पन्न हो रही थी और उपनिवेशवाद के समापन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत व अन्य उपनिवेशों की स्वतंत्रता भी कहीं निश्चित थी। ऐसी परिस्थितियों में सोवियत का अभ्युदय न सिर्फ वैचारिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में ही हुआ। अमेरिका और सोवियत के नस्ल में ध्रुवीकरण संव्याप्त बन गया।

युद्धोत्तर काल

द्वितीय विश्वयुद्ध के पटाक्षेप के बाद सोवियत और अमेरिका के बीच के सम्बन्ध मात्र दो राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध नहीं थे बल्कि, युद्धोपरात के ध्रुवीकरण की स्पष्टतम अभिव्यक्ति थे। विश्वयुद्ध के बाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास इन सम्बन्धों के विकास से अंतरंग रूप से जुड़ा है। इन सम्बन्धों में महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का विकास की दृष्टि से और इन प्रवृत्तियों को एक ऐतिहासिक रूप से क्रमबद्ध करने के उद्देश्य से, सोवियत और अमेरिका के सम्बन्धों को निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है—

1 1945 से 1955—दुराग्रही दशक,

2 1955 से 1963—सन्तुलन सप्ताह,

3 1963 से 1973—शांति सद्भाव का दशक

4 1973 से वर्तमान—भूमिकाओं के बदलाव का काल

प्रथम चरण 1945 से 1955 दुराग्रही दशक

अमेरिका सोवियत सम्बंधों के इस प्रथम चरण की प्रमुख प्रयत्ति की शीत युद्ध की सज्ञा से भी विभूषित किया जाता है। इस काल में युद्ध के बाद उभर आये शक्ति के सतुलन के प्रति दोनों ही राष्ट्र अत्यधिक सहिष्णु और सचेत रहे। इस बदले हुए शक्ति के समीकरण में अधिक चिंता की स्थिति पश्चिमी राष्ट्रों की थी, जो कि सोवियत की तुलना में द्वितीय विश्वयुद्ध की प्रक्रिया से पहिले के मुकाबले अधिक कमजोर हो गये थे। इन राष्ट्रों की मानसिकता में एक विशेष अनिश्चितता और सुरक्षा की आवश्यकता की भावना व्याप्त थी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एकमात्र परमाणु शक्ति का राष्ट्र के रूप में अमेरिका में भले ही एक आत्मविश्वास था लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों की चिंता उस खा रही थी। जहाँ तक सोवियत का सम्बंध है वह अपनी बढ़ी हुई क्षमता के प्रति जागरूक था, लेकिन उसकी आवश्यकता तात्कालिक रूप से प्रभाव क्षेत्र को स्थापित प्रदान करने की थी न कि इस प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की। पश्चिमी राष्ट्रों से अंतर्विरोधों के बावजूद सोवियत की नीति तुलनात्मक रूप से अधिक समय की नीति थी। इसके विपरीत राजनीतिक पहल की आवश्यकता पश्चिमी राष्ट्रों के लिए अधिक थी।

शीतयुद्ध क्या है ? इस प्रश्न के परिभाषा के स्तर पर अनेक उत्तर दिये जा सकते हैं। इस अक्सर वाक्ययुद्ध की सज्ञा भी दी जाती है कुछ समीक्षकों द्वारा इसमें युद्ध की सम्भावनाओं का समावेश भी किया गया है। परिभाषा के विवाद में न उलझकर शीत युद्ध के वास्तविक तथ्यों को समझना अधिक अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में शीत युद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की वह राजनीति है जिसका उद्देश्य भौगोलिक आधिपत्य नहीं अपितु प्रभाव क्षेत्र कायम करना है। अतः शीत युद्ध के विभिन्न उपागमों में वाक्ययुद्ध राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आर्थिक उपकरण सैनिक उपकरण आदि सभी का आवश्यकतानुसार समावेश है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सीमित युद्ध की नीति भी समाहित की जा सकती है। अतः शीत युद्ध की राजनीति युद्ध की विभिन्नताओं से बचते हुए भी परस्पर प्रतिद्वंद्वी व्यवस्थाओं के विचारधाराओं और हितों की टकराव की राजनीति है। इस प्रतिद्वंद्विता के विकास में घटनाओं का एक विस्तृत चक्र है।

ट्रुमैन के बारह सूत्र

द्वितीय विश्व युद्ध के पुरातन बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमैन ने

अमेरिका के भावी विदेश नीति के नीतिपरक बारह सूत्रों की घोषणा 28 जनवरी 1945 को यह कह कर की गई—

1 अपने स्वार्थों के लाभ के लिए अमेरिका प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहता और इस सम्बंध में अमेरिका किसी भी बड़े और छोटे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा।

2 किसी भी राष्ट्र की सम्प्रभुता को बलपूर्वक छीनना गलत है और राष्ट्रों को अपनी सम्प्रभुता पाने का पूरा हक है।

3 मित्र राष्ट्रों में ऐसे तमाम प्रादेशिक परिवर्तन (जो कि जल्द की जाएंगे) की स्वतंत्र सहमति के अभाव में किये गए हों) अस्वीकार्य हैं।

4 विश्व के सभी राष्ट्रों को अपने आन्तरिक मामलों में किसी विदेशी हस्तक्षेप के निषेध का अधिकार है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के मामलों में अमेरिका के हस्तक्षेप को लागू हो।

5 अमेरिका की कामना पराजित देशों में लोकतन्त्रिक शासन की स्थापना करना है। उसकी उद्देश्य यह है कि वे स्वतंत्र और समान हों।

6 विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना किसी भी देश की सरकार को मायता नहीं मिलनी।

7 समुद्रों में आवागमन और वाणिज्यिक संचार को स्वतंत्र और समान एवं स्वतंत्र अधिकारों की आवश्यकता है।

8 सभी राष्ट्रों को बंदरगाहों, नहरों, रेलमार्गों, विमानमार्गों, तारमार्गों और व्यापार सबंधों में सहमति चाहिए।

9 जहां तक परस्पर विरोध के बिना संभव हो, अमेरिका को विश्व शांति को बनाए रखना चाहिए और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए।

निश्चित राजनीतिक अभिप्राय था। विश्वयुद्ध के दौरान पश्चिमी राष्ट्रों की सनाआ और सोवियत की सना के आधिपत्य के अनेक क्षेत्रों में अब भी विवाद सुलझाने बाकी थे। इन बारह सूत्रों का प्रमुख उद्देश्य इन विवादों के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण को स्पष्ट करना था। शासन के स्वरूप को निर्धारित करने के अधिकार का सूत्र अथवा पराजित देशों में शांतिपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन की स्थापना का रूप से उन विवादों की ओर इंगित करते थे जो पश्चिमी राष्ट्रों और सोवियत के बीच सुलझाने बाकी थे। इन बारह सूत्रों का महत्व इस बात से भी था कि ऐतिहासिक अलगाव की नीति से हटकर प्रथम बार इन सूत्रों द्वारा अमेरिका की भावी सक्रिय योगदान की नीति को परिभाषित किया गया। इस नई नीति का आधार एक तरफ पश्चिमी गोलार्द्ध में अमेरिका प्रभुत्व की असंदिग्धता थी तो साथ ही साथ पश्चिमी गोलार्द्ध से परे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में और विवादों में अमेरिका की भावी भूमिका की योजना भी थी।

दूरगम्य का विकास

ट्रूमैन के 12 सूत्र एक तरफ अमेरिकी विदेश नीति का दूरगामी प्रारूप प्रस्तुत करता था तो साथ ही साथ सोवियत संघ की द्वितीय विश्वयुद्ध के उपजे विवादों के सम्बंध में चेतावनी भी था। इस परीक्षा चेतावनी की सोवियत संघ में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। एक ओर जहां तक पूर्वोत्तर में प्रभाव का प्रश्न था सोवियत नीति अविचलित रहने का दृढ़ संकल्पित थी। अन्य प्रभाव के प्रश्न सोवियत नीति के लिए खून प्रश्न थे। इस प्रकार की सोवियत प्रतिक्रिया में अमेरिकी और विश्वपट्ट यूरोपीय राष्ट्रों की ओर अधिक विचलित किया। उनमें बीच एक निश्चित समझ उभर कर सामने आई जिसका कि मूल अभिप्राय साम्यवाद के विस्तार की नाकेबंदी करना था।

5 मार्च 1946 को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुल्टन नगर में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। इस वक्तव्य में निहित विचारों ने साम्यवाद परिसीमन के सिद्धांत को जन्म दिया। इस नई नीति का प्रमुख उद्देश्य रूस के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र के विरोध के साथ साथ इसका भावी विस्तार को रोकने की योजना तैयार करना था। चर्चिल ने इस कथन के बाद अमेरिका के ऊपर नतत्व का दायित्व था कि वह इस नई नीति के क्रियान्वयन को दोस अभिव्यक्ति दे। इस नवीन आवश्यकता के दोहरे पक्ष थे। प्रथम आधिगम्यता यूरोपीय राष्ट्रों को उनके पुनरुत्थान में सहाय्य सहयोग दिया जाय। दूसरी ओर विवादग्रस्त क्षेत्रों में जहां साम्यवाद के प्रसार की तात्कालिक आशंकाओं से नैनक

हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई जाय। इन दोहरे दायित्वा का निर्वाह अमेरिका न सभाला।

ट्रूमेन सिद्धांत एवं मार्शल योजना

इस नये दायित्व के निर्वाह के लिए मार्च 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमेन ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे ट्रूमेन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य विवादग्रस्त क्षेत्रों को आर्थिक और सैनिक सहायता देना था। तात्कालिक रूप से इस प्रतिवेदन के द्वारा यूनान को 25 करोड़ डॉलर और टर्की को 15 करोड़ डॉलर की सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रतिवेदन स्वीकार हुआ, और अमेरिकी विदेश नीति की एक नई परिपक्वी प्रारम्भ हुई। ट्रूमेन सिद्धांत विगत में घोषित किये गये बारह सूत्रों का एक प्रकार से व्यावहारिक पक्ष था। पहले घोषित सूत्र में अंतराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के सक्रिय हस्तक्षेप की बात निहित थी। ट्रूमेन सिद्धांत द्वारा उसे क्रियात्मक करने की पहल हुई। एक दृष्टि से, ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध 'मुनरो सिद्धांत' जिसमें पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिका के एक छत्र प्रभाव की घोषणा की थी, की विस्तृत अभिव्यक्ति हम ट्रूमेन सिद्धांत में पाते हैं।

अमेरिकी नीति के इस नये दायित्व के दूसरे पक्ष का निर्वाह मार्शल योजना के अंतर्गत हुआ। इसकी घोषणा 5 जून, 1947 को की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्उत्थान में सक्रिय सहयोग करना था। अंतरण रूप से इसका यह मुख्य उद्देश्य होते हुए भी, इस योजना की कतिपय वैचारिक एवं परोपकारी स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। इस योजना की घोषणा करते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री मार्शल ने कहा कि "हमारी नीति किसी देश या सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। यह भूख, दरिद्रता, निराशा और अ-यवस्था के विरुद्ध है। इसका उद्देश्य विश्व में एक ऐसी अव्यवस्था को तैयार करना है, जिससे स्वतंत्र संस्थाओं को विकसित करने वाली राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उपस्थित हो सकें। समुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा यूरोप को सहायता देने जान से यह वांछनीय है कि यूरोपीय देशों की इस सम्बन्ध में आवश्यकता के विषय में कोई समझौता हो सके। अमेरिकी सरकार के लिए न तो यह उचित होगा और न ही प्रभावशाली कि वह यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा करने वाले आर्थिक उपायों का निमाण करे। यह कार्य मूलतः यूरोपीय है, जिसकी पहल यूरोप से ही हानी चाहिए। हमारा दायित्व तो मात्र सहायता देना है।"

मार्शल योजना की घोषणा में यूरोपीय राष्ट्रों में उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। इस घोषणा के मनव्य को जल्दी से जल्दी क्रियाविध करने हेतु यूरोपीय राष्ट्र इच्छुक थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस संबंध में पहल की। इसके फलस्वरूप जुलाई,

1947 में पेरिस में 16 यूरोपीय राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक सहयोग की आधारशिला रखी गई। सम्मेलन में एक "यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति" का गठन किया गया। इस सम्बन्ध में एक 4 वर्षीय परस्पर सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। इस समिति ने अमेरिका के मמש एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि अमेरिका 13 बिलियन डॉलर धनराशि खर्च करने का आश्वासन दे तो 1951 की समाप्ति तक एक ऐसी यूरोपीय अर्थव्यवस्था स्थापित की जा सकती है जो कि पृथक् आत्मनिर्भर हो।

पश्चिमी राष्ट्रों ने इस आर्थिक प्रतिवेदन को सिद्धान्त स्वीकार किया गया और इस सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रस्ताव दिसम्बर 1947 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया। इस आर्थिक प्रस्ताव को "माशेल योजना" अथवा 'यूरोपीय राहत कार्यक्रम' के नाम से जाना गया। इसके अन्तर्गत तत्कालीन 15 माह के लिए 6 अरब 80 करोड़ डॉलर की व्यवस्था की गई और अगले 4 वर्षों के लिए 17 अरब डॉलर का प्रावधान रखा गया। इस प्रस्ताव के औचित्य पर बल देते हुए ट्रूमेन ने कहा "इन 16 राज्यों को जो कि उसी की तरह स्वतंत्र सत्ताओं की सुरक्षा एवं राष्ट्रों के बीच स्थाई शांति के लिए सकल्प बद्ध हैं, अमेरिका इन्हें इनके पुर्ननिर्माण कार्यों में सहायता देकर विश्वशांति एवं अपनी स्वयं की सुरक्षा में योगदान करे।"

यूरोपीय राहत हेतु इस आर्थिक सहायता की नियोजित क्रिया बर्तन के लिए यूरोपीय राष्ट्रों का एक संगठनात्मक स्वरूप आवश्यक था। अतः 1948 में "यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन" की स्थापना की गई। माशेल-योजना के क्रियाव्ययन से प्रेरित यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जिसमें की भविष्य में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोजन की आधारशिला भी रखी। माशेल योजना का आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट रूप में यूरोपीय राष्ट्रों पर पड़ा। एक ओर इस नीति के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में दूरगामी सामूहिक हितों का जन्म हुआ दूसरी ओर अमेरिका यूरोपीय राष्ट्रों में अपनी इच्छा से राजनीतिक बदलाव में भी सक्षम रहा। फ्रांस और इटली जहां सरकारों में साम्यवादी भी सम्मिलित थे, उन्हें इस प्रभाव के फलस्वरूप साम्यवादियों को पदमुक्त कर दिया गया। अतः अमेरिकी पहल द्वारा यूरोप पर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव स्थापित हुआ।

सोवियत प्रयास

अमेरिका के नवत्व में हो रही उन विभिन्न चेष्टाओं के विरोध में और कुछ इसने समानांतर सोवियत के प्रयास भी रहे। शीतयुद्ध के सन्दर्भ में वस्तुतः

सोवियत और अमेरिका के सम्बन्धों की समय-परीक्ष रूप से किये गये प्रयासों में ही देखने को मिलती है। परस्पर सम्बन्धों में स्थिरता इस प्रारम्भिक काल में दोनों राष्ट्रों के बीच का द्वन्द्व-परीक्ष माध्यमों का द्वन्द्व था। विश्वयुद्ध के दौरान हुए विभिन्न शांति सम्मेलनों में याल्टा का सम्मेलन अत्यधिक राजनीतिक महत्व का था। अनेक विषयों पर सहमति के बावजूद इस शिखर सम्मेलन में भी बहुत से विवाद के प्रश्न बच गये थे। इन प्रश्नों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक वर्षों तक अपनी तात्कालिकता बनाये रखी। सोवियत की नीति के दो पक्ष थे। प्रथम तो यह कि अमरिक्का रूप से उसके प्रभाव में आ चुके क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन न किया जाये और इन क्षेत्रों को प्राथमिक रूप से द्विपक्षीय वार्ताओं व संधियों द्वारा स्थायित्व दिया जाय। द्वितीय, उनके आर्थिक विकास को समाजवादी व्यवस्था के अनुकूल विकसित कर सोवियत आर्थिक व्यवस्था से अन्तरगता से जोड़ा जाय।

सन 1946 से लेकर 1949 तक सोवियत संघ ने 17 द्विपक्षीय सम्मेलन किये। युद्ध के दौरान ही पोलैण्ड से संधि हो चुकी थी। जुलाई, 1947 में चेकास्लोवाकिया के साथ भी एक संधि की गई। फिनलैण्ड के साथ 1947 में शांति-संधि और उसके उपरान्त अप्रैल 1948 में एक मैत्री संधि स्थापित हुई। फिनलैण्ड के साथ किये गये सम्मेलन से सोवियत की एक विशेष नीति स्पष्ट हुई। वह यह कि, ऐसे राष्ट्रों से भी जिनमें समान व्यवस्था लागू करमा व्यावहारिक न हो उनके साथ भी शांति स्थापित की जाय अर्थात्, जिन्हें स्पष्ट रूप में प्रभाव में न ला सके उन्हें कम से कम तटस्थ बनाने का प्रयास तो किया जाये। संधियों के इस उभरते स्वरूप से, सोवियत की नीति का एक और पक्ष भी उदघाटित होता है इस दृष्टिकोण के अनुसार यह प्रतीत होता है कि सोवियत प्रारम्भिक रूप से बहुपक्षीय सैनिक गठबंधनों के पक्ष में नहीं था अपितु इसकी तुलना में वह द्विपक्षीय आधार पर सम्मेलनों द्वारा राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र का स्थायित्व चाहता था।

राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय प्रक्रिया की तुलना में आर्थिक प्रश्नों के संबंध में सोवियत का दृष्टिकोण भिन्न था। आर्थिक पुनर्उत्थान और एकीकरण की योजना को सोवियत बहुपक्षीय प्रारूप देने का पक्षधर था। 1947 से ही सोवियत ने पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों की औद्योगिक विकास और इसकी अर्थव्यवस्थाओं को सोवियत अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मतलब व्यक्त किया। ऐसे प्रारूप का प्रस्ताव 'मॉलोटोव योजना' के अंतर्गत किया गया। 1947 से 1949 के बीच तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए कुछ द्विपक्षीय आर्थिक सम्मेलन भी किये गये। लेकिन मासल योजना के सक्रिय होने के बाद सोवियत ने भी 1949 में भी सभी पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों की एक आर्थिक परिषद गठित की जिसे 'कोमिन्वॉन' अथवा 'पारस्परिक'

आर्थिक सहायता परिषद् की सज्ञा मिली।

आंतरिक रूप में सोवियत संघ ने तीव्र आर्थिक विकास की विस्तृत योजना तयार की। इसका उद्देश्य सोवियत की आर्थिक क्षमता को जो कि ऐतिहासिक कारणों से पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में पिछड़ी हुई थी शीघ्र से शीघ्र पश्चिम के समक्ष लाना था अथवा सोवियत के लिए आंतरिक और पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों के आर्थिक दायित्वों का निर्वाह करना सुनिश्चित था। आर्थिक विनाश पर अत्यधिक रूप से बल देना सोवियत की यथायवादी एवं दूरदर्शी दृष्टि का परिचायक था। अपने वैचारिक दायित्वों के निर्वाह के लिए भी अपने सीमित संसाधनों के बावजूद सोवियत कुछ कुछ सक्रिय रहा। तत्वीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखते हुए सोवियत के वैचारिक प्रसार की नीति में अधिक यथायवादी दृष्टिकोण अपनाया। 1947 में वासा में सम्पन्न पूर्वी यूरोपीय और कुछ पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के साम्यवादी दलों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एक नये मंच कायम फाम अथवा साम्यवादी सूचना संस्थान की स्थापना की गई वस्तुतः इसका मुख्य उद्देश्य स्थापित हुआ। इस संस्था की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य को रखा किंतु करत हुए इसका घोषणा पत्र में कहा गया कि द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका का सम्मिलित होना विश्व बाजार के बटवार की प्रयोगिता में अपने हितों को सर्वोपरि बनाने के उद्देश्य से प्रेरित था जबकि सोवियत संघ का यूरोप में युद्ध से सार्थक स्वतंत्रता और लाक्षणिक पुनर्स्थापन से प्रेरित थी। कायम फाम का दायित्व साम्यवादी आंदोलन को वैचारिक नेतृत्व देना और पश्चिमी विचार धारा का प्रत्युत्तर देना था।

इन विभिन्न चप्टाओं में अमेरिका के प्रत्युत्तर के रूप में सोवियत की नीति के विभिन्न आधार स्पष्ट होते हैं। जयन्त विचारधारा के प्रसार का प्रश्न माध्यमिक वरीयता का हो जबकि प्रभाव क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण का प्रश्न प्राथमिक दायित्व का हो। इन क्षेत्रों में भी राजनीति एवं सैनिक एकीकरण से पूर्व आर्थिक एकीकरण पर महत्व की नीति सोवियत ने एक विशिष्ट दृष्टिकोण की परिचायक है।

विस्फोटक राजनीतिक स्थिति

अपन-अपन प्रभाव क्षेत्रों को सुनिश्चित एवं एकीकृत करने का सोवियत और अमेरिका की नीति समांतर रूप से जारी रही। ये चप्टायें चूँकि स्वयं के प्रभाव क्षेत्रों से संबंधित थीं और किन्हीं अथवा राष्ट्रों पर सीधे प्रभाव डाली नहीं थी अतः इन घटनाओं के प्रति सोवियत और अमेरिका में परस्पर विरोध होते हुए भी यह विरोध विस्फोटक नहीं बना। किन्तु इस काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे राजनीतिक प्रकरण भी आये जिन्होंने सोवियत और अमेरिका के सम्बंधों में

एक रूप में विद्योत्पत्ति विधियाँ पदा की। एमी कुछ स्थितियाँ जिनके द्वारा द्वा
महाभारतिका व बीष श्री १ मुद्रा की गजतीति विनमिता हुई प्रमुत्त रूप में विमना
विता है।

जमन विवाद में भूतना की मयन महत्त्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाली
स्थिति थी। द्वितीय विश्वयुद्ध की सामरिक नीति व कृतकृत्य जमनी व पूर्वी
भाग पर रूप की आधारित या ता विनमिता भाग पर यूरोपीय गजतीति था। यान्ता
जिनके सम्मेलन में भा हन मयन व मयनामिति की बनाय गजतीति मयन व यद्वर नाइ
अनिम विनमिता सम्भव नहीं हो सका था। मन् १९४७ की दूमा घापणा और
भागत योजना व भाग-भाग विनमिता जमनी व दूबडा का जाहिर विनमिता जमन
जिनकी को गजतीति करती का विनमिता द्वा का अभियान यमा जिनका प्रथम परण
था— मुद्रा परिवर्तन मुद्रा परिवर्तन करती ही जमन भाग का भागी व्यापारिक
व भागत प्रणम व मयन द्वा मयन और विनमिता जिनका न अपने अपन अधीन
हलाकों का जोहता गुरु विनमिता। द्वा परिवर्तन जमना ता गजतीति करती की बाधयाही
गुरु हुई उपर मन् १९४७ में इनके मयन विनमिता और भाग जुड़े विनमिता यद्वर
समि मयन घेर का और व्यापक बनाया जा गजतीति और एमी नीव लादी जा रही
थी जिनके गजतीति मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन
'उत्तरी गजतीति मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन मयन
के राती भाग विनमिता जा रहे थे एमी अनिविषय की विनमिता म साविद्यत द्वारा मन्
१९४८ में मोलन गजतीति की गुरुभागत नाविकती करती गई। रूप के मयन कदम
ने पश्चिमी राष्ट्रों की सीधी राजनीतिक चुनौती दी और वास्तव में एक अंतर
राष्ट्रीय मयन उत्पन्न हो गया। जहाँ मयन नाविकती व नाविकती प्रभाव का
प्रदम था, जमनी उपयोगिता का निरर्थक मिट्ट करती हेतु पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा
हुवाई माध्यम में अनेक राजनीतिक मयन पश्चिमी समयन वाल मयन जहाँ की पूर्वी
जमनी म बाहर लाया गया। मई, १९४८ में नाविकती समाप्त की गई। इसके बाद
विनमिता फास और अमरिका व अधीनस्थ जमनी व तीना पश्चिमी क्षेत्रों का एकी
करण पूरा कर दिया गया और औपचारिक रूप से २१ सितम्बर, १९४९ को
संघीय जमन गणराज्य की स्थापना कर दी गई। इसके बाद संविद्यत संघ की
विवश हाकर अपने अधीनस्थ जमन भाग में ७ अक्टूबर, १९४९ को जमन प्रजा
सत्तात्मक गणराज्य व रूप में गठन करना पडा। जमनी अत में बट के रहा। द्वा
जमन राष्ट्रों का औपचारिक अस्तित्व प्रबल हो गया। यह सही है कि अब भी
पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा पूर्वी जमनी व अस्तित्व को मा यता नहीं दी, लेकिन साविद्यत
के द्वारा पश्चिमी जमनी को भी मा यता प्रदान नहीं की गई।

जमन विवाद के एकदम विपरीत अनुभव, ईरान यूनान और टर्की को घट
नामा से मिलता है। द्वितीय विश्वयुद्ध व दोगान सनिक जाधिपत्य को देखते हुए

यहां पर भी भावी प्रभाव की लड़ाई थी। लेनिन सोवियत की सामरिक नीति को देखते हुए यह क्षेत्र पूर्वी यूरोप की तुलना में न तो उस तीव्र सामरिक महत्व के थे और न ही इन क्षेत्रों में सतत हस्तक्षेप की सोवियत के पास क्षमता था। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप को सोना पश्चिमी राष्ट्रों के लिए एक निश्चित तथ्य बन चुका था और इस सम्बंध में पश्चिमी राष्ट्र कम या अधिक असहाय ही थे। लेनिन ऐसी स्थिति इन दूसरे प्रदत्तों के सम्बंध में नहीं थी। न तो रूस की यह कोई तात्कालिक प्राथमिकता थी और न ही ऐसा कोई हस्तक्षेप पश्चिमी राष्ट्रों को मान्य था। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में सोवियत सेनाएं ईरान के एक भाग में जमी रही थीं और टर्की पर भी सीमित आधिपत्य बनाये रखा। लेनिन ईरान से शीघ्र ही सोवियत सनाओं का हटना पड़ा और बाद में ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत दी गई बाहरी सहायता के फलस्वरूप यूनान और टर्की को भी पश्चिमी राष्ट्र सोवियत के प्रभाव से स्वतंत्र कराने में सफल हुए। सोवियत टर्की यूनान और ईरान में हस्तक्षेप की नीति वस्तुतः पूर्वी यूरोप की समस्या को सुलझाने में पश्चिमी राष्ट्रों पर अत्यंत दबाव बनाए रखने की आवश्यकता की नीति थी। इस नीति ने सोवियत संघ का वांछित सफलता भी दी।

शीत युद्ध की विस्फोटक स्थितियां में ऐतिहासिक महत्व की स्थिति कारियाई युद्ध रहा। द्वितीय महायुद्ध में पूर्व कोरिया जापान के आधिपत्य में था। युद्ध की प्रक्रिया के दौरान कोरिया के उत्तरी भाग पर सोवियत सनाओं का और दक्षिणी भाग पर अमेरिकी सनाओं का आधिपत्य स्थापित हुआ। युद्ध के बाद एक अस्थाई सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत 38वीं समानांतर रेखा द्वारा कोरिया का विभाजन हुआ। इस विभाजन के बावजूद नौ दानों पक्षों में टकराहट की स्थिति बनी रही। सन 1950 में कोरिया विवाद ने एक नाटकीय मोड़ लिया। जून, 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण का आरोप लगा जबकि तथ्य इसका विपरीत थे। इस संबंध में 25 जून, 1950 को दक्षिणी कोरिया की ओर से एक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष रखा गया। इन दिनों चीन की सहायता के प्रश्न पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बहिष्कार की नीति अपना रखी थी। अतः विवाद सुरक्षा परिषद में आया तो सोवियत की अनुपस्थिति में एक प्रस्ताव पारित कर उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित किया गया और दक्षिणी कोरिया को सहायता प्रदान करने का आवाहन किया गया।

इस सम्बंध में अमेरिका ने नतत्व में एक संयुक्त राष्ट्र सेना के गठन का निर्णय हुआ। रूस की अनुपस्थिति में अमेरिका ऐसे निर्णय के प्रति पहले से ही आश्वस्त था। कोरिया के समीप ही अमेरिका का सातवां नौ सैनिक बेड़ा उपस्थित था। सुरक्षा परिषद के निर्णय के तुरंत बाद इस बेड़े से अमेरिका का ध्वज उतार

कर राष्ट्र सघ का ध्वज फहरा दिया गया और इस दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए उपस्थित किया गया। युद्ध जब बढ़त बढ़त चीन की सीमाओं का छूने लगा तब बाध्य होकर चीन को उत्तरी कोरिया में अपने सैनिक भेजने पड़े जिससे युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया और जब तब कथित संयुक्त राष्ट्र सेना को ढकेलना शुरू हुआ तब स्थिति बिल्कुल बदल गई। स्थिति की तात्कालिक गंभीरता को समझते हुए सोवियत सघ ने अपना बहिष्कार खत्म किया। करीब एक वर्ष के युद्ध के बाद युद्ध विराम अंतरिम रूप से लागू हुआ। औपचारिक रूप से युद्ध की समाप्ति तटस्थ राष्ट्रों के एक आयोग की सहायता में 27 जून 1953 को सम्भव हो पाई। इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सघ की सैनिक कायबाही का भी अंत हुआ। कोरिया विवाद का वास्तविक एवं अंतिम हल तो इस पूरी प्रक्रिया से नहीं हो पाया, लेकिन कोरियाई अनुभव ने एक ओर हस्तक्षेप की नीति की सीमित साधकता को स्पष्ट किया दूसरी ओर शीतयुद्ध की राजनीति को उसकी चरम अभिव्यक्ति तक पहुंचा दिया।

सैनिक गठबंधनों की रणनीति

द्वितीय विश्व युद्ध के गर्भ से उपजी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में सैनिक गठबंधनों की रणनीति का एक विशिष्ट स्थान है। दो खेमों का नतत्व कर रही महाशक्तियों के लिए यह स्वाभाविक आवश्यकता थी कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र को आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से ही नहीं अपितु, सैनिक एकजुटता के माध्यम से भी एकीकृत करें।

इस सम्बंध में पहले पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा की गई क्योंकि उनके दृष्टिकोण में साम्यवाद के बड़े हुए खतरे निपटने के लिए सैनिक तत्परता की भी आवश्यकता थी। अप्रैल, 1949 में ही पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन स्थापना का निणय ले लिया गया। 'नाटो' की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सभी पश्चिमी राष्ट्रों को साम्यवादी खतरे के विरोध में सैनिक रूप से एकजुट करना था। इसी दृष्टि से बाद में सितम्बर 1951 को जापान के साथ भी एक संधि क्रियावित्त की गई, जोकि अनिश्चितकालीन थी। 'नाटो' के गठन के बाद पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा नवम्बर, 1949 में परस्पर प्रति रक्षा सहायता कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 'नाटो' की रणनीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करना था। इन चेष्टाओं द्वारा अमेरिका ने अपने प्रथम प्रयास के रूप में निकट के पश्चिमी राष्ट्रों को सैनिक रूप से प्रतिबद्ध किया।

इस प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अमेरिका की कामना अर्थात् सहयोगी राष्ट्रों को भी इसके प्रति प्रेरित करना था। इस उद्देश्य से अक्टूबर, 1951 में अमेरिका द्वारा पारस्परिक सुरक्षा सहायता उपयोग कानून पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत अमेरिका ने अर्थात् राष्ट्रों में उसके साथ सैनिक संधि करने का आह्वान

किया और ऐसे राष्ट्रों को सैनिक महायत्ना देने के लिए सात अरब 33 करोड़ डालर का प्रावधान रखा गया। इसके तत्काल बाद दिसम्बर, 1951 में आस्ट्रेलिया और यूजोल्ड के साथ मुरदा संधि की गई और तत्पश्चात् चीन ही फिलिपीन के साथ। इन द्विपक्षीय संधियों का अंतिम उद्देश्य एक नये सैनिक गठबंधन का निर्माण था। इसकी त्रिवारिता मई 1954 में दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन की स्थापना के रूप में हुई। इस संगठन का उद्देश्य प्रमुख पश्चिमी राष्ट्रों, मेक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रों का एक बृहत् सैनिक संगठन तैयार करना था। पश्चिमी एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संधि संगठन जिम बगदाद संधि का नाम भी जाना गया की स्थापना 1955 में की गई। इस प्रकार अमेरिकी विदेश नीति ने एक ओर पश्चिमी राष्ट्रों को तो साथ ही साथ अन्य मित्र राष्ट्रों का भी सैनिक रूप में प्रतिबद्ध किया।

सैनिक संधियों की राजनीति की इन प्रतिष्ठा इतना में सोवियत संघ की दृष्टि एक रूप में मुख्यात्मक ही रही जो कि उसकी तत्कालिक सामर्थ्य की परिचायक थी। सैनिक संधियों की पहल पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा की गई और एक लम्बे समय तक सोवियत संघ ने उसका कोई विशेष प्रत्युत्तर नहीं दिया। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा तत्काल सैनिक संगठनों के निर्माण के बाद, 14 मई 1955 को वारसा संधि की स्थापना हुई। इसका प्रभाव क्षेत्र पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों तक सीमित था। सामूहिक सैनिक गठबंधन की नीति के विपरीत सोवियत नीति ने द्विपक्षीय मंत्री संधियों पर अधिक बल दिया जो कि उसकी विदेश नीति के एक निरंतर सूत्र के रूप में स्थापित हुआ। बाद में साम्यवादी क्रांति के बाद सोवियत की पहल पर उसके साथ मैत्री संधि हुई। भविष्य में भी जहाँ वही साम्यवादी व्यवस्था अथवा सोवियत की पक्षधर सरकार का उदय हुआ। सोवियत विदेश नीति का उद्देश्य इन राष्ट्रों को किसी बृहत् सैनिक गठबंधन में बांधने का नहीं था। इन राष्ट्रों के साथ सम्बंधों में भी सोवियत ने द्विपक्षीय मैत्री संधि की नीति को ही अपनाया। अंतर-राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि इस नीति के फलस्वरूप उसकी उत्तरोत्तर मफलता मिली। वर्तमान में, जब पश्चिमी राष्ट्रों के बृहत् गठबंधन का तो विघटित हो चुके हैं अथवा निष्क्रिय प्रायः हो रहे हैं द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से सोवियत के प्रभाव में निरंतर वृद्धि हुई है।

पुराग्रही काल का अवसान एक समीक्षा

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का दशक एक ऐसी प्रक्रिया का दशक था जिसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के पुराने समीकरण नष्ट हो चुके थे, और एक नये समीकरण का उदय हुआ था। स्वाभाविक है कि किसी भी बदलाव की स्थितियों के प्रारम्भिक रूप अत्यधिक अनिश्चित, संशयपूर्ण और

परस्पर दुराग्रह भाव के होते हैं। इस दशक में सोवियत और अमेरिका के सम्बन्ध भी इस स्वाभाविकता की पुष्टि करते हैं। सन 1945 एवं नये बदलाव का प्रथम पड़ाव था। 1955 तक यह बदलाव की स्थितियाँ अनिश्चितता के दौर से गुजरती हुई, एक निश्चिन्न स्थायित्व पा चुकी थी। इस स्थायित्व का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई मानसिकता के रूप में पदापण हुआ। यह सही है कि पश्चिमी राष्ट्रों के सोवियत व्यवस्था और हितों के प्रति मूलभूत अतिविरोध थे। लेकिन इतिहास ने इस परस्पर विरोधी व्यवस्था और हितों के उन्मूलन की सम्भावना समाप्त कर दी थी। साम्यवादी व्यवस्था और रूस अब एक ऐतिहासिक सत्य बन चुके थे। सोवियत मध्य में भी इस बीच अपनी औद्योगिक एवं सैनिक प्रगति के कारण एक नये आत्म विश्वास का सूत्रपात हुआ। पश्चिमी राष्ट्रों से अब वह शांतिपूर्ण प्रतिद्वंद्विता करने को सक्षम था। अतः दुराग्रही दशक के अवसान के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भावनाओं ने भी जन्म लिया। लेकिन यह सम्भावनाएँ उतनी ही अनिश्चित थी जितनी कि यह उभरती हुई नई मानसिकता।

द्वितीय चरण

संक्रमण सप्ताह 1955-1963

सोवियत और अमेरिका के परस्पर सम्बन्धों के विकास का यह द्वितीय चरण वस्तुतः संक्रमणकाल था। नेतृत्वकारी बदलाव वैचारिक स्तरों पर पुनर्समीक्षा और बदली हुई आर्थिक एवं राजनीतिक अपेक्षाओं का फलस्वरूप उस काल का उदघाटन दूरगामी महत्त्व का था। लेकिन चूंकि यह काल एक नये संक्रमण की प्रक्रिया को दर्शाता है अतः इसमें कुछ ऐसी घटनाओं का भी समावेश है जो भले ही सीमित समय के लिए इस प्रक्रिया को स्थिर अथवा प्रतिगामी तक बना गयीं। जहाँ तक बदलाव की एक दूरगामी दृष्टि का प्रश्न है इस चरण में इसका असंदिग्ध निरूपण हुआ। बदलाव के इस दूरगामी दृष्टिकोण के विकास में निम्न बातें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रही।

1. सोवियत व्यवस्था में नेतृत्व परिवर्तन का तात्पर्य सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की स्थितियों से नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया अपने आप में विविध प्रकार के वैचारिक मध्यम से अन्तरण रूप में जुड़ी होती है सन 1953 में स्टालिन के देहांत के बाद एक ऐसा ही वैचारिक मध्यम लेखन का मिला, जो कि न सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्नों अपितु आन्तरिक राजनीतिक प्रश्नों से भी जुड़ा था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में सोवियत मध्य अपनी एक नई दूरगामी भूमिका को परिभाषित करना चाहता था। जहाँ तक उसकी क्षमता का प्रश्न था वह पिछले दशक में अत्यधिक तीव्रगति में बढ़ी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न शक्ति का संतुलन स्थायित्व पा चुका था। अतः रूस के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि

कोण में कुछ ऐसे गुणात्मक तत्त्वों के समावेश की आवश्यकता थी जो एक ओर तृतीय राष्ट्रा में समाजवादी व्यवस्था के प्रति साफ पैदा कर सकें और साथ ही साथ आर्थिक राजनीतिक एवं सामरिक क्षमता के स्तर पर पश्चिमी राष्ट्रो के साथ उसकी समानता को स्वीकार करा सकें। इस नवीन आवश्यकता का निर्वाह सोवियत न दूरगामी नीति तैयार करके किया।

महत्व का बन गया। वैचारिक और राजनीतिक मथन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का 20 वा अधिवेशन ऐतिहासिक वाण बिजयी रहा और उनका नेतृत्व भी स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्तृत महत्व का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धान्त इस अधिवेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धान्त का प्राथमिक तात्पर्य पश्चिम की साम्राज्यवादी व्यवस्था से जुझने के लिए एक बहुचरणीय द्वन्द्व की राजनीति तयार करना था। तात्कालिक रूप में इस विराधी व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकारा जाए और ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहिष्णुता की अवस्था स्थापित हो। इस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवस्था को सोवियत संघ का तृतीय राष्ट्रो में प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने हेतु प्रयुक्त किया जाय। इस सम्बन्ध में तृतीय राष्ट्रो के प्रति आर्थिक एवं राजनीतिक सहायता का एक समुचित दृष्टिकोण हो जो कि तात्कालिक रूप में उग्र दोखने वाला न हो और जिसके द्वारा तृतीय विश्व के साथ एक दूरगामी सम वय की नींव डाली जाये। इस सम्बन्ध में तृतीय राष्ट्रो में आंतरिक व्यवस्था परिवर्तन के सम्बन्ध में गर पूँजीवादी विकास का पथ का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धान्त का मूल तात्पर्य यह था कि विकास के ऐतिहासिक क्रम में तृतीय राष्ट्रो के लिए यह संभव है कि वे पूँजीवाद की स्थिति से गुजरे बिना समाजवादी व्यवस्था की ओर उन्मुख हो सकते हैं। ऐसी सम्भावना उन स्थितियों में उभर सकती है जबकि इन राष्ट्रो को साम्राज्यवाद के शोषण से मुक्त होने का अवसर मिले और साथ ही साथ समाजवादी व्यवस्था का सहयोग भी। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के इस बीसवें अधिवेशन के बाद तृतीय राष्ट्रो की आर्थिक, सैनिक एवं राजनीतिक सहायता की नीति सोवियत संघ की विदेशी नीति का स्तम्भ बन गई। सोवियत मायसा थी कि यदि तृतीय राष्ट्रो से साम्राज्यवादी व्यवस्था के आर्थिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाय तो स्वतन्त्र ही साम्राज्यवादी व्यवस्था विनाश निश्चित हो जायगा। इस दृष्टि से सोवियत संघ की यह नई नीति तन्त्र द्वारा अभिव्यक्त ऐसी ही धारणा का परिमार्जित और व्यावहारिक स्वरूप था। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के इस 20वें अधिवेशन ने सोवियत विदेश नीति के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका की नई दिशा दी और अभिप्राय स्वरूप विदेश राजनीति में एक नये अध्याय का सूत्रपात किया।

2 अमेरिका की विदेश नीति के सम्बन्ध में भी आइजन हावर के आगम के बाद एक नई मानसिकता का जन्म होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति सक्रिय हस्तक्षेप की नीति रही थी लेकिन इस नीति का अनुसरण करते हुए अमेरिका का कोई विशेष सफलताएँ अर्जित न हो सकी और वह अनेकों जगह अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में फँस गया। ऐसी स्थिति का अमेरिका की आन्तरिक राजनीति में भी मूल्यांकन प्रारम्भ हुआ भले ही यह मूल्यांकन अत्यधिक तटस्थ था। कोरिया का विवाद एक उच्चतम विवाद था। स्वयं आइजन हावर ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जिस पर वे जीते अमेरिकी जनता का आश्वासन दिया था कि वे शीघ्र ही कोरिया विवाद को सुलझायेंगे और वहाँ पर अमेरिकी उपस्थिति का अन्त करेंगे। कोरिया के सम्बन्ध में तो यह एक नई नीति का परिचायक था भले ही अतः आइजन हावर ने अमेरिका के सीमित हस्तक्षेप की नीति जानी रखी थी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें अधिवेशन के बाद अमेरिकी मानसिकता में कुछ प्रारम्भिक बदलाव हुआ। वह सोवियत संघ के साथ संबंध बढ़ाने का आधिकारिक रूप से तत्पर हुई। इस बीच राष्ट्रपति आइजन हावर ने सीमित हस्तक्षेप की जो नीति अपनाई थी उसके अधिकांशतः प्रतिकूल परिणाम ही रहे। मध्यपूर्व में उनकी सैनिक सहायता की चेष्टाओं की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। 1958 में लेबनॉन जामूसी काण्ड और उसकी विश्व समूह द्वारा भत्सना अमेरिकी नीति के लिए सकोच का विषय बन गई और 1958 में ही ईराक में आन्तरिक शांति का विफल करने के ब्रिटिश और अमेरिकी प्रयत्न घराशाही हुए। इन सबने अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक नई दूरगामी मानसिकता की स्थितियाँ उत्पन्न की।

3 जहाँ तक परस्पर शक्ति के सन्तुलन का प्रश्न था, पिछले दशक में सोवियत संघ अपने विकास के द्वारा सामरिक रूप से अमेरिका के समक्ष आ गया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका की एकछत्र शक्ति उसके परमाणु आयुधों ने स्थापित की जो कि अन्य राष्ट्रों के पास नहीं थी। लेकिन इस बीच रूस ने बाहरी हस्तक्षेप की तुलना में अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने पर अधिक बल दिया। रूस द्वारा परमाणु आयुध तैयार कर लिये गये। यही नहीं अत्यधिक गोपनीयता के बाद रूस ने 1951 में समस्त विश्व को इस बात में स्तब्ध कर दिया कि उसके द्वारा विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया। इसी बीच सोवियत संघ ने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के सफल परीक्षणों की घोषणा भी की। अब यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो गया था कि आणविक हथियारों की तकनीक की जो सर्वाधिकारिता पश्चिम के पास थी वह अब नहीं रही। अतः भावी विश्वयुद्ध की कल्पना अत्यधिक भयंकर बन गई। शक्ति के इस नये आणविक सन्तुलन को कुछ विचारकों ने अत्यधिक सटीक रूप से 'भय के सन्तुलन' की परिभाषा दी है। वस्तुतः स्थिति

भी अब ऐसी ही बन गई थी। टकराहट की खुली राजनीति का अवसान अपरि-
वर्तनीय निष्कप बन गया।

अंतर्राष्ट्रीय सवध

शिथिलता का शंशक काल

रुइचेव के आगमन से पूर्व ही अथ राष्ट्रों के साथ मत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने की प्रक्रिया रूस की विदेश नीति में प्रारम्भिक रूप से आ चुकी थी। 1953 से लेकर 1955 के बीच रूस द्वारा अथ राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। कोरिया सफट में ठहराव की स्थिति के बाद रूस ने फिलैंड से अपने सैनिक अड्ड हटाय और जापान के साथ शांतिपूर्ण सम्बन्धों की पहल की। पश्चिमी जर्मनी यूनायन और इजरायल के साथ भी द्विपक्षीय स्तर पर सुधारने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। आस्ट्रिया के साथ एक संधि की गई और यूगोस्लाविया के साथ भी कामिनीफ म के समापन के बाद सम्बन्ध सुधारने के प्रयास हुए। रुइचेव ने अपने आगमन के तुरंत बाद अप्रैल, 1956 में अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के बढ़ाने की दृष्टि से ब्रिटेन एवं यूरोपीय राष्ट्रों का भ्रमण किया। इसका पहले ही 1954 में 4 महाशक्तियों का जमन विवाद पर सम्मेलन हो चुका था जिसने जेनेवा समझौते का माग प्रस्तुत किया था। अपने इन सौहार्दपूर्ण वातावरण के प्रयासों के बाद सोवियत संघ ने अमेरिका की ओर रुख किया 1959 में सोवियत उपप्रधानमंत्री ने अमेरिका की ओर भ्रमण किया और उचित पष्ठ भूमि तैयार होने पर सितम्बर, 19 9 में रुइचेव की अमेरिका की यात्रा हुई। इस यात्रा ने दोनों राष्ट्रों के बीच एक नई समझौदा की ओर यह निणय लिया गया कि 16 मई 1960 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर विचार करने हेतु इन महाशक्तियों और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन की योजना सौहार्दपूर्ण वातावरण में की गई थी। सम्मेलन की तयारियां हो चुकी थी कि इसी बीच विमान कांड अप्रत्या-
शित रूप से घटा। अमेरिकी विमान सोवियत क्षेत्र में जावूसी कर रहा था और उसे मार गिराया गया। इसमें तात्कालिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। प्राश्निक रूप से अमेरिका ने जावूसी के कृत्य को उचित ठहराया लेकिन सोवियत एवं अन्य विश्व द्वारा भी इस घटना की अत्यधिक निंदा होने पर अमेरिका को उसका लिए क्षमा याचना भी करनी पड़ी। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और सयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर जो नाटकीय घटनाचक्र चला, जिसमें रुइचेव ने अपनी बात पर जोर देते हुए अपने जूते को मेज पर बार बार पटका पेरिस शिखर सम्मेलन सटार्ड में पड़ गया। अंत में इस स्थिति ही बनना पड़ा। यद्यपि इस रूस की अनुपस्थिति में भी औपचारिक रूप से आयोजित करने का प्रयत्न प्रयास भी

हुए। पेरिस शिखर सम्मेलन का आयोजन में एक और भी विवाद था जो कि अधिक वास्तविक महत्व का था। पश्चिमी जर्मनी जर्मन विवाद को इस सम्मेलन में नहीं आन देना चाहता था, जबकि सोवियत संघ की यह इच्छा थी कि इस विवाद पर जो यथास्थिति है उस पर अंतिम और औपचारिक सहमति हाँ जाये अभी तक पूर्वी जर्मनी व स्वतंत्र अस्तित्व को पश्चिम ने नहीं स्वीकार किया था और उसे सोवियत संघ के अधीन मानते हुए, राजनयिक औपचारिकतायें सोवियत संघ के माध्यम से ही की जाती थी। पेरिस शिखर सम्मेलन के अवसर पर राजनयिक परिपत्र और बीसा पूर्वी जर्मनी द्वारा जारी किये जाने लगे। इस पर तीव्र प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अंत में एक मध्यमार्गी निणय लिया गया कि यह परिपत्र जारी ता सोवियत संघ द्वारा ही किये जायेंगे लेकिन उसमें इस बात का भी उल्लेख होगा कि उह पूर्वी जर्मन सरकार की ओर से जारी किया जा रहा है। इस विवाद ने भी पेरिस सम्मेलन के पूव सशय की स्थिति पैदा कर दी थी। अंत में 'यू टू' काण्ड जैसे बिस्फोटक अवसर के आन के बाद पेरिस सम्मेलन का तात्कालिक रूप से स्थगित होना एकदम सुनिश्चित बन गया था।

केनेडी और क्यूबा संकट

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में केनेडी का दृष्टिकोण भी मूलतः पुराने प्रशासन में भिन्न नहीं था। चुनाव के बाद अपनी प्रथम घोषणा में केनेडी ने भी वही नीति ब्यक्त की जिसके कि दोहरे आधार थे, मित्र राष्ट्रों की असंदिग्ध सहयोग और अन्य राष्ट्रों में हस्तक्षेप की नीति में क्रमिक कमी। केनेडी काल में रूस और अमेरिका के बीच सोहराई की पुनः औपचारिक वापसी हुई। इसी समय दोनों राष्ट्रों के बीच खुले आकाश से सबधित अणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर भी हस्ताक्षर हुए। अपने विभिन्न भाषणा में सितम्बर 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषण और उससे पूर्व जून 1963 में भी राष्ट्रपति केनेडी के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा और परस्पर प्रतिद्वंद्वी व्यवस्थाओं में सह अस्तित्व की बात पर बल दिया। एक बार फिर दोनों राष्ट्रों के बीच सोहराईपूर्ण स्थिति बनी। लेकिन इसी बीच ऐतिहासिक क्यूबा संकट की घटना हुई जिसे शीतयुद्ध का चर्मोत्कष भी कहा गया है।

जून 1959 में क्यूबा में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में वामपंथी क्रांति हुई। यह घटना अमेरिका के लिए अत्यधिक चिन्ताजनक थी क्योंकि अमेरिका की परम्परागत स्थिति पश्चिमी गोलार्द्ध में एकछत्र वचस्व की थी, जिसे इस घटना के रूप में अप्रत्याशित चुनौती मिली। क्रांति के बाद क्यूबा और सोवियत संघ के बीच जनरल सम्बन्धों का विकास हुआ। यह अमेरिका के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी। क्यूबा को लगातार सोवियत आर्थिक और सैनिक मदद भी

मिलती रही, लेकिन आंतरिक क्रांति की सुदृढता को देखते हुए अमेरिका किसी कारगर हस्तक्षेप की स्थिति में नहीं था। क्रांति के स्थिर होने की प्रक्रिया में अमेरिका एक असहाय दशक था। लेकिन 31 सितम्बर, 1962 को सोवियत संघ की इस घोषणा ने कि प्रक्षेपास्त्रों सहित आधुनिक हथियार यूगवा को दिये जायेंगे, अमेरिका की तीव्रतम प्रतिक्रिया पाई। 22 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति क्वेनडी ने यह स्पष्ट चेतावनी दी कि पश्चिमी गोलार्द्ध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जायेगा। अगले ही दिन यूगवा की नाकबंदी कर दी गई जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि यदि प्रक्षेपास्त्रों से सदा रूसी जहाज इस नाकेबंदी को तोड़ेगा तो उस एक प्रकार से युद्ध की घोषणा मान लिया जायेगा। सफ्ट के अंतिम क्षणोत्क रूस और अमेरिका के बीच हाट लाइन के जरिये नार्ता होती रही। अमेरिका के इस आश्वासन पर कि वह यूगवा के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा 2 अक्टूबर 1962 को ही रूस ने अपने प्रक्षेपास्त्री बेड़े की वापसी की घोषणा की। एक अभूतपूर्व सफ्ट, रोमांचकारी स्थितियों से गुजरते हुए टल गया। कुछ राजनीतिक प्रेसकों की यह मायता है कि इस पूरी घटना ने तृतीय विश्वयुद्ध की आसनाएँ खड़ी कर दी थी, और रूस का यह अत्यधिक अनुत्तरदायी काम था। लेकिन वस्तुस्थिति का और सोवियत मानस का यदि सही विश्लेषण किया जाये तो एक दूसरी दृष्टि उभरती है। यूगवा की क्रांति के बाद लगातार अमेरिकी हस्तक्षेप उसकी आंतरिक राज नीति में दखल द रहा था। सी आई ए जैसी संस्थायें किसी भी रूप में फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व वाली क्रांति को विफल करने की प्रक्रिया में सक्रिय थी। इस दृष्टि से देखा जाय तो सोवियत संघ का वास्तविक उद्देश्य यूगवा में प्रक्षेपास्त्रों का केन्द्र बनाना नहीं था क्योंकि यह मूलतः असम्भव था। उसका वास्तविक उद्देश्य यूगवा की क्रांति को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करवाना था जिसमें सोवियत संघ इस पूरे सफ्ट के द्वारा सफल भी रहा। अपने प्रक्षेपास्त्रों की वापसी रूस द्वारा अमेरिका के इस आश्वासन पर की गई कि यूगवा में आंतरिक घटयंत्र और हस्तक्षेप की सभी चेष्टाएँ बंद कर दी जायेगी। वस्तुतः अपने प्रक्षेपास्त्रों को हटाने को बाध्य होने की बाहरी विफलता के बदले सोवियत ने वास्तविक सफलता अर्जित कर ली थी। भविष्य में यूगवा की अफ्रीका और लातिनी अमेरिका में सक्रिय भूमिका ने इस दूरगामी सफलता को और अधिक स्पष्ट कर दिया।

सत्रमण का समापन

यूगवा के सफ्ट के बाद जिस शीत युद्ध के इतिहास का चर्चा उप जिन्हु बहा जाता है सोवियत संघ और अमेरिका में सीधे टकराहट में गिरावट की ओर बढ़ने का सत्रमण काल समाप्त हुआ। आगे आने वाले चरण में भी दोनों

के बीच टकराहट की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, लेकिन व प्रारंभिक टकराहट की स्थितियों से गुणात्मक रूप से भिन्न थी। सन 1975 से लेकर क्यूबा संकट तक के घटनाचक्र ने कुछ मूल प्रवृत्तियाँ स्पष्ट की। प्रथम, दोनों राष्ट्रों में एक नये परिप्रेक्ष्य का सूत्रपात हुआ। इसके राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक आधार थे और यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बदले हुए शक्ति के समीकरण की माँगता पर आधारित था। द्वितीय सत्रमण के इस काल में पिछले चरण की कुछ अनुभूतियाँ भी उजागर हुईं। उभरते हुए नये दृष्टिकोण के बावजूद दोनों राष्ट्रों में परस्पर संशय की स्थिति भी बनी रही। अनेकों बार शिथिलता के वातावरण में आकस्मिक दरारें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आईं जिनके फलस्वरूप उस नवीन प्रक्रिया का विकास उतनी सुगमता से सम्भव नहीं हो सका। इस पूरे चरण में एक सन्तुलित दृष्टिकोण दोनों राष्ट्रों में उभरा जिनकी अधिक स्पष्ट और मुखरित अभिव्यक्ति को अगले चरण तक इंतजार करना पड़ा।

तृतीय चरण

तनाव शिथिल्य (देतात) दशक (1963-1973)

क्यूबा के संकट का एक दोहरा और विचित्र प्रभाव पड़ा। एक ओर जहाँ इसने शीत युद्ध की पराकाष्ठा की अनुभूति क्यबाही, दूसरी ओर इसने शिथिलता की आवश्यकता को भी उग्र रूप से रेखांकित किया। इस घटना के बाद यूरोपीय राष्ट्र विशेषतः युद्ध की कल्पना से भयभीत रहे। दूसरा विश्वयुद्ध उनकी घरेलू पर लड़ा गया था अतः उसका उह अत्यधिक कटु अनुभव था। किसी भी प्रकार से वे विश्वस्तरीय तनाव में जूझन को तैयार नहीं थे। यूरोपीय राष्ट्रों की इस उग्र अनुभूति का अमेरिकी विदेशनीति पर सीधा दबाव पड़ा और वह शिथिलता की नीति को और अधिक तत्परता से लागू करने का वाध्य हुई। यूरोपीय परिवेश को देखते हुए यह कदापि आश्चर्यजनक नहीं था कि (देतात) तनाव शिथिल्य के वास्तविक प्रचलन की पहले यूरोप में ही हुई। पश्चिमी जर्मनी के चांसलर बिली ब्राट ने यूरोपीय राष्ट्रों में शिथिलता की प्रक्रिया को लागू करने का विचार रखा। उसकी व्यवस्था का मूल तात्पर्य यह था कि महाशक्तियों में तनाव शिथिल्य की प्रक्रिया की अपनी कठिनाइयाँ और पेचीदगियाँ हो सकती हैं। लेकिन कम से कम यूरोपीय परिवेश में तो एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण की स्थापना होनी चाहिए जिसके द्वारा परस्पर प्रतिद्वंद्वी विचार धारा वाले समस्त यूरोपीय राष्ट्रों में समन्वय स्थापित हो सके। यूरोपीय राष्ट्रों की इस अभिव्यक्त धारणा ने महाशक्तियों में देतात की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने का काम किया क्योंकि महाशक्तियों के अनेक विवाद विशेषतः जर्मन विवाद यूरोपीय परिवेश में जुड़े थे। अतः विश्वव्यापी स्तर पर तनाव शिथिल्य की मानसिकता स्थापित करने में

इस यूरोपीय पहल का असदिग्ध योगदान रहा।

महाशक्तियों में सम्बन्धों के सामायीकरण की प्रक्रिया का अर्थ प्रबलतम कारण तत्त्व चीन का स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में उभरना था। सोवियत और चीन के सम्बन्धों में अनेक वर्षों में दरार पड़ रही थी जो कि इन राष्ट्रों में सैनिक मुठभेड़ के बाद और अधिक प्रबल हो गई। सोवियत चीन विवाद के महत्वपूर्ण वैचारिक आर्थिक और सामरिक पक्ष थे। अतः इस विवाद के परस्पर निबटारे की सम्भावनाओं एक लम्बे अरस तक असम्भव बन चुकी थी। इस प्रक्रिया के अभिप्राय जितने अधिक स्पष्ट हुए उसी के अनुपात में तनाव शायित्य की प्रक्रिया भी प्रबल हुई। सोवियत की नीति में भारत का महत्व तो बड़ा एशियाई राष्ट्र के रूप में और मध्य ही साथ अमेरिका के साथ भी एक विश्व व्यापी समझौता करने की आवश्यकता हुई। उस समय का मतभेद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के किसी आगामी विवेकीकरण को रोकना था। रूस की समझ में विश्वव्यापी समाजवादी आंदोलन की पुरी और वैचारिक केन्द्र मौजूक था। जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है तात्कालिक रूप से अमेरिका और चीन के बीच सम्बन्धों का समीकरण जुड़ पाना सम्भव ही था। एक ओर इस मांग में अमेरिका की पारस्परिक कठिनाइयाँ थी जसे ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रश्न आदि, दूसरी ओर चीन की ओर से भी कोई विशेष सकेत आना सम्भव नहीं था क्योंकि सोवियत और चीन में विवाद के सन्दर्भ में चीन द्वारा सोवियत पर लगाये गये प्रमुख वैचारिक आरोपों में सोवियत अमेरिका 'तनाव शायित्य प्रमुख था। अमेरिका के साथ सम वय स्थापित करने की नीति चीन की दृष्टि से संशोधनवादी थी जिसके मूल में सोवियत की विस्तारवादी कामना बताई गई। अतः जहाँ तक सोवियत चीन विवाद का प्रश्न था अमेरिका और चीन के बीच भी सम्बन्धों को मिला सका, लेकिन कालान्तर में अमेरिका और चीन के बीच भी सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के इस दशक में निश्चयीकरण के प्रश्न ने दोनों महाशक्तियों के बीच अधिकाधिक वार्ताओं का अवसर दिया। विद्यमान युद्ध के अनुभवों के बाद अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक था। हस्तक्षेप की नीति के विरोध में प्रबल आंतरिक जनमत था, जो कि शस्त्रों की अघाघुष होड़ की भी कटु आलोचना करता था। जहाँ तक सोवियत संघ का प्रश्न है शस्त्रों की अघाघुष होड़ उसका आर्थिक संसाधनों के कम करके उन संसाधनों को जनवल्याण की कामना थी कि शस्त्रों की होड़ को कम करके उन संसाधनों को जनवल्याण बारी आंतरिक विकास में लगाया जाये। साथ ही साथ शीत प्रदंश में तल की खोज इत्यादि से संबंधित तकनीक को भी सोवियत की आवश्यकता थी जो पश्चिमी राष्ट्रों से सुगमता से मिल सकती थी। अतः इन आर्थिक एवं विकास

संघी आवश्यकताओं ने महाशक्तियों को निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया की ओर अधिक प्रेरित किया। इस प्रक्रिया का स्वाभाविक अभिप्राय दोनों राष्ट्रों में शिथिलता की प्रक्रिया को और अधिक सम्पुष्ट बनाना भी हो गया।

सामायीकरण का विकास क्रम

सोवियत संघ और अमेरिका में नेतृत्व में बदलाव के बावजूद दोनों राष्ट्रों में संघों के सामायीकरण की प्रक्रिया यथावत चली रही। स्टालिन के पतन के बाद लिओनिड ब्रेज्नेव का नेतृत्व के रूप में उभरना अधिक गूढ़ राजनीतिक अभिप्राय वाला नहीं था। ठीक उसी तरह जॉनसन का नेतृत्व भी विदेश नीति के स्तर पर कोई बदलाव का परिचायक नहीं था। इन समसामयिक परिस्थितियों में अनेक विवाद अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरे। वियतनाम का गृहयुद्ध और 1967 में इजरायल और अरब में युद्ध अत्यधिक उग्र स्थितियाँ थीं। भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध भी विश्वस्तरीय महत्व का था। चीन से सम्बंध विच्छेद के बाद भारत रूस मैत्री में बढ़ोत्तरी हुई। विशेषतः 1963 में चीन और भारत में टकराव के बाद इन संबंधों की भृशता और अधिक प्रगाढ़ हुई। अमेरिका द्वारा भारत-पाक युद्ध के सम्बंध में पाकिस्तान का सहयोग भारत को सोवियत संघ के ओर अधिक निकट लाया। इस पूरे घटनाचक्र में सोवियत विदेश नीति ने एक नई शक्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धोपरांत ताश्कंद का शांति समझौता सोवियत पहल और कूटनीतिक सूझबूझ का परिचायक था। इन कूटनीतिक प्रयासों में सोवियत भूमिका पश्चिम के लिए एक विशेष किस्म की चुनौती बन गई। अमेरिकी प्रयास पाकिस्तान को अपने ओर अधिक निकट लाने के लिए तीव्र हुए और अन्त में अमेरिकी विदेश नीति को इस संबंध में वांछित सफलता भी मिली। वियतनाम का गृहयुद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया समय तब ध्यान आकर्षित किया। जहाँ के गृहयुद्ध की स्थिति में उत्तरी वियतनाम की खुले रूप में सोवियत समर्थन प्राप्त था। तो दक्षिणी वियतनाम की ओर से अमेरिकी सैनिक रूप से मलग्न थे। स्वाभाविक था कि इस शिथिलता की प्रक्रिया में टकराव आती। राष्ट्रपति जॉनसन ने अपने चुनावी आश्वासन में वियतनाम युद्ध की समाप्ति और वहाँ अमेरिकी सैनिक भागीदारी को समाप्त करने की बात कही थी। लेकिन प्रारम्भिक रूप से वा 52 बमबर्क विमानों की वापसवाही गलत किय जाने के बाद भी गृह की तनाव प्रकृति बनी रही।

वियतनाम की घटनाओं के मध्य ही अरब इजरायल गणराज्य पक्ष और दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। परम्परागत रूप से अमेरिका इजरायली हितों का पक्षधर रहा है। अरब राष्ट्रों की आरंभिक स्थिति का नाश सम्बा

इस यूरोपीय पक्ष का असाध्य योगदान रहा।

अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध

महासन्धिया में सम्बन्धों का असाध्य विकास की प्रक्रिया का अन्त प्रवर्तन में
कारण तब चीन का स्वतंत्र अस्तित्व का रूप में उभरना था। सोवियत और
चीन के सम्बन्धों में अन्तर्गत घर्षणों का कारण पड़ रही थी जो कि इन राष्ट्रों में सन्धि
मुठभेड़ का बाद और अधिक प्रबल हो गई। सोवियत चीन विवाद के महत्वपूर्ण
वैचारिक आधिकार और सामरिक पक्ष थे। अतः इस विवाद का परस्पर निबटारा
की सम्भावनाओं का सम्बन्ध अलग तब असम्भव बन चुकी थी। इस प्रक्रिया के अन्तिम
प्रायः जिन्होंने अधिक स्पष्ट रूप उगीं व अनुपात में तनाव दायित्व की प्रक्रिया भी
प्रबल हुई। सोवियत की नीति में भारत का महत्व तो बढ़ा एशियाई राष्ट्र के
रूप में और न यही साथ अमेरिका के साथ भी एक विश्व व्यापी समझौता
करने की आवश्यकता हुई। उस समय का मतभेद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दायित्व
के किसी आगामी विश्वीकरण की रोकना था। रूस की समझ में विश्वव्यापी
समाजवादी आन्दोलन की घुरी और वैचारिक नेटवर्क मौजूद था। जहाँ तक अमे
रिका का प्रश्न है तात्कालिक रूप में अमेरिका और चीन के बीच सम्बन्धों का
समीकरण कुछ घाना सम्भव ही था। एक ओर इस मांग से अमेरिका की
पारस्परिक कठिनाइयाँ थी जैसा ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रश्न आता,
दूसरी ओर चीन की ओर से भी कोई विशेष सन्तुष्टि आना सम्भव नहीं था क्योंकि
सोवियत और चीन में विवाद के सन्दर्भ में चीन द्वारा सोवियत पर लगाय गये
प्रमुख वैचारिक आरोपों में सोवियत अमेरिका तनाव दायित्व प्रमुख था। अम
रिका के साथ समर्थ स्थापित करने की नीति चीन की दृष्टि से, सशोषणवादी
थी जिसके मूल में सोवियत की विस्तारवादी कामना बताई गई। अतः जहाँ तक
सोवियत चीन विवाद का प्रश्न था अमेरिका की इसका तात्कालिक लाभ नहीं
मिल सका लेकिन कालान्तर में अमेरिका और चीन के बीच भी सम्बन्धों की
घुरी बनी जो कि सोवियत चीन विवाद की स्वाभाविक परिणति थी।
सामाजीकरण के इस दशक में निराशाजनक प्रश्न ने दोनों महाशक्तियों
के बीच अधिकाधिक वार्ताओं का अवसर दिया। वियतनाम युद्ध के अनुभवों के
बाद अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक था। हस्तक्षेप की
नीति के विरोध में प्रबल आंतरिक जनमत था, जो कि शस्त्रों की अघाघुय हो
की भी कटु आलोचना करता था। जहाँ तक सोवियत सत्ता का प्रश्न है शस्त्रों की
अघाघुय हो उसने आधिकार ससाधनों के लिए भारी बोध थी। सोवियत सत्ता
की कामना थी कि शस्त्रों की होड़ को कम करके उन ससाधनों की जनकल्याण
कारी आंतरिक विकास में लगाया जाय। साथ ही साथ भी प्रदेशों में तेल की
खोज इत्यादि से संबंधित तकनीक को भी सोवियत को आवश्यकता थी जो
पश्चिमी राष्ट्रों से सुगमता से मिल सकती थी। अतः इन आर्थिक एवं विकास

संघ की आवश्यकताओं ने महाशक्तियों को निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया की ओर अधिक प्रेरित किया। इस प्रक्रिया का स्वाभाविक अभिप्राय दोनों राष्ट्रों में शिथिलता की प्रक्रिया को और अधिक सम्पूर्ण बनाना भी हो गया।

सामायिकरण का विकास क्रम

सोवियत संघ और अमेरिका में नेतृत्व में बदलाव का बावजूद दोनों राष्ट्रों में संघर्ष के सामायिकरण की प्रक्रिया गंभीरता से जारी रही। स्ट्रुश्चेव के पतन के बाद लिओनिड ब्रेज्नेव के नेतृत्व के रूप में उभरना अधिक मूल राजनीतिक अभिप्राय वाला नहीं था। ठीक उसी तरह जॉनसन का नेतृत्व भी विदेश नीति के स्तर पर कोई बदलाव का परिचायक नहीं था। इन समसामयिक परिस्थितियों में अनेक विवाद अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरे। वियतनाम का गृहयुद्ध और 1967 में इजरायल और अरब में युद्ध अत्यधिक उग्र स्थितियाँ थीं। भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध भी विश्वस्तरीय महत्व का था। चीन से सम्बंध विच्छेद के बाद भारत रूस मैत्री में बढ़ोत्तरी हुई। विशेषतः 1963 में चीन और भारत में टकराव के बाद इन संघर्षों की शृंखला और अधिक प्रगाढ़ हुई। अमेरिका द्वारा भारत-पाक युद्ध के सम्बंध में पाकिस्तान का सहयोग भारत को सोवियत संघ के ओर अधिक निकट लाया। इस पूरे घटनाचक्र में सोवियत विदेश नीति ने एक नई साझा स्थापित करने का प्रयत्न किया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धोपरांत शांति का शांति समझौता सोवियत पहल और कूटनीतिक सूझबूझ का परिचायक था। इन कूटनीतिक प्रयासों में सोवियत भूमिका पश्चिम के लिए एक विशेष किस्म की झुलसावट बन गई। अमेरिकी प्रयास पाकिस्तान को अपने ओर अधिक निकट लाने के लिए तीव्र हुए और अंत में, अमेरिकी विदेश नीति को इस संघर्ष में वांछित सफलता भी मिली। वियतनाम के गृहयुद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लम्बे समय तक ध्यान आकर्षित किया। वहाँ के गृहयुद्ध की स्थिति में उत्तरी वियतनाम को खुले रूप से सोवियत समर्थन प्राप्त था। तो दक्षिणी वियतनाम की ओर से अमेरिका सैनिक रूप से सलग्न था। स्वाभाविक था कि इससे शिथिलता की प्रक्रिया में रुकावट आती। राष्ट्रपति जॉनसन ने अपने चुनाबी वाद्वसन में वियतनाम युद्ध की समाप्ति और वहाँ अमेरिकी सैनिक भागीदारी को समाप्त करने की बात कही थी। लेकिन प्रारम्भिक रूप से ही 52 बमबर्क विमानों की कामवाही खत्म किए जाने के बाद भी संघर्ष की तनाव प्रकृति जारी रही।

वियतनाम की घटनाओं के मध्य ही अरब इजरायल संघर्ष फूट पड़ा और दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। परम्परागत रूप से अमेरिका इजरायली हिता का पक्षधर रहा है। अरब राष्ट्रों की ओर सोवियत रुचान की भी एक सम्बन्धी

प्रक्रिया थी। अतः पश्चिमी एशिया के इस संकट ने एक बार फिर दाना महाशक्तियों के बीच वाक् युद्ध छेड़ दिया। महाशक्तियों का विवाद संयुक्त राष्ट्र सभ के मंच पर भी प्रकट हुआ। 18 जून, 1967 का राष्ट्र सभ की महासभा की बैठक में सोवियत सभ द्वारा अरब राष्ट्रों की मांगताओं को समर्थन देने वाला प्रस्ताव रखा गया और अमेरिका पर तनाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। सोवियत प्रतिनिधि मंडल ने अपने पक्ष का न माने जाने पर महामभा से बहिष्मन किया। वास्तविक रूप से युद्ध की समाप्ति इजरायल की विजय के साथ हुई। युद्ध की पूरी प्रक्रिया में सोवियत सभ ने अरब राष्ट्रों का समर्थन तो किया लेकिन इसमें सैनिक समर्थन नहीं था। पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों ने सोवियत सभ के इस सीमित समर्थन को अपर्याप्त समझा। अरब इजरायल युद्ध से जा तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं व दोनों महाशक्तियों के उभरते हुए विश्व स्तरीय दृष्टि कोण के विपरीत थी।

लेकिन एक गुणात्मक अंतर था कि वियतनाम युद्ध और पश्चिमी एशिया संकट, वाक् युद्ध के अलावा दोनों महाशक्तियों में कोई स्पष्ट टकराव नहीं पदा नहीं कर सका। दोनों महाशक्तियों का दृष्टिकोण इन समस्याओं के शांतिपूर्ण निवारण का था न कि टकराव का। लेकिन साथ ही साथ दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ना चाहती थीं। इस मिश्रित मानसिकता के बीच 23 जून, से 26 जून, 1967 तक ग्लासबरो का शिखर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्यतः वियतनाम और पश्चिमी एशिया संकट पर विचार विमर्श हुआ। एक रूप से यह शिखर सम्मेलन चीन द्वारा आणविक शक्ति के रूप में उभरने की समीक्षा से भी प्रेरित था। तात्कालिक रूप से ग्लासबरो सम्मेलन की कोई स्पष्ट सफलता नहीं देखी जा सकती। दोनों महाशक्तियाँ कोई कारगर सौदबाजी नहीं कर सकीं। लेकिन सम्मेलन का आयोजन असफलता के बावजूद भी एक सौमित्र्य के दृष्टि कोण का परिचायक था जिसमें मतभेदों के होते हुए भी बैठकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता स्पष्ट हुई। सम्मेलन का एक मात्र सफल तत्व यह था कि इसने बाद दोनों महाशक्तियों ने अधिक समयित भाषा का प्रयोग किया और मध्य सम्भव अनावश्यक रूप से तनाव की स्थितियाँ नहीं उभरने दी।

तात्कालिक विवाद के अंत में 1968 का चेकोस्लोवाकिया संकट और 1969 का जर्मन संकट भी प्रमुख रहे। सन 1967 के प्रारम्भ से ही चेकोस्लोवाकिया में कुछ उदारवादी प्रवृत्तियाँ उभरने लगीं। 1968 में सोवियत समर्थक नेतृत्व को सत्ता में हटाना पड़ा और नया उदारवादी नेतृत्व आया जिसने अनेक सुधारवादी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जो कि प्रगतिशील समाजवादी अवधारणाओं के विषय में। इस पूरी प्रक्रिया की हम एक अंत्यपूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों में भी देख सकते हैं। जुलाई में वारसा सम्मेलन के बाद वारसा संधि के तदनुसार द्वारा

एक संपुक्क पत्र लिखा गया, जिसमें नये चेकोस्लाविकिया नेतृत्व की प्रति कान्तिकारी एव समाजवादी व्यवस्था के विरोधी कायत्रमा की तीव्र भत्सना की गई। पत्र में यह चतावनी भी समाहित थी कि यदि ऐसी नीतियों को नहीं बदला गया तो मीधी और कठोर कायवाही भी गी जायेगी। चेकोस्लोवाकिया द्वारा सुयावो की निरंतर अवहलना के बाद 21 अगस्त, 1968 को सोवियत सघ और अन्य वारमा संधि राष्ट्रों के सैनिक दल चेकोस्लावाकिया जा पहुच और वहा क उदारवादी नेतत्व को अपदस्थ कर दिया। काफी विचार विमर्श के बाद चेकोस्लाव सरकार क प्रतिगामी नीतिया पर न चलने के वचन के बाद सितम्बर 1968 के मध्य तक सेनायें वापस बुला ली गई। एक साल के भीतर उदारवादी नेतत्व की चेकोस्लाव कम्युनिस्ट पार्टी में भी पराजय हो गई और वहा पुन सोवियत समर्थक नेतत्व की सरकार बन गई। इसी समय मार्च 1969 में बर्लिन को लेकर एक ओर सकट उत्पन्न हुआ। विभाजित बर्लिन क पश्चिमी भाग में पश्चिमी जर्मन सरकार द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव करवाय जाने के निणय को पूर्वी जर्मन सरकार न यह कह कर चुनौती दी कि बर्लिन अभी तक 1945 के पोट्सडम समझौते के आधीन है। अत वहा पर चुनाव करवाय जान का प्रयास उस पश्चिमी जर्मनी के भाग के रूप में आरापित करना है। अपन विरोध में, पूर्वी जर्मनी ने पश्चिमी बर्लिन जाने वाले मार्गों पर प्रतिवध लगा दिया। इसमें निपटने के लिए वायुमार्ग द्वारा पश्चिमी जर्मन निर्वाचन मण्डल बर्लिन पहुंचाया गया। विषय की तात्कालिकता से बढ कर इस विवाद का कोई और उग एव उत्तेजित स्वरूप नहीं उभरा।

चेकोस्लोवाकिया और बर्लिन सकट को यदि तुलनात्मक रूप में देखा जाये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तिया उभरती है। दोनों ही घटनायें अपन आप में अत्यधिक रोमाचकारी थी, जिहाने ऊपरी तौर पर तनाव की स्थितिया उत्पन्न की। लेकिन जिस प्रकार में इन दोनों अवसरों पर महाशक्तियों की प्रतिक्रियाएं हुई, वह भार भिन्न चरण की प्रतिक्रियाओं से भूलत भिन्न थी। जब चेकोस्लोव प्रभाव के क्षेत्र मानने की अवधारणा को पश्चिम की भी अनौपचारिक मान्यता मिली जान पड़ती है। अत कोई बृहद स्तर की प्रतिक्रिया अथवा वाक पुद्ग चकोस्लोव सकट के प्रचार में नहीं हुआ। जहा तक बर्लिन विवाद का प्रश्न था, सोवियत सघ की यह मान्यता बच चुकी थी कि यथार्थित को दूरगामी स्थायित्व प्रदान करना ही व्यावहारिक समाधान है। यथार्थित यह थी कि, विभाजित बर्लिन का एक भाग पश्चिमी जर्मन क्षेत्र में था तो दूसरा भाग पूर्वी जर्मनी के क्षेत्र में। इस दृष्टि में देखा जाये तो सोवियत सघ की किसी तीव्र और बृहद प्रतिक्रिया के अभाव में, पूर्वी जर्मनी के कदम का अभिप्राय भूलत औपचारिक विरोध मात्र था। अत इन दोनों समस्याओं क तात्कालिक स्वरूप के बावजूद भी इनमें कोई पूर्वी पश्चिमी विवाद नहीं उभर सका। भूलत यह 'दत्तात' के विकास का एक नया पड़ाव था।

सामायीकरण का स्यायित्व

सातवें दशक व आगमन व साथ साथ महासक्तिता म सम्बन्ध के सामायीकरण की प्रक्रिया न एक तीव्र गति पवडी। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में निवसन ने अपनी विजय के साथ ही विश्व स्तरीय सामायीकरण की प्रक्रिया को तानू करने की घोषणा की और इस हेतु सभी राष्ट्रों को आह्वान किया। पद सम्मान के तुरत बाद निवसन द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों का भ्रमण किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति की यह यात्रा अपन आप म अत्यधिक दूरगामी महत्व की थी और किन्हीं मायनों म पद सम्भालने के बाद क्यूबचेव द्वारा यूरोपीय भ्रमण की याद दिनाती थी। अमेरिकी विदेश नीति का यह नट्टिकोण था कि यूरोप से सन्धित सभी परपरागत विवाद सदैव व लिए सलम हो जाए अथवा स्यायी विश्वशांति की नीव ही रखी जा सक्ती।

अतः शीघ्र ही जमन विवाद के सुलझाने की एक तात्कालिक प्रक्रिया देखने की ली जिसम सोवियत सघ की समन का भी बराबर योगदान था। इस प्रक्रिया प्रथम कडी व रूप म 12 अगस्त 1970 को रूस और पश्चिमी जमनी व बीच सधि हुई। दोनों राष्ट्रों द्वारा जिस सघि पत्र पर हस्ताक्षर किये गय उसका आधार दानो पक्षों द्वारा वस्तुस्थिति की स्वीकारना और उसे मायता देना स समझौते ने एक बहुपक्षीय सधि व भाग को भी प्रशस्त किया। सितम्बर

... म अमेरिका सोवियत सघ ब्रिटेन और फ्रांस व बीच जर्मन विवाद पर समझौता हुआ। समझौते की रूपरेखा रूस और पश्चिमी जमनी के बीच हुई सधि की धारणाओं पर आधारित थी। चार महासक्तिताओं द्वारा यह निणय किया गया कि पूर्वी और पश्चिमी जमनी के बीच आवागमन की सुविधायें बिना विशेष उत्पन्न की जाये विभाजित बर्लिन के बीच आवागमन की सुविधायें बिना विशेष प्रतिबन्ध व उपसंध्य करवाई जाये, और इस हेतु सोवियत सघ विशेष सुविधायें भी प्रदान करे। जमन विवाद के सुलझाने की अन्तिम महत्वपूर्ण कडी पूर्वी और पश्चिमी जमनी के बीच समझौता था। 8 नवम्बर, 1972 को पश्चिमी जमनी की राजधानी म दोनों राष्ट्रों द्वारा एक सधि पर हस्ताक्षर किये गये। इस सधि के द्वारा दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे के परस्पर अस्तित्व की स्वीकार किया और आपसी सहयोग की सम्भावनाएँ व्यक्त की। किसी भी विवाद की स्थिति म दोनों राष्ट्रों न भविष्य में बल प्रयोग को अनुचित ठहराया। दोनों राष्ट्रों के बीच इस ऐतिहासिक सधि के समापन के साथ साथ एक ऐतिहासिक विवाद का बहुप्रतीक्षित अन्त हुआ।

यूरोपीय सौहार्द की चरम अभिव्यक्ति 1973 का हेलसिंकी सम्मेलन कहा जा सकता है। इस सम्मेलन में 36 यूरोपीय राष्ट्रों व विदेश मंत्री 3 स 5 जुलाई,

1973 के बीच एकत्रित हुये। अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी और यूरोपीय राष्ट्रों के परस्पर सुरक्षा और सौहार्द की स्थापना इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। इस सम्मेलन का महत्व इस बात से भी है कि यूरोपीय परिवेश में अपनी तरह का प्रथम प्रयास होने के साथ साथ, इसकी विषयवस्तु भी उतनी ही विस्तृत थी जितनी इसकी मददगारता। सम्मेलन में पथक रूप से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रश्नों पर प्रस्ताव पारित किये गये। इन प्रस्तावों का सम्मिलित तात्पर्य राजनयिक सम्बंधों के साथ साथ पश्चिमी राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान था। सम्मेलन की सफलता में रूस ने सक्रिय सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप उसे विश्वव्यापी प्रशंसा भी मिली।

अब महत्वपूर्ण विवादों में कोरिया और वियतनाम के विवाद थे। सम्बंध के इस उभरते हुये अंतर्राष्ट्रीय माहौल में इन विवादों को भी सुलझाने का मौका मिला। तात्कालिक रूप से यद्यपि इन विवादों में एक तदर्थ समाधान ही उभरा और अंतिम परिणामों को कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ा। 1972 में उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच सम्बंधों को सामान्य बनाये जाने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये। 4 जुलाई 1972 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ और वल प्रयोग में कमी की बात कही गई तथा युद्ध के दौरान अस्त व्यस्त हुए नागरिकों की बदला बदली का प्रश्न भी सुलझाया गया। जुलाई, 1973 में दोनों राष्ट्रों के बीच एक सम्बंध समिति की भी स्थापना हुई। वियतनाम की आंतरिक युद्ध की स्थिति में प्रत्यक्ष अमेरिकी हस्तक्षेप में कमी हुई। एक सम्बंध अनुभव के बाद अमेरिका को यह स्पष्ट हो गया था कि उसे वियतनाम से हटना होगा। इस समझ के अनुकूल अमेरिका ने जनवरी 1973 में एक समझौता किया, जिनके द्वारा वियतनाम युद्ध की समाप्ति की सिद्धांततः घोषणा हुई और इस हेतु व्यावहारिक योजना बनाये जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। जहाँ तक पश्चिमी एशिया का प्रश्न था अमेरिका की परम्परागत नीति में भी कुछ बदलाव आया। इजरायल को समर्थन और सैनिक मदद जारी रखते हुए किसिजर द्वारा पश्चिमी एशिया में अरब राष्ट्रों और इजरायल को साथ साथ लाने के प्रयास भी किये गये।

त्रिकोणात्मक सन्नियता

अमेरिकी विदेश नीति में निक्सन और किसिजर की सामूहिक समझ का महत्वपूर्ण मनव्य महासक्तिों के स्तर पर एक त्रिकोणात्मक गतिशीलता को प्रस्तुत करना था। वस्तु स्थिति के स्तर पर सोवियत चीन विवाद की प्रक्रिया के साथ साथ अमेरिका और चीन में सम्बंध बढ़ने ने ठोस आधार था। लेकिन इस आधारों की श्रियाचित निक्सन प्रशासन के दौरान प्रारम्भ हुई। प्रथम प्रयास

सांस्कृतिक एवं खेल गूट स्तर का रहा। 1971 के वर्ष में अमेरिकी टबलटेनिस टीम के चीन भ्रमण का विगपण राजनय की मज्ञा भी दी गई। अक्टूबर, 1971 में साम्यवादी चीन के मयुक्कन राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करना एवं ऐतिहासिक मोह था। निम्नन ने सोवियत के साथ सन्ध्या में बड़ोत्तरी के समानांतर चीन के साथ भी यही प्रक्रिया प्रारंभ की। विभिन्न के गुप्त राजनयिक प्रयासों के बावजूद राष्ट्रपति निक्मन की बीजिंग यात्रा की घोषणा हुई। मार्च 1972 में प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में निक्मन ने चीन की यात्रा की। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य किसी तात्कालिक समझौते की संभावना नहीं थी, यह यात्रा मूलतः दो बातों से प्रेरित थी। प्रथम उद्देश्य तात्कालिक था जिसका मुख्य अभिप्राय आगामी दूसरा अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रति चीन के दृष्टिकोण को निकट से जानना था जिसके द्वारा भविष्य में किसी सामूहिक दृष्टिकोण के विकास की संभावनाएँ खोजी जा सकें। इन दोनों उद्देश्यों में अमेरिकी विदेश नीति की आशा तीव्र सफलता मिली।

22 मई से 30 मई 1972 तक राष्ट्रपति निक्मन की सोवियत यात्रा हुई। इस लम्बी यात्रा के दौरान अनेक पारस्परिक हिता के समझौतों पर विचार विमर्श हुआ जिनका प्राक्क चीन अमेरिका वातावरण से कहीं अधिक ठोस था। व्यापारिक 'अ' सहयोग के समझौते हुए निक्मन के इस दस भ्रमण का सबसे महत्वपूर्ण समझौता हथियारों के परिसीमन से संबंधित था। 26 मई 1972 को सामरिक दान परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर हुए। निक्मन की इस सोवियत यात्रा के तत्काल बाद 18 जून 1973 को ब्रयनव की अमेरिका यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा के दौरान सोवियत और अमेरिकी म तकनीकी सहयोग से संबंधित विचार विमर्श हुए और अनेक व्यापारिक प्रश्नों पर भी आदान प्रदान हेतु सहमति हुई। इसी दौरान सबसे महत्वपूर्ण नियम सोवियत और अमेरिका के बीच सयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के बारे में हुआ। यह प्रस्तावित किया गया कि 1975 से इस कार्यक्रम का सामू किया जाये। सोवियत और अमेरिका के संबंधों में सामायीकरण के ठोस आधार इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उभर कर सामने आया, जिसके फलस्वरूप दोनों राष्ट्रों में सम्बंधों के सामायीकरण की दूरगामी आधारभूमि तैयार हुई।

जहाँ तक अमेरिका और चीन के बीच उभरते हुए समीकरण का प्रश्न था सोवियत नीति इसका प्रति उदासीन कदापि नहीं थी। नए नये समीकरण के अभिप्रायों को आत्मसात करते हुए सोवियत ने अपने एशियाई और अफ्रीकी सम्बंधों पर अधिक बल देना प्रारंभ किया। दक्षिणी एशियाई उपमहाद्वीप में सोवियत सैनिक सहायता इसी उद्देश्य की परिचायक थी। एक सैनिक रूप में

सशक्त भारत, चीन के लिए स तुलन का काय कर सकता था। अपनी इस नीति की स्पष्टतम अभिव्यक्ति सोवियत ने सन 1971 में की, जबकि भारत सोवियत मंत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि का तात्कालिक प्रयोग और महत्व 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान देखने को मिला। अमेरिकी नौ सेना के 7वें वेडे की हिन्द महासागर में उपस्थिति के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में भारतीय सेनाओं की असदृश विजय हुई। इसके फलस्वरूप बांग्ला देश का अस्तित्व हुआ। 1971 का षट्पाचक्र भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अत्यधिक महत्व का था। परम्परागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के दृष्टिकार के बाद और भारत के सैनिक हस्तक्षेप के सफल प्रदान के बाद, भारत को अर्नोपचारिक रूप से उपमहाद्वीपीय शक्ति की मान्यता मिली। 1971 के युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप की नीति की सफलता पर एक और प्रदर्शनचिह्न लग गया। इस विवाद में चीन का मौन अंतर्राष्ट्रीय पक्ष वेस्तो के लिए विश्लेषण का विषय बन गया और साथ-ही साथ चीन की किसी महत्वपूर्ण एशियाई भूमिका की अवधारणा की अभ्यावहारिक दिक्कत लगी। चीनी क्यों म अफ्रिका में हो रहे राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी इन तीनों महाशक्तियों का त्रिकोणात्मक समीकरण परिलक्षित हुआ। चाहे मोर्जम्बिक की स्वतंत्रता का प्रश्न हो या अंगोला का, नामपची घाराआ का प्रमुख स्थान सोवियत समर्थक बना और जिम अंत में सफलता भी प्राप्त हुई। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका तो विफल पक्ष की ओर ही था, लेकिन गलत राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण चीन का भी अफ्रिकी मंच पर सोवियत नीति की सफलता को सहन करना पड़ा। इस प्रकार हम दायते हैं कि अमेरिका और चीन के बढ़ते हुए समीकरण के प्रत्युत्पत्तर में सोवियत की प्रमुख प्रवृत्ति एशियायी एक अफ्रिकी राष्ट्रों में अपने सहयोग की परम्परा को और अधिक प्रभावी और बृहद बनाता रहा। इस नीति ने सोवियत हिता का बहुत लाभ पहुंचाया।

सामायीकरण दशक का अनुभव और अभिप्राय

महाशक्तियों के बीच सम्बन्धों के सामायीकरण की प्रक्रिया, जैसाकि उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है इन दो राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रही। महाशक्तियों में सम्बन्धों से सामायीकरण की इच्छा ने वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तनाव कम करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि इस चरण में टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं हुई थी। एक इतना था कि जब भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुईं तो उनके समाधान के लिए परम्परागत वार्ता के द्वार खोले गये जैसाकि शीतयुद्धकालीन राजनीति में सम्भव नहीं था। सामायीकरण की इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने में सबसे अधिक महयोगी परम्परागत विचारों हेतु अपनाया गया व्यावहारिक दृष्टिकोण था। अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीति के उत्तरोत्तर विकास में आर्थिक एवं तकनीकी प्रश्नों पर परस्पर राष्ट्रा के बीच निमरता एक वास्तविकता थी। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे विवादों का निपटाना अत्यधिक आवश्यक था जोकि ऐतिहासिक कारणों से अनावश्यक बनते जा रहे थे। सामाजिकरण की मानसिकता ने मूलतः इस मतभेद का आत्मसा किया। अतः सामाजिकरण का पूर्ण प्रक्रिया कोई अनिश्चितकालीन सहयोग बनने पर्यायक नहीं है अपितु मात्र परम्परागत विवादों से उभरने का दृष्टिकोण है। इस परिप्रेक्ष्य में ही सामाजिकरण के वास्तविक तात्पर्य का मूल्यांकन हो सकता है। दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिद्विद्धता न रही हो, ऐसा उस प्रक्रिया का निष्कर्ष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आगामी वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि परस्पर प्रतिद्विद्धता न सिर्फ बनी रही अपितु इसकी परिधि और अधिक विस्तृत भी हुई। गुणात्मक अंतर अब इस बात का था कि यह प्रतिद्विद्धता किसी सम विषय अंतर्राष्ट्रीय बातावरण में हो, अनावश्यक प्रवृत्तियों से प्रेरित न हो और कुछ निर्धारित सीमाओं के भीतर ही हो जिनमें रहते हुए विश्वव्यापी सकट से उन से बचना पड़े। ऐसे ही एक समविषय मिश्रित दृष्टिकोण की अभिव्यक्तियां अगले वर्षों में देखने को मिलती हैं।

चतुर्थ चरण

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का काल (1973 से अब तक)

सावा रहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास अनेक बद है कि विश्वस्तरीय युद्ध सदैव एक नये शक्ति के संतुलन को जमाने देता है अतः परम्परागत शक्तियों का अवसान और शक्ति के नये केन्द्र का उद्भव होता है दोनों विश्वयुद्ध इस बात के साक्षी कहे जाते हैं। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की राजनीति में एक विचित्र गतिशीलता देखी गई। टकराहट की विचित्र स्थितियां तो उत्पन्न हुईं लेकिन कोई विश्व व्यापी सकट देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का संतुलन एक उत्तरोत्तर विकास के क्रम से बदलता रहा। इस घटनाचक्र में विभिन्न ऐतिहासिकता का समावेश था। सन 1945 में तत्कालीन ध्रुवीकरण के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक शक्ति सर्वोपरि थी। सोवियत संघ व ध्रुवीकरण के दूसरे केन्द्र के रूप में उपस्थित होने के बावजूद उसमें उतनी क्षमता का अभाव था। अमेरिका के आणविक आयुधों ने ही वास्तव में द्वितीय विश्वयुद्ध का पटाक्षेप किया था। युद्ध के बाद उसके हस्तक्षेप की क्षमता अनुलनीय थी। यूरोप और पश्चिमी गोलार्ध का प्रश्न ही अथवा हिंद-चीन से लेकर पश्चिमी एशिया में उत्पन्न स्थितियां, अमेरिका का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष स्थिति में था।

हस्तक्षेप की इस नीति और क्षमता का अभाव युद्ध के बाद दो दशकों में सोवियत नीति में व्याप्त था। लेकिन इन वर्षों में भी सोवियत क्षमता एक स्थिर गति से बढ़ रही थी। पूँजीवादी राष्ट्रों की क्षमता से प्रारम्भिक वर्षों में अत्यधिक क्षीण उसके बाद के वर्षों में समानता का संघर्ष, फिर समानता की प्राप्ति और अंत में वरीयता की होड़ यह एक क्रम रूस की विश्वव्यापी हस्तक्षेप की क्षमता को दर्शाता है।

इस ऐतिहासिक क्रम के विकास में जहाँ एक ओर रूस की उत्तरोत्तर विकास की स्थिति रही, वहीं अमेरिका एक अर्ध-पश्चिमी राष्ट्र की क्षमता में उत्तरोत्तर अवसान हुआ। 1973 तक यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयी। इससे पूर्व भी अफ्रीका राष्ट्रीय आन्दोलन के सदर्भ में इसका प्रारम्भिक आधार मिलते हैं। किंतु 1973 के बाद यह प्रवृत्ति और अधिक मुखरित हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक दिग्विप्लव का वातावरण नये शक्ति के सन्तुलन के रूप में स्वीकार हुआ। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों की आर्थिक एवं सामरिक शक्ति के अवसान के मूलभूत ऐतिहासिक कारण ये हैं। इन राष्ट्रों की शक्ति के साम्राज्यवाद की आधारभूत तत्त्वों पर टिकी थी। उपनिवेशवाद के अंत के बाद राजनीतिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र अधिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हुए। इसका स्पष्ट अभिप्राय था जिस अनुपात में ये राष्ट्र साम्राज्यवाद के आर्थिक शोषण में मुक्त हुए, ठीक उसी अनुपात में पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्रों की आर्थिक क्षमता को ठेस पहुँचेगी जो कि उनकी राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमता में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगी। अतः पश्चिमी राष्ट्रों के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना या कम से कम उस स्तर तक बनाये रखने की लड़ाई मूलतः इतिहास के विरुद्ध लड़ाई थी। यह नितांत असम्भव था। जहाँ तक सोवियत संघ का प्रश्न था, उसका लिए इस ऐतिहासिकता से जुड़कर चलना न सिर्फ वैचारिक दृष्टि से बलिहीन था, अपितु सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टि से भी लाभप्रद। सन् 1945 में जो क्षमता अमेरिका एवं पश्चिमी राष्ट्रों की थी उस क्षमता की आड़े अब सोवियत संघ का माग बन रहा था। बदले हुए ऐतिहासिक सन्दर्भों ने महाशक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में भी बदलाव प्रस्तुत किया। अमेरिका एक दूसरे वियतनाम अथवा दूसरे कोरिया के अनुभव करने के विचारमात्र से सन्नत था। जब कि दूसरी ओर, सोवियत संघ के अनुभवों में क्यूबा और अंगोला से लेकर अफगानिस्तान तक के दृष्टांत समाहित हो रहे थे। परंपरागत प्रभाव के दायरे से हटकर परीक्षा प्रभाव की परिधि में भी यही ऐतिहासिक क्रम देखने को मिलता है। विश्वयुद्ध के बाद का इतिहास नाटो की उभरती नपुंसकता और सेटो और सीटो के वस्तुतः विघटन का इतिहास है। द्विपक्षीय मंत्री संधियों के अनुभवों से दूसरी ओर सावित्र संघ के मंत्री एवं प्रभाव क्षेत्र में निरंतर बढ़ती हुई है। उपरोक्त विश्लेषण इस अंतिम चरण की प्रमुख प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से रेखांकित

कारण विघटन के कगार पर था। अतः अमेरिका से अनुरोध किया गया कि वह क्यूबा के साथ अपने वैमनस्य की नीति त्याग दे। पश्चिमी गोलार्द्ध में राष्ट्रों में परस्पर मतभेद और उनमें फूट अमेरिकी स्थिति के लिए वास्तव में एक विकट समस्या थी जिसका कि एक मात्र समाधान क्यूबा पर से प्रतिबंध हटा लेना ही था। अतः न चाहते हुए भी अमेरिका को एमेल निणय में सहयोग देना पड़ा।

महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और एशियाई सदस्य

20वीं शताब्दी के सातवें दशक में अंतराष्ट्रीय घटनाचक्र का एक विशेष एशियाई सदस्य रहा है। दशक के उदघाटन के साथ एशियाई महाद्वीप में घटनाओं का क्रम न अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति के संतुलन में 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद गुणात्मक अंतर आया जिसके फलस्वरूप भारत को एक उपमहाद्वीपीय शक्ति के रूप में भाव्यता मिली। इसी वर्ष, युद्ध से पूर्व हुई भारत और रूस मैत्री संधि, एक विशेष सामरिक महत्व की सिद्ध हुई। रूस और चीन के उभरते हुए विवाद और चीन और अमेरिका के बीच एक नये समीकरण के आयोजन के मदद में इसका और भी अधिक महत्व उभरा। इस घटना के बाद एशियाई संतुलन के सदस्य में दोनों महाशक्तियाँ और विशेषतः अमेरिका और अधिक तत्पर हुईं। अमेरिकी विदेश नीति के पश्चिम एशियाई प्रयासों में, उनके चीन के साथ संबंधों में मामा-यीकरण की तत्कालिकता में अथवा पाकिस्तान और ईरान पर और अधिक निर्भर होने में, इन सभी स्थितियों में इस बदले हुए एशियाई संतुलन की समझ थी। सामरिक नीति एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के निमाण में व्यस्त रही। यद्यपि इसका आधार बहुत सीमित अवधि वाला मित्र हुआ जबकि एक आंतरिक इस्लामिक क्रांति के फलस्वरूप शाह अपदस्थ हुए और एक अमेरिका विरोधी इस्लामी नेतृत्व की स्थापना हुई। पर यह घटनाचक्र इस चरण के उत्तरार्द्ध में ही घटा और तब तक ईरान अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक भूमिका निभाता रहा।

पश्चिमी एशियाई संकट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें अमेरिकी नीति को परस्पर विरोधी राष्ट्रों में समन्वय स्थापित करने वाली नीति के रूप में सफलता मिली। इस सफलता की एक सीमित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी थी। प्रारम्भिक तौर पर अरब राष्ट्रों में सोवियत की विदेश नीति को सफलता मिली थी और इस समय अपने अस्तित्व में आने के साथ ही पश्चिमी प्रभाव राष्ट्रों में। लेकिन मित्र और रूस के बीच सम्बंधों में दरार पड़ने के बाद वहाँ एक अमेरिकी भूमिका की सम्भावनाएँ उभरीं। जर्मिजर की राजनयिक चेष्टाओं से मित्र के साथ तारतम्य स्थापित हुआ। सम्बंधों की इस कड़ी में निरंतर विकास हुआ। जर्मिजर के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही, प्रारम्भिक अमरपना के बाद अतः 4, सितम्बर 1975

करता है उस प्रवृत्ति को जो बदली हुई ऐतिहासिकता में महाशक्तियों की बदली भूमिकाओं की परिचायक है।

अमेरिकी नीति एक नई भूमिका को खोज

यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि परम्परा हस्तक्षेप की नीति ने न सिर्फ अमेरिका को आघात पहुंचाया है बल्कि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी उदारवादी साख को भी नष्ट किया है अमेरिका विदेश नीति अब एक नया रूपान्तरण की आवश्यकता को भी नष्ट किया है। नोबिल के साथ संबंधों में सामाजीकरण के साथ साथ इस नये दृष्टिकोण में समस्त परम्परागत जमाने के अन्तिम रूप से समाप्त करना भी एक प्रारम्भिक आवश्यकता थी। निक्सन प्रशासन के दौरान ऐसी ही एक नीति की पहल हुई थी, जिस बाद व प्रशासन ने भी विकसित किया। निक्सन प्रशासन के दौरान वियतनाम युद्ध को अन्तिम रूप में खत्म करने की घोषणा की जा चुकी थी। फोड प्रशासन के नस्लावधान में वियतनाम के ऐतिहासिक मकद पर अन्तिम विराम लगा। 30 अप्रैल 1975 को, दक्षिणी वियतनाम की सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ। इसी के समानांतर एक लम्बे समय में चला आ रहा कम्बोडिया का यह युद्ध भी 18 अप्रैल 1975 को मिहानुक के नरसंहार के बाद वियतनाम की विजय के साथ समाप्त हुआ। इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं ने अमेरिका एक ही एक लम्बे टकराव के बाद पराजय हुई। लेकिन अमेरिकी विदेश नीति ने एक मयापवादी दृष्टिकोण अपनाया और इस पराजय का एक परिवर्तनीय तथ्य के रूप में स्वीकार किया।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी एक नई साख बनाने की यह नीति पश्चिमी एशियाई संकट और लातिनी अमेरिका के राष्ट्रीय संबंधों में भी फोड प्रशासन के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। जुलाई 1975 में अमेरिका ने क्यूबा के साथ अपने परंपरागत प्रतिरोध को समाप्त करने के प्रयास किये। कोस्टारिका की राजधानी सान जोसे में 29 जुलाई 1975 को 21 सन्स्थीय अमेरिकी राष्ट्रों के सम्मेलन का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इन राष्ट्रों द्वारा पिछले 11 वर्षों से क्यूबा पर लगाय गये सामूहिक राजनयिक और व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के पक्ष में 16 राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका स्वयं भी शामिल था। इस घटना का यदि करीब से विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि अमेरिकी दृष्टिकोण अपने स्वयं की विवशता से प्रेरित था कि परोपकारी उद्देश्य में। इस प्रस्ताव के पारित होने से पूर्व ही अनेक अमेरिकी राज्यों ने क्यूबा के साथ द्विपक्षीय स्तर पर व्यापारिक एवं राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इसके पश्चात् अमेरिका राज्यों का सम्मेलन आंतरिक मनमोहा के

कारण विपटन के जगार पर था। अतः अमेरिका से अनुरोध किया गया कि वह यूरोप के साथ अपने वैमनस्य की नीति त्याग दे। पश्चिमी गोलार्ध में राष्ट्रों में परस्पर मतभेद और उनमें घुट अमरिबी स्थिति न लिए वास्तव में एक विपट समस्या थी जिसका कि एक मात्र समाधान यूरोप पर ही प्रतिबन्ध हटा लेना ही था। अतः न चाहते हुए भी अमरिका को ऐसा निणय में मग्योग देना पड़ा।

महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता और एशियाई संकट

20वीं शताब्दी के शालर्यें दशक में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र का एक विशेष एशियाई मन्दम रहा है। दशक के उदघाटन के माथ एशियाई महाद्वीप में घटनाओं का क्रम न अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। भारतीय उपमहाद्वीप में गणित के सन्तुलन में, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद गुणात्मक अन्तर आया जिसके फलस्वरूप भारत को एक उपमहाद्वीपीय शक्ति के रूप में मान्यता मिली। इसी वर्ष, युद्ध में पूर्व हुई भारत और रूस मैत्री संधि एक विनोद सामरिक महत्व की मिट्टी हुई। रूस और चीन के उभरते हुए विवाद और चीन और अमेरिका के बीच एक नये समीकरण के आयोजन के मन्दम में इसका जीर भी अधिक महत्व उभरा। इस घटना के बाद, एशियाई सन्तुलन के मन्दम में दोनों महाशक्तियाँ और विपक्ष अमेरिका और अधिगतत्पर हुई। अमरिबी विदेश नीति के पश्चिम एशियाई प्रयासों में, उमने चीन के साथ संवधा में सामाग्यीकरण की तरफालिकता में अथवा पाकिस्तान और ईरान पर और अधिक निर्भर होने में इन सभी स्थितियों में इस बदल हुए एशियाई सन्तुलन की समथ थी। सामरिक नीति एक महत्वपूर्ण केन्द्र के निर्माण में व्यस्त रही। यद्यपि इसका आधार बहुत सीमित अवधि वाला मिट्टी हुआ जबकि एक आन्तरिक इस्लामिक क्रांति के फलस्वरूप शाह अपदस्थ हुए और एक अमेरिका विरोधी इस्लामी नेतृत्व की स्थापना हुई। पर यह घटनाचक्र इस चरण के उत्तराद में ही घटा और तब तक ईरान अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक भूमिका निभाता रहा।

पश्चिमी एशियाई संकट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें अमेरिकी नीति की परस्पर विरोधी राष्ट्रा में समन्वय स्थापित करने वाली नीति के रूप में सफलता मिली। इस सफलता की एक भीमित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी थी। प्रारम्भिक दौर से अरब राष्ट्रा में सोवियत की विदेश नीति की सफलता मिली थी और इजरायल अपने अस्तित्व में आने के माथ ही पश्चिमी प्रभाव राष्ट्र था। लेकिन मिश्र और रूस के बीच सम्बन्ध में दरार पड़ने के बाद वहाँ एक अमेरिकी भूमिका की सम्भावनायें उभरी। किसिजर की राजनयिक चेष्टाओं से मिश्र के साथ तारतम्य स्थापित हुआ। सम्बन्धों की इस कड़ी में निरन्तर विकास हुआ। किसिजर के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही, प्रारम्भिक असफलता के बाद अन्ततः 4, सितम्बर, 1975

पर विचार विनिमय के अलावा भारत को यह आश्वासन भी दिया कि उसके परमाणु कार्यक्रम हेतु जो भी अमेरिका की प्रतिबद्धता है उसे बिना शर्त निभाया जायेगा। इसके बाद जून, 1978 में भारतीय प्रधानमंत्री और अप्रैल, 1979 में विदेश मंत्री की अमेरिका यात्राएं हुईं। इन बातों में कोई ठोस निश्चय मूलतः सम्भव नहीं था। अतः इन द्विपक्षीय वार्ताओं का स्तर अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर विचार विमर्श और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने से अधिक का नहीं रहा। भारतीय नेतृत्व को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि उत्तरोत्तर रूप से सो. संघ पर भारत की निम्नता बढ़ी है। सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस निम्नता का विकल्प सम्भव नहीं है। अतः भारत अमेरिका सम्बंधों में वढोत्तरी का कोई ऐसा तात्पर्य पूर्णतः अव्यावहारिक है जिसका स्पष्ट अथवा परोक्ष अभिप्राय भारत-रूस सम्बंधों में कठिनाई उत्पन्न करना हो। ऐसी स्थिति में इन सीढ़ाद्रूप यात्राओं का कोई स्पष्ट लाभ दोनों राष्ट्रों को नहीं मिला। भारत को स्पष्ट यूरेनियम दिया जाना संबंधी प्रश्न पर कठिनाईयां पूर्ववत् रही। गमजोशी के इस सीमित अंतराल के बाद, भारत अमेरिका सम्बंधों में पुनः ठहराव आ गया।

विश्व स्तरीय शक्ति के संतुलन में अपने स्थान के साथ चीन का एशियाई महाद्वीप में भी एक विशेष महत्त्व है। रूस-चीन विवाद के बाद चीन की यह एशियाई भूमिका, विशेषतः अमेरिकी दृष्टिकोण में और अधिक महत्त्वपूर्ण बन गई। इस दृष्टि में चीन ने साथ-साथ चीन की जो पहल निक्सन के दौरान प्रारंभ हुई थी, उत्तरोत्तर विकसित होती रही। दोनों राष्ट्रों के बीच उभरते हुए समन्वित विश्व दृष्टिकोण में रूस के प्रसार को सीमित करने का अभिप्राय था। इस अभिप्राय में अमेरिका की यह दृष्टि थी कि एशियाई महाद्वीप में उसका दायित्व चीन निभाये और अन्यत्र उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अमेरिका की हो। इस दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर परिपक्वता आई और इसी के समानांतर अमेरिका और चीन के परस्पर संबंध विकसित हुए। नवम्बर 1974 में किमिन्नर की चीन यात्रा हुई। यह उनकी सातवीं चीन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान चीन की यह समझ थी कि अमेरिका और चीन के संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाये और इस हेतु रूस और अमेरिका के बीच संबंधों के सामाजिकरण के अभिप्रायों को भी चीन के सदस्य में स्पष्ट किया जायेगा। किमिन्नर द्वारा एक और यात्रा किए जाने के बाद, दिसंबर, 1975 में राष्ट्रपति फोर्ड की चीन यात्रा भी नियोजित की गई। इस यात्रा के दौरान चीनी नेताओं द्वारा राष्ट्रपति निक्सन को दिये गये स्वागत की तुलना में राष्ट्रपति फोर्ड की अगवानों अत्यधिक सामान्य और फीकी रही। महत्त्व स्पष्ट था कि जब तक ताइवान इत्यादि पम्परागत प्रश्न नहीं निबट जाते एवं रूस और अमेरिका के बीच संबंधों का अभिप्राय स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक अमेरिका के साथ चीन के संबंध किसी विशेष महत्त्व के नहीं हैं। अमेरिका के नय नतृत्व के

को मिश्र और इजरायल के बीच एक आंतरिक समझौता हुआ। इस आंतरिक समझौते के आधार विवादास्पद मीमात्रों पर मुलह स्वेज नहर में आवागमन की सुविधा, और 'तटस्थ क्षेत्र' 'बफर' क्षेत्र के प्रावधान जिसमें कि मिश्र, अमेरिका, इजरायल और संयुक्त राष्ट्र का सामूहिक पर्यवेक्षण ही आदि थे। इसके बाद 10 अक्टूबर, 1975 को मिश्र और इजरायल के बीच एक समझौता किया गया, जिसमें उपयुक्त प्रावधानों की क्रियाविधित करने की विस्तृत योजना तैयार हुई। 15, मार्च 1976 को राष्ट्रपति सादात ने सोवियत रूस से मंत्री संधि रद्द कर दी। इसके उपरान्त 5, मई, 1975 को अमेरिका ने मिश्र को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की सहायता देने का समझौता किया। इसके बाद इजरायल और मिश्र में परस्पर बातचीत होती रही। अमेरिका ने काटर प्रशासन के आगमन के बाद मिश्र के राष्ट्रपति सादात की नवम्बर, 1977 में इजरायल की यात्रा हुई। इस ऐतिहासिक क्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सितम्बर, 1978 में काटर बेगिन सादात का वॉशिंग्टन में पड़ाव है जो कि तेरह दिनों तक चला। ऐसी घटना अभूतपूर्व थी। न सिर्फ किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इतने दिनों तक मध्यस्थता करना एक अद्वितीय स्थिति, बल्कि अव्यक्त हुए शिखर सम्मेलनों की तुलना में भी यह अत्यधिक लम्बी अवधि का था। एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन शीघ्र ही उसकी क्रियाविधित खटाई में पड़ गयी। अमेरिकी नीति के लिए यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। अतः उभरे हुए मतभेदों के बीच बातचीत के और दौर चले। अतः 25, मार्च, 1976 को राष्ट्रपति काटर की उपस्थिति में मिश्र और इजरायल के बीच शांति संधि सम्पन्न हुई। अमेरिकी विदेश नीति को अपने नये प्रयासों की एकमात्र सफलता मिली।

अफगानिस्तान में भी एक आतंकिक मंचन हो रहा था और यह सम्भावना प्रबल बनती जा रही थी और कि वहाँ एक सोवियत समर्थक नेतृत्व उभरेगा। इन स्थितियों के बीच अमेरिकी विदेश नीति 1 फरवरी, 1975 में एक महत्वपूर्ण घोषणा के द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने पर 10 वर्ष में चला आ रहा प्रतिबंध हटा लिया। इस सन्दर्भ में भारत द्वारा व्यक्त तीव्र प्रतिक्रिया और भारतीय विन्धमन्त्री की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा का स्थगन कोई विनोद प्रभावशाली नहीं बना। 1977 में अमेरिका और भारत दोनों के नेतृत्व परिवर्तन हुआ, अमेरिका का नेतृत्व राष्ट्रपति काटर ने और भारत में प्रथम बार जनता पार्टी की विजय के साथ मोरारजी दे सभावा और कांग्रेस तथा इंदिरा गांधी का नेतृत्व अपदस्थ हुआ। तात्कालिक सदर्भों में इन बन्धनों ने अमेरिकी विदेश नीति को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भारत के साथ भी किसी सामूहिक दृष्टिकोण को उभारने के प्रयास किए जायें। इस उद्देश्य में जनवरी, 1978 में राष्ट्रपति काटर ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विवादों

पर विचार विनिमय के अलावा भारत को यह आश्वासन भी दिया कि उसके परमाणु कार्यक्रम हनु जा भी अमेरिका की प्रतिबद्धता है उसे बिना शर्त निभाया जायेगा। इसका बाद जून, 1978 में भारतीय प्रधानमंत्री और अप्रैल, 1979 में विदेश मंत्री की अमेरिका यात्राएं हुईं। इन बातों में कोई ठोस नियम मूलतः सम्भव नहीं था। अतः इन द्विपक्षीय वार्ताओं का स्तर अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर विचार विमर्श और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में अधिक का नहीं रहा। भारतीय नेतृत्व को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि, उत्तरोत्तर रूप से सो. संघ पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस निर्भरता का विकल्प सम्भव नहीं है। अतः भारत अमेरिका सम्बन्धों में बलोत्तरी का कोई ऐसा तात्त्व्यपूर्ण अन्वयावहारिक है, जिसका स्पष्ट अथवा परोक्ष अभिप्राय भारत-रूस सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न करना हो। ऐसी स्थिति में इन सीमाद्वेषण यात्राओं का कोई स्पष्ट लाभ दोनों राष्ट्रों को नहीं मिला। भारत को श्रेष्ठ यूरैनियम दिये जाने संबंधी प्रश्न पर कठिनाईयां पूर्ववत् रही गमजोशी के इस सीमित अंतराल के बाद, भारत अमेरिका सम्बन्धों में पुनः ठहराव आ गया।

विश्व स्तरीय शक्ति के संतुलन में अपने स्थान के साथ, चीन का एशियाई महाद्वीप में भी एक विशेष महत्त्व है। रूस-चीन विवाद के बाद चीन की यह एशियाई भूमिका, विशेषतः अमेरिकी दृष्टिकोण में और अधिक महत्पूर्ण बन गई। इस दृष्टि से चीन के साथ संबंधों की जो पहल निक्सन के दौरान प्रारम्भ हुई थी, उत्तरोत्तर विकसित होती रही। दोनों राष्ट्रों के बीच उभरते हुए समन्वित विश्व दृष्टिकोण में रूस के प्रसार को सीमित करने का अभिप्राय था। इस अभिप्राय में अमेरिका की यह दृष्टि थी कि एशियाई महाद्वीप में उसका दायित्व चीन निभाये और अन्य उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अमेरिका की हो। इस दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर परिपक्वता आई और इसी के समानांतर अमेरिका और चीन के परस्पर संबंध विकसित हुए। नवम्बर 1974 में किंसिजर की चीन यात्रा हुई यह उनकी सातवीं चीन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान चीन की यह समझ थी कि अमेरिका और चीन के संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाये और इस हेतु रूस और अमेरिका के बीच संबंधों के सामायीकरण के अभिप्रायों की भी चीन के सदस्य में स्पष्ट किया जायेगा। किंसिजर द्वारा एक और यात्रा किए जाने के बाद, दिसंबर, 1975 में राष्ट्रपति फोर्ड की चीन यात्रा भी नियोजित की गई। इस यात्रा के दौरान चीनी नेताओं द्वारा राष्ट्रपति निक्सन को दिये गये स्वागत की तुलना में राष्ट्रपति फोर्ड की अगवानों अत्यधिक सामान्य और फीकी रही। मतव्य स्पष्ट था कि जब तक ताइवान इत्यादि पम्परगत प्रश्न नहीं निबट जाते एवं रूस और अमेरिका के बीच संबंधों का अभिप्राय स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक अमेरिका के साथ चीन के संबंध किसी विशेष महत्त्व के नहीं हैं। अमेरिका के नय नेतृत्व के

के रूप में राष्ट्रपति कार्टर के आगमन के बाद नये प्रयास हुए। अगस्त, 1977 में राज्य सचिव साईरसबैस और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजिंस्की चीन यात्रा हुई। इन राजनयिक गतिविधियों के फलस्वरूप चीन-अमेरिका संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। 15, दिसम्बर, 1978 को अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की और यह कहा कि 1, जनवरी, 1979 से चीन व अमेरिका के बीच यथावत रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। इसी मतभेद की एक और घोषणा बीजिंग से भी हुई। इस घटना के फलस्वरूप चीन की एकमात्र सरकार के रूप में बीजिंग सरकार को मान्यता मिली, यद्यपि ताइवान के माध्यमनोपचारिक अमेरिकी संबंधों का प्रश्न अब भी यथावत बना रहा।

सोवियत प्रति-प्रयास

एशियाई महाद्वीप में अमेरिका और चीन की उभरती हुई इस घुरी के सदम में एक अमेरिका के अथ एशियाई प्रयासों के सदम में, रूस के भी प्रयास रहे। भारत में नेतृत्व परिवर्तन के तुरंत बाद अप्रैल 1977 में रूस के विदेश मंत्री ग्रोमिक्को की भारत यात्रा हुई। इस यात्रा का तत्कालिक उद्देश्य, नेतृत्व परिवर्तन के बाद रूस की तरफ से भारत रूस संबंधों में पुन आस्था व्यक्त करना था। साथ ही साथ अमेरिका के संभावित प्रयासों का मूल्यांकन भी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था। सोवियत निमंत्रण पर अक्टूबर, 1977 में भारतीय प्रधानमंत्री एक विदेश मंत्री की रूस की राजकीय यात्रा हुई। इस यात्रा के फलस्वरूप भारत के नये नेतृत्व और रूस के बीच संबंध स्थापित हुआ। दोनों राष्ट्रों के बीच आधिक सहयोग का एक दीर्घकालीन कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की समीक्षा और प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता का सिद्धांत, हिंद महासागर का एक शांति क्षेत्र के रूप में अस्तित्व, और समस्त एशियाई राष्ट्रों में द्विपक्षीय संबंधों के माध्यमों से सहकारिता, आदि मत समुचित विनिर्मुक्ति में व्यक्त किये गये। इस यात्रा के दौरान संध के नेतृत्व ने भारतीय पक्ष की अनेक शिकायतों का समाधान किया और भारत को हर स्थिति में सहयोग हेतु आश्वासित किया। मई 1978 में भारतीय रक्षामंत्री जगजीवनराम की रूस की यात्रा हुई, जो कि भारत और रूस के बीच सैनिक सहयोग के विकास में एक अगला चरण भी। मार्च, 1979 में सोवियत प्रधान मंत्री कोमीगिन भारत-यात्रा पर आये। उसके बाद जून, 1979 में ही प्रधान मंत्री देसाई की रूस यात्रा हुई। देसाई की इस यात्रा के दौरान, भारत की ओर से यह स्पष्ट कर दिया, कि ही दूसरे राष्ट्रों के साथ भारत से संबंधों का आधार भारत रूस मंत्री में व्यवधान नहीं हो सकता। भारत रूस मंत्री की बलि देकर भारत अन्य संबंध नहीं बढ़ाना चाहता। प्रधान मंत्री देसाई की यात्रा के दौरान

क्रियाविवृति में गतिरोधों का उत्पन्न होता जाता है स्वाभाविक एवं व्यावहारिक सदेह था। ऐसी स्थिति में जबकि सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक स्थितियाँ उचित रूप में विकसित न हो, तो एक बार सामयिकी नेतृत्व की स्थापना हो भी जाये तो उसका निर्वाह कठिन होगा। इस स्थिति का एक स्पष्ट अभिप्राय था। यदि आंतरिक असंतुलन की स्थिति को संभालना पड़े तो यह सोवियत संघ के लिए एक अतिरिक्त दायित्व होगा और जिसमें परीक्षा प्रयासों के साथ साथ सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकताएँ भी उत्पन्न सकती हैं। ऐसे कुछ सीमित अनुभव मिथ एवं अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों में सोवियत को हो चुके थे। किंतु इन अनुभवों में भी हस्तक्षेप तक की स्थिति नहीं पहुँच पाई थी। लेकिन इन अभिप्रायों की ओर अधिक उग्र अभिव्यक्ति का सामना जोध हो उस की विदेश नीति को करना पड़ा।

महाशक्तिय प्रतिद्वन्द्विता का अफ्रीकी संघ

उपनिवेशवाद के अन्तर्धान के साथ साथ अफ्रीकी राष्ट्रों में राजनीतिक स्वतंत्रता की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उपनिवेशवाद के अन्तिम वर्षों में, अमेरिका के अफ्रीकी राष्ट्रों में आर्थिक हितों में अत्यधिक वृद्धि हुई। अतः इन राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं भावी आर्थिक स्वतंत्रता की भूमिका, स्वाभाविक रूप से अमेरिका के लिए चिंतनीय थी। इस दृष्टि से, उत्पन्न हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी उपनिवेशी राष्ट्रों का दुराग्रही व्यवहार रहा। यह व्यवहार राष्ट्रीय आंदोलनों के उत्थार के साथ साथ और अधिक स्पष्ट रूप से उत्पन्न। साथ ही साथ, अमेरिका में भी एक अफ्रीकी समुदाय था। इस अल्पमत समुदाय के साथ भी नैदानात्मक अमेरिकी राजनीति की एक वलकित प्रवृत्ति रही। इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप, अफ्रीकी राष्ट्रों में अमेरिकी विदेश नीति की साक्ष परंपरागत रूप से अत्यधिक सदेहास्पद बनी रही। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में, अमेरिकी विदेश नीति के लिए अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच एक नई साल और सहभावना स्थापना करना एक विश्वव्यापी साक्ष के लिए आवश्यक था।

जहाँ तक सोवियत संघ का प्रश्न है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी आन्दोलनों के साथ एकजुटता उसकी नीति का अविभाज्य अंग था। अफ्रीकी राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय सोवियत सहयोग की एक लक्ष्य परम्परा बनी। 1951 में नक्रुमा के नेतृत्व में हो रहे घाना के आंदोलन से लेकर अंगोला में अगस्टिनो नेटा के नेतृत्व के समकाल तक, सोवियत सक्रियता का एक लक्ष्य योगदान रहा। इस योगदान की परंपरा के प्रमुख दृष्टांत लाइबेरिया, गिनी, इकोपीया सोमालिया, अल्जीरिया, एवं मोजाम्बिक आदि अनेक राष्ट्रों के राष्ट्रीय आंदोलन हैं। इनमें कुछ स्थितियों में, जैसे अल्जीरिया और मोजाम्बिक, में दीर्घ कालीन दृष्टि भी हुआ। ऐसी स्थितियों में सोवियत समर्थन की विश्वसनीयता

और अधिक स्पष्ट हुई। इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप, सोवियत संघ को अनेक सामरिक सफलताएँ भी मिली जिनमें 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' में सैनिक सुविधाएँ अत्यधिक महत्व की थी। अफ्रीकी राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद सोवियत संघ की भूमिका एक आर्थिक सहयोगी के रूप में भी बनी। इन प्रयासों के सम्मिलित प्रभाव ने एक विशिष्ट सोवियत स्थिति को जन्म दिया।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विश्वव्यापी सामाजिककरण की प्रक्रिया का अफ्रीकी मंच पर भी प्रभाव हुआ। विघटननाम के अनुभव के बाद, अमेरिका को यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी हस्तक्षेप की नीति प्रतिगामी सिद्ध हुई है। भविष्य में भी सीधे हस्तक्षेप की संभावनाएँ न तो औचित्यपूर्ण ही हैं और न ही व्यावहारिक। इस समय के बाद, अमेरिकी नीति का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे नये स्वरूप को प्रस्तुत करना था जोकि अमेरिका को पुनः एक शांतिप्रिय एवं परोपकारी राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करे। इसी उद्देश्य से, राष्ट्रपति कार्टर के आगमन के तुरंत बाद अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ सीमाद्वेषण सारतम्य स्थापित करने के प्रयास किये गये। 1977 में सत्ता सभालने के तुरंत बाद 'एड्युयग मिशन' का अफ्रीका में आगमन हुआ। यह ने 3 फरवरी से 12 फरवरी तक तंजानिया और नाइजीरिया का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास हुआ कि दक्षिणी अफ्रीका के विभिन्न संकटों को सुलझाने में अमेरिका का एक उदारवादी दृष्टिकोण है। इस यात्रा के बाद रोडेसिया संकट के संबंध में अमेरिका ने कुछ सकारात्मक आशय भी व्यक्त किये। राज्य सचिव साइरस वैंस द्वारा रोडेसिया की अल्पमत सरकार को एक चेतावनी भी दी गई। लेकिन इस संबंध में कोई विशेष प्रयास देखने को नहीं मिले। अफ्रीका में एक नई भूमिका की चाह होते हुए भी, अमेरिकी विदेश नीति के लिए यह संभव नहीं था। विशेषतः दक्षिणी अफ्रीका में उसके अत्यधिक महत्वपूर्ण हित हैं। कुछ ऐसे खनिज जिनका सामरिक महत्व है, दक्षिण अफ्रीका में ही उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में बाहरी रूप में अमेरिकी नीति भले ही परोपकारी होने का प्रयास करे वस्तुतः यह एक असंभव स्थिति है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण ताजा घटनाओं में भी उपलब्ध हैं। अंगोला और दक्षिण अफ्रीका विवाद अंगोला के अस्तित्व से ही है। अंगोला के राष्ट्रीय आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया था। दिसंबर, 1981 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंगोला पर आक्रमण कर दिया गया। इस स्थिति में अमेरिका ने स्पष्ट एवं खुले रूप से दक्षिण अफ्रीका का समर्थन किया एवं इस संबंध में सुरक्षा परिषद में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग भी किया। दक्षिण अफ्रीका की रणभेद नीति के पक्ष में ऐसे विशेषाधिकार के प्रयोग की एक अमेरिकी परंपरा ही बन गई है। ऐसी स्थिति में, सोवियत संघ से प्रतिद्वंद्विता की कामना करते हुए भी अमेरिकी विदेश नीति कोई प्रभावी सफलता प्राप्त करने में असमर्थ

सिद्ध हुई है। अफिरा = वह एक ऐतिहासिक विडवना की शिकार है।

अफिरा में अमेरिकी प्रथम प्रयासों की तुलना में सोवियत संघ की सक्रियता में एक आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलकता है। इस सदम में 1977 में सोवियत राष्ट्रपति पोडगार्नी की अफिरा यात्रा के अनुभव उत्प्रेक्षनीय हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य अफिरा में अमेरिकी प्रयासों का प्रत्युत्तर देना था। वैसे तो अफिरा सोवियत संघों की एक सखी प्रक्रिया रही है, लेकिन सोवियत राज्याध्यक्ष का अफिरा भ्रमण एक प्रथम अनुभव था। मार्च, 1977 में आयोजित इस यात्रा के दोहरे पक्ष थे। अपनी इस बारह दिवसीय यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति पोडगार्नी, एक ओर स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच सोवियत संघों में प्रगाढ़ता लाना चाहते थे, तो दूसरी ओर विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं के साथ सक्रिय एकजुटता प्रदर्शित करना चाहते थे।

तजानिया और जांबिया की यात्रा के दौरान, अफिरा में सोवियत उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। यह कि, अफिरा में सोवियत भूमिका निजी स्वार्थों के दृष्टि कोण से प्रेरित नहीं है, और न ही परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार सामरिक अथवा सैनिक सुविधाएं हैं। सोवियत प्रयास मुख्यतः साम्राज्यवाद और रणभेद नीति के उन्मूलन के पक्षधर हैं जो कि उसकी विचारधारा के भी प्रमुख अंग हैं। सोवियत जांबिक एवं राजनीतिक सहयोग अफिरा की राष्ट्रों को साम्राज्यवाद से मुक्त करवा कर उन्हें समाजवादी व्यवस्था की ओर प्रेरित करना है। इस हेतु सोवियत संघ अफिरा की राष्ट्रों के साथ समानता के आधार पर मैत्री संबंध स्थापित करने का इच्छुक है। सोवियत राष्ट्रपति द्वारा तजानिया के राष्ट्रपति जुलियस येरेरे के समाजवादी विचारों और विशेष प्रयासों की सराहना की गई। तजानिया और चीन में मैत्री संबंध होते हुए भी रूस की सफलता मिली। इस यात्रा की समाप्ति पर तजानिया के वक्तव्य में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि, अनुभव के आधार पर अफिरा ने यह सीखा है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रभावशाली संघर्ष समाजवादी राष्ट्रा की आर्थिक एवं राजनीतिक एकजुटता के बिना असंभव है। केनय कांडका के नरत्व वाल जांबिया में भी सोवियत विचारों की समर्थन मिली। सोवियत और जांबियाई नेताओं के बीच अनेक अफिरा एवं विश्वस्तरीय प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिणी अफिरा के विवादों के मानवीय समाधान पर बल दिया गया और इसमें अवरोध उत्पन्न करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों की भत्सना की गई। इन आंदोलनों में सक्रिय सहयोग हेतु अन्य राष्ट्रा का सामूहिक आह्वान भी किया गया। लेकिन राष्ट्रपति कांडका का मत था कि किसी भी स्थिति में सहायक का तात्पर्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अंगोला में क्यूबा और सोवियत संघ की भूमिका से संबंध अनेक संघर्ष भी स्पष्ट किये गए। राष्ट्रपति पोडगार्नी की मोजम्बिक यात्रा दोनो राष्ट्रों के बीच संबंधों का ठोस स्वरूप देने हेतु थी।

दोना के बीच 15 वर्षीय मंत्री संधि हुई। राष्ट्रपति और फेलियो पार्टी के नेता सामोरा मागेल के नेतृत्व की सराहना की गई। इस दृष्टि से माजिम्बेका का चीनी प्रभाव में मुक्त होना विशेष उत्तरेखनीय था।

अपने अफ्रीकी प्रयास के दौरान अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं से भी सोवियत राष्ट्रपति ने विचार विमर्श किया। इनमें, जिबाब्बे अफ्रीकी संघ (जापू) के जोशुआ 'कोमा' दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी संगठन (स्वापो) के अध्यक्ष साम नूजोमा और दक्षिण अफ्रीकी, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस (ए० एन० सी०) के अध्यक्ष विलाइवट टाबा महत्वपूर्ण थे। लुसाका में हुई वर्तमान में इन संगठनों के साथ सोवियत एकजुटता एवं उनके उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। दक्षिणी अफ्रीका में बहुमत के हेतु सोवियत संघ ने अपने दायित्व का निर्वाह करने और आवश्यक आर्थिक, राजनैतिक एवं सैनिक सहायता देने का स्पष्ट आश्वासन दिया। इस सदन में यह भी व्यक्त किया गया कि अफ्रीका में सोवियत सैनिक उपस्थित सत्ताज्यवाद के विरोध और अफ्रीकी जन आंदोलनों के समर्थन से प्रेरित है। इस अवसर पर, जिनेवा सम्मेलन की असफलता में अमेरिकी नीति में ईमानदारी की कमी और उसके दागलेपन की भी स्पष्ट भत्सना की गई।

दो महाशक्तियों की प्रतिष्ठा बनाए अफ्रीका में संतुलन सोवियत संघ के पक्ष में ही रहा है, यह उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अफ्रीका में अमेरिकी समर्थक राज्य नहीं रहे हैं। लेकिन अधिकांशतः अमेरिकी समर्थक राष्ट्र अफ्रीकी महाद्वीप की प्रमुख ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से बड़े हुए राष्ट्र थे ऐसे राष्ट्र जिनके उभरती हुई घाग के सीधे या पराक्ष रूप से विराधी या अवरोधक रहे हैं। अधिकांश राष्ट्रीय आंदोलनों में अमेरिका की भूमिका और विशेषतः जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका में रणनीति का उसका समर्थन एस तथ्य थे जिनके फलस्वरूप अमेरिका के प्रति अफ्रीका में एक महाद्वीपीय असंतोष व्याप्त रहा। इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ की स्थिति रही। सोवियत संघ को भले ही कोई निश्चित प्रतिबद्धता महाद्वीपीय स्तर पर नहीं मिला लेकिन राष्ट्रीय आंदोलनों में उसका समर्थन और सैन्य सहयोग होने के नाते, अफ्रीका में सोवियत संघ की एक मंत्रीपूर्ण वातावरण मिला। अनेकों राष्ट्र स्वतंत्र होने के साथ साथ सोवियत संघ के साथ जुड़ते चले गये, यद्यपि इन संबंधों में प्रतिबद्धता का स्तर समान नहीं था। 17 अप्रैल, 1980 को स्वतंत्र जिम्बाब्वे के अस्तित्व के साथ सोवियत संघ की एक ओर मित्र राष्ट्र बना। इसके विपरीत बाहरी परिवर्तन के दायरे के बाद भी अमेरिकी नीति में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया। हाल ही में अमेरिका द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को समर्थन एवं सैन्य सहायता का स्तर समान नहीं था। 17 अप्रैल, 1980 को स्वतंत्र जिम्बाब्वे के अस्तित्व के साथ सोवियत संघ की एक ओर मित्र राष्ट्र बना। इसके विपरीत बाहरी परिवर्तन के दायरे के बाद भी अमेरिकी नीति में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया। हाल ही में अमेरिका द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को समर्थन एवं सैन्य सहायता का स्तर समान नहीं था। 17 अप्रैल, 1980 को स्वतंत्र जिम्बाब्वे के अस्तित्व के साथ सोवियत संघ की एक ओर मित्र राष्ट्र बना। इसके विपरीत बाहरी परिवर्तन के दायरे के बाद भी अमेरिकी नीति में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया। हाल ही में अमेरिका द्वारा दक्षिणी अफ्रीका को समर्थन एवं सैन्य सहायता का स्तर समान नहीं था।

का प्रयोग किया गया। अमेरिका की इस दुराग्रही नीति का, अनेक आशाओं के बाद भी निकट भविष्य में अतः संभव प्रतीत नहीं होता।

समसामयिक घटनाचक्र

समसामयिक घटनाचक्र मुख्यतः निम्न घटनाओं के दायरे में उसता रहा है—ईरान की इस्लामिक क्रांति, अफगानिस्तान का समाजवादी स्वरूप, चीन में आंतरिक सत्ता परिवर्तन, पोलैंड का समाजवादी संकट और पश्चिमी एशिया में युद्ध की विभीषिका। समसामयिक घटनाचक्र के इन घटानों को अनेक विशेषज्ञों द्वारा अत्यधिक दूरगामी प्रभाव का माना गया है, क्योंकि ये सभी घटनाएँ अपने आप में भविष्य की दिशासूचक कही जा सकती हैं। भविष्य की इस दिशा को, पिछले विवेचन के ऐतिहासिक सदर्भ में रखा जाये तो इसमें स्पष्ट निरंतरता भी देखने को मिलेगी। इन घटनाओं के महाशक्तिय प्रतिद्वंद्विता के सदर्भ और भी अधिक स्पष्ट है। कुछ पक्षों द्वारा अमेरिकी नेतृत्व के रूप में 20 जनवरी, 1981 को राष्ट्रपति रीगन के आगमन को भी एक महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है। यह सही है कि इस घटना की भी महत्वपूर्ण तात्कालिकता है, लेकिन इसके माध्यम से अमेरिकी नीति में कोई गुणात्मक परिवर्तन की तलाश एक फूहड़ प्रयास होगा। पिछले दशक के अनुभवों ने अमेरिकी जनता के बीच एक राष्ट्रीय आघात और अपमान की मानसिकता उत्पन्न की। इस मानसिकता का फायदा उठाते हुए रोनल्ड रीगन की विजय हुई, जिन्होंने चुनावी आश्वासन दिया था कि वे अमेरिका के राष्ट्रीय सम्मान और शक्ति को पुनः स्थापित करेंगे। अतः विजय के बाद उग्र वक्तव्य उनके लिए स्वाभाविक था। इन वक्तव्यों में अनेक विक्षेपण गुणात्मक बदलाव की रीतिरिधा खोजने लगे, जो कि वस्तुस्थिति के स्तर पर प्रारंभ से ही मूलतः असंभव थी। पिछले डेढ़ वर्ष का अनुभव इस बात का साक्ष्य है कि न सिर्फ वक्तव्यों की उपता में कमी आई है बल्कि, अमेरिकी विदेशनीति के वास्तविक स्वरूप में भी यथावत यथाव्यवही दृष्टिकोण बना रहा है। आज भी अमेरिकी नीति ऐतिहासिक दुविधा में फंसी है कि वह स्वयं के हितों के पक्ष में रहे या प्रभाव के लिए उभरते असंतोषों के पक्ष में। फॉर्कलेण्ड का संकट इस असमंजस की स्थिति का नवीनतम उदाहरण है जिसमें अमेरिका की भूमिका को दोनों ही पक्षों ने दोगला माना। यही नहीं, अर्जेंटीना के द्वारा इस खुली घोषणा ने कि यदि आवश्यकता हुई तो वह सोवियत संरक्षण का सहारा भी लेगा, अमेरिका के लिए उसके परंपरागत प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध में भी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी। ऐसी ही कुछ प्रवृत्ति अन्य घटनाओं में भी उभरी हैं।

ईरान की इस्लामी क्रांति

16 जनवरी, 1979 को ईरान में शाह सत्ता समाप्त प्रायः सी हो गई, जबकि उन्होंने ईरान छोड़ा। फरवरी 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी के आगमन के साथ ईरान का एक नया इतिहास प्रारंभ हुआ। ईरान में इस्लामी क्रांति की स्थापना अनेक दृष्टिकोणों से महत्व की है। एक ओर इसने जहाँ अमेरिकी नीति के एक महत्वपूर्ण सामरिक केन्द्र को ध्वस्त कर दिया, वहीं दूसरी ओर ईरान को एक ऐसी निरपेक्षता प्रस्तुत की जो कि अपने राजनीतिक और वैचारिक स्वरूप में एकदम भिन्न थी। अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध अथवा व्यवहार में जो विचार-धाराएँ थी, उनसे असंगत होकर किया गया। साम्राज्यवाद का विरोध किसी स्वतंत्रता के सिद्धांत अथवा प्रगतिशील विचारधारा के माध्यम में नहीं अपितु इस्लाम के धार्मिक आधार पर किया गया। अतः वैचारिक स्तर पर ईरान की क्रांति पूँजीवादी समाजवादी और तृतीय राष्ट्रीय की मिश्रित व्यवस्था से गुणात्मक रूप से भिन्न थी। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भों के कारण, अमेरिका के साथ ईरान का वैमनस्य अत्यधिक उग्र और तात्कालिक था। इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद अमेरिका की सामरिक सुविधाएँ बढ़ कर दी गईं और साथ ही साथ उसके आर्थिक हितों पर भी सीधा प्रहार किया गया।

इस पूरे घटनाचक्र का अत्यधिक रोमांचकारी उद्घरण ईरान द्वारा अमेरिकी दूतावास में कायरत व्यक्तियों की बंधक बनाम जाने की घटना है। 4 नवम्बर, 1979 को यह घटना घटी जिसके द्वारा कुछ उग्रवादी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और वहाँ कायरत अमेरिकी नागरिकों को बंदी बना लिया गया। इस कायवाही को धार्मिक सत्ता द्वारा उचित कहा गया और उन्हें रिहा करने की अमेरिका के सामने शर्तें रखी गईं। इन शर्तों का प्रमुख उद्देश्य अमेरिका से आर्थिक मुआवजा वसूल करना था और अमेरिकी बंको में ईरानी पूँजी को सुरक्षित करना था। महाशक्ति अमेरिका के लिए ईरान की ललकार वास्तव में विचित्र और खोज भरी स्थिति थी। वार्ता के प्रारंभिक प्रयासों के बाद अमेरिका द्वारा अप्रैल, 1980 में बंधकों को छोड़ने का सैनिक प्रयास किया गया। इस प्रयास की असफलता ने अमेरिकी नीति में और झेंप पैदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसे बहद हास्यास्पद बनाया। आंतरिक असंतोष के समक्ष राज्य सचिव साईरस वेंस को त्यागपत्र देना पड़ा। इन घटनाओं ने चुनावी माहौल में राष्ट्रपति काटर की स्थिति और अधिक दयनीय बनायी, और उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को रिहायी को एक निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। चुनाव में पराजय के बाद भी प्रयास जारी रहे। 20 जनवरी, 1981 को, जिस दिन राष्ट्रपति रीगन को बाय भार सभालना था, इससे पूर्व ही अमेरिका और ईरान के

बीच बंधन की रिहायी के संबंध में समझौते की घोषणा की गई। इस समझौते के अनुसार अमेरिका ने 8 बिलियन डॉलर का मुआवजा देने की बात मंजूर की और अमेरिकी बंको में ईरानी पूंजी के संरक्षण के संबंध में समझौता किया।

अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव का कोई सीधा प्रभाव सोवियत संघ के संदर्भ में नहीं पड़ा। यह सही है कि अमेरिकी बंधन का जो संकट था, उस दौरान सोवियत संघ और ईरान में सम्पर्क बढ़े। वैसे भी वैचारिक रूप से भिन्न होते हुए भी सोवियत संघ के प्रति ईरान के दृष्टिकोण में उदासीनता और पारस्परिकता का मिला जुला भाव रहा। भविष्य में इन संबंधों के सुधरने की संभावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण अवरोध हैं। प्रथम, तो यह कि आंतरिक राजनीति में ईरान की धार्मिक सत्ता का विरोध बामपंथी कर रहे हैं और इस संबंध में अभी तक कोई दूरगामी सोवियत दृष्टि स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरा प्रमुख अवरोध है ईरान ईराक युद्ध और ईराक सोवियत प्रेमी है। सितम्बर 1980 में दोना दशा के बीच युद्ध की स्थिति तक बन गई। अतः ईरान ईराक सीमा विवाद के उचित समाधान के बिना सोवियत और ईरान के संबंधों में वर्तमान ठहराव की स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन की संभावनाएँ नहीं मिलती। लेकिन अमेरिका के सक्रिय विरोध की ईरान की नीति वास्तविक रूप में सोवियत सामरिक हितों की पुष्टि ही करती है।

अफगानिस्तान की समाजवादी क्रांति

अप्रैल, 1978 में अफगानिस्तान में सैनिक सत्ता परिवर्तन के माध्यम से एक समाजवादी और सोवियत पक्षीय नेतृत्व सत्ता में आया। नूर मोहम्मद ताराकी के नेतृत्व में हुई इस ऐतिहासिक घटना का समय 'क्रांति' की संज्ञा मिली। तत्तीय राष्ट्रा में 'बिना पूंजीवाद समाजवादी व्यवस्था का माध्यम' का सिद्धांत अफगानिस्तान में एक बार पुनः संकट में पड़ा। उत्पादन शक्तियाँ के अविनियमित होने की स्थिति में वैचारिक एवं व्यवस्थागत बदलाव कितना कठिन और अव्यावहारिक है, इस बात का अनुभव सोवियत नीति की अफगानिस्तान में करना पड़ा। सैनिक माध्यम से समाजवादी नेतृत्व की स्थापना मात्र से अफगानिस्तान में समाजवादी विचारधारा और व्यवस्था लागू करने के प्रयास हुए। बामपंथी पार्टियों के दो पंथों 'खल्क' और 'परचम' के बीच आंतरिक विवाद भी उत्पन्न हुआ। यह विवाद समाजवादी प्रवृत्तियों की गलत रूप से नीति के अधिक विस्फोटक बन गया। इस बीच जहाँ स्थिति में एक तात्कालिकता भी थी सोवियत राय थी कि वैचारिक और व्यावहारिकता से लागू किया जा

आंतरिक विवादों में सामयिक हस्तक्षेप नहीं कर सका और इस सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण को प्रियायित नहीं करवा सका। परिणाम स्वाभाविक थे। आंतरिक टकराहट के फलस्वरूप एक और आंतरिक सैनिक सत्ता परिवर्तन हुआ। नूर मोहम्मद तरावी की हत्या के बाद सितम्बर, 1979 में हाफिजुल्लाह अमीन ने नेतृत्व लिया। उसकी नीतियों के प्रति सोवियत नेतृत्व आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वह वांछित नीति के विपक्षी घटक का था। अतः शीघ्र ही एक और सत्ता परिवर्तन हुआ और अमीन की हत्या के बाद 27 दिसम्बर, 1979 में बरबक कर माल का नेतृत्व स्थापित हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति में अत्यधिक जटिलता और अशांति व्याप्त हो गई। अमेरिका समर्थित गेरिल्ला घुसपठिया के पाकिस्तान के माध्यम से सक्रिय होने के कारण स्थिति और भी अधिक बिगड़ हो गई। अतः सोवियत सेनाओं का सैनिक हस्तक्षेप वामपंथी नेतृत्व को दबाने के लिए एक अनचाही आवश्यकता बन गई। जनवरी 1980 के प्रारंभ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और काफी तैदाद में रूस की सेनाओं को उपस्थित होना पड़ा। सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के दो प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम, यह कि अफगानिस्तान की वामपंथी पार्टी में फूट की स्थिति को खत्म किया जावे और उस सही दृष्टिकोण के आधार पर सगठनात्मक और वैचारिक रूप से पुनः एकजुट बनाया जावे। दूसरी ओर गेरिल्ला हस्तक्षेप को नेस्तेनाबूद किया जाये जिसके कारण वामपंथी पार्टी के प्रयासों में भी अत्यधिक कठिनाइयाँ आ रही थी। इन उद्देश्यों में सोवियत हस्तक्षेप ने उत्तरोत्तर सफलता पाई है।

अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति सामरिक दृष्टि से अमेरिका के लिए अत्यधिक चिंता का विषय थी, विशेषतः उस स्थिति में जबकि ईरान में अपना सामरिक केन्द्र अमेरिका पहले ही खो चुका था। इस घटना के माध्यम से, अमेरिकी नीति ने एक बार फिर विश्वव्यापी प्रचार युद्ध प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में जबकि अमेरिकी नीति अपनी एक नई साख तैयार करने में लगी थी और अमेरिका की एक शांतिप्रिय और अहस्तक्षेपवादी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रही थी, अफगानिस्तान में सोवियत का हस्तक्षेप एक सुनहरा अवसर था। इस संकट को लेकर तृतीय राष्ट्रों में सोवियत नीति को विस्तारवादी और स्वतंत्रता विरोधी सिद्ध करना अमेरिका के दूरगामी और तात्कालिक हितों के आधार पर सख्त उतरता था। अमेरिका ने प्रारंभिक रूप से प्रचार के माध्यम से इस हेतु एक विश्वव्यापी प्रयास किया। तात्कालिक रूप में इन प्रयासों को आशा से अधिक सफलता भी मिली। 14 जनवरी 1980 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में सोवियत हस्तक्षेप के विरोध में एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 104 और विपक्ष में 18 वोट पड़े और 18 राष्ट्रों ने मतदान में भाग नहीं लिया जिसमें प्रमुख रूप से भारत भी था। लेकिन, यह तात्कालिक

सफलता इस उग्र रूप में अधिक दिन तक नहीं बनी रही। सोवियत संघ ने भी प्रचार के द्वारा यह धारणा बनाने का प्रयास किया कि अफगान संकट की प्रारंभिक और मूल जड़ अमेरिका द्वारा प्रेरित गेरिल्ला हस्तक्षेप था और इस का हस्तक्षेप भी आंतरिक संकट के इस सदम में देखा जाना चाहिए। इस प्रचार के समानान्तर, सोवियत समाजों के निर्देशन में अफगानिस्तान में आंतरिक स्थायित्व लाने का प्रयास भी तेजी आई। इसके फलस्वरूप अफगानिस्तान की वामपंथी पार्टियों का विघटन नियंत्रित हुआ उसकी नीतियों में यथासंभव दो दृष्टिकोण समाविष्ट हुआ और इन नीतियों का धैर्यपूर्ण क्रिया करने से जन असंतोष और विरोध भी अत्यधिक कम हुआ। साथ ही गेरिल्ला हस्तक्षेप भी नियंत्रण में कर लिया गया।

इन घटनाओं के साथ ही सोवियत संघ ने अफगान समस्या का सभी प्रकार के हस्तक्षेप खत्म किये जाने के आधार पर एक 'राजनीतिक समाधान' किये जाने की बात रखी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अमेरिका द्वारा लगाये गये न्यायसत्ता के आरोपों की प्रामाणिकता की खोज करने के प्रयास भी किये। एक वर्ष से अधिक के हस्तक्षेप के बाद स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक दल अफगानिस्तान की यात्रा पर गया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति में जन असंतोष अथवा न्यायसत्ता देखने को नहीं मिलती और वहाँ की आंतरिक स्थिति अत्यधिक शक्तिपूर्ण और व्यवस्थित प्रतीत होती है। अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति का एक और औचित्य देते हुए सोवियत संघ ने यह दावा किया कि उसकी सेनाओं की उपस्थिति कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि ऐसा अफगानिस्तान की मायता प्राप्त सरकार के आमंत्रण पर किया गया था। इन विविध वास्तविकताओं और परस्पर विरोधी मायताओं के समानांतर प्रचार के फलस्वरूप संघ के प्रति प्रारंभिक विरोध अब अधिकाधिक रूप विरल होता गया। इस बात का संकेत अमेरिका के आह्वान के बाद भी जुलाई, 1980 में हुए मास्को ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उपस्थिति और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रीय सम्मेलन में हुई प्रतिक्रिया से मिलता है। मास्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करने का आह्वान अमेरिका ने रूसी हस्तक्षेप का प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए किया। तृतीय राष्ट्रों की ओर से ही नहीं, पश्चिमी गुट के राष्ट्रों से भी इसका कोई उत्साहवर्धक समयन नहीं किया। इस आह्वान के बाद अमेरिका अफगान संकट की अपनी मायता के सदम में, और अधिक एकाकी हो गया। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने भी अपने संयुक्त मत में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया और अफगानिस्तान में सभी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की समाप्ति और समस्या के राजनीतिक समाधान की बात कही। मर्तव्य के अभाव में राजनीतिक समाधान के वास्तविक स्वरूप की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई। इन घटनाओं के बाद अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति

पर अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान केन्द्रित नहीं रहा, विशेषतः इसलिए भी कि अनेक अन्य महत्वपूर्ण विवाद उभरे, जिसके फलस्वरूप अफगान संकट की तात्कालिकता नहीं रही।

1945 के बाद के घटना चक्र ने जिस भूमिकाओं के बदलाव की ज़रूरत दी, अफगानिस्तान का संकट उसकी प्रबलतम अभिव्यक्ति है। सोवियत संघ, जिसकी परम्परागत प्रभाव क्षेत्र में पर हस्तक्षेप की क्षमता नहीं थी, का एक नई क्षमता की दक्षिण के रूप में अभ्युदय देखने को मिला। अमेरिका, जिसकी प्रच्छन्न शक्ति में हस्तक्षेप की एक परम्परा रही थी आज एक भू-दृष्टि की सी स्थिति में था। हस्तक्षेप का प्रतिरोध सेला के बहिष्कार से अधिक नहीं बन सका और उसमें भी निराशा ही हाथ लगी। स्वयं पश्चिमी गुट के राष्ट्रों में किसी उग्र कार्यवाही किये जाने की संभावना में मतभेद नहीं रहा। तृतीय राष्ट्रों की असहमति भी अपरिभाषित रूप से ही व्यक्त हुई, जो कि विगत में अमेरिका द्वारा किये गए हस्तक्षेप की निरन्तर तीव्र भर्त्सना की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न स्थिति थी। यह परिवर्तित परिदृश्य एक भावी प्रवृत्ति का परिचायक है।

चीन का आंतरिक मथन

माओत्से-तुंग के निधन के बाद चीन में आंतरिक बदलाव की स्थितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गईं। एक लंबे समय तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक संघर्ष इतना अधिक बदलाव वाला रहा कि उसके आधार पर कोई दूरगामी प्रवृत्ति रेखांकित करना एक असंभव सा कार्य था। लेकिन पार्टी की 11वीं कांग्रेस से उग्रवादी तत्त्वों का प्रभुत्व कम होता जान पड़ रहा था। माओ की पत्नी के नेतृत्व में बहुचर्चित 'घोड़ों और डोंगहसियाओं' पिंग, उग्रवादी और उदारवादी वंचारिकता के दो प्रतिनिधि बिंदु थे। 11वीं कांग्रेस के बाद उदारवादी मायता की स्थापना हुई लेकिन डोंग के नेतृत्व स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाया। अंतिम रूप में डोंग के नेतृत्व की स्थापना 1980 में हुई जब हुआ कुओ फेंग के त्यागपत्र के बाद शाओ जियांग पदासीन हुए। इस पूरी प्रक्रिया में विशेष नीति के स्तर पर, तमाम सवालों समाप्त हुए। माओ की मृत्यु के बाद रूस और चीन में जो एक सीमित समय के लिए निकटता की संभावना जागी थी, उस पर स्पष्ट विराम लगा। चीन की नीति तीव्र आंतरिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पश्चिमी राष्ट्रों और विशेषतः अमेरिका के ओर अधिक निकट आई। अप्रैल, 1980 में चीन की विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करना इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पूर्व ही अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध तेजी से स्थापित हुए और पश्चिमी पूंजी का निवेश चीन में बड़े पैमाने पर होने लगा। राजनयिक व्यवहार के स्तर पर

भी रूस और चीन के बीच वैमनस्य भी स्पष्ट रूप से बना रहा। लेकिन यह राज नीतिक समझ चीन को और अधिक मित्र विहीन बना गई। वियतनाम का रुझान निरंतर सोवियत संघ की ओर बढ़ा। फरवरी, 1979 में चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण एक ऐतिहासिक विदम्वना बन गई। कपुचियाई संकट, में चीन द्वारा पाल पाट नेतृत्व का समयन उसकी वैचारिक विवृति का एक और स्पष्ट दृष्टिकोण बना। इस पूरी प्रक्रिया में, चीन द्वारा प्रारंभ से ही एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव रहा, जिसके फलस्वरूप उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर और प्रश्न चिह्न लगे। जून, 1981 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चेंबरमेन के पद पर हुआओ बेंग के पदासीन होने से डेंगह्सियाओ पिंग की उदारवादी नीति की स्थापना की एक और स्पष्ट पुष्टि हुई। ऐसी स्थिति को देखते हुए यदाकदा के कुछ बचनव्यो के बावजूद भी रूस चीन संबंधों में बदलाव की स्थिति की कोई प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने उभरते हुए त्रिकोणात्मक समीकरण को भविष्य में और अधिक स्थायित्व मिलने की ही प्रबल संभावना है। जिसके फलस्वरूप एक ओर चीन का विश्व अय-व्यवस्था से अंतरण रूप से जुड़ने की निश्चित संभावना है और दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप, तृतीय विश्व में उसके साथक योगदान में कमी भी उत्तनी ही सुनिश्चित है।

पोलेण्ड का आंतरिक संकट

पोलेण्ड का आंतरिक संकट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विनोद महत्व का बन गया है। इस आंतरिक घटनाचक्र के कुछ महत्वपूर्ण अभिप्राय हैं। प्रथम समाजवादी व्यवस्था और विचारधारा के कुछ सद्धातिक पक्ष पोलेण्ड की स्थिति से जुड़े हुए हैं। क्या समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत पार्टी से स्वतंत्र ट्रेड यूनियन का आयोजन संभव है? क्या इस प्रकार का आयोजन राजनीतिक व्यवस्था में एक समानांतर जोर स्वतंत्र केन्द्र बन सकता है? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनके सुलझाने के स्वरूप से अय समाजवादी राष्ट्रों में भी व्यवस्थागत अभिप्राय जुड़े हैं। द्वितीय ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, सोवियत संघ का क्या दृष्टिकोण हो और इस संबंध में उसकी क्या रणनीति हो, एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तृतीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनीपचारिक रूप से रूस के प्रभाव क्षेत्र के रूप में मान्यता दिये गये पूर्वी यूरोप में, पश्चिमी प्रतिस्पर्धा का स्वरूप क्या हो। विगत में पश्चिमी राष्ट्रों के दृष्टिकोण में बदलाव कितना संभावित, व्यावहारिक और वांछित है इसका निगम एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। इन विभिन्न पहलुओं को देखते हुए पोलेण्ड के आंतरिक संकट की न सिर्फ तात्कालिक बेद्वयता है अपितु, इसके दूरगामी अभिप्राय भी हैं जो अधिक दिशा निर्देशक हैं।

विश्व युद्ध के बाद जिन पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों में समाजवादी नेतृत्व की

स्थापना हुई उसमें वहाँ की वामपंथी शक्तियों के अलावा सोवियत सैनिक भूमिका का भी अत्यधिक योगदान था। सभी पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों में आर्थिक और सामाजिक शक्तियों के विकास का स्तर और वामपंथी नेतृत्व की क्षमता का स्तर एक जैसा नहीं था। अतः इन असमान रूप से विकसित स्थितियों में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के राय में और अधिक सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। सोवियत निर्देशन के बाद भी विभिन्न नेतृत्वों द्वारा अलग-अलग स्थितियों में ऐसी व्यवस्था के निर्माण की रणनीति तैयार की। स्वाभाविक था कि ऐसी स्थिति में अनेकों अपवाद भी उभरते। युगोस्लाविया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के अनुभव ऐसे अपवादों के साक्षी हैं। इस वृद्धि का नवीनतम उदाहरण पोलैण्ड का आंतरिक संकट है। पोलैण्ड के वामपंथी नेतृत्व ने समाजवादी व्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने में ज़रूरत से अधिक सतकता बरती जो कि उसकी उदारवादी समझ की भी परिचायक रही। कृपि पर अधिक ध्यान केंद्रित रहा। यही नहीं, कृपि के क्षेत्र में भी मामूलीकरण की प्रक्रिया को आवश्यक रूप में लागू नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप कृपि में मझले स्तर के निजी स्वार्थों की स्थापना संभव हो गई। इसके समानांतर औद्योगीकरण पर ममुचित बल न दिया जाने के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की नियम प्रणाली में महत्व में कमी आई। इस प्रक्रिया के द्वारा उत्तरोत्तर मजदूर वर्ग में असंतोष की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, और उन्हें यह आभास होने लगा कि उनके और कृपि में कार्यरत वर्गों के साथ में निरंतर असमानता पनप रही है।

स्थिति ने एक गंभीर मोड़ लिया, जबकि लैस वैंलेसा के नेतृत्व में सोलिडे रिटी 'नामक एक स्वतंत्र 'ट्रेड यूनियन' का आयोजन हुआ। इस प्रक्रिया के प्रारंभ से ही पोलैण्ड में एक उग्ररूपी राजनीतिक और वैचारिक विवाद व्याप्त हो गया। वामपंथी नेतृत्व द्वारा प्रारंभ में समझौतावादी नीति अपनाई गई, जो कि उसके लिए और अधिक घातक सिद्ध हुई। अगस्त 1980 में समाजवादी व्यवस्था होते हुए भी हड़ताल के अधिकार की मांग स्वीकार कर ली गई। इसके बाद स्थिति में सुधार की बजाय और अधिक अव्यवस्था फैली। वामपंथी पार्टी में भी नेतृत्व परिवर्तन की एक सीमित प्रक्रिया देखी गई। अनेक तथ्य उपचार सफल नहीं हो सके, क्योंकि स्वतंत्र 'ट्रेड यूनियन' ने अब अपने आपको एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति के केंद्र के रूप में और पार्टी के अंदर ही एक घटक के रूप में आयोजित करने के प्रयास किये। पार्टी संगठन में भी अनेक स्तर पर भ्रष्टाचार-व्याप्त था, अतः इन घटनाओं से निपटने की उसकी क्षमता निरंतर अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। ऐसी स्थिति में अतः 13 दिसंबर, 1981 को 'माशल लॉ' लागू किये जाने की घोषणा की गई। इसके बाद उत्तरोत्तर स्थितियों में अराजकता पर नियंत्रण पाने पर सफलता मिली है। प्रारंभिक रूप से लगाये गये अनेक प्रतिबंधों में से कुछ पूर्ण

रूप से हटा लिये गये हैं और अंग्र छूटें दी गई है। साथ ही साथ वामपंथी पार्टी में भी भ्रष्टाचार के उन्मूलन के कारणर वदम उठाये गये हैं और अनेक स्तरों पर नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन भी किये गये हैं। जहां तक लैंस बैनेता और "सोलिडेरिटी" का प्रश्न है, उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समाजवादी व्यवस्था के मूल प्रारूप में रहते हुए ही उनकी स्वतंत्रता की कोई मांग सकारात्मक स्वरूप में सकती है अन्यथा नहीं। स्वतंत्र ट्रेड यूनियन का तात्पर्य वदोपि यह संभव नहीं है कि वह पार्टी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण से मुक्त हो और अपनी चेतना का स्तर समाजवादी वैचारिकता से न जोड़कर तात्कालिक आर्थिक सुविधावाद से ही जोड़े।

पोलेण्ड के घटनाक्रम से कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं। प्रथम तो यह कि समाजवाद की वैचारिक भावनाओं में विभिन्न वर्गों व स्वतंत्र संगठनात्मक आयोजन का औचित्य संवत्सा वर्जित है। वर्गों के बीच असंतुलन की स्थिति हो सकती है, लेकिन उनका निवारण खुली प्रतिद्वंद्विता के माध्यम से न होकर एक समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से होना आवश्यक है। परस्पर असंतुलन की स्थितियों के वैचारिक अथवा व्यावहारिक पक्षों का मूल दायित्व वामपंथी पार्टी का है, और इसी मंच के द्वारा एक आंतरिक संघर्ष की प्रक्रिया से समस्त मतभेद सुलझने आवश्यक है। द्वितीय रूप से पोलेण्ड संकट में हुई सोवियत प्रतिक्रिया पूर्वी यूरोप के विगत के संकटों की प्रतिक्रियाओं से भिन्न है। पहले के सीधे हस्तक्षेप की नीति के विपरीत सोवियत प्रतिक्रिया अत्यधिक सतर्क रही और उसने परोक्ष हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। इस प्रकार का सोवियत व्यवहार दोहरे महत्त्व का है। एक ओर जहां यह पश्चिमी राष्ट्रों की हस्तक्षेप की आशंका और प्रचार को ध्वस्त करता है, वहीं दूसरी ओर यह सोवियत संघ में एक आत्मविश्वास की भावना का भी परिचय देता है। पूर्वी यूरोप का सामरिक महत्त्व आज भी सोवियत संघ के लिए असादिग्न प्राथमिकता का है। अतः यह कहना गलत होगा कि इस प्रकार का सोवियत व्यवहार उसकी सामरिक प्राथमिकताओं में वदस्ताव का परिचायक है। वास्तव में सोवियत नीति आज इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि बिना सीधे हस्तक्षेप के भी पूर्वी यूरोप में वह अपनी भावना को लागू करवा सकती है। हा यदि भविष्य में कभी इस आत्मविश्वास में कमी आई तो सीधे, हस्तक्षेप की निस्संदेह भविष्यवाणी की जा सकती है। एक अन्य पक्ष इस संकट की घटनाओं से परिलक्षित होता है। पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध, रोगन की तथाकथित उग्रवादिता के बावजूद, प्रचार की सीमाओं से अधिक नहीं बढ़ सका। यह प्रचार भी रूसी हस्तक्षेप की आशंकाओं पर आधारित रहा अतः इसमें भी कोई ठोस तत्वों का समावेश नहीं हो सका। वाटर प्रशासन से ही अमेरिकी नीति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव-अधिकारों के प्रश्न की

बात रखी, जिसका परोक्ष किंतु प्रमुख उद्देश्य रूस के हस्तक्षेप के विरोध में प्रचार करना था। इस नारे को कम्बोडिया के सकट के बाद पोलेण्ड की स्थिति में भी व्यक्त किया गया। लेकिन अनेक स्थितियाँ में स्वयं अमेरिका द्वारा तानाशाही व्यवस्थाओं का समर्थन, विशेष उल्लेखनीय रूप से उसका एवं पश्चिमी राष्ट्रों का दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का समर्थन, कुछ ऐसे खुले तथ्य थे जो कि अमेरिका के इस मानव अधिकार प्रेम पर प्रश्नचिह्न लगाते रहे। यस्तुतः इस प्रचार का कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव नहीं देखा जा सका। जहाँ तक प्रचार से बढ़कर कोई कारगर कदम उठाये जाने की बात थी, स्वयं पश्चिमी राष्ट्रों में परस्पर मतभेद और स्पष्ट द्वेष। सम्भावित सोवियत हस्तक्षेप की स्थिति में किसी सामूहिक सैनिक कार्रवाही का प्रश्न तो दूर, आर्थिक प्रतिबन्धों के स्तर पर भी अमेरिका द्वारा प्रस्तावित उपचारों पर पश्चिमी राष्ट्रों में मतभेद सम्भव नहीं हो पाया। सीमित स्तर के आर्थिक प्रतिबन्धों की कार्रवाही तो देखी गई लेकिन न तो उसका तात्कालिक स्वरूप ही विस्तृत था और न ही उसमें किसी दूरगामी प्रतिबद्धता का समावेश। अतः एक बार फिर पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को पश्चिम की असहायता या भ्रम मिली।

पश्चिमी एशिया में प्रलय

पश्चिमी एशिया का समसामयिक घटनाचक्र एक बार फिर इस क्षेत्र में विस्फोटक स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है। ईरान और ईराक के बीच युद्ध की स्थिति, इजरायल का गोलान पहाड़ियों पर अतिक्रमण और हाल ही में इजरायल द्वारा फिलस्तीन मुक्ति संगठन को जद्दाभूल समाप्त करने के प्रयास, पश्चिमी एशिया में प्रलयकारी स्थितियों की शृंखला के प्रमुख उदाहरण हैं। सितंबर, 1980 में ईरान और ईराक के बीच एक सीमित युद्ध की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, जो कि तात्कालिक रूप से सीमा विवाद से संबंधित थी। इसके अलावा ईराक द्वारा ईरान में बदलाव चाहने वाली प्रवृत्ति के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग तथा अन्य परम्परागत मतभेद इस युद्ध की पृष्ठभूमि में समाहित हैं। इस्लामी क्रांति के बाद वैचारिक असहिष्णुता का भी इसमें योगदान कहा गया है। कुछ मायताओं के अनुसार दोनों राष्ट्रों के लिए इस युद्ध की उपादेयता आंतरिक संकटों से ध्यान विचलित करने की नीति में भी देखी गई है। इस युद्ध की प्रक्रिया में ईराक की उत्तरोत्तर असफलता का एक क्रम रहा है, यद्यपि साथ ही साथ ईराक ने अनेक अवसरों पर समझौते का प्रारूप प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। अभी तक ईराक की यह मायता थी कि कोई समझौते का प्रारूप युद्ध की समाप्ति के लिए पूरा शर्त हो और फिर युद्ध की समाप्ति की जावे। लेकिन निम्नलिखित कारणों ने ईराक की वामपंथी 'बाघ' पार्टी से भी एक आंतरिक विवाद उत्पन्न किया।

उत्पन्न कर दिया। हास ही में जून, 1982 में सद्दाम हुसैन की नीतियाँ की कठोर आंतरिक आलोचना हुई। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इजरायल द्वारा लेबनान पर किये गये आक्रमण के सदम में, ईराक ने अरब एक्जूटता का आभास दिया और समझौते को शत बनाय बिना एक पक्षीय रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा की। इन तात्कालिक नये प्रयासों के फलस्वरूप ईरान और ईराक में किसी समझौते की संभावना प्रबल बन गई है और साथ ही साथ ईराक में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता।

मिश्र इजरायल अमेरिका घुरी के बनने के बाद पश्चिमी एशिया में कुछ नई प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हुई हैं। एक ओर अपनी इन नीतियों के फलस्वरूप मिश्र अरब समुदाय में बहुमुखी आलोचना का केन्द्र बना है। यह प्रक्रिया कैम्प डेविड के समझौते से स्पष्ट उभरी। दूसरी ओर इस समीकरण के बनने के बाद इजरायल की नीति और अधिक उग्र और खतरनाक हुई हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उत्तरोत्तर यह संभावना बनने लगी है कि पश्चिमी एशिया में यह त्रिकोणात्मक समीकरण अधिक दिनों तक क्रियाशील नहीं रह पायगा। इस सदम में नेतृत्व परिवर्तन की घटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित रहा है। राष्ट्रपति अनवर सादात की 6 अक्टूबर, 1981 को आकस्मिक हत्या हुई, जिसके बाद 14 अक्टूबर, 1981 को हुसेनी सुबारक ने राष्ट्रपति पद संभाला। नये नेतृत्व की घोषणाओं में यद्यपि सादात की नीतियों के ही दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही गई है, फिर भी कुछ एक वक्तव्य सशय पैदा करते हैं ऐसी किसी प्रवृत्ति के भावी विकास में इजरायली उग्रवाद की कुछ तात्कालिक घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। पश्चिमी एशिया में इजराईली विस्तारवाद का अत्यधिक दुराग्रही कदम गोलान पहाड़ियों में लिया गया। दिसंबर 1981 में इजरायल द्वारा गोलान पहाड़ियों का अतिक्रमण हुआ। ऐसे खुले अतिक्रमण के समक्ष परंपरागत मिश्र अमेरिका के लिए इजरायल का समर्थन करना संभव नहीं हुआ। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजरायल को स्पष्ट चेतावनी मिली और अमेरिका ने भी अस्पष्ट और परोक्ष तरीके से इजरायल की नीतियों में नियंत्रण लाने का प्रयास किया। इन विभिन्न चेतावनियों का, ऐसा प्रतीत होता है कि, इजरायल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जून, 1982 में इजरायल द्वारा फिलस्तीन मुक्ति संगठन को जघामूल खरम करने और नेस्तेनाबूद करने की मुहिम अपने आप में सबसे विचित्र अपराधिक प्रवृत्ति की परिचायक है। यह सही है कि 'पी० एल० ओ०' द्वारा रोरिल्ला युद्ध की वारदातें होती रही हैं, लेकिन साथ ही साथ फिलस्तीन के मुक्त के प्रश्न का औचित्य और भी अधिक सही है। ऐसी स्थिति में जबकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा फिलस्तीन की स्वतंत्रता के प्रति सक्रिय समर्थन किया गया है, इजरायल की आतंकवादी कायवाही पी० एल० ओ०, सीरिया और लेबनान के विरुद्ध ही नहीं है अपितु पूरे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय

के विरुद्ध भी है।

पश्चिमी एशिया के तात्कालिक घटनाचक्र से कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ उभरती हैं। प्रथम, ईरान-ईराक विवाद में महाशक्तियों की तटस्थता अपने आपमें एक विचित्र और अमूल्य स्थिति है। जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है, उसके लिए यह एक खोपी गई स्थिति है, क्योंकि विवाद से संबंधित दोनों ही पक्ष उसके प्रतिरोधी हैं। सोवियत नीति के सदर्भ में इस तटस्थता का एक विशेष अर्थ है। ईरान के साथ उसके मैत्री संबंध ही नहीं अपितु बिरादराना संबंध भी है। ईरान की अमेरिका विरोधी स्थिति को देखते हुए सोवियत नीति किसी भी स्थिति में उस विरोध में शिथिलता नहीं देखना चाहता। ऐसी स्थिति में जबकि सोवियत संघ की यह मायता है कि ईरान-ईराक विवाद में न सुलझन वाला कोई मूलभूत संकट नहीं है, उसका इस विवाद के प्रति निरपेक्षता पश्चिमी एशिया सदर्भ में महत्वपूर्ण है। यही नहीं, रूस ने अपने प्रभाव के द्वारा ईराक के नेतृत्व को भी मैत्री की ओर प्रेरित किया है। तात्कालिक घटनाओं से इस प्रयास की सफलता भी देखने को मिलती है। द्वितीय प्रवृत्ति, अपने पश्चिमी एशियाई प्रभाव क्षेत्र में अमेरिका की क्षमता की सीमाएँ दर्शाती है। अमेरिकी नीति को स्पष्ट है कि इजरायल का उग्र विस्तारवाद स्वयं उसके हितों के लिए दूरगामी रूप से अत्यधिक विपरीत है। लेकिन इस दृष्टिकोण के होते हुए भी अमेरिका किसी निश्चित रूप में इजरायली दृष्टिकोण को नियंत्रित करने में असफल रहा है। इजरायल के तात्कालिक आक्रमण की घटनाओं के अलावा, इस असफलता के अभिप्राय भविष्य में मिश्र और अमेरिका संबंधों पर भी हो सकते हैं। यदि अमेरिका मिश्र को इजरायल की भावी नीतियों के प्रति आश्वस्त करने में असफल रहता है, तो इजरायल मिश्र संबंधों में सामायीकरण की प्रक्रिया में उभरे सदेहों को दखते हुए भविष्य में मिश्र अमेरिका इजरायल के समीकरण को भी विघटन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति का स्पष्ट लाभ सोवियत नीति को मिलेगा, इसमें सदेह नहीं। एक अन्य प्रवृत्ति पश्चिम एशिया में सोवियत प्रभाव की साक्ष्यता को अधिक दर्शाती है। इजरायल द्वारा और लेबनान पर आक्रमण किये जाने के बाद, जिसके भावी परिणाम सीरिया पर भी हुए इजरायल ने युद्ध विराम के अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को लागू नहीं किया। अतः सोवियत संघ को यह खुली चेतावनी देनी पड़ी कि 10 अक्टूबर, 1980 को हुए सोवियत सीरिया मैत्री समझौते के अंतर्गत प्रावधान के आधार पर, यदि इजरायल द्वारा युद्ध विराम नहीं किया जाता है तो सोवियत संघ खुले हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति को बचाने के लिए सोवियत संघ ने अमेरिका से यह अनुरोध किया कि वह इजरायल को युद्ध विराम लागू करने हेतु बाध्य करें। इसी के बाद युद्ध-विराम संभव हो सका। इस दृष्टि से सोवियत प्रभाव की एक और भावी सफलता हो सकती

इजराईल के विस्तारवाद व विरोध में समस्त अरब राष्ट्रा की एकजूटता का सोवियत प्रस्ताव शीघ्र ही प्रचलित हो गया है। भविष्य में इस विचार के ध्वजारोहण एवं ठोस स्वरूप के उभरने की प्रबल संभावना है। इस घटना चक्र की अंतिम प्रवृत्ति पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चिंता का विषय है। सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव की न सिर्फ खुसी अवहलना इजरायल द्वारा की गई अपितु साथ ही साथ ऐसे कदम भी उठाये गये जिन्होंने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बनाया। इन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में उल्लेखनीय है कि अमेरिका की भी परोक्ष सहमति थी। ऐसी स्थिति में इजराईल की प्रवृत्ति न सिर्फ पश्चिमी एशिया की राजनीति पर बल्कि साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की साधकता पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नचिह्न लगा गई।

शिक्षा-बोध एक सिंहावलोकन

पिछले 35 वर्षों से अधिक के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में बदलाव की एक मोन और अतर्निहित प्रवृत्ति समाहित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी किसी विश्वव्यापी विभीषिका की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई, लेकिन ऐतिहासिक बदलाव की प्रक्रिया क्रमिक रूप से विकसित होती रही। इस क्रमिक विकास में प्रेरक शक्तियों के रूप में अनेक आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक द्वंद्व उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और विशेषतः महाशक्तियों के परस्पर संबंधों के सदन में शक्ति के समीकरण में अनेक बदलाव हुए। ऐसे बदलाव की क्रमिक अभिव्यक्तियों का स्वरूप सामान्यतः उग्र और विस्फोटक नहीं था। सीमित युद्ध और सीधी टकराव तो देखी गई लेकिन इनमें पूरे विश्व को समाहित कर लेने का प्रारूप नहीं था। इस क्रमिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों और भावी दिशा-बोध के आधारों को निम्न रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

1 द्वितीय विश्वयुद्ध की उत्तरोत्तर स्थिति एक गुणात्मक परिवर्तन की द्योतक थी। दो विश्व युद्धों के बीच शक्ति के विन्दोद्गीकरण की स्थिति, अब एक स्पष्ट ध्रुवीकरण के रूप में स्थापित हुई। अत्यधिक महत्वपूर्ण और दूरगामी अभिप्रायों के सदन में, पहले की तुलना में यह ध्रुवीकरण सवपक्षीय था—आर्थिक, राजनीतिक एवं वैचारिक तत्वों के समावेश के फलस्वरूप। अब ध्रुवीकृत प्रतिद्वंद्विता शक्ति के समीकरण के स्तर पर ही नहीं थी अपितु व्यवस्थागत बन गई थी।

2 उपनिवेशवाद के अवसान की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रतिद्वंद्विता का उद्देश्य भौगोलिक आधिपत्य नहीं रहा। अब प्रतिस्पर्धा प्रभाव क्षेत्रों की बन गई। इस गुणात्मक बदलाव के महत्वपूर्ण अभिप्राय थे। विदेश नीति संचालन और उद्देश्य प्राप्ति में युद्ध की साधकता कम हुई। नये उपकरणों और माध्यमों की रणनीति तैयार हुई, जिसमें तात्कालिक सतुलन को एक स्थायित्व प्रदान करना

एक प्राथमिक अवश्यकता बन गई। सैनिक एवं आर्थिक गठबन्धनों का आयोजन, सैनिक और आर्थिक मदद का राजनय, और शस्त्रों की होड़ द्वारा महा-शक्तियुक्त क्षमता में दूरगामी सतुलन की स्थापना, इस नई नीति के प्रमुख दायित्व बन गये। प्रारम्भिक चरण में, इन्हीं दायित्वों के सशयपूर्ण वातावरण के निर्वाह ने 'शीत युद्ध' की मानसिकता और वास्तविक अभिव्यक्तियों को जन्म दिया।

3 आणविक शक्ति के महाशक्तियुक्त ने विश्व में वस्तुतः भय के सतुलन की स्थापना की। सोवियत संघ की मानसिकता में एक आत्मविश्वास और वैचारिक परिपक्वता का समावेश हुआ और इसके समानांतर अमेरिका को अपनी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप की निरंतर असफलता का आभास भी। साम्राज्यवादी व्यवस्था एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्तरोत्तर क्षीण हो रही थी। तृतीय राष्ट्रों में राजनीतिक स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता के स्वर को भी जन्म दिया। ऐसी स्थिति में अनावश्यक हस्तक्षेप और सीधी सैनिक संलग्नता की नीति तात्कालिक और दूरगामी, दोनों ही स्तरों पर अत्यधिक आत्मघातक थी। इन विभिन्न ऐतिहासिक आवश्यकताओं ने 'देतात' के दृष्टिकोण का सूत्र पाल लिया। ऐसा बदलाव आकस्मिक नहीं था, और न ही इसकी क्रिया बस तात्कालिक रूप से स्पष्ट संभावना थी। अतः इस पूरी बदलाव की मानसिकता में एक संक्रमणकाल का भी समावेश हुआ।

4 'देतात' के स्थायित्व की प्रक्रिया के समांतर, ध्रुवीय गुटों की आंतरिक एकजुटता में भी गुणात्मक परिवर्तन के आधार उभरे। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद भी पैदा हुए, जिसके फलस्वरूप अमेरिका के एकछत्रीय नेतृत्व को स्पष्ट चुनौती मिली। सामूहिक सैनिक अथवा आर्थिक कार्यवाही में यूरोपीय राष्ट्रों ने सक्रिय भूमिका निभाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। रूस-चीन विवाद के फलस्वरूप समाजवादी राष्ट्रों की एकजुटता पर भी प्रश्न चिह्न लगा। चीन के शक्ति के स्वतंत्र केन्द्रक रूप में उदय ने एक नया त्रिकोणात्मक समीकरण को जन्म दिया। जहाँ तक अन्य समाजवादी राष्ट्रों का प्रश्न था, स्वेच्छा अथवा आर्थिक एवं सैनिक प्रभुत्व के फलस्वरूप सोवियत संघ का व्यवस्थापक बना रहा। चीन द्वारा उत्तरोत्तर रूप से पश्चिमी राष्ट्रों के समर्थन, और प्रमुख शत्रु के रूप में सोवियत संघ के अनौचित्यपूर्ण विरोध के फलस्वरूप तृतीय राष्ट्रों के बीच उसकी साख में निरंतर गिरावट आई। इसके विपरीत एक व्यावहारिक सतुलन और दूरगामी परिप्रेक्ष्य के फलस्वरूप तृतीय राष्ट्रों में सोवियत संघ के प्रति प्रतिबद्धता में निरंतर वृद्धि हुई। इस प्रभाव के विस्तार ने सोवियत संघ के लिए चीन विवाद से हुई हानि, की पर्याप्त पूर्ति की। अतः त्रिकोणात्मक समीकरण के उभरने के बावजूद तुलनात्मक रूप से सोवियत प्रभाव में कोई गंभीर कमी नहीं आई।

5 इन बदली हुई परिस्थितियों में महाशक्तियों की भूमिका में बदलाव के कास का सूत्रपात हुआ। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के लिए वियतनाम अथवा कोरिया जैसे अनुभवों की पुनरावृत्ति अपरिहार्य बन गई, जिसकी चरम अभिव्यक्ति ईरान द्वारा दी गई खुली चुनौती में हुई। इसके विपरीत सोवियत अनुभवों में अगोला स लेकर अफगानिस्तान तक के नवीन अनुभव समाहित हुए। इस पूरी प्रक्रिया में पश्चिमी प्रतिरोध स्वरूप प्रचार और सीमित सामूहिक वायवाही से अधिक नहीं बढ़ सका। वस्तुतः, भूमिकाओं का यह बदलाव असंदिग्ध रूप से गुणात्मक है।

6 साम्राज्यवादी व्यवस्था में उपनिवेशी आधिपत्य पर मात्र अंतिम विराम क्षेप है—दक्षिणी अफ्रिका में रंग भेदी व्यवस्था। स्वयं इतिहास इस दायित्व का निर्वाह करेगा। सैनिक गठबंधनों की साम्राज्यवादी रणनीति पूर्ण विघटन के बगार पर है। परोक्ष हस्तक्षेप के प्रतिरोध में उभरते राष्ट्रीय एक जन आंदोलन हैं। साम्राज्यवाद के अन्त में व्यवस्थागत बदलाव और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आधिक्य व्यवस्था की मांग साम्राज्यवाद पर अंतिम और अपरिवर्तनीय कूटाराघात है। लेनिन का इतिहास बोध आज की वास्तविकता है—‘वस्तुतः साम्राज्यवाद पूँजीवाद के विकास की चरम सीमा है।’ इसके बाद मात्र अवसान की एक लंबी और दुरूह प्रक्रिया क्षेप है। सोवियत संघ का नेतृत्व भले ही संदिग्ध हो, वैचारिक और व्यवस्थागत आधार पर विश्वस्तरीय ध्रुवीकरण एक ऐतिहासिक निश्चितता है। वर्तमान में, सोवियत संघ का नेतृत्व ही इसका प्रतीक है, यद्यपि इस प्रक्रिया में अन्य भावी स्वरूप भी निहित हो सकते हैं।

7 इन ऐतिहासिक सदर्भों में “नव शीत युद्ध” दूरगामी परिप्रेक्ष्य के अभाव से उत्पन्न एक तात्कालिक भ्रम है। 1982 की ऐतिहासिकता 1945 के सदर्भों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। इतिहास की पुनरावृत्ति असंभव है; यदि ऐसा प्रयास हो तो इसकी परिणति, प्रथम बार दुःखांतिका में और दूसरी बार प्रहसन में होती है। विश्व दोनों का ही अनुभवी है। अतः भविष्य के गम में नव शीत युद्ध नहीं, अपितु बहुरंग वैचारिक युद्ध समाहित है।

महाशक्ति समीकरण और चीन । विश्व राजनीति का त्रिकोण

एक ऐतिहासिक तथ्य को विभिन्न विश्लेषणात्मक अभिप्राय दिए जा सकते हैं। ऐसा निरंतर होता भी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की स्वतंत्र भूमिका का विश्लेषण, इस प्रवृत्ति का स्पष्टतम उदाहरण है। 1949 में साम्यवादी चीन का अभ्युदय ही नहीं अपितु कालांतर में उभरा सोवियत चीन विवाद भी, मूलभूत ऐतिहासिक महत्व का परिचायक है। प्रथम घटना ने जहाँ एक ओर जनवादी विचारधारा को अप्रतिम विस्तार दिया वहीं दूसरी न बेचारिक विवाद के नये आयाम उत्पन्न किये। सभी विश्लेषण इन ऐतिहासिक स्थितियों के महत्व के प्रति एक मन हैं, लेकिन इनके अभिप्रायों के प्रति उग्र रूप से विवाद प्रस्त। कुछ अतिउत्साही बुद्धिजीवी, विचारधारा की निरर्थक की घोषणा करते हुए व्यापारिक भी हो उठते हैं। साथ ही साथ, उदासीन दार्शनिकता से प्रेरित कुछ अन्य हितों की सर्वोपरिता के 'शाश्वत सत्य' को अभिव्यक्त करते हैं। साम्राज्यवाद अथवा समाजवाद में गुणात्मक विभेद, ऐसे विश्लेषण की दृष्टि में मात्र औपचारिक तथ्य हैं। अतः विश्लेषण की दृष्टि से अनावश्यक भी।

उपरोक्त मानसिकतायें, एक सही दृष्टिकोण को असंभव बनाती हैं। क्या विचारधारा का निर्माण सदमों की शून्यता में होता है? क्या सदमों का आधिक सामाजिक व्यवस्थागत स्वरूप नहीं होता है? क्या हित इन व्यवस्थागत अभिप्रायों से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं? क्या राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंधों का अस्तित्व इन आंतरिक व्यवस्था की आवश्यकताओं से स्वतंत्र रह सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। न तो विचारधारा ही शून्यता में पनपती है, और न ही आधिक सामाजिक सदमों का स्वरूप व्यवस्थागत अभिप्रायों से स्वतंत्र। राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंधों का स्वरूप निस्मदेह आंतरिक व्यवस्था के अभिप्रायों से जुड़कर ही बनता है, जिसमें तात्कालिक हित अथवा अहित की व्याख्या भी समाहित होती है। अतः विश्लेषण के इन विभिन्न परस्पर पक्षों को एक दूसरे से

जोड़कर ही सही विश्लेषण मभव है। ऐसा विद्वानशुणात्मक दृष्टिकोण विशेषतः समाजवादी राष्ट्रों के परराष्ट्र सम्बन्धों को समझने के लिए और अधिक अपरिहाय है क्योंकि, इन राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत वैचारिक समझ वस्तुतः इन विभिन्न अभिप्रायों का समन्वित स्वरूप अभिव्यक्त करती है। विवाद इस बात का हो सकता है कि किसी विशेष स्थिति में चीन अथवा सोवियत संध की वैचारिक समझ गतन रही हो। लेकिन जैसी भी वैचारिक समझ रही उससे ही अनुरूप परराष्ट्र सम्बन्धों का निर्धारण हुआ और व्यावहारिक जिया बति भी। इस सध्य में अपवाद प्रायः असम्भव है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साथ-साथ आंतरिक विकास का स्वरूप भी वैचारिक समझ से जुड़ा होता है। आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रिया, खुद, केन्द्रीय रूप से संचालित एवं निर्धारित होती है, अतः वैचारिक मयन और उससे उपजे राजनीतिक नियम निर्णायक महत्त्व के होते हैं। अतः वैचारिक समझ न सिर्फ आंतरिक विकास की प्राथमिकताओं का परिचय देती है, अपितु साथ ही साथ परराष्ट्र सम्बन्धों के विश्लेषण में आवश्यक कड़ी का भी प्रारूप दर्शाती है। इस दृष्टि से समाजवादी राष्ट्रों की आंतरिक एवं परस्पर वैचारिक विवादों की स्थितियाँ, सर्वपक्षीय आधारों की एक समुक्त अभिव्यक्ति को उभारती हैं। ऐसे ही सर्वपक्षीय विश्लेषण के दृष्टिकोण, और उसके अंतर्गत वैचारिक मयन की स्थितियों के विवेचन, के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय और सोवियत चीन विवाद, के अभिप्रायों को रेखांकित किया जा सकता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक गुणात्मक रूप से भिन्न ध्रुवीकरण का सूत्रपात हुआ। इसके विभिन्न अभिप्रायों की समीक्षा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस नये गुणात्मक ध्रुवीकरण का वैचारिक पक्ष 1949 में चीन की जनवादी क्रांति के बाद और अधिक प्रबल बन गया। विश्व में व्यवस्थागत प्रतिद्वंद्विता के स्तर पर, साम्राज्यवादी व्यवस्था ने आत्मरक्षा की दृष्टि से उग्रहस्तक्षेप की नीति अपनायी। वास्तविक क्षमता के स्तर पर, ससाधनों का सतुलन साम्राज्यवाद के पक्ष में था। अमेरिका का आणविक वचस्व इसका प्रतीक था। लेकिन, तीव्र आंतरिक विकास द्वारा सोवियत संध ने शीघ्र ही सतुलन की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके समानांतर, उपनिवेशवाद के अवसान की प्रक्रिया भी अपनी ऐतिहासिक गति से विकसित हुई। स्थितियों का सतुलन निरंतर बदल रहा था। साम्राज्यवाद ऐतिहासिक अवसान की ओर उन्मुख था। ऐसी स्थिति में सोवियत चीन विवाद ने विश्व राजनीति में एक नया पक्ष जोड़ दिया। महाशक्तिय सतुलन ने पारस्परिकता को जन्म दिया, तो साथ ही साथ एक उग्र वैचारिक विवाद का प्रारूप भी। दो प्रमुख समाजवादी राष्ट्रों का यह पारस्परिक विवाद निरंतर विकसित हुआ। अमेरिका और चीन का उभरता समीकरण, इस प्रक्रिया का एक नया मोड़ बन गया। महाशक्तिय ध्रुवीकरण के बीच, अमेरिका—चीन समीकरण से एक

त्रिकोण की स्थापना हुई। विद्वत् युद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अपरि-
भाषित अभिप्राय के विवाद में उत्पन्न गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इस नये पक्ष के विकास को हम तीन चरणों में
विभाजित कर सकते हैं। निम्न में से प्रत्येक चरण की गुणात्मक विनिष्ठता रही

(1) 1949 से 1959 प्रथम चरण ध्रुवीकृत विश्व की वैचारिकता।

(2) 1959 से 1969 द्वितीय चरण वैचारिक विवाद और महाशक्तियों
पारस्परिकता।

(3) 1969 से 1979 तृतीय चरण त्रिकोणात्मक समीकरण की गतिशीलता।

प्रत्येक चरण में विवेचन में चीन के बदलते दृष्टिकोण को रेखांकित करना
एक प्राथमिक और आवश्यक कार्य है। अन्य दो महाशक्तियों के सम्बन्ध की
प्रक्रिया की समीक्षा हम पहले ही कर चुके हैं। अतः चीन के दृष्टिकोण में बदलाव
की पथक रूप से रेखांकित करना होगा। चीन की नीति के विवेचन को तीन स्तरों
पर देखना होगा। प्रथम आन्तरिक वैचारिक मथन, द्वितीय, आन्तरिक विकास
के स्वरूप का विवाद एवं सन्दर्भों के बीच चीन की परराष्ट्र नीति इसी विश्व
दृष्टिकोण का व्यावहारिक पक्ष है। इस प्राथमिक विवेचन के बाद, प्रत्येक चरण
में चीन सावित सन्ध्या और चीन अमेरिका सम्बन्ध, के स्वरूप का पृथक् विवेचन
किया जायगा। अतः प्रत्येक चरण में इसी पक्ष के आधार पर समीक्षा के एक
विकास की प्रवृत्ति स्वतः स्पष्ट होगी।

प्रथम चरण 1949 से 1959 ध्रुवीकृत विश्व की वैचारिकता

1949 का वर्ष विश्व समाजवादी क्रान्तिशास्त्र का दृढ़ स्तम्भ था। चीन में
समाजवादी विचारधारा वाल नेतृत्व की विजय हुई। इस घटना ने, न सिर्फ सबसे बड़े जन-समुदाय के अस्तित्व की स्थापना की,
बल्कि समाजवादी विचारधारा की मात्रा दृढ़ करने के लिए अग्निकाष्ठों में भी
व्यावहारिक सिद्ध किया। निम्न दृष्टिकोण में। स्वतंत्रता के विचार-
धारा के प्रति कृपक वगैरे का निर्माण करने के लिए करना, चीन की कम्यु-
निस्ट पार्टी और माओ के निर्देशों के अन्तर्गत था। जापानी सामन्त
की स्थापना इस नयी प्रक्रिया का अन्तर्गत नहीं आया, मात्र प्रारम्भ था।
समाजवादी व्यवस्था के निर्माण का एक स्तर और दृढ़ कार्य, जापानी रे-
हामिक क्षमिष्व बन गया। समाजवादी विचार के नियमना उपसर्ग के रूप में
व्यावहारिक परिवर्तन था। मात्र सावित सन्ध्या के व्यावहारिक स्वरूप में
ये अथवा, कुछ भी अन्तर्गत नहीं। ऐसे ही मिश्रित वातावरण में
समाजवादी सरचना की नीति का विकास किया।

समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत का विकास, और

जोड़कर ही सही विश्लेषण संभव है। ऐसा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विशेषतः समाजवादी राष्ट्रों के परराष्ट्र सम्बंधों को समझने के लिए और अधिक अपरिहार्य है क्योंकि, इन राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत वैचारिक समझ वस्तुतः इन विभिन्न अभिप्रायों का समन्वित स्वरूप अभिव्यक्त करती है। विवाद इस बात का हो सकता है कि किसी विशेष स्थिति में चीन अथवा सोवियत संघ की वैचारिक समझ गलत रही हो। लेकिन जैसी भी वैचारिक समझ रही उसके ही अनुरूप परराष्ट्र सम्बंधों का निर्धारण हुआ और व्यावहारिक क्रिया बति भी। इस तथ्य में अपवाद प्रायः असंभव है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों ने साथ साथ, आंतरिक विकास का स्वरूप भी वैचारिक समझ से जुड़ा होता है। आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रिया, चूंकि, कठोर रूप से संचालित एवं निर्धारित होती है अतः वैचारिक मथन और उससे उपजे राजनीतिक नियम निर्णायक महत्व के होते हैं। अतः वैचारिक समझ न सिर्फ आंतरिक विकास की प्राथमिकताओं का परिचय देती है, अपितु साथ ही साथ परराष्ट्र सम्बंधों के विश्लेषण में आवश्यक कड़ी का भी प्रारूप दर्शाती है। इस दृष्टि से समाजवादी राष्ट्रों की आंतरिक एवं परस्पर वैचारिक विवादों की स्थितियाँ सवपक्षीय आधारों की एक संयुक्त अभिव्यक्ति को उभारती हैं। ऐसे ही सवपक्षीय विश्लेषण के दृष्टिकोण, और उसके अंतर्गत वैचारिक मथन की स्थितियों के विवेचन, के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अग्रगण्य और सोवियत चीन विवाद के अभिप्रायों को रेखांकित किया जा सकता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक गुणात्मक रूप से भिन्न ध्रुवीकरण का सूत्रपात हुआ। इसके विभिन्न अभिप्रायों की समीक्षा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस नये गुणात्मक ध्रुवीकरण का वैचारिक पक्ष 1949 में चीन की जनवादी क्रांति के बाद और अधिक प्रबल बन गया। विश्व में व्यवस्थागत प्रतिद्वंद्विता के स्तर पर, साम्राज्यवादी व्यवस्था ने आत्मरक्षा की दृष्टि से उग्रहस्तक्षेप की नीति अपनायी। वास्तविक क्षमता के स्तर पर संसाधनों का संतुलन साम्राज्यवाद के पक्ष में था। अमेरिका का आणविक दबदबा इसका प्रतीक था। लेकिन, तीव्र आंतरिक विकास द्वारा सोवियत संघ ने घीघ्र ही संतुलन की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके समानांतर, उपनिवेशवाद के अवसान की प्रक्रिया भी अपनी ऐतिहासिक गति में विकसित हुई। स्थितियों का संतुलन निरंतर बदल रहा था। साम्राज्यवाद ऐतिहासिक अवसान की ओर उन्मुख था। ऐसी स्थिति में सोवियत चीन विवाद ने विश्व राजनीति में एक नया पक्ष जोड़ दिया। महाशक्ति संतुलन ने पारस्परिकता को जन्म दिया, तो साथ ही साथ एक उग्र वैचारिक विवाद का प्रारूप भी। दो प्रमुख समाजवादी राष्ट्रों का यह पारस्परिक विवाद निरंतर विकसित हुआ। अमेरिका और चीन का उभरता समीकरण, इस प्रक्रिया का एक नया मोड़ बन गया। महाशक्ति ध्रुवीकरण के बीच, अमेरिका—चीन समीकरण से एक

त्रिकोण की स्थापना हुई। विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपरि-
भाषित अभिप्रायो के विवाद में उत्पन्न गयी।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस नये पक्ष के विकास को हम तीन चरणों में
विभाजित कर सकते हैं। निम्न में से प्रत्येक चरण की गुणात्मक विशिष्टता रही

(1) 1949 से 1959 प्रथम चरण ध्रुवीकृत विश्व की वैचारिकता।

(2) 1959 से 1969 द्वितीय चरण वैचारिक विवाद और महाशक्तियों
पारस्परिकता।

(3) 1969 से 1979 तृतीय चरण त्रिकोणात्मक समीकरण की गतिशीलता।

प्रत्येक चरण के विवेचन में चीन के बदलते दृष्टिकोण को रेखांकित करना
एक प्राथमिक और आवश्यक कार्य है। अतः दो महाशक्तियों के सम्बन्ध की
प्रक्रिया की समीक्षा हम पहले ही कर चुके हैं। अतः चीन के दृष्टिकोण में बदलाव
को पृथक् रूप से रेखांकित करना होगा। चीन की नीति के विवेचन को तीन स्तरों
पर देखना होगा। प्रथम, आंतरिक वैचारिक मथन, द्वितीय, आंतरिक विकास
के स्वरूप का विवाद एवं सन्दर्भों के बीच चीन की परराष्ट्र नीति इसी विश्व-
दृष्टिकोण का व्यावहारिक पक्ष है। इस प्राथमिक विवेचन के बाद, प्रत्येक चरण
में चीन सोवियत सम्बन्ध और चीन अमेरिका सम्बन्ध, के स्वरूप का पृथक् विवेचन
किया जायेगा। अतः प्रत्येक चरण में इसी पक्षों के आधार पर समीक्षा से एक
विकास की प्रवृत्ति स्वतः स्पष्ट होगी।

प्रथम चरण 1949 से 1959 ध्रुवीकृत विश्व की वैचारिकता

1949 का वर्ष विश्व समाजवादी क्रांतिकारिता हेतु अभूतपूर्व था। चीन में
समाजवादी विचारधारा वाले नेतृत्व की विजय दूरगामी ऐतिहासिक महत्व की
थी। इस घटना ने, न सिर्फ सबसे बड़े जन समुदाय के भविष्य की दिशा बदली,
बल्कि, समाजवादी विचारधारा को मात्र यूरोपीय परिवेश से परे एशिया में भी
व्यावहारिक सिद्ध किया। निःसंदेह यह अतुलनीय था। सर्वहारा वर्ग की विचार-
धारा के प्रति कृपक वर्ग की निषादक प्रतिबद्धता स्थापित करना चीन की कम्यु-
निस्ट पार्टी और माओ के निजी योगदान की परिचायक थी। जनवादी शासन
की स्थापना इस नयी प्रक्रिया का चरम बिंदु नहीं अपितु मात्र प्रारम्भ था।
समाजवादी व्यवस्था के निर्माण का एक लम्बा और दुर्बल कार्य, आगामी ऐति-
हासिक दायित्व बन गया। समाजवादी विकास के नियम तो उपलब्ध थे, लेकिन
व्यावहारिक परिवेश नया था। मात्र सोवियत संघ के व्यावहारिक अनुभव सम्मुख
थे, अथवा, कुछ भी अनुकरणीय नहीं। ऐसे ही मिश्रित वातावरण में चीन ने
समाजवादी संरचना की नीति का विकास किया।

उत्पादन की उपलब्ध शक्तियों का विकास, और उत्पादन के सम्बन्धों में

समानांतर आधार पर परिवर्तन, इस नये दायित्व के दोहरे पक्ष थे। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में, दोनों का ही वर्तमान स्वरूप अत्यधिक अविश्वसित और भावी विकास के लिये अवरोधक था। समाजवादी व्यवस्था के विकास में, पक्ष उत्पादन दायित्वों के विनाश की जाये अथवा अधविश्वसित उत्पादन क्षमता के रहते हुए उत्पादन के सम्बंधों में क्रान्तिकारी परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाये, यह वैचारिक विवाद का प्रमुख आधार था। अब तक की संवैधानिक व्याख्या और सोवियत अनुभव के अनुसार उत्पादन की दायित्वों का विकास प्राथमिक है, और ऐसे विकास की तुलना में ही उत्पादन के सम्बंधों और निजी स्वामित्व की व्यवस्था में परिवर्तन हो। प्रारम्भ में सोवियत निर्देशन के आधार पर नियंत्रित लिये गए। लेकिन उत्तरोत्तर रूस में चीन के व्यावहारिक पक्षों पर माओ का निजी वैचारिक दृष्टिकोण भी विश्वसित हुआ जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को भी प्रभावित किया।

1955 में माओ ने घोषणा की कि कृषि के क्षेत्र में सामूहिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जायेगा। साथ ही साथ भारी उद्योग सम्बंधित प्रशासन की पार्टी के सीधे निरीक्षण के अन्तर्गत लाया जायेगा। 1956 में, विकास के विभिन्न व्यावहारिक पक्षों को माओ ने अपने संवैधानिक लेख "दस प्रमुख सम्बंधों में स्पष्ट किया। इसमें आर्थिक विकास में, भारी और छोटे उद्योग तथा कृषि में परस्पर आवश्यक सतुलन पर बल दिया गया तथा उनके क्षेत्रीय बंटवारे को भी रेखांकित किया गया। इस लेख में व्यक्त अनेक विचार समाजवादी विकास की सोवियत व्याख्या से भिन्न थे। इन्हीं विचारों को 1958-59 के दौरान (प्रेट लीप फारवर्ड) 'लंबी छसांग कार्यक्रम' द्वारा क्रियावित किया गया है। माओ द्वारा दिया गया मुहावरा, "दो टांगों पर चलना" (walking on two legs), प्रचलित किया गया। दो टांगों का अभिप्राय था—उद्योग और कृषि, भारी और छोटे उद्योग, आधुनिक और पुरातन, एवं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास। इनमें सतुलन का नारा दिया गया। क्रिया-व्ययन के स्तर पर कृषि 'कम्यून' व्यवस्था द्वारा सामूहिकीकरण की प्रक्रिया लागू की गई, और उद्योगों के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन कार्यक्रमों के स्वरूप में लागू करने हेतु, "जनसना" (Peoples militia) का गठन किया गया, जिसका प्रमुख दायित्व इन कार्यक्रमों के प्रतिरोध पर नजर रखना था।

इन विभिन्न अति-
मे आंतरिक विवाद के
विचित्र अनिश्चितताओं
बीच विवाद का
ही विजयी

६. एक ओर पार्टी
व्यवस्था में एक

बाद कर दिया गया। थोड़े समय के लिये, माओ ने सक्रिय राजनीति में भाग न लेने की घोषणा की, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें कुछ सैद्धांतिक अध्ययन पर समय व्यतीत करना था। सरकार ने 'चैयरमैन' पद से मुक्त हुए, लेकिन 'पार्टी चैयरमैन' वे ही रहे। कुछ समय बाद माओ की सक्रिय वापसी के साथ आंतरिक मथन का एक नया चरण उभरा — "सांस्कृतिक क्रांति" के सिद्धान्त के रूप में।

चीन का विश्व दृष्टिकोण

विकास के इस प्रथम चरण में चीन के विश्व दृष्टिकोण के निमाण में दो प्रमुख आधार थे। प्रथम, साम्राज्यवादी व्यवस्था से मूलभूत विरोध था, जिसके तात्कालिक अभिप्राय ताइवान के विवाद में भी अभिव्यक्त थे। द्वितीय विभिन्न पारस्परिक वैचारिक मतभेदों के बावजूद समाजवादी राष्ट्रों में सहयोग के मूलभूत आधार थे, जो विशेषतः सोवियत संघ के आर्थिक सहयोग में तात्कालिक रूप से उपलब्ध थे। इन दो मूलभूत मान्यताओं के आधार पर चीन के विश्व दृष्टिकोण में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को आका गया। अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर, माओ की यह मान्यता थी कि कोई भी आंतरिक अथवा अन्तर-राष्ट्रीय शक्ति जिस बहुराज्यवादी प्राप्त नहीं है, मूलतः एक निर्बल शक्ति है भले ही बाहरी रूप में वह अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत हो। एक दूसरी मान्यता जिसका सुरक्षा से सम्बंध था यह थी कि, जन समर्थित शासन पर बाहरी हस्तक्षेप अथवा आक्रमण कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि, विपरीत से विपरीत स्थिति में भी एक 'सुरक्षात्मक गृह-युद्ध की नीति' अपनायी जा सकती है अतः आंतरिक सुरक्षा और शक्ति का आधार जन समर्थन है न कि सैनिक बल। इन दो मान्यताओं ने चीन के सामंजस्यपूर्ण शक्तियों के मूल्यांकन को निरंतर प्रभावित किया।

1949 में ही माओ ने चीन में विजय के अवसर पर अपने लेख "जनता के लोकतंत्र और अधिनायकत्व पर (on People's Democracy and Dictatorship)" में चीन के विश्व दृष्टिकोण का प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया — "साम्राज्यवादी आक्रमण ने चीन की जनता के पश्चिम से सीलने के सभी सुभावने सपनों को ध्वस्त कर दिया है। अब तक के अनुभवों से चीन की जनता को यह मूलभूत सबक मिला है कि हमें बाहरी स्तर पर सोवियत संघ और अन्य जनवादी लोकतंत्रों के साथ जुड़ना चाहिए, और एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण करना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप एक पक्ष की ओर झुक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही। सन यात सेन के चालीस वर्षों के अनुभव और कम्युनिस्ट पार्टी के पिछले अट्ठाईस सालों के अनुभव ने हमें सिखाया है — एक पक्ष की ओर झुकना, और हम इस बात के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि विजय पाने और उसे मजबूत बनाने के लिए किसी एक

पक्ष की ओर झुकना जरूरी है— साम्राज्यवाद के पक्ष की ओर अथवा समाजवाद के पक्ष की ओर। तीसरा रास्ता नहीं है। क्या ब्रिटेन और अमेरिका के वर्तमान शासक, जो कि साम्राज्यवादी हैं, एक 'जनवादी राज्य' की महायत्ना करेंगे? यदि हां तो वे ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि, उनके पूँजीवाणी मुन, वा कमालना चाहते हैं, और उनके 'बंकर' व्याज बढ़ोरना चाहते हैं, ताकि वे अपने आपका अपने स्वयं की आयिक मकट ग उबार सकें। यह कोई चीन की जनता का मदद दन की बात नहीं है। पाठक का चाहिए कि वे सन यात सेन को पढ़ें। उाका यह मन्वा परामर्श था कि, साम्राज्यवादी राष्ट्रों स मदद की आगा मत करो, अपितु उन राष्ट्रों क साथ एकता स्थापित करा जा हम बराबरी का दजा दत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम साविजन नेतरम जाने साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे में हैं। मत हम इसी पक्ष ग सचची और मैत्रीपूर्ण सहायता की आगा करत हैं।"

माओ के उपयुक्त विश्लेषण ग कुछ महत्वपूर्ण पक्ष उभरत हैं। प्रथम, यह कि विश्व का प्रमुख अनविरोध साम्राज्यवाद और समाजवाद की व्यवस्थाओं के बीच है। इसी आधार पर विश्व म एक व्यवस्थागत ध्रुवीकरण है। द्वितीय, साम्राज्यवाद का एक मोर्चे क रूप म सक्रिय विरोध, समाजवादी राष्ट्रों म एकजूटता का आधार है। तृतीय प्रत्येक समाजवादी राष्ट्र के लिए यह एकजूटता आर्थिक विकास की दृष्टि स उपयोगी है। अंतिम यह कि, यद्यपि यह मोर्चा सोवियत नेतृत्व म आयोजित है इसम प्रत्येक समाजवादी राष्ट्र का बराबरी का दर्जा है। अतः नेतृत्वकारी भूमिका के कारण सोवियत सघ का यह समाजवादी दायित्व है कि वह प्रत्येक राष्ट्र क हितों को बराबरी का महत्व द, और समाजवादी सरचना के उनके विभिन्न परिवेशों को समझें।

साम्राज्यवादी व्यवस्था के सक्रिय विरोध के सदम म एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष माओ के चिन्तन का था। स्वयं चीन पर साम्राज्यवादी आक्रमण का अनुभव हमकी ऐतिहासिक प्रेरणा थी। माओ की मान्यता थी कि, साम्राज्यवादी विस्तारवाद का सीधा डर सोवियत सघ को नहीं था, क्योंकि वह एक विश्व शक्ति थी। विशेषतः आणविक सतुलन के अस्तित्व के बाद, यह और अधिक सही था। साम्राज्यवाद के आतंक का सीधा प्रभाव या तो कमजोर समाजवादी राष्ट्रों पर था, अथवा 'एशिया अफिका के नवोदित राष्ट्रों पर, जिन्हें साम्राज्यवाद अपने नव विस्तारवाद के जाल में बांधना चाहता था। अतः साम्राज्यवादी अतक और आधिपत्य के विरुद्ध सघ की रणभूमि में यही प्रनादित राष्ट्र थे। इस दृष्टि से समाजवादी राष्ट्रों को विकसित और सुरक्षित किया जाय, तथा साथ ही साथ साम्राज्यवाद से सीधी टक्कर भी ली जाये। ऐसी स्थितियों म, एक उग्र सहयोग और हस्तक्षेप की नीति मात्र एक स्वाभाविक अभिप्राय था। माओ ऐसी उग्र नीति की सफलता को भी निश्चित मानते थे। इस विश्वास का आधार था कि, साम्राज्यवाद के बाहरी

उग्र स्वरूप के भावजूद, अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण यह वास्तविक स्तर पर एक कमजोर शक्ति है। विरोध का विश्वव्यापी जन आधार, साम्राज्यवाद की शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अतः साम्राज्यवाद के विरोध में आयोजित समाजवादी राष्ट्रों के मोर्चे का, इन सदस्यों में एक ऐतिहासिक दायित्व है।

चीन सोवियत संबंध मंत्रों के विशिष्ट सदस्य (1949-59)

आंतरिक विकास की वैचारिक मायताओं और अपने विश्व दृष्टिकोण की दृष्टि से चीन के लिए सोवियत संघ के साथ निरवच्छेद संबंध स्थापित करना एक स्वाभाविक पहलू था। सोवियत संघ के लिए भी समाजवादी गुट में चीन को सम्मिलित करना एक महत्वपूर्ण उपसन्धि थी। लेकिन, प्रारंभ से ही सोवियत संघ ने यह स्वीकार किया कि अल्पसंख्यक समाजवादी राष्ट्रों की तुलना में चीन का एक अलग और विशेष स्थान है। यद्यपि यह मायता किसी औपचारिक रूप में व्यक्त नहीं हुई, फिर भी सोवियत चीन संबंधों का विकास इसी आधार पर हुआ। चाहे वह आर्थिक विकास संबंधों सहायता का प्रश्न रहा हो अथवा सैनिक सहायता का, चीन की विशिष्टता परस्पर संबंधों के विकास में परिलक्षित हुई। लेकिन साथ ही साथ सोवियत संघ के इस समाजवादी दृष्टिकोण की सीमाएँ भी थी। समाजवादी विकास के स्थापित नियमों और विश्व स्तर पर समाजवादी राष्ट्रों की आत्मरक्षा से संबंधित सामरिक प्रश्नों पर किसी भी प्रकार का समझौता सोवियत संघ की दृष्टि में आत्मघाती था। अतः असंभव भी। इन्हीं दोहरी प्रवृत्तियों के बीच, सोवियत चीन संबंधों के विशिष्ट सदस्य विकसित हुए।

चीन की आंतरिक क्रांति की लड़ाई के दौरान सोवियत संघ ने आशानुकूल सहायता दी। हथियारों और आर्थिक मदद के साथ साथ वैचारिक एवं सामरिक मार्गदर्शन भी दिया गया। 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आने के बाद संबंधों को एक नयी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फरवरी, 1950 में माओ की सोवियत यात्रा के दौरान, चीन सोवियत मैत्री संधि सम्पन्न हुई। इसमें अथवा बातों का अंशवाची चीन को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता का भी प्रावधान था। इस संधि की औपचारिक स्वरूप देने से पूर्व चीन और सोवियत संघ में वार्ताओं का एक लंबा दौर रहा। अतः, स्टालिन और माओ के बीच वार्ता में अनेक शकानों का निवारण हुआ और संधि पत्र पर औपचारिक हस्ताक्षर हुए। इस संधि के बाद, चीन के आर्थिक विकास से संबंधित अनेक समझौते हुए। सोवियत संघ ने चीन को 20 करोड़ डालर का ऋण देने का आश्वासन दिया जिसका मुँग तान चार किस्तों में किया जायेगा। 1954 के बाद इस ऋण की वापसी चीन द्वारा दस किस्तों में की जायेगी और सोवियत संघ इस पर मात्र एक प्रतिशत ब्याज लेगा। आर्थिक विकास और संसाधनों के दोहन के लिए आर्थिक सहायता

साथ तकनीक और प्रबंध-व्यवस्था आदि भी चीन की तत्कालीन आवश्यकता थी। अतः एक दूरगामी सहयोग की दृष्टि से चीन और सोवियत संघ की अनेक सम्मिलित पूंजी कंपनियाँ (Joint Stock Companies) के निर्माण की भी व्यवस्था उभरी। 1953 में इस उद्देश्य से चीन और सोवियत संघ के तीन संयुक्त निगमों की स्थापना हुई। तल त मॉनो की मोज और उत्पादन के लिए, खनिजों की खोज और उत्पादन के लिए, तथा नागरिक विमान सेवाओं के लिए। अक्टूबर, 1949 में ही यह निगम हो चुका था कि, सोवियत संघ चीन को एक अरब रबल मूल्य के पाँच एव उपकरण आदि देगा। 1953 में, चीन में औद्योगिक विकास की योजना को लागू करने की दृष्टि से, सोवियत संघ ने यह दायित्व लिया कि 91 नए मस्याना की स्थापना तथा 50 पुराने मस्याना को नयी तकनीक के आधार पर विवसित करने हेतु, तकनीकी सहयोग और आर्थिक ऋण भी दिया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा सोवियत संघ और चीन में आर्थिक सहयोग की तीव्र प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1950 के बाद चीन का लगभग 80 प्रतिशत व्यापार सोवियत संघ के साथ था। इसमें निरंतर वृद्धि हुई।

लेकिन गीघ्र ही समाजवादी विकास की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह के प्रश्न पर, चीन सोवियत संघ में मतभेदों का गंभीर रूप उभरने लगा। विकास की आंतरिक समस्याओं के संदर्भ में चीन ने जहाँ अति उत्साही दृष्टिकोण अपनाया, उमके अनुपात में सोवियत वैचारिक समीक्षा का स्तर भी स्पष्ट हुआ। स्टालिन की मृत्यु के बाद सितंबर, 1954 में खुश्चेव की चीन यात्रा हुई। जिसमें परस्पर संबंधों के साथ साथ दोनों राष्ट्रों की आंतरिक स्थितियों पर भी विचार हुआ। माओ के दृष्टिकोण में स्पष्ट भिन्नता थी, लेकिन इन बातों में कोई तीव्र सोवियत प्रतिनिधियाँ देखने को नहीं मिली, क्योंकि स्वयं खुश्चेव अपने नेतृत्व के संघर्ष में माओ की शुभकामना चाहते थे। आर्थिक प्रश्नों के साथ साथ आणविक तकनीकी के सहयोग पर भी चीन सोवियत संबंधों के साथ ही मानसिकता बनी। सोवियत मान्यता थी कि यदि चीन स्वयं को समाजवादी गुट का राष्ट्र मानता है, तो उस स्वतंत्र आणविक क्षमता की क्या आवश्यकता है। इसके ठीक विपरीत, चीन का दृष्टिकोण था कि, प्रत्येक समाजवादी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता ही अंततः सामूहिक एकजुट शक्ति को जन्म दे सकती है। अतः चीन को आणविक तकनीक देना सोवियत संघ का दायित्व है, भले ही इसके प्रयोग के लिए विशेष 'गारंटी' की व्यवस्था हो सकती है। इन उभरते हुए परस्पर संशयों के बीच, चीन ने कोरिया संकट और विपत्तियों में सोवियत नीति की समीक्षा की। चीन का मत था कि 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान सोवियत संघ एवं अन्य समाजवादी राष्ट्रों को अधिक प्रभावी हस्तक्षेप करना चाहिए था। जहाँ तक ताइवान का विवाद था उसमें भी सोवियत संघ की धैर्यपूर्ण नीति, चीन ने अत्यंत बर्तायी इस उभरती

समीक्षा के समानांतर चीन ने अपनी, दृष्टि को एशिया अफ्रिका के राष्ट्रा पर भी केन्द्रित किया। 1955 का बाङ्गु सम्मेलन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 1956 में, चाउ एन लाई ने आठ एशियाई राष्ट्रो का भ्रमण किया। इससे पूर्व 1954 में भारत के साथ पञ्चशील सिद्धांतों के आधार पर एक सम्झौता भी किया गया, जिससे भारत ने तिब्बत को चीन का भाग माना।

सोवियत चीन संबंधों में उभरते वैचारिक विवाद की दृष्टि से 1956 में सोवियत पार्टी का 20 वा अधिवेशन दूरगामी प्रभाव का था। छद्मचेव और इसकी नीतियों की औपचारिक स्थापना हुई। इस अधिवेशन में सोवियत विदेश-नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निणय हुए, संक्षेप में जिन्हें "शांतिपूर्ण सहअस्तित्व" के सिद्धांत में जाना गया (विस्तार से वणन के लिए पिछला अध्याय देखिये)। इन निणयों की चीन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अब तक चीन की एक नई मानसिकता बन गई थी कि सोवियत संघ समाजवादी दायित्वों को सक्रिय रूप से नहीं निभा रहा है। कोरिया ताइवान आदि इसके अनुभव थे। 20 वें अधिवेशन में व्यक्त विचारों ने चीन की इस मानसिकता को और अधिक स्पष्ट बनाया। सोवियत पार्टी ने स्टालिन की भूमिका की समीक्षा की, और अनेक स्थितियों में उसकी नीतियों की तीव्र भत्सना की गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस समीक्षा से कतई सहमत नहीं थी। उसके प्रतिनिधि ने इस अधिवेशन में अपना स्पष्ट विमत व्यक्त किया। सोवियत संघ द्वारा दिये गये स्टालिन की भूमिका के मूल्यांकन में अलग चीन की पार्टी ने अपना पृथक मूल्यांकन प्रस्तुत किया। इस पूरे वैचारिक विवाद से सोवियत चीन संबंधों में तीव्र मतभेद उभरे।

इन मतभेदों में चीन का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। 1956 में हंगरी में सोवियत कदम को चीन ने उचित कहा। चीन की मायता थी कि, हंगरी में सोवियत संघ ने प्रतिगामी शक्तियों को पराजित करने के लिये प्रभावी कदम उठाया है। चीन की अपेक्षा थी कि अन्यत्र भी सोवियत नीति ऐसी ही सक्रियता का प्रमाण दे। नवम्बर, 1957 में माओ ने अपने विचार मास्को में आमोजिन वामपंथी पार्टी के अधिवेशन में रखे। इन में दो प्रमुख बातें थी। प्रथम, माओ का मूल्यांकन था कि साम्राज्यवादी शक्तियों की तुलना में जनवादी शक्तियाँ कहीं अधिक सशक्त हैं। इस धारणा को माओ ने अपने मुहावरे "पूब की हवा पश्चिम पर हावी है" में व्यक्त किया, तथा सोवियत आणविक क्षमता के उदाहरण से इसे पुष्ट किया। द्वितीय, ऐसी स्थिति में माओ ने समाजवादी शक्तियों की सत्रिय एकजुटता पर बल दिया। उन्होंने यह दृढ़ रूप से व्यक्त किया कि 'समाजवादी गुट का एक नेता' अवश्य होना चाहिये, और सोवियत संघ को यह दायित्व स्वीकार करना चाहिये। साम्राज्यवाद से समन्वय नहीं अपितु, संघर्ष का दृष्टिकोण हो। सोवियत दृष्टि में ऐसा मूल्यांकन संवत्सा अयथापवादों का था। यह सही है कि जनवादी

राशितया अधिक दृढ़ हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ वे उतनी मजबूत भी नहीं हैं कि साम्राज्यवादी राशितयों से सीधे टक्कर से सके। अतः सोवियत दृष्टिकोण के अनुसार, विश्व में तनाव कम करना एक दोहरी आवश्यकता है। प्रथम, स्वयं समाजवादी राष्ट्रा को एक सुरक्षित एवं बर्तमान रहित वातावरण प्रदान करने में लिये। दूसरे, साम्राज्यवाद की व्यवस्थागत कमजोरियों का उभारन और तृतीय राष्ट्रा में समाजवादी प्रभाव को बढ़ाने में लिये। चीन की दृष्टि जहाँ एक ओर अत्यधिक उग्र थी, वही सोवियत संघ एक सम्बन्ध और क्रमिक संघर्ष की पक्षधर थी।

1958 का वर्ष सोवियत-चीन सम्बन्धों के लिये अत्यधिक घातक रहा। इससे पहले 1957 में हुए सामग्री पाटिया के सम्मेलन में ही मतभेदों का एक स्वरूप उभर चुका था। लेकिन सोवियत संघ ने, इस सम्मेलन के लिये माओ की मौजूदगी यात्रा के दौरान ही, चीन के साथ सम्बन्धों को सुधारने की पहल भी की। सोवियत संघ इस बात के लिये राजी हुआ कि वह चीन को आणविक हथियारों की तकनीक भी उपलब्ध करायेगा। इस अभिप्राय के एक समर्थन पर हस्ताक्षर हुये। 1958 में चीन ने आन्तरिक आर्थिक विकास हेतु 'लंबी छलांग कार्यक्रम' (Great Leap Forward) कार्यक्रम की घोषणा की। इसकी तात्कालिक सोवियत प्रतिप्रिया उग्र हुई। सोवियत पार्टी ने इस वचारिक और विकास दोनों ही आधारों पर आरम्भवात कहा। सोवियत संघ ने चीन को सभी आर्थिक सहायता तात्कालिक प्रभाव से बंद करने की घोषणा की। इस पूरी घटना ने सोवियत चीन संबंधों के भावी विकास पर एक बहुत बड़ा प्रभावित्व लगा दिया। चीन ने सोवियत संघ की भूमिका की ओर अधिक उग्र तथा खुली आलोचना प्रारम्भ की। माओ ने साम्राज्यवाद का मूल्यांकन करते हुये उसे 'कागजी शेर' (Paper Tiger) की संज्ञा दी और, इस दृष्टि से, सोवियत संघ के साम्राज्यवाद से समन्वय के प्रयासों को एक हास्यास्पद स्थिति कहा।

सोवियत चीन मतभेद अब तक अधिकांशतः स्पष्ट हो चुके थे। 1959 के प्रारम्भ में क्यूबेच ने बीजिंग की यात्रा की जिसका प्रमुख उद्देश्य चीन के नेतृत्व की पयाथवादी स्थितियों को समझाने का प्रयास था। 1958 में ताइवान के समीप एक बार संकट फिर मढराया। ईराक में एक आन्तरिक क्रांति के द्वारा साम्राज्यवाद समर्थन सत्ता को अपदस्थ कर दिया गया था। इन स्थितियों में अमेरिका ने लेबनान में और ग्रीटन में जाडन में अपनी सैनिक उपस्थिति के द्वारा सीधे हस्तक्षेप के प्रयास किये। चीन की यह आशा थी कि इस सैनिक उपस्थिति का ताइवान विवाद पर भी प्रभाव हो सकता है। अतः उसने सोवियत संघ में यह अपेक्षा की कि वह भी सक्रिय हस्तक्षेप करे। सोवियत नीति का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। चीन के लिये यह एक असहनीय स्थिति थी। क्यूबेच ने अपनी यात्रा के दौरान सोवियत नीति को उचित और व्यावहारिक ठहराया और चीन संयह

आशा की कि यह स्थितियों का सही लेखा जोखा करे, तथा किसी उग्रवादी काय-चाही में सलग्न न हो। झुझेव का प्रयास पूर्णतः असफल रहा। अगस्त 1959 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 8वें 'प्लेनरी अधिवेशन में सोवियत आलोचना को औपचारिक और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि, सोवियत पार्टी का नेतृत्व अब सगोपनवादी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो रहा है। इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति उसकी आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों में हुए सांस्कृतिक प्रयत्नों में मिलती है। अमेरिका के साथ सम्बन्धों में सामायीकरण के निर्णय को सोवियत संघ ने यथावत रखा। 1959 में झुझेव की प्रथम ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा हुई। चीन द्वारा इसकी तीव्र प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अपनी अमेरिका यात्रा के बाद अक्टूबर, 1959 में झुझेव ने एक बार फिर चीन की यात्रा की। इस बार झुझेव न खुसी सभा में चीन की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की ममय को गलत बताया। इस बीच सोवियत संघ ने भारत के साथ अपने बढ़ते हुये संबंधों की दृष्टि से, तिब्बत के विवाद में अपनी तटस्थता दर्शायी। चीन के लिये असुविधा का यह एक और कारण बन गया। दिसम्बर, 1959 में स्टालिन के जन्म दिवस के अवसर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टालिन का वर्णन करते हुये उस "साम्राज्यवाद का पक्का दात्र जिसने कभी समझीता नहीं किया" बताया। ऐसे खुले मूल्यांकन का स्पष्ट अभिप्राय था। यह कि स्टालिन का नेतृत्व असमझीतावादी था और वर्तमान नेतृत्व जो स्टालिन की आलोचना करता है समझीतावादी है।

उपरोक्त विवेचन से सोवियत चीन सम्बन्धों में एक दशक का विकास स्पष्ट होता है। सम्बन्धों की स्थापना सहकारिता और एकजुटता के वातावरण में हुई। दशक की समाप्ति के आते आते इसमें उग्र विवाद के क्षीण स्वर उभरने लगे। स्थापना से ही रूस और चीन के बीच सम्बन्धों में एक विशिष्टता थी। दोनों समाजवादी राष्ट्र एक दूसरे के परस्पर महत्व को समझते थे। अतः सम्बन्धों में अल्प समाजवादी राष्ट्रों की तुलना में दोनों राष्ट्रों के लिये एक परस्पर महत्व था। समाजवादी सिद्धान्तों के व्यावहारिक परिवेश की भिन्नता ने अनेक स्तर पर वैचारिक मतभेद उभारे। चाहे वह चीन में आन्तरिक विकास की रणनीति का प्रश्न हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी राष्ट्रों की एकता और सक्रियता का प्रश्न माओ के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक 'स्वतन्त्र' दृष्टिकोण विकसित हुआ। सोवियत नेतृत्व द्वारा भी इन भिन्नताओं को समझने और कुछ हद तक इनसे समझीता भी करने के प्रयास हुए। लेकिन इन प्रयासों की सीमायें थी जो उत्तरोत्तर स्पष्ट हुईं। दशक के अन्त तक सोवियत चीन सम्बन्धों में विवाद अनौपचारिक रूप से स्थाई बन चुका था। वामपंथी राष्ट्रों के बीच और खुले अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर, इसकी अभिव्यक्ति होनी शेष थी। विकास का यह

अगले दशक में स्पष्ट हुआ।

चीन-अमेरिका संबंध विवाद और कटुता (1949-1959)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी गुट की स्थापना साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिये एक नई चुनौती थी। 1949 में चीन में समाजवादी नेतृत्व की स्थापना ने साम्राज्यवाद के सामने एक और पराजय उपस्थित की। स्वाभाविक था कि, ऐसी स्थिति में चीन और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के संबंध आवश्यक रूप से कटु होते। तात्कालिक स्थितियों ने इस आवश्यक कटुता की स्थिति में कुछ और आयाम जोड़ दिये। गृहयुद्ध में चांग काई शेक की पराजय तो हुई लेकिन ताइवान पर उसका शासन यथावत बना रहा। तात्कालिक रूप से, भौगोलिक पचीसगिया को देखते हुये, वामपंथी सेनाओं की विजय सम्भव नहीं बन सकी। अतः एक संघर्ष समय तक इस विवाद का चीन के लिये महत्व स्वाभाविक था। गृहयुद्ध की स्थिति में भी अमेरिका ने चांग काई शेक को समर्थन दिया था। ताइवान के बनने के बाद यह समर्थन और अधिक स्पष्ट तथा उग्र बन गया। शीतयुद्ध की मानसिकता में, साम्यवाद का हर स्थिति में विरोध पश्चिमी राष्ट्रों की स्पष्ट नीति थी। जहाँ तक चीन का प्रश्न था, विचारधारा के स्तर पर, गृहयुद्ध के अनुभवों के कारण अथवा भावी सहयोग की सम्भावनाओं की दृष्टि से, किसी भी स्थिति में अमेरिका के साथ सामाजिक सम्बंधों का प्रदान ही नहीं था। इन दूरगामी कारणों में तात्कालिक विवादों के जुड़ने के साथ ऐसी कोई सम्भावना पूर्णतया असंभव बन गई। अतः चीन में समाजवादी नेतृत्व के तुरंत बाद, चीन अमेरिका सम्बंधों में आवश्यक कटुता की स्थापना हुई जोकि उत्तरोत्तर विकसित भी हुई।

ताइवान के प्रश्न के साथ कोरिया विवाद का प्रश्न जुड़ने से, चीन अमेरिका सम्बंधों में कटुता ने एक उग्र स्वरूप लिया। जून, 1950 में दक्षिणी कोरिया में यह आरोप लगाया कि उस पर उत्तरी कोरिया द्वारा आक्रमण किया गया है। 27 जून, को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सातवें जहाजी बेड़े को भेजने के आदेश दिये। आदेश में यह कहा गया कि "कोरिया पर आक्रमण द्वारा यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध होता है कि साम्यवाद तोड़-फोड़ की नीति की सीमाओं पार कर चुका है। ऐसी स्थिति में ताइवान पर भी आक्रमण और कब्जे की सम्भावनाएँ प्रबल बन गई हैं। अतः सातवें बेड़े को वहाँ भेजना एक आवश्यक कदम है।" चीन द्वारा अमेरिका को इस घोषणा की तीव्र भत्सना की गई। चाऊ-एन लाई ने ट्रूमैन-वक्ताव्य को चीन पर आक्रमण की सजा दी और इसे एक पहले से विचारे हुये साम्राज्यवादी कायंत्रण की अभिव्यक्ति कहा गया। चीन ने यह दोहराया कि ताइवान उसका अविभाज्य अंग है और वहाँ किसी भी हस्तक्षेप का बड़ा जवाब

दिया जायेगा। जब तक ताइवान को मुक्त नहीं करा लिया जाता, सधप जारी रहेगा। नवंबर, 1950 में चीन के प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के सम्मुख भी इसी भाषण का प्रतिवेदन रखा। कोरिया विवाद पर हुई बहस में चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि, वह औपचारिक रूप से कोरिया विवाद पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इसका उल्लेख काय विधि में किया गया है वह पूर्वग्रहों के आधार पर चीन और उत्तरी कोरिया को आक्रमक राष्ट्र बताता है। अपने लम्बे वक्तव्य के अंत में, चीन के प्रतिनिधि ने तीन मांगें रखीं। यह कि चीन की भूमि अर्थात् ताइवान में तथा उत्तरी कोरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप की भत्सना की जाये और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो ताइवान से अमेरिकी सेनाओं को हटाया जाये, तथा कोरिया विवाद का समाधान सभी बाहरी हस्तक्षेप के बिना वहाँ की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार आंतरिक रूप में किया जाये। संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप कोरिया के आंतरिक युद्ध में तात्कालिक रूप से ठहराव की स्थितियाँ आईं। लेकिन इस पूरे विवाद ने अमेरिका-चीन सम्बंधों में तनाव की उग्र स्थितियाँ भी उत्पन्न कीं। फरवरी, 1951 में अमेरिका और ताइवान के बीच परस्पर सैनिक सहायता समझौता हुआ। समझौते पर चीन की तीव्र प्रतिक्रिया तथा अमेरिका-चीन सम्बंधों में और अधिक गिरावट स्वाभाविक थी।

आइजनहावर के राष्ट्रपति काल के दौरान राज्य सचिव के रूप में जान फॉर्स्टर डलैस की नीतियाँ ने चीन-अमेरिका विवादों को प्रारम्भिक रूप से और अधिक बटु बनाया। 1954 में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO) की स्थापना हुई। चीन ने इसकी कड़ी निंदा करते हुये इसे चीन के विरोध में आयोजित षडयंत्र बताया। इसी वर्ष दिसम्बर में अमेरिका ने ताइवान के साथ पारस्परिक सैनिक संधि भी की। संधि का प्रमुख उद्देश्य यह था कि चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण की सम्भावनाओं के विरोध में अमेरिकी नीति को स्पष्ट कर दिया जाये। इस संधि के बाद जनवरी, 1955 में अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि ताइवान की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। इन दोनों घटनाओं की चीन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। चीन की प्रतिक्रिया का दोहरा स्वरूप था। एक ओर जहाँ अमेरिका के इन निणयों की तीव्र भत्सना की गई, वहीं साथ ही साथ चीन को यह आभास भी हुआ कि तात्कालिक रूप से ताइवान को स्वतंत्र करवाना व्यावहारिक स्तर पर सम्भव नहीं है। विशेषतः सोवियत संघ से हुई वार्ताओं के बाद ऐसा दृष्टिकोण और भी स्पष्ट हो गया। सोवियत संघ की यह माँग थी कि ताइवान पर किसी सैनिक कार्रवाई द्वारा विजय प्राप्त करना व्यावहारिक और आत्मघाती होगा। अतः तात्कालिक नीति इस क्षेत्र में विवाद को कम करने की होनी चाहिये। चीन के लिये भी, ऐसी सोवियत समझ के होते हुये, कोई अन्य विकल्प सम्भव नहीं था।

1955 में बाहुग सम्मेलन के दौरान चीन की ओर से अमेरिका के साथ वार्ता की पहल करने की बात उभरी। एक प्रेस वक्तव्य में चाऊ एन-माई ने कहा कि चीन दक्षिण पूर्व एशिया और ताइवान आदि के प्रश्न पर तनाव कम करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने को तैयार है। इस वक्तव्य की तात्कालिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिकी घोषणा में कहा गया कि अमेरिका चीन के इस बदलते हुए रुख के प्रति आशावान है, लेकिन जब तक दक्षिण पूर्व एशिया में तनाव कम करने के प्रमाण नहीं मिले और चीन इस बात का आश्वासन न दे कि वह ताइवान के सम्बंध में आक्रमण की नीति नहीं अपनायेगा, तब तक वार्ताओं का कोई साधक स्वरूप नहीं उभर सकता। इस घोषणा के बाद चीन और अमेरिका के बीच वार्ताओं को आयोजित करने के अनेक आधार विचारणीय रहे। जुलाई, 1955 में अमेरिका और चीन के एक संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया कि दोनों राष्ट्रों ने राजदूत स्तर पर वार्ताएँ करने का फैसला किया है। चेकोस्लोवाकिया में उपस्थित चीन और अमेरिका के राजदूतों के माध्यम से ये वार्ताएँ होंगी। राजदूत स्तरीय इन वार्ताओं का दौर करीब तीन वर्ष तक चला। 1958 में अमेरिकी राजदूत के चेकोस्लोवाकिया से स्थानांतरण के बाद कुछ समय के लिये ये वार्ताएँ बंद हो गयीं। वार्ताओं के इन तीन वर्षों में अमेरिका और चीन सम्बंधों में आंशिक सुधार हुआ। सितम्बर, 1955 में दोनों राष्ट्रों के बीच यह समझौता हुआ कि एक दूसरे देश में रहने वाले चीनी अथवा अमेरिकी मूल के लोगो की परस्पर बदला बदली की अनुमति दी जायेगी। मई, 1956 में एक संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया कि दोनों राष्ट्र क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का आदर करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। इसी वर्ष अगस्त में चीन द्वारा यह घोषणा की गई कि उसने पिछले सात सालों से अमेरिकी सबाददाताओं की चीन यात्रा पर लागू प्रतिबंध को हटा दिया है। शुरू में अमेरिका ने अपने सबाददातों को चीन की यात्रा की इजाजत नहीं दी, लेकिन शीघ्र ही अमेरिका की तरफ से भी अपने सबाददातों की चीन यात्राओं पर लगाय गये प्रतिबंध को हटा लिया गया। इन वार्ताओं के दौरान झूलझूल विवादों पर कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक समझौता नहीं हुआ।

तात्कालिक रूप से परस्पर कटुता में आई कमी अधिक दिन तक नहीं टिक सकी। 1958 में ताइवान के समीप एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। चीन अमेरिका सम्बंधों में तनाव इसकी स्वाभाविक परिणति थी। जुलाई, 1958 में ईराक में एक आंतरिक उथल-पुथल के द्वारा पश्चिम समर्थित सत्ता अपदस्थ हो गई। इस घटना की तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिकी सेनाएँ लेबनान पहुँची और ब्रिटिश सेनाएँ जोर्डन। इस कायवाही का तात्कालिक उद्देश्य, ईराक जैसी घटना की लेबनान और जोर्डन में पुनरावृत्ति को रोकना था। लेकिन

से एक नई व्याख्या थी। पिछले दशक में विकास के अनेक उग्रवादी प्रयासों की असफलता से प्रेरित होकर माओ ने चिंतन की एक नई दृष्टि विकसित की। 1960 के बाद अनेक व्याख्याओं में यह बदलाव विकसित हुआ। माओ ने 'सांस्कृतिक क्रांति' की आवश्यकता के सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए कहा कि, कम विकसित आर्थिक सामाजिक स्थितियों में, शोषण की व्यवस्था की सबसे कमजोर बड़ी वैचारिकता तथा निबल उत्पादन संबंध हैं। साथ ही साथ यही निर्बल बड़ी, उत्पादन के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन को लागू करने में अग्रणी तात्कालिक अवरोध हैं। अतः आर्थिक सामाजिक क्रांति से पूर्व, आवश्यकता एक 'सांस्कृतिक क्रांति' की है। इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य भावी विकास के वैचारिक अवरोधों को धराशायी करना है। माओ के इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अभिप्राय था। यह कि, उत्पादन शक्तियों के वांछित विकास के पहले ही उत्पादन संबंधों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन न सिर्फ संभव है अपितु नितांत आवश्यक भी। पर दृष्टिकोण अब तक के माओ समाजवादी सिद्धांतों के एक दम विपरीत था।

'सांस्कृतिक क्रांति' में व्यक्त किये गये विचारों का विवाद चीन में समाजवादी व्यवस्था में प्रारम्भ से ही उठ खड़ा हुआ था। लेकिन 1960 के बाद ही माओ की स्पष्ट परिलक्षित हो सकी। 'सांस्कृतिक क्रांति' के दौरान माओ ने क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उसने कहा कि, प्रत्येक पुरानी व्यवस्था के बदलने के बाद जब नई व्यवस्था लागू होती है तब उसमें भी हितों के नये छुट पुट आधार बन जाते हैं। पार्टियों के अंदर भी ऐसे हित हो सकते हैं। अतः 'सांस्कृतिक क्रांति' का दायित्व ऐसे हितों का पर्दाफाश करना है तथा उन्हें पार्टियों के दायित्वों से हटाना भी है। 'सांस्कृतिक क्रांति' में नई मानसिकता का जन्म होना चाहिए। इस दृष्टि से माओ ने 'चार पुराने आधारों' की आलोचना की— पुराना चिंतन, पुराने विचार, पुरानी आदतें, तथा पुराने रीति रिवाज। इन्हें बदलना 'सांस्कृतिक क्रांति' का प्रमुख उद्देश्य कहा गया। 'सांस्कृतिक क्रांति' में सैनिक व्यवस्था के स्वरूप को भी बदलने पर बल दिया गया। कहा गया कि, जनता की सेना का दायित्व मात्र बाहरी सुरक्षा नहीं है। सेना को आंतरिक आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस दृष्टि से, सैनिक व्यवस्था का पुनर्गठन 'सांस्कृतिक क्रांति' का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

इस पूरी प्रक्रिया में चीन की आंतरिक स्थिति में नई अनिश्चितताओं को जन्म दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक वैचारिक विवाद उत्तरोत्तर रूप से उग्र हुआ। इसके समानांतर, सांस्कृतिक क्रांति के उपचारों को लागू करते के साथ ही आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर ख़ुले रूप में पार्टियों का आंतरिक विवाद उभर कर सामने आया। इस प्रक्रिया में दौरान माओ की पहले से स्पष्ट की गई आर्थिक विवास की रणनीति को उग्र रूप से लागू किया गया। उत्पादन के साधनों

मे कोई विशेष आधुनिकरण नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी की प्रमुख दृष्टि प्रवर्ध व्यवस्था पर ही केन्द्रित थी। अतः "सांस्कृतिक क्रांति" की स्थितियाँ जहाँ एक ओर तीव्र राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन की परिचायक थी, वहीं दूसरी ओर उत्पादन शक्तियों के विकास में साधारणतया ठहराव की स्थितियों के बीच चीन का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हुआ।

चीन का विश्व-दृष्टिकोण

छठे दशक के प्रारम्भ में ही चीन में उभरते आंतरिक वैचारिक मयन के अन्तर्राष्ट्रीय आयाम भी विकसित हुए। अमेरिका तथा सोवियत संघ में परस्पर सम्बन्धों की घुर्घ्रात ने चीन के विश्व दृष्टिकोण के विकास को निरन्तर प्रभावित किया। जैसे तो प्रारम्भ से ही सोवियत संघ ने चीन को एक धैर्यपूर्ण नीति अपनाने के लिए परामर्श दिया। लेकिन अब ऐसे परामर्श को चीन ने दूसरे ही दृष्टिकोण में समझा। चीन की यह मानसिकता बनने लगी कि महाशक्तियों के हित तथा अन्य सभी राष्ट्रों के हित गुणात्मक रूप से भिन्न हैं। ऐसी मानसिकता की पृष्ठभूमि में, सोवियत संघ के आंतरिक विकास के प्रति चीन की वैचारिक समझ भरे रही। चीन का दृष्टिकोण था कि, सोवियत विदेश नीति में समझौतावादी प्रवृत्तियों से पथक नहीं है। 1962 में माओ ने एक बहद पार्टी सभा को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की कि सोवियत पार्टी और राज्य का नेतृत्व सशोधनवादियों के हाथों में चला गया है। अतः उनसे किसी क्रांतिकारी भूमिका की अपेक्षा करना एक मुलावा होगा। इसी के साथ साथ, चीन के नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपनी हस्तक्षेप की नीति में अधिक सक्रिय हो रही हैं। चाहे वह हिंद चीन का प्रश्न हो, अथवा पश्चिमी एशिया या अफ्रिका का साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपनी कुचेष्टाओं में उत्तरोत्तर उग्र हो रही हैं। लेकिन साम्राज्यवाद की व्यवस्था अपने स्वयं के आंतरिक अंतर्विरोधों के कारण, इन्हीं हस्तक्षेप की नीतियों से पराजित भी होगी। क्योंकि वह एक कागजी शेर (Paper Tiger) मात्र है।

ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समझ के आधार पर, चीन ने अपने विश्व दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित किया। इस विश्व दृष्टिकोण के अनुसार तीन प्रमुख विश्वस्तरीय अंतर्विरोध बताये गये। प्रथम मार्क्सवादी लेनिनवादी शक्तियों और सशोधनवादी शक्तियों के बीच, द्वितीय, समाजवादी शक्तियाँ और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच, तथा तृतीय एशिया-अफ्रिका तथा लातिनी अमेरिकी मानव समुदाय और अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के बीच। इन अन्तर्विरोधों की व्याख्या करते हुए 1962 में माओ ने कहा कि, प्राथमिक महत्व को विश्वस्तरीय अंतर्विरोध अमेरिकी नेतृत्व में साम्राज्यवाद और एशिया अफ्रिका तथा लातिनी

अमेरिका के बीच है। इससे पहले की मायता कि, प्रमुख अंतर्विरोध साम्राज्यवाद और समाजवाद के बीच है, मामों की दृष्टि में वह साधक नहीं रहा। साम्राज्यवाद के पड़यंत्रों का सीधा निशाना यह तृतीय विश्व के राष्ट्र हैं, जो कि तात्कालिक रूप से साम्राज्यवादी साजिश के शिकार हैं। अतः साम्राज्यवाद से लड़ने के लिये एक विश्व स्तरीय एकजुटता की आवश्यकता है। सभी समाजवादी राष्ट्रों का भी यही दायित्व है कि इस प्राथमिक लड़ाई में अपना सहयोग दें। लेकिन समाजवादी राष्ट्रों के बीच भी माक्सवादी लेनिनवादी वैचारिक मायताओं तथा सशोधनवादियों के वैचारिक विरोध हैं। सशोधनवादियों की पराजय, इस दृष्टि से न सिर्फ समाजवाद को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है, अपितु, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के पड़यंत्रों की पराजय में लिए भी। जहाँ तक सोवियत दृष्टिकोण का प्रश्न है वह साम्राज्यवाद के आणविक भय के जाल में फँस गया है। अतः सोवियत भूमिका मुख्यतः साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को मौन स्वीकृति देना बन गई है। सोवियत संघ निरंतर क्रांतिकारी आन्दोलनों के साथ विश्वासघात कर रहा है। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र मात्र अमेरिकी साम्राज्यवाद के पिछलग्गु से अधिक नहीं हैं। उनकी स्थिति भी असहायक है। गुट निरपेक्षता अथवा ऐसा कोई अर्ध-आमीजन भी विश्व शांति को स्थापित करने के लिए प्रभावी नहीं हो सकता। स्पाई शांति अपने आप नहीं मिलती। स्पाई शांति को सतत संधियों के द्वारा जीता जाता है। अतः ऐसे समस्त संधियों की एक मात्र प्रेरणा चीन के क्रांतिकारी नस्ल तथा सक्रिय भूमिका से ही संभव है। चीन को अपनी नीति में तीन स्तरीय सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रथम, अर्ध-राष्ट्रों में हो रहे साम्राज्यवादी आतंक और हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़े जा रहे संधियों को सक्रिय सहयोग। द्वितीय, साम्राज्यवाद के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा। तृतीय, समाजवादी विचारधारा में उभर रही सशोधनवादी प्रवृत्तियों का सक्रिय विरोध।

चीन के इस नवपरिभाषित विश्व दृष्टिकोण के अनेक अभिप्राय हैं। विदेश नीति के निर्माण के व्यावहारिक पक्ष इससे प्रभावित हुए। एशिया अफ्रिका के राष्ट्रों के साथ अपने सम्बंधों को पढ़ाना इसका प्रमुख अभिप्राय था। समाजवादी गुट के राष्ट्रों के बीच, सोवियत संघ की सशोधनवादी प्रवृत्तियों की आलोचना इसका अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था। हिंद चीन में अमेरिकी सैनिक उपस्थिति का विरोध और यहाँ चल रहे मुक्ति संधियों में तात्कालिक सक्रिय भूमिका इस नीति का एक प्रमुख दायित्व भी था। इस दायित्व के दोहरा उद्देश्य थे। एक ओर जहाँ इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद के विरोध में संधि करना था, वहाँ दूसरी ओर यह आशा भी थी कि सोवियत सशोधनवादी नीति की तुलना में चीन की क्रांतिकारी दृष्टि को समर्थन मिलेगा। इन नीतियों का व्यावहारिक स्तर पर लागू करवाने में दो भूतभूत कठिनाइयाँ उपस्थिति हुई। प्रथम यह है कि ऐसी बहुपक्षीय नीति को

क्रिया विवृत करने के लिए आर्थिक तथा सैनिक सहायन चीन के पास उपलब्ध नहीं थे। दूसरा पक्ष सांस्कृतिक क्रांति के सन्दर्भ से जुड़ा है। इस अवधि में चीन की राजनयिक गतिविधियाँ एक दम कम हो गईं। कुछ राष्ट्रों में निगुक्त राजदूतों के अलावा अन्य सभी को 'राजनीतिक शिक्षा' के लिए चीन बुला लिया गया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान वैचारिक विवाद भी मुख्यतः आंतरिक प्रश्नों पर केन्द्रित रहा। अतः वैचारिक स्तर पर उभरती हुई नई विश्व दृष्टि न तो गहन आंतरिक विवाद का कारण बनी और न ही इसकी क्रिया-प्रति-क्रिया पर कोई सक्रिय रूप देखा उभर पाई। अतः इस चरण में चीन के परराष्ट्र सम्बन्धों विशेषतः अमेरिका और चीन के साथ सम्बन्धों को, इस तुलनात्मक निष्क्रियता के सन्दर्भ में देखना होगा।

चीन-सोवियत सम्बन्ध मंत्रों की विशिष्टता से वैमनस्य तक (1959-1969)

इस चरण में चीन सोवियत सम्बन्धों में सीधी टकराहट की अनेक स्थितियाँ उपस्थित हुईं। दोनों राष्ट्र अनेक स्तरों पर परस्पर विवाद में उलझे। 1959 में ही चीन के आंतरिक विकास की नीति की तीव्र भत्सना तथा आर्थिक सहयोग को खतम करने के सोवियत निर्णय से ही एक वैचारिक प्रतिद्वंद्विता के आधार तैयार हो चुके थे। इस दशक में इसी आधारों की उत्तरोत्तर उग्र अभिव्यक्तियाँ हुईं। परस्पर आलोचना के दोहरे स्तर रहे। समसामयिक प्रश्नों पर एक-दूसरे की आलोचना उभरने लगी। प्रारम्भ में, यह सीमित स्तर पर हुई, तथा धीरे-धीरे खुले रूप से भी आरोप-प्रत्यारोप की प्रक्रिया होने लगी। इस परस्पर बचा-छागिक विवाद का दूसरा स्तर समाजवादी राष्ट्राँ के बीच एक-दूसरे की भावनाओं का प्रचार करना भी रहा। सीमा विवाद आदि प्रश्न बाद की स्थितियों में उभरने लगे।

जून, 1960 में रूमानिया कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन के दौरान सोवियत और चीन प्रतिनिधियों में पहली वैचारिक झड़प देखने को मिली। क्लुशेव ने सीधा आरोप लगाया कि चीन की अति उग्रवादी नीति न सिर्फ चीन के लिए आत्मघाती है अपितु पूरे समाजवादी गुट के लिये एक सम्भावनी खतरा भी है। इसी वर्ष दिसम्बर में मास्को में आयोजित वामपंथी दलों के सम्मेलन में यह विवाद और अधिक स्पष्ट रूप से उभरा। चीन के दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिये समाजवादी गुट का एक मात्र राष्ट्र अल्बानिया सामने आया। सोवियत पार्टी के लिये यह एक नई चुनौती थी। अतः सोवियत आक्रोश का अल्बानिया केन्द्र बन गया। अक्टूबर, 1961 में आयोजित सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के 22वें अधिवेशन में अल्बानिया तो आमन्त्रित नहीं किया गया। अधिवेशन के दौरान अल्बानिया की

नीतियों पर सीधा प्रहार किया गया, जो कि परोक्ष रूप से चीन पर वेदित था। चीन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित चाउ-एन साई इसके विरोध में अधिवेशन से उठकर चले गये। सोवियत चीन विवाद इसके बाद अधिक प्रखर हुआ।

1962 का वर्ष दोनों राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्धों के लिये अत्यधिक महत्व का बन गया। क्यूबा का संकट अनेक अभिप्रायों वाला था। जहाँ एक ओर इसने शीत युद्ध की पराकाष्ठा अभिव्यक्त की, वही सोवियत चीन संबंधों में भी परस्पर छुत्ती आलोचना को प्रारम्भ किया। इस घटना के बाद चीन ने इसे सोवियत सम्योतावादी नीति की स्पष्टतम अभिव्यक्ति कहा तथा इसे समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिये अत्यधिक शर्मनाक बताया। क्यूबा विवाद के समानांतर, भारत चीन सैनिक झड़पें भी हुईं। इस विवाद में सोवियत संघ ने अपनी तटस्थता व्यक्त की, जिसका स्पष्ट अभिप्राय चीन के ऐसे कदम की आलोचना करना था। कुछ राजनीतिज्ञ पयवैक्षकों के अनुसार, क्यूबा विवाद तथा भारत चीन युद्ध का एक साथ होना आकस्मिक नहीं था। इस मायता के अनुसार, चीन ने अपनी नीति को सोवियत 'सम्योतावादी' नीति से भिन्न प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चीन का उद्देश्य स्पष्ट था। यह कि, जहाँ एक ओर सोवियत नीति ने साम्राज्यवादी बेतावनी के आगे समर्पण कर दिया, वही चीन ने दूसरी ओर अपने आत्म विश्वास का परिचय देने का प्रयास किया। चीन स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहता था कि, जहाँ तक एशियाई प्रश्नों की बात है, महाशक्तियाँ भी बिना चीन के कोई कदम नहीं उठा सकती। भले ही ऐसी समय के वास्तविक क्षमतागत आधार चीन के पास नहीं थे, फिर भी इस घटना ने सोवियत नीति को अधिक सक्रिय एशियाई भूमिका सँभार करने को प्रेरित किया।

1963 में पूर्वी जर्मनी में आयोजित साम्यवादी राष्ट्राँ के सम्मेलन तक सोवियत चीन विवाद प्रखर रूप से उभर चुका था। चीन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना का एक 25 सूत्रीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में सोवियत नीति की सवपक्षीय आलोचना करते हुए, विशेषतः उसका इस बात पर निंदा की गई कि स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत नेतृत्व का सम्पूर्ण दृष्टिकोण सगोपनवादी बन गया है। पिछले वर्षों में यह दृष्टिकोण उत्तरोत्तर स्पष्ट हुआ है। चीन ने इस आलोचना के साथ साथ पहलीबार सीमा विवाद का प्रश्न भी उठाया। चीन ने यह मत व्यक्त किया कि इस ओर चीन के बीच 19वीं शताब्दी के बीच अनेक सीमा समझौते हस्ताक्षरों के अन्तर्गत के कारण असमान शर्तों पर हुए थे। अतः 19वीं शताब्दी के इन समझौतों पर पुनर्विचार आवश्यक है सोवियत संघ ने असमानता के इस चीनी दावे का खटन किया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1963 में हुई आणविक परीक्षण संधि की चीन ने तीव्रतम भर्त्सना की। चीन ने इसे विश्व आधिपत्य तथा एकाधिकार की

साजिश कहा, तथा यह स्पष्ट किया कि इसको थोपने के सभी प्रयासों का सक्रिय विरोध किया जायेगा। फरवरी 1963 में सोवियत पत्र 'प्रावदा' ने एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया 'अन्तराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में एकता स्थापित करने हेतु सोवियत पार्टी का सघर्ष'। सोवियत सघर्ष की तरफ से चीन की नीति की यह प्रखरतम सवपक्षीय आलोचना थी। इस लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अन्तराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की एकता के लिये चीन का पथकतावादी दृष्टि कोण सबसे बड़ा खतरा है। अतः समस्त साम्यवादी दलों का यह दायित्व है कि वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों से भटकाव को समझने तथा इस भटकाव के प्रति सक्रिय विरोध द्वारा अन्तराष्ट्रीय सहकार की एकता में विभाजन का रोकें। मतभेदों के इस स्पष्ट और खुले स्वरूप के बाद सोवियत चीन सम्बन्धों में परस्पर आलोचना की स्थिति निरन्तर बनी रही।

सोवियत चीन के उभरते हुये मतभेदों ने एशियाई राष्ट्रों के बीच दोनों की प्रतिद्वन्द्विता का भी घड़ा बना दिया। सोवियत सघर्ष ने 1961 के बाद भारत के साथ और अधिक निकट के सम्बन्ध बनाये। आर्थिक सहायता के साथ सैनिक सहायता की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई। 1962 में ही सोवियत सघर्ष ने भारत को मिग विमान बेचने तथा इन विमानों के उत्पादन के लिये कारखाना लगाने का समझौता किया। एशिया तथा अफ्रीका के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच भारत और सोवियत प्रभाव को कम करने की दृष्टि से चीन भी सक्रिय हुआ। दिसम्बर 1963 में चाउ एन-लाई ने एशिया तथा अफ्रीकी राष्ट्रों का बहुराष्ट्रिय भ्रमण किया। चीन का तात्कालिक उद्देश्य आगामी द्वितीय गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के स्थान पर एक एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्ताव को रखना था। इस बैकल्पिक प्रस्ताव के द्वारा तृतीय विश्व के राष्ट्रों के बीच चीन ने सोवियत तथा भारत के विरुद्ध आयोजन की सम्भावनाओं की तलाश की। चीन को कोई उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रस्तावित गुट निरपेक्ष सम्मेलन यथावत आयोजित हुआ। 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत को सोवियत सघर्ष का परोक्ष समर्थन मिला। चीन ने 'भारतीय प्रतिक्रियावादियों' को दिये गये सोवियत समर्थन की कड़ी निन्दा की। लेकिन ताण्डव द समझौते ने एशियाई सन्दर्भ में एक नई सोवियत भूमिका को प्रकट किया। इस तात्कालिक असफलता के बाद भी चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के प्रयास जारी रखे। इन प्रयासों को उत्तरोत्तर रूप में सीमित सफलता भी मिली।

हिन्द चीन संबंध में सोवियत चीन प्रतिस्पर्धा का स्वरूप गुणात्मक रूप से भिन्न रहा। वियतनाम, कम्बोडिया तथा लाओस आदि में चल रहे जनसघर्षों में चीन और सोवियत सघर्ष दोनों का विवाद का स्वरूप बाह्यित रणनीति के प्रश्न पर अधिक उभरा। 1965 के बाद वियतनाम में अमेरिकी बमबारी तथा सैनिक

हस्तक्षेप में बढ़ोत्तरी हुई। इन स्थितियों में, चीन ने गरिस्ता रणनीति पर अधिक बल दिया तथा साम्राज्यवाद से जिसो भी प्रकार की वार्ता का विरोध किया। इसके विपरीत सोवियत दृष्टिकोण था कि, संपन्न के जारी रहने हृषे, वार्ताओं की सम्भावनाओं में मुह नहीं मोड़ना चाहिये। चीन ने इस सोवियत दृष्टिकोण की बड़ी भत्सना की। लेकिन 1967 में स्वयं वियतनाम ने अमेरिका के साथ वार्ताएं प्रारंभ करने की नीति पर बल दिया। इन प्रयासों को सोवियत संघ का पूरा समर्थन मिला। वार्ताओं के इस निष्पक्ष को गमन बताते हुए चीन ने इसे सोवियत और अमेरिका की किसी जुत्सी साजिश बताया। चीन का प्रचार था कि इस साजिश के द्वारा महापश्चिमी वियतनामी जनता को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर रही है। चीन ने वियतनाम को इस पक्ष में प्रति सचेत रहने की सलाह दी थी सक्रिय चीन समर्थन का आश्वासन भी। वियतनामी नेतृत्व ने मूसलूय का परिचय दिया तथा दोनों राष्ट्रों के प्रति अपनी वृत्तज्ञता व्यक्त करत हुए अपने आपको सोवियत चीन विवाद में सीधे रूप से नहीं जलपने दिया।

रुद्धचेष्ट के नेतृत्व के पतन के बाद चीन और सोवियत संघ के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के आशिक प्रयास हुए। ग्रैमनेव नेतृत्व ने चीन का आह्वान किया कि चीन दोनों राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रयत्न करे तथा समाजवादी गुट की एकता का मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे। इसके बाद दोनों राष्ट्रों में सीमाविवाद पर वार्ताओं का एक सीमित दौर चला। इन वार्ताओं में कोई भी समझौता नहीं हो सका। इसी वर्ष चीन ने प्रथम आणविक परीक्षण किया था। अतः इन वार्ताओं में भी उसने अपनी क्षमता से उभरी दृढ़ता को व्यक्त किया। वार्ताओं के विफल होने के बाद सोवियत नेतृत्व ने यह घोषणा की कि उसने चीन के साथ सम्झौता को सामान्य बनाने के भरसक प्रयास किये लेकिन चीन की नीति हठधर्मी बनी रही। इसके बाद सोवियत संघ की नीति चीन के प्रति उग्रतर बन गई। चीन में आंतरिक "सांस्कृतिक क्रांति" का प्रभाव इस दौरान अपने चरम पर था। इस द्वाचरिक मयन में चीन की दृष्टि सोवियत संघ के प्रति और अधिक वमनस्यकारी बनी। चीन की पार्टी में कुछ लोग सोवियत संघ के साथ सबंधों के सामान्यीकरण के भी पक्षधर थे। इनकी मान्यता थी कि हिंद चीन में बढ़ती हुई अमेरिकी उग्र नीति को देखते हुए सोवियत संघ के साथ सबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिये। ऐसे दृष्टिकोण का उग्र प्रतिरोध हुआ, जिसके फलस्वरूप चीन के सेनाध्यक्ष को पदमुक्त कर दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हुई उग्रवादी घटनाओं में, जनवरी, 1967 में बीजिंग स्थित सोवियत दूतावास की नाकेबंदी कर दी गई। इस घटना ने सोवियत चीन सम्बन्धों में और अधिक वमनस्य पदा किया। फरवरी में सोवियत दूतावास में बम कर रहे बमचारियों को हटा लिया गया और चीन ने भी सोवियत संघ में पठ रहे सभी चीनी विद्यार्थियों

पिया को वापस बुला लिया।

1968 के बाद सोवियत चीन सम्बन्धों में वैमनस्य की चरम स्थिति का उत्पन्न हुई। 1968 में रूस द्वारा चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप की चीन में उग्रतम प्रतिक्रिया हुई। चीन में इस धारणा को सोवियत सभ्यता की घड्यत्रकारी नीति का प्रबलतम प्रमाण कहा। यह एक विचित्र स्थिति थी। क्योंकि, 1956 में जब हंगरी में इसी प्रकार का सोवियत बंदम उठाया गया था तब चीन ने उस सन्निय समर्थन दिया था। यही नहीं उस घटना के दौरान चीन ने यह दावा भी किया था कि, सोवियत सभ्यता हंगरी में हस्तक्षेप के लिये क्षिप्त रह रहा था तथा उसकी सन्निय प्रेरणा के पल्लवस्वरूप ही सोवियत सभ्यता हंगरी में बंदम उठाने की तैयार हुआ था। चीन की नीति में इस विरोधाभास ने चीन को एक नये विश्व दृष्टिकोण की समझ तैयार करने को प्रेरित किया। चेकोस्लोवाकिया विवाद के समानांतर सोवियत-चीन सीमा पर भी तनाव में वृद्धि हुई। इसकी चरम परिणति 1969 में हुई। सोवियत और चीन के बीच उस्सुरी नदी तथा दमस्की द्वीप पर प्रथम बार सीमा विवाद को लेकर सैनिक झड़पें हुई। सैनिक झड़पें सीमित होत हुये भी उग्र थी। इस घटना ने दोनों राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों को अमृतपूव रूप से कटु बनाया। सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए वार्ताएं प्रारम्भ हुई। लेकिन वार्ताओं की दृष्टान्त तो दूर, वार्ताओं को आयोजित करने की कार्यविधि तक पर कोई आम राय नहीं बन पाई। चीन की यह मायता थी कि वार्ताओं में इस बात को आधार माना जाये कि 19वीं शताब्दी के दौरान हुई संधियाँ असमान थी। सोवियत मत था कि ऐसे किसी पूर्वाधार को वार्ताओं का आधार बनाना—निम्सार है जेम्स कोई सफल परिणाम नहीं निकले।

पिछले दशक के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सोवियत-चीन सम्बन्धों में बदलाव बने। वैचारिक विवाद ने अन्तर्गत क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की जन्म दिया। साथ ही साथ, मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण के अभाव में सीमा विवादों में जटिल बन गया। चीन का विकास एक स्वतंत्र आणविक शक्ति के रूप में हुआ, जिसने सोवियत-चीन सम्बन्धों के साथ साथ विश्व स्तरीय सम्बन्धों के सम्बन्ध में भी नये अन्तिम प्रायो और आवश्यकताओं को जन्म दिया। इस चरण के अन्तिम वर्षों में, चीन के एक नये विश्व दृष्टिकोण का विकास हुआ। इस दृष्टिकोण ने सोवियत-चीन सम्बन्धों को वैचारिक आधार पर अधिक प्रदीप्त बनाया। लेकिन साथ ही साथ नये विश्व सतुलन की दृष्टि में, दोनों देशों के बीच एक टकरावट म्यन्त्रियों में भी कमी आई। ये मिश्रित प्रवृत्तियाँ अपने चरण में उद्घाटित हुई।

चीन-अमेरिका सम्बन्ध अपरिनायित टह्णव (1959-1969)

चीन अमेरिका सम्बन्धों का यह द्वितीय चरण एक अन्तिम चरण है।

का युग कहा जा सकता है। दोनों राष्ट्रों के बीच टकराव की स्थितिया रही, तथा साथ ही साथ वार्ताओं का एक औपचारिक प्रभ भी बना रहा। करीब एक दशक के अंतराल के बाद राजदूत स्तरीय वार्ताएँ पुन प्रारम्भ हुई। इन वार्ताओं के दौरान परस्पर विचार विनिमय से अधिक कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों में परस्पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। कुल मिला कर संबंधों में न तो कोई विशेष गिरावट ही आयी और न ही कोई सकारात्मक स्वरूप उभरा। निरंतर एक ठहराव की स्थिति बनी रही।

केनेडी के नेतृत्व के दौरान अमेरिकी विदेशनीति में कुछ नई मानसिकताएँ भी उभरी। इन विभिन्न मतों का अभिप्राय मूलतः चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना नहीं था। प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के प्रश्न को एक नई योजना के तहत संचालित करना था। केनेडी प्रशासन के दौरान दो चीन के सिद्धांत का मन भी उभरा। चीन का अस्तित्व एक वास्तविकता थी तथा ताइवान को बनाय रखना भी प्रमुख उत्तरदायित्व था। इस दृष्टि यह विचार उभरा कि दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अमेरिकी नीति की रूप रत्ना बनाई जावे। ऐसे प्रस्ताव की चीन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई जिसमें कहा गया कि यह प्रस्ताव चीन की क्षेत्रीय अखण्डता का विरोधी है तथा अमेरिका की एक चालाकी भरी साजिश है। चीन की समुक्त राष्ट्र सच की सदस्यता पर भी एक नई व्यावहारिक नीति तैयार की गई। उत्तरोत्तर रूप से अमेरिका को यह स्पष्ट हो रहा था कि चीन की सदस्यता के पक्ष में विश्व जनमत बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा बार बार 'वीटो' का प्रयोग आलोचना का केन्द्र बन गया था। अतः अमेरिका ने एक प्रस्ताव द्वारा यह पारित करवाया कि चीन की सदस्यता का मामला एक "महत्वपूर्ण प्रश्न" है। इस प्रस्ताव का तात्पर्य था कि, इस प्रश्न पर निर्णय के लिये दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता बन गई। अब कुछ और वर्षों तक अमेरिका, बिना 'वीटो' का प्रयोग किये चीन की सदस्यता को रोकने में सक्षम बन गया था। जहाँ तक दोनों राष्ट्रों के बीच सीधे सम्पर्क की बात थी, अमेरिका ने राजदूत स्तरीय वार्ताओं को पर्याप्त माना तथा इसके स्तर को बढ़ाने की बात पर बल नहीं दिया।

छठे दशक के प्रारम्भ में चीन में खाद्यान्न आदि की धिक्क समस्या उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप हांगकांग के इलाके में चीनी शरणार्थियों की समस्या भी उभरी। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा, क्योंकि इस घटना को लेकर ताइवान ने चीन के विरुद्ध सक्रिय प्रचार प्रारम्भ किया। तनाव की स्थिति में बीच अमेरिका का भावना जहाँजी बड़ा बड़ा तैनात हुआ। इसी के साथ साथ अमेरिका ने यह प्रस्ताव भी रखा कि, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए, अमेरिका चीन को खाद्य सहायता दे सकता है। चीन द्वारा इसकी उग्रतम प्रतिक्रिया हुई जिसमें

अमेरिका के इस प्रस्ताव की चीन के आत्म सम्मान के अपमान की साजिश कहा गया। चीन की गेरिल्ला रणनीति के विरुद्ध सफलता के लिए कनेडी प्रशासन ने यह मत व्यक्त किया कि अमेरिकी सेनावा को भी गेरिल्ला लड़ाई का प्रशिक्षण दिया जाये। इस नई सैनिक सक्रियता की आलोचना करते हुये चीन ने इसे अमेरिका का हास्यास्पद प्रयास बताया। अमेरिका और रूस के बीच आणविक परीक्षण संधि की भी तीव्रतम भत्सना की गई। 1963 के एक 'सम्पादकीय म' चीन ने इस संधि को पड्यत्र बताया जिसके द्वारा साम्राज्यवाद अपनी कुचेष्टाओं पर आवरण डालना चाहता था। चीन ने मांग की कि यदि वास्तव में निःशस्त्रीकरण लागू करना है तो आणविक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिये, तथा इस हेतु सभी राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाये। 1963 के दौरान ब्यूबा घटना के बाद पुनः सोवियत अमेरिका सम्बन्धों के सामान्य बनने की प्रक्रिया को चीन ने विचित्र स्थिति कहा। ब्यूबा अनुभव के बाद भी यदि अमेरिका सोवियत उद्देश्यों को शांतिप्रिय मानता है तो, चीन की दृष्टि में, यह अमेरिका का बहुत बड़ा मुलावा है। इन विभिन्न आरोपों प्रत्यारोपों के बीच राजदूत स्तरीय वार्ताओं में भी कुछ कमी आई।

अक्टूबर 1964 में चीन का प्रथम परीक्षण हुआ। इस परीक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जानसन ने इसकी भत्सना की तथा साथ ही साथ इस कदम द्वारा चीन की आणविक शक्ति बनने की इच्छा का मजाक भी उड़ाया। राजदूत स्तरीय वार्ताओं में चीन द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि वह आणविक हथियारों का "प्रथम प्रयोग न करने" हेतु अमेरिका के साथ समझौता करने को तैयार है। अधिक आणविक क्षमता वाले अमेरिका ने इस प्रस्ताव को एकदम ठुकरा दिया। इस बीच अमेरिकी नीति में डलैस की यह मायता कि चीन में साम्यवाद अपने आंतरिक अन्तर्विरोधों के कारण स्वयं ही खत्म हो जायेगा पूर्ण रूप से अस्वीकृत हुई। ऐसी अमेरिकी समझ चीन की दृष्टि में ऐतिहासिक रूप से स्वाभाविक थी। अतः चीन ने इस समझ का मजाक उड़ाया और इसे अमेरिकी नीति की दया नहीं अपितु विवशता बताया।

वियतनाम युद्ध में बड़े हुए अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप ने चीन-अमेरिका संबंधों में निरंतर गिरावट की स्थितियां उत्पन्न की। आंतरिक वैचारिक विवाद के बाद चीन ने सोवियत संधि के साथ सम्बन्ध सुधारने के विचार को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। साथ ही साथ अमेरिका के प्रति भी एक उग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। सितम्बर 1965 में लिन पियाओ ने एक विस्तृत लेख में गेरिल्ला नीति को माओ का ऐतिहासिक योगदान बताया इस लेख में कहा गया कि साम्राज्यवाद का आतंक पाहे जितना बढ़े, माओ की क्रांतिकारी गेरिल्ला नीति के कारण अतंत वियतनामी जनता की विजय और साम्राज्यवाद की पराजय निश्चित है। कोरिया युद्ध

के अनुभवों के आधार पर चीन को यह आशंका थी कि वही अमेरिका द्वारा उस पर आक्रमण न हो। ऐसी स्थिति में चीन द्वारा अमेरिका को निरंतर चेतावनी दी जाने लगी। चीन के विदेश मंत्री चेन यी ने अमेरिका को चेतावनी दी कि, यदि अमेरिका की चीन पर आक्रमण की कोई योजना है तो ऐसा बन्धु अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। यदि एक बार अमेरिका चीन की घरती पर आया तो गेरिल्ला रणनीति के फलस्वरूप उसका निव्वलन असम्भव हो जायेगा। मार्च, 1966 में अमेरिका के राज्य सचिव डीन रस्क 3 एक दस सूत्रीय चीन नीति के प्रारूप को प्रस्तुत किया। इस प्रारूप में प्रमुख रूप से कहा गया कि, अमेरिका द्वारा चीन पर आक्रमण करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन, यदि उसके मित्र ताइवान पर कोई सकट आता है तो अमेरिका अपने दायित्व को निभाने में दूर नहीं रहेगा। अमेरिकी नीति इस वक्तव्य के अनुसार, चीन के साथ संबंध सुधारने की ही है। लेकिन अमेरिका मंत्री का ऐसा कोई कदम नहीं उठायेगा जो उसके मित्र राष्ट्रों को आशंकित करे तथा ऐसा आभास दे कि अमेरिकी नीति चीनी उपद्रवादिना को कोई पुरस्कार दे रही हो। इस वक्तव्य में एशियाई राष्ट्रों की अधिक आर्थिक सहायता आदि देने की बात भी कही गई जिससे उन्हें साम्यवाद के खतरे से लड़ने के लिये सुदृढ़ बनाया जा सके।

अमेरिकी नीति के प्रत्युत्तर के रूप में 10 मई 1966 का चाऊ एन साई ने एक 4 सूत्रीय नीति की घोषणा की। इस घोषणा के पिछले तिन का तीसरा आणविक परीक्षण हुआ था जो कि हाईड्रोजन बम के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम था। इन चार सूत्रों में प्रमुख रूप से यह वक्तव्य किया गया कि चीन अपनी ओर से कोई वैमनस्य बढाना नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका के साथ सम्बंध सामान्य होने के लिए ताइवान विवाद का सुलझना एक प्राथमिक बात है। चीन इस प्रश्न पर कोई समझौतावादी नीति नहीं अपना सकता क्योंकि इस प्रश्न को सुलझाने के लिये वह बातों को माध्यम का भी प्रयोग करेगा। चाऊ एन साई की घोषणा का अर्थ प्रमुख तत्त्व यह था कि वह अमेरिका की भावी हस्तक्षेप के प्रति खुली चेतावनी देता। इस दृष्टि से यह कहा गया कि चीन की कचनी ओर करनी मफक नहीं है। यदि उस पर आक्रमण हुआ तो मुह तोड़ जवाब भी दिया जायेगा और ऐसी स्थिति में युद्ध की सीमाएं बसा होंगी यह अमेरिका पर निभर नहीं करेगा। चीन का अनुभव भाओ की गेरिल्ला नीति की निरंतर सफलता का अनुभव है। भाओ सकट में भी इसी नीति के द्वारा साम्राज्यवाद को मुह तोड़ जवाब मिलेगा। आणविक परिसीमन के प्रश्न पर चीन ने "प्रथम प्रयोग न करने" के समझौते की बात दोहराई। अमेरिका की प्रतिनिधिता थी कि, ऐसा समझौता तभी सम्भव है जब चीन आणविक परिसीमन सचि में भी प्रतिबद्ध होने को तैयार हो। चीन ने इस प्रस्ताव को एकदम ठुकरा दिया।

वियतनाम युद्ध के दौरान एक लम्बे समय से चली आ रही राजदूत स्तरीय वार्ताओं पर भी विराम लगा। अमेरिका के साथ वार्ताओं की आलोचना करते हुए सोवियत संघ ने यह प्रचार किया कि चीन की नीति दोगली है। एक तरफ चीन क्रांतिकारिता के भाषण देता है और वियतनाम को उग्र नीति के लिये उकसाता है, तो दूसरी ओर वह अमेरिका के साथ अपनी वार्ताओं में भी लगा हुआ है। ऐसी सोवियत आलोचना की चीन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। चीन ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि उसने वार्ताओं की गोपनीयता को मग किया है। अमेरिका और रूस की मिसीभगत है जो कि सोवियत संघ के बेहूद प्रचार से व्यक्त होती है। अतः 7 सितंबर, 1966 को राजदूत स्तरीय वार्ता की 131वीं बैठक में चीन के राजदूत न माओ के आदेश पर इन वार्ताओं को एक-पक्षीय रूप से खत्म करने की घोषणा की। इस घोषणा के प्रस्ताव में वार्ताओं के पिछले 17 वर्षों के अनुभव को इस बात का साक्ष्य कहा गया कि अमेरिकी नीति निरंतर उग्रवादी तथा पडयंत्रकारी रही है। उसने चीन के साथ सम्बंध सुधारने की थोड़ी घोषणाओं की आड़ में चीन विरोधी सक्रियता को निरंतर उकसाया है। वियतनाम के तात्कालिक अनुभव इसके साक्ष्य हैं। अतः इन वार्ताओं की कोई सायकता अब नहीं रही है। माओ के आदेशों के अनुसार वार्ताएं खत्म की जाती हैं और साम्राज्यवाद को यह चेतावनी दी जाती है कि तमाम उग्रवादिता के बावजूद वह मात्र एक कामजी शेर है। जनवादी आन्दोलन के सामने साम्राज्यवाद की पराजय निश्चित है।

वियतनाम युद्ध की इन चरम अभिव्यक्तियों से, चीन अमेरिका सम्बंधों में एक लम्बा अवरोध उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति जॉनसन के शासन के अंतिम वर्षों में अमेरिका चीन सम्बंधों में सामायीकरण के समस्त प्रस्ताव विफल रहे। इस बीच वियतनाम विवाद के सन्दर्भ में अमेरिका तथा चीन दोनों की स्थिति विचित्र हुई। चीन के उग्रवादी उपदेशों के बावजूद वियतनाम ने वार्ताएँ प्रारम्भ करने के सोवियत परामर्श को अधिक व्यावहारिक माना। अमेरिका के अनुभव भी वियतनाम विवाद में अत्यधिक कटु और असफल रहे। उग्र सैनिक हस्तक्षेप और बमबारी के बावजूद अमेरिका समर्थित दक्षिणी वियतनाम को सफलता नहीं मिल सकी। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका को अत्यधिक सैनिक खर्च उठाना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय जनमत भी अमेरिकी कायवाही के विरुद्ध में उग्ररूप से व्यक्त हुआ। साथ ही साथ आंतरिक जनमत का विरोध भी आयोजित हुआ और यह मांग उठी कि अमेरिका को दक्षिणी वियतनाम के पक्ष में अपनी सैनिक सशक्तता को खत्म करना चाहिए। इसी मानसिकता का पक्ष लेते हुये, रिचर्ड निक्सन ने अपना चुनाव अभियान आयोजित किया। निक्सन की विजय के साथ अमेरिकी नीति में विद्यस्तराय तनाव कम करने की प्रवृत्ति उभरी। अमेरिका चीन सम्बंधों में भी, इन बदले

हुये सदस्यों के साथ एक नये चरण का सूत्रपात हुआ ।

तृतीय चरण 1969 से 1979

त्रिकोणात्मक समीकरण की गतिशीलता

"सांस्कृतिक क्रांति" के अनुभव चीन के लिए मिश्रित अभिप्राय वाले रहे । एक लम्बे आन्तरिक मथन की प्रक्रिया में चीन की व्यवस्था में तथान्वित वैचारिक सुदृढीकरण का हुआ लेकिन आधुनिक विकास की दृष्टि से चीन समय के साथ नहीं चल पाया । "सांस्कृतिक क्रांति" के दौरान ही अनेक वैचारिक विवाद उभरे, लेकिन माओ की दृष्टि निरन्तर सघन के बाद विजयी हुई । जहाँ तक पार्टी में आन्तरिक सुधार तथा एकता स्थापित करने का प्रश्न था, पुराने तत्व तो खरम हुये, लेकिन मतभेदों के नये दायरे उभरने लगे । इस बार का विवाद पहले के विवादों की तुलना में न सिर्फ गुणात्मक रूप से भिन्न था, अपितु उत्तर भी । पार्टी के विभिन्न अंगों का क्या योगदान हो, जन संघर्ष का विकास की प्रक्रिया में कितना तथा कैसा योगदान औचित्यपूर्ण है औद्योगिक केन्द्रों में स्वायत्त 'कम्यून' व्यवस्था पर पार्टी के निरीक्षण का क्या स्वरूप हो, औद्योगीकरण में तकनीकी शास्त्रांग और राजनीतिक दृष्टि के हस्तक्षेप के बीच सन्तुलन का आधार कैसा हो, तथा आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं का क्या व्यावहारिक स्वरूप हो, आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको "सांस्कृतिक क्रांति" की प्रक्रिया ने तीव्र रूप से प्रस्तुत किया । प्रश्न तो परिभाषित थे, लेकिन अंतिम विकल्प के निश्चय होने से थे । इस आवश्यकता ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में नये दृष्टिकोण की एक नई बहस को जन्म दिया ।

1969 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 9वाँ अधिवेशन ऐतिहासिक महत्व का कहा जा सकता है । अधिवेशन में 'सांस्कृतिक क्रांति' की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की गई । साथ ही साथ सांस्कृतिक क्रांति के अनुभवों की खूबी समीक्षा भी हुई, जिसमें नीतियों के साथ साथ व्यावहारिक स्तर पर उनके क्रिया-वर्धन के पक्ष को भी समीक्षित किया गया । कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की गिरावट, तथा उद्योगों के पिछड़े तकनीकी आधार पर चिन्ता व्यक्त हुई । अधिवेशन के दौरान वैचारिक बहस भी मुख्यतः आन्तरिक विकास के कार्यक्रमों पर केन्द्रित रही । आधुनिकरण के प्रश्न को यद्यपि उत्साहवर्धक मायता नहीं दी गई, फिर भी इसकी आवश्यकता को देखते हुए उस एक सन्तुलित स्वरूप में स्वीकार किया गया । विकास कार्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रश्न को पहले के उग्र दृष्टिकोण से नहीं देखा गया । यहाँ पर भी एक समन्वित विचार को बल मिला, जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तो लिया जाये, लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ । अतः जहाँ तक आन्तरिक विकास की दृष्टि का विवाद था, इस नवें अधिवेशन से एक मिश्रित मानसिकता उभरी । एक ओर जहाँ पहले के अति

क्रांतिकारी तथा अतमुखी दृष्टिकोण पर विराम लगा, वही दूसरी ओर बदलाव की मानसिकता को भी उग्र अभिव्यक्ति नहीं मिल सकी। एक नये दृष्टिकोण का सहमा हुआ सा प्रथम कदम उठाया गया।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस नवें अधिवेशन का महत्व इस बात से आकांक्षित जा सकता है कि इसने एक बदलाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की। इसके बाद के वर्षों में आधुनिकीकरण का प्रश्न अधिकाधिक महत्व का बनता गया। 1973 में हुये पार्टी के 10वें अधिवेशन में यह दृष्टिकोण और अधिक मुखरित हुआ। इसके साथ ही आधुनिकीकरण का विवाद पार्टी का प्रमुख विवाद बन गया। माओ के नेतृत्व के दौरान ही लिनपियाओ का पतन हुआ। इसके बाद उग्रवादी प्रवृत्तियों को नेतृत्व स्वयं माओ की पत्नी चिंगच्यान ने दिया। लेकिन आधुनिकीकरण के पक्षधर विचार को अधिक बल मिला। स्वयं माओ की तरफ से आधुनिकीकरण के प्रश्न पर किसी तीव्र और खुली आलोचना का अभाव इस बात का परिचायक कहा जा सकता है। पार्टी के 10वें अधिवेशन के बाद, आधुनिकीकरण के प्रश्न की स्पष्ट मायता तो मिली लेकिन विवाद भी यथावत बना रहा। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद यह विवाद एकाएक उग्र बन गया। माओ की पत्नी के नेतृत्व में आयोजित 'चौकड़ी' का एक सीमित समय तक प्रभाव रहा। सीमित होत हुये भी यह अत्यधिक उग्र रहा। 1977 में "सांस्कृतिक क्रांति" के दौरान अपदस्थ जेंग सियाओ पिंग की पार्टी के 11वें अधिवेशन में पुनर्स्थापना हुई इसी के साथ आधुनिकीकरण के पक्षधर विचार को एक स्थाई स्वीकृति भी मिली।

11वें अधिवेशन के बाद निरंतर आधुनिकीकरण के व्यावहारिक पक्षों को परिभाषित किया गया। आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुये "चार आधुनिकीकरण" की व्याख्या हुई—उद्योग, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विज्ञान एवं तकनीकी। इस बदलती दिशा को एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य भी दिया गया। अतः राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा करते हुये, यह मत व्यक्त किया गया कि साम्राज्यवाद के शोषण के आर्थिक आधार अत्यधिक कमजोर बन गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में उनके साथ सहयोग की प्रक्रिया द्वारा आंतरिक आर्थिक म्वायमता को कोई खतरा नहीं है। स्वयं साम्राज्यवाद विकट आर्थिक संकट में पड़ा है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी शर्तें थोपने में सक्षम नहीं है। एक नई व्याख्या के अनुसार यह भी व्यक्त किया गया कि, उत्पादन की क्षमता का तथा विज्ञान विज्ञान एवं तकनीक का कोई बग आधार नहीं होता। बग आधार उत्पादन की क्षमताओं के उपयोग की व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं। उन साम्राज्यवादी राष्ट्रों से भी आधुनिकीकरण की आवश्यकता के लिए यदि गंगा मज्जोग मिया जाये तो वैचारिक दृष्टि से वह अनौचित्यपूर्ण नहीं होगा। चीन का यह दृष्टिकोण एक समये समय से चले आ रहे सोवियत दृष्टिकोण के समदृष्ट का। विज्ञान में ऐसे

दृष्टिकोण के लिये सोवियत संध की आलोचना हुई थी। आज स्वयं चीन इस दृष्टिकोण का पक्षधर बन गया था "सांस्कृतिक क्रांति" के बाद वैचारिक विवाद मात्र वैचारिक सन्दर्भों वाला नहीं रहा। वैचारिक विवाद विकास के अभिप्रायों से जुड़ गया। इसी से एक नया दृष्टिकोण उभरा।

चीन का विश्व-दृष्टिकोण

आन्तरिक विकास की प्राथमिकताओं के फेरबदल तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी बदलत हुए सन्दर्भों के बीच चीन के विश्व-दृष्टिकोण का एक नया स्वरूप उभरा। आन्तरिक विकास की आवश्यकताओं की समीक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्तियों को भी रेखांकित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा में चीन की दृष्टि में तीन बातें प्रमुख महत्व की थी। प्रथम, तृतीय विश्व द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता के संधर्ष तथा हस्तक्षेप की उग्रवादी नीति के कारण साम्राज्यवादी व्यवस्था के आर्थिक आधार भंगकर सफट से प्रस्त हैं। इस आर्थिक सफट के फलस्वरूप, साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच भी अमेरिकी सर्वाभ्यता को चुनौती मिली है। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों तथा अमेरिका के बीच आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद उत्तरोत्तर विकसित हुये हैं। द्वितीय, विपत्तनाम के संधर्ष में जनवादी शक्तियों की विजय ने साम्राज्यवाद की उग्र हस्तक्षेप की नीति को पूर्णतया आत्मघाती सिद्ध कर दिया है। संधर्ष की रणनीति के स्तर पर भी, परम्परागत सैनिक युद्ध की नीति पर गेरिल्ला प्रणाली की विजय भी सिद्ध हुई है। अमेरिकी साम्राज्यवाद इन विपरीत अनुभवा के बीच भावी हस्तक्षेप के प्रति प्रेरित होने में कतरा रहा है। तृतीय, चेकोस्लोवाकिया अनुभव एक अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व का है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई सोवियत उग्रवादिता का परिचायक है। सोवियत संध सशोषणवादी नीतियों के बाल में साम्राज्यवाद से मिली भगत की नीति से कहीं अधिक दुराग्रही बन गया है। सशोषणवादी प्रवृत्तियों ने साम्राज्यवादी विस्तार के आधार तैयार कर दिये हैं। इस बदली हुई स्थिति में सोवियत नीति साम्राज्यवाद में मिली भगत की नहीं अपितु साम्राज्यवाद से खुली प्रतिस्पर्धा की बन गई है। सोवियत शक्ति का उग्र अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नये गुणात्मक चरण का परिचायक है। इस समीक्षा के प्रमुख अभिप्राय के फलस्वरूप, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संधर्ष को 'शोधित जनता' की लड़ाई के स्थान पर "शोधित राष्ट्रों" की लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। 1969 में नव वर्ष के अवसर पर एक "सपादकीय" में माओ का हवाला दते हुये इस बदलाव को रेखांकित किया गया। यह व्यक्त किया गया कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संधर्ष उग्र होंगे, लेनिन पहने की तुलना में उनका प्रारूप कुछ भिन्न होगा।

इस बदलाव की प्रक्रिया को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 1969 में हुये 9वें अधिवेशन में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। विश्व राजनीति की समीक्षा करते हुये, चार प्रमुख अंतर्विरोध रेखांकित किये गये—(1) शोषित राष्ट्रों तथा साम्राज्यवाद एवं 'समाजवादी' साम्राज्यवाद के बीच, (2) विश्व सवहारा तथा साम्राज्यवादी एवं सशोधनवादी राष्ट्रों के बुजवा वर्ग के बीच, (3) साम्राज्यवाद तथा समाजवादी साम्राज्यवाद के बीच, साथ ही साथ, साम्राज्यवादी राष्ट्रों में एक दूसरे के बीच, (4) समाजवादी राष्ट्रों तथा साम्राज्यवाद एवं 'समाजवादी' साम्राज्यवाद के बीच। इन विभिन्न अंतर्विरोधों में पहला अंतर्विरोध, अर्थात् सभी राष्ट्रों तथा साम्राज्यवाद एवं समाजवादी साम्राज्यवाद के बीच का अंतर्विरोध, प्राथमिक महत्व का है। अतः सभी राष्ट्रों को साम्राज्यवाद तथा 'समाजवादी' साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिये। उक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि चीन के विश्व दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन हुये। सोवियत संघ को अब मात्र सशोधनवादी ही नहीं कहा गया अपितु उसे साम्राज्यवादी संज्ञा भी दी गयी। इससे पूर्व चीन के दृष्टिकोण में अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया, अफ्रीका तथा सातवीं अमेरिकी जनसमुदाय की एक जुटता का प्रारूप था। अब साम्राज्यवाद तथा समाजवादी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अब सभी का एक जुटता का प्रारूप तैयार हुआ इस प्रारूप का आधार "शोषित जनता" नहीं अपितु, "शोषित राष्ट्र" बने। एक अन्य प्रमुख अभिप्राय जो कि स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त नहीं किया गया, यह था कि समाजवादी गुट के नेतृत्व के साम्राज्यवादी बन जाने के बाद समाजवादी गुट की मान्यता अस्तित्व बिहीन हो गई है।

इस नये विश्व दृष्टिकोण के अनुरूप व्यावहारिक पक्षों को 1973 में हुये 10वें अधिवेशन में और अधिक स्पष्ट किया गया। 10वें अधिवेशन में व्यक्त विचारों में निम्न बातें प्रमुख थीं। पहली, 9वें अधिवेशन में व्यक्त चार प्रमुख अंतर्विरोधों को स्पष्ट रूप से पुनः व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन उसकी मान्यता के अभिप्राय यथावत बने रहे। साथ ही साथ शोषित राष्ट्रों एवं जनता को सक्रिय समर्थन की बात भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं हुई। दूसरी 9वें अधिवेशन के बाद हुई अनेक राजनयिक उपलब्धियों को रेखांकित किया गया जिनमें संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और पश्चिमी राष्ट्रों से सम्बंधों में सामान्यीकरण का विशेष उल्लेख था। इस समीक्षा के दौरान विगत में हुए दो गुणात्मक रूप से भिन्न भटकावों को रेखांकित किया गया। इस संदर्भ में व्यक्त किया गया कि लियु शाओ ची का बुजवा वर्ग के साथ गठबंधन और त्रासिकारी सचप का मुला देने का दृष्टिकोण गलत था, साथ ही साथ लिन पियाओ का यह मत कि अतित्रासिकारी दृष्टिकोण में बुजवा वर्ग के साथ सभी प्रकार के समय-समय को त्याग देना चाहिये, भी

दूसरा गुणात्मक भटकाव था। दोनों ही दृष्टिकोण अतिवादिता से प्रस्त रहें। अतः इनकी बदलना एक समन्वित दृष्टि के लिये आवश्यक है। तीसरी, तात्कालिक नीति के स्तर पर तृतीय विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों में आंतरिक क्रांति के संघर्षों पर कम बल दिया गया। इन राष्ट्रों को साम्राज्यवाद या और 'समाजवादी' साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रेरित करना एक तात्कालिक आवश्यकता है। तृतीय विश्व के राष्ट्रों में ऐसी सम्भावना की बात, विगत में इन राष्ट्रों को दी गई प्रति क्रियावादी राष्ट्रों की सज्ञा से गुणात्मक रूप से भिन्न स्थिति था। इसी सन्दर्भ में वामपंथी पार्टियों के साथ संबंधों की तुलना में राज्य स्तरीय सम्बंधों की नीति को अधिक तात्कालिक उपयोगिता का कहा गया। अतिम रूप में, इन अनेक व्यावहारिक बदलावों को वैचारिक तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी दिया गया। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर लेनिन के विचारों को उद्धृत किया गया। यह व्यक्त किया गया कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत अपना आप में गलत नहीं है। इसके गलत अथवा सही होने का प्रश्न निश्चित ऐतिहासिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। स्टालिन और लेनिन के नेतृत्व में इस सिद्धांत का आचरण सही था। ऐसी ही सन्दर्भ आज चीन के आचरण के आधार हैं।

नव परिभाषित विश्व दृष्टिकोण में 10वें अधिवेशन के बाद, सोवियत संघ की अग्रिम उग्र खतरे के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। इस सन्दर्भ में यह मायता व्यक्त की गई कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप साम्राज्यवादी अमेरिका की तुलना में 'समाजवादी' साम्राज्यवादी सोवियत संघ की क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है। छठा दशक अमेरिकी हस्तक्षेप का दशक था। सातवा दशक सोवियत विस्तारवादी आतंक का दशक है। साम्राज्यवादी क्षति निरंतर गिरती हुई क्षमता वाली है जबकि 'समाजवादी' साम्राज्यवादी सोवियत संघ उभरती हुई शक्ति है। अतः विश्व शांति के लिये सोवियत संघ अधिक बड़ा खतरा है। इस सन्दर्भ में सोवियत संघ की नीति को पुराने साम्राज्यवादियों की नीति से कहीं अधिक पड़पड़कारी बताया गया। कहा गया कि, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की सोवियत और चीनी मायता में गुणात्मक अंतर है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का दो स्तरों पर प्रयोग होना चाहिये—विश्व शांति के स्थायी प्रारूप के लिये, और साथ ही साथ क्रांतिकारी संघर्षों का बढ़ावा देने के लिये। सोवियत नीति में, चीन के अनुसार दूसरे दृष्टिकोण का अभाव है।

इस विश्लेषण के आधार पर, चीन के "तीन विश्व" के सिद्धांत की स्पष्टतम परिभाषा 1974 में हेंग सियाओपिंग के समुक्त राष्ट्र संघ में दिये गये वक्तव्य से मिलती है। इस प्रारूप के अनुसार निम्न वर्गीकरण किया गया—1. प्रथम विश्व, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ हैं। इन महाशक्तियों ने अधिसत्त्व का एकाधिकारवादी पूँजीवाद समान आधिकार आधार है। अतः महाशक्तियों का बणन व्यवहार पर नहीं

अपितु वग चरित्र पर आधारित है। ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से आगामी वर्षों में सोवियत सघ अधिक खतरनाक चुनौती है, (2) द्वितीय विश्व, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के सभी विकसित राष्ट्र किसी एक महाशक्ति के नियंत्रण में हैं, लेकिन नियंत्रण का स्तर एक सा नहीं है। इनमें से कुछ किसी न किसी रूप में औपनिवेशिक सम्बन्धों को भी बनाये हुये हैं, (3) तृतीय विश्व, जिसमें चीन सहित एशिया अफ्रीका तथा साततिनी अमेरिका के सभी क्षोणित राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों के बीच जकता का कोई वग आधार नहीं है। लेकिन महाशक्तियों का आतंक इहे एक सूत्र में बाधता है। आर्थिक स्तर पर पिछडे होने के कारण, कच्चे माल पर आधारित इनकी अव्यवस्थाएँ इहे आर्थिक स्वायत्तों के स्तर भी एक बनाती है। इनकी शक्ति इस बात से है कि ये अपने ससाधनों पर स्वतन्त्र नियंत्रण बनाये रखें और बाहरी पूँजी के हस्तक्षेप का विरोध करें। विश्व का प्रमुख अतर्विरोध प्रथम विश्व एवं तृतीय विश्व के बीच है अतः द्वितीय विश्व के राष्ट्रों को महाशक्ति आतंक से स्वतन्त्र होने के लिए तृतीय विश्व के साथ एक जुटता बनानी चाहिए। उसी में उनका दूरगामी हित है।

उपरोक्त विवेचन के बाद चीन ने अपने विश्व दृष्टिकोण को एक नारे के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया—“राज्यों की स्वतन्त्रता, राष्ट्रों की मुक्ति और जनता की क्रांति चाहिए” इस नये नारे के द्वारा चीन ने अपनी नीति में राज्यों की स्वतन्त्रता का एक नया पक्ष जोड़ दिया। राष्ट्रों की मुक्ति और जनता की क्रांति चीन की नीति में पहले से ही उदघोषित तत्व रहे हैं। नये तत्व का जुड़ाव मात्र औपचारिक बदलाव नहीं था। चीन की नीति में यह गुणात्मक स्तर पर बदलाव का परिचायक था। राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और जनता की क्रांति के पक्ष उत्तरोत्तर रूप से कम महत्व के बने, तथा राज्यों की स्वतन्त्रता नीति का प्रमुख केन्द्र बन गया। इसी गुणात्मक बदलाव के सदर्थों में, चीन ने एक त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रीय सक्रियता को जन्म दिया।

चीन सोवियत सघ के लगाव और अलगाव के बीच (1969-1979)

सातवें दशक में चीन की विदेश नीति में एक नई सक्रियता को जन्म दिया। पिछले दशक के दौरान आन्तरिक व्चारिक मथन के बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण चीन की नीति में समाहित हुआ। 1969 में चीन की एक स्वतन्त्र आणविक शक्ति के रूप में भी स्थापना हो चुकी थी। अमेरिका के साथ सम्बन्धों में सामायीकरण की स्थितया आने के बाद, चीन ने अपने एक सीमित महाशक्ति स्वरूप को भी पहिचाना। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि, विदेश नीति के दृष्टिकोण में वैमनस्वकारी पूवग्रहा के स्थान पर एक प्रतिद्वन्द्विता की नीति को अपनाया जावे। अर्थात् चाहे वह अमेरिका के साथ सम्बन्धों का प्रश्न हो अथवा सोवियत सघ के

साथ संबंधों का प्रश्न अपने स्वयं अस्तित्व को परिलक्षित करती हुई खुली प्रतिद्वंद्विता की जाने। वैचारिक विश्व दृष्टिकोण के अनुसार चीन की मान्यता यह थी कि सोवियत संघ उभरती हुई शक्ति है। अतः सोवियत संघ के साथ इस प्रतिद्वंद्विता की नीति का अधिक उग्र होना स्वाभाविक ही था। वैचारिक स्तर पर चीन अथवा आधिक राजनीतिक स्तर पर की नीति सोवियत संघ के साथ खुली प्रतिद्वंद्विता की बनी। इनके दो अभिप्राय हैं। प्रथम यह कि सोवियत संघ के साथ परस्पर संबंधों में वैमनस्य के पूर्वग्रहों में हटकर एक यथायथानी सतुलन की स्थिति बनाई जाये। ऐसी नीति जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ का कोई सीधा खतरा चीन की सीमाओं पर कम हो जाये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की सक्रियता के लिये भी लाभप्रद थी, द्वितीय जहाँ तक वैचारिक द्वंद्व का प्रश्न है तथा अथ राष्ट्रा में अपने प्रभाव को बढ़ाने की बात है, सोवियत संघ के साथ खुली प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाई जाये। ऐसी नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के एकाकीपन समुक्त होने के लिए आवश्यक थी। एक अथ महत्वपूर्ण आधार सोवियत-चीन संबंधों के स्वरूप की दृष्टि से अत्यधिक महत्व का था। यह कि आंतरिक विकास की आवश्यकताओं के लिए पश्चिमी राष्ट्रो से सहायता लेते हुये भी उन पर पूर्ण रूप से आश्रित होने की स्थिति पैदा न की जाये। इस दृष्टि से सोवियत संघ के साथ भी एक अधिक सहयोग की प्रक्रियाओं, भले ही सीमित रूप से, प्रारम्भ किया जाये।

इन सम्भावनाओं के प्रति जहाँ तक सोवियत दृष्टिकोण का प्रश्न था, वह पहले से ही सकारात्मक था। सातवें दशक में अमेरिका और चीन के बीच बनते हुये समीकरण में, इसे एक तात्कालिकता भी दी। विश्व स्तर पर यदि एक त्रिकोणात्मक समीकरण उभरता है तो, सोवियत दृष्टि में यह आवश्यक था कि अमेरिका को इस बात का एक तरफ़ा लाभ नहीं मिलना चाहिये। तीन शक्तियों में से बड़ी एक मात्र ऐसी शक्ति थी जो अथ दो शक्तियों के साथ सीधे सम्पर्क में थी। सोवियत नीति की यह स्पष्ट धारणा थी कि सम्बंधों में सुधार तो अनेक स्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन कम से कम चीन के साथ सीधा सम्पर्क तो स्थापित होना चाहिये। अथवा, चीन अमेरिका समीकरण के प्रति सोवियत संघ एक अनभिज्ञ तथा भ्रूक दशक रह जायेगा। सफलता अथवा असफलता भी प्राथमिक रूप से इस बात पर निर्भर करनी है कि भविष्य में उभरते समीकरण में सोवियत हस्तक्षेप करने में तो सक्षम हो। अमेरिका के साथ सम्बंधों में समन्वय और सम्पर्क की प्रक्रिया स्थाई रूप से बन चुकी थी। चीन के साथ भी परस्पर संबंधों में ऐसी ही प्रक्रिया की आवश्यकता थी। जहाँ तक अथ प्रभाव का प्रश्न था, सोवियत नीति भी चीन के साथ खुली और उग्र प्रतिस्पर्धा की थी। चीन त प्रभाव का मात्र सामरिक अथवा राजनीतिक अभिप्राय नहीं था। वैचारिक स्तर पर भी यह सोवियत मान्यता की चुनौती थी। अतः ऐसी समस्त स्थितियों के द्वारा जहाँ चीन और

अमेरिका मिलकर प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करें, सोवियत सघ द्वारा इसका वैचारिक स्तर पर भी उग्र प्रचार किया जायें। सोवियत नीति को चीन के स्वतंत्र अस्तित्व का स्पष्ट आभास था। अतः सोवियत मायता में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि, अमेरिका के साथ मिलकर अथवा उस पर दबाव डाल कर, चीन की अंतर्राष्ट्रीय शांति में प्रतिबद्धता हासिल की जायें। सोवियत दृष्टि से, आणविक परीक्षामन के प्रश्नों पर चीन की प्रतिबद्धता, इस सदन में तात्कालिक महत्व की थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका स्याई हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सतुलन को स्वीकार कर चुका था। चीन के महत्व को देखते हुए, उससे भी ऐसी ही स्वीकृति की अपेक्षा थी। इन विभिन्न व्यावहारिक मायताओं के साथ, सोवियत सघ के परिपक्व विश्व दृष्टिकोण ने चीन के साथ उससे सम्बन्धों की नीति का निर्धारण किया।

सोवियत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय स्तर पर सबंधों में तीन प्रमुख पक्ष रहे—सीमा विवाद का प्रश्न, परस्पर आर्थिक सहायता का प्रारूप तथा विश्व स्तरीय आणविक सतुलन की रूपरेखा। अमेरिका तथा चीन के बीच सबंध बनने की प्रक्रिया के साथ, सोवियत सघ ने चीन के साथ सीमा विवाद के प्रश्न पर वार्ता करने की पहल की बात रखी। 1972 में निक्सन की चीन यात्रा से कुछ ही समय पूर्व सोवियत सघ ने यह खुशी घोषणा की कि, वह चीन के साथ न सिर्फ सीमा विवाद निबटाने को तैयार है अपितु एक अनाक्रमण संधि के लिए भी तत्पर है। तात्कालिक रूप से इसका प्रमुख अभिप्राय निक्सन यात्रा के दौरान उससे परिणामों को प्रभावित करना था। 1973 में 10 वें अधिवेशन के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत सघ के प्रति अपने वैचारिक दृष्टिकोण को और अधिक उग्र बनाया। लेकिन सीमा विवाद के प्रश्न पर सोवियत सघ के साथ सामायीकरण की बात रखी गई। 1974 में अमेरिका और सोवियत सघ के बीच ग्लाडीवा स्टोक में द्वितीय सामरिक शस्त्र परिसोमन संधि पर हस्ताक्षर हुये। इस संधि से यह स्पष्ट हो रहा था कि चीन के साथ अमेरिका सबंधों के सामायी होना प्रमुख विश्व प्रश्नों पर सोवियत अमेरिका सबंधों में सामूहिक दृष्टिकोण के लिये कोई विशेष प्रभाव नहीं रखता। इस दृष्टि से 1974 में चीन ने अपनी तरफ से भी सोवियत सघ के साथ सीमा विवाद को सुलझाने की पहल की। चीन के प्रस्ताव में एक नया उल्लेखनीय परिवर्तन था। प्रथम बार चीन ने इस आरोप को कि, 19वीं शताब्दी की सोवियत-चीन संधियों को असमान माना जाये, तथा उन्हें भावी वार्ताओं का आधार भी बनाया जायें, औपचारिक रूप से व्यक्त नहीं किया गया। अर्थात् सीमा विवाद की भावी वार्तायें, चीन के दृष्टिकोण में, बिना किसी पूर्व शर्त के आयोजित की जा सकती हैं। माओ की मृत्यु के बाद यह सम्भावना व्यक्त की गई कि सोवियत चीन सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार होगा।

कुछ 7वीं दृष्टा। दिगम्बर 1976 में चीन ने एनपरीय रूप में सोवियत संघ का विरोध करने हुए मीमांसाओं की सम्मति को अस्वीकार किया। 1979 में सोवियत और चीन के बीच हुई 1950 में हुई संधि औपचारिक रूप में खत्म हुई। त्रिगुण यह संधि सारम हुई उगी दिन चीन ने सोवियत संघ के साथ सीमा यातायात प्रारम्भ करने की घोषणा भी की। इस वर्ष सीमा विवादों में बातों का एक सीमित दौर रहा। लेकिन 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति का विरोध प्रकट करते हुए यह बातों अनिश्चितता के लिए स्फूर्ति कर दी गई। अफगान समस्या के उग्र स्वरूप के अवतार के साथ ही दोनों राष्ट्रों में पुनः यातायात की एक मानसिकता बनी है।

जहाँ तक व्यापार आदि संबंधों का प्रश्न है, इस क्षेत्र में भी सीमा के निरंतर प्रगति हुई है। दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापारिक संबंधों की पुनः शुरुआत 1970 में हुई। इस वर्ष दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार मात्र 4 करोड़ 20 लाख रुबल का रहा। 1973 में बढ़कर यह 22 करोड़ 30 लाख तथा 1976 तक 40 करोड़ रुबल तक पहुँच गया। 1973 में दोनों राष्ट्रों के बीच नागरिक वायु संचार की भी पुनः शुरुआत हुई। सोवियत संघ के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों की प्रक्रिया में एक सीमित स्तर पर स्थिरता की प्रकृति उभरी है। आणविक परिसीमन का प्रश्न अधिक दुरुह रहा है। अपने विकास के दौरान चीन ने हाल ही में अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र की क्षमता का परिचय भी दे दिया है। इस बड़ी हुई क्षमता का कोई विशेष प्रभाव सोवियत संघ के लिये नहीं देखा जा सकता। क्योंकि पहले की क्षमता के आधार पर भी सोवियत संघ चीन की आणविक मार के घेरे में था। लेकिन इस नई क्षमता ने चीन की आणविक मार को अमेरिकी महाद्वीप तक पहुँचा दिया। इन घटनाओं के बाद सोवियत संघ ने इस बात पर और अधिक बल दिया है। कि विश्व स्तरीय आणविक परिसीमन के प्रश्न पर चीन की प्रतिबद्धता हासिल की जाये। इस दृष्टि से सोवियत संघ ने अमेरिका पर भी अपने दबाव को बढ़ाया कि, वह भी चीन को ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिये तैयार करे। एक निश्चित सतुलन की स्थिति में आ जाने के बाद, यह स्पष्ट सम्भावना बनती है कि चीन भी विश्व स्तरीय परिसीमन के प्रश्न पर अपने आपको समर्पित करने हेतु तैयार हो।

जहाँ तक अयत्न प्रभाव का प्रश्न था, चीन ने इस सम्बन्ध में सक्रिय प्रयास किये। विरोधित भाओ की मृत्यु के बाद इन प्रयासों में तीव्र गति आई। 1978 में जापान और चीन के बीच एक मंत्री संधि हुई और इसी वर्ष डेग सियाओपिंग की जापान यात्रा की। अयत्न प्रभाव की दृष्टि से, सोवियत विरोधी आयोजन में, चीन के शीयस्थ नेताओं की रूमानिया, युगोस्लाविया तथा ईरान की यात्राएँ हुई। दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के साथ भी संबंधों को सामान्य बनाने की सक्रियता

दिखाई गई चीन की सोवियत विरोधी प्रतिस्पर्धाओं के प्रमुखतः तीन केंद्र कह जा सकते हैं। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा तृतीय विश्व के राष्ट्र विशेषतः अफ्रीकी राष्ट्र। अफ्रीका के मुक्ति सघर्षों में चीन की यह स्पष्ट नीति उभरी कि, सोवियत तथा अमेरिकी समर्थित शक्तियों के बराबर एक चीन समर्थित शक्ति को भी तैयार किया जाये। इस नीति की स्पष्टतम अभिव्यक्ति अगोला में हुई। वहां पर सोवियत समर्थित एम० पी० एल० ए० तथा अमेरिका समर्थित एफ० एन० एल० ए०, दो घटक थे। प्रारम्भ में चीन का समर्थन एम० पी० एल० ए० को ही मिला। लेकिन बाद में इसमें विवाद उत्पन्न किये गये, और चीन के समर्थन से एक नया घटक "यूनिटा" अस्तित्व में आया। इसके फलस्वरूप चीन का स्वतंत्र प्रभाव तो व्यक्त हुआ, लेकिन इतने सघर्ष की जनवादी शक्तियों को कमजोर बनाया। ऐसी ही नीति अफ्रीका अयत्त मोजाम्बिक, जिम्बावे आदि में भी देखी गई। इस नीति के फलस्वरूप चीन अफ्रीकी मुक्ति सघर्षों के बीच अत्यधिक अलोकप्रिय हुआ। जायर में फ्रांस के समर्थन जैसी घटनाओं ने, पूरे अफ्रीका में चीन की साज को गहरी चोट पहुंचायी।

सोवियत सघर्ष के साथ अयत्त प्रभाव प्रतिस्पर्धा में चीन की विशेष सफलता नहीं मिली है। यही नहीं परम्परागत मित्र भी नहीं रहे। इस सदन में चीन के लिये सबसे बड़ी ऐतिहासिक विडम्बना वियतनाम के सदन में हुई। वियतनाम के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद चीन ने उस सोवियत प्रभाव से अलग रखने के उग्र प्रयास किये। लेकिन वियतनाम की दृष्टि में सोवियत दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक और साधक था। अतः सोवियत वियतनाम सम्बन्धों में तीव्र प्रगति हुई। जुलाई, 1978 में वियतनाम 'कोमिकोन' का सदस्य बन गया। इसके बाद नवम्बर 1978 में सोवियत सघर्ष और वियतनाम के बीच एक दीर्घकालीन मैत्री संधि सम्पन्न हुई। कम्बोडिया विवाद के दौरान वियतनाम ने पालपॉट के शासन के सोवियत विरोध का समर्थन किया। चीन ने दूसरी ओर पॉलपॉट की सत्ता का समर्थन किया। उस विवाद के दौरान वियतनाम का कम्बोडिया में हस्तक्षेप हुआ वियतनाम को "दक्षिण पूर्वी एशिया का न्यूबा" होने की सजा भी इस घटना के बाद मिली। चीन वियतनाम सम्बन्धों में इस घटना चक्र ने उग्र तनाव उत्पन्न किया। इसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिणति 1979 में चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण में हुई। कम्बोडिया भी पॉलपॉट के शासन का पतन हो चुका था। वहां भी चीन की विफलता हाथ लगी। वियतनाम में चीन के हस्तक्षेप की विश्व स्तरीय आलोचना हुई। चीन को अब तत्त वियतनाम से हटाना पड़ा। चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया में, इस प्रक्रिया के द्वारा अपने परम्परागत मित्रों को खो दिया।

जहां तक यूरोपीय राष्ट्रों का प्रश्न है वहां पर भी चीन की मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र चीन के साथ द्विपक्षीय स्तर पर आधिक

तथा राजनीतिक सम्बंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई। पश्चिमी यूरोप और चीन के बीच आर्थिक सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र चीन के सोवियत विरोधी प्रयासों का प्रतिपक्ष नहीं उठा सकते। यही नहीं, ऐसे प्रयासों की तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई। पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र चीन के साथ सम्बंधों के ऐसे किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, जिसका फलस्वरूप सोवियत संघ के साथ उनके विनियमित हो रहे संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। न तो वे सोवियत संघों में चीन से वैमनस्य को, और न ही चीन के साथ संघों में सोवियत संघ से वैमनस्य को, कोई प्राथमिक क्षति मानने को तैयार हैं। दोनों के साथ समान व्यवहार तथा द्विपक्षीय स्तर पर संबंधों का विकास उनका प्रमुख दृष्टिकोण है। पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में भी, चीन की परम्परागत मित्र अल्बानिया भी उसकी नीतियों की आलोचना करने लग गया है। अनवर होक्सा के नेतृत्व में अल्बानिया ने सोवियत और चीन दोनों की ही नीति को बगहीन दृष्टिकोण की नीति कहा है। बिगड़ते संबंधों के बीच चीन ने अल्बानिया को सभी आर्थिक सहयोग बंद कर दिया है। विगत में चीन की भत्सना का प्रमुख पात्र, युगोस्लाविया आज चीन का एक मात्र पूर्वी यूरोपीय मित्र बन रहा है। युगोस्लाविया ने साम्यवादी छेमे में तनाव को कम करने हेतु मध्यस्थता की नीति भी अपनाई है। 1977 में इस उद्देश्य से माशस टिटो की सोवियत यात्रा हुई, और 1978 में उन्होंने चीन का भ्रमण भी किया। चीन ने उनका भव्य स्वागत किया और युगोस्लाविया के स्वतंत्र प्रयासों की भरपूर प्रशंसा भी हुई। लेकिन युगोस्लाविया की मध्यस्थता की भूमिका को देखते हुए, चीन युगोस्लाव मंत्री का कोई विपरीत सोवियत पर सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में भी युगोस्लाविया के साथ संबंधों का एक विशेष महत्व है। भविष्य में चीन और सोवियत के बीच संघों में सामायीकरण की प्रक्रिया में युगोस्लाविया की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मात्र यह तथ्य, स्वयं में महत्वपूर्ण अभिप्रायों वाला है।

उपरोक्त विवेचन यह स्पष्ट करता है कि, पिछले दशक के दौरान सोवियत चीन संघों में प्रमुख दो प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्त हुई हैं। प्रथम, द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर, सोवियत चीन संघों में एक सीमित लगाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। यद्यपि इसमें प्रगति अत्यधिक धीमी रही है। वर्तमान ठहराव भविष्य में एक नई सक्रियता की सम्भावनाएँ भी लिये गये हैं। द्वितीय, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है। चीन की नीति अधिकांशतः विफल और आत्मघाती ही रही है। एक ओर जहाँ सोवियत विरोधी मोर्चे की सम्भावनाओं में चीन कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है, वहीं एक स्वतंत्र प्रयास के रूप में चीन की सक्रियता भी स्थापित हुई है। विश्व के राष्ट्र चीन के साथ बिना किसी पूर्वग्रह के संबंध बढ़ाने के लिये तत्पर हैं। इन संबंधों की द्विपक्षीय आधार पर ही आयोजित होने की सम्भावना है। इससे

अधिक कोई अन्य अभिप्राय सम्भव नहीं है। भावी वर्षों में भी सोवियत चीन सबंधों का विकास इही सदर्भों में होगा। भावी सोवियत चीन मैत्री, एक दूसरे के स्वतंत्र अस्तित्व की मायता पर आधारित होगी, न कि किन्हीं असमान शर्तों पर।

चीन-अमेरिका सबंध मैत्री की ओर सहमे हुये कदम (1969-1979)

चीन और अमेरिका के बीच नवोदित समीकरण के प्रति अनेक पर्यवेक्षक अति उत्साही दृष्टिकोण अपना रहे हैं। कुछ अन्य ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के प्रभाव की समाप्ति का स्पष्ट लक्षण बताया है। लेकिन चीन-अमेरिका के बीच उभरते सबंधों का सही विश्लेषण किया जाय तो, ऐसी दोनों ही मायतायें निराधार प्रतीत होंगी। जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है वह आज भी सापक्ष है। चाहे सोवियत संघ के साथ सबंधों का प्रश्न हो अथवा अमेरिका के साथ चीन का विश्व दृष्टिकोण आज भी प्रमुख सद्म है। अति उत्साही दृष्टिकोण इस बात का समझने में अक्षम हैं कि अब तक के चीन-अमेरिका सबंधों की प्रक्रिया कोई तीव्र विकास की गति को प्रतिपादित नहीं करती है। पिछले दशक में, चीन को राजनयिक मायता का प्रश्न भी एक दुरूह प्रक्रिया वाला रहा है। ताइवान का प्रमुख विवाद जोकि दोनों पक्षों के लिये अत्यधिक महत्व का है सुलझना शेष है। यह कोई आसान विवाद भी नहीं है। परम्परागत विवादों के सुलझाने की स्थिति में भी ऐसा अनेक नये पक्ष उभरेंगे जोकि नये त्रिकोणात्मक संतुलन की उपज होंगे। चीन-अमेरिका सबंधों का स्वतंत्र विकास आज के अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में असम्भव है। इन दोनों राष्ट्रों से सोवियत सबंधों का प्रभाव एक विशाल महत्व का है। अतः परम्परागत विवादों के सुलझाने के बाद भी चीन-अमेरिका सबंधों की कोई सतत विकास की प्रक्रिया सम्भव नहीं है। अब तक के चीन-अमेरिका सबंधों का दायरा परम्परागत जड़ता को समाप्त करने की प्रक्रिया रही है। इस परिधि में भी दोनों पक्षों के कदम अत्यधिक सहमे हुए प्रतीत होते हैं। परस्पर सबंधों के बनने की प्रक्रिया का औचित्य स्थापित करना दोनों राष्ट्रों के लिये आन्तरिक स्तर पर एक दुरूह कार्य रहा है। इस दशक का विश्लेषण इन पक्षों को उद्घाटित करेगा।

राजनीतिक प्रयासों के मूलभूत आर्थिक आधार भी थे। उग्र अमेरिकी हस्तक्षेप की नीति आर्थिक हितों के विपरीत थी। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक हित चीन ने साथ सबंधों में जुड़े थे। तृतीय विश्व के राष्ट्रों में आर्थिक स्वतंत्रता की मांग ने साम्राज्यवाद की व्यवस्था को अपूरणीय आघात पहुँचाया। इस दृष्टि से, अमेरिका को नये विश्व बाजार की तात्कालिक आवश्यकता थी। मुद्रा के रूप में डॉलर का मूल्य अनिश्चित बन रहा था। जापान की आर्थिक प्रतिद्वंद्विता विश्व

बाजार में ही नहीं अपितु, अमेरिकी बाजार में भी उग्र घुनीती के रूप में उभर चुकी थी। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र भी औद्योगिक संकट के भवर में थे। इन राष्ट्रों की नीति स्वतंत्र स्तर पर भी इस संकट से उभरने के लिये पहले से ही क्रियाशील रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में शिथिलता की भाँति यूरोप से ही उपजा थी। इन्हीं राष्ट्रों ने सोवियत संघ के साथ संबंध बढ़ाने की पहल की थी, और अब चीन के साथ भी ऐसी ही प्रक्रिया में संलग्न थे। अमेरिका के लिए इन संबंधों के बीच चीन के साथ सामाजीकरण का प्रश्न राजनीतिक महत्व से कहीं अधिक महत्व का था। आर्थिक संबंधों की प्रक्रिया को स्थाई करने के लिए राजनीतिक स्तर पर सामाजीकरण अनिवार्य था। चीन, न सिर्फ राजनीतिक महत्व का राष्ट्र था, अपितु अपनी 75 करोड़ जनसंख्या के साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक बाजार भी। जहाँ तक चीन का प्रश्न था, वहाँ का नया उभरता दृष्टिकोण आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण का पक्षधर था। इन आर्थिक आधारों के विकास के साथ-साथ चीन अमेरिका संबंधों का भी विकास हुआ। राजनीतिक अथवा वैचारिक स्तर पर अनेक अडिगताएँ भी उभरी। इन सब अवरोधों के बीच में भी संबंधों की एक नई परिभाषा तथा राजनीतिक विवादों से जूझने का एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ।

निक्सन प्रशासन के आगमन के बाद, एक लम्बे समय से चली आ रही विदेश-नीति में पुनर्विचार की मायता स्पष्ट रूप से परिभाषित हुई अमेरिका को पिछले अनुभव उग्र हस्तक्षेप की नीति की विफलता के अनुभव थे। अतः आवश्यक बदलाव को व्यक्त करते हुये, जनवरी 1969 में निक्सन ने अपने प्रथम नीतिपरक भाषण में उद्घोषणा की कि 'टकराहट के एक लम्बे काल के बाद हम वास्तविकी के काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्र को हमारा यह संदेश है कि, हमारे प्रशासन के दौरान सम्पर्क और वार्ता के द्वार सदैव खुले रहेंगे। जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, उन्हें हम शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धिता के लिये आमंत्रित करते हैं।' निक्सन की इस घोषणा का चीन के साथ संबंधों के लिये एक परोक्ष लेकिन स्पष्ट अभिप्राय था। दोनों राष्ट्रों में संबंधों के सामाजीकरण में कोई तात्कालिक सुधार नहीं हुआ। अप्रैल, 1969 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 9वें अधिवेशन के बाद चीन की ओर से भी भावी संबंधों के आधार तैयार हुये। जुलाई, 1969 में, बहुप्रचलित "निक्सन सिद्धांत" प्रतिपादित हुआ। इसके अनुसार अमेरिकी विदेशनीति की यह मायता व्यक्त की गई कि एशिया के तनाव कम करने की दृष्टि से कहाँ पर अमेरिकी प्रतिबद्धता को कम किया जायगा। जहाँ कहीं भी विवाद है, प्रमुख दायित्व वहीं की शक्तियों का होगा और अमेरिका विद्यतनाम जैसी सोची हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनायेगा। नये वय के प्रारम्भ से, इस अमेरिकी बदलाव को देखते हुये, चीन अमेरिका की राजदूत स्तरीय वार्ताएँ पुनः प्रारम्भ हुई। लेकिन, इस बीच दक्षिण पूर्वी एशिया की कुछ घटनाओं ने, जिनसे चीन सम्बंधित कम्बाधिया के सिद्धान्त

नेतृत्व का पतन हुआ, चीनकी नीति को अमेरिका के प्रति जशा त बनाये रखा।

इन आशकाओं के समानांतर अमेरिका की ओर नये प्रयास हुए। फरवरी 1971 में निक्सन ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने यह व्यक्त किया कि 'अमेरिकी नीति चीन को विश्व समुदाय में सकारात्मक सबंध बनाने हेतु प्रेरित करने की नीति है। इस दृष्टिकोण के साथ अमेरिका सक्रिय भी है। चीन की ओर से अमेरिकी प्रयासों का प्रत्युत्तर जनता के राजनय के रूप में अमेरिकी टेलि-टेलिस टीम को आमंत्रित करके दिया गया। स्वयं चार्ल्स एन सार्स ने इस टीम के स्वागत के अवसर पर अमेरिका के साथ सबंध सुधारने की आशा व्यक्त की। 15 जुलाई, 1971 में निक्सन प्रशासन के लिये अभूतपूर्व सफलता की घोषणा का दिन बन गया। अमेरिकी जनता के टेलिविजन पर सम्बोधित करते हुये निक्सन ने चीन के साथ सबंध सुधारन के लिये की गई 'कीसिजर' की गुप्त यात्राओं की स्वीकार किया। अपनी भावी चीन यात्रा की घोषणा करते हुये निक्सन ने कहा कि 'आज मैं हमारे विश्व शांति के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को व्यक्त करन उपस्थित हुआ हूँ। विश्व में स्थाई शांति का कोई भी प्रारूप चीन और उसको 75 करोड़, जनता की भागीदारी के बिना असम्भव है। मैं हमारी नीति को स्पष्टतम संदर्भ में रखना चाहूंगा। हमारी नीति का कोई भी कदम हमारे परंपरागत मित्रों के हितों की बलि देकर नहीं उठाया जायेगा। चीन के साथ हमारी मैत्री किसी अन्य राष्ट्र के विरोध के लिये भी नहीं है। बिना किसी दूसरे का दुश्मन हुये कोई भी राष्ट्र हमारा मित्र हो सकता है। ऐसे दृष्टिकोण और भावना के बीच, मैं चीन की भावी यात्रा कर रहा हूँ, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि यह यात्रा शांति की यात्रा बन जायेगी।' निक्सन प्रशासन की इस नीति की आंतरिक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हुई। कुछ उग्रविरोधियों ने इसकी तीव्र निंदा भी की, और इस अति उत्साही तथा अयथाववादी की सज्ञा दी गई। लेकिन आम स्तर पर, अमेरिकी जनता की मानसिकता पिछले अनुभवों के आधार पर हस्तक्षेप की नीति की विरोधी बन चुकी चुकी थी। अतः साधारण स्तर पर इस नीति का स्वागत ही हुआ। शायद ऐसी स्थिति को जानते हुये ही, निक्सन ने अपनी घोषणा को साव-जनिक घोषणा बनाने का निश्चय किया। इस नये समीकरण में, जहाँ तक चीन की पहल का सवाल था, वह अत्यधिक सहमी हुई रही। अमेरिका के साथ सत्रधों ने पार्टी में एक उग्र विवाद को जन्म दिया। लिन पियाओ तथा माओ के बीच विवाद स्पष्ट रूप से उभरा। पार्टी के 9वें अधिवेशन के बाद लिन पियाओ के पतन के आधार उभरने लगे, जोकि उसने द्वारा किये गये, 'संस्कृत' के उदासीन क्रिया-बन पर आधारित रहे। इस बढ़ते हुये विवाद के बीच मात्रा न स्वयं साव-जनिक रूप से इस बदलाव को व्यक्त किया। यात्रा कर रहे तबहारम्ना को माओ ने कहा कि, 'हम निक्सन को पकट के रूप में या फिर राष्ट्रपति के रूप में भी

हमारे पक्ष दानने को तैयार है। माओ की खुसी रशोहरि के बाद राजनयिक गतिविधियाँ अमेरिका की तरफ मोड़ दी गई। चीन की पार्टी का आंतरिक विवाद भी उपद्रव। 1971 में मिन पिमाओ के पास के गांव माओ का दृष्टि कोण पुनः स्थापित हो गया। चीन के मिसे दम बदलाव की स्थिति का औचित्य पुनः ठहराना एक मुद्दा बन गया। यथास्थित दृष्टिकोण ने स्तर पर मुद्दानीवी मग तो दूर फिर भी समझ सक्ता था। पवित्र जनमानस में दम बदलाव को स्थापित करना माओ की पद्धति में एक अविवाद था।

तीस प्रमुख बातें इस बदलाव के औचित्य के कि नहीं हैं। प्रथम, विपत्त नाम संपन्न अमेरिका की चीन के प्रातिविकारी दृष्टिकोण का अनुभव किया गया है। बदली हुई परिस्थितियाँ में अमेरिका के लिए यह अगम्य है। गया है कि यह चीन का राजनीतिक अस्तित्व को नकार सके। सामाज्यवाद द्वारा की गई चीन की राजनयिक नाकबंदी स्वयं धराशाही हो गयी है। पहले अमेरिका की है, अतः सम्बन्धों में चीन क्षमता और आत्मविश्वास के साथ शामिल होगा और अमेरिका एक कमजोर स्थिति में। द्वितीय, वार्ताएँ अपने आप में कोई वैचारिक भटकाव नहीं दर्शाती। वार्ताओं का होना तथा समाप्तीयावादी दृष्टिकोण एक दूसरे के पर्याप्त नहीं है। किन्हीं विषय स्थितियों में वार्ताओं भी संपन्न का माध्यम हो हो सक्ती है। दम दृष्टि में यह कहा गया कि 'जैम को तैसा' किस रूप में दिया जाये, यह असंगत अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। कभी वार्ताएँ करना जस को तैसा होता है तो कभी वार्ताएँ न करना भी पहले भीतम मही थे कि हमने वार्ताएँ नहीं की, और आज भी हम वार्ता करके सही है। दोनों स्थितियों में हमने अमेरिका को जैम को तैसा दिया है। तृतीय, इन बदलाव की स्थितियों का समस्त ऐतिहासिक उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये प्रातिकारी समय का दौरान हुई, उन स्थितियों की पुनः धार करवाया गया जब कम्युनिष्ट पार्टी ने युद्धी मिन-सांग के साथ वार्ताओं का एक सम्बन्ध दूर बताया था। स्पष्ट था—यह कि त्रिम प्रकार उस समय वार्ताएँ प्रातिकारी आंदोलन को बढ़ाने में सहायक थी, ठीक उसी प्रकार आज की स्थिति है। इस सदन में, प्राति के दौरान अपनायी गई संयुक्त मोर्चे की नीति को भी पुनः दोहराया गया। इन विभिन्न आचारों पर, पार्टी और पार्टी के सक्रिय प्रचार के माध्यम में चीन ने बदलाव की इस मानसिकता को स्थापित किया।

1972 में निकसन की चीन यात्रा के साथ, अमेरिका चीन सम्बन्धों में एक नया अध्याय जुड़ा। निकसन की यात्रा के दौरान परस्पर विचारों का आदान प्रदान से अधिक कोई अन्य परिणाम नहीं निकला। लेकिन, मात्र यात्रा अपने आप एक महत्व की थी। चीन और अमेरिका के बीच विभिन्न प्रश्नों पर वार्ताओं का वास्तविक दायित्व किसिजर और चाऊ एन चाई का रहा। किसिजर की निरंतर

चीन यात्राएँ हुई। इन विभिन्न यात्राओं में, प्रारम्भिक उत्साह का क्रमिक अवसान देखने को मिलता है। आर्थिक मामलों में सहयोग की प्रक्रिया में तो निरंतरता आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कोई संयुक्त दृष्टिकोण नहीं उभर सका। यह स्वाभाविक ही था। जहाँ एक ओर चीन की नीति आत्मकेंद्रित और सीमित थी, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के दृष्टिकोण में उसकी विश्वस्तरीय भूमिका और विश्व संतुलन के प्रश्न भी अत्यधिक महत्व के थे। यूरोपीय राष्ट्रों के हेलसिंकी सम्मेलन में, पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को परीक्षा में लाया गया। चीन ने इस सम्मेलन की तीव्र आलोचना की, और इसकी तुलना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी को छूट दिए जाने वाली नीति से की गई। इस तुलना का अभिप्राय था कि, जर्मनी को दी जाने वाली छूट ने द्वितीय विश्वयुद्ध पैदा किया, सोवियत संघ के प्रति ऐसी नीति एक और विश्वयुद्ध को जन्म देगी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1974 में ब्लॉम्फील्ड में द्वितीय सामरिक शास्त्र परिसीमन संधि हुई। चीन ने इसकी उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस संधि को आगामी जापान-सोवियत संधि से पूरा बनाया जा रहा नियमों की सजा दी गई। चीन की दृष्टि में संधि की वैधता एक कागज के टुकड़े से अधिक नहीं थी, और न ही इसकी कोई विश्व शांति में उग्र योगिता थी। 1974 में किंजिंजर की 7वीं चीन यात्रा हुई। यात्रा के दौरान अमेरिका-चीन सम्बंधों में ठहराव स्पष्ट हुआ। प्रथम अवसर था कि, माओ किंजिंजर से नहीं मिले। चीन-अमेरिका सम्बंधों में यह ठहराव सम्बंधों में समय तक बना रहा। आर्थिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति हुई। दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़कर 1974 में 100 करोड़ डॉलर का हो गया। लेकिन इस क्षेत्र में भी कुछ अवरोध उत्पन्न हुये। चीन पार्टी में आंतरिक विवाद, विशेषतः माओ की मृत्यु के बाद उभरा। इन वर्षों में परस्पर आर्थिक सहयोग में भी कुछ मिरावट आई। चीन की नीति इन वर्षों में पश्चिमी यूरोप तथा जापान के साथ सम्बंधों में प्रति अधिक सक्रिय रही, यूरोपीय राष्ट्रों से विशेषतः सैनिक व्यापार भी हुआ, जिसमें 10 करोड़ डॉलर के जेट इंजिन की खरीद विशेष उल्लेखनीय थी। अमेरिका के साथ सम्बंधों में ठहराव बना रहा।

1977 में चीन-अमेरिका सम्बंधों में एक बार पुनः सक्रिय स्वरूप उभरा। इस वर्ष चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 10वां अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में हेंग सियाओ पिंग के नेतृत्व की पुनः स्थापना हुई। इस नेतृत्व के आगमन के साथ ही चीन में एक दूरगामी आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को भी स्वीकृत किया गया। पश्चिमी राष्ट्रों के साथ एक लम्बे समय का आर्थिक सहयोग इस नये कार्यक्रम का अग्र भाग था। विश्व स्तर पर बढ़ती हुई सोवियत सक्रियता, चीन-अमेरिका के लिये एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक सदस्य था।

अमेरिका में काट्टर नेतृत्व के आगमन के बाद चीन से संबंध सुधारने की नई

पहल की गई। अगस्त 1977 में अमेरिकी विदेश मंत्री हार्रिस वॉस की चीन यात्रा हुई। इस यात्रा के दौरान चीन ने अमेरिका का यह स्पष्ट किया कि जब तक उसके अस्तित्व को औपचारिक मान्यता नहीं मिलती, तथा ताइवान का प्रश्न नहीं सुलझाया जाता, तब तक सम्बंधों में कोई भी वास्तविक सम्भव नहीं है। इन प्रश्नों पर अमेरिकी प्रशासन में एक सम्बन्धी आंतरिक मन्त्रणा रही। दिसंबर, 1978 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यह ऐतिहासिक घोषणा की कि, जब तक कि चीन और अमेरिका के बीच राजनयिक सम्बंध स्थापित होंगे। इसी आधार पर एक घोषणा चीन में भी की गई। जनवरी 1979 में, औपचारिक मान्यता देने के बाद, चीन ने प्रथम प्रतिनिधि के रूप में डेंग सियाओ पिंग की अमेरिका यात्रा हुई। इस यात्रा के दौरान दोनों राष्ट्रों के विदेश दफ्तरों में विभिन्न एक बार पुनः व्यक्त हुआ। डेंग ने खुले रूप से सोवियत संघ की भूमिका की, और इस सम्बंध में विमतनाम का उसके कम्युनिस्टों के आक्रमण पर सबके सियान की बात भी कही गई। ऐसी खुली घोषणाएँ और आलोचनाएँ, अमेरिकी नीति के लिए सकोच का विषय बन गईं। अमेरिकी नीति अपने सोवियत संबंधों के महत्व को भी उतना ही मानती थी जितना कि चीन के साथ संबंधों के महत्व को। डेंग की अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद चीन द्वारा विमतनाम पर आक्रमण ने अमेरिकी नीति के लिए और अधिक विचित्र स्थिति उत्पन्न की।

राजनयिक मान्यता के बाद चीन अमेरिकी संबंधों में कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं करी जा सकती। ताइवान का परंपरागत विवाद आज भी उपस्थित है। चीन को औपचारिक मान्यता देने के बाद भी, अमेरिका और ताइवान के संबंध मर्यादित बने हुए हैं। ताइवान का प्रश्न चीन के लिए एक आत्मसम्मान का प्रश्न है। लेकिन, बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अमेरिका ने लिए ताइवान का सामरिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का प्रभाव क्षेत्र सोवियत प्रभाव में समा गया है। अतः इस दृष्टि के ताइवान में अमेरिकी उपस्थिति उसके सामरिक हिता के लिए और अधिक अपरिहार्य बन गयी है। 1980 में अफगान विवाद और सोवियत हस्तक्षेप, चीन और अमेरिका के लिए विन्ना का विषय अवश्य है। सोवियत संघ का बढ़ता हुआ प्रभाव दोनों राष्ट्रों के बीच अधिक निकट सहयोग के आधार भी बनाता है। लेकिन दोनों राष्ट्र एक दूसरे के डरावो के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नहीं हैं और न ही उन्होंने ऐसी क्षमता की संभावना का परिचय ही दिया है। चीन, समुक्त मोर्चे की संभावनाओं में, अमेरिकी सक्रियता तथा निश्चित प्रतिबद्धता चाहता है। अमेरिका ऐसी किसी स्थिति के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि वह चीन की सीमित क्षमता को समझता है। अतः व्यावहारिक स्तर पर ऐसे किसी मोर्चे का प्रमुख दायित्व अमेरिका का होना जायगा। यही नहीं, चीन-सोवियत संबंधों के भावी स्वरूप के बारे में भी कोई

निश्चित अमेरिकी दृष्टिकोण बनना असंभव है। इन विभिन्न अनिश्चितताओं को देखते हुए यह दृष्टिकोण गलत होगा कि, भविष्य में अमेरिका चीन संबंधों में कोई सक्रिय एकजूटता उभरेगी। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को सैनिक सामान दिया है, जिसकी चीन में उग्रप्रतिक्रिया भी हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि विभिन्न अनिश्चितताओं के बीच अमेरिका ताइवान में अपने सामरिक बल को खो देने के लिए तैयार नहीं होगा। चीन भी इस प्रश्न पर समझौता नहीं कर सकता। अतः चीन अमेरिका संबंधों का भावी स्वरूप सीमित सहयोग और असीमित अनिश्चितताओं के मिश्रित सदृशों में विकसित होगा।

एशिया की जागृति

एशिया की जागृति बीसवीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। मानव सभ्यता और संस्कृति का पोषक यह पुरातन भूखण्ड, एशिया, शताब्दियों तक विदेशी शासता की शृंखलाओं में जकड़ा रहा। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ने इसे विदेशी शासन के शिकरे से मुक्त होने में सहयोग दिया। शताब्दियों से महानिद्रा में डूबा एशिया अब उठ खड़ा हुआ है। इसे अपने महत्व का ज्ञान हो गया है। सम्पूर्ण महाद्वीप में चेतना की नयी सहर दी गई हैं और पिछले तीस वष में इस भूखण्ड पर घटने वाली घटनाओं ने आभास करा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केन्द्र यूरोप से हटकर एशिया में बसा आया है जहाँ आने वाले कुछ वर्षों में मानवता के भविष्य का फैसला होना है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार टॉयनबी ने लिखा है कि 'साम्यवाद की चुनौती का भी महत्व कम हो जायेगा जब भारत और चीन की कहीं अधिक शक्तिशाली सभ्यताएँ पश्चिम की चुनौती का उत्तर देने लगेंगी। जितना प्रभाव रूस अपने साम्यवाद द्वारा डालने की आशा करता है, उससे कहीं अधिक गहरा प्रभाव ये सभ्यताएँ आने चलकर हमारे पाश्चात्य जीवन पर डालेंगी।' इस दृष्टिकोण में स्पष्ट सभ्यतापरक चुनौती की बात का एक साफ आधार है। लेकिन, एशिया के गम से भी उग्र सामाजिक आर्थिक सघर्षों की उत्पत्ति अत्यंत प्रबल सम्भावना बनती जा रही है। चीन और हिन्द चीन के अनुभव इस ऐतिहासिकता के सजीव साक्षी हैं।

परिचय

एशिया भूमण्डल का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूव में प्रशांत महासागर से पश्चिम में भूमध्य सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिन्द महासागर तक फैला हुआ है। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व के एक तिहाई भू भाग पर इसका अधिकार है और ससार की आधे से अधिक जनता इस भूखण्ड पर निवास करती है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश—चीन और

भारत—इसी महाद्वीप के अंग हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से एशिया को निम्नांकित पाँच भागों में बाटा जा सकता है—

- (1) सोवियत एशिया।
- (2) पूर्वी एशिया।
- (3) दक्षिण पूर्वी एशिया।
- (4) दक्षिणी एशिया।
- (5) पश्चिमी एशिया।

सोवियत एशिया—सोवियत संघ का अधिकांश क्षेत्र एशिया में आता है। उसके 15 गणराज्यों में 8 गणराज्य—कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरगीजिया, ताजिकिस्तान, जार्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया—पूरी तरह एशिया महाद्वीप के भौगोलिक दायरे में हैं। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य—रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य (RSFSR)—का काफी क्षेत्र एशिया में है। भौगोलिक दृष्टि से सोवियत संघ को एशिया की शक्ति मानना चाहिये, किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे नस्लगत आधार पर तथा राजधानी के मौसमों में स्थित होने के कारण यूरोपीय शक्ति माना जाता है। भारत ने भी यदाकदा सोवियत संघ को एशिया का ही एक अंग माना है। जून 1965 में होने वाली अल्जीरियाई सम्मेलन में उसने सोवियत संघ को आमंत्रित किये जाने की मांग की थी। लेकिन यह चीन की उपस्थिति को संतुलित करने की दृष्टि से व्यक्त विचार था।

पूर्वी एशिया—इसे सुदूर पूर्व (Far East) भी कहते हैं। इसके अंतर्गत चीन, ताइवान, हांगकांग, कोरिया, जापान व बाह्य मंगोलिया आते हैं। महायुद्ध से पूर्व जापान को छोड़कर ये सारे देश साम्राज्यवादी लिप्सा, दमन और शोषण के शिकार थे। जिन दिनों यूरोप की शक्तियाँ अजेय समझी जाती थीं उन दिनों छोटे से जापान ने दैत्याकार रूस को पराजित करके (1904-5) तथा 'एशिया एशियावासियों का है' का नारा देकर गोरे साम्राज्यवादियों की नींद हुराम कर दी थी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से गोरा को खदेड़कर जापान ने अपने साम्राज्य बना लिया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही सुदूर पूर्व की नींद उचट गयी। आज समस्त सुदूर पूर्व जाग चुका है और विदेशी शासन कलक को घों चुका है। चीन और जापान के अभ्युदय से एक नये सुदूर पूर्व का जन्म हुआ है। उनकी नीतियों और आचरण पर बहुत कुछ सीमा तक विश्व शांति निर्भर है।

दक्षिण पूर्वी एशिया—असाधारण अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आठ राष्ट्र—बर्मा, थाईलैंड, इण्डोनेशिया, मलयेसिया, फिलीपाइन्स, वियतनाम, कम्पूचिया और

एशिया की जागृति

एशिया की जागृति बीसवीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। मानव सभ्यता और संस्कृति का पोषक यह पुरातन भूखण्ड, एशिया, शताब्दियों तक विदेशी दासता की शृंखलाओं में जकड़ा रहा। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति और समुक्त राष्ट्र की स्थापना ने इन विदेशी दासता के शिखरों में मुक्त होने में महयोग दिया। शताब्दियों से महानिद्रा में डूबा एशिया अब उठ खड़ा हुआ है। इसे अपने महत्व का ज्ञान हो गया है। सम्पूर्ण महाद्वीप में चेतना की नयी लहर दौड़ गयी है और पिछले तीस वर्षों में इस भूखण्ड पर घटने वाली घटनाओं ने आभास करा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केन्द्र यूरोप से हटकर एशिया में चला आया है जहाँ आने वाले कुछ वर्षों में मानवता के भविष्य का फैसला होना है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉयनबी ने लिखा है कि 'साम्यवाद की चुनौती का भी महत्व कम हो जायेगा जब भारत और चीन की कहीं अधिक शक्तिशाली सम्प्रदाय पश्चिम की चुनौती का उत्तर देने लगेंगे। जितना प्रभाव उस अपने साम्यवाद द्वारा डालने की आशा करता है, उससे बड़ी अधिक गहरा प्रभाव ये सम्प्रदाय आगे चलकर हमारे पाश्चात्य जीवन पर डालेंगे।' इस दृष्टिकोण में व्यक्त सम्प्रदायपरक चुनौती की बात का एक सामक्य आधार है। लेकिन, एशिया के कम से भी उग्र सामाजिक आर्थिक संघर्षों की उत्पत्ति अत्यंत प्रबल सम्भावना बनती जा रही है। चीन और हिंद चीन के अनुभव इस ऐतिहासिकता के सजीव साक्षी हैं।

परिचय

एशिया भूमण्डल का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में भूमध्य सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व के एक तिहाई भू भाग पर इसका अधिकार है और सत्तर वीं आधे से अधिक जनता इस भूखण्ड पर निवास करती है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश—चीन और

भारत—इसी महाद्वीप के अंग हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से एशिया को निम्नांकित पांच भागों में बाटा जा सकता है—

- (1) सोवियत एशिया।
- (2) पूर्वी एशिया।
- (3) दक्षिण पूर्वी एशिया।
- (4) दक्षिणी एशिया।
- (5) पश्चिमी एशिया।

सोवियत एशिया—सोवियत संघ का अधिकांश क्षेत्र एशिया में आता है। उसके 15 गणराज्यों में 8 गणराज्य—कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरगीजिया, ताजिकिस्तान, जार्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया—पूरी तरह एशिया महाद्वीप के भौगोलिक दायरे में हैं। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य—रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य (RSFSR)—का काफी क्षेत्र एशिया में है। भौगोलिक दृष्टि से सोवियत संघ को एशिया की शक्ति मानना चाहिए, किंतु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उस नस्लगत आधार पर तथा राजधानी के मास्को में स्थित होने के कारण यूरोपीय शक्ति माना जाता है। भारत ने भी यदाकदा सोवियत संघ को एशिया का ही एक अंग माना है। जून 1965 में होने वाली अल्जीरियाई सम्मेलन में उसने सोवियत संघ को आमन्त्रित किये जाने की मांग की थी। लेकिन यह चीन की उपस्थिति को संतुलित करने की दृष्टि से व्यक्त विचार था।

पूर्वी एशिया—इसे सुदूर पूर्व (Far East) भी कहते हैं। इसके अंतर्गत चीन, ताइवान, हांगकांग, कोरिया, जापान व बाह्य मंगोलिया आते हैं। महायुद्ध से पूर्व जापान को छोड़कर ये सारे देश साम्राज्यवादी सिप्सा, दमन और शोषण के शिकार थे। जिन दिनों यूरोप की शक्तियाँ अजेय समझी जाती थीं उन दिनों छोटे से जापान ने दैत्याकार रूस को पराजित करके (1904-5) तथा 'एशिया एशियावासियों का है' का नारा देकर बार साम्राज्यवादियों की नींद हुराम कर दी थी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में घेरा को खदेड़कर जापान ने अपने साम्राज्य का किया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही सुदूर पूर्व की नींद उचट गयी। आज समस्त सुदूर पूर्व जाग चुका है और विदेशी शासन क्लृप्त को धो चुका है। चीन और जापान के अभ्युदय से एक नये सुदूर पूर्व का जन्म हुआ है। उनकी नीतियों और आचरण पर बहुत कुछ सीमा तक विश्व शांति निर्भर है।

दक्षिण पूर्वी एशिया—असाधारण अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के आठ राष्ट्र—बर्मा, थाईलैंड, इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन्स, वियतनाम, कम्पूचिया और

लायास— इस क्षेत्र में आते हैं। यह हिंद महासागर का प्रशांत महासागर में मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है और एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक प्राकृतिक पुल का कार्य करता है। महाशक्तियों के मध्य यह संघर्ष का मुख्य स्थल है, क्योंकि यदि इस क्षेत्र पर साम्यवादी चीन का प्रभुत्व हो जाये तो फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साम्यवाद की स्थापना का कार्य मुश्किल पड़ी होगा। प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से एशिया बहुत समृद्ध है। चावल, टीन, रबर यहां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बर्मा, थाइलैंड और वियतनाम एशिया का 'चावल का कटोरा' (rice bowl) कहलाते हैं। पूर्वी एशियाई राज्यों को, चावल की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं राष्ट्रों द्वारा होती है। इन स्थितियों के कारण, इस क्षेत्र का अत्यधिक सामरिक महत्त्व है।

दक्षिणी एशिया—दक्षिणी एशिया के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका आते हैं। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में था। दो सौ वर्षों के ब्रितानी शासन ने विरासत के रूप में इन राष्ट्रों के लिए लगभग एक ही राजनीतिक समस्याएँ छोड़ी हैं। लेकिन, उपनिवेशवाद के अंतर्गत सभी राष्ट्रों में समान आर्थिक तथा सामाजिक विकास नहीं पाया। ब्रिटेन उपनिवेशी राष्ट्रों में सर्वाधिक प्रबल था। अतः उसकी एक विश्व स्तरीय फैलाव की नीति थी। उपनिवेशवाद के तृतीय चरण में जब पूँजी का निर्यात भी संभव बन गया, तब भारत का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया। इसके सामरिक महत्त्व और आंतरिक विकास की स्थिति को देखते हुए यहां पर एक औद्योगीकरण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई। इसके फलस्वरूप भारत में, भले ही एक सीमित स्तर पर, पूँजीवादी व्यवस्था का भी विकास हुआ। विकास के इस ऐतिहासिक क्रम ने भारत को एशिया में ही नहीं अपितु सभी उपनिवेशों में सर्वाधिक विकसित राष्ट्र बना दिया। स्वतंत्रता के बाद यह विशिष्टता और अधिक स्पष्ट हुई।

कारी योजना को विफल बनाने के लिए पश्चिमी एशिया की सुरक्षा व्यवस्थाओं का दूढ़ होना जरूरी है। विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हवाई और समुद्री मार्ग पश्चिमी एशिया में स्थित हैं। ये यूरोप को दक्षिणी व पूर्वी एशिया, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका से जोड़ते हैं। यह केवल स्वज नहर को उदजन बम गिरा कर नष्ट कर दिया जाय तो पश्चिमी यूरोप का सम्पूर्ण आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो जायेगा। यदि भूमध्य सागर के तट पर स्थित किसी देश पर सोवियत सघ का राजनीतिक नियंत्रण हो जाये तो पश्चिमी राष्ट्रों के लिए एशिया में अपना प्रभाव बनाये रखना मुश्किल हो जायेगा। अतः अमेरिका आदि पश्चिमी देश इस क्षेत्र को साम्यवादी प्रभाव से बचाने की जी जोड़ कोशिश में लगे रहते हैं।

पश्चिमी एशिया का व्यापारिक व आर्थिक महत्त्व भी है। विश्व का लगभग 28 प्रतिशत तेल पश्चिमी एशिया में पाया जाता है। यूरोप अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत तेल पश्चिमी एशिया से प्राप्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अरब डॉलर से अधिक की पूँजी पश्चिमी एशिया में तेल के व्यापार में लगी हुई है। इतनी पूँजी के विनियोग और तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के कारण अमेरिका पश्चिमी एशिया पर अपना प्रभाव बनाये रखना चाहता है। ऊपर तेल और युद्ध कूटनीति की दृष्टि से उपयोगी होने के कारण सोवियत सघ भी पश्चिमी एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का इच्छुक है। अतः भौगोलिक, सामरिक और व्यापारिक महत्ता के कारण पश्चिमी एशिया महाशक्तियों के मध्य सघष का अखाड़ा बना हुआ है।

जागृति के कारण

एशिया की जागृति किसी एक ऐतिहासिक घटना का परिणाम नहीं है। यह विकास की प्रक्रिया है जिसके मूल में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और राष्ट्रीय आन्दोलनों की भूमिका रही है। औद्योगिक क्रांति की ऐतिहासिक घटना के बीच एशिया मशीनों की चुनौती स्वीकार नहीं कर सका। मशीनों के बल पर और उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता ने एशिया को यूरोप के औद्योगिकीकृत देशों के नियंत्रण में पहुँचा दिया। लगभग 300 वर्ष तक एशियावासी यूरोप की उपनिवेशवादी शक्तियों की दासता में जीवन बिताने पर विवश हुए।

1789 में होने वाली फ्रांस की राज क्रांति ने पहली बार यूरोप और एशिया के बौद्धिक सम्बन्धों में परिवर्तन लाने की चेष्टा की। फ्रांसिसी क्रांति के शारों—स्वतंत्रता, समानता और विद्वत्-वैद्युत्व—का एशिया पर स्थायी प्रभाव पड़ा। जनतन्त्र और राष्ट्रवादिता, क्रांति की दो मुख्य धन थीं। इनके पीछे यूरोप की भूमि पर लहलहाते लगे। लेकिन यूरोप से भी अधिक एशिया की भूमि इन्हें अपने विकास के अनुकूल मिली। कुछ समय तक तो एशिया की रूढ़िवादिता ने इनके

पैर जमने नहीं दिये, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, छापेबानो की स्थापना, मातायात की सुविधाओं के विस्तार ने रूढ़िवादिता के पजे को, जो एशियाई जनता को कसे हुए था, ढीला कर दिया और उसके स्थान पर राष्ट्रवादिता की भावनाएँ जोर पकड़ने लगीं।

जापान पहला राष्ट्र था जिसने औद्योगीकरण और राष्ट्रवाद की शिक्षाएँ हृदय से ग्रहण कीं। 1905 में शक्तिशाली रूसियों को हराकर उसने सम्पूर्ण एशिया का सिर गौरव से ऊँचा कर दिया। समस्त सत्तार ने रूस जापान युद्ध की गति को विस्मय से देखा। ऐसे उत्कृष्ट संगठन, युद्ध क्षमता और अदम्य साहस का परिचय जापान देगा, सोचा ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद जापान ने जो "एशिया एशियावासीयों का है" नारा लगा तो सारे एशिया में नव जागरण की सहर दौड़ गयी और एशिया के निवासी विदेशियों की आर्थिक और राजनीतिक दासताओं में मुक्त होने की बात सोचने लगे। भारत में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस', चीन में कुओमिनतांग, तुर्की में नेशनलिस्ट पार्टी, इण्डोनेशिया में 'राष्ट्रीय इण्डोनेशियाई दल' आदि के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलनों ने जोर पकड़ा। एशिया के विभिन्न राष्ट्रों के भूमी नामरिकों ने विदेशी ताकतों के विरुद्ध चलाये गये ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलनों को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। प्रथम महायुद्ध ने एशिया में चल रहे इन राष्ट्रीय आन्दोलनों को उत्तेजनीय गति दी। युद्ध के दौरान अनन्क एशियाई देशों में स्वतन्त्रता की मांग ने इतना जार पकड़ा कि एक बार तो विदेशी शासकों के लिए उसे दबाना बठिन हो गया।

सन् 1917 की रूसी क्रांति हो गयी। यह कोई मामूली क्रांति नहीं, एक नयी व्यवस्था, जीवन पद्धति व नई सामाजिक संरचना का सदेग था। यह सबहारा या समाज के दलित वर्ग के शोषण के विरुद्ध मुक्ति के लिए विश्वव्यापी आवाज थी। इस रूसी बोलशेविक क्रांति से एशियाई उपनिवेशों की जनता को अपनी आजादी के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा मिली और दूसरी ओर साम्राज्यवादियों को चेतावनी कि उन्हें अब एशिया से हट जाना चाहिये।

द्वितीय महायुद्ध एशिया और यूरोप के पारस्परिक सम्बंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्र आपस में सड़कर या तो नष्ट हो गये या इतने कमजोर कि समुद्र पार एशियाई राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में रखना अब उनसे लिए सम्भव न रहा। राजनीतिक अथवा सैनिक कारणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने साम्राज्यवादी व्यवस्था के उपनिवेशों को बाल बाल पटाक्षेप किया। आर्थिक विवशता ने बीच, उपनिवेशों पर नियंत्रण असंभव था। शोषण की परोक्ष नीति की आवश्यकता थी, जो राजनीतिक स्वराज तो दे दे, लेकिन आर्थिक शोषण को नव-उपनिवेशी माध्यम से बनाय रखे। उन्हें विवश होकर एशिया के रेशा से भागना पड़ा। ब्रिटेन की नीति

अधिक दूरदर्शी थी अतः शांति पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हो गया। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता पायी। इसके बाद बर्मा, चीन, इण्डोनेशिया, थाइलैंड, मलाया आदि एक-एक करके स्वतंत्र हुए और सबने अपनी अपनी जनता की इच्छा के अनुरूप शासन व्यवस्थाएँ स्थापित की। 1949 में चीन में साम्यवाद आया। उसके उपरान्त एशिया पर विदेशी नियंत्रण इतिहास की घटना मान बनकर रह गया।

एशिया की समस्याएँ

एशिया शुरू से विभिन्न घमों, संस्कृतियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं वाला महाद्वीप रहा है। सभी एशियाई राष्ट्रों का स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उनकी अपनी विशेषताएँ हैं। अपनी विदेश नीति है और वे सब अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से पूँछ-पूँछ और साधन अपना रहे हैं। लेकिन उनकी सामाजिक, आर्थिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक समस्याओं और आकांक्षाओं में समानता पायी जाती है। एशिया के निवासी उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शोषण के शिकार रहे हैं, इसलिए पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों के प्रति शका और सदेह की दृष्टि से देखते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका में एशिया को दो पूँछ-गुंटा—साम्यवादी एशिया और गैर साम्यवादी एशिया—के रूप में देखने की प्रवृत्ति पायी जाती है, लेकिन एशिया के निवासी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस दृष्टि से नहीं सोचते। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी है। उनके सम्मुख पुनर्निर्माण और विकास की समस्याएँ लगभग एक सी हैं।

शताब्दियों के विदेशी शोषण ने एशियाई देशों को भुखमरी, दरिद्रता, पीड़ा तथा अगणित दुखों के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ के अधिकांश लोग भूमिहीन किसान हैं जो पेट भरने के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते। अशिक्षित दरिद्र, अघबिश्वास में डूबे ये अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं। लगभग सभी देश अति जनसंख्या से पीड़ित हैं तथा अपने जीवन के लिए सघन में रत हैं। यहाँ सबके लिए भोजन उपलब्ध नहीं है। यदि भोजन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवाओं की व्यवस्था निकट भविष्य में एशिया में नहीं की गई तो संभावना है कि आने वाली शताब्दी तक एशिया के निवासी बीमारी और अपर्याप्त भोजन के कारण असमय ही काल के घास बन जायेंगे।

एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक जीवन भी उपयुक्त आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन से प्रभावित है। यदि एशिया के निवासी अपनी समस्याओं के निवारण में सरकार व अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ मिलकर जुट जायें तभी उनकी जीवन दशाओं में नाटिकारी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एशिया के निवासी रुढ़िवादी हैं और किसी भी परिवर्तन को अपनी परम्परा व रीति रियाज़ा के

लिए चुनौती मागकर चलते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश एशियाई देशों के नेता भी सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हैं। ऐसी हालत में यहाँ जनतांत्रिक संस्थाओं की सफलता संदिग्ध है। 'गामन' व्यवस्था में यहाँ कितना ही परिवर्तन क्या न कर दिया जाए सत्ता हमेशा उसी अष्टवर्ग के हाथ में बनी रहती है जो पहले से यहाँ शासन करता करता चला आ रहा है। यह घोषी हुई उपनिवेशी विरासत की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।

एशिया विश्व के सगभग सभी बड़े 'घमों की जननी' है। किसी अन्य महाद्वीप में राष्ट्रीय या राजनीतिक मामलों पर घम का इतना प्रभाव देखने में नहीं आता, जितना कि एशियाई राष्ट्रों में। पश्चिम के अनेकवादी और समाजवादी आन्दोलन भी एशियाई लोगों के धार्मिक दृष्टिकोणों को बदलने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का अविवर्तित बने रहते हुए, इस हड़िवादी स्थिति में बदलाव की संभावनाएँ अत्यधिक क्षीण हैं।

समस्याओं की दृष्टि से इस तरह पश्चिमी जगत और एशिया के बीच भारी अंतर है। पश्चिमी जगत पूर्णतः औद्योगिकृत है। उसकी समस्याएँ औद्योगीकरण की देन हैं। जबकि एशियाई जगत की समस्याएँ भूमि, कृषि, घम और औद्योगिक विकास की समस्याएँ हैं। जापान जैसे देश में भी चालीस प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। जहाँ पश्चिमी राष्ट्रों के स्तर का औद्योगीकरण हो चुका है। भारत और चीन को छोड़कर जहाँ कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास देखने को मिलता है एशिया के सभी देश अभी औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़ी अवस्था में हैं। एशिया की जागृति को समझने के लिए इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

जागरण की प्रवृत्तियाँ व परिणाम

३५

एशिया में जागरण के परिणामस्वरूप एक साथ दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ क्रियाशील हुई हैं। बौद्धिक स्तर पर एक ओर तो यह आकांक्षा है कि पश्चिम का अनुकरण क्रिया जाये उसने रहस्यों को सीखा जाये तथा उसके कौशल को प्रयोग में लाया जाय। दूसरी ओर यह कि परम्परागत जीवन क्रम को कायम रखा जाये तथा अपने भाग्य का स्वयं निर्माण किया जाये। ये प्रवृत्तियाँ एक राष्ट्र में ही नहीं, एक व्यक्ति में भी साथ साथ पायी जाती हैं। कुछ प्रसंगों में उही व्यक्तियों द्वारा पुरानी प्रथाओं की ओर लौटने का आग्रह किया जाता है जिन्होंने पश्चिमी ज्ञान स्रोत में गहन अध्ययन किया था। पश्चिमी पद्धतियों और विचारों के आयात ने जागरण में योग दिया है, लेकिन स्थायी परिणाम जागत राष्ट्रों द्वारा अपने निजी व्यक्तित्व को महत्व देना है।

भौतिक स्तर पर भी दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ क्रियाशील हैं, जिन्हें

सकारात्मक (positive) और नकारात्मक (negative) दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है—

सकारात्मक प्रवृत्तियाँ व अधिकार

एशिया की जागृति के अनेक सकारात्मक परिणाम निकले हैं

(1) सामाजिक व राजनीतिक क्रांति—एशिया के निवासी आज उस शक्ति को जो उन्होंने कभी उपनिवेशवाद और पश्चिम का विरोध करने में लगायी थी, सामाजिक कुरीतियों, सामन्तशाही, दरिद्रता, अशिक्षा आदि मिटाने में लगा रहे हैं। सम्पूर्ण एशिया में स्त्रियों की दशा सुधरी है। अधिकांश देशों में भावात्मक व राजनीतिक एकता दिखाई देती है, भले ही इसकी एकता के कोई स्थाई आधार नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन राष्ट्रों में राष्ट्रीयताओं का सघन भी उभरा है।

(2) राष्ट्रीयता का विकास—जागृति के परिणामस्वरूप सभी एशियाई देशों में राष्ट्रीयता की प्रबल लहर आई है जिसने इस्त्रायल से लेकर फिलीपाईंस तक नये राष्ट्रों का निर्माण किया है। राष्ट्रीयता की भावना ने आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के कार्यक्रमों को गति दी है। सामन्तवादी व्यवस्था को मिटाने, जनतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा भाषा धर्म अज्ञान अविश्वास, रूढ़िवादिता, जातिवाद और क्षेत्रीयता जैसी बुराइयों के होते हुए भी राष्ट्रीय समाजों में एकता लाने में सफलता पाई है। एशियाई राष्ट्रवाद ने अफ्रीका के नवजागरण में भी योग दिया है और वहाँ साम्राज्यवादियों द्वारा अपनायी गयी जातिभेद और रंग भेद की नीतियों के विरुद्ध जनमानस बनाया है। लेकिन, आंतरिक विकास के आधार पर इन राष्ट्रों में एकता में अनेकता की विचित्र स्थिति है। असमान आर्थिक विकास के कारण विभिन्न अधविकसित राष्ट्रीयताएँ भी अस्तित्व में हैं। जिनके सघन उत्तरोत्तर उभरे हैं।

(3) उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की अत्येष्टि—पुराने ढंग के उपनिवेशवाद का पतन एशिया की जागृति का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम है। सभी एशियाई देशों की विदेशी नीतियों का लक्ष्य उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध है। पश्चिमी साम्राज्यवादी अभी तक धन मशीनरी, शिल्पज्ञान युद्ध सामग्री आदि देकर और सैनिक संधियों में बांधकर कुछ एशियाई राष्ट्रों को अपने प्रभाव में बनाय रखने की चेष्टा करते हैं किन्तु इससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी इसमें सन्देह है। जागृत एशिया साम्राज्यवाद के हर रूप से नफरत करता है—चाहे वह विचारधारा के निर्यात के रूप में हो अथवा आर्थिक सहायता समझौता या सैनिक सगठनों या अड्डों के रूप में। उसके लिए साम्यवाद नहीं साम्राज्यवाद पहले नम्बर का दुश्मन है तथा इसके वर्तमान नव-उपनिवेशी पटयत्र सघन का

प्रभुत्व दाखिल भी ।

(4) साम्यवाद के प्रति आक्षेपण—एशियाई राष्ट्रों में साम्यवाद के प्रति आक्षेपण बढ़ रहा है । इसके कई कारण हैं । प्रथम, रूस के अतिरिक्त साम्यवाद का दूसरा महत्वपूर्ण गढ़ चीन भी एशिया में स्थित है । दूसरे, सोवियत रूस ने सदस्य स्वाधीनता आंदोलनों का समर्थन और पश्चिमी देशों द्वारा किये जाने वाले घोरण का विरोध किया है । तीसरे, साम्यवाद वहां अधिक पनपता है जहां व्यवस्थागत विपत्तियों के फलस्वरूप गरीबी, बेकारी, आर्थिक पिछड़ाव निरंतर पनपता हो । एशिया के देशों की ये आधारभूत समस्याएँ हैं । चौथे, साम्यवादी प्रवृत्ति से पहले रूस और चीन बहुत पिछड़े हुए थे साम्यवादी शासन कुछ घंटों से वर्षों में इन देशों ने जो आगामी उन्नति की है, उससे सभी एशियाई राष्ट्र प्रभावित हैं । पाचवें, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस प्रकार एशियाई राष्ट्रों के राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप किया है और एक राष्ट्र को दूसरे के विरुद्ध लड़ाने की कोशिश की है उससे पूँजीवाद ने एशियाई राष्ट्रों की सहानुभूति खो दी है । अतः, एशियाई लोग के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा रोटी प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है । गरीबी, भूख और रोग की छाया में जीने वाले एशियाई 'वाद' की फिक्र नहीं करते । वे अपनी समस्याओं का व्यावहारिक हल चाहते हैं और उन्हें साम्यवादी व्यवस्था में यह संभव प्रतीत होता है ।

(5) स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने की प्रवृत्ति—एशिया के अधिकांश देश पश्चिमी देशों की भाँति गुटबन्दी में विश्वास नहीं रखते । वे न तो साम्यवाद के अंध भक्त हैं और न पूँजीवादी के कट्टर उपासक । उनकी ऐसी मानसिकता उनकी व्यवस्था की उपज है । एक ओर साम्राज्यवाद से प्रभावित होने के साथ साथ, आंतरिक स्तर पर एक घोरण की व्यवस्था कायम है । प्रथम पक्ष उन्हें साम्राज्यवाद विरोधी बनाता है, लेकिन द्वितीय पक्ष उनका साम्यवाद से सहम रहने का कारण भी है । अतः एक व्यावहारिक नीति के रूप में गुटों से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति एशिया के जागरण की विशेषता है । नेहरू की गुटनिरपेक्षता में उन्हें अपनी अक्षुण्ण रखने का प्रभावशाली साधन मिला है । इस दृष्टि से, जैसा बल्लोवियस मकमूद लिखा है, 'भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का नेता है तथा इसमें संदेह नहीं कि उसने समय समय पर इन (एशियाई) राष्ट्रों का भागदशन किया है ।'

(6) भ्रातृत्व भावना और सहयोग—जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है एशिया के राष्ट्रों में विद्यमान व्यापक भिन्नताओं के बावजूद उनकी समस्याएँ, आवश्यकताएँ और आकांक्षाएँ लगभग समान हैं । जैसा सभी राष्ट्रों को उपनिवेशवादी पीड़ाओं का अनुभव है जापान को छोड़कर सभी तकनीकी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं अज्ञान, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट का समाधान सभी को ढूँढना है, आर्थिक

असंतोष और आंतरिक दशाएँ सभी देशों में आंतरिक उपद्रवों व दंगों को भड़काती हैं। ऐसी अवस्था में जागृति के परिणामस्वरूप एशियाई राष्ट्रों में एकता और भाईचारे की भावना का जन्म होना स्वाभाविक था। मार्च 1947 में, विश्व मामलों की भारतीय परिषद (Indian Council of World Affairs) ने नई दिल्ली में एशियाई सम्बन्धों के सम्मेलन (Asian Relations Conference) का आयोजन किया जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधि आये। इसका उद्देश्य एशियाई राष्ट्रों के बीच मैत्री व सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा एशियाई जनता की प्रगति व हिता में वृद्धि करना निश्चित किया गया। नेहरू ने सम्मेलन का महत्त्व बताते हुए कहा कि 'परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है तथा एशिया को अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। एशिया के देश अब दूसरे के हाथ का मोहरा नहीं बनेंगे। विश्व के विषयों में उनकी अपनी नीतियों का होना निश्चित है।'

दो वष बाद, दूसरा एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में (जनवरी 1949 में) इण्डोनेशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाया गया जिसमें भाग लेने वाले 19 देशों के प्रतिनिधियों ने उच्च पुलिस और सेनाओं के इण्डोनेशिया में अविलम्ब चले जाने और 1 जनवरी, 1950 तक उम्र स्वतन्त्र किये जाने की मांग की। इस अवसर पर एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पारस्परिक एकता का परिचय देते हुए गुटबन्दी की भावना को बुरा बताया और भविष्य में और भी अधिक पारस्परिक सहयोग के लिए सहमति प्रगट की।

मई 1950 में फिलीपाइन्स में एशियाई राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से बोगोर् में एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया। इसके उपरान्त भारत, बर्मा, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका (जिन्हें कोलम्बो शक्तियों का नाम दिया गया) के प्रधानमन्त्री 1954 में बोगोर में मिल जहाँ उन्होंने एक विशाल अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया जिसका परिणाम बाण्डुंग सम्मेलन था।

बाण्डुंग सम्मेलन—यह प्रथम एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन था। जिन 29 राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में भाग लिया वे शक्ति व राजनीतिक की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली नहीं थे, किन्तु ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्पराओं की दृष्टि से वे केवल पुराने ही नहीं, बरन् सम्माननीय भी थे। भाग लेने वाले राष्ट्रों में विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। वे सभी राष्ट्र पारम्परिक शक्तियों के अधीन रह चुके हैं और उनका यह दृढ़ विश्वास है कि उनके नवनिर्माण का युग प्रारम्भ हो चुका है। अपने स्वागत भाषण में इण्डोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अहमद सुकर्णो ने कहा, "मुझे आशा है कि यह सम्मेलन इस बात का सबूत देगा कि एशिया और अफ्रीका का पुनर्जन्म हुआ है। एक नया एशिया और एक नया अफ्रीका जीवित हुआ है।" इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने यह निश्चय

रिया कि वे आर्थिक विकास हेतु एक दूसरे की विशेषज्ञों, अग्रणी याजनायों तथा उपयुक्त साधन सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करेंगे। इस सम्मेलन में अफ्रीका में व्याप्त जातीय भेद भाव की निंदा की गई। निःस्त्रीकरण का समय निया गया तथा अणु परीक्षण और आधुनिक आमुखा के प्रयोग पर प्रतिबन्ध की मांग की गई। सदस्य राष्ट्रों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना स्वीकार किया और उपनिवेशवाद की निंदा की। बाण्डुंग सम्मेलन के विषय में पश्चिमी राष्ट्रों का यह क्षया भी कि 'चाऊ-एन साइ' जैसे व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण यह सम्मेलन पश्चिमी विरोधी नीतियों का पालन करता। लेकिन बाण्डुंग सम्मेलन ने सिद्ध कर दिया कि एशिया के राष्ट्र गुटबन्दी के उपासक नहीं हैं, वे 'याव चाहते हैं और बुराई का उन्मूलन ही उनका एक मात्र उद्देश्य है। चाऊ-एन साइ की उपस्थिति में अनेक एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने साम्यवाद की निंदा की और उसे उपनिवेशवादी व विस्तारवादी बताया। बाण्डुंग सम्मेलन ने एशियाई राष्ट्रों के अनेक और विभिन्न पक्ष मामलों आये, किंतु सबका उद्देश्य एशियाई राष्ट्रों के मध्य गारस्परिक सहयोग और अच्छे सम्बंधों की वृद्धि करना था। बाद में यही एशियाई आयोजन गुटनिरपेक्षता के बृहद आयोजन में समाहित हो गया।

नकारात्मक प्रवृत्तियाँ व परिणाम

नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ साथ जागतिक के फलस्वरूप एशियाई राष्ट्रों में नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील हुई हैं। इससे दो मुख्य कारण हैं—

{ 1 } आकांक्षाओं की बढ़ती शक्ति—राजनीतिक जागरण ने एशियाई जनता की आकांक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है। जागरण के फलस्वरूप प्राप्त, राजनीतिक स्वतन्त्रता को लोग साध्य नहीं अपितु, एक महान सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन का साधन मान बैठे। लेकिन एशियाई समाज का जैसा चरित्र है। (जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है) उसने अतर्गत किसी बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन की बहुत शीघ्र आशा व्यक्त नहीं की। अतः आकांक्षाओं की बढ़ती शक्ति का परिणाम 'हताशाओं की बढ़ती शक्ति' हुआ जिससे राष्ट्रीय संघर्षों का उग्र बनना तथा, अंतर्राष्ट्रीय तनावों में भी विचित्र स्थितियों को जन्म दिया।

{ 2 } सामाजिक आर्थिक शक्ति से पहले राजनीतिक शक्ति—यूरोप के दशों में राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप आई राजनीतिक शक्ति से पहले वहाँ शोचनीय शक्ति के कारण आर्थिक व सामाजिक शक्ति हो चुकी थी। राजनीतिक शक्ति ने जब महत्वकांक्षाओं को बढ़ाया तो उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक आर्थिक साधन उन राष्ट्रों के पास थे। लेकिन एशिया के देशों में आर्थिक शक्ति से पहले राजनीतिक शक्ति हुई है। यहाँ आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक

आर्थिक साधन नहीं हैं तथा व्यवस्था का स्वरूप भी शोषक है। अतः प्रत्येक राष्ट्र को शान्ति, समृद्धि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जी-तोड़ कोशिश और जन-आकांक्षाओं को कुचलने की आवश्यकता पड़ती है। परिस्थितियों से साफ़ उठाने के इरादे से साम्राज्यवादी देश आर्थिक और सैनिक सहायता के जासू फँसाते हैं, जिनमें एशियाई सरकारें आसानी से फँस जाती हैं। इनसे राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद व युद्ध उत्पन्न होते हैं।

एशिया में जागरण से उत्पन्न इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के निम्नांकित परिणाम हमारे सामने आये हैं

(1) बाण्डुग भावना की समाप्ति या एशियाई एकता आन्दोलन में दरारें— बाण्डुग भावना क्षणिक ही रही। दस वर्षों के भीतर उच्च राष्ट्रीयता के विकास तथा महाशक्तिवाद की चालबाजी ने एशियाई राष्ट्रों में जाग रही एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया। राष्ट्रीय हिता की विभिन्नता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि दस वर्षों के भीतर 1965 में जो दूसरा एशियाई सम्मेलन बुलाया जाना था वह अभी तक आयोजित नहीं किया जा सका है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 29 जन 1965 को अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था किन्तु सम्मेलन की तिथि से दस दिन पूर्व अल्जीरिया में क्रांति हो गयी और प्रधानमंत्री बेनबेला की सरकार का पतन हो गया जो इस सम्मेलन को आयोजित कर रही थी।

जागृति के परिणामस्वरूप एशियाई राष्ट्रों में जो वैयक्तिक दृष्टिकोण विकसित हुआ है (जिसे वह सच्ची स्वतन्त्रता समझते हैं) उससे उनकी राष्ट्रीय हित की धारणा में प्रबुद्धता के स्थान पर मकीणता की बढावा है दूसरे एशियाई राष्ट्रों की एकता खण्डित हुई है। उनमें अनावश्यक सीमा विवाद और गण्ड पनपे हैं। इससे एशिया के देश अपने बहुमूल्य साधनों की विकास ताय में लगाने की पेशा विनाशकारी कार्यों (युद्ध सामग्री आदि खरीदने) में समान की विवश हुए हैं। इस काम में साम्राज्यवादी शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। सभी एशियाई देशों की आन्तरिक राजनीति में उनका हेस्तक्षेप स्पष्ट दिखाई देता है। एशियाई राष्ट्रों की इससे बड़ी हानि पहुँच रही है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय संधि का कड़ाहा—आज एशिया का धायद ही कोई ऐसा देश हो जो अपने किसी दूसरे एशियाई देश के साथ मित्रता में न उलगा हुआ हो। इन विवादों के कारण वहीं-वहीं एशिया के क्षेत्र में युद्ध चल रहा है या युद्ध का वातावरण बना रहता है। एशिया की इस स्थिति का दमकर टामस रत का कथन ठीक सगता है कि "एशिया इस समय संधि का याम्निविक कड़ाहा और भविष्य में भी रहेगा।" कुछ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवाद निम्नांकित हैं—

- (अ) चीन—रूस विवाद,
- (आ) चीन—विमलनाम विवाद,
- (इ) चीन—भारत विवाद,
- (ई) भारत—पाक विवाद, मध्य
- (उ) अरब—इस्लाम विवाद।

भविष्य

कुछ भी हा, राष्ट्रीय राजनीतिक एवं औपचारिक दृष्टि से एशिया का जाग्रण पूरा हो चुका है। पश्चिम अब उग चुका अपनी अधीनता में नहीं ला सकेगा। शाताब्दियों की निष्क्रियता के बाद कम से कम एशियाई देश अब स्वयं अपने भाग्य का निर्णय तो करने लग हैं।

सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से अव्यय एशिया के दस भिन्न अवस्था में हैं। जिन देशों में करा-कारगाने काफी बढ़ चुके हैं और धाक भास सैधार बरन के साज समान तयार हैं उनकी समस्याएँ एक प्रकार की हैं और जो इस दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनकी दूसरे प्रकार की। यूरोप और अमेरिका के देशों को अपना सामाजिक और औद्योगिक विनाश करने में जितना समय लगा है उसमें वही अधिक समय एशिया के नव जागृत देशों को लगेगा। यहाँ सुधार की माग तो उग्र है। यदि सुरुन ही कुछ न कुछ करके जनता को धात नहीं किया जायेगा तो वह राजनीतिक ढांचे को ही उलट पुलट कर रख देगी। नैजिन वतमान व्यवस्था के रहते बदलाव की संभावनाएँ कम हैं। भावी सप्प अवस्थापरक हामा, ऐसी आशा है।

इन देशों में एक प्रवृत्ति और है—जनसंख्या का, जो तेजी से बढ़ रही है। इसका परिणाम यह होता है कि यहाँ उत्पादन जितना बढ़ना है वह बड़ी हुई आबादी पर सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है और देश के विकास कार्यों के लिए कुछ नहीं बच पाता। अतः एशियाई राष्ट्यों की एक समस्या यह है कि वे नये नये माध्यम जुटाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए जमा पूँजी इकट्ठी करने का उपाय करें। इसके लिए जो कुछ भी किया जाता है उससे देश की जनता पर बोझ बढ़ना है जबकि जनता आज के बोझ से ही छुटकारा पाने के लिए छटपटा रही है। जनसंख्या की समस्या का भी समाधान, व्यवस्थागत अभिप्रायों में जुड़ा है। वतमान स्थिति के रहने मुनाफे की अव्यवस्था है। जिसके फलस्वरूप मसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। जनता को क्रय शक्ति कम है। जाय के स्तरों में भी गहरा विभेद है। अतः कुछ अभिजनों की आश्वस्तता का उत्पादन तो होता है। नैजिन, जो साधारण की वश्यकताएँ पटनी कर पाती। एशियायी

राष्ट्र ससाधना की दृष्टि से सम्पन्न हैं। आवश्यकता एक ऐसी व्यवस्था की है जो इन ससाधना का 'जन हित' में प्रयोग कर सके।

ऐसी दृष्टि से, एशिया की प्रमुख भावी प्रवृत्तियाँ का दोहरा स्वरूप है। एक ओर शोषण के बढ़ाने के साथ, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बल मिलेगा। दूसरी ओर, व्यवस्थागत बदलाव की शक्तियाँ भी इन्हीं स्थितियों से सशक्त रूप से उभरेंगी। एशिया की यही द्वि-द्वैतात्मक दिशा है।

अफ्रीका का अभ्युदय

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछले चार दशक अफ्रीका के लोगों के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। "विदेशी आधिपत्य द्वारा आरोपित अंधेरे और औपनिवेशिक शासन की जेल की कोठरियों से अफ्रीका और अफ्रीकी लोगों का अभ्युदय समकालीन विश्व स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है।"¹

सम्पूर्ण महाद्वीप में अफ्रीकी चल पड़े हैं, दिशा के विषय में निश्चित हुए बगैर वे कही जा रहे हैं।² सम्पूर्ण अफ्रीका में आशा की एक नई लहर का संचार हो रहा है ठीक उसी तरह जिन तरह अतीत में सबसे निराशा का वानावरण व्याप्त रहता था।³ 'इसके अभ्युदय ने तत्त्वों के नये 'सेट'—नय ढंग की जोखमा, अवसर और जटिलताओं—का प्रस्तुत करके विश्वराजनीति के गणक को बदल दिया है।⁴ सारी दुनिया अफ्रीका की जागृति को गौर से देख रही है क्योंकि अफ्रीका आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण केन्द्र भी है और उसके स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अभिकरण (Agent) भी।

महाशक्ति की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रों के लिए अफ्रीका विशेष महत्वपूर्ण है। सर हार्कड मकाइण्डर के विचार से यह एक 'विश्व द्वीप' है और जिसका विश्वद्वीप पर शासन होता है उसी का विश्व पर नियंत्रण होता है। 'अफ्रीका पर अपना प्रभाव बनाय रखने की लालसा विश्व की हर महाशक्ति में पाई जाती है। समुक्त राज्य अमरीका में तो एक कहावत बन गयी है कि "कल अमरीका की दक्षिण एशिया में थी लेकिन आज अफ्रीका में है।" इतना ही नहीं, विश्व की ममन्त महत्वपूर्ण, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में यह 'अधरा महाद्वीप' रहा है। यदि यह कहा जाय कि मानवता का भाग्य सदैव कुछ न कुछ अफ्रीका के साथ जुड़ा रहा है तो अतिशयोक्ति न होगी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों में मनभेद अफ्रीका के छगडों को लेकर ही हुये थे। 20वीं शताब्दी में जब जर्मनी और इटली ने अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित

करन शुरू किये ता मित्र राष्ट्र बोखला उठे थे। द्वितीय महायुद्ध के दौरान भी अफ्रीका न बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फ्रांसीसी सेनाओं 3 भागकर अफ्रीका में ही शरण ली थी और अफ्रीका के भूदानों में ही कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का फसला हुआ था। कांगो में यदि 'यूरेनियम' न मिला होता तो अणुबम का निर्माण वर्षों बाद हुआ होता। पिछले दशक के आरम्भ में (1960) महायुद्ध का सबूत अफ्रीका के ही एक देश कांगो न ही खड़ा किया था। मानव जाति का भोभाग्य था कि संयुक्त राष्ट्र इस सबूत का सफलतापूर्वक सामना कर सका। अतः दुनिया का विश्वास संयुक्त राष्ट्र से उठ गया होता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्र में भी परीक्षा भी, अफ्रीका में ही हुई थी। यदि इटली द्वारा एथियोपिया (इथियोपिया) पर किये गये आक्रमण का मुकाबला करने में राष्ट्र सफल हो गया होता तो न तो उसका जनाजा उठता और न ही विश्व का द्वितीय महायुद्ध का मूह देखना पड़ता। डाग हैमरशोल्ड की विश्वास था कि वर्तमान दशक में "विश्व की शांति और स्थिरता अफ्रीका के विकास, उसके प्रजातीय संघर्षों की दिशा तथा शेष सत्तार द्वारा अफ्रीकी जनता के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता की पद्धतियों से बहुत अधिक प्रभावित होगी।

परिचय

संयुक्त राज्य अमेरिका से क्षेत्रफल में लगभग चार गुना बड़ा, अफ्रीका समस्त भूखण्ड के पाँचवें भाग का घेर हुआ है। इसका क्षेत्रफल एक करोड़ पन्द्रह लाख वर्गमील है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान 'सहारा' इसी महा-द्वीप में है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका के बराबर है और जिसमें भौगोलिक और ऐतिहासिक तथा कुछ सीमा तक सांस्कृतिक रूप से अफ्रीका की दो भागों—उत्तर व दक्षिण अफ्रीका—में विभाजित कर रखा है। भूमध्य सागर की लहरों को छूता हुआ उत्तर अफ्रीका सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से बहुत उन्नत है। रोमन साम्राज्य के युग में यह यूरोप का ही एक अंग था। मिस्र के पिरामिड और स्फिक्स इसके गवाह हैं। दक्षिण अफ्रीका इनसे पूरी तरह भिन्न है। वहाँ आवागमन की पर्याप्त सुविधायें तक नहीं हैं। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका का बहुत पिछड़ा हुआ है और वहाँ के पुराने रीतिरिवाजों व अंधविश्वासों की बहुलता है।

अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है, जो 1 की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इसमें 50 लाख व्यक्ति (यूरोपियन) हैं और 5 लाख एशियाई जिनमें नब्बे ति गोरा का आधा भाग अकेले दक्षिणी अफ्रीका में बसता

इस महाद्वीप में मुख्यतः तीन जातियाँ—हैमिट, नीग्रो और बाण्टू—पाई जाती हैं। लगभग 850 भाषायें बोली जाती हैं जिनमें 300 की अपनी लिपि भी है। मुख्य भाषाओं में 10 सेमिटिक, 47 हैमिटिक, 142 बाण्टू और 264 सूहानी हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं जिनमें मुसलमान और ईसाई अधिक हैं।

समर के कुल उत्पादन का 55% सोना, 90% हीरा, 81% कोबाल्ट, 62% प्लेटिनम, 50% क्रोमियम, 36% मैंगनीज, 27% ताँबा, 2/3 काँच और 3/5 ताँबे का तेल यहाँ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कानो में यूरेनियम का विशाल भण्डार है जो अणु-उत्पादन में प्रयोग होता है। कच्चा सोहा इनका है कि सारे विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। लेकिन इस विशाल प्राकृतिक सम्पदा के पीछे रहते हुये भी अफ्रीका के मूल निवासी अत्यधिक विपन्न और दरिद्र हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 1961 की दर पर, अफ्रीका के निवासियों की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 43 डॉलर है जबकि उत्तरी अमेरिका की 882 यूरोप की 350 और लैटिन अमेरिका की 107 डॉलर वार्षिक है। केवल एशिया के निवासियों की आय उससे कम, 36 डॉलर वार्षिक है। ये आँकड़े भी अफ्रीकी जनता के रहन सहन के स्तर का वास्तविक चित्रण नहीं करते। मोरे का यहाँ औपनिवेशिक शासन रहा है। इसलिए अच्छी भूमि और उद्यान के विशाल प्रतिष्ठानों पर उनका स्वामित्व है। एंगियार्ड (विशेषतः भारतीय) व्यापार करते हैं या उन प्रतिष्ठानों में नौकरी। मूल निवासी काले लोग जो अपने ही घर में शताब्दियों तक गुनाम रह रहे हैं अब दासता या चाकरी से निकल कर स्वतंत्र व्यवसायों की ओर बढ़ रहे हैं। कृषि अभी तक मुख्य उद्योग है। सम्पूर्ण विश्व के औद्योगिक उत्पादन में अफ्रीका का योगदान कुल दो प्रतिशत है। अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। 90% अशिक्षित हैं। लोगों की औसत आयु (Life expectancy) बहुत कम है। दुनिया की लगभग सभी बीमारियाँ यहाँ पायी जाती हैं। मलेरिया, बोट और मीढ़ की बीमारियाँ इनकी सामान्य हैं कि कहा जाता है कि “हरेक अफ्रीकी अस्वस्थ होता है।” अस्वस्थ आदमी सामान्य तर्ही होता यह अफ्रीका की समस्या है। भोजन, कपड़ा और भूतल की समस्याएँ अत्यधिक विषम हैं। कहीं कहीं तो पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिलता।

इन सबका सम्मिश्रित प्रभाव यह हुआ है कि अफ्रीका अराजकता में है। आकस्मिक जागृति ने उसे एक अदभुत स्थिति में पहुँचा दिया है। उसे पश्चिमी जीवन पद्धति और तोर-तरीक़ा से घृणा नहीं है। वह भी पश्चिम के उनत नागरिकों की भाँति जीवन ध्यनीत करना चाहता है और सभी सम्पत्ति में सम्पन्नता का इच्छुक है। लेकिन उगरे भाग में अनेक बाधाएँ हैं जिन्हें दूर करना उसके लिए आवश्यक है—

औपनिवेशिक पृष्ठभूमि

अफ्रीका के राजनीतिक इतिहास के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मिस्र को छोड़कर सम्पूर्ण अफ्रीकी इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जो अफ्रीकी सभ्यता का प्राचीन मिट्टा कर सके। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने यूगाण्डा, के या और ट्रा सवाल में ऐसे अवशेषों को खोज निकाला है, जिनसे पता चलता है कि सभ्यता का सूय एशिया की अपेक्षा अफ्रीका में सबसे पहले निकला था। यहाँ के मूल निवासी बौन कद के पीले लोग थे जिन्हें उत्तर पूर्व से वाली जातियाँ न आक्रमण करके दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। बाद में पीले अफ्रीकियों का अस्तित्व ही मिट गया।

नील की घाटी की सभ्यता निश्चय ही सबसे पुरानी (पाँच हजार वर्ष पूर्व) मानी जाती है। इसके बाद कार्थेज की सभ्यता का वर्णन मिलता है जिसे बाद में रोमन साम्राज्य में लुप्त कर दिया। मिस्र के अलावा अफ्रीका में प्राचीन सभ्यता का दूसरा केन्द्र इथियोपिया माना जाता है जहाँ मानवी से ग्यारहवीं शताब्दी के बीच इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस्लाम के सम्पर्क में आने के कारण अफ्रीकी पश्चिमी एशिया और यूरोप के सम्पर्क में आये। पंद्रहवीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी नाइजीरिया के तट पर उतरे थे। अफ्रीकी जनता उस समय आदिम जीवन बिता रही थी। पुर्तगालियों के बाद अन्य यूरोपिय अफ्रीका के रेगिस्तानी और घन जंगल वाले क्षेत्रों में दूर दूर तक चले गए। इनमें से अधिकांश गुलामों और सन के लाभप्रद व्यापार के लिए तथा साथ ही 'जघेरे महाद्वीप' में ईसाई धर्म की ज्यादातम जलाने के लिए उद्देश्य से जाय थे। उन्हें मध्य और दक्षिण अफ्रीका के प्रदेशों में खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तु-मूल्य वस्तुओं की बड़ी मात्रा में मिलने की आशा थी। गुलामों का व्यापार एक दूसरा बड़ा आकर्षण था। यद्यपि फ्रान्स की राजनीति के प्रभाव में यूरोपीय देशों ने दास प्रथा का समाप्त कर दिया, तथापि सहस्राब्दी गुलामों द्वारा और अफ्रीका ले जाय जाते और बेचे जाते थे। इससे भी बड़ी व्यापार में गुलामों के व्यापारी मध्य अफ्रीका से गुलामों का धोखा से अथवा उद्वेगपूर्ण पकड़ कर ले जाते थे और अरब देशों की भड़िया में उन्हें उबल देते थे। उनके सौंठों पर पट्टे पहन, लोहे की जंजीरों में बंधे गुलाम, लम्बे बाँझों के पीछे चलते हुए देखे जा सकते थे। उनमें से जो भाग्य का कैदियों के रूप में अथवा राज्यों के कष्ट का सहन में असमर्थ होते उन्हें मार डाला जाता था। १० वें शताब्दी है कि 1835 से 1850 के मध्य कम से कम १० लाख गुलामों द्वारा गुलाम प्रति वर्ष अफ्रीका से निर्यात किए गए थे। इसमें से १० लाख प्रतिशत लोग शामिल नहीं हैं जो नई दुनिया में पहुँचने से पहले ही दोरान मर गये या मार डाले गए थे।

सन 1800 ई० नव अफ्रीका का 90 प्रतिशत भाग दुनिया के लोग के लिये अगम और अज्ञात था। यूरोप के दुस्माहसी अवेषण इस काले महाद्वीप में फलत ही चले जाते थे और कबीला की जगह पर अपन उपनिवेश खड़े करते चले जाते थे। धीरे धीरे सारा अफ्रीका गुलामी की जजीरो में जकड़ा गया। इतने बड़े महाद्वीप का जो भारत से दस गुना बड़ा है और जिसमें भारत सहित चीन, संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिमी यूरोप एक साथ समा सकता है, जैसे गुलाम बनाया गया इसका सजीव वर्णन हमें हेंरी जानस्टन नामक अंग्रेज के लेखों में मिलता है, जिसने नाइजीरिया पर यूनिवर्सल जंक (ब्रिटिश बड़ा) फहराया था। उनसे पता चलता है कि किस प्रकार छल फरब, बल प्रयोग या नाना प्रकार की धमकियां देकर यूरोपीय लुटेरों ने भोले भाले अफ्रीकी सरदारों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और कानूनी संरक्षण पाने के लिए जाली कागज और संधिपत्र तैयार कर लिए।

1912 तक यूरोपीय शक्तियां ने अफ्रीका के प्रदेशों को पूरी तरह आपस में ठीक उसी प्रकार बांट लिया था जिस प्रकार भूख कुत्ते रोटी दखकर झपट पड़ते हैं और उसे टुकड़े टुकड़े करके बांट लेते हैं। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर अफ्रीका पांच औपनिवेशिक क्षेत्रों—फ्रांसीसी, ब्रिटिश, बेल्जियम, स्पेनिश और पुर्तगाली—में विभक्त था। 1951 में सम्पूर्ण महाद्वीप में तरेपन में छ केवल चार देश स्वतंत्र थे। 1955 में पांचवां दश स्वतंत्र हुआ। 1969 में यह संख्या 41 पहुंच गई। आज केवल नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर जहां अल्पसंख्यक गारे सागा का शासन है सभी देश स्वतंत्र हो चुके हैं।

अभ्युदय के कारण

यह उत्प्रेक्षनीय है कि अफ्रीका के अन्य देशों में स्वतंत्रता, बिना सशस्त्र संघर्ष के आई है। एशिया की जागृति के पीछे राष्ट्रीय आन्दोलनों की पद्धति है, लेकिन अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे राष्ट्रीय आन्दोलन की संज्ञा दी जा सके। अधिक से अधिक के-या के माउ माउ आन्दोलन का नाम लिया जा सकता है जिसके अंतर्गत अफ्रीकी नौकरों ने अपना यूरोपीय स्वामियों की भोका पाकर हथियारों करके औपनिवेशिक शासकों को कुछ समय के लिए आतंकित करने में सफलता पाई थी।

अफ्रीका की जागृति में एशिया विशेषकर भारतीय मूल के लोगों का थोड़ा-बहुत हाथ अवश्य है जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह या अहिंसात्मक प्रतिरोध की रीनिया का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। अफ्रीका के दूसरे देशों के मूल निवासियों का भल ही इसका रहस्य आज

तक समझ न आया हो, लेकिन इसन 'उपनिवेशवाद' और 'विदेशी शासन' को उनकी नजर में हमेशा के लिए घणित धारणार्थे अवश्य बना दिया है।

अफ्रीका की जागृति के कारणों में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सबसे बड़ा हाथ है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वे अफ्रीका को गुलाम बनाये रख सकें। साम्यवादी रुस के महाशक्ति के रूप में अवतरित होने के बाद गोरे लोगों के शासन के विरुद्ध उत्तेजना पैदा होना स्वाभाविक था। यूरोपीय देशों को इसलिये एक एक करके अफ्रीकी प्रदेशों को आजाद करके भागना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना उनके लिए स्वतन्त्रता का नव संदेश लेकर आई। अज्ञान और अधीनता के अन्धकार में कुम्भकरण की नींद सोने वाला अफ्रीका एकाएक अगड़ाई लेकर उठ बैठा।

अफ्रीका की समस्याएँ

राजनीतिक स्वतन्त्रता में महाद्वीप का रूपांतरण अभी नहीं किया है। अफ्रीकी दशों की अथर्व्यवस्था पर राजनीतिक स्वतन्त्रता का निष्पकारी प्रभाव देखने में नहीं आता। लगभग सारे राष्ट्र आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यों में लग हैं। उनकी पहली समस्या यह है कि विश्व के दूसरे राष्ट्रों के विकास स्तर तक किस प्रकार पहुँचा जाये।

सही भाग की खोज—एशिया की भाँति अफ्रीका भी पूँजीवाद और समाजवाद के संघर्ष के बीच विकास की सही दिशा का मार्ग खोजन का प्रयास कर रहा है। चूँकि उनके मित्रों और शत्रुओं की सूची अलग है तथा उनका आर्थिक और राजनीतिक ढाँचा भिन्नता है, इसलिए अफ्रीकी राष्ट्रों में राजनीतिक व आर्थिक विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अलग अलग मांग पड़े हैं। उदाहरण के लिए, मलावी, ट्यूनिशिया, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, मारनका, गबन, सेनगल आदि पूँजीवादी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और पश्चिमी गुट के मित्रों के रूप में पहचान जाते हैं तो घाना, गिनी, माली, न ज़ाम्बिया वगैराह आदि न नियोजित विकास का समाजवादी मार्ग पकड़ा है। उनकी पहली समस्या पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना है। यदि यह समाप्त नहीं हुई तो उन्हें भय है कि उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता अर्थहीन हो जायगी। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर इसका विनाश प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी दशों में निम्नी विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना एशिया से भिन्न और वही क्रान्तिकारी है, क्योंकि यहाँ इसमें जटिलताएँ बढ़ती हैं और सम्पूर्ण व्यवस्था के ढेर हो जाना का खतरा होता है। शिक्षा के अभाव में प्रशिक्षित कर्मचारियों (personnel) की एक आर कमी पाई

सन 1800 ई० तक अफ्रीका का 90 प्रतिशत अगम और अज्ञात था। यूरोप के दुस्माहर्ष म फलत ही चले जात थे और कबीलो की जगह चले जात थे। धीरे धीरे सारा अफ्रीका गुलामी इतन बड़े महाद्वीप का जो भारत से दस गुना बड़ा चीन संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिमी यूरोप को गुलाम बनाया गया इसका सजीव वर्णन हम इसके लेखों में मिलता है जिसने नाइजीरिया पर यूरोप फहराया था। उनसे पता चलता है कि किस प्रकार नाना प्रकार की धमकियाँ देकर यूरोपीय लुटेरों ने भूमि जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और कानूनी तत्वांगण और सधिपत्र तैयार कर लिये।

1912 तक यूरोपीय शक्तियाँ ने अफ्रीका को प्रभुत्व में ठीक उसी प्रकार बाँट लिया था जिस प्रकार भूखण्ड पड़त हैं और उस टुकड़े टुकड़े करके बाँट लेते हैं। अफ्रीका पाँच औपनिवेशिक क्षेत्रों—फ्रांसीसी, ब्रिटिश, जर्मन, बेल्जियम और पुर्तगाली—में विभक्त था। 1951 में सम्पूर्ण अफ्रीका केवल चार दश स्वतंत्र थे। 1955 में पाँचवाँ देश तंयह सन्ध्या 41 पहुँच गई। आज केवल नामीबिया छोड़कर जहाँ अल्पसंख्यक गोरे लोगों का शासन है, है।

अभ्युदय के कारण

यह उल्लेखनीय है कि अफ्रीका के अन्तर दशों में सघन के आई है। एशिया की जागृति के पीछे परम्परा है लेकिन अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सजा दी जा सके। अधिक से अधिक बेच्यो के नाम लिया जा सकता है जिसके अंतर्गत अफ्रीकी स्वामियों की मौका पाकर हत्याएँ करने औपनिवेशिकों के लिए आतंकित करने में सफलता पाई थी।

अफ्रीका की जागृति में एशिया विशेषकर भाषा-उद्भूत हाथ अवश्य है जिन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह व अहिंसात्मक प्रतिरोध की रीतियाँ कायी। अफ्रीका के दूसरे देशों के मूल निवासियों का

है। अल्पसङ्ख्यक कबीला बहुसङ्ख्यक से, अशिक्षित और गरीब जातियाँ शिक्षित और सम्पन्न जातियों से तथा ग्रामीण लोग शहरी जनो से भय खाते हैं। कबीला या जाति के प्रति वफादारी मर्यादा राष्ट्रीयता और एकरूपता में बड़ी बाधक है।

जनतन्त्र की स्थापना मुश्किल—सच्ची राष्ट्रीयता और राजनीतिक चेतना के अभाव में जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना अफ्रीका में एक समस्या है। जहाँ जनतन्त्र है भी वहाँ उसका रूप निजी अधिनायकवाद (personal dictatorship) से मिलता जुलता है। अफ्रीकी देशों में सत्ता जनतन्त्र के नाम पर कभी निरुत्तर शासकों के हाथ में रही है ता कभी सैनिक तानाशाहों के हाथ में। इसका मुख्य कारण यह है कि सत्ता पर अधिकार करने के लिए शक्ति किसी क्षात्र पर पहले से ही कब्जा होना जरूरी है। नवयुवक विद्यार्थियों ने शासकों और सेना, इन तीनों में सेना ही सबसे बड़ा और संगठित बल है। इसलिए पिछले दशकों में अफ्रीकी देशों में जितनी क्रांतियाँ हुई हैं वे या तो शासक बल के किसी व्यक्ति द्वारा की गई हैं अथवा किसी महत्वाकांक्षी सैनिक अधिकारी द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्त होते ही राजनीतिक दलों और कार्यक्रमों के अभाव में प्रायः प्रत्येक प्रशासन के साथ सैनिक अधिकारी लगा दिए गये हैं। चूंकि ये साधारण सैनिक स्वतंत्रता प्राप्त होते ही उच्च अफसरों के हतबे प्राप्त कर चुकें हैं अतः राजनीतिक महत्वाकांक्षियों का इसके भय में पड़ा होना कोई अनहानी बात नहीं थी। अतः फिलहाल जनतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना अफ्रीका में संदिग्ध है।

जातीयता और रंगभेद—‘महाद्वीप की विलक्षणताओं में सबसे गम्भीर समस्या जाति की है।’¹ अनेक जातियाँ और प्रजातियाँ का जम देने वाला अफ्रीका अनेक छोटे छोट खण्डों में बँटा हुआ है। कोई भी दो जातियाँ एक दूसरे का पसंद नहीं करती। अपनी परम्परागत कलह प्रियता के कारण ये जातियाँ हर समय साधारण से मतभेद पर मारकाट पर उतर आती हैं। जातिवाद के आधार पर इस महाद्वीप में अनेक गहनयुद्ध और सैनिक क्रांतियाँ हुई हैं। दूसरे पिछड़े हुए देशों की तरह अफ्रीकी देशों में भी स्वतंत्रता आर्थिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत के रूप में आई है जो जातीय महत्वाकांक्षियों को भी बढ़ावा देती है।

जातिवाद के अतिरिक्त रंगभेद अफ्रीका के जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली तत्व है। रंगभेद के कारण सम्पूर्ण महाद्वीप में काले और गौरे लोगों के बीच एक प्रकार की गहरी खाई पड़ गई है। काले लोग अपने आपका गौरो से हीन मानते हैं जिन देशों में गौरे लोग नहीं रहते वहाँ के काले लोग भी हीनता की भावना से ग्रस्त हैं। जान गुथर का विचार है कि ‘सब वस्तुओं से ऊपर रंगभेद ही है जो कि अफ्रीका में अमनोप तथा विद्वेष

जाती है ता दूसरी ओर जनता को नयी नीतिया व पद्धतिया के प्रति व्यापकता करना मुश्किल होता है। प्राकृतिक साधना की दृष्टि से घनी हान के कारण अफ्रीकी राष्ट्रों व साधना पर अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकार का समाप्न होना उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसने लिए कौन सा माग उचित रहगा यह अफ्रीकी राष्ट्रों व लिए समस्या है।

राष्ट्रीयता व राजनीतिक चेतना का अभाव— कहा जाता है कि "अफ्रीका में राज्य है, राष्ट्र नहीं।" अफ्रीकी देश प्राकृतिक इकाइया नहीं हैं। वह मन मान ढंग से औपनिवेशिक शासकों। इस तरह बताया है जैम स्कूल व बच्च किसी मानचित्र में पमान (scale) की मदद से खान खोज कर तास हर रंग भर दते हैं। वहां की अशिक्षित जनता के हृदय में राष्ट्र की कल्पना का अभाव है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषाओं की परम्पराएं, भौगोलिक सीमाएं और क्षेत्रों का ऐतिहासिक विभाजन राष्ट्रों के बीच नहीं पाया जाता। कहने के लिए अफ्रीका में राष्ट्रीयता नाम की चीज जरूर है लेकिन वह वास्तविकता से कौसा दूर है। वह एक प्रकार से विदेशी शासन की चुनौतियों की प्रतिक्रिया अथवा विघटनकारी शक्तियों को एकत्रीकृत करने या आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याओं को मिटाने की कोशिश है," जिस विदशिया में पदा किया है। अफ्रीका के लोगों के लिए राष्ट्रीयता का अर्थ सिर्फ इतना है कि काले लोगों को गोरों से हीन न माना जाय।

राष्ट्रीयता के विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है—प्रथम, नमिक सामाजिक और बौद्धिक विकास की (जो शिक्षा या परम्परावादी संस्कारों से संभव है) और दूसरी राजनीतिक चेतना की। यूरोपीय देशों के हाथों में पड़ने से पूर्व अफ्रीकी देश उस असम्य युग में थे जिससे विश्व के अधिकांश राष्ट्र शताब्दियों पहले निकल चुके थे। अतः जब यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका पहुंची तब उन्होंने अफ्रीकियों का सामाजिक मनुष्य मानने से भी इनकार कर दिया और व उनसे उन प्रकार का व्यवहार करने लगे जो हिंसक पशु से किया जाता है। शताब्दियों के विदेशी शासन में भी अफ्रीकियों की शैक्षणिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास की गति बहुत धीमी रही। अतः जब अफ्रीका के राष्ट्र स्वतंत्र हुए तो वे प्रायः उतने ही पिछड़े हुए थे जितने वे गुलामी से पहले थे। उदाहरण के लिए कांगो के पहले स्वतंत्र प्रधानमंत्री, लमुम्बा उस देश के पहले स्नातक थे। यही दशा अरबो देशों की थी। राजनीतिक चेतना की कमी के कारण स्वायत्तशासी संस्थाओं की सफलता वहां सदिग्ध है और विघटनकारी व पर्यक्तवादी शक्तियों को बल मिलने की पूरी स्थितियां विद्यमान हैं। आज भी अफ्रीकी देशों के लोग समूचे जनसमूह की अपेक्षा वय या नबीले के प्रति अपनी अफादारी व्यक्त करते हैं। सामाजिक न्याय जनताधिकार न होकर सामंतवादों

महाशक्तियों का हस्तक्षेप—यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अफ्रीका से पलायन के उपरांत पश्चिमी एशिया की भांति अफ्रीका में भी रिक्तता आ गई। इस अवसर का लाभ उठाकर संयुक्त राज्य अमरीका अफ्रीका में पूँजीवाद और सोवियत संघ व चीन साम्यवाद के नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं।

1960 के दशक तक अफ्रीका पर संयुक्त राज्य अमरीका की पकड़ थी, क्योंकि उसके मित्रों (ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल व बेल्जियम) द्वारा स्वाधीन किया जान वाले अफ्रीकी राष्ट्र अपने औपनिवेशिक शासकों पर आर्थिक विकास के लिए निर्भर थे। औद्योगीकरण के अभाव में कच्चा माल निर्यात करना उनके लिए आवश्यक था जिनका संयुक्त राज्य अमरीका सबसे बड़ा खरीदार था। सामंतशाही हान के कारण सामाजिक ढांचा आर्थिक पूँजीवाद को बड़ा बाध रहा था। लेकिन अमरीकी सरकार की महत्वाकांक्षाएँ ही अफ्रीका में अमरीका की दुश्मन बन गयीं। स्वतंत्र अफ्रीकी राष्ट्रों ने जब गुट निरपेक्ष या स्वतंत्र नीति पर चलने का निर्णय लिया तो अमरीका इसे गवारा नहीं कर सका। उसने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करके और सीमा सम्बंधी विवादों को भड़काकर ऐसे राष्ट्रों का मदक सिंघान की सोची जिसका परिणाम उसके हितों के लिए ही घातक हुए। उदाहरण के लिए, इथियोपिया में हल सिलामी के नरत्व और लोकप्रियता से खिन होकर उसने वहाँ सैनिक ताकत दिखाई। जब परिणाम लाभकारी नहीं निकले तो सोमालिया को सहायता देकर उससे इथियोपिया पर आक्रमण कराया। इथियोपिया इससे रुस के प्रभाव में चला गया। 1975 में जंगला की आजादी के तत्काल बाद वहाँ आंतरिक शासन में अमरीका ने जा हस्तक्षेप किया उससे उसका मुह बाला हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ने वाले तीन समूहों में उनमें कबोलेवान पर आघात एफ० एन० एल० ए० का समर्थन किया, जबकि जनता में लोकप्रियता एम० पी० एल० ए० को प्राप्त थी। इतना ही नहीं दक्षिणी अफ्रीका की गारी सरकार, जो रंगभेद पर चलती है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के समर्थन पर टिकी है। अंगोला में दक्षिणी अफ्रीका से अमरीका ने सैनिक भी भिजवाये थे और सीमा अतिक्रमण भी कराया था। इन सबसे अमरीका की पहचान अब अफ्रीका में आंतरिक शासन में हस्तक्षेप और रंगभेद का समर्थन करने वाले राष्ट्र के रूप में होने लगी है। लेकिन आर्थिक और सैनिक सहायता के बल पर उसे कुछ क्षेत्रों में सफलता मिली है और वह अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।

साम्यवादी शक्तियाँ भी अपने प्रभाव विस्तार के लिए प्रयत्नशील हैं। सोवियत रुस और साम्यवादी चीन दोनों ही अफ्रीका में विशेष रुचि ले रहे हैं।

उत्पन्न करता है। यह अफ्रीकी हीनता का प्रधान कारण है जिससे उपद्रव और विद्रोह उत्पन्न होते हैं। यह गोर तथा काले दोनों ही प्रकार के लोगों के मस्तिष्क का प्रिगाट देता है।¹⁹

दक्षिणी अफ्रीका मध्य म रंगभेद का विषय समाज की नसा म गहरा उतर गया है। वहाँ के गारे शासक अपनी ताति की श्रेष्ठता और काले लोग की हीनता सिद्ध करने के लिए क्रूरतम उपायों का निःसर्कोच सहारा लेते हैं। रंग के बारे म गौरे लोग इतने शकालु हैं कि अपने किसी साथी गौरे के आचरण से अप्रमत्त न हों पर व अक्सर यह कह देते हैं कि इसम कुछ काला छन है। दक्षिण अफ्रीका मध्य म रंगभेद हर जगह अपने बीमरस रूप म दिखाई देता है। "पाकों म यूरोपियनों की र्वचा पर अफ्रीकी नहीं बैठ सकत, सावजनिक पुस्तकालया तक मे उनका प्रवेश निषिद्ध है। गौरा के लिए निर्धारित थमा म काला के लिए स्थान या तो बस की छत पर होगा या पीछ की सीटों सर। टना क भोज नालया म काला को भोजन की अनुमति नहीं मिल सकती। वायुधानों के गद्दे की चादरो का इस्तेमाल अगर कोई अफ्रीकी यात्री कर ले तो उसे गौरा द्वारा इस्तेमाल की गई चादरो से अलग रखकर धोया जायेगा। इस दश म अतर्जातीय खेलकूद की बात ता अकल्पनीय है। यहाँ कई प्रसिद्ध नीग्रो खिलाडी हैं, जा बाहर जाकर गौरा के साथ खेल सकते हैं, कि तु अपने देश के गौरो के साथ खेलन का अधिकार उह नहीं। बाहर स आने वाले जश्वत लोगो के साथ भी दक्षिणी अफ्रीका म उठा अशिष्ट व्यवहार होता है।²⁰

राजनीतिक अस्थिरता—अफ्रीका के नवस्वतंत्र राष्ट्रों म सरकारों का स्थायित्व नहीं पाया जाता। चूँकि समाज छोटे-छोटे समूहों, टुकड़ा और कबीलों म बँटा हुआ है इसलिए मौका पाकर ये राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह की स्थितियाँ पैदा कर देते हैं। राजनीतिक हत्याओं, विद्रोह और सशस्त्र विप्लव की जितनी घटनाएँ अफ्रीका म होनी हैं उतनी किसी दूसरे महाद्वीप म नहीं होती। घाना का उदाहरण एक नमून क रूप म प्रस्तुत किया जा सकता है जिसक लोकप्रिय नेता ए. नूमा (जिनका घाना की स्वतंत्रता और अफ्रीकी एकता आन्दोलन म महत्वपूर्ण योगदान रहा है) फरवरी 1966 म उम समय पदच्युत कर दिये गये थे जब वे चीन की यात्रा पर गये थे। राजनीतिक अस्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण कारण अफ्रीका म व्यापक राजनीतिक संगठनों का अभाव है। राजनीतिक दलों को न तो सरकार चलाने का अनुभव है और न उनमें पश्चिमी राजनीतिक दलों का अनुशासन पाया जाता है। अनिरुद्ध गुप्ता के शब्दों म, "स्वतंत्रता की जलबाजी ने अफ्रीकी राष्ट्रवादियों को इतना समय ही नहीं दिया कि वे अपने एरिषयार्थ प्रतिष्ठों की भाँति जनता के सभी वर्गों को मिलाने वाले स्थायी राजनीतिक संगठनों का निर्माण कर लेते।"²¹

शिक्षक, भूगर्भशास्त्री, डाक्टर आदि विकास के कार्यों में भाग दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक स्तर पर मोवियत सघ अफ्रीकी देशों में प्रगतिशील तत्वों का समर्थन करना है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आर्थिक और सैनिक सहायता भी देता है। कागो, अगोला, इथियोपिया आदि के विवाद में उसकी भूमिका इसका उदाहरण है। बौद्धिक स्तर पर अफ्रीका में मार्क्सवाद लाने के लिए वह बड़ी बड़ी छात्रवर्तियाँ देकर अफ्रीकी छात्रों को सोवियत विश्वविद्यालयों में स्थान देता है जहाँ उनके मस्तिष्क को मार्क्सवाद के रंग में रंग कर वापस उन्हें पुनः उनके देश भेज दिया जाता है। मास्का का लुमुम्बा विश्वविद्यालय अफ्रीकी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है।

सारांश यह कि अफ्रीका, रूस, चीन सभी की मिलीजुली अफ्रीका में है। यद्यपि अभी तक इस महाद्वीप में कोई दश पूरी तरह समाजवादी नहीं बना है तथापि इसमें कोई संशय नहीं कि अफ्रीकी महाद्वीप की समस्याएँ वहाँ मार्क्सवाद का आवाहन करती दिखाई देती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अत्यवस्था में इस महाद्वीप की समस्याओं का उत्तर देने की क्षमता नहीं है।

अभ्युदय के परिणाम

अफ्रीका के अभ्युदय ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर व्यापक प्रभाव डाला है। प्रथम, इसने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद पर धूर प्रहार किया है। यद्यपि नाभीब्रिया और दक्षिणी अफ्रीका में अभी साम्राज्यवादी और गरीब सत्तारों विद्यमान हैं तथापि यह दिन दूर नहीं है जब सम्पूर्ण अफ्रीका इनके घोषण से मुक्त होकर स्वाधीनता की माँग लेने लगेगा।

दूसर, अफ्रीका राज्यों में उदय से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्प्रभुताधारी राज्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के कुल सन्ध्य राष्ट्रों में एक तिहाई अफ्रीकी है। वर्तमान में यह सिद्धता है कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में जलिलताएँ बढ़ती हैं। नया प्रशिक्षण व अनुभव से हीन राजनयियों का बड़ा समूह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मध्यस्थ के रूप में मुखिल बनाना है। तीसरा अनुभव और आन्तरिक समस्याओं के दबाव में इनके नेता विदेशी नीति सम्बन्धी मामलों पर दैनिक परिचर्या की भाँति विचार करते हैं। विदेशी प्रभाव के प्रति स्थानीय प्रतिनिधियों के विषय में व विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि है तथा भाषा-
 १० रूप में जो वस्तुस्थिति है व उनकी सामाजिक नागरिकों और विदेशी
 ११ में इनकी छान।¹²

तीसरा, अफ्रीका की जातिगत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नए निरन्तरता का
 १२ का स्वरु बनाया है। यामिन विद्यता है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों

जहाँ तक अफ्रीका में चीन के हस्तक्षेप का प्रश्न है, सुरेंद्र प्रतापसिंह लिखते हैं कि 'चीन के अनुसार उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध यदि सबसे तीव्र लड़ाई कही जा रही है तो वह स्याम अफ्रीका है। आ अफ्रीका के नव स्वतंत्र दशा तथा उपनिवेशों में आजादी के लिए चल रही गुरिल्ला वारवाहियों की सहायता करने अपनी एक प्रातिविकारी भावमूर्ति स्या पित की जा सकती है। चीन यह मानता है कि अमेरिका व रूस के खिलाफ सफल लड़ाई अफ्रीकी मैदान में लड़ी जा सकती है, यही कारण है कि चीन अपने का अफ्रीका के मुक्तों को उगारने वाले भसीहा के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसलिए एक आर अहा वह अमेरिका को साम्राज्यवादी कहना है, तो रूस को 'मशान्त्रवादी' और सामाजिक साम्राज्यवादी'। पर सिर्फ नारा बलफाजिया से तो काम चलता नहीं है। अफ्रीकी मुक्तों को इनसे सावधान रहने की चेतावनी देने के साथ साथ उन्हें घन भी देना पड़ता है, जिससे वे आर्थिक मजदूरियाँ में नहीं फिर उही शक्तियों के पास न पहुँच जाए।"

चीन से सहायता पाने वाले मुख्य देश हैं—तंजानिया, माली गिनी, जाम्बिया और सोमालिया। 1276 मील लम्बे तनजाम रेल मार्ग के निर्माण में (जिस उसने 1970 से 1976 के मध्य छ वर्ष के अल्पकाल में किया) अफ्रीका में चीन के प्रति सम्मान की भावना को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। जाम्बिया के एक एक श्रमिक ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 'उपनिवेशवादी यदि इसी तरह हमारे साथ काम करते तो अफ्रीका अविकसित न होता।' वह अफ्रीकियों के श्रेष्ठ विरोधी मनोविज्ञान का लाभ उठाने की कोशिश भी कर रहा है तथा चीनी नमून के साम्यवाद और संगठन शक्ती को अफ्रीका में निर्यात करने का उत्सुक है।

जहाँ तक अफ्रीका में सोवियत संघ की भूमिका का प्रश्न है, आजादी से पहले उनकी स्वतंत्रता में उसकी रुचि थी और अब आजादी के बाद उनकी आर्थिक स्वाधीनता में। सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के समाजवादी राज्यों की 'मन्त्र से वहाँ 250 बिजली घर खोल गये हैं जिनमें अस्वान जलविद्युत स्टेशन उल्लेखनीय है। अल्जीरिया का धातुकर्मीय संयंत्र (metallurgical plant) नाइजीरिया का धातु कारखाना तथा इथियोपिया की अस्सब तेल रिफाइनरी सोवियत संघ की सहायता से बनी है। कांगो के तेल शोधक कारखाने में पोलंड ने सहायता दी है और इथियोपिया में टायर का कारखाना स्थापित करने में चेकोस्लोवाकिया ने। सोमालिया में अफ्रीका के अपने ढंग के सबसे बड़े गैशन 'पक' करने वाले कारखाने का बनाने में सोवियत संघ का सहयोग रहा है। इतना ही नहीं, अल्जीरिया सियरा लियोन, इथियोपिया, गिनी नाइजीरिया कांगो, तंजानिया आर दूसरे कई अफ्रीकी देशों में हजारों की संख्या में प्राविन

शिक्षक, भूगर्भशास्त्री, डाक्टर आदि विकास के कार्यों में योग दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक स्तर पर सोवियत संघ अफ्रीकी देशों में प्रगतिशील तत्वों का समर्थन करना है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आर्थिक और सैनिक सहायता भी देता है। कागो, अगोला, इथियोपिया आदि के विवाद में उसकी भूमिका इसका उदाहरण है। बौद्धिक स्तर पर अफ्रीका में साम्यवाद सान के लिए वह बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियाँ दकर अफ्रीकी छात्रों को सोवियत विश्वविद्यालयों में स्थान देता है जहाँ उनके मस्तिष्क को साम्यवाद के रंग में रंग कर वापस उन्हें पुनः उनके देश भेज दिया जाता है। मास्को का लुमुम्बा विश्वविद्यालय अफ्रीकी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा आश्रयण है।

सारांश यह कि अमरीका, रूस, चीन सभी की दिलचस्पी अफ्रीका में है। यद्यपि अभी तक इस महाद्वीप में कोई देश पूरी तरह समाजवादी नहीं बना है तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि अफ्रीकी महाद्वीप की समस्याएँ वहाँ साम्यवाद का आवाहन करती दिखाई देती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अल्पव्यवस्थाओं में इस महाद्वीप की समस्याओं का उत्तर देने की क्षमता नहीं है।

अभ्युदय के परिणाम

अफ्रीका के अभ्युदय में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर व्यापक प्रभाव डाला है। प्रथम, इसने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद पर क्रूर प्रहार किया है। यद्यपि नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में अभी साम्राज्यवादी और गोरी सरकारें विद्यमान हैं तथापि वह दिन दूर नहीं है जब सम्पूर्ण अफ्रीका इनके शासन से मुक्त होकर स्वाधीनता की सासे लेने लगेगा।

दूसरे अफ्रीका राज्यों में उदय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्प्रभुताधारी राज्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के कुल सभ्य राष्ट्रों में एक तिहाई अफ्रीकी है। बर्नार्ड मैक्के लिखता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिलताएँ बढ़ती हैं। तथा प्रशिक्षण व अनुभव से हीन राजनयिकों का बड़ा समूह अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सम्पादन के कार्य को मुश्किल बनाता है। सीमित अनुभव और आंतरिक समस्याओं के दबाव में इनके नेता विदेशी नीति सम्बन्धी मसला पर दैनिक परिचर्या की भाँति विचार करते हैं। विदेशी प्रभाव के प्रति स्थानीय प्रतिक्रिया के विषय में वे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं तथा साव-जनिक रूप से जो वक्तव्य देते हैं वे उनकी शासकीय नीतियों और निजी विश्वासों से मेल नहीं खाते।¹²

तीसरे, अफ्रीका की जागृति ने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में गुट निरपेक्षता की आवाज को दृढ़ बनाया है। वालिन लिखता है कि 'यह अरब राष्ट्रवाद या

जिसने सबप्रथम तटस्थता के विचार को अफ्रीका में आयात किया। तथा यह बहुत कुछ सीमा तक गमाल अब्दुल नासिर का काम था।¹³ नासिर 1955 के बाडुग सम्मेलन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने ही ए. क्यूमा आदि अफ्रीका के दूसरे नेताओं के बीच तटस्थता और गुटनिरपेक्षता की धारणाओं को लोकप्रिय बनाया था। अफ्रीकी राज्यों की शीतयुद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। बर्नार्ड मैक्के के शब्दों में “अफ्रीकियों के लिये शीतयुद्ध केन्द्रीय मुद्दा नहीं है।”¹⁴ वे राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास के साथ साथ अफ्रीकी एकता और विदेशी शासन व ‘श्वेत सर्वोच्चता’ की समाप्ति के कार्यों में लग गये हैं।¹⁵ महाशक्तियों की समस्याओं और प्रतिद्वन्द्वता में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। राबर्ट गुड के शब्दों में उनका नारा है—“शीत युद्ध को अफ्रीका से बाहर रखो।”¹⁶

चाहे, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी अफ्रीका के उदय का भारी प्रभाव पड़ा है। अफ्रीकी राज्यों की विदेश नीतियों के क्रियाव्ययन में संयुक्त राष्ट्र की अहम् भूमिका होती है। वह उन्हें दूसरे राष्ट्रों से सम्पर्क बढ़ाने का लाभकारी मध्य प्रदान करता है, राजनयिक प्रशिक्षण की दृष्टि से वह अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए उपयोगी पाठशाला है आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र व उसके विशिष्ट अभिनर्णन बहुमूल्य सहायता प्रदान करते हैं, तथा कुछ सीमा तक उनकी अखण्डता और सुरक्षा बनाए रखने में भी संयुक्त राष्ट्र योग देता है।

अतः, तथा अंतर्राष्ट्रीय व ध्रुत्व की भावना के विकास में भी अफ्रीका के जागरण का प्रभाव पड़ा है, जिसे पश्चिमी से निम्नांकित गीपक व अतगत अध्ययन किया जा सकता है—

अफ्रीकी भ्रातृत्ववाद

कहा जाता है कि “एशिया अफ्रीका की सुनना में राजनीतिक दृष्टि से बहुत आगे है, लेकिन ‘एकता की खोज’ की दृष्टि से बहुत पीछे है।” अपनी अगणित भिन्नताओं के बावजूद अफ्रीका के उदय ने अफ्रीकावासियों के हृदय में एकता की भावनाओं का संचार किया है। इसके चार मुख्य कारण हैं। प्रथम, एशिया की अपेक्षा अफ्रीकी राज्यों में अधिक भौगोलिक समानता व समीपता है, दूसरा, जातिभेद वहाँ अफ्रीकी भ्रातृत्ववाद पर वह दुष्प्रभाव नहीं डालता जो नस्ल, संस्कृति और जाति की भिन्नता के कारण एशियाई राष्ट्रों की एकता पर पड़ता है, तीसरा, विदेशी आधिपत्य, शोषण और रंगभेद का नकारा

स्वयं रूप से उन्हें आपस में जोड़ने का ही काम लिया है तथा, चीना, 'या-यहारिक' राजनीति में दिनों दिन अब अफ्रीका के लोग एकता के महत्व का समझन लग रहे हैं।

भ्रातृत्ववाद या एकता की भावना का ध्येयगण अफ्रीका में बीसवीं शताब्दी में हुआ है। 1919 में पेरिस में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्रों ने पहली बार एक सावजनिक सभा आयोजित करके राष्ट्र सच के समक्ष यह मांग रखी थी कि अफ्रीका के मूल निवासियों का अन्तर्गर्भीय संरक्षण प्राप्त होना चाहिये तथा अफ्रीकी दशा में जनता की इच्छा का शासन स्थापित किया जाना चाहिये। इसके उपरान्त 1937 में लन्दन में 'एक अफ्रीकनयूरा' की स्थापना हुई और एन्क्रूमा व जामा क्यूटा द्वारा अफ्रीकी एकता आन्दोलन को संगठित करने के लिए अनवरत प्रयास किए गये। इन्हीं में एक 1945 की मन्चेस्टर सभा में उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा अफ्रीका के प्रादेशिक विभाजन की निंदा की गयी।

बाङ्गु सम्मेलन

अफ्रीकी भ्रातृत्ववाद की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति अपने सर्वोत्तम रूप में पहली बार बाङ्गु गा सम्मेलन में प्रगट हुई। अप्रैल 1955 में इण्डोनेशिया के बाङ्गु ग नगर में हुए इस सम्मेलन में 29 राष्ट्रों के 340 एशियाई और अफ्रीकी प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इनमें साम्यवाद विरोधी, साम्यवाद समर्थक, तटस्थ और स्वतंत्र सभी प्रकार के लोग थे। स्वतंत्र जगत को इस सम्मेलन से आशका थी कि चाऊ एन लाई की उपस्थिति के कारण इस सम्मेलन द्वारा साम्यवाद को शक्ति की प्रगति को रोक रोकना और एशियाई व अफ्रीकी राष्ट्र इस सम्मेलन में उपनिवेश विरोधी प्रवृत्तियों का प्रज्ज्वलित करके सम्मेलन को विश्व-व्यापी आधार पर पश्चिम व अमरीका—विरोधी प्रवृत्ति में परिणत कर दें। कदाचित् इसी आशका के कारण अमरीकी सरकार ने सम्मेलन के लिए बधाई-पत्र तक नहीं भेजा। परन्तु वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस सम्मेलन में न केवल मानवीय मौलिक अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के सिद्धांतों व उद्देश्यों के प्रति सम्मान का पहला सिद्धान्त स्वीकार हुआ, अपितु वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को और भी समर्थन मिला।

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई व अफ्रीकी देशों ने निश्चय किया कि वे आर्थिक विकास के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। सभी ने एक स्वर से उपनिवेशवाद की निंदा की और अफ्रीका में हो रहे जातीय भेदभाव व पथक्त्व का लज्जाजनक बताया। इस सम्मेलन में दस सिद्धान्तों वाला निम्न-

कित प्रस्ताव स्वीकार किया गया—

(१) मानव के मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान ।

(२) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति सम्मान की भावना ।

(३) बड़े और छोटे सभी राज्यों को तथा सब जातियों को समान समझना ।

(४) दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ।

(५) प्रत्येक राष्ट्र के इस अधिकार का सम्मान कि वह स्वयं अकेले ही अथवा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सामूहिक रूप से आत्मरक्षा कर सकता है ।

(६) महाशक्तियों द्वारा विशेष हितों की पूर्ति के विशेष उद्देश्य के से की गयी सामूहिक प्रतिरक्षा की व्यवस्थाओं का प्रयोग न करना तथा दूसरे देशों पर दबाव न डालना ।

(७) आक्रमण के काय न करना, इसकी धमकी न देना, किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता या राजनीतिक स्वतंत्रता भंग करने के लिए शक्ति का प्रयोग न करना ।

(८) सब अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान संधिबार्ता, सराधन पञ्चनिर्णय, दायित्व निणय आदि के शांतिपूर्ण उपायों से करना अथवा अन्य ऐसे शान्तिपूर्ण उपायों से करना जिन्हें विवाद करने वाले सब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार स्वयं चुनें ।

(९) पारस्परिक हितों तथा सहयोग की वृद्धि ।

(१०) पाप के प्रति तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान की भावना सम्मेलन की सम्मति में इन सिद्धांतों के पालन से विश्व में शांति और सहयोग की भावना बढ़ सकती है ।'

इस सम्मेलन के विषय में डॉक वॉर्नट न लिखा है कि "यह एशिया और अफ्रीका के पुनरुत्थान का प्रतीक था ।"

एफ्रो एशियन सालिडेरिटी काफेंस

यह सम्मेलन अराजकीय स्तर पर दिसम्बर 1957 के अंतिम सप्ताह में काहिरा में हुआ । इसमें दोनों महाद्वीपों से 500 प्रतिनिधि आए । इस सम्मेलन में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद और जातीय भेदभाव की निन्हा की गई । काहिरा में इस सम्मेलन की एक स्थायी संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया । अप्रैल 1960 में बानात्री में इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ ।

आफ्री सम्मेलन

दिसम्बर 1958 में घाना की राजधानी आफ्री में डा० एनक्रूमा क प्रयत्नों के फलस्वरूप अफ्रीकी राज्यों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें 28 अफ्रीकी देशों के 200 प्रतिनिधि आए। अफ्रीकी एकता संगठन की दिशा में आफ्री सम्मेलन एक सीमा चिह्न था। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीका के जागृत व्यक्तियों को जातीय भेदभाव, बनावटी सीमाओं व उपनिवेशवाद से मुक्त करके उनमें बहुत्व व एकता की भावना का प्रसार करना था। एक प्रस्ताव द्वारा एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की घोषणा की गई जिसका सध्य अफ्रीकी लोगों के मध्य एकता और सहयोग का विकास करना था।

आफ्री सम्मेलन ने सम्पूर्ण महाद्वीप को झकझोर दिया और सभी अफ्रीकी देशों में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई। सम्मेलन का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि डा० एनक्रूमा को अफ्रीकी एकता का संगठन का नेता माना जाने लगा। अफ्रीकी देशों में आत्मविश्वास और चेतना इतनी पनपी कि फ्रांसीसी गिनी के प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी समुदाय का सदस्य होने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि 'हम दासता की अमीरी से स्वतन्त्रता की गरीबी को तरजीह देते हैं।' इससे चिढ़कर जब फ्रान्स ने गिनी की आर्थिक सहायता बंद कर दी तो घाना ने उसे 780 लाख डालर की सहायता प्रदान की।

दुर्भाग्य से इस विषय में सभी पश्चिमी राज्य एकमत नहीं हो सके। उनमें से बहुत से फ्रांस की नाराज करने के पक्ष में नहीं थे। अफ्रीकी राज्यों में दो गुट हो गये। एक गुट जो स्वतन्त्र नीति के पक्ष में था 'कसाब्लाका गुट' कहलाया। इसमें घाना, गिनी, माली, मिस्र, मोरक्को और अल्जीरिया थे। इन छ राज्यों ने मिलकर जून 1962 में एक सामूहिक विकास की योजना बनाई बोमाको में राजनीतिक सचिवालय स्थापित किया, जनरल फोंजी के नेतृत्व में सैनिक ब्रिग बनाई और एक साक्षात् बाजार की स्थापना की जिसका मुख्यालय कसाब्लाका में रखा गया। दूसरा गुट, जिसमें नाइजीरिया, सियरा लियोन, लाइबेरिया, लीबिया, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, टोगो और सोमालिया थे 'मोनो-टोविया गुट' कहलाया। इसका दृष्टिकोण पश्चिम समर्थक था जिसका पहला सम्मेलन लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया में हुआ। इस गुट के देश स्वयं को मयाधवादी, कहते थे। उनके द्विचार से अफ्रीकी साया बाजार' का अर्थ बवल 'कोको को ताबे से बदलना था।'

कुछ समय तक ये दोनों गुट अफ्रीका के लोगों को संगठित करने की अपना-अपना चढ़ बिधटित करने में लग गये। इसका मुख्य कारण नाइजीरिया और घाना के आपसी मतभेद थे। नाइजीरिया व नेता एनक्रूमा के अफ्रीकी एकता संगठन के कार्यों को शका की दृष्टि से देखते थे। नाइजीरिया व एक राजनीतिज्ञ न

वित्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया—

(१) मानव के मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान ।

(२) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति सम्मान की भावना ।

(३) बड़े और छोटे सभी राज्यों को तथा सब जातियों को समान सम्मान ।

(४) दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ।

(५) प्रत्येक राष्ट्र के इस अधिकार का सम्मान कि वह स्वयं अकेले ही अथवा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सामूहिक रूप से आक्रमण कर सकता है ।

(६) महाशक्तियों द्वारा विशेष हितों की पूर्ति के विशेष उद्देश्यों के से की गयी सामूहिक प्रतिरक्षा की व्यवस्थाओं का प्रयोग न करना तथा दूसरे देशों पर दबाव न डालना ।

(७) आक्रमण के काय न करना, इसकी धमकी न देना, किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता या राजनीतिक स्वतन्त्रता भंग करने के लिए शक्ति का प्रयोग न करना ।

(८) सब अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सन्धिवादी, सराजन पंचनिर्णय यायिक निर्णय आदि के शांतिपूर्ण उपायों से करना अथवा अन्य ऐसे शांतिपूर्ण उपायों से करना जिन्हें विवाद करने वाले दल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार स्वयं चुनें ।

(९) पारस्परिक हितों तथा सहयोग की वृद्धि ।

(१०) याय के प्रति तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान की भावना सम्मेलन की सम्मति में इन सिद्धांतों के पालन से विश्व में शांति और सहयोग की भावना बढ़ सकती है ।

इस सम्मेलन के विषय में डाक चार्ज न लिखा है कि "यह एशिया और अफ्रीका के पुनरुत्थान का प्रतीक था ।

एफ्रो-एशियन सॉलिडेरिटी कान्फेंस

यह सम्मेलन अराजकीय स्तर पर दिसम्बर 1957 के अन्तिम सप्ताह में काहिरा में हुआ । इसमें दोनों महाद्वीपों से 500 प्रतिनिधि आये । इस सम्मेलन में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद और जातीय भेदभाव की निंदा की गई । काहिरा में इस संगठन की एक स्थायी संस्था स्थापित करने का निश्चय किया गया । अप्रैल 1960 में कोनाक्री में इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ ।

दिसम्बर 1958 में घाना की राजधानी आफ्रा में डा० एनक्रूमा व प्रयत्नों के फलस्वरूप अफ्रीकी राज्यों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें 28 अफ्रीकी देशों के 200 प्रतिनिधि आये। अफ्रीकी एकता संगठन की दिशा में आफ्रा सम्मेलन एक सीमा चिह्न था। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीका के जागत व्यक्तियों को जातीय भेदभाव बनावटी सीमाओं व उपनिवेशवाद से मुक्त करके उनमें बहुत्व व एकता की भावना का प्रसार करना था। एक प्रस्ताव द्वारा एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की घोषणा की गई जिसका लक्ष्य अफ्रीकी लोगों के मध्य एकता और सहयोग का विकास करना था।

आफ्रा सम्मेलन में सम्पूर्ण महाद्वीप को झकझोर दिया और सभी अफ्रीकी देशों में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई। सम्मेलन का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि डा० एनक्रूमा को अफ्रीकी एकता का संगठन का नेता माना जाने लगा। अफ्रीकी देशों में आत्मविश्वास और चेतना इतनी पनपी कि फ्रांसीसी गिनी के प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी समुदाय का सदस्य होने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि 'हम दासता की अमीरी से स्वतंत्रता की गरीबी को तरजीह देते हैं।' इससे चिढ़कर जब फ्रांस ने गिनी की अधिक सहायता बंद कर दी तो घाना ने उसे 280 लाख डालर की सहायता प्रदान की।

दुर्भाग्य से इस विषय में सभी पश्चिमी राज्य एकमत नहीं हो सके। उनमें से बहुत से फ्रांस को नाराज करने के पक्ष में नहीं थे। अफ्रीकी राज्यों में दो गुट हो गये। एक गुट जो स्वतंत्र नीति के पक्ष में था कस्तालाका गुट' कहलाया। इसमें घाना, गिनी, माली मिस्र, मोरक्को और अल्जीरिया थे। इन छ राज्यों ने मिलकर जून 1962 में एक सामूहिक विकास की योजना बनाई बोमाको में राजनीतिक सचिवालय स्थापित किया जनरल फाजी के नेतृत्व में सैनिक कमान बनाई और एक साक्षात् बाजार की स्थापना की जिसका मुख्यालय कस्ता-ब्लान्का में रखा गया। दूसरा गुट, जिसमें नाइजीरिया, सियरा लियोन लाइबेरिया, लीबेरिया, इथियोपिया ट्यूनीशिया टोगो और सोमालिया थे 'मोनो-टोबिया गुट' कहलाया। इसका दृष्टिकोण पश्चिम समर्थक था जिसका पहला सम्मेलन लाइबेरिया की राजधानी मानोरोबिया में हुआ। इस गुट के दश स्वयं की यथायवादी कहते थे। उनका ज़िच्चार से अफ्रीकी साक्षात् बाजार का अर्थ बचस "कोको को तावे से बनना था।"

कुछ समय तक ये दोनों गुट अफ्रीका के लोगों को संगठित करने की अपेक्षा उन्हें विघटित करने में लग गये। इसका मुख्य कारण नाइजीरिया और घाना के आपसी मतभेद थे। नाइजीरिया के नेता एनक्रूमा के अफ्रीकी एकता संगठन के कार्यो को शक की दृष्टि से देखते थे। नाइजीरिया व एक राजनीतिज्ञ न

टिप्पणी करते हुए कहा था कि "यदि कोई अपने आपका ऐसा मसीहा समझन की गलती करे जिसका लक्ष्य अफ्रीका नेतृत्व करना है तो अफ्रीकी भातृत्ववाद का सम्पूर्ण उद्देश्य ही चीपट हो जायगा।" इस आक्षेप का इशारा ए.कूमा की तरफ था।

मोशी सम्मेलन

फरवरी 1963 में मोशी में एक एफा एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 30 से अधिक प्रस्ताव पास किये गये जिनमें उपनिवेशवाद के उन्मूलन, पराधीन राष्ट्रों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता, अमरीका से विमर्शनात्मक आग्रहों का बहिष्कार करने, दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति आदि की मांग की गई। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों से यह अपील की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन पर बस दें ताकि वह एशिया और अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके।

अफ्रीकी एकता संगठन

मई 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों का अदीस अबाबा में एक सम्मेलन हुआ जिसमें महत्वपूर्ण अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की गई। उपस्थित होने वाले 31 राष्ट्राध्यक्षों ने अफ्रीका में एकता राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य तथा प्रतिरक्षा नीतियों में परस्पर सहयोग, अफ्रीका से उपनिवेशवाद के उन्मूलन और सदस्य देशों की स्वतंत्रता की संयुक्त प्रतिरक्षा की भावना को लेकर अफ्रीकी एकता संगठन के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये।

इस सम्मेलन में घाना के राष्ट्रपति ए.कूमा ने सभी अफ्रीकी देशों के लिए एक द्विसदनीय संसद की स्थापना का सुझाव रखा। वह चाहता था कि अपनी स्वतंत्रता और इतिहास को सुरक्षित रखते हुए 'अरब लीग' या 'अमरीकी राज्यों के संगठन' जैसी कोई संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हो जाये, जिसके माध्यम से सभी अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में पूर्ण सहयोग व साझेदारी का विकास हो सके। सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भावना के बहाव में यह वचन भी दिया कि वे भविष्य में एक-दूसरे के विरुद्ध कभी कोई विध्वंसात्मक या शत्रुतापूर्ण कार्रवाही नहीं करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने वाले अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत अफ्रीकी एकता संगठन ने अपने घोषणापत्र में निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये—

(१) पराधीन अफ्रीकी राष्ट्रों का मुक्त कराना और भ्रष्ट सहयोग और

- (२) अथ राष्ट्रों के घरेलू मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण,
- (३) शान्तिपूर्ण ढंग से सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान,
- (४) दूसरे राष्ट्रों की सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान तथा

(५) गुट निरपेक्षता की नीति का पालन ।

यह निश्चय भी किया गया कि सगठन की तीन मुख्य सस्थायें होंगी । पहली, राज्याध्यक्षों की एक असेम्बली (सभा) और सरकार होगी, जिसकी बैठक वष में कम से कम एक बार होगी । असेम्बली सगठन की सर्वोच्च सस्थ होगी ।

दूसरी सस्था मन्त्रि परिषद होगी, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के परराष्ट्रमन्त्री शामिल होंगे जो वष में कम से कम एक विचार विमर्श के लिये अवश्य मिलेंगे ।

तीसरे, एक सचिवालय होगा, जिसमें सचिव व उसके सहायक होंगे ।

इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता और पक्ष निर्णय के लिए भी एक आयोग स्थापित किया जाएगा जो सदस्य राष्ट्रों के सभी आपसी विवादों का समाधान करेगा । प्रत्येक वर्ष 25 मई को 'अफ्रीकी एकता दिवस' मनाने का भी निर्णय किया गया ।

अफ्रीकी एकता सगठन की बैठक वष में एक बार होती है, लेकिन महत्वपूर्ण तात्कालिक समस्याओं पर विचार करने के लिए इसके विशेष सम्मेलन भी बुलाये जाते हैं ।

जुलाई 1964 में 28 अफ्रीकी राष्ट्रों के अध्यक्ष जवा काहिरा में दूसरी बार मिले तो उन्होंने अफ्रीकी एकता सगठन के विभिन्न आयोगों के मुद्दाव पर विचार किया और अदीस अबाबा (इथियोपिया) में अफ्रीकी एकता सगठन के स्थाई सचिवालय की स्थापना की । दायल तेल्ली इसके प्रथम सचिव नियुक्त हुए ।

अफ्रीकी एकता सगठन की स्थापना हुए लगभग बीस वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों में वह एकता दिखाई नहीं देती जिसकी उससे आशा की गई थी । वार्षिक सम्मेलन में सभी राष्ट्रों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति तक नहीं आते, कुछ केवल परराष्ट्रमन्त्रियों या सरकारी अधिकारियों को ही भेज कर सन्तोष कर लेते हैं लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है ।

सदभ

- 1 टाम म्वोया, "टेशस इन अफ्रीकन डेवलपमेण्ट (1964), पृ 55
- 2 पीटर अब्राहम, "रिपोर्ट आन अफ्रीका" (1955), प 6
- 3 वेसिल डेविडसन, "दि अफ्रीकन अवेकनिंग" (1964), प 233
- 4 थान जूनियर, "अफ्रीकन डिप्लोमेसी स्टडीज इन डिटर्मिनेटस आफ फॉरेन पालिसी" (1966) पृ 174 75
- 5 फ्रेड बक, "अफ्रीकाज क्वेस्ट फॉर आर्डर" (1964), पृ 82
- 6 Africa has states, not nations
- 7 कॉलमन, "नेशनलिज्म इन ट्रापिकल अफ्रीका," दि अमेरिकन पालि० साइस रिव्यू, (1954), प 407 8
- 8 शुल्जबर्गर, पामर व परकिंस कृत "इण्टरनेशनल रिलेशंस" (1964) से उद्धृत, पृ 556
- 9 वही " " " "
- 10 वेद प्रकाश सिंह, "द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात एशिया और अफ्रीका," (दिल्ली), पृ 19
- 11 अनिरुद्ध गुप्ता, "गवर्मेंट एण्ड पालिटिक्स इन अफ्रीका," (1975, दिल्ली) पृ 24
- 12 "अफ्रीका इन वर्ल्ड पालिटिक्स," (1963), पृ 398
- 13 जक्स वासिन, "दि अरब रोल इन अफ्रीका" (1962), प 17
- 14 "इण्टरनेशनल कन्फ्लिक्ट पैटर्न" (1963), प 13
- 15 वही " " " "
- 16 "अफ्रीकाज अन्फिनिशड स्ट्रगल फार फ्रीडम दि रियल इशु," पृ 373

भारत के परराष्ट्र सम्बन्ध

यदि आगामी सदी में हम चीन की सन्धी का इतिहास लिखा जायेगा, तो युगांतकारी घटनाक्रम के रूप में तो महायुद्ध की विभीषिका की चर्चा होगी, न ही महाशक्ति के व्युत्पन्न की न परमाणु शक्ति के उदय की और न बाद मितारों तक पहुँचने के सफल प्रयास की, अपितु जिस एक घटनाक्रम को आसानी से युगांतकारी महत्व का ठहराया जाएगा, वह होगा उपनिवेशवाद के अंत की वह प्रक्रिया जिसने कराइो अरबों लोगों को, एशिया के अफ्रीका के, लातीन अमेरिका के लोगों को अपने भाग्य के खुद ही निर्माता बनने का मौक़ा ही नहीं दिया बल्कि भाग्य निर्माता बना दिया और इस प्रकार वास्कोडिगामा युग का अंत लाकर, मानव सभ्यता के इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय खोल दिया है। स्वतंत्र भारत की परराष्ट्र नीति उसी ऐतिहासिक यात्रा का एक ऐसा जयघोष है जो इस नये युग की पहचान कराता है।

जब द्वितीय महायुद्ध के अंत हान के बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की एक न बाद दूसरी कड़ियाँ बँडियाँ टूटने लगीं तब यह स्मरणीय है कि भारत की दासता की कड़ियाँ बँडियाँ पहले टूटीं और उनके टूटते ही जैसे साम्राज्यवाद के दुग तेजी से धराशायी होते गए, उस एक सत्कारपायी भूचाल आ गया हो। भारत, वर्मा हिंदचीन इण्डोनेशिया, पश्चिम एशिया के अनेक देश तेजी से आजाद होते चले गए और अधः दासता में जकड़ा चीन जापान के पराजित होते ही कुछ ही दिन में महायुद्ध की चपेट में आ गया जिससे उबरने में उसे लगभग 4 वर्ष लगे और जब साम्यवादी दल के नेतृत्व में नया चीन संगठित हुआ, तब पुराने हिंदुस्तान की तरह वह भी एकीकृत रूप में उभर नहीं पाया। उसके भी दाँट बड़े साम्राज्यवादियों ने कर दिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्राज्यवादियों के हाथों जो देशों के बटवारे का मिलसिला चला जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के दो तीन टुकड़े हो गए, भारत भी उनमें एक था। पर विभाजन हो जाने के बाद भी हिंदुस्तान का जो बड़ा भाग भारत के रूप में उदित हुआ उसने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान की अपनी साम्राज्य-

वाद विरोध, उपनिवेशवाद विरोध, रंगभेद विरोध की परंपरा न केवल जारी रखी बल्कि उसकी आवाज को बुलंद किया। एशिया की एकता और सुदृढ़ता के प्रयत्न जारी रखे अफ्रीका की मुक्ति और उसे भाईचारे के सुदृढ़ बंधन में बांधने का प्रयत्न जारी रखे लातीन अमरीकी देशों के साथ समानता व बहुत्व तथा साहचर्य के नये पुल तैयार किये, उसने समाजवाद के महादुष्ट सोवियत और उनके साथी समाजवादी देशों साथ सौहार्दपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को विकसित करने में दिलचस्पी दिखाई, नये चीन से बिरादराना ताल्लुकात बढान में पहल की। नये भारत की ओर से कोशिश यह भी रही कि पश्चिम यूरोप के देशों के आप्रत मजदूर दम और उनकी समाजवादी पार्टियों से नये और सुखद रिश्ते बनें, ब्रिटेन के लेबर दल से बनने भी सगे और महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति के आगमन में अग्रद्वार ले रहे महाशक्ति के रूप में उदित सयुक्त राज्य अमरीका को अपनी नई पहचान बताते हुए उससे सौहार्द और मित्रता से पूर्ण सम्बंधों को विकसित करे ताकि उनकी अमित शक्ति विश्वभर के सघनशील देशों और लोगों के लिए सकट मोचक बन सके, विघ्नकारी नहीं।

ये सारी शुभ और कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ जो भारत की परराष्ट्रनीति का आधार बनी 33 करोड़ लोगों के एक सुदीर्घ, और तेजस्विता पूर्ण स्वाधीनता आंदोलन की विरासत थी। हिंदुस्तान का भूगोल और हिंदुस्तान के इतिहास ने इन प्रवृत्तियों को जन्म दिया और सींचा था, वह अनन्क माध्यमों से प्रकट होती रही। आजादी के बाद, उसका प्रमुख माध्यम बना वह सत्ताधारी दल जो स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा अहिंसक सत्याग्रह के रूप में आंदोलन करने वाला दल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनका श्रेष्ठतम नायक जवाहर लाल नेहरू जो स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और परराष्ट्र मंत्री बन। व उन गांधी जी के अग्र्यतम शिष्य थे जिन्होंने कांग्रेस को एक जनवादी, अहिंसाधर्मी महान आंदोलन के रूप में ढाला, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, उसकी अस्मिता और तेजस्विता के सबसे उज्ज्वल प्रतीकों में प्रमुख थे, स्वाधीनता संग्राम के एक पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व। भारत की परराष्ट्रनीति पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की अमित छाप है।

भारतीय परराष्ट्रनीति की दिशा उसके लक्ष्य

भारत की परराष्ट्र नीति कुछ प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति में सतत चेष्टावान रहती है जो भारतीय परराष्ट्र नीति के अपेक्षाकृत स्थायी आधारों को भी प्रकट करती है। भारत की परराष्ट्र नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं—

1. भारतीय स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता को बनाय रखना। राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने वाले क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

व नेतृत्व धारणा करने वाली शक्तियों के साथ अपने समुचित सम्बंध बनाये रखना ।

2 साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और राष्ट्रीय उत्पीड़न का सवत्र ओर हर समय विरोध करना और विरोध करने वाला को मदद देना ।

3 एशिया और अफ्रीका में नस्लवाद के आधार पर गैरनस्लों का दमन करने वाले देशों तथा इजराइल और दक्षिणी अफ्रीका का विरोध करना और उसके उन्मूलन के सभी प्रयत्नों को बल देना ।

4 एशिया तथा साम्राज्यवाद से पीड़ित अथवा लानीनी और अफ्रीकी लोगों के साथ एक समान आधार वाले भाईचारे और सहयोग व साहचर्य के अनक आधारों के निर्माण के लिए प्रयत्नवान रहना ।

5 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयत्न करना और इस प्रयास में जुटे रहना कि कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप के आस पास शांतिक्षेत्र बना रह सके ।

6 अपने हितों के सवधन के लिए तथा मानवता के व्यापक हितों का ध्यान रखते हुए, सयुक्त राष्ट्रसंघ एवं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करना और उन्हें पुष्ट और समृद्ध बनाने की चेष्टा करना ।

इन उपयुक्त सदियों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय नीति निर्माताओं ने जो नीतियाँ अपनाई हैं उसमें विलग्नता की नीति एक महत्वपूर्ण अंग है । भारत के शासक वर्ग अपने हितों और अथवा सामान्य हितों की पूर्ति के लिए अपने आपको बड़ी ताकतों की मजिद गुटबंदी से दूर रखकर, हर कदम पर स्वतंत्र निणय ले सकने के आग्रही हैं जिस वे विलग्नता की नीति कहते हैं ।

भारत की परराष्ट्र नीति के उपर्युक्त उद्देश्य राष्ट्रीय हितों एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के समन्वय को स्पष्ट करते हैं ।

प्रत्येक राष्ट्र अपनी परराष्ट्र नीति में राष्ट्रीय हितों का सर्वोच्च प्राथमिकता देता है । यद्यपि बदलती परिस्थितियों के साथ परराष्ट्र नीति के व्यवहार में सामयिक परिवर्तन आते रहते हैं किन्तु परराष्ट्र नीति के आधारभूत उद्देश्य एवं सिद्धांत अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं । भारत 1947 में भी गुटनिरपेक्ष था और आज भी है यद्यपि गुटनिरपेक्षता के आयाम बदलते रहे हैं । पण्डित नेहरू ने 4 दिसम्बर 1947 को संविधान सभा में कहा था

“आप चाहें कोई भी नीति अपनाएँ, परराष्ट्र नीति निर्धारण की कला राष्ट्र-हित के सम्पादन में निहित है । हम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग एवं स्वतंत्रता की चाहें कितनी ही बातें करें किन्तु अन्तर्गतत्वा एवं सरकार अपने देश की भलाई के लिए ही काय करती है और कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो उसके राष्ट्र के लिए अहितकर हो । अतः सरकार का स्वरूप चाहें

साम्राज्यवादी हो अथवा साम्यवादी हो, उसका परराष्ट्र मंत्री मूलतः राष्ट्रीय हित में ही सोचता है।”

भारतीय परराष्ट्र नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व

भारतीय परराष्ट्र नीति बहुत से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तत्वों से प्रभावित होती है जो कि स्थायी और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के हैं।

भूराजनैतिक तत्व— भारत एक विशाल देश है जिसे उपमहाद्वीप की सजा दी जाती है इसकी समुद्री सीमा लगभग 6000 कि० मी० एवं स्थल सीमा लगभग 15000 कि० मी० है। भारत की जनसंख्या लगभग 68 करोड़ है। भारत के लिए हिंदमहासागर और हिमालय का विशेष महत्व है। हिंदमहासागर में होने वाली गतिविधियों का भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता रहता है।

भारत की स्थल सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा एवं बंगलादेश से मिलती हैं। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा एवं व्यापार के आधारभूत हित हैं इसीलिए भारत हिंदमहासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखना चाहता है। भारत अपने सीमावर्ती राज्यों में बसने वाले भारतीयों के कल्याण के प्रति सचेत है। पश्चिम एशिया के देशों से भारत को तेल की प्राप्ति होती है।

आर्थिक तत्व—सदियों की पराधीनता के कारण भारत का आर्थिक शोषण होता रहा। स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपना आर्थिक औद्योगिक विकास द्रुतगति से करना चाहता था। भारत ने बिलग्नता की ऐसी नीति अपनाई जिससे भारत के विकास के लिए शांतिपूर्ण स्थिति के निर्माण में मदद मिले तथा दोनों गुटों के देशों से अच्छे सम्बन्ध विकसित हो तथा यथासम्भव आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। 35 वर्षों के विकास में भारत की गरीबी और विपन्नता तो नहीं मटी पर उसके औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के फलस्वरूप आज हम दूसरे दशकों की तकनीक का निर्यात करने में सक्षम हैं।

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति—अतीत से ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने साम्राज्य विरोधी एवं अनाक्रमण की नीति अपनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रितानी साम्राज्यवाद के उन सभी सैनिक अभियानों का विरोध किया जिनके द्वारा अंग्रेज साम्राज्यवादी दूसरे पड़ोसी देशों को अपने अधीन लाने का प्रयत्न करते थे।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सभी देशों के साथ मित्रता एवं सहयोग की नीति अपनाई है। पाकिस्तान ने भारत पर कई आक्रमण किए हैं किंतु सन् 1965 के युद्ध में पाकिस्तान का जो भाग छीन लिया गया था वह तत्काल सम

सीते द्वारा लौटा दिया गया है। सन् 1971 के बांग्ला देश के संकट के समय भी हस्तगत भूमि का भारत ने पाकिस्तान को शिमला समझौते के अंतर्गत वापिस लौटा दिया। भारतीय परमाणु नीति के सिद्धांतों एक आदर्शों पर यह हमारे अतीत के स्पष्ट प्रभाव हैं।

राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव—भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः अहिंसात्मक रहा जिसका प्रभाव प्रारम्भिक काल में हमारी शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर पड़ा। भारत में हर प्रकार के उपनिवेशवाद, जातिवाद एवं रंगभेद की नीतियों का विरोध करना प्रारम्भ किया। भारत राइशिवा में अल्पमत के शासन के विरुद्ध रहा और आज हम नामिबिया के स्वतंत्रता आंदोलन का समयन कर रहे हैं जिसमें भारत की स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग स्पष्ट होता है। भारत महाशक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली नवसाम्राज्यवादी नीतियों के प्रति भी सचेत है।

विचारधारा—भारत की परराष्ट्र नीति का सद्वातिक एवं दार्शनिक पक्ष भारत की ऐतिहासिक परम्परा के साथ जुड़ा हुआ है। विलम्बता की नीति अतिवादी मार्गों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाए की आप्रही है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की परराष्ट्र नीति पर गांधीवाद का प्रभाव है पर 'यवहार में शास्त्रास्त्रों के हस्तमाला में समय आने पर कोई हिचक नहीं रही है। भारतीय समाज व्यवस्था की समस्याओं के सदर्भ में भारतीय नस्ल वग समाजवादी विचारधारा के प्रति सहानुभूति लिखाता है यद्यपि समूची आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह पूँजीवादी रंग में रंगी हुई है वत सविधान में समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिसकी व्याख्या का अधिकार यह नेतृत्व वग अपने पास ही रखता है। परराष्ट्र नीति के निर्माता पण्डित नेहरू के विचारों पर उदारवादी एवं फबियन ढंग की समाजवादी विचारधारा का समीक्षित प्रभाव था। अपने घर में विपन्नता की अन्ती हुई धाई का रोकने के लिए चिंता न करत हुए भी भारत आज अंतराष्ट्रीय व्यवस्था में समानता स्थापित करने हेतु लक्ष्य है और अंतराष्ट्रीय अव्यवस्था में सस्यागन एवं सार्वभौमिक परिवर्तन का हामी है।

नेतृत्व की भूमिका—भारत की परराष्ट्र नीति पर सर्वाधिक प्रभाव पण्डित नेहरू का रहा है। पण्डित नेहरू राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अंतराष्ट्रीय समस्याओं पर कांग्रेस के रुख का मुखरित करते रहे हैं। व अंतराष्ट्रीय राजनीति और उसने खिलाड़ियों में अधिकांश से खूब परिचित थे और व अंतराष्ट्रीय राजनीति के घटनाचक्र और ऊँच नीच की, कांग्रेस में सर्वाधिक जानकारी रखते थे। वस्तुतः यही कारण है कि भारत के प्रथम परराष्ट्र मंत्री की भूमिका उहान बहुत कुशलता और दूरदर्शिता से निभाई और उसे बहुत आयामी बनाया। अगर किसी

एक नीति के निर्धारण में और बहुत कुछ उसके कार्यान्वयन में नौकरशाहियत हावी नहीं हो पाई और राष्ट्रीय नेतृत्व वग की प्रतिभा के दर्शन होते हैं ता वह है इसकी परराष्ट्र नीति। पण्डित नेहरू द्वारा निर्धारित सिद्धांत एवं आदर्श 1977 में स्थापित जनता सरकार द्वारा भी स्वीकार किये गये। पण्डित नेहरू ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं फासीवाद का विरोध किया। उन्होंने महा-शक्तियों के संघर्ष से न केवल भारत को अपितु एशिया को भी दूर रखने का प्रयास किया। उन्होंने भारत के लिए विलम्बिता एवं पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिन अग्र्य व्यक्तियों ने छुटपुट रूप में इस नीति के विकास में मदद की व थे कृष्ण मेनन, गिरिजाशंकर वाजपेयी तथा सरदार पणिकर।

1966 से श्रीमती गांधी ने भारतीय परराष्ट्र नीति को नेहरू के बाद के सत्तार का सामना कर सकने योग्य बनाया। विकासशील देशों में भारतीय हितों की भूमिका को बदलते-सदस्यों में नई दिशा दी है। 18 मई 1974 को भारत ने पोकरण में परमाणु परीक्षण किया और 1975 से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत प्रवेश कर चुका है। अब अग्र्य देशों की तरह भारत में भी सशक्त के महत्व पर अधिकाधिक जोर दिया जाता है और आज सैनिक साज सज्जा का अधुनातन बनाने की धुन नेतृत्व वग में खूब धर कि है।

राष्ट्रीय हित—किसी भी देश की नीति का निर्माण केवल आन्तर्गत के आधार पर नहीं किया जा सकता। वह उन लोगों की समझ और दृष्टि से राष्ट्रीय हितों एवं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है जो उस देश का नेतृत्व वग का होता है। भारत की परराष्ट्र नीति में भी राष्ट्रीय हितों का महत्व दिया गया है। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय हित हैं—

राष्ट्र की एकता को बनाये रखना,

अखण्डता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना,

देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना इस ढंग से करना कि नेतृत्व वग और उनसे जुड़े पूँजीपति वग और धनी किसानों के हितों को बढ़ावा मिले।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ बनाना, जो पूँजीवादी व्यवस्था पर आच न लाये तथा

अग्र्य राष्ट्रों के साथ मंत्री एवं सहयोग की नीति बनाये रखना।

अंतर्राष्ट्रीय वातावरण—किसी भी देश की परराष्ट्र नीति की सफलता बदलती हुई। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति जागरूकता पर निर्भर है। भारत की परराष्ट्र नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों पाये जाते हैं। प्रारम्भ में भारत ने पश्चिमी गुट के प्रति सहानुभूति रखत हुए भी शीतयुद्ध का विरोध किया तथा सैनिक संगठनों से अलग रहा। सन् 1962 में चीनी आक्रमण

के बाद भारत चीन सम्बंध विगड़ गया ये किन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में (1975 से) दोनों दशान सम्बंध सुधार के प्रयास किए। समान उद्देश्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के कारण भारत एवं सोवियत संघ के सम्बंधों में विशेष घनिष्टता रही है। सन् 1980 से हमारे पड़ोस में होने वाली घटनाओं के कारण भारत के सुरक्षा वातावरण में परिवर्तन आया है। भारत इसके प्रति सचेत है एवं हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी लग हुए हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय परराष्ट्र नीति निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों की حامती है। और वह कई तत्वों से संचालित होती है। जवाहर लाल नेहरू का शब्दा में

“मैं भारतीय परराष्ट्र नीति का जनक नहीं हूँ। मैंने उसकी केवल आवाज दी है। यह नीति भारतीय परिस्थितियों की उपज है। भारत की भूतकालीन विचारधारा एवं स्वतंत्रता संग्राम में विकसित विचारों और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम हैं।”

भारतीय परराष्ट्र नीति स्वतंत्रता, “यावत् एवं मानव मूल्यों का महत्व प्रतिपादित करती है। भारत न अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों में सक्रिय भूमिका निभायी है और विश्व मंच पर एशिया एवं अफ्रीका की आवाज को बुलव किया है।

भारतीय परराष्ट्र नीति का विकास

भारतीय परराष्ट्र नीति को 1946 से लेकर अब तक भारत के सामने आए प्रमुख संकटों और विभिन्न प्रधान मंत्रियों के कार्यकाल के आधार पर भी समझा जा सकता है।

प्रमुख संकट

- 1 1946-48 में पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद।
- 2 1962 में चीन-भारत सीमा संश्लेषण संघर्ष।
- 3 1965 में पाकिस्तान-भारत युद्ध।
- 4 1970-71 में बंगला देश संकट।

नेहरू युग

1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय शीत युद्ध प्रारम्भ हो चुका था और दुनिया को गुटों में विभाजित करने के प्रयास चल रहे थे। भारत ने सनिक एवं शक्ति गुटों से दूर रहने का निश्चय किया। पण्डित नेहरू के शब्दों में, “हम उन शक्ति गुटों से दूर रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध

हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं।" भारत ने विलम्बता की जो नीति अपनाई उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता को महत्व देना भी प्रमुख है। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभायी है। पण्डित नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात् एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन आयोजित किया और एशिया को शीत युद्ध से दूर रहने का आह्वान किया।

यद्यपि प्रारम्भ में भारत की विलम्बता की नीति अस्पष्ट रही क्योंकि स्टालिन और अमेरिकीय नेतृत्व दोनों ही भारत को सही मायने में तटस्थ देश नहीं समझते थे। सन् 1950 से पूर्व भारत ने पश्चिमी जर्मनी को ठो कूटनीतिक मायता दे दी लेकिन पूर्वी जर्मनी का नहीं दी।

कोरिया युद्ध एवं हिंदचीन में भारत की सक्रिय निष्पक्ष भूमिका

भारत ने कोरियाई युद्ध में भी पहले पश्चिम का साथ दिया पर बाद में तनाव को कम कराने के प्रयास भी किए। बाद में युद्ध बंदियों को लौटाने के लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से भारत की प्रमुख भूमिका रही। फ्रांस और हिंदचीनी जनता के संघर्ष के समय विवाद के शांतिपूर्ण समाधान हेतु भारत ने 6 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की और जेनेवा समझौते का पालन करवाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग बना, भारत को उसका अध्यक्ष बनाया गया।

पंचशील

भारत ने 'नाटो' एवं 'सीटो' की स्थापना के बाद भी मुटव दी का विरोध जारी रखा और विलम्बता की नीति के द्वारा शांति क्षेत्र के विस्तार के प्रयास किए। 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बती क्षेत्र के बीच व्यापार और आवागमन आदि के बारे में भारत-चीन समझौते में पांच सिद्धांतों का समावेश किया गया जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सिद्धांत हैं—

- 1 पारस्परिक सन्तुष्टि एवं प्रभुत्व का सम्मान।
- 2 अनाक्रमण।
- 3 एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप।
- 4 समानता एवं पारस्परिक हित का ध्यान।
- 5 शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

अप्रैल सन् 1955 में इंडोनेशिया के वाडुग नगर में एक विशाल अफ्रो-एशियाई एकजुटता और समान धर्मों राष्ट्रों के मंच का निर्माण हुआ जिसमें यूरोपीय और अमेरिकी साम्राज्यवादियों को उद्धिग्न किया ही, इससे साविधत संघ में भी कुछ खनबली मची। अफ्राशियन देशों के इस सम्मेलन में पंचशील

के सिद्धांतों को और भी व्यापक बनाया गया। इसके बाद दुनिया के अधिकांश देशों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी। इन सिद्धांतों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए गये लेकिन ये आदर्श स्वीकार किये जाने के बाद भी अधिकांश देशों की परराष्ट्र नीति के व्यवहार में नहीं मिलते।

हंगरी एवं स्वेज संकट

1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप एवं उमीदों के स्वेज नहर पर ब्रिटन, फ्रांस एवं इजराइल के आक्रमणों की विश्व भर में प्रतिक्रिया हुई। भारत ने इन घटनाओं में स्वेज पर आक्रमण की अधिकृत तोड़ आलोचना की।

भारत पर चीन का आक्रमण

सन् 1949 में चीन में साम्यवादी व्यवस्था कायम हुई। उस समय से ही भारत और चीन के सम्बन्धों का महत्व बढ़ गया। भारत ने चीन को कूटनीतिक मान्यता प्रदान की। लेकिन तिब्बत की व्यवस्था जैसे अंग्रेजी जमाने में थी उससे आगे बढ़कर साम्यवादी चीन ने उसे अपन साधन धनिकता से जोड़ लिया। तिब्बत में पुराने भारत को कुछ रियायतें मिली हुई थी जिसे पंचशील समझौते के बाद नया भारत को छोड़ना पड़ा पर भारतीय नेता तिब्बत की स्वायत्तता के पक्षधर रहे। वह इतना घना जुड़ाव पैदा नहीं करते थे और यह तो कतई नहीं कि चीन की फौजें स्थायी तौर पर वहां रहें। चीन की अपनी गृहनीति के फलस्वरूप तिब्बत के कुलीन वर्ग के नेतृत्व में विद्रोह भड़क उठा और तिब्बत के दलाई लामा ने भागकर भारत में शरण ली। इसने सबंधों में कड़ुता पैदा कर दी। प्रारम्भ में कुछ तनाव बढ़ता गया। भारतीय नेताओं का इसमें कुछ अटकलें नहीं लगा कि जाब कश्मीर में पसन्द नहीं करते थे उसे बखुद तिब्बत में करना पंचशील के सिद्धान्तों के विरोध में नहीं मानते थे।

भारत और चीन के बीच 1959 से ही सीमा विवाद भी बढ़ता रहा। भारत और चीन के बीच व्यावहारिक रूप से 'माय मैकमोहन रेखा' को चीन ने वाद में अस्वीकार कर दिया। यह रेखा 1914 में शिमला संधि द्वारा तय की गई थी जिसमें गुलाम भारत की ओर से अंग्रेजों और तिब्बत तथा चीन के बीच सीमा निर्धारण किया गया था। ब्रिटानी सरकार की ओर से सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया था। चीन ने लद्दाख एवं अक्साई चीन के क्षेत्रों पर विवाद उठाया।

20 अक्टूबर 1962 को प्रातःकाल भारत की उत्तरी सीमा पर चीन ने हमला कर मुठभेड़ हुई। इस आवांमिश्र आक्रमण के साथ ही चीन ने भारत का हजारों वर्ग मील क्षेत्र अपन कब्जे में ले लिया। इस युद्ध में अमेरिका और

ब्रिटन न सैनिक सहायता दी किंतु चीन न 21 नवम्बर 1962 को इक्तरफा ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दिसम्बर 1962 में कुछ राष्ट्रों ने भारत-चीन वार्ता के लिए कोलम्बो प्रस्ताव रखे और भारत और चीन के बीच गति राध समाप्त कराने का प्रयास किया किंतु चीन न कुछ शर्तें लगाकर यह प्रस्ताव बाद में अस्योकार कर दिया।

चीन के आक्रमण ■ भारत की कमजोरी स्पष्ट हुई और विलम्बता की नीति पर भी प्रश्न उठने लगे किंतु विलम्बता से यह लाभ अवश्य हुआ कि भारत का बिना शर्त पश्चिमी सहायता मिली और सांग्रियत संधि ने इस संकट के समय चीन का साथ नहीं दिया और भारत के निबट आता गया।

शास्त्री युग

27 मई 1964 को पंडित नेहरू के स्वयंवास के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत का प्रधानमंत्री बन जाँ कि अल्पकाल तक ही रह सके। उन्होंने भारत की परराष्ट्र नीति का आधारभूत सिद्धांतों का जगाव रखा और 5 अगस्त 1964 को पाकिस्तान का साथ युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा जिसे पाकिस्तान न स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान न मार्च अप्रैल 1965 में कच्छ के रेत क्षेत्र में भारत पर आक्रमण किया। राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर 30 जून 1965 को अग्रजों की मध्यस्थता के फलस्वरूप भारत-पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें पहली बार भारतीय नतत्व ने अपना विवाद अंतर्राष्ट्रीय पंच समझौते के लिए सौंप दिया।

अगस्त 1966 में कश्मीर में सशस्त्र घुसपैठिये भेजे गये जिनका भारतीय सेना न सफाया किया। 1 सितम्बर 1965 को पाकिस्तान न कश्मीर के छम्ब क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। अखनूर पर पाक फौजों अधिकार नहीं कर पाई। भारत ने अमेरिकी पैटार्टेको को भी परास्त कर दिया। चीन न भी भारत पर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया। 23 सितम्बर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्तक्षेप से युद्ध विराम कराया गया। इस समय बहुत सा पाकिस्तानी अंश भारत के अधिकार में आ गया था जिसे सोवियत मध्यस्थता द्वारा 10 जून 1966 को बिये गये पाक-भारत ताशकंद समझौते द्वारा वापस लौटा दिया गया। ताशकंद समझौते द्वारा 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति पर दोनों देशों की सेनायें लौटाने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ताशकंद समझौता भारत की उदारता और पाकिस्तान के साथ तनावों को कम करने के प्रयासों का प्रमाण था। यद्यपि स्वर्गीय शास्त्री समझौता कराकर लौट नहीं पाये, पर उन्होंने भारतीय परराष्ट्र नीति एवं सुरक्षा व्यवस्था को मयार्थ

बादी बनाने का प्रयास किया। सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध ने भारत की सजगता स्पष्ट कर दी। अब भारत सैन्यबल के द्वारा समाधान खोजने की दिशा में दृढ़तर कदमों से बढ़ रहा था।

इन्दिरा युग की परराष्ट्र नीति (जून 1966—मार्च 1977)

शास्त्रीजी के आकस्मिक निधन के पश्चात स्वर्गीय नेहरू की पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री बनीं। उन्होंने विलम्ब भारत के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदार एवं शांतिवादी नीतियों पर चलते रहने का भरोसा दिया। श्रीमति गांधी ने पहले 11 वर्ष तक बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ में भारतीय परराष्ट्र नीति का कुशल संचालन किया। यद्यपि इस युग में दो घटकों (गुटबन्दी पर आधारित) की राजनीति कमजोर पड़ने लगी किन्तु एशिया में और विशेषकर दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। भारत का अपना घर-आगन सकटग्रस्त हो गया था।

भारत-पाक तनाव में वृद्धि

1966-67 में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर छिड़पुट घटनाएँ होती रही। याहिया खाँ के सत्ता में आने के उपरांत भारत-पाक सम्बन्धों में और भी तनाव आया।

रबात सम्मेलन (मोरक्को)

22 मितम्बर 1969 को मोरक्को की राजधानी रबात में इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पाकिस्तान ने भारत के प्रवेश का विरोध किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पहुँचने के बाद भी सम्मेलन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया क्योंकि याहिया खाँ ने सम्मेलन का बहिष्कार करने की धमकी दी।

विमान अपहरण कांड

30 जून 1971 को इंडियन एयर लाईन्स के एक विमान का अपहरण करके हवाई अड्डे पर उतारा गया। पाकिस्तान ने अपहरणकर्ताओं को शरण दी। विमान के यात्रियों को अवश्य सौटा दिया गया लेकिन विमान को लाहौर हवाई अड्डे पर जता दिया गया जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव तीव्र हो गया और भारत ने पाकिस्तान के विमानों के भारतीय प्रदेश के ऊपर से उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।

बंगला देश सकट दक्षिणी एशिया की राजनीति

पूर्वी एव पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक तनाव व विग्रह कई वर्षों से रूप ले रहा था। जनरल याहिया खा ने दिसम्बर 1970 में विवश होकर पाकिस्तान में चुनाव कराये जिनमें पूर्वी बंगाल को अवामी लीग को शेख मुजीब व नेतृत्व में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में गठित पीपुल्स पार्टी को बहुमत मिला। अवामी लीग की स्वायत्तता की मांग को याहिया खान एव भुट्टो द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और आन्दोलन का दमन किया जाने लगा। विवश होकर पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने मार्च 1971 में स्वतंत्र बंगला देश की घोषणा की गई।

शरणार्थियों की समस्या और भारत पाक तनाव

पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान मुक्ति आन्दोलन को भारत का षड्यन्त्र बतलाया और पूर्वी बंगाल में दमन और अत्याचार का चक्र चलता रहा जिससे लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। श्रीमति गांधी ने यूरोप के कई देशों तथा अमेरिका की यात्रा की तथा बंगला देश समस्या के बारे में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। भारत द्वारा बंगला देश में अत्याचारों को मानवाधिकार विरोधी और नरस बतलाया। भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ने पर भी पश्चिमी देशों ने अधिक ध्यान नहीं दिया।

अमेरिका-चीन पाकिस्तान

अमेरिका और चीन ने बंगलादेश समस्या को पाकिस्तान का मात्र आंतरिक मामला बतलाया तथा उसे सैनिक और आर्थिक सहायता जारी रखी। जुलाई 1971 में श्रीमति गांधी ने पत्र द्वारा चीन को बंगला देश की घटनाओं से अवगत कराया लेकिन चीन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति निसन के समय भारत अमेरिका सम्बन्धी में तनाव बढ़ा। अमेरिका ने बंगला देश समस्या के प्रति प्रारम्भ में उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया। अमेरिका का कोई वरिष्ठ अधिकारी श्रीमति गांधी की यात्रा के समय ग्युमान हवाई अड्डे पर उपस्थित नहीं था। इस स्थिति में श्रीमती गांधी न वाशिंगटन यात्रा नहीं की और सीधे भारत लौट आयी।

भारत सोवियत संधि (1971)

अगस्त 1971 से पूर्व दक्षिणी एशिया में निरन्तर तनाव बढ़ रहा था।

एक ओर जहाँ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के संघर्ष में अमेरिका और चीन पाकिस्तान के सैनिक शासकों की मदद कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शरणार्थियों के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। अमेरिका एवं चीन में नई दोस्ती स्थापित हो रही थी जिसमें बाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता भी स्पष्ट हो गई। अमेरिका और चीन मिलकर सोवियत संघ का प्रभाव कम करना चाहते थे। इस प्रकार भारत का सुरक्षा वातावरण भी विगड़ चुका था। हिंद महासागर में अमेरिका अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अतः भारत को देश की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक था। भारत ने सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त 1971 को शांति मैत्री एवं सहयोग की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस और भारत की मैत्री संधि कोई सैनिक संधि नहीं है। संधि की धारा 4 में स्वयं सोवियत संघ ने भारत की विलग्नता की नीति को सम्मान देने की बात की है। यद्यपि संधि में यह व्यवस्था है "कि दोनों देशों में से किसी पर आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर दोनों पक्ष शीघ्र ही परम्परा विचार विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जा सके और शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ।"

(भारत सोवियत संधि से) जहाँ एक ओर इस संधि से भारत एवं रूस के सम्बन्धों की और घनिष्ठता स्पष्ट होती है वहीं दूसरी ओर कुछ निहित स्थाप इसके सन्दर्भ में भारत की विलग्नता की नीति पर प्रश्नचिह्न लगाने लगे। अमेरिका एवं चीन ने इस संधि का विरोध किया।

दिसम्बर 1971 का भारत-पाक युद्ध

पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान में) जिसे वहाँ के लोग अब स्वतंत्र बंगलादेश मानने लगे थे) भारतीय हस्तक्षेप का आरोप लगाकर 3 दिसम्बर 1971 भारत के कई स्थानों पर हवाई आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ द्वारा 'वीटो' के कारण सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। 6 दिसम्बर 1971 को श्रीमति गांधी ने संसद में बंगला देश गणराज्य का मान्यता देने की घोषणा की।

भारत-पाक युद्ध 14 दिन चला और 16 दिसम्बर 1971 को बंगला देश की राजधानी ढाका में पाकिस्तान सेना के जनरल ए० के० नियाजी ने अपनी 90 हजार फौज के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगभग 1400 वर्ग मील भूमि पर भारत ने अधिकार कर लिया जिसे बाद में शिमला समझौते द्वारा लौटा दिया गया। 17 दिसम्बर 1971 को भारत ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और पाकिस्तान से युद्धबन्दी प्रस्ताव

की स्वीकृति हेतु अपील की। भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना सातवा जहाजी बेड़ा ६० पूर्वी एशिया से बंगाल की खाड़ी में भेजा था जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना एवं भारत को डराना था किंतु हिंद महासागर में सोवियत युद्ध पोतों की उपस्थिति के कारण अमेरिका कोई सक्रिय कदम नहीं उठा सका।

बंगला देश संकट के प्रभाव

1971 में बंगला देश के निर्माण और भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय के कई प्रभाव हुए। भारत की परराष्ट्र नीति में सपायवाद एवं आत्मविश्वास बढ़ा। यह भी स्पष्ट हो गया कि इस क्षेत्र में अमेरिका की नीति महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और शक्ति राजनीति से अधिक प्रभावित थी। वह दक्षिण एशिया में 'भारत के वचस्व' को मानने से इंकार करता रहता था। पर बंगला देश निर्माण के बाद अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। इस संकट से न केवल पाकिस्तान विखंडित हुआ अपितु यह भी स्पष्ट हो गया कि 1947 में भारत का घातक आधार पर विभाजन अनुचित था। राष्ट्रीय राजनीति में श्रीमति गांधी की और अधिक समर्थन प्राप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख एवं प्रतिष्ठा भी बढ़ी। दक्षिणी एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत का महत्व स्वीकार किया जाने लगा। किंतु भारत के पड़ोसी देशों में यह भावना घर करने लगी कि भारत उनके प्रति दबाव की नीति अपना सकता है लेकिन भारत ने इस प्रकार की शकाओं को निमूल साबित कर दिया।

शिमला सम्मेलन जुलाई 1972

पाकिस्तान के विखंडित हो जाने और बंगला देश के बनने के बाद जुलै के अली भुट्टो के नेतृत्व में बचे-खुचे पाकिस्तान में एक नागरिक सरकार बनी जिसने पारस्परिक वार्ता द्वारा भारत के साथ सम्बंध सुधारने का प्रयास किया। जून 1972 के अंत में एक शिखर सम्मेलन के आयोजन का निश्चय हुआ। 3 जुलाई 1972 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गये। जिनकी प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं

1. भारत और पाकिस्तान की सरकारें पारस्परिक विवादों को समाप्त करने और उपमहाद्वीप में स्थायी शांति के लिए कार्य करेंगी।
2. अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण उपायों से हल करने का प्रयास करेंगी।
3. दोनों देश परस्पर घृणापूर्ण प्रचार नहीं करेंगे।
4. सम्बंधों का सामायजन के लिए (1) डाक सार सेवा एवं संचार

व्यवस्था पुनः स्थापित की जाएगी।

(ii) नागरिका का आन जान की सुविधाएँ दी जाएगी।

(iii) व्यापारिक एवं अन्य आर्थिक मामलों में सहयोग का क्रम अतिशीघ्र प्रारम्भ होगा। विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ाया जायेगा।

5 स्थायी शांति की स्थापना के सम्मम दोनों सरकारें सहमत हैं कि—

(i) भारत और पाकिस्तान की सेनाएँ अपनी अंतराष्ट्रीय सीमाओं में लौट जायेंगी।

(ii) दोनों देश बिना परस्पर हानि पहुँचाए जम्मू काश्मीर में 17 दिसम्बर 1971 को हुए युद्ध विराम की नियंत्रण रेखा को मान्यता देंगे।

(iii) सेनाओं को वापसी इस समझौते के लागू होने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी।

6 दोनों देशों की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्ष उचित अवसर पर पुनः मेंट करेंगे। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि शांति स्थापना और सम्बन्ध बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे।

शिमला समझौता भारत-पाक युद्ध के बाद भारत की उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की इच्छा का प्रतीक है यद्यपि जनसच्ची नेता श्री बाजपेयी ने जीती हुई भूमि को लौटाने के निर्णय का विरोध किया।

पाकिस्तान द्वारा बंदी भारतीय नागरिकों को मुक्त कर दिया गया यद्यपि ऐसी खबरें भी आती हैं कि सभा बंदी वापस नहीं किए गये हैं। पाकिस्तानी मुद्दबंदियों एवं अन्य मानवीय समस्याओं पर 28 अगस्त 1973 को नई दिल्ली समझौता हुआ। इस समझौते द्वारा पाकिस्तान से सभी बंगालियों और बंगला देश से काफी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों और भारत से 195 मुद्दबंदियों को छोड़कर शेष सभी मुद्दबंदियों की जल्दी ही अदला-बदली करने का निर्णय किया गया।

पाकिस्तान ने बंगलादेश को फरवरी 1974 को कूटनीतिक मान्यता दे दी और फिर बंगला देश ने इस्लामिक सम्मेलन में भाग लिया। भारत, बंगलादेश एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने 9 अप्रैल 1974 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत द्वारा परमाणु विस्फोट (18 मई 1974)

भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही शांतिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति

के प्रयोग की नीति रखी है। परमाणु आयोग की स्थापना के साथ ही भारत ने परमाणु तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के प्रयोग प्रारम्भ कर दिये थे। यद्यपि भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्षीकरण का समर्थन करता है और परमाणु आमुखा की रोक का समर्थन करता था। किन्तु हमारे परमाणु प्रसार विरोध संधि (एम० पी० टी०) 1968 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस पर हस्ताक्षर नहीं करवा लेना में पाकिस्तान एवं चीन भी सम्मिलित हैं। भारत इस संधि को जे-भाव पूरा समझता है और उसका मत है कि इस संधि को लागू करने से पूर्व जिन देशों के पास परमाणु आयुध हैं उनके द्वारा आयुध निर्माण पर भी रोक लगायी जाए।

18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान में पोकरण नामक स्थान पर प्रथम (गैस) परमाणु परीक्षण किया जो भारत की विज्ञान एवं तकनीक में प्रगति का द्योतक है। पाकिस्तान ने हमारे प्रति तीव्री प्रतिक्रिया व्यक्त की और जुटो में घोषणा की कि यदि भारत परमाणु बम बना सकता है तो पाकिस्तान भी परमाणु बम बनाएगा चाहे उसे पान पात पारकर जीवित रहना पड़े। पश्चिम के परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र जिनमें—अमेरिका, कनाडा आदि भी भारत की इस सफलता से प्रसन्न नहीं हुए यद्यपि प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अणुशक्ति का विकास शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहता है। इसमें भारत एवं अमेरिका के बीच भी तनाव उत्पन्न हुआ।

श्रीमती गांधी के युग में भारत-अमेरिका सम्बन्ध

राष्ट्रपति जीनसा के निमन्त्रण पर माघ 1966 में श्रीमती गांधी अमेरिका की यात्रा पर गयी। किन्तु अमेरिका ने भारत की आर्थिक कठिनाइयों का लाभ उठाने का प्रयास किया। उनके दबाव पर ही रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा जिससे भारत की साथ की ठेक पहुंचायी। अमेरिका ने भारत की आर्थिक सहायता में 1968 में कटौती की। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में तनाव का प्रमुख कारण वियतनाम की समस्या भी थी। प्रारम्भ में ही भारत द० पूर्वी एशिया में नव साम्राज्यवाद का विरोध कर रहा था। भारत ने वियतनाम पर अमेरिकी हमले की आलोचना की। जनवरी 1970 में भारत द्वारा उत्तरी वियतनाम की सरकार के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए गए जिससे तनाव और बढ़ा।

1971-72 में अमेरिका सम्बन्धों में बहुत बिगाड़ आया जिसका प्रमुख कारण था बंगला देश सबूट। अमेरिका ने 'युद्धपोत राजनय' (गनबोट डिप्लो-मैसी) की बात चलकर 'सातवें बेड़े' (सेवेन फ्लीट) को बंगाल की खाड़ी में

भेजा। किंतु अमरीकी कूटनीति पूरी तरह अमष्ण हो गई। 1973 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में द्वियोगा गार्मिया द्वीप में अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के निणय से सन 1974 में भारत और अमेरिका के संबंधों को पुनः आघात लगा। भारत अमेरिका संयुक्त आयोग की बैठक 1975-76 में भी आयोजित की गई। भारत ने अमेरिका के साथ सहयोग एवं समझौते के प्रयास जारी रखे। काटर के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत अमेरिका संबंध सुधारने के प्रयास फिर किए गए। दिवंगत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की अत्येष्टि पर राष्ट्रपति काटर की मा श्रीमति सिलियन काटर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल भारत भेजा गया था।

चीन से सम्बन्ध सुधार का प्रारम्भ

1962 के सैनिक संघर्ष के बाद भारत एवं चीन के संबंधों में ठहराव आ गया और बीच-बीच में सीमा पर गड़बड़ी होती रही लेकिन 1970 से ही चीन ने भारत विरोधी प्रचार कम कर दिया। इस और भारत के बढ़ते हुए सहयोग के कारण भी चीन को अपनी नीति परिवर्तित करनी पड़ी। बंगला देश समस्या के कारण भारत-चीन संबंध पुनः बिगड़े और भारत सोवियत संघ से चीन और परेशान हो गया। 29 अप्रैल 1975 को चीन द्वारा एक बखतब्य प्रसारित किया गया जिसमें कहा गया कि भारतीय संघ में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया जाना अवध अधिग्रहण है।

1976 में भारत-चीन संबंधों में सुधार होने लगा। अप्रैल 1976 में भारत ने चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया और सितम्बर में चीन राजदूत ने भी भारत में अपना पद ग्रहण किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि मण्डलों का आवागमन भी प्रारम्भ हो गया।

जनता सरकार की परराष्ट्र नीति (मार्च 1977 से 1979)

भारत में आंतरिक आपातकाल के पश्चात् प्रजातांत्रिक माध्यम से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई एवं विदेश मंत्री श्री वाजपेयी ने भारतीय परराष्ट्र नीति के आधारभूत सिद्धान्तों को बनाये रखने पर बल दिया।¹ जनता सरकार ने 'अमली गुटनिरपसत्ता' (जेनुइन नॉन अलाईमेंट) अपना सच्चे अर्थों में गुट निरपसत्ता पर बल दिया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत की परराष्ट्र नीति में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा।

मार्च में 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण करते हुए परराष्ट्र मंत्री श्री वाजपेयी ने स्पष्ट किया "ई सरकार के शासन मकाले

ही न केवल गुट निरपेक्षता के मार्ग पर चलते रहने की अपितु उसके मौलिक तथा सकारात्मक रूप को पुनः प्रतिष्ठित करने की घोषणा की। यह सतोष का विषय है कि वास्तविक गुटनिरपेक्षता पर हमारे द्वारा दिए गए जार और उस नीति के उत्साह एवं गतिशीलता से आगे बढ़ने के हमारे निष्पक्ष को सही अर्थों में देखा और समझा गया है।”

पड़ोसियों से सम्बन्ध सुधार

जनता सरकार ने पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्री लंका, बंगलादेश आदि से सम्बन्ध सुधारने के प्रयास किए। अप्रैल 1977 में श्री बाजपेयी द्वारा पाकिस्तान के समक्ष युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत-पाक सौहार्द नीति को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। पाकिस्तान में सैनिक शाही स्थापित होने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो पर मुकदमा चलाया गया और जब अप्रैल 1979 में उन्हें फांसी दी गई तब भी श्री देसाई ने कोई अपील जारी न कर दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के रवय का एक कठमुल्तापन दिखाया। इस शैली की भारत की आम जनता ने भत्सना की। राष्ट्रपति रेड्डी ने अपनी ओर से ‘अपील’ करना उचित समझा। अपील न करने के इस ‘वचन शरिद्वय’ ने जनता दल के अमानवीय स्वरूप को उदघाटित किया था।

पाकिस्तान से सलाल समझौता

अप्रैल 1978 में पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों के सलाहकार श्री आगा-शाही की भारत यात्रा के समय सलाल पन बिजली परियोजना के जरिये एक पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर हुए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापार में भी वृद्धि की गई। प्रधानमंत्री देसाई एवं विदेशमंत्री बाजपेयी ने अक्टूबर, 1977 में मास्को की यात्रा की जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि जनता सरकार न केवल अमेरिका से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखना चाहती थी बल्कि सोवियत संघ के साथ भी अच्छे सम्बन्ध बनाए रखनी चाहती थी।

जिमी कार्टर की भारत यात्रा

जनवरी 1978 में राष्ट्रपति कार्टर ने भारत यात्रा की जिसके संयुक्त घोषणा पत्र में कई समान सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि पश्चिमी एशिया की समस्याओं का व्यापक, ‘यायोचित एवं स्थायी समाधान’ निकालने की तात्कालिक आवश्यकता है। अफ्रीकी जनता के

आत्मनिर्णय और बहुमत शासन की उचित आकांक्षाओं के प्रति समयन व्यक्त किया गया और सभी रूपों में नस्लवाद की निंदा की गई। दोनों पक्षों ने दुनिया के औद्योगिक और विकासशील राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों की समीक्षा की।

यों तो भारत अमेरिका के बीच सम्बन्ध सुधारने की सम्भावना बढ़ती दिख रही थी, पर तारापुर के लिए भारी पानी के बारे में (यूरेनियम) और भारत द्वारा एन० पी० टी० पर हस्ताक्षर न करने से सम्बंधित विवाद से छटपट बनी रही। अमेरिका ने 1979 में भारत को यह आश्वासन दिया कि वह पाकिस्तान को अणुशक्ति विस्फोट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से रोकने की गंभीर कोशिश करेगा।

भारत और श्रीलंका संबंध

भारत के दक्षिण और हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जिसे मई 1972 से श्रीलंका गणराज्य कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की और कच्चाटीबू द्वीप की समस्या रही है। कच्चाटीबू द्वीप के बारे में जून 1974 में समझौता किया जा चुका था और इसे श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में मान लिया गया। जुलाई 1977 में श्रीलंका में भण्डारनायके का पतन हो गया और श्री जयवर्धन ने सत्ता सम्भाली। श्रीलंका में तमिल विरोधी दंगे हो गए जिनसे प्रभावित होने वाले लोगों को भारत ने भी धन-राशि दी। अक्टूबर 1978 में राष्ट्रपति जयवर्धन ने भारत की यात्रा की और फरवरी 1979 में प्रधानमंत्री देसाई—श्रीलंका की यात्रा पर गए। दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को निरंतर बढ़ाया गया है।

बंगला देश के साथ फरक्का समझौता

भारत ने फरक्का बांध पर पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में बंगलादेश के साथ 5 नवम्बर 1979 को ढाका में हस्ताक्षर किए। यह विवाद पिछले कई वर्षों से बना हुआ था।

22 जून 1978 को भारत इण्डोनेशिया और थाइलैंड ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा अण्डमान सागर में समुद्री सतह का स्थायी रूप से सीमा निर्धारण कर दिया गया।

जनता सरकार पश्चिमी एशिया में अरब देशों का समयन करती रही। जनता सरकार की विदेश नीति को श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने निरंतरता

एक परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय सहमति की विदेशनीति कहा किन्तु वह भारतीय परराष्ट्र नीति को अधिक यथार्थवादी आधार नहीं दे पाए। मर्यादाओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से कई देशों की यात्राएँ कीं। औपचारिक रूप से सम्बन्ध सुधार की घोषणा के बावजूद भी न तो भारत के साथ पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा ही कम हुई और न ही बगला देश के भारत विरोधी दखल में परिवर्तन आया। 1979 के प्रारम्भ से जनता दल में आंतरिक शक्ति संघर्ष तीव्र हो गया। जुलाई 1979 में चौधरी चरणसिंह कायदाहक प्रधानमंत्री बने और जनवरी 1980 तक भारतीय विदेश नीति को सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

लुसाका राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में भारत अकेला पड़ गया तथा हवाना के छठे असलमन राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में भारत का प्रधानमन्त्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व ही नहीं हा पाया और पिछले अधिवर्षों में नेतृत्व करने वाले भारत की आवाज अनसुनी कर दी गई।

भारत ने चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयास किया था लेकिन श्री वाजपेयी की चीन यात्रा के समय चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया जिससे कि भारतीय विदेश मंत्री को बीच में ही यात्रा समाप्त कर लौटना पड़ा। जनता सरकार की अधिक असफलताएँ आंतरिक क्षेत्र में थीं। जितना समय उसे मिला उतने में उसने अन्य देशों की सरकारों के साथ सम्बन्ध बनाने और विवादों और समस्याओं को समझकर उनके लिए वार्ताएँ करने का प्रयास किया। कई दलों का गठबन्धन होने के कारण जनता दल की नीतियों में भी अधिक स्पष्टता नहीं थी और आंतरिक शक्ति राजनीति के कारण इस दल का विघटन हो गया और मध्यावधि चुनाव कराये गये।

इंदिरा गांधी का पुनरागमन और 1980 से भारतीय परराष्ट्र नीति

जनवरी 1980 में मध्यावधि चुनावों में इंदिरा कांग्रेस भारी बहुमत से विजय हुई और श्रीमति गांधी भारत की पुनः प्रधान मंत्री बनीं। उनके नेतृत्व में एक स्थिर राजनीतिक सरकार की स्थापना हुई और उन्होंने भारत की परराष्ट्र नीति को बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में नई दिशा देना प्रारम्भ किया।

दक्षिणी पश्चिमी एशिया में तनाव एवं शीत युद्ध

दिसम्बर 1979 में जब अफगानिस्तान के निमंत्रण पर सोवियत सैनिक वहाँ पहुँचे। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा तीव्र बन गई। भारत ने दिसम्बर 1980 में श्री ब्रेशनेव की भारत यात्रा के

समय अफगानिस्तान के सम्बंध में अपना मत वैभिय प्रकट किया। सोवियत पक्ष से सहमत न होते हुए भी भारत सोवियत की निंदा करने की नीति को ठीक नहीं समझता क्योंकि फौजें वहाँ अफगान शासन के निमंत्रण पर ही आई और पाकिस्तान से हो रही कारवाईयाँ उनकी उपस्थिति को स्थायी बना रही हैं।

अफगानिस्तान की समस्या एवं भारत

भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के आगमन का उतना तीव्र विरोध नहीं किया जितना कि पश्चिमी देशों ने किया है जिन्होंने उसे हस्तक्षेप की सजा दी। किंतु अफगानिस्तान की घटनाओं के कारण भारत के सुरक्षा वातावरण में बहुत परिवर्तन आया है। भारत के राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न हों जिनसे दक्षिणी एशिया में शीतयुद्ध निरंतर चलता रहे। सोवियत संघ से मैत्री के सद्बोध में भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक उपस्थिति का विरोध न करने में बड़े समय से काम किया है किंतु भारत अफगानिस्तान में सोवियत नीति को पूरा समझन भी नहीं दे सकता है। अफगानिस्तान के सम्बंध में शक्तिशाली देशों के समय भी सहमति नहीं हो सकी तथा दोनों देशों की संयुक्त विज्ञप्ति में अफगानिस्तान का उल्लेख भी नहीं किया गया। अमेरिका इसे अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप मानता है और इसे सोवियत विस्तारवाद के खतर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और पाकिस्तान को प्रमुख अग्रवर्ती राष्ट्र बतलाकर उसे 32 अरब डॉलर की आर्थिक एवं सैनिक सहायता दिये जाने की घोषणा रीगन प्रशासन कर चुका है। अमेरिका पाकिस्तान को एफ 16 किस्म के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी देगा जो दूर तक मार कर सकते हैं। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बंधों में तनाव पैदा हो गया है और भारत को अपने सुरक्षा बजट में मजबूरन वृद्धि करनी पड़ रही है। भारत को इसमें सन्देह नहीं है कि यह सारी अमरीकी मदद भारत के विरुद्ध ही काम में ली जायेगी, जैसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान सोवियतों से तो लड़न में रहा। उल्टा यह उन्हें आवश्यक कर रहा है कि वह सोवियत से मैत्री सम्बंध चाहता है। इन द्विपक्षीय प्रयोग केवल भारत के विरुद्ध ही होंगे जैसा पहले भी हुआ।

पाकिस्तान का आणविक कार्यक्रम एवं इस्लामिक बम

पाकिस्तान उन थोड़े से मुस्लिम देशों में है जो पिछले कुछ वर्षों से आणविक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 1971 के उपरान्त उसकी शक्ति लगभग 70 प्रतिशत बढ़ गई है। अमेरिका की कांग्रेस की विशेष

के समक्ष ये तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि पाकिस्तान कराची के पास इस प्रकार की परमाणु भट्टी चला रहा है जिससे भविष्य में परमाणु विस्फोट किया जा सके और परमाणु हथियार भी बनाए जा सकें। इस सन्दर्भ में कई अरब देश पाकिस्तान द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर आधिक्य कठिनाइयाँ के बावजूद अरबों डॉलर व्यय किया जाना भारत से उसकी हठधर्मिता पूर्ण प्रतिस्पर्धा का ही परिचायक है। यह कार्यक्रम भारत के लिए भी सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही यदि परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकें तो यह इस उपमहाद्वीप की शांति एवं सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा पैदा कर सकता है।

हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा

1970 से ही अमेरिका द्वारा डिएगो गार्सिया में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के प्रयासों से ही हिन्द महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिला। भारत हिन्द महासागर में बाहरी हस्तक्षेप का निरन्तर विरोध करता रहा है और संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा पारित 1971 के उस प्रस्ताव का समर्थक है जिससे हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विभिन्न सम्मेलनों में भी इस प्रस्ताव के पक्ष के जनमत तैयार करता रहा है और शिखर सम्मेलनों द्वारा हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं।

अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक उपस्थिति के बाद 1981 में अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपनी नौसैनिक उपस्थिति में और वृद्धि कर दी है। अरब सागर में अमेरिका के 32 से भी बड़े जहाज एवं 13 छोटे जहाज हैं जिनमें विमान वाहक युद्धपोत भी शामिल हैं। सोवियत संघ के इस क्षेत्र में 13 युद्धपोत तथा 17 भी अधिक हवाई जहाज हिन्द महासागर में हैं। इन गतिविधियों से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को भी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। दोनों महाशक्तियों की निरन्तर बढ़ती हुई नौसैनिक गतिविधियाँ न केवल भारत अपितु हिन्द महासागर के अन्य छोटे तटवर्ती राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए गम्भीर चुनौती उत्पन्न करती है और शांति क्षेत्र की स्थापना मात्र एक प्रस्ताव रह गया है।

भारत चीन सम्बन्ध-सीमा विवाद पर वार्ता

यद्यपि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक उपस्थिति के बारे में चीन और अमेरिका की नीति समान है तथापि चीन दक्षिणी एशिया में भारत जैसे प्रमुख

राष्ट्र के साथ सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है और यह हेंग सिआओ पिंग के सत्ता में शक्तिशाली हो जाने के बाद उनकी यथाथवादी नीति का भी भाग है। चीन जहाँ एक ओर भारत से सम्बन्ध सुधार कर सोवियत संघ पर भारत की निर्भरता कम करना चाहता है वहीं दूसरी ओर इससे दक्षिणी एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव कम करने की रणनीति भी चला रहा है। जून 1981 में चीन के विदेश मंत्री फुआंग हुआ न भारत यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और घनिष्ठ बनाने के माग में आने वाली बाधाओं पर भी विचार विमर्श किया। इसके बाद भारत का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल विदेश मंत्रालय में सचिव श्री गोसाल्वेज के नेतृत्व में चीन गया और वहाँ चीनी नेताओं से भारत-चीन सम्बन्धों के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया। भारत और चीन के व्यापारिक आर्थिक सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में सम्बन्ध घनिष्ठ बनाने के लिए वातावरण तैयार किया गया। किंतु भारत-चीन के बीच जो हजारों मील की भूमि सबंधी विवाद है उनके समाधान की दिशा में ठोस संकेत नहीं मिल पाये हैं।

अक्षय चीन क्षेत्र पर चीनी दावा

भारत-चीन भूमि विवाद में चीन ने नवीन प्रस्तावों में यह भी रखा है कि भारत यदि अक्षय चीन का क्षेत्र चीन के अधिकार में छोड़ देता है तो चीन भारत के अन्य क्षेत्रों को लौटाने पर विचार कर सकता है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं का द्वितीय दौर नई दिल्ली में 17 मई 1982 से प्रारम्भ हुआ जिसका नेतृत्व चीन के उप विदेश मंत्री फु हाओ ने किया। चीन के प्रतिनिधि मण्डल में 11 सदस्य थे। इन वार्ताओं में विशेषकर सीमा विवाद के जटिल प्रश्न को सुलझाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। चीन के द्वारा मेकमोहन रेखा को आधार रेखा माने जाने में भी अभी संदेह है। चीन द्वारा जो जिनेवा प्रस्ताव (कुछ क्षेत्रों को भारत द्वारा चीन को दिये जान और बदले में चीन द्वारा भारत को भूमि दिये जाने से सम्बंधित) प्रस्तुत किया गया था। उस पर भी मई 1982 की वार्ताओं में विचार किया गया। अभी तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का शीघ्र समाधान तो संभव नहीं लगता क्योंकि बिना इसमें कई जटिल प्रश्न हैं किंतु आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और वन्य जीविक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग में अभिवृद्धि पर अवश्य प्रगति हुई है। भारतीय विदेश मंत्री नरसिंहराव ने चीन यात्रा का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है। यात्रा की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

यदि भारत और चीन जैसे विशाल क्षेत्र और जनसंख्या वाले देशों में पारस्परिक तनाव कम होते हैं और सहयोग के क्षेत्र विकसित होते हैं तो इससे एशिया

की क्षेत्रीय राजनीति में भी परिवर्तन की सम्भावनाएँ हैं तथा साथ ही भारत-चीन सम्बंध सुधार का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा।

रीगन प्रशासन से भारत के सम्बंध

भारत और अमेरिका के सम्बंधों में सुधार तनाव आते रहे हैं किंतु सोवियत संघ की अफगानिस्तान में सैनिक उदारनीति का नाम पर राष्ट्रपति रीगन द्वारा पाकिस्तान को 3.2 अरब डालर की सैनिक और आर्थिक मदद की घोषणा से भारत-अमेरिका सम्बंधों पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। पाकिस्तान यदि एफ-16 किस्म के विमान प्राप्त करता है तो उससे भारत को भी अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत बनाने के लिए फास से मिराज 2000 प्रकार प्रकार के विमान खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। यह सौदा श्रीमती गांधी की 1981 के फास यात्रा के बाद किया गया।

तारापुर यूरोनियम विवाद

1981 से अमेरिका ने 1963 के द्विपक्षीय समझौते के आधार पर तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए यूरोनियम सप्लाई बंद कर दी है। इससे भारत और अमेरिका के बीच न केवल तनाव में वृद्धि हुई है अपितु अविश्वास भी बढ़ा है। नई दिल्ली और वाशिंगटन में तारापुर संयंत्र भारीपानी समझौते के बारे में कई बार बातचीत हुई है किंतु भारत और अमेरिका ने उस समझौते को विधिवत समाप्त नहीं किया।

भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा दिए जाने वाले 5.8 अरब डालर के सबसे अधिक धनराशि के ऋण का भी सर्वाधिक विरोध अमेरिका द्वारा ही किया गया फिर भी यह ऋण भारत के लिए स्वीकृत हो गया है जिससे भारत को आर्थिक स्थिति को सुधारन में मदद मिलेगी।

भारत और अमेरिका के सम्बंधों में तनाव होते हुए भी श्रीमती गांधी की अमेरिका यात्रा जुलाई 1982 में निश्चिन्ता की गई थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति रीगन से अत्यंत द्विपक्षीय मामलों पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के मामले में रीगन पुनर्विचार को तैयार नहीं है, पर अत्यंत छोटे मोटे मामलों में उनका रुख भारत के लिए नरम रहेगा। मसलन मुद्राकोष के ऋण, तारापुर ईंधन इत्यादि।

भारत और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था

साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के युग से अंतर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर

धनी औद्योगिक देशों का प्रभुत्व रहा है। 20वीं शताब्दी के मध्य से एशिया और अफ्रीका राज्यों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जो कि आज सभ्यता में संयुक्त राष्ट्र सभ में दो तिहाई बहुमत रखते हैं। इन देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन की मांग की जा रही है और यह मांग अर्थव्यवस्था को अधिक समानतावादी और 'यायपूण बनाने के लिये है। भारत भी विकासशील देशों में एक है और वह भी इस मांग को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। 1970 से ही अक्टाड गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्रसभ में इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किये जाते रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन किये जायें और उसे अधिक 'यायपूण बनाया जाये। भारत ने 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग का समर्थन किया।

भारत "77 के समूह" (विकासशील देशों द्वारा अपनी समस्याओं के सदृश में स्थापित विचार विमर्श का समूह जिसके लगभग 125 सदस्य हैं) का प्रमुख सदस्य राष्ट्र है और यह इसका कई वर्षों तक अध्यक्ष भी रहा है। भारत ने विकसित देशों को इस बात के लिये आगाह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गरीब देशों का शोषण समाप्त किया जाए और उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उचित भागीदारी प्रदान की जानी चाहिए।

भारत संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा स्थापित विलीवाट आयोग का भी सदस्य रहा है जिसमें श्री एल० के० झा एक सदस्य थे। इस आयोग ने 1980 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें साधनों और लाभों के उचित वितरण पर बल दिया गया और यह सुझाव भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तर-दक्षिण के देशों (अमीर व गरीब देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए) वातावरण जारी रखनी चाहिए जिससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले आर्थिक तनावों को कम किया जा सके।

उत्तर व दक्षिण के राज्यों के बीच अर्थिक सम्बंध सुधारने के लिए प्रयासों में उत्तरी (धनी) देशों के संरक्षण के बाद के कारण विशेष प्रगति नहीं हो पाई है फिर भी वातावरणों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रहे हैं। 22 से 24 अक्टूबर, 1981 को वानकून (मेक्सिको) में विकसित व विकासशील देशों में से 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को अधिक सहायता और सहयोग दिये जाने पर बल दिया गया। भारत द्वारा विकसित देशों से अपील की गई कि वे अपनी संरक्षणवादी नीतियां छोड़ दें।

1982 के प्रारम्भ में नई दिल्ली में दक्षिण के विकासशील देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कई देशों के प्रतिनिधियों ने पारस्परिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया। सम्मेलन में भारत ने इस बात पर बल दिया कि तीसरी दुनिया के विकासशील देशों को सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करनी चाहिए और विकसित देशों के कठोर रवैये के प्रति सजग रहना चाहिए। भारत ने विकासशील देशों को अपने देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी और सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन कई लोगों की मान्यता है कि इस सम्मेलन के कोई विशिष्ट परिणाम नहीं निकले और इसमें केवल विदेश सचिवों के स्तर पर कुछ ही देशों का औपचारिक विचार विमर्श हुआ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बहुत सी बाधाओं के होते हुए भी भारत नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग का समर्थन करता रहेगा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत दक्षिण के विकासशील देशों की आवाज को बुलन्द करता रहेगा। भारत न विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के समन्वय ग्रुप स्थापित करने का भी सुझाव दिया है जिस पर भविष्य में भी विचार किया जायगा।

भारत और पड़ोसी राष्ट्र

श्रीमती गांधी के सत्ता में वापस आने के बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्पर्क सूत्रों को बराबर बनाये रखा गया है। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक सम्बंध और अधिक बढ़ाये गये हैं। यद्यपि बंगला देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है किन्तु भारत ने इस संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया है।

न्यूमर द्वीप विवाद

बंगाल की खाड़ी में हाल ही में उभरा द्वीप भारत और बंगला देश के बीच विवाद का प्रमुख विषय बन गया है। बंगला देश इसे तलपट्टी द्वीप कहता है तथा इस पर अपना दावा करता रहा है। बंगला देश की नौकाएँ भी इस द्वीप के आस पास देखी गई थी। इस द्वीप पर भारत का अधिकार है और यह समुद्री सर्वेक्षण के अनुसार भी भारत के निकोबार द्वीप समूह के अधिक समीप है। भारत ने इस संदर्भ में पारस्परिक वार्ता द्वारा तनाव को कम करने का भी प्रयास किया है और विदेश मंत्री नरसिंहराव ने बंगला देश की यात्रा भी की लेकिन बंगला देश के नय मांगल ला प्रशासक जनरल इरसाद ने अपनी एक घोषणा में कहा है कि उन्होंने न्यूमर द्वीप पर बंगला देश का दावा छोड़ा नहीं है।

भारत और बंगला देश के मध्य गंगा नदी के पानी के बंटवारे के बारे में विवाद भी नहीं सुलझाया जा सका है। फरक्का बांध के सम्बन्ध में 1977 में जा समझौता किया गया था उससे वर्तमान सरकार पूर्णतः सहमत नहीं है।

भारत और पाकिस्तान तथा भारत और चीन के सम्बन्धों में भी परिवर्तन की सम्भावनाएं हैं। जहां एक ओर महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण दक्षिणी एशिया में तनाव बना हुआ है वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच अनाक्रमण समझौते के बारे में वार्ताएँ चल रही हैं तथा भारत और चीन पारस्परिक तनावों को कम करने और सीमा विवाद को सुलझाने के पयासों में रत है। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारत न केवल दक्षिणी एशिया में अपितु सम्पूर्ण विश्व में शांति चाहता है।

अक्टूबर 1981 में श्रीमती गांधी ने आशियान के दो देशों और टागा तथा फिजी की यात्रा की और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही मलबोन राष्ट्र-मण्डल में भाग लिया जहां विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। श्रीमती गांधी ने इस सम्मेलन में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सधन में विकसित देशों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की भी मांग की।

8 नवम्बर से 15 नवम्बर, 1981 तक भारत की प्रधानमंत्री न बल्गारिया इटली और फ्रांस की यात्रा की। फ्रांस यात्रा के समय दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में समान दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गए तथा भारत न ऊर्जा व सधन में फ्रांस से सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये। अब भारत और फ्रांस के मध्य फ्रांस द्वारा भारत को मिराज 2000 किस्म के 40 विमान दिये जाने का भी समझौता किया जा चुका है।

अप्रैल 1982 में श्रीमती गांधी ने सऊदी अरब की यात्रा की और दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को और घनिष्ठ बनाने पर बल दिया गया। भारत और सऊदी अरब न संयुक्त आयोग की भी स्थापना की। सऊदी अरब द्वारा भारत को अधिक तेल निर्यात का निणय किया गया।

भारत अमेरिका के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर अमेरिका की विश्व व्यापी रणनीति का गंभीर प्रभाव पड़ता रहा है। श्रीमती गांधी न 'इण्डिया टुडे' को अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि जिन देशों से मित्रता है उसे हम और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं जहां नहीं है उसे हम उत्पन्न करना चाहते हैं और जहां विरोध है वहां सबंधों को हम मधुर बनाना चाहते हैं।¹

भारत अंग्रेज देश में दूसरे देशों के सैनिक अथवा अंग्रेज किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध है। गन वपों में अफ्रीका और एशिया के देशों में जो सैनिक

हस्तक्षेप और आंतरिक विद्रोह को भड़काने वाली प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय तनावों में जटिलता लाने के संदर्भ में अधिक पड़ता है। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ भी व्यवहार में कमजोर पड़ा है, उसकी उपेक्षा की गई है जो कि अनुचित है। भारत इजराइल द्वारा गोलन पहाड़ियों के क्षेत्र और गाजा पट्टी को अपने देश में मिलाने के निष्पत्ति का कटु विरोधी रहा है और संयुक्त राष्ट्र में इस प्रकार के प्रस्ताव का भारत द्वारा समर्थन दिया है। लेबनान में इजराइली नरस आक्रमण और फिलीस्तीनियों और लेबनानियों के जीवन, संपदा और नगरों को नष्ट करने की इजराइली राक्षसी कारवाही का भारत ने खुलकर और बहुत बलवती से विरोध किया जब कि अनेक अरब राष्ट्र दुर्भाग्यपूर्ण चुप्पी साधे रहें।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 1947 से अब तक भारत की विदेश नीति बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में निर्मित और व्यवहृत की गई है। उसे अधिकाधिक यथार्थवादी बनाये जाना का प्रयास किया गया है। भारत आज विकासशील देशों में प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान तथा जनशक्ति सम्पन्न देश है।

भारत-पाक सम्बन्ध

अनावृत्त समझौते की राजनीति

आज भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों में संक्रमण की स्थिति है। पाकिस्तान और भारत के बीच बगला देश विवाद के बाण शिमला समझौता पारम्परिक सम्बन्धों का आधार बना। भारत ने पाकिस्तान से छोटी हुई भूमि वापस लौटा दी और सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। भुट्टो के शासन काल में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध थोड़े सुधरे किन्तु कश्मीर की समस्या का शांति पूर्वक द्विपक्षीय आधार पर सुलझाने के लिए शिमला समझौते की शर्तों के अनुसार बचनबद्ध होते हुए भी पाकिस्तान ने इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास किया।

मार्च 1977 में जनता पार्टी का शासन स्थापित होने पर भारत ने पाकिस्तान से सम्बन्ध और सुधारने का प्रयास किया। जुलाई 1977 में पाकिस्तान में पुनः सैनिक ताना स्थापित हो गया और पाकिस्तान ने भारतीय विदेश मंत्री श्री वाजपेयी द्वारा रखे गए युद्ध न करने के समझौते के प्रस्ताव पर विचार टाल दिया। दोनों देशों के बीच व्यापारिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध सुधरते गए। 1978 में सलाल परियोजना के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भुट्टो को फांसी दिए जाने के समय भी भारत ने अहमशेष के सिद्धान्त का पालन किया किन्तु पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट करने की योजना

के सम्बन्ध में समाचार मिलने पर भारत अवश्य चिंतित रहा।

अफगान संकट और पाकिस्तान की अमेरिकी सहायता से उत्पन्न तनाव

अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों के आगमन के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक और आर्थिक सहायता देने का नया प्रस्ताव किया। कार्टर द्वारा प्रस्तावित सहायता को जनरल जिया ने ठुट के मुह में जीरा कहकर अस्वीकार कर दिया। लेकिन 1981 में रीगन प्रशासन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के अनुसार अमेरिका से पाकिस्तान का 32 अरब डॉलर की आर्थिक और सैनिक सहायता दी जाएगी। इस सहायता में पाकिस्तान का एक—16 विमानों का सौदा भी सम्मिलित है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का आधुनिकतम हथियार दिए जाने से भारत चिंतित है और अमेरिकी सरकार से भारत में विरोध भी प्रकट किया है। इससे भारत के सुरक्षा वातावरण में गंभीर परिवर्तन की सम्भावना है तथा भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तानी साथ शक्ति का लगातार बढ़ते जाना भारत के लिए भी अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करना आवश्यक बना देता है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने स्वयं यह स्पष्ट किया था कि अमेरिका द्वारा दिये जाने वाले हथियार सावियत संघ के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किये जा सकते। इससे प्रश्न यह उठता है कि क्या इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया जायेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक अविश्वास और तनाव में वृद्धि का कारण अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिया जाना बन सकता है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान और सहयोग की आवश्यकता है।

यद्यपि श्रीमती गांधी के आलोचक कहते हैं कि युद्ध का भय पदा कर हमारा ध्यान देश की बुनियादी आवश्यकताओं से हटाने का एक साधन है यह विद्वम्बना ही है कि भारत और पाकिस्तान की जनता युद्ध की छाया से भी बचना चाहती है किन्तु बहुत सी समस्याएँ हैं जो हम बार बार युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर देती हैं।

भारत ने पाकिस्तान के समक्ष युद्ध करने के समझौते के बारे में प्रस्ताव 1949 में ही रखा था किन्तु उसे पाकिस्तान के शासकों ने स्वीकार नहीं किया था। 12 अप्रैल 1982 को जनरल जिया ने फैसलावाद में कहा कि 'हम चाहते हैं कि प्रभुसत्ता, सम्मान और गरिमा के आधार पर भारत के साथ हमारे सम्बन्धों के सुधार हों। मुझे आशा है भारत हमारी इस भावना को करेगा।' भारत में अधिकांश लोगों की धारणा है कि अमेरिका में

को सैनिक साज सामान और एफ—16 विमान देने का जो विरोध हो रहा है उसे समाप्त करने के लिए ही “युद्ध न करने” के समझौते का ढोंग किया जा रहा है। इस सम्बंध में स्थिति का मौके पर अनुमान लगाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति पाकिस्तान और भारत के दौर पर भी आयी थी। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को मदद देने के बारे में निणय में भी देर हो गयी।

‘युद्ध न करने’ का प्रस्ताव नये सम्बंधों की पेचीदगी

एक ओर पाकिस्तान अमेरिका से घातक एफ—16 विमान खरीद रहा है और दूसरी ओर 1981 के अंत में पाकिस्तान ने भारत के साथ अनाक्रमण समझौता करने का प्रस्ताव किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ 16 अति आधुनिक विमान बेचने के निणय से दक्षिणी एशिया में अस्थिरता में बढ़ि हुई है। रीगन प्रशासन ने भारत के विरोध और रोप पर ध्यान दिये बिना अपने निणय में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 1968 और 1971 में भी हथियार दिये थे और उद्देश्य यह था कि साम्यवादी प्रभार को रोका जाए परंतु उन हथियारों का प्रयोग भारत में लड़ने में किया गया। अतः वर्तमान हथियारों की दौड़ भी अनाक्रमण समझौते की प्रगति में बाधक है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने भारत से युद्ध न करने के समझौते की पेशकश की है। इस प्रस्ताव के बारे में भारत में व्यापक सदेह पाये जाते हैं। प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने हाल ही में अपनी जम्मू यात्रा के समय सेना के जवानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ‘भारत चाहता है कि विश्व में शांति हो और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध से बचा जाए परंतु हमें हर स्थिति का सामना करने को तैयार रहना है। युद्ध का खतरा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और हथियार खरीदने की दौड़ से मामला और गम्भीर हो गया है।’ जनरल जिया ने भारत के साथ अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव इसलिए भी प्रस्तुत किया क्योंकि उनसे पूर्व सैनिक शासकों ने जब 1965 और 1971 में भारत से सैनिक संपर्क किया तब लाभ की अपेक्षा उन्हें हानि ही अधिक हुई। जिन राजनीतिज्ञों ने उनका उकसाया उन्होंने ही सत्ता प्राप्त की। 1971 में जनरल याहिया से सत्ता भुट्टो के हाथों में आ गयी। युद्ध न करने का समझौता जिया के लिये आदम इस लिये हो सकता है कि पड़ोसी अफगानिस्तान में सोवियत संप्रदाय की सेनाएं पड़ी हैं जो कि न केवल एक महाशक्ति हैं अपितु उनकी भारत के साथ भी घनिष्ठ मित्रता है। जिया न केवल अपने देश में कानून और व्यवस्था को बचोरता से लागू कर रहे हैं अपितु भारत के

साथ घनाक्रमण या युद्ध करने के समझौते के प्रस्ताव द्वारा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह भी जताना चाहा है कि अमेरिका से आधुनिकतम हथियार और सहाय विमान प्राप्त करते हुए भी पाकिस्तान भारत से लड़ना नहीं चाहता है। उनका आलोचना और विरोधिया की धारणा है कि वह न तो पाकिस्तान में परिवर्तन करा कर जनतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और न ही भारत के साथ सम्बन्धों का युद्ध न करने के समझौते और घनिष्ठता तक से जाना चाहते हैं। यह जनता का ध्यान परलु समस्याओं से हटाना चाहते हैं किंतु यह आलाचना पूर्णतः नहीं नहीं हो सकती है।

भारत और पाकिस्तान की स्थिति में 1971 में पाकिस्तान के विभाजन के बाद बहुत अंतर आ गया है। अब भारत दक्षिणी एशिया में एक प्रमुख शक्ति है। अब पाकिस्तान का भारत से उस प्रकार का सैनिक सम्पर्क नहीं सम्भव लगता है और न ही सामर्थ्य हाँ सकता है जैसे कि 1971 से पूर्व हाँ मगता था। यद्यपि अमेरिका पाकिस्तान को मोक्षित विस्तारवाद को रोकने के लिए दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अन्तर्वर्ती (फ्रंटलाइन) राज्य के रूप में काम करना चाहता है।

जनरल जिआ के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री आगाशाही ने अमेरिका के अवर विदेश सचिव जेम्स वकल की इस्लामाबाद यात्रा के समय यह संकेत दिया था कि पाकिस्तान ने भारत के समक्ष युद्ध बजन प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से भारत के समक्ष बहुत बाद में रखा गया। 14 अप्रैल 1982 को भारतीय समाचार पत्रों ने पाकिस्तानी रिपोर्टों के हवाले से लिखा कि पाकिस्तान के शासक जनरल जिआ का कहना है कि अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह युद्ध बजन प्रस्ताव को स्वीकार कर या अस्वीकार करे। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके भारत वही गलती करेगा जो कि पाकिस्तान ने 29 वर्ष पूर्व की थी, किंतु भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि चाहे युद्ध बजन समझौता हो या न हो भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा।

युद्ध बजन समझौता अथवा मित्रता और सहयोग की सन्धि दृष्टिकोणों का अन्तराल

भारत ने पाकिस्तान के युद्ध बजन प्रस्ताव पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया है। भारत के विदेश सचिव एवं दूसरे अधिकारी पाकिस्तान की यात्रा पर भी गए-ये एवं द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार विमर्श किया गया था। मार्च 1982 में पाकिस्तानी विदेश मंत्री श्री आगाशाही ने भारत-पाक सम्बन्धों पर नई दिल्ली में भारतीय नेताओं ने विचार

था, किंतु भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ मौलिक मतभेद हैं, जिन्हें सुलझाया जाना आवश्यक है। युद्ध वजन समझौता करना उतना आसान नहीं है, जितना कि उसके बारे में कहना और प्रचार करना। भारत सरकार की ओर से युद्ध वर्जन समझौते के बारे में उन सात सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया था, जिन्हें इनमें शामिल किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत शिमला समझौते के अंतर्गत स्वीकृत सिद्धांतों से मेल खाते हैं। इसके अंतर्गत एक दूसरे की अखण्डता, प्रभुसत्ता की सम्मान द्विपक्षवाद एवं गुट निरपेक्षता आदि सिद्धान्त आ जाते हैं। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत भी कहे जा सकते हैं। स्वयं पाकिस्तान स्वीकार करता है कि ये सिद्धान्त रचनात्मक एवं उपयोगी हैं, किंतु क्षेत्राधिकार के बारे में मतभेद रहा है। भारत ने यह प्रस्ताव किया था कि दोनों देश अपने पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक सम्प्रभुता अखण्डता और राष्ट्रीय हिता के सम्मान के आधार पर शांति और मित्रता पूर्वक रहना चाहता है।

भारत पाकिस्तान तनाव के बिन्दु

भारत और पाकिस्तान अपने सम्बंधों का सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास अवश्य कर रहे हैं, किंतु भारत विभाजन से लेकर अब तक दाना के दृष्टिकोणों, रणनीतियों एवं विदेशनीतियों में बहुत अंतर रहा है। दाना के बीच विवाद के मुद्दे हैं, जिनके कारण युद्ध वजन समझौता होना दुष्कर प्रतीत होता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक अविश्वास और मनोवृत्ति निम्न तनाव भी बना हुआ है, जिसके कारण सुझावों से भी सन्देह उत्पन्न होता है। भारत का विचार है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के विशेष सम्बंध हैं, जबकि पाकिस्तान यह मानता है कि भारत रूस की ओर झुका हुआ है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ 1959 का वह समझौता अब भी बना हुआ है, जिसके अंतर्गत साम्यवाद से प्रेरित आक्रमण हान पर वह अमेरिका के साथ परामर्श कर सकता है। भारत को यह भी भय है कि पाकिस्तान अपने नवीन एवं आधुनिक बंदरगाह गुजरात को विदेशी नौचालन के अड्डे के रूप में बदल सकता है।

कश्मीर अनसुलझा प्रश्न

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण कश्मीर है। कश्मीर के बारे में यद्यपि पाकिस्तान की नीति में परिवर्तन प्रतीत होता है, किंतु वह कश्मीर को अब भी एक समस्या मानता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार

हमारी भावनाएँ अब भी कश्मीर के बारे में वैसे ही हैं, जैसी कि पहले थी, परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने 1972 में शिमला सम्मेलन के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया था।" कश्मीर के बहुत सारे भाग पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। इस भाग को आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जनरल जिया ने अप्रैल 1982 में यह स्पष्ट कर दिया कि वह कश्मीर को प्रस्तावित युद्ध वजन समझौते से पथक रखना चाहते हैं क्योंकि कश्मीर एक अत्यंत राष्ट्रीय मुद्दा है। जनरल जिया ने इन विचारों के महत्वपूर्ण कूटनीतिक एवं सैनिक परिणाम हो सकते हैं। इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि जिया युद्ध वजन प्रस्ताव द्वारा कुछ खो नहीं रहे हैं।

भारत का मत है कि पाकिस्तान कश्मीर तथा अन्य कोई द्विपक्षीय मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सचय मंच में नहीं उठा सकता लेकिन पाकिस्तान इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता। वह यह नहीं मानता कि कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्रसचय या अन्य किसी अंतराष्ट्रीय मंच पर उठाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान का तर्क यह है कि शिमला समझौते में यह व्यवस्था है कि जम्मू एवं कश्मीर की वास्तविक नियंत्रण रेखा का जो 17 दिसम्बर 1971 के युद्ध विराम के बाद निर्धारित हुई थी, दोनों पक्ष आदर करेंगे, लेकिन दोनों पक्षों की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र सचय में भी कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की यही स्थिति है और यह संयुक्त राष्ट्र सचय की कार्यसूची में भी दर्ज है। अतः पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सचय में कश्मीर विवाद के अंतिम हल के बारे में बात करने से न रोका जा सकता है।

कश्मीर के बारे में जिनेवा में झड़प

भारत और पाकिस्तान के बीच जिनेवा के मानवाधिकार आयोग में इस बात पर झड़प हो गई थी कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि आगाहिलाली ने कश्मीर का उल्लेख पारम्परिक तौर पर किया जिससे कि भारत सहमत नहीं है। भारत कश्मीर का अपना भाग मानता है। विश्व मंच पर कश्मीर का उल्लेख करने के बारे में भारत और पाकिस्तान के अपने अपने तर्क हैं। जनरल जिया ने इस्लामी शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कश्मीर का उल्लेख ही नहीं किया था वरन् इसे प्राप्त करने के लिए समस्त इस्लामी समुदाय से सहायता का आग्रह भी किया था।

हु जा, एलएल और स्कार्दू का मामला

एक प्रमुख महत्वपूर्ण विवाद जो भारत-पाक के बीच चल रहा है, जनरल जिया द्वारा कूटनीतिक दृष्टि से

के साथ विलय करना है और शेष पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कश्मीर के रूप में घोषित करना है। यह क्षेत्र जो कि कश्मीर के भाग है अफगानिस्तान और सिक्खियान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के समीप है इसका पाकिस्तान में विलय भारत द्वारा न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही ऐतिहासिक रूप से हुआ, गिलगित आदि क्षेत्र कश्मीर के भाग हान से नकारे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जून 1982 के प्रारम्भ में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया है जिसके अनुसार ऐतिहासिक आधार पर यह प्रमाणित होता है कि हुआ, गिलगित और स्कादू के क्षेत्र प्रारम्भ से ही कश्मीर के भाग रहे हैं। यह क्षेत्र चीन और पाकिस्तान के सामरिक क्षेत्र में सहयोग के कारण भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इन क्षेत्रों को पाकिस्तान के साथ मिलाना न केवल भारत के लिए चुनौतिया उत्पन्न कर सकता है अपितु भविष्य में चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में विद्यमान अमूल्य खनिज सम्पदा का लाभ उठा सकते हैं। यह नवीनतम विवाद जा कि युद्ध 'वजन प्रस्ताव पर विचार के समय उठाया गया है समझौते के मामले में बाधाएं ही उपस्थित कर सकता है। भारतीय विदेश नीति एवं कूटनीति के महासचिवों के लिए यह चुनौती प्रस्तुत करता है और अधिक से अधिक सावधानी पूर्ण रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता है।

महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और भारत पाक रैस्त्र दौड़

जब पाकिस्तान सीटों एवं सटो का सदस्य था, तब ता वह अमेरिका से सहायता प्राप्त करता ही था, किंतु 1979 से गुटनिस्पेक्षता की नीति अपनाते हुए भी पाकिस्तान अमेरिका से सय सहायता प्राप्त कर रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा एफ—16 विमान और एम—60 टैंक दिए जाने का समझौता किया गया है। पाकिस्तान परमाणु विस्फोट की भी तैयारी कर रहा है। यद्यपि प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने का अधिकार है किंतु भारत को आशंका है कि इन तीव्रगति से चलन वाले विमानों और अग्नि शस्त्रों का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कर सकता है क्योंकि इनका प्रयोग रूस के विरुद्ध तो किया नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमेरिका एवं चीन द्वारा दिए गए हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर भी चुका है। पाकिस्तान का प्रश्न यह है कि भारत जेयु-आर, मिराज 2000, मिग विमान और आधुनिकतम रूसी टैंक खरीद रहा है और अपनी सय व्यवस्था को अधिक से अधिक शक्तिशाली बना रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की यह दौड़ पारस्परिक अविश्वास को ही प्रकट करती है। दोनों देशों को अत्यवस्थाओं पर इससे भार ही बढ़ता है।

अतः दोनों देशों के बीच हथियारों की दौड़ कम करने के लिए वार्ता होनी चाहिए। इस संदर्भ में जनरल जिया ने अनुपात से भारत और पाकिस्तान की सेनाएं कम करने का भी प्रस्ताव रखा था। उनके शब्दों में 'युद्ध से राजनीतिक समस्याएं हल नहीं होती। 1981 में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें न केवल लोगो के बीच ही विश्वास का निर्माण करना है बल्कि दोनों सरकारों के बीच भी करना है।'

भारत और पाकिस्तान भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से आकार में समान नहीं हैं। अतः पाकिस्तान को अपने को भारत का प्रतिद्वंद्वी नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ है जबकि भारत की 66 करोड़ है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यदि पाकिस्तान भारत से होड़ करे तो वह दोनों देशों के लिए हानिकारक होगा। यदि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूर्ति का प्रयास करता है तो भारत बिदकता है और भारत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाता है तो पाकिस्तान चिढ़ता है। यह दृष्टिकोण परस्पर अविश्वास में वृद्धि करता है।

पाकिस्तान, भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 में की गई संधि एवं दोनों देशों के घनिष्ठ सम्बंधों से भी आशंकित है। पाकिस्तान का मत है कि रूस तो संधि के अंतर्गत सुरक्षा वायवाही कर सकता है किंतु अमेरिका पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसा नहीं कर सकता है। भारत अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के प्रति आशंका व्यक्त करता रहा है।

गुट निरपेक्षता और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोणों में अंतर है। भारत सरकार का मत है कि पाकिस्तान को गुटनिरपेक्ष होते हुए किसी भी विदेशी शक्ति को अपने जमीन पर सैनिक अड्डे बनाने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान का मत है कि गुटनिरपेक्षता की उन्नी परिभाषा को स्वीकार किया जाएगा, जिसे हवाना और नई दिल्ली में उसने स्वीकारा था। क्यूबा में रूसी अड्डे हैं। इथोपिया और दक्षिणी यमन में भी है फिर भी वे गुटनिरपेक्ष हैं। अतः पाकिस्तान अमेरिका, और चीन से सहायता लेना भ्रम नहीं कर सकता और विशेषतः तब जबकि अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं बैठी हुई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलकर मैत्रीपूर्ण सम्बंध बनाने के प्रयास करने चाहिए और पारस्परिक संदेहों को दूर करना चाहिए। ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि देशों की जनता के बीच और सरकारों के बीच घुणास्पद वातावरण समाप्त हो और सहयोग की दिशा में बढ़ा जा सके। यदि जैसे तैसे युद्ध वजन समझौता हो भी गया तो आवश्यक नहीं कि स्थायी शक्ति का बंटवारा हो ही जाए। कोई भी मामला संयोग पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान के साथ शांति, मित्रता और

सहयोग की संधि का प्रस्ताव किया है, किंतु पाकिस्तान की प्रतिक्रिया यह है कि वह संधि प्रस्ताव पर तब ही विचार करेगा, जबकि भारत पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दे कि उसने (भारत ने) अनाक्रमण समझौते के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। यह प्रतिक्रिया नई दिल्ली के लिए आवश्यकजनक है क्योंकि मित्रता और सहयोग की संधि में दोनों पक्षों को यह स्पष्ट आश्वासन मिलना है कि दोनों देश पारस्परिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कामवाही करते रहेंगे। मित्रता संधि का प्रस्ताव युद्ध वजन समझौते के प्रस्ताव में एक कदम आगे ही है जिसे जर्नल जिया द्वारा टाला जाना सर्वेह अधिक उत्पन्न करता है और यह लगता है कि वह युद्ध वजन समझौता करना नहीं चाहते, अपितु करार के लिए दिखावा करते रहना चाहते हैं।

भारत ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि के लिए समुक्त आयोग स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है, ताकि बिना किसी देरी के दोनों देशों के बीच अधिक समझ और सहयोग के विकास में मदद मिले। इस कदम से युद्ध वजन समझौता की आरंभ में मदद मिल सकती है, किंतु जर्नल जिया की भावना है कि समुक्त आयोग की स्थापना पर विचार भी युद्ध वजन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही किया जा सकता है। इस प्रकार की गत लगाना भी समझौते के भाग में बाधा ही उपस्थित कर सकता है। राजनैतिक और कूटनीतिक सम्बन्धों में तनाव के कई क्षेत्र हो सकते हैं, किंतु आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग से दोनों देशों की परस्पर नजदीक लान में बहुत मदद मिल सकती है।

कुछ अंतराल और तनावों के पश्चात् भारत पाक सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने के लिए आग विचार विमर्श करने का निणय किया गया है। विदेश मंत्रालय के सचिव श्री नटवर सिंह जून 1982 के प्रथम सप्ताह में भारत के प्रधानमंत्री का एक पत्र लेकर पाकिस्तान गये थे। राष्ट्रपति जिया ने युद्ध वजन प्रस्ताव पर विचार विमर्श को जारी रखने का सुझाव दिया है। पारस्परिक वार्ताओं और अधिकारियों तथा नेताओं की कूटनीतिक यात्राओं से भी दोनों देशों के बीच मौजूद आशंकाओं को दूर करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। चाहे वार्ता भारत के आकांक्षा से हो अथवा पाकिस्तान की भाव पर वार्ताओं से सम्बन्ध सुधार और सौहार्द का माग सरल होता है। यदि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधरते हैं तो दक्षिणी एशिया में स्थायी शांति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। यद्यपि महाशक्तियों की विश्वव्यापी रणनीतियों के कारण आठवें दशक में एशिया में तनावों में बहुत वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र के देशों की फूट का लाभ उठाकर बाहरी शक्तियों ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है। यदि दक्षिणी एशिया के दो प्रमुख देश भारत और पाकिस्तान पारस्परिक तनावों को कम

करने में सफल होते हैं तो यह क्षेत्रीय शान्ति के लिए एक सकारात्मक प्रयास होगा। यद्यपि भारत और पाकिस्तान के बीच उपयुक्त वर्णित बहुत सी बाधाएँ एवं विवाद के मुद्दे हैं, जिनके कारण और द्विपक्षीय सम्बन्धों पर बाहरी शक्तियों के प्रभाव के कारण युद्ध वजन समझौता हाना निकट भविष्य में सम्भव नहीं लगता है। पाकिस्तान में स्वयं जिया का शासन व्यापक समय पर आधारित नहीं है।

विडम्बना यह है कि पाकिस्तान में इस समय भी युद्ध की प्रबल मनोस्थिति बनी हुई है। राखजूद हमके कि वह अमेरिका से आधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सनाओ के अनुपात की बात पाकिस्तान की ओर से 1980 में बही गयी थी, जब तत्कालीन विदेश सचिव श्री नाठे पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और श्रीमती गांधी के विशेष दूत श्री न्युमिन्टन भी यही प्रस्ताव किया गया था। भारत का दृष्टिकोण यह है कि समय आन पर इस बात पर भी विचार कर लिया जाएगा।

पाकिस्तान में यह सद्भावितक विचार धनपा कि भारत न पाकिस्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया है और वह उसे शक्तिशाली नहीं देखना चाहता, किन्तु भारत न बार-बार दोहराया है कि एक सफल और स्वतन्त्र पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में शांति के हित में है। भारत में इस बात पर तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान में युद्धवजन प्रस्ताव अधिक शक्तिशाली होकर किया है अथवा जनरल जिया की कमजोर स्थिति के कारण। किन्तु इस बात पर विचार की ज्यादा आवश्यकता है कि किस प्रकार का द्विपक्षीय समझौता किया जाए, जो कि इस उपमहाद्वीप में शांति के हितों के लिए उपयोगी हो और मानसिक रूप से भारत और पाकिस्तान की सरकारों के लिए स्वीकार्य हो।

श्री आगाशाही के उत्तराधिकारी साहिबजादा याकूब अली की धारणा भी यही है कि युद्ध वजन समझौते की शत के रूप में वह यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कश्मीर के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जा सकेगा। इससे भी अनाक्रमण समझौते के प्रति और दोनों देश के बीच विद्यमान विवादों को सुलझाने के बारे में पाकिस्तान की नीति का पता लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच न केवल सरकारी स्तर पर अपितु दोनों देशों की जनता के बीच भी पारस्परिक सम्बन्धों और समझ में सुधार होना चाहिए क्योंकि 1947 से पूर्व दोनों देशों के बीच जो सामाजिक और सांस्कृतिक एकता थी, उसे कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा विभाजन के साथ ही नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। पाकिस्तान जनता में यदि कोई सद्भाव भी है तो उसका पता लगना भी कठिन होता है क्योंकि पाकिस्तान में समाचार साधन स्वतन्त्र नहीं है।

आवश्यकता इस बात की है कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताओं से निवाला जाय और उन्हीं दम उपमहाद्वीप के दो देशों के पारस्परिक सम्बन्धों के रूप में दृष्टा जाय ताकि वे दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से हानि वाले तात्पर्य का मही तरीके से परछाया जा सके। अब तक दोनों देशों के सम्बन्धों पर हम दृष्टि से अधिर विचार किया गया है कि उनका महाशक्तियों से किस प्रकार के सम्बन्ध हैं।

भारत-पाक युद्ध चक्रण समझौते से पूरा आवश्यक कदम

भारत और पाकिस्तान के बीच आज का सम्बन्ध सुधारण के लिए नवीन वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उन्हीं के सन्दर्भ में सम्बन्धों के स्थायित्व के लिए निम्न कदम उठाये जाने की आवश्यकता है —

1. भारत पाकिस्तान संयुक्त आयोग की स्थापना ताकि गैर राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन मिले।
2. दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय मामलों की स्पष्ट व्याख्या जिससे उनका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करके जटिलता में वृद्धि नहीं किया जा सके।
3. कश्मीर की समस्या, जो कि दोनों के बीच प्रमुख मुद्दा है पर विचार करने के लिए दोनों की सहमति से उचित मानदण्ड निर्धारित करना।
4. भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच सद्भाव के वातावरण में वृद्धि।
5. समाचार माध्यमों द्वारा एक दूसरे के विरोध में प्रचार करने के स्थान पर सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए प्रयास। इस क्षेत्र में दोनों ही देशों में सरकारी समाचार तंत्र की प्रमुख भूमिका हो सकती है।
- बंगलादेश के स्वर्गीय राष्ट्रपति जिया उर रहमान द्वारा प्रस्तावित दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के विकास के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा ही सक्रिय सहयोग, जिससे एशिया के इस भाग में स्थित सभी विकासशील देशों की समस्याओं का पारस्परिकता के आधार पर हल करने में मदद मिल सकती है और कम से कम गैर राजनीतिक क्षेत्रों में तो क्षेत्रीय सहयोग का सरचात्मक और स्थायी आधार किया जा सकता है। इस दिशा में "आसियान" और यूरोपीय समुदाय से प्रेरणा ली जा सकती है।

भारत और पाकिस्तान में सम्बन्धों में सुधार और सहयोग की दिशा में उठाये जाने वाला कोई भी कदम दोनों के लिये ही लाभप्रद होगा। चाहे

युद्धवर्जन समझौता किया जा सके अथवा नहीं। भारत को पाकिस्तान से युद्ध टालने का प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि इस उपमहाद्वीप में सैनिक संधि का लाभ बाहरी शक्तियों और हथियार बेचने वालों को ही हो सकता है, जसा कि अब तक के इतिहास से स्पष्ट है। भारत को पाकिस्तान के साथ अनाक्रमण समझौते के बारे में बात चीत अवश्य रखनी चाहिए किंतु साथ ही सभी प्रकार से भारत की अखण्डता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।

मई 1982 के अंत में विदेश मंत्रालय के सचिव श्री नटवरसिंह द्वारा प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का एक पत्र जनरल जिया को दिया गया। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि फरवरी 1982 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता के आधार पर भारत-पाक वार्ताएँ पुनः प्रारम्भ की जाएँगी। अब पाकिस्तान ने एक स्थायी संयुक्त आयोग की स्थापना का विचार स्वीकार कर लिया है, जो कि व्यापार आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सम्बंधों जैसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय प्रश्नों पर विचार कर सकता है।

भावी वार्ताओं में पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित युद्धवर्जन समझौते और श्रीमती गांधी द्वारा प्रस्तावित मित्रता सहयोग और शांति की संधि के बारे में विचार किया जायेगा। यद्यपि पारस्परिक विचार विमर्श की प्रक्रिया लम्बी अवश्य चल सकती है किंतु इससे दोनों देशों के बीच उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति के प्रयासों में मदद मिलेगी। दोनों के बीच में जो तनाव और अविश्वास का वातावरण रहा है उसे दूर करने के लिए समय लगना स्वाभाविक है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन की सम्भावना अवश्य दिखाई देती है।

विलम्बता या गुट-निरपेक्ष आंदोलन : तीसरी दुनिया का एक विकल्प

अपन शैशव में कि-हो राष्ट्र विशेष की विदेश नीतियाँ का विश्व दृष्टिकोण गुटनिरपेक्षता आज विश्व का प्रबलतम सामूहिक स्वर है। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती समय की ताल को जितना स्पष्ट समझा उतना ही यह और मुखरित हुआ। गुट निरपेक्षता के विकास के दौरान इसे अनेक सैद्धांतिक और व्यावहारिक अवरोधों से जूझना पड़ा। स्वयं अपनी परिभाषा की तलाश गुट निरपेक्षता के लिए एक दुरुह कार्य रहा। तत्व और शब्दावली, दोनों ही स्तरों पर इसे अनेक परम्परागत राजनीतिज्ञों और विश्लेषकों के असहिष्णु दृष्टिकोण का सामना करना पड़ा। कुछ ने इसे पूर्ण रूप से निरर्थक, तो दूसरों ने हास्यास्पद और व्यावहारिक स्तर पर असंभव तक कहा। लेकिन इन प्रश्नों और दृष्टिकोणों के प्रति सचेत तथा आलोचक रूप से गतिशील रहते हुए, गुट-निरपेक्षता ने न सिर्फ एक नयी ऐतिहासिक सभा की स्वरूप और तत्व दिया, बल्कि इसे विश्व राजनीति का एक प्रबलतम मंच भी बना दिया। इस सफलता के मूलभूत ऐतिहासिक सदस्य थे, जिन्होंने समझने और व्यावहारिक स्तर पर प्रतिफलित करने के लिए एक दूर दृष्टीय नतत्व भी उपस्थित हुआ। अतः गुट-निरपेक्षता जैसे बहुदलित आंदोलन, जिसमें आज दो तिहाई विश्व प्रतिबद्ध है, के जन्म और विकास में महत्वपूर्ण व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ कारक रहे हैं। इस दृष्टि से, गुट निरपेक्षता के ऐतिहासिक सदस्य और नेतृत्वकारी प्रारंभिक प्रयासों के विवेचन के बिना इसकी सही समझ अथवा समीक्षा असंभव है।

ऐतिहासिक सदस्य

पश्चिमी राष्ट्रों में पूँजीवाद की स्थापना के बाद उसका जो बाहरी विस्तार हुआ वास्तव में वही से यह नई ऐतिहासिकता जुड़ी है। असीमित विस्तार में

उपनिवेशवाद के प्रभुत्व के खप भी थे जब इस विश्व-यापी आधिपत्य में सूर्यास्त नहीं होता था । लेकिन, प्रत्येक ऐतिहासिक स्थिति के स्वयं के आंतरिक अंतर्विरोध होते हैं जो भविष्य में इतिहास बनाने की प्रक्रिया को पण्ड भूमितयार करते हैं । उपनिवेशवाद की व्यवस्था इस ऐतिहासिकता का कोई अपवाद नहीं थी । उपनिवेशवाद का अंत उसके जन्म में ही समाहित था । उन अंत की प्रक्रिया की प्रारंभिक अनुभूतियां द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से ही होन लगी । उपनिवेशी राष्ट्र अपने विस्तारवादी अभियानों के फलस्वरूप दो विश्वयुद्ध इतिहास में लिख चुके थे । इस प्रक्रिया में उनकी क्षमता इतनी खो चुकी थी कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति असंभव बन गयी थी । इन उभरते सदमों में इतिहास की करवट न उपनिवेशवाद के अंत और राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को सुनिश्चित बना दिया । 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध ने इस प्रक्रिया में एक ऐसी निरंतरता प्रस्तुत की कि एक शताब्दी में अधिकांश की परतंत्रता की व्यवस्था को तोड़ कर एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा । उनका स्वतंत्र स्वर इस ऐतिहासिकता का एक स्वाभाविक परिणाम था । अंत गुटनिरपेक्षता के राजनैतिक, आर्थिक, वैचारिक और भावनात्मक अभिप्रायों को उपनिवेशवाद के अंत की ऐतिहासिकता से जोड़े बिना समझना असंभव है ।

गुट निरपेक्षता, इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की कोई अपरिवर्तनीय परिणति नहीं थी । उपनिवेशवाद का अंत गुटनिरपेक्षता के उदय के लिए एक आवश्यक किंतु पर्याप्त सदम नहीं था । औपचारिक रूप में स्थापित करने की मानसिकता की भी आवश्यकता थी । इस मानसिकता को तैयार करने में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए ध्रुवीकरण का सदम अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा अपनी तात्कालिकता के कारण और साथ ही साथ अपने गुणात्मक अभिप्रायों के कारण, शीतयुद्ध के राजनैतिक ध्रुवीकरण ने गुट-निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया । एक लंबे उपनिवेश आधिपत्य से स्वतंत्र होकर एक लंबे संघर्ष बाद किसी दूसरे अधिपत्य का स्वीकार सेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक अमुविधाजनक स्थिति थी । अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व एक ऐसी भूमिका की तलाश में वे जो उनके आत्मसम्मान और दामता के अनुरूप हो । समता के स्तर पर किसी एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्वतंत्र भूमिका अजित करवाना एक भागीरथी प्रयत्न होता जिसकी संभावनाएँ भी अत्यधिक सदिग्ध बनती । अतः, आत्मसमान की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी, अपितु आवश्यक थी । स्वतंत्रता और सामूहिकता को इस मानसिकता न गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनैतिक नींव रखी । इस प्रक्रिया की शीतयुद्ध के तात्कालिक राजनैतिक वातावरण ने गति प्रदान की ।

राजनैतिक रूप से मिली स्वतंत्रता के बाद भी नवोदित राष्ट्र आर्थिक रूप से

परावसनी ही था रह। यही नहीं, राजनैतिक शासन मूलभूत आर्थिक शोषण का मात्र बाहरी अभिप्राय था। उपनिवेशवादो व्यवस्था ने आर्थिक पिछड़ेपन का आधार तैयार किया, जिनमें उमरना और अधिक महत्वपूर्ण, तबिन उनना ही दुरुह काय था नवोन्ति राष्ट्रों का तीव्र आंतरिक आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। ऐस विकास को सम्भावित यना के लिए दो स्थितिया की आवश्यकता थी। प्रथम तो यह कि, विश्वस्तर पर शांतिपूर्ण शातावरण तैयार हो जिनका फलस्वरूप उन पर किसी विश्वव्यापी संकट में अनचाही सलग्नता न थोपी जा सके। द्वितीय आंतरिक आर्थिक विकास के लिए जिन बाहरी सहयोग की आवश्यकता है, यह नवोन्ति राष्ट्रों को बिना पूर्वाग्रहों और शर्तों के मिलना सम्भव हो सके। अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अनावश्यक विचारों में न उलझना विकास की एक शर्त थी। नवोदित राष्ट्रों में दम प्रकार का दृष्टिकोण और भी अधिक स्वाभाविक था क्योंकि वचारिक स्तर पर उनकी कोई पूर्व और निश्चित प्रतिबद्धता नहीं थी।

अतः उपनिवेशवाद के अंत के ऐतिहासिक सम्म, आर्थिक विकास में स्वावलंबन की कामना और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक आरम्भसम्मानपूर्ण भूमिका की तलाश गुट निरपेक्षता की अनौपचारिक परिभाषा के मूलस्तम्भ बन गया। इन्हीं मतव्यो और मिश्रित अवधारणाओं को गुट निरपेक्षता की भावी और औपचारिक रूप से परिभाषित सना मिली। शीतयुद्ध के तात्कालिक सदस्य और उत्प्रेरणा न गुट निरपेक्षता के प्रारम्भिक स्वरूप को भी परिभाषित किया। नवोदित राष्ट्रों की दूरगामी आकांक्षओं की प्राथमिक राजनैतिक अभिव्यक्ति शीतयुद्ध के दौरान हुई। अतः इसकी प्रारम्भिक औपचारिक परिभाषाओं में इस ध्रुवीकरण का सदस्य अत्यधिक प्रबल है। तथ्य शाश्वती के स्तर पर गुट निरपेक्षता शब्द के चयन से ही स्पष्ट प्रतीक होता है। लेकिन तृतीय राष्ट्रों का अभ्युदय और उनका राजनैतिक स्वर किन्हीं तात्कालिकताओं से नहीं जुड़ा था, अपितु मूलभूत ऐतिहासिक सदस्यों की कोख से उपजा था। इस दृष्टि से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध का दृष्टिकोण इनके जन्म में ही समाहित था। गुट निरपेक्षता की यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति, इसके विकास के साथ-साथ उत्तरोत्तर स्पष्ट हुई।

नैतिककारी सम्म और पहल

नवोदित राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मन्ध की आवश्यकता कोई विवाद का विषय नहीं थी। प्रत्येक नवोदित राष्ट्र इस प्रकार की एकजुटता और सामूहिकता की ओर स्वाभाविक रूप से उन्मुख होता, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभवों में अत्यधिक समानता थी। विवाद इस बात का था कि इस सामूहिक

विलयनता या गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया का एक विकल्प

समन्वय का स्वरूप क्या हो और ऐसे किसी भावी प्रारूप में प्रतिबद्धता का स्तर क्या हो। इन उभरते हुए प्रश्नों के निवारण के स्वरूप से गुट-निरपेक्षता की भावी परिभाषा जुड़ी हुई थी। तृतीय राष्ट्रों में अपने विशिष्ट आर्थिक एवं राजनतिक विकास के कारण, और स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में अगुवा होने के कारण भी, इन प्रश्नों पर भारत के दृष्टिकोण ने विशेष प्रभाव रखा। भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोण में गुट निरपेक्षता की मानसिकता औपचारिक स्वतंत्रता से पूर्व भी देखी जा सकती है। मार्च 1947 में एक एशियाई सबंधों के अधिवेशन में भारत की अंतरिम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेहरू द्वारा प्रकट विचारों में इसका प्राथमिक प्रारूप मिलता है। शब्दावली के स्तर पर भले ही गुट-निरपेक्षता शब्द का प्रयोग न हुआ हो, लेकिन इसके भावी मूल मतव्य, स्वतंत्र विदेशी नीति, ध्रुवीकरण की राजनीति में असह्यता और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेदवाद आदि का विरोध, नेहरू के इस वक्तव्य में समाहित थे। भारत के अलावा प्रारंभिक नेतृत्वकारी प्रयासों और समय में मिश्र और युगोस्लाविया का भी अप्रतिम योगदान रहा। अरब विश्व में मिश्र न सिर्फ स्वतंत्र होने वाला प्रथम राष्ट्र था बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसका समस्त अफ्रीकी महाद्वीप पर भी एक प्रतीकारम्भ प्रभाव था। अपने तुलनात्मक विकास के स्तर पर और वृत्तव्य के स्तर पर मिश्र एक विकसित राष्ट्रीय चेतना का राष्ट्र था। प्रो० अली मजहरही के मत में मिश्र का एक "राष्ट्रीयता केन्द्रित" विश्व दृष्टिकोण प्रारंभ से ही था। इस दृष्टिकोण के केन्द्रीय परिधि में अरब विश्व उनकी बाह्य परिधि के रूप में अफ्रीकी महाद्वीप और उत्तरोत्तर परिधि के रूप में इस्लामिक राष्ट्रों की अवधारणा थी। तीन स्तरीय प्रभाव परिधि के ऐसे दृष्टिकोण में, गुट निरपेक्षता जैसे राजनतिक प्रभाव क्षेत्र का समावेश जा कि मिश्र के दृष्टिकोण की ओर अधिक विश्व-यापी बनाता, एक स्वाभाविक और विकास की द्योतक मायता बन गई। अतः ऐसे राष्ट्रीयता केन्द्रित और विश्वव्यापी नीतिज्ञ की कामना वाले विश्व दृष्टिकोण का गुट निरपेक्षता के भावी स्वरूप में समावेश मिश्र के योगदान का परिचायक है। गुट निरपेक्षता को तात्कालिक ध्रुवीकरण के सदम से जोड़ने में युगोस्लाविया का योगदान विशेष महत्व का कहा जा सकता है। सोवियत गुट से बादविवाद बढ़ जाने और सबंधों में वस्तुतः विघटन आ जाने के बाद युगोस्लाविया एक नये विदेश नीति के दृष्टिकोण की तलाश में था। समाजवादी गुट से मतभेदों के बावजूद युगोस्लाविया पश्चिम की ओर नहीं बढ़ना चाहता था। अतः युगोस्लाविया की विदेश नीति को एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण की तलाश थी जो उसे द्वीय राजनीति में एक सक्रिय और स्वतंत्र भूमिका दे सके। गुट ।

का प्रारूप ऐसी आवश्यकता के लिए एक स्वाभाविक विकल्प था। नहरो-नासिर टीटो यह नेतृत्वाकारी समन्वय गुट निरपेक्षता के मूल प्रारूप को ही नहीं अपितु उसका भावी विकास को भी निरंतर प्रभावित करता रहा। अफ्रीका-एशिया की आम एकता बनाम गुटनिरपेक्षता

नवादिह राष्ट्रों की प्रथम ऐतिहासिक सामूहिक अभिव्यक्ति 1955 में बाहुग सम्मेलन में हुई। इस सम्मेलन का आयोजन का आधार गुटनिरपेक्षता के विकास में इसका परोक्ष योगदान अत्यधिक महत्व का रहा। इस सम्मेलन के दौरान और बाद में तृतीय राष्ट्रों में एक बहुरिक विवाद छिड़ा। यह कि, तृतीय राष्ट्रों की सामूहिकता का स्वरूप स्पष्ट रूप से राजनैतिक हो अथवा नहीं अर्थात् तात्कालिक शीतयुद्ध के समन्वय में एक राजनैतिक दृष्टि को परिभाषित किया जाय अथवा इस समन्वयिक सदस्य के प्रति मौन रह कर कोई अस्पष्ट समन्वय तक ही सीमित रहा जाये। बाहुग अधिवेशन का आयोजन तृतीय राजनैतिक योग्यताओं के आधार पर नहीं किया गया था। इस सम्मेलन में जो राष्ट्र आमंत्रित हुए उन्हें एशिया अफ्रीका के राष्ट्र होने के नाते ही आमंत्रित किया गया था, भले ही वे दो गुटों की राजनीति के प्रभाव के राष्ट्र रहे हों। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक समझ बाहुग अधिवेशन से व्यक्त हुई उसमें पक्षधरों के सिद्धांतों जैसी मायताओं से अधिक कुछ व्यक्त नहीं किया गया। एक दूसरे राष्ट्रों की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अक्षुण्णता का आदर परस्पर अहस्तक्षेप और अनानुमति की नीति समानता और परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सामूहिक एवं पक्षीय आत्मरक्षा का अधिनार आदि सिद्धांत बाहुग सम्मेलन में व्यक्त किये गये। इस प्रक्रिया के द्वारा गुटनिरपेक्षता जैसे सुपरिभाषित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति नहीं हुई अपितु मात्र तृतीय राष्ट्रों में परस्परता का भाव व्यक्त हुआ।

बाहुग सम्मेलन अपने आप में सफल होत हुआ भी, भारत मित्र और युगोस्लाविया के दृष्टिकोण में अपर्याप्त था। किन्हीं सिद्धांतों की घोषणा मात्र उनका दृष्टिकोण में सहयोग का ठोस आधार नहीं हो सका था। नहरो-नासिर-टीटो की दृष्टि और अधिक महत्वाकांक्षी थी, जिसमें तृतीय राष्ट्रों का समा-योजन का एक ऐम स्पष्ट राजनैतिक स्वल्प प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया जिन्हें द्वारा तात्कालिक राजनैतिक सम्मेलनों की गमीना और एक मंत्रिय राजनैतिक भूमिका का प्रारूप बन सके। तृतीय राष्ट्रों का राजनैतिक रूप में संगठित होना पर बल दिया गया। यह राष्ट्र या तो

अनुविधानिक स्थिति पर सम्मिलित थे

अथवा उनके प्रभावशक्ति का महत्वपूर्ण भाग था। ऐसी स्थिति में तृतीय राष्ट्रों को एकत्रित करने के लिए किसी राजनैतिक योग्यता का मापदण्ड इन राष्ट्रों को स्वीकार नहीं था। उनकी दृष्टि में बाहुग सम्मेलन के प्रकार के ही अथवा आयोजन किये जायें, जिनमें बिना किसी राजनैतिक पूर्व शर्तों और मापदण्डों के, सभी एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों को समान रूप से सम्मिलित किया जाये यह दृष्टिकोण भारत, मिथ और युगोस्लाविया को मान्य नहीं था। लेकिन इन राष्ट्रों की नतुत्वकारी भूमिका और पहल होने के कारण इनके दृष्टिकोण को ही उत्तरोत्तर सफलता मिली। इस दृष्टि से देखा जाय तो, सन् 1956 में ब्रिजोनी में नहर्, नासिर और टीटा की शिखरवार्ता परोक्ष रूप से गुटनिरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कहा जा सकता है। इन प्रणेताओं के सामूहिक दृष्टिकोण ने गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। इनके सम्मिलित दृष्टिकोण और प्रयासों के फलस्वरूप ही गुटनिरपेक्षता के आधार पर तृतीय विश्व के समायोजन की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ। विपक्षी दृष्टिकोण में नेतृत्व और पहल का अभाव होने के कारण तृतीय राष्ट्रों में वह दृष्टिकोण कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं पा सका। 1961 के प्रथम काहिरा तैयारी सम्मेलन से और इसी वर्ष के बेल ग्रेड के प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन से, एक ऐसी ऐतिहासिक प्रवृत्ति अस्तित्व में आई जिसने कालांतर में दो तिहाई विश्व को समाहित कर लिया।

बेलग्रेड सम्मेलन के बाद भी एक बार फिर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि तृतीय राष्ट्रों का दूसरा सम्मेलन बाहुग की परिपाटी पर हो अथवा बेलग्रेड की। इस विवाद के पुनः उपस्थित होने की स्थिति में कुछ नये राजनैतिक समीकरण भी थे। 1962 में भारत और चीन के बीच एक सीमित युद्ध लड़ा जा चुका था, और साथ ही साथ कश्मीर के विवाद पर भारत पाक सम्बन्धों में भी और अधिक कटुता आई थी। मिथ और इजराइल का विवाद प्रारम्भ से ही विस्फोटक था और उसमें भी अधिक गिरावट आई। साथ ही साथ अरब राष्ट्रों में भी विभिन्न गुटों के प्रति सलग्नता के कुछ स्वरूप देखे गये। ऐसी स्थिति का देखते हुए भारत और मिथ का एक आम एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के प्रति विरोध और अधिक स्थाई और प्रखर हुआ। जहाँ तक युगोस्लाविया का प्रश्न था वह चूँकि एक यूरोपीय राष्ट्र था, जहाँ उसका एशियाई अफ्रीकी आधार पर आयोजन का विरोध प्रारम्भ से ही मूलभूत था। इन स्थितियों को देखते हुए, इन तीनों राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास हुए कि इण्डो-शिया द्वारा प्रस्तावित बाहुग की परिपाटी का कोई सम्मेलन समय न हो सके। यदि ऐसा कोई सम्मेलन होता तो राजनैतिक योग्यता और मापदण्ड के अभाव में, उसमें चीन पाकिस्तान और इजराइल का सम्मिलित होना स्वाभाविक था। ऐसी

स्थिति स्पष्ट रूप से भारत और मिश्र को सन्ध अमाय थी जिसे युगोस्लाविया का भी सक्रिय समयन प्राप्त था। अतः अब बाडुग की परिपाटी का दूसरा सम्मेलन आयोजित करने का प्रश्न उठा तो भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि चीन को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है तो सोवियत सन्ध को सम्मिलित करना होगा क्योंकि वह भी एक एशियाई राष्ट्र है। राजनैतिक मापदण्डों के अभाव में भारत के प्रस्ताव के औचित्य को गलत सिद्ध करना एक असम्भव बात थी। अतः भारत की इस भायता को स्वीकार किये जाने के बाद, बाडुग परिपाटी के अधिवेशन को आयोजित करने में चीन की जो रधि थी वह स्वतः ही खरम हो गई। तात्कालिक रूप से यह तय हुआ कि 1964 में प्रस्तावित द्वितीय गुटनिरपेक्ष सम्मेलन प्रस्तावित आधार पर आयोजित किया जाये और बाडुग आधार वाले सम्मेलन के प्रस्ताव को तदर्थ रूप से 1965 तक स्थगित किया जाये। यह स्थगन वस्तुतः बाडुग परिपाटी के सम्मेलन के प्रस्ताव का अन्त बन गया। इसके बाद बाडुग बनाम बेलग्रेड का विवाद पुनः नहीं उभर सका। और तृतीय राष्ट्रों का गुटनिरपेक्षता के आधार पर आयोजन एक उत्तरोत्तर विकसित सत्य बन गया। इस पूरी प्रक्रिया से यह परिलक्षित होता है कि भारत, मिश्र और युगोस्लाविया की नतस्वकारी भूमिका और पहल न गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वास्तविक स्वरूप और विकास को गुणात्मक रूप से प्रभावित किया। यह प्रभाव कालांतर में भी यथावत बना रहा।

एक परिभाषित सन्ध की खोज

गुटनिरपेक्षता की एक सटीक परिभाषा की चिन्ता गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कम और विश्लेषण को अधिक रही है। यह एक विचित्र स्थिति इस बात की उत्तरदायी भी रही है कि गुटनिरपेक्षता के वास्तविक अभिप्राय के स्थान पर इसके औपचारिक स्वरूप पर वादिक बहस अधिक देखन की मिली। इस बहस का दायरा शब्दावली पर अधिक केन्द्रित रहा और गुटनिरपेक्षता के आंतरिक तत्व पर कम। एक सही समीक्षा के लिए इस स्थिति में, यह आवश्यक होगा कि गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करने में शब्दावली संबंधित और तत्व सम्बंधी दोनों ही स्तरों पर सन्तुलित विवेचन किया जाये। गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सवप्रथम भारतीय विदेश नीति की कुछ उद्धोषणाओं में मिलता है। इस शब्द से पूर्व तटस्थता आदि शब्द के भी प्रयोग हुए हैं। अनेक पश्चिमी लेखकों ने शब्दावली के स्तर पर बाल की खाल निकालने जैसे प्रयास भी किये। कुछ ने इसे तटस्थता कहते हुए इसकी तुलना स्विटजरलैंड जैसे राष्ट्रों की तटस्थता से भी की। ऐसी तटस्थता का मूल अभिप्राय एक प्रकार की निष्क्रियता से भी लिया गया। अन्य लोगो ने इसे नकारात्मक अथवा सकारात्मक तटस्थता

बतलान का भी प्रयास किया, ता कुछ ने इसके लिए एकपक्षीयता, अप्रतिबद्धता यथवा असलग्नता आदि शब्दावली का भी प्रयोग किया। इन विभिन्न औपचारिक परिभाषाओं में गुटनिरपेक्षता का मूल अभिप्राय एक तरह की निष्क्रियता से लिया गया। ऐसी धारणा इस भावना पर आधारित थी कि ध्रुवीकृत विश्व में किसी भी गुट से जुड़े बिना वादे अंतर्राष्ट्रीय भूमिका अमम्भव है। अमेरिका के राज्य सचिव जान फास्टर डलस ने इस दृष्टिकोण में प्रेरित होकर गुट निरपेक्षता को एक हास्यास्पद, असम्भव और अनतिक्रिशीय नीति तक कहा। निष्क्रियता जैसी धारणा से प्रेरित होकर गुटनिरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विलग्न रहन की नीति भी कहा गया और इसकी तुलना द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व अमेरिकी विदेश नीति से भी किये जाने का प्रयास हुआ। गुटनिरपेक्षता से सद्वास्तविक एवं व्यावहारिक दोनों ही स्तरों पर ऐसी धारणा को संवधानी चिन्तन पूर्ण सिद्ध किया।

एक और आशय गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के प्रति यह भी रहा है कि अपनी शब्दावली के स्तर पर और अपने दृष्टिकोण के स्तर पर, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी यदि कोई भूमिका है तो वह वास्तविक तथ्यों से न जुड़कर कोई सकारात्मक दृष्टि देने की भूमिका नहीं है, अपितु संघर्ष के विपरीत अवरोध उत्पन्न करने की भूमिका है। गुट निरपेक्षता की ऐसी धारणा उसके उदय के प्रारम्भिक वर्षों में अधिक देखने का मिलती है। आलोचना का प्राथमिक अभिप्राय इस सिद्धांत की नकारात्मक शब्दावली से लिया गया है। गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग इस बात का सूचितक बताया गया है कि गुटों से निरपेक्षता एक नकारात्मक दृष्टि है और इससे गुटों के सदस्य से हटकर कोई अन्य परिभाषा यथवा तत्त्व दृष्टिकोण नहीं होता। इस धारणा के प्रत्युत्तर के रूप में अन्य विशेषज्ञों ने गुटनिरपेक्षता की शब्दावली के मर्म को भी सकारात्मक और इसकी दूरगामी दृष्टि को भी अपने सकारात्मक ध्येय की ओर उन्मुख कहा है। जहां तक गुटनिरपेक्षता शब्द का विवाद है, यह कहा गया है कि यह शब्द मूलतः भारत की देन है। अतः इसके शान्दिक अभिप्राय को भारतीय चिन्तन और शब्दावली की परम्परा में देखना चाहिए। भारतीय चिन्तन में यह एक निरंतर परम्परा रही है कि अनेक सकारात्मक विचारों को नकारात्मक शब्दावली से परिभाषित किया गया है। यही नहीं, अन्य भाषाओं की तुलना में साधारण सकारात्मक अभिप्राय भी उसी प्रकार परिभाषित हुए हैं। इस मन्दम में अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे अहिंसा, अन्न, अद्वैत, अपरिहाय, अहस्त्येय आदि। ऐसी ही शब्दावली की परम्परा में देखने पर गुटनिरपेक्षता भी शान्दिक रूप में नकारात्मक होते हुए भी, मतलब के स्तर पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। अतः इस दृष्टि में

शान्तावली के स्तर पर, और अब तक के व्यवहार के अनुभव के आधार पर गुट निरपेक्षता को एक नकारात्मक मिथ्यात अथवा दृष्टिकोण कहना सर्वथा अनुचित होगा।

आलोचना का एक और माध्यम, यह भी रहा है कि गुटनिरपेक्षता एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ सिद्धान्त है और इसकी रचना की कोई प्रेरणा शक्ति नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण में शीतयुद्ध के सदस्य का गुट निरपेक्षता के जन्म के लिए प्राथमिक महत्व का कहा जाना है अर्थात्, गुट निरपेक्षता अपनी किसी स्वयं की प्रेरणाओं से जनित नहीं है, अपितु शीतयुद्ध के ध्रुवीकरण की स्थिति के प्रति मात्र एक प्रतिक्रिया है। इसी में जुड़ा हुआ एक और दृष्टिकोण गुटनिरपेक्षता का शीतयुद्ध के सदस्य में एक नए शक्ति के गठबंधन और केंद्र को स्थापित करने की प्रतिक्रिया के रूप में दर्शाता है। इस तरह से यह कहा गया है कि, एक ओर जहाँ गुटनिरपेक्षता शीतयुद्ध के शक्ति संपर्क और ध्रुवीकरण का विरोधी सिद्धान्त है, तो वहीं दूसरी ओर, इसके स्वयं का अभिप्राय शक्ति के एक तृतीय गुट का आयोजित करना है। अतः गुटनिरपेक्षता न सिर्फ शीतयुद्ध के शक्ति समीकरण के विरोध की एक प्रतिक्रिया है, अपितु साथ ही साथ यह उन्हीं मायताओं पर आधारित है जिनकी यह विरोधी है। गुटनिरपेक्षता का ऐसा दृष्टिकोण एकपक्षीय है। यह सही है कि शीतयुद्ध का सदस्य इसकी परिभाषा में तात्कालिक महत्व का रहा लेकिन गुटनिरपेक्षता का निर्धारण मात्र इस सदस्य के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सदस्य भी थे, जिनसे गुटनिरपेक्षता अधिक अंतरण रूप से जुड़ी थी। मात्र यह तथ्य कि शीतयुद्ध के अवनयन के बाद भी इसका अस्तित्व न सिर्फ बना रहा है बल्कि इसमें आवश्यकता के बढ़ि भी हुई है, इस बात का स्पष्टतम प्रमाण है कि गुटनिरपेक्षता की प्रेरणा सिर्फ शीतयुद्ध की स्थिति की प्रतिक्रिया ही नहीं थी। जहाँ तक शक्ति के एक तृतीय केंद्र अथवा गुट बनाने का दृष्टिकोण है, प्रारम्भ से ही यह एक अव्यावहारिक दृष्टि है। जिसके प्रति गुटनिरपेक्षता नेतृत्व निरन्तर सजग रहा है। आज भी अपने विकास की स्थिति में समस्त गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति किसी एक महाशक्ति के पराक्रम के सामने समानता नहीं पा सकती। ऐसी स्थिति में शक्ति के किसी तीसरे केंद्र की स्थापना तो गुटनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में और न ही उसकी व्यावहारिकता में समाहित है। इसके ठीक विपरीत गुटनिरपेक्षता शक्ति की प्रतिद्वंद्विता के दृष्टिकोण से नहीं अपितु समान हिता और दृष्टिकोण वाले राष्ट्रा में परस्पर समन्वय सहचारिता और मतभेद पर आधारित है।

अभी तक का विवेचन यह दर्शाता है कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। इस

प्रकार का अभ्यास अधिक सुगम है। यदि सकारात्मक रूप से गुट निरपेक्षता को परिभाषित करने का प्रयास किया जाय और स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करने का कहा जाये कि गुट निरपेक्षता क्या है तो यह एक अत्यधिक असुविधाजनक स्थिति होगी। औपचारिक परिभाषा के स्तर पर ऐसी किसी स्पष्ट धारणा को रेखांकित करना एक असम्भव कार्य है। इस दृष्टि से, गुट निरपेक्षता की औपचारिक परिभाषा की तुलना म यदि इस सिद्धांत की ऐतिहासिक प्रेरणाओं और सदस्यों को रेखांकित किया जाये तो यह अधिक साथ प्रयास होगा। ऐसे विवचन से मुख्य गुट निरपेक्षता के प्रमुख मतभेद और अभिप्राय निम्न कह जा सकते हैं —

- 1 गुट निरपेक्षता उपनिवेशवाद की प्रक्रिया से निकले नवोदित राष्ट्रों की एक स्वतंत्र अंतराष्ट्रीय भूमिका का प्रारूप है।
- 2 राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्रता के एक सचेत संघर्ष से जनित वह मानसिकता है जो भावी परतंत्रता और आश्रय की सम्भावनाओं का अपरिहार्य मानती है।
- 3 अतः एक स्वतंत्र नीति जो कि समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित हो गुट निरपेक्षता की प्राथमिक प्रेरणा है।
- 4 उपनिवेशवाद को विरामित से ऐतिहासिक रूप से जुड़ी होने के कारण, और इसके कटु अनुभवा के प्रति सचेत होने के कारण, उपनिवेशवाद और उससे सलग्न आधिपत्य की प्रक्रियाओं का विरोध गुट निरपेक्षता की ऐतिहासिक दृष्टि है। उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, रंगभेद की नीति और साम्राज्यवाद का व्यवस्थागत विरोध, इस ऐतिहासिक प्रकृति की अभिव्यक्तिया है।
- 5 शीतयुद्ध के तात्कालिक सदन में पैदा होने के फलस्वरूप गुटा के आधार पर धुंकीकरण का विरोध और सैनिक सलग्नता का प्रतिरोध, एक स्वतंत्र विदेशनीति के व्यावहारिक सिद्धांत है।
- 6 गुट निरपेक्ष राष्ट्रा के बीच सहचारिता, आर्थिक राजनैतिक और सांस्कृतिक सम्बंध, परस्पर एकजुटता की आयोजित करने की दृष्टि से, आवश्यक आलवन है।

इन ऐतिहासिक प्रेरणाओं की दृष्टि से गुट निरपेक्षता का मूल मतभेद और उसकी सक्रिय भूमिका का प्रारूप स्पष्ट होता है। सदस्यों से विकास के साथ साथ और परस्पर एकजुटता में बढ़ोतरी के साथ साथ, गुट निरपेक्षता औपचारिक स्वरूप में सदस्यों की सामयिकता से प्रभावित होती रही है। सदस्यों में इसकी प्रवृत्ति के कुछ पक्ष और अधिक मुखरित बदलाव के साथ साथ इन प्रवृत्तियों के तुलनात्मक ज्ञान में भी

शीतयुद्ध की ससत्तामयिवता न इसके राजनीतिक पक्ष को प्रचुर बनाया तो इसके बाद उत्तरोत्तर स्थितियां न उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध से गुटनिरपेक्षता को और अधिक अंतरंग रूप में जाड़ा।

सदस्यता का प्रारम्भिक मापदण्ड, जो कि शीत युद्ध के सदस्य में परिभाषित किया गया था किसी राष्ट्र के गुटनिरपेक्ष होने के लिए विशेष योग्यताओं को आवश्यक बताता था। यह योग्यतायें प्रथम गुटनिरपेक्ष राष्ट्रा के सम्मेलन के लिए 1961 में काहिरा में तयारी सम्मेलन में व्यक्त की गई। इनके अनुसार गुटनिरपेक्ष राष्ट्र वह राष्ट्र है—

- 1 जो शांतिपूर्ण सहजस्तित्व के आधार पर एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वाह करे और स्वयं का शक्ति के गुटा और प्रवृत्तियों के पक्ष में सलग्न न करे।
- 2 जो उपनिवेशवाद के विरोध को प्रेरणा से, सतत रूप से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलनों का समर्थक रहा हो।
- 3 जो ऐसे किसी सैनिक गठबन्धन का सदस्य न हो, जो कि महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता के सदस्य में बनाया गया हो।
- 4 जो किसी महाशक्ति के साथ ऐसी किसी द्विपक्षीय संधि अथवा प्रादेशिक सुरक्षा संधि, में जो कि महाशक्तियुक्त प्रतिद्वन्द्विता के सदस्य में हो, अपना स्वयं की स्पष्ट सहमति के आधार पर सलग्न न करे।
- 5 जो किसी विदेशी शक्ति को अपनी स्पष्ट सहमति के आधार पर ऐसे कोई सैनिक अड्डे बनाने की सुविधा न दे, जिनका कि प्रयोग महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता के सदस्य में हो।

इन प्रारम्भिक सदस्यता की योग्यता में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास के साथ उत्तरोत्तर, औपचारिक स्तर पर, बदलाव आया है। यद्यपि प्रारम्भ में ही कुछ ऐसे वाक्यों का समावेश किया गया, जिनके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की सदस्यता में आवश्यक स्वविवेक का प्रावधान बना रहे। 'स्पष्ट सहमति के आधार पर' और 'महाशक्तियुक्त प्रतिद्वन्द्विता के सदस्य में ऐसे वाक्य थे जिनके द्वारा किन्हीं राष्ट्रों के सदस्य में, सम्भावित विशेष स्थितियों को देखते हुए, छूट भी दी जा सके। उत्तरोत्तर रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आंतरिक स्वरूप और शीतयुद्ध के प्रारम्भिक सदस्य में भी बदलाव आया है। अतः इसकी सदस्यता के आधारों में भी इस प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से आया। लेकिन औपचारिक स्तर पर, आज भी सदस्यता के ये मापदण्ड मान्य हैं। इस दृष्टि से गुटनिरपेक्षता ने निरंतरता और बदलाव के बीच जो समन्वय स्थापित किया,

उसके फलस्वरूप इसकी सदस्यता में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ, इसकी राजनैतिक चेतना भी प्रखर और परिपक्व बनी है।

आंदोलन का स्वरूप प्रवृत्तियाँ और विकास

अपने शशव की शकाओं और अनुभवों से सीखता हुआ, आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन तृतीय विश्व का वयस्क राजनैतिक स्वर है। अनुभवों की वाष्पान्ति न इस न सिर्फ एक ऐतिहासिक परिपक्वता दी है, अपितु एक अभूतपूर्व विस्तार भी। इस पूरी प्रक्रिया में गुटनिरपेक्षता के दृष्टिकोण और व्यवहार, दोनों में ही एक सतत आन्तरिक मयन हुआ है। इस मयन की परिणति गुटनिरपेक्षता के औपचारिक और भौगोलिक विस्तार में ही नहीं, अपितु माघ ही साथ इसके षचारिक आयातों के विस्तार में भी हुई। अपनी इस यात्रा के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अनक औपचारिक और बौद्धिक बहुस की साधकता पर प्रश्न चिह्न लगा दिए। शीत युद्ध को गुटनिरपेक्षता के जन्म का निर्धारक मर्म स्थापित करने वाली मायता पूरा रूप से धराशापी हुई। अपने प्रथम सम्मेलन से लेकर अपने पिछले सम्मेलन तक, जो कि शीत युद्ध में शिथिलता का काल भी रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई। आज स्वतंत्र विश्व का दो तिहाई से अधिक राष्ट्र समुदाय गुटनिरपेक्षता में समाहित है। इसमें औपचारिक सदस्य, पर्यवेक्षक और अतिथि राष्ट्रों के रूप में राष्ट्रों की प्रतिबद्धता के विभिन्न स्तर भी हैं। प्रारम्भिक तौर पर

वर्ष	सम्मेलन	सदस्य		पर्यवेक्षक		अतिथि	
		राष्ट्र	समूह	राष्ट्र	समूह	राष्ट्र	समूह
1961 बेलग्रेड (युगोस्लाविया)		25	—	3	—	—	—
1964 काहिरा (मिश्र)		47	—	10	2	—	—
1970 लुसाका (ज़ाम्बिया)		53	—	12	1	—	5
1973 अल्जीरिया (अल्जीरिया)		75	—	9	—	3	12
1976 कोलंबो (श्री लंका)		86	1	9	13	7	—
1979 हवाना (क्यूबा)		95	2	9	8	10	—

तर सफल अनुभव हुए। उपनिवेशवाद का अंत और तृतीय विश्व की स्वतंत्रता इस समायोग की साक्षी है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से उभरी वैचारिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया और उसकी उत्तरोत्तर उग्रता का गुटनिरपेक्ष आदान-प्रदान पूरा रूप से आत्मघात करने में अभी असफल रहा है। गुटनिरपेक्षता एक दोहरी मानसिकता के भवर में फंसी है। एक ओर एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था की कामना है, तो दूसरी ओर इसमें सफलता हेतु आवश्यक निर्णायक वैचारिक दृष्टि और नियम का अभाव भी। प्रतिबद्धता और वैचारिक निश्चय के बिना व्यवस्थागत बदलाव का साकार करना गुटनिरपेक्ष आदान-प्रदान का एक आत्मघाती दिवास्वप्न है। क्या इतिहास की निर्णायक गति में जा कि वैचारिक ध्रुवीकरण की उत्तरोत्तर उग्रता को दर्शाती है, ऐसा आत्मघात संभव है? क्या ध्रुवीकृत वैचारिकता के बिना निर्णायक व्यवस्था परिवर्तन की परिश्रमिता सापेक्ष बन सकती है? इन प्रश्नों पर, इतिहास का स्वर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। न तो तृतीय विश्व के आर्थिक एवं राजनैतिक आयाजन का विघटन संभव है, और न ही वैचारिक ध्रुवीकरण के बिना व्यवस्थागत बदलाव। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रा की स्पष्ट प्रस्तावना भल न भी हो, गुटनिरपेक्ष आदान-प्रदान में उत्तरात्तर वैचारिक ध्रुवीकरण भावी विकास की एक अपरिहार्य आवश्यकता है। साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था और उसका राजनैतिक स्वरूप एक ही शोषण की दो स्मृतियाँ हैं। आर्थिक शोषण से मुक्ति गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की ऐतिहासिक आवश्यकता है। वैचारिक ध्रुवीकरण इसका अपरिहार्य और अनिवार्य अभिप्राय है। आवश्यकता से जुड़कर अभिप्राय से विमुक्त होना नितान्त असंभव है।

इतिहास की गति से लगाव और अलगाव के बीच गुटनिरपेक्ष आदान-प्रदान की अन्तर्गत प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। इन विभिन्न प्रवृत्तियों में, प्रारम्भिक शिफारिश के बाद, उत्तरोत्तर ऐतिहासिक दृष्टि का विकास हुआ। विभिन्न और वैचारिक संकीर्ण अपना महत्व खो चुके हैं और गुटनिरपेक्षता अपनी परिभाषा के तात्त्विक आधार पर केन्द्रित हुई है। इस पूरी प्रक्रिया और भावी वैचारिक समन की आवश्यक संभावनाओं की संक्षेप में निम्न प्रमुख प्रवृत्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. एशिया अफ्रीका के मजबूत राष्ट्रों में परस्पर सहयोग का प्रारम्भ एवं साधारण और अपरिभाषित आधार पर, बाहुल्य सम्मेलन का रूप में हुआ।
2. एक स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य और सहयोगी राष्ट्रों का मापदण्ड का प्रश्न प्रारम्भिक रूप से विवादास्पद रहा। लेकिन, ऐतिहासिक आवश्यकता और धारण, मिथ एवं युगोन्मादित्व का स्पष्ट दृष्टिकोण

अतिथि अथवा पयवेक्षक के रूप में सम्मिलित होने के बाद अनेक राष्ट्र इसके पूर्ण सदस्य भी बने। सिर्फ मायता प्राप्त सरकारों के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन में विभिन्न राष्ट्रीय सघर्षों में सलग्न सगठनों को भी अपने आंदोलन में समाहित किया है। इस प्रकार का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विस्तार निम्न सारणी में क्रमबद्ध रूप से व्यक्त है—

सदस्यता में विस्तार के साथ साथ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलते सधर्षों की तुलना में, गुटनिरपेक्षता में अपनी वैचारिक समझ को भी विस्तृत किया। इस वैचारिक परिपक्वता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक स्थाई आत्मविश्वास पैदा किया और इसके प्रतिराष्ट्रीय स्वर को और अधिक मुखरित बनाया। प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की प्रक्रिया को गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने एक सतही अभि व्यक्त के रूप में समझा। लेकिन उत्तरोत्तर विकास में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इस शोषण की प्रक्रिया को इसकी ऐतिहासिक विरासत और व्यवस्थागत स्वरूप में भी आत्मसात किया। उनकी दृष्टि अब स्पष्ट थी, यह कि शोषण कि ही नीतियों का कोई ऐच्छिक परिणाम नहीं है बल्कि एक व्यवस्थागत बदलाव का प्रश्न है। इस शोषण की व्यवस्था का मूलभूत आर्थिक आधार साम्राज्यवाद से उपजता है और इस आधार पर ही राजनैतिक शोषण और असमानता की नींव भी रखी है। आर्थिक और राजनैतिक लड़ाई एक दूसरे की पूरक हैं और इन दोनों ही स्तरों पर बराबर बल व्यवस्थागत बदलाव के सघर्ष के लिए आवश्यक है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए गुटनिरपेक्षता ही एकमात्र ऐतिहासिक शक्ति है। फोल्म्बी अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि “गुटनिरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद के प्रत्येक स्वरूप और अभिव्यक्ति के विरुद्ध और अनेक प्रकार के समस्त अधिपत्य के विरुद्ध सघर्ष के लिए एकमात्र सक्षम शक्ति है।” गुटनिरपेक्षता के चिंतन और व्यवहार में उभरता हुआ यह आर्थिक दृष्टिकोण और उसे व्यवस्थागत रूप में समझने और राजनैतिक शोषण से जाड़ने की जागरूकता, इसके वैचारिक पक्ष का एक निर्णायक पैदाव है। इस मानसिकता का आत्मसात करने के फलस्वरूप, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अनेक औपचारिक शकाओं की समाप्ति हुई है और, इसमें बदलाव की एक ऐतिहासिक शक्ति का प्रारूप समा गया है। इन प्रवृत्तियों का विकास न तो जाकस्मिक ही था और न ही बिना एक लम्बे समय के प्रतिफलित। ऐसी जागरूकता का विकास एक क्रमबद्ध रूप में हुआ है।

प्रवृत्तियों का दिशा-बोध एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

अनेक प्रश्नों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्तर और इतिहास की लाल में एक सहज अनुरूपता थी। ऐसे समस्त प्रश्नों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को निर-

तर सफल अनुभव हुए। उपनिवेशवाद का अन्त और तृतीय विश्व की स्वतन्त्रता इस समायोग की साक्षी है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से उभरी वैचारिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया और उसकी उत्तरोत्तर उग्रता को गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूर्ण रूप से आत्मसात करने में अभी असफल रहा है। गुटनिरपेक्षता एक दोहरी मानसिकता के भवर में फंसी है। एक ओर एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनतिक व्यवस्था की कामना है, तो दूसरी ओर इसमें सफलता हेतु आवश्यक निर्णायक वैचारिक दृष्टि और निर्णय का अभाव भी। प्रतिवद्धता और वैचारिक निश्चय के बिना व्यवस्थागत बदलाव का साकार करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक आत्मघाती दिव्यस्वप्न है। क्या इतिहास की निर्णायक गति में जा कि वैचारिक ध्रुवीकरण की उत्तरोत्तर उग्रता को दर्शाती है, ऐसा आत्मघात संभव है? क्या ध्रुवीकृत वैचारिकता के बिना निर्णायक व्यवस्था परिवर्तन की परिष्कल्पना सापेक्ष बन सकती है? इन प्रश्नों पर, इतिहास का स्वर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। न तो तृतीय विश्व के आर्थिक एवं राजनतिक आयोजन का विघटन संभव है और न ही वैचारिक ध्रुवीकरण के बिना व्यवस्थागत बदलाव। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रा की स्पष्ट प्रस्तावना भले न भी हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उत्तरोत्तर वैचारिक ध्रुवीकरण भावी विकास की एक अपरिहार्य आवश्यकता है। साम्राज्यवादी अव्यवस्था और उसका राजनतिक स्वरूप एक ही शोषण की दो स्थितियाँ हैं। आर्थिक शोषण से मुक्ति गुटनिरपेक्ष राष्ट्रा की ऐतिहासिक आवश्यकता है। वैचारिक ध्रुवीकरण इसका अपरिहार्य और अनिवार्य अभिप्राय है। आवश्यकता से जुड़कर अभिप्राय से विमुख होना, नितांत असंभव है।

इतिहास की गति से लगाव और अलगाव के बीच गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अन्तरंग प्रवृत्तियाँ का विकास हुआ है। इन विभिन्न प्रवृत्तियों में, प्रारम्भिक मिस्र के बाद, उत्तरोत्तर ऐतिहासिक दृष्टि का विकास हुआ। विभिन्न औपचारिक संकीर्ण अपना महत्व खोज चुके हैं और गुटनिरपेक्षता अपनी परिभाषा के तात्त्विक आधार पर केन्द्रित हुई है। इस पूरी प्रक्रिया और भावी वैचारिक मयन की आवश्यक संभावनाओं को संक्षेप में निम्न प्रमुख प्रवृत्तियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है—

1. एशिया अफ्रीका के समस्त राष्ट्रों में परस्पर सहयोग का प्रारम्भ एक साधारण और अपरिभाषित आधार पर, बाहुल्य सम्मेलन के रूप में हुआ।
2. एक स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य और सहयोगी राष्ट्रों के मापदण्ड का प्रश्न, प्रारम्भिक रूप से विवादास्पद रहा। लेकिन, ऐतिहासिक आवश्यकता और भारत, मित्र एवं युगोस्लाविया के स्पष्ट दृष्टिकान

न गुटनिरपेक्षता के आंदोलनात्मक स्वरूप का सूत्रपात किया। तात्कालिक अन्तर्राष्ट्रीय सन्ध और तृतीय विश्व की स्वतन्त्र भूमिका की चाह न इस एक विशिष्ट राजनैतिक स्वरूप और स्वर दिया। इस प्रारम्भिक स्थिति में भी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने अर्थ मूलभूत ऐतिहासिक दायित्वों से विमुक्त नहीं था। उपनिवेशवाद, रंगभेद नीति और एक दूरगामी विश्वशांति की स्थापना, आदि प्रश्न गुटनिरपेक्षता से अलग रूप से जुड़े रहे। शीतयुद्ध का तात्कालिक घातावरण गुटनिरपेक्षता का कारण नहीं, अपितु मात्र उत्प्रेरक सद्भ था।

- 3 स्वतः प्रेरणा न रही, अपितु निरंतर कटु अनुभवों ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को एक नये ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विकास हेतु प्रेरित किया। इस प्रेरणा के फलीभूत होने तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन मात्र औपचारिक अभिव्यक्ति का कर रहे गया। 1964 से 1970 तक इसकी निष्क्रियता, जिसके बीच कोई सम्मेलन नहीं हुआ, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। इस निष्क्रियता का एक अर्थ महत्वपूर्ण कारण था। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनक्रमों में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का मतकय नहीं था, और परस्पर सम्बन्धों के स्तर पर भी राजनैतिक सहोदरता का कोई विशेष आधार भी नहीं। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राजनैतिक स्तर पर पुनर्जीवन के लिए भी नये आधारभूत प्रयोजनों की आवश्यकता थी।
- 4 6 वर्ष के अंतराल के बाद, 1970 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पुनः सक्रिय स्थापना, एक गुणात्मक परिवर्तन को सहेजे थी। राजनैतिक दृष्टि में भले ही नहीं, लेकिन अधिक शोषण की अवस्था में समस्त गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में एकता का एक दूरगामी मूलभूत आधार था। इस दूरगामी आधार की समझ ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सिर्फ एक नई चेतना, अपितु सक्रियता भी दी। आर्थिक सघन सगठन का आधार बना। इस ऐतिहासिक मोड़ के बाद, आंदोलन में एक निरंतर विस्तार की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ, जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता और सम्भावना समाप्त प्रायः हो गई।
- 5 इस नयी प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हुआ। प्रारम्भिक समझ की आस्था सुधारवादी कार्यक्रम में थी। अनुभवों ने इसे व्यवस्थापरक बनाया। व्यवस्थागत समय का उदय, इसकी नयी ऐतिहासिकता का परिचायक बना। सघन की सीमाएँ अब सुधारवादी

नहीं रही। नई अंतराष्ट्रीय व्यवस्था की माँग के साथ, गुट-निरपेक्ष आंदोलन इतिहास में उभरते व्यवस्थागत और मूलभूत ढाँचे के साथ जुड़ गया।

- 6 व्यवस्थागत समझ में विवाद का अगला पड़ाव एक द्विद्वारमक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राजनीतिक है अथवा आर्थिक, इस औपचारिक विवाद पर विराम लगा। कोलम्बा सम्मेलन ने दाना पटा का एक दूसरे का पूरक घोषित किया। एक मानवीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन अनिवार्य है, और नयी अंतराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को साकार करने हेतु एक राजनीतिक एकजुटता और निश्चय भी आवश्यक और अपरिहार्य बात। गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण ने विकास की यह एक नयी स्थिति बनी।
- 7 इस विरामित स्थिति में नया विवादों का जन्म दिया है। राजनीतिक एकजुटता का व्यापक स्वरूप क्या है, उस प्रश्न पर हवाना सम्मेलन परस्पर प्रतिद्वंद्वी प्रवृत्तियों का परिचायक है। एक ओर यह है। एक और अत्यधिक दुबल पक्ष था। वह यह कि विकास की आवश्यकताओं और अन्य राष्ट्रों में उपलब्ध संसाधनों का दखल हुए, पश्चिमी राष्ट्रों से जुड़ा जाय। सिंगापुर और जेपर द्वारा प्रस्तावित इस मत का सम्मेलन में गम्भीरता से नहीं लिया क्योंकि यह मूलतः विचित्र और हास्यस्पद था। क्यूबा आदि द्वारा प्रस्तावित मित्रता कि समाजवादी राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के "स्वाभाविक सहयोगी" हैं, सम्मेलन में अत्यधिक चर्चित हुआ। इस पर तीव्र मत और विमय व्यक्त हुए। अतः मतभेद के अभाव में प्रस्ताव पर बल नहीं दिया गया।
- 8 हवाना सम्मेलन में समाजवादी राष्ट्रों की "स्वाभाविक सहयोगी" की औपचारिक भाष्यता देने के प्रश्न पर उभर विवाद से एक प्रवृत्ति भी अभिव्यक्त होती है। ऐसे विवाद का उठना आकस्मिक कदापि नहीं था। समाजवादी राष्ट्रों, विशेषतः सोवियत संघ के प्रति अनक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की निकटता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से आवश्यक वचारिक ध्रुवीकरण के विकास की ही एक अभिव्यक्ति है। स्वाभाविक था कि, कुछ राष्ट्र जो ऐसे ध्रुवीकरण के पक्षधर नहीं थे, अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते। लेकिन ये राष्ट्र भी, औपचारिक भाष्यता के विरुद्ध होत हुए भी इस निरंतर उभरती प्रक्रिया के सहभागी रहे थे। गुटनिरपेक्ष

वहारिक था। अतः पश्चिमी राष्ट्रों के साथ किसी भी रूप में एकरूपता का भाव असम्भव प्रायः रहा। अन्तिम, इसके ठाव विपरीत राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा का समाजवादी वैचारिकता से कोई मूलभूत अलगाव नहीं था। किन्हीं स्थितियों में तो इसी विचारधारा के तत्वाधान में राष्ट्रीय आंदोलन आयोजित हुए। ऐसी स्थिति में सोवियत व्यवस्था और विचारधारा के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण था। सोवियत संघ का यदा-कदा और अस्पष्ट विरोध, विचारधारागत अथवा व्यवस्थागत नहीं अपितु परिस्थितिगत और तात्कालिक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के सदर्भ में ही सम्भव हो सका।

- 9 लेकिन इस आवश्यक वैचारिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के अधिक स्पष्ट विकास में कुछ मूलभूत अंतर्विरोध निहित हैं। इन अंतर्विरोधों की स्पष्ट रूप से रेखांकित करना एक समाजवादी आवश्यकता है। सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के राष्ट्रीय आंदोलनों का विशिष्ट सदर्भ एक जसा नहीं रहा है। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व का वय चरित्र और वैचारिक दृष्टिकोण, एक अत्यधिक मूलभूत पक्ष है। समस्त राष्ट्रों का साम्राज्यवाद की व्यवस्था से तो अंतर्विरोध है, लेकिन एक निश्चित ऐतिहासिक वय दृष्टि के अभाव में, समाजवादी वैचारिकता से दूरगामी प्रतिबद्धता भी उत्पन्न हो सदेहास्पद है। आंतरिक रूप से स्वयं शोषण की व्यवस्था पर आरुढ़, और साम्राज्यवादी शासन का व्यवस्थागत विरोध, एक ऐतिहासिक विडम्बना है। इस मूलभूत ऐतिहासिक प्रश्न के निवारण के साथ गुट निरपेक्षता में भावी ध्रुवीकरण की प्रक्रिया अंतरंग रूप से जुड़ी है। इतिहास की दृष्टि दोनों ही स्तरों के अंतर्विरोधों पर केन्द्रित है अथवा अवरोध, मूलतः औपचारिक है। सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक है। अतः उसकी नीतियों में हान वाली गलत अभिव्यक्तियों का साधारणतया समाजवादी व्यवस्था के दाप का अभिप्राय समझ लिया जाता है। एक अन्य पक्ष तृतीय राष्ट्रों के नवादी नेतृत्व, विशेषतः अफ्रीका के सदर्भ में, एक विचित्र मानसिकता का परिचायक है। सांस्कृतिक शोषण के भी शिकार रहने के फलस्वरूप, इन राष्ट्रों में "स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता" की विचित्र मानसिकता व्याप्त है। यह मानसिकता उन्हें अपनी तथा कथित 'विशिष्ट स्थिति' के माह में उलझाती है और एक ऐतिहासिक आरंभभूत दृष्टि से विमुख भी करती है।

आंदोलन व आज तक के अनुभवों से, अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्रों की निरंतर तीव्र भत्सना हुई, लेकिन एक भी प्रस्ताव में आलोचना हेतु सोवियत संघ का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। यही नहीं, कोलम्बो सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि समाजवादी राष्ट्रों से निकट के आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किए जायें, और इस हेतु इन राष्ट्रों से यह अपील भी की गई कि वे गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के हितों को बढ़ाने हेतु विशेष सुविधाओं का प्रावधान करें। साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशी शासन के विरुद्ध ऐसी निकटता का उभरना वस्तुतः स्वाभाविक था। इसके अनेक ऐतिहासिक एवं व्यावहारिक कारण रहे हैं। पहला, सोवियत संघ के एक प्रतिद्वंद्वी शक्ति के रूप में अम्युदय में साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रभाव को सीमित किया और एक नव संतुलन को जन्म दिया। इस स्थिति में उस प्रक्रिया के लिए उचित वातावरण तैयार किया, जिसमें उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन का वल मिला और इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में गति आई। दूसरा, सोवियत संघ द्वारा ऐसे संघर्षों को खुला और प्रभावी सहयोग और समर्थन दिया गया। तीसरा, शीत युद्ध की अवस्था में भी, पश्चिमी राष्ट्रों की तरह सोवियत संघ ने सैनिक गठबंधनों की उपवादी नीति नहीं अपनाई और अन्य राष्ट्रों में अपने उभरते प्रभाव का संचालन द्विपक्षीय आधार पर किया। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से सोवियत संघ ने रणभेद नीति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रश्नों पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के दृष्टिकोण का निरंतर समर्थन किया जबकि पश्चिमी राष्ट्रों की भूमिका इसका ठीक विपरीत रही। पांचवा, सोवियत संघ के योजना-बद्ध विकास की अद्यवस्था की सफलता, तृतीय विश्व के आर्थिक स्वतंत्रता की अद्यवस्था के संघर्ष में प्रेरणादायी बनी। यही नहीं, अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ आर्थिक सम्बन्धों में सोवियत संघ द्वारा द्विपक्षीय स्तर पर निरंतर सहायता दी गई, जिसकी व्यापारिक शक्तें पश्चिमी नीति से कहीं अधिक उदार और भिन्न थीं। छठा, राजनैतिक व्यवस्था और विचारधारा के स्तर पर पश्चिमी मायतायें तृतीय राष्ट्रों के अनुभव की दृष्टि से अनुपयोगी और अवावहारिक सिद्ध हुईं। विचारधारा के स्तर पर टकराव राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभवों से उपजा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सदभाव में मूलभूत भिन्नता के कारण, पश्चिमी लोक-तन्त्रीय व्यवस्था द्वारा शासन का संचालन स्वाभाविक रूप से अद्य-

व्यवहारिक था। अतः पश्चिमी राष्ट्रों के साथ किसी भी रूप में
 एकरूपता का भाव असम्भव प्रायः रहा। अन्तिम, इसके ठाक विप-
 रीत राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा का समाजवादी वचारिकता
 से कोई मूलभूत अलगाव नहीं था। किन्हीं स्थितियों में तो इसी
 विचारधारा के तत्वाधान में राष्ट्रीय आंदोलन आयोजित हुए। ऐसी
 स्थिति में सोवियत व्यवस्था और विचारधारा के प्रति सहिष्णुता
 का दृष्टिकोण था। सोवियत संघ का यदा-कदा और अस्पष्ट विरोध,
 विचारधारागत अथवा व्यवस्थागत नहीं अपितु परिस्थितिगत और
 तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के सदर्भ में ही सम्भव हो सका।
 9 लेकिन इस आवश्यक वचारिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के अधिक
 स्पष्ट विकास में कुछ मूलभूत अंतर्विरोध निहित हैं। इन अंतर्वि-
 रोधों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना एक यथार्थवादी आवश्यकता
 है। सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के राष्ट्रीय आंदोलनों का विशिष्ट
 सदर्भ एक जसा नहीं रहा है। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के नतत्व
 का वग-चरित्र और वचारिक दृष्टिकोण एक अत्यधिक मूलभूत
 पक्ष है। समस्त राष्ट्रों का साम्राज्यवाद की व्यवस्था से तो अत-
 विरोध है लेकिन एक निश्चित ऐतिहासिक वग दृष्टि के अभाव
 में, समाजवादी वचारिकता से दूरगामी प्रतिबद्धता भी उतनी ही
 सदेहास्पद है। आंतरिक रूप से स्वयं शोषण की व्यवस्था पर
 आलूझ, और साम्राज्यवादी शोषण का व्यवस्थागत विरोध, एक
 ऐतिहासिक विडंबना है। इस मूलभूत ऐतिहासिक प्रश्न के निवारण
 के साथ गुट निरपेक्षता में भावी ध्रुवीकरण की प्रक्रिया अंतरण
 रूप से जुड़ी है। इतिहास की दृष्टि दोनों ही स्तरों के अंतर्विरोधों
 पर केन्द्रित है अथवा अवरोध मूलतः औपचारिक है। सोवियत संघ
 समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक है। अतः उसकी नीतियाँ में होन
 वाली गलत अभिव्यक्तियों को साधारणतया समाजवादी व्यवस्था
 के शोषण का अभिप्राय समझ लिया जाता है। एक अथवा पक्ष तृतीय
 राष्ट्रों के नवोदित नतत्व, विशेषतः अफ्रीका के सदर्भ में, एक
 विचित्र मानसिकता का परिचायक है। सांस्कृतिक शोषण व भी
 शिकार रहने का फलस्वरूप इन राष्ट्रों में 'स्वतंत्रता' का लिए
 स्वतंत्रता की विचित्र मानसिकता व्याप्त है। यह मानसिकता
 उन्हें अपनी तथा कथित 'विशिष्ट स्थिति' का माह में उत्प्रेरणा
 है। और एक ऐतिहासिक और सर्वभूत दृष्टि से विमुख भी करती
 है।

राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज विवाद संयुक्त राष्ट्र सभ के सामने रखा गया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के प्रस्ताव पर सोवियत सभ ने वोटो कर दिया। इजरायल ब्रिटन और फ्रांस ने स्वेज क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। 2 नवम्बर 1956 को अमेरिका द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हुआ गया कि ब्रिटन तथा फ्रांस सैनिक कार्यवाही तुरन्त बन्द कर दे। युद्धबन्दी के लिए संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना तैयार करने का प्रस्ताव भी पास किया गया तथा तब सोवियत सभ ने भी ब्रिटन और फ्रांस को सैनिक कार्यवाही बन्द करने की चेतावनी दी, तब युद्ध बन्द किया गया। 15 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र आपात सेना दस्ता भी भेजा गया।

1967 का अरब इजरायल युद्ध

यद्यपि स्वेज संकट के बाद पश्चिमी एशिया में संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना तैनात की गई थी किन्तु अरबों और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता चला गया। फिलीस्तीनी शरणार्थियों की समस्या भी बनी रही। इजरायल और मिश्र की सेना के बीच तनाव बना रहा और 5 जून 1967 को इजरायल ने अरबों पर आक्रमण कर दिया। जोर्डन, सीरिया, मिश्र आदि बहुत से अरब देश मिलकर भी इजरायल के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। इजरायल ने पांच दिन के युद्ध में ही न केवल अरबों की युद्ध क्षमता का ध्वस्त कर दिया, अपितु मिश्र का साइनाई का क्षेत्र, सीरिया का गोलन पहाड़िया, जोर्डन नदी के पश्चिमी किनारे का बहुत सा क्षेत्र और पूरे जेरुसलम नगर को अपने अधिकार में कर लिया। इस युद्ध में अमेरिका इजरायल का समर्थन कर रहा था तथा अरब देशों की सोवियत सभ से मदद मिल रही थी। इस युद्ध में इजरायल अरबों पर विजयी रहा तथा उसने अवध रूप से अधिकृत भूमि को अपने नियन्त्रण में बनाए रखा।

अरब और इजरायल के बीच विवाद ही गहरा नहीं होता गया अपितु इस क्षेत्र में महाशक्तियाँ ने भी अपना पांव जमा लिया। 1954 में केन्द्रीय संधि संगठन (सेटो) की स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में की गई और उसके बाद सोवियत सभ ने भी इस क्षेत्र में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया।

1973 का अक्टूबर युद्ध—योम्किपुर युद्ध

यह अरबों इजरायल के बीच चौथा युद्ध था। अरबों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध प्रारम्भ किया। मिश्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने कहा कि यदि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल की सहायता नहीं करता और उसे नवीनतम आयुधों से लैस नहीं करता और

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अधुनातन समयाएँ एवं तनाव क्षेत्र

पश्चिमी एशिया और अरब इजरायल विवाद

पश्चिमी एशिया अथवा मध्य पूर्व विश्व राजनीति में द्वितीय महायुद्ध के बाद बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। फिलीस्तीन का प्रदेश प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटेन को सरक्षित प्रदेश (मे-डेट) के रूप में प्राप्त था। फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि उसके लिए इस मे-डेट का शासन प्रबंध चलाना सम्भव नहीं है ब्रिटेन द्वारा यह समस्या संयुक्त राष्ट्र सभ के समक्ष प्रस्तुत की। फिलीस्तीन को दो भागों में विभाजित करन का निणय लिया गया, लेकिन अरबों और यहूदियों में सघर्ष प्रारम्भ हुआ। यहूदियों ने इजरायल राज्य की घोषणा कर दी और इराक, लेबनान आदि अरब राष्ट्रों ने फिलीस्तीन पर आक्रमण कर दिया लेकिन अरब राज्य इजरायल के प्रत्याक्रमण को नहीं झेल पाए। संयुक्त राष्ट्र सभ ने कई बार युद्ध विराम कराया। महाशक्तियों ने इजरायल नाम के राज्य को मान्यता दे दी।

इजरायल के निर्माण के समय से ही पश्चिमी एशिया में तनाव बना हुआ है और 1948 में अब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई है।

स्वेज सकट

स्वेज नहर नू राजनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। सन् 1869 में निर्मित यह नहर ब्रिटेन तथा फ्रांस की एक कम्पनी द्वारा संचालित थी और यहां पर ब्रिटेन की सेना भी रखी गई थी। जुलाई 1954 में एक समझौते द्वारा सेनाएं हटा ली गईं। लेकिन मिश्र और पश्चिमी राष्ट्रों के सम्बन्धों में सुधार नहीं हुआ। 26 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर का

राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज निजाद संयुक्त राष्ट्र सभ के सामने रखा गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के प्रस्ताव पर सोवियत सभ ने वोट कर दिया। इजरायल ब्रिटेन और फ्रांस १ स्वज क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। २ नवम्बर १९५६ को अमेरिका द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हुआ गया कि ब्रिटेन तथा फ्रांस सैनिक कार्यवाही तुरन्त बन्द कर दे। युद्धबंदी के लिए संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना तयार करने का प्रस्ताव भी पास किया गया तथा तब सोवियत सभ १ भी ब्रिटेन और फ्रांस को सैनिक कार्यवाही बन्द करने की चेतावनी दी, तब युद्ध बन्द किया गया। १५ नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र आपात सेना दस्ता भी भेजा गया।

१९६७ का अरब इजरायल युद्ध

यद्यपि स्वज सफट के बाद पश्चिमी एशिया में संयुक्त राष्ट्र सभ की सत्ता सत्तात की गई थी किंतु अरबों और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता चला गया। फिनीस्तोनी शरणार्थियों की समस्या भी बनी रही। इजरायल और मिश्र की सेना के बीच तनाव बना रहा और ५ जून १९६७ को इजरायल ने अरबों पर आक्रमण कर दिया। जोर्डन, सीरिया, मिश्र आदि बहुत से अरब देश मिलकर भी इजरायल के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। इजरायल ने पांच दिन के युद्ध में ही न केवल अरबों की युद्ध क्षमता का ध्वस्त कर दिया, अपितु मिश्र का साइनाई का क्षेत्र, सीरिया का गालन पहाड़िया, जोर्डन नदी के पश्चिमी किनारे का बहुत सा क्षेत्र और पूरे जेरुसलम नगर को अपने अधिकार में कर लिया। इस युद्ध में अमेरिका इजरायल का समर्थन कर रहा था तथा अरब देशों को सोवियत सभ से मदद मिल रही थी। इस युद्ध में इजरायल अरबों पर विजयी रहा तथा उसने अवध रूप से अधिकृत भूमि को अपने नियंत्रण में बनाए रखा।

अरब और इजरायल के बीच विवाद ही गहरा नहीं होता गया अपितु इस क्षेत्र में महाशक्तियों ने भी अपना पांव जमा लिए। १९५४ में केन्द्रीय संधि संगठन (सेटो) की स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में की गई और उसके बाद सोवियत सभ ने भी इस क्षेत्र में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया।

१९७३ का अक्टूबर युद्ध—योम्किपुर युद्ध

यह अरबों इजरायल के बीच चौथा युद्ध था। अरबों ने अपनी छोई हुई प्रतिष्ठा और प्रदेशों को पुन प्राप्त करने के लिए युद्ध प्रारम्भ किया। मिश्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने कहा कि यदि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल की सहायता नहीं करता और उसे नवीनतम आयुधों से लैस नहीं करता और

सोवियत संघ से अरब राष्ट्रों को आधुनिकतम सहायता प्राप्त होती तो इजरायल के लिए यह युद्ध महमा पड़ता। युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कई बैठकें बुलाई गईं, लेकिन रुक चाहता था कि इजरायल का 1967 के युद्ध से पहले की स्थिति पर लौटने के बारे में प्रस्ताव पारित किया जाए। केवल वर्तमान युद्ध से पून की स्थिति लाने से सम्बंधित प्रस्ताव ही पारित हो सके।

22 अक्टूबर का रुम तथा अमेरिका ने संयुक्त प्रस्ताव रखा, जिसमें यह मांग की गई कि युद्धरत पक्ष तुरंत युद्ध बंद कर दें और जो जगह है उस जगह ही रहें। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 12 घंटे के अंदर सारी शायदाही रोक दें। युद्ध बंदी के तुरंत बाद सुरक्षा परिषद के 1967 के 242वें प्रस्ताव को पूर्ण रूप से लागू किया जाए जिसमें कहा गया है कि इजरायल अवधि रूप से अधिभूत अरब क्षेत्रों से अपनी सनाए लौटा ले। सम्बंधित पक्ष स्थायी शांति की स्थापना के लिए समझौता वार्ता प्रारम्भ कर दें। इस प्रस्ताव का सीरिया ने स्वीकार नहीं किया और अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच भी तनाव उत्पन्न हो गया। इजरायल और मित्र द्वारा युद्ध विराम स्वीकार कर लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के गठन के बारे में विचार विमर्श हुआ और एक सैनिक दुबड़ी तुरंत युद्ध विराम का उल्लंघन रोकने के लिए तैनात कर दी गई।

अंत में 11 नवम्बर 1973 को इजरायल और मित्र के बीच छ सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों को गत युद्धों की अपेक्षा इस युद्ध में अधिक क्षति हुई। युद्धविराम के बाद मित्र और इजरायल के मध्य समझौता वार्ता चलती रही। किंतु समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। राष्ट्रपति सादात यह मानकर चले कि इजरायल अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण शांति स्थापना चाहता है और यदि बहुत रुक न अपनाया जाए तो दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकता है।

तेल कूटनीति और पेट्रो डॉलर राजनीति

1973 के अक्टूबर युद्ध के बाद भी अरब इजरायल विवाद का समाधान कोसों दूर रहा। तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा पेट्रोल की कीमतों में 1973 से कई गुना वृद्धि की गई। इसके निम्न परिणाम हुए —

- 1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट।
- 2 तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि।
- 3 अमेरिका की मुद्रा डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय साख गिरना।
- 4 औद्योगिक देशों में गम्भीर उर्जा संकट।

5 अरब देशा की राष्ट्रीय आय म बहुत अधिक वद्धि ।

6 अमेरिका की पश्चिमी एशिया तथा अरब देशो के प्रति नीति म परिवर्तन ।

1974 से 1976 तक तत्कालीन अमेरिकन विदेश मंत्री हैनरी किस्सीजर न कई अरब देशो की यात्राए की और उनसे सम्बन्ध सुधारन के प्रयास किए । 1973 के युद्ध मे पहले मित्र और सोवियत सघ के बीच सम्बन्ध त्रिगडने लगे थे जो कि आगे चलकर बिल्कुल खराब हो गए और राष्ट्रपति सादात न 1976 म सोवियत सघ के साथ 1971 म की गई शांति मित्रता और सहयोग की सन्धि तो टुकरा दिया । मित्र धीरे धीरे अमेरिका के पक्ष म होता चला गया और 1978 मे अमेरिका की मध्यस्थता से ही इजरायल और मित्र के बीच कैम्प डेविड समझौता हो गया ।

पश्चिमी एशिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा

1945 के बाद अमेरिका और सोवियत सघ दाना महाशक्तियों के रूप म उभरे तथा उनके हित और नीतियाँ विश्व व्यापी होती चली गईं । पश्चिमी एशिया म भी उनके निम्न हित हैं —

- 1 कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा ।
- 2 सामरिक हित ।
- 3 व्यापारिक और आर्थिक हित ।
- 4 पारस्परिक प्रभाव को कम करने से सम्बन्धित हित ।
- 5 तेल हित (विशेष अमेरिका के)

अमेरिका और सोवियत सघ प्रारम्भ से ही क्रमशः इजरायल और अरब देशो का समन्वय करते रहे जा कि स्वेज संकट के समय से ही स्पष्ट होता है । दोनों देशो द्वारा समुक्त राष्ट्र सघ म कई प्रस्तावो को वीटा किया जा रहा है । अमेरिकी इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण करता रहा है और सोवियत सघ ने मित्र, सीरिया इराक आदि देशो को आयुध प्रदान किए हैं । 1973 के युद्ध मे जिन एस०ए० 2 मिसाइलो, एफ 4 ई फेटम विमानो आदि का प्रयोग किया गया था, वे महाशक्तियों द्वारा ही द्यो हुई है । भूतपूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किस्सीजर की 'शटल' कूटनीति को काट्टर प्रशासन न भी जारी रखा (जिसका तात्पर्य है विदेश मंत्री द्वारा पश्चिमी एशिया म एक देश से दूसरे देश बार बार आ जाकर सम्पर्क कायम रखना) अमेरिका ने इस क्षेत्र मे अपने तेल एवं सामरिक हितो की रक्षा के लिए अपनी नीति मे परिवर्तन किया । जनवरी 1974 मे सेनाएँ पुनः हटान के बारे मे

हुआ। 4 सितम्बर 1975 को माइनाई क्षेत्र की सेनाओं के बारे में समझौता किया गया।

सादात की इजरायल यात्रा और कैम्प डेविड समझौते

अमेरिकी प्रयासों एवं मध्यस्थता के साथ ही मिथ की इजरायल के प्रति नीति में परिवर्तन आया और राष्ट्रपति सादात ने इजरायल से सम्पर्क प्रारम्भ किया। अरब राष्ट्रों की आलोचना की परवाह न करते हुए अनवर सादात ने इजरायल जान का निणय किया और 10 नवम्बर 1977 को उन्होंने इजरायल जाने का निणय किया और 10 नवम्बर 1977 को उन्होंने इजरायली समक्ष में पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने में सहयोग का अनुरोध किया। सादात की यह यात्रा पश्चिमी एशिया की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद मिथ और इजरायल नजदीक आते गए।

सादात की यात्रा के बाद इजरायली प्रधानमन्त्री मीनाचिम बेगिन ने इस्माइलिया में आकर सादात से वार्ता की। वार्ता में कई बार गतिराध उत्पन्न हुए तथा फिलिस्तीनी छापामारों ने बहुत से इजरायली लोग की हत्या भी की। 15 मार्च 1978 को इजरायल ने पड़ोसी देश लेबनान में स्थित फिलिस्तीन के छापामार अड्डा पर आक्रमण भी किया।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर के प्रयत्नों से अमेरिका में कैम्पडेविड में 13 दिन की नाजुक बातचीत के बाद 18 सितम्बर 1978 को मिथ और इजरायल के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुए।

इनमें दो दस्तावेज प्रमुख थे —

1 पश्चिमी एशिया में शांति से सम्बन्धित दस्तावेज

- 1 जोर्डन के पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी के लोगों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।
- 2 इस क्षेत्र के लोगों का शांति वार्ता में प्रतिनिधित्व होगा।
- 3 यहाँ के लोगों का नागरिक स्वशासन पाँच वर्ष के अन्दर दिया जाएगा।
- 4 शांति काल में सुरक्षा सम्बन्धी कारणों के कुछ क्षेत्रों में इजरायल अपनी सेना रहेगा।
- 5 शांति सम्बन्धी संयुक्त वार्ताएँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 242 (सन 1967) के सिद्धांतों पर आधारित होंगे।

2 मिथ और इजरायल के बीच शांति संधि से सम्बन्धित बातचीत

इस दस्तावेज के आधार पर इजरायल और मिथ के बीच शांति संधि

के बारे में वार्ता जारी रखने का निणय किया गया और इजरायल अधिकृत साइनाई के क्षेत्र को मिश्र को लौटाने की बात की गई।

कैम्प डेविड समझौते की अरब देशों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सीरिया ने कहा कि इस समझौते द्वारा अरब हिता का बलिदान कर दिया गया है। फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष यासिर अराफात ने इस समझौते का साम्राज्यवादी चाल पर आधारित बतलाया। सोवियत संघ द्वारा भी कैम्पडेविड समझौते की तीव्र भत्सना की गई और उसे एक पडयॉन की सजा दी गई।

मार्च 1979 मिश्र इजरायली सन्धि

मिश्र और इजरायल के बीच वार्ताओं का कई दौर चले और इसमें राष्ट्रपति कार्टर की प्रतिष्ठा भी दाब पर लग गई। और अमेरिका के गंभीर प्रयत्नों के बाद 26 मार्च 1979 को मिश्र और इजरायल के बीच वाशिंगटन में एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर राष्ट्रपति कार्टर ने भी हस्ताक्षर किए। सन्धि की प्रमुख व्यवस्थाएँ हैं —

- 1 साइनाई क्षेत्र में इजरायल द्वारा मिश्र की प्रभुसत्ता को स्वीकृति।
- 2 सन्धि लागू होने के 9 माह के भीतर इजरायली सेनाओं का साइनाई के 2/3 भाग से हटना।
- 3 इसके बाद दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना।
- 4 दोनों देशों द्वारा पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा हल करना।

शांति सन्धि का अरब देशों द्वारा तुरन्त विरोध किया गया और अप्रैल 1979 में अरब लीग के देशों ने मिश्र का बहिष्कार किया और काहिरा में अरब लीग का कार्यालय भी हटा लिया। सितम्बर 1979 में हवाना में गुप्त निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भी मिश्र विरोधी अरब राज्यों ने उसके गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से निष्कासन की मांग की गई जिसके बारे में निणय स्थगित कर दिया गया किन्तु, इस सन्धि के बाद अमेरिका ने मिश्र का भी आर्थिक तथा सैनिक सहायता देना प्रारम्भ कर दिया और इजरायल और अमेरिका के घनिष्ठ सम्बन्ध बन रहे। मिश्र और इजरायल के बीच 1967 में अधिकृत अर्थ अरब क्षेत्रों के बारे में विवाद अभी भी बना हुआ है और इजरायल फिलीस्तीनी स्वायत्तता के बारे में मिश्र सहित अरब देशों से भिन्न दृष्टिकोण रखता है। फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चे (पी० एल० ओ०) को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा फिलीस्तीनियों का एक मात्र प्रतिनिधि मान लिया गया है। लेकिन अमेरिका और इजरायल उसे फिलीस्तीनियों का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं करते। अरब देशों ने मिश्र के विरुद्ध आर्थिक कूटनीतिक प्रतिबन्ध भी लगाए हैं।

जेरुसलम इजरायल की राजधानी

तेल अवीव प्रारम्भ से ही इजरायल की राजधानी रहा है। लेकिन 1948 में इजरायल के निर्माण के समय से ही जेरुसलम नगर के नियंत्रण की समस्या बनी रही है। यह पूरा नगर इजरायल ने जेरुसलम मुस्लिम तथा यहूदी दोनों का धार्मिक स्थल है, इसलिए यह पूरा नगर इजरायल का नहीं हो सकता किंतु इजरायल ने जेरुसलम पर न केवल अधिकार बनाएँ रखा अपितु उसने जेरुसलम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा भी की है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेरुसलम को इजरायल की राजधानी बनाने की घोषणा को अनुचित बतलाया है। इस निषेध की मित्र और अमेरिका ने भी आलोचना की है।

इजरायल द्वारा ईराक की परमाणु भट्टियां नष्ट किया जाना

इजरायल की आक्रमणकारी और बल प्रयोग वाली नीतियों के कारण पश्चिमी एशिया की समस्या का समाधान कठिन है। उसने 1981 में ईराक की कुछ परमाणु भट्टियों को आक्रमण करके नष्ट कर दिया। यह कायवाही किसी भी देश के आंतरिक मामला में खुला हस्तक्षेप है जो कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का भी उल्लंघन करता है। इजरायल के इस कार्य को अरब देशों ने कटु आलोचना की लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तब अमेरिका ने वीटो कर दिया। इससे अमेरिका के प्रति अरब देशों में विराघ तथा नाराजगी बढ़ी है।

1980 में पश्चिमी यूरोप के देशों ने अरब इजरायली विवाद को सुलझाने में भी योजना प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र के सभी राज्यों की अखंडता तथा एकता को स्वीकार किया जाए।

साउदी अरब के विदेश मंत्री की आठ सूत्री शान्ति योजना

8 अगस्त 1981 को साउदी अरब के राजकुमार फाहद ने पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान के लिए निम्न प्रस्ताव रखे —

- 1 1967 में अवैध रूप से अधिकृत क्षेत्रों से इजरायल का वापिस लौटना।
- 2 1967 के युद्ध में अधिकृत क्षेत्रों पर से इजरायली बस्तियों को हटाना जैसे जोडन नदी का पश्चिमी किनारा, गाजापट्टी और सीरिया की गोलन पहाड़िया।

- 3 जेरुसलम जैसे पवित्र स्थानों पर सभी धर्मों के लोगों को पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देना।
- 4 20 लाख के लगभग विस्थापित फिलीस्तीनियों के पुनर्वास के अधिकार को मान्यता देना।
- 5 फिलीस्तीनियों वाले जाडन नदी के पश्चिमी किनारे की सन्तमण काल में कुछ माह के लिए संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में रखना।
- 6 जेरुसलम नगर के अरब क्षेत्र को राजधानी बनाते हुए फिलीस्तीनीयों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना।
- 7 इस क्षेत्र के सभी राज्यों के शांति पूर्वक रहने के अधिकार को मान्यता प्रदान करना (जिनमें इजरायल भी सम्मिलित है)।
- 8 संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा इसके सदस्यों द्वारा इस सिद्धांतों को क्रियान्वित कराने की गारंटी देना।

इस आठ-सूत्री शांति योजना को कई दशों का समयन प्राप्त होने लगा है और पी० एल० ओ० के अध्यक्ष यासर अरफात ने सख्ती प्रस्तावों का स्वागत किया है। इसकी तीव्र आलोचना केवल लीबिया ने की है। नवम्बर 1981 के अंत में अरब लीग सम्मेलन में इस पर विचार हुआ था।

अमेरिकी इजरायली सामरिक समझौता

राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आने के बाद और अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक उपस्थिति के कारण अमेरिका और इजरायल के बीच सहयोग और मित्रता और गहरी हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेगिन की अमेरिका यात्रा के समय दोनों देशों ने सोवियत विस्तारवाद को रोकने के प्रयासों में सामाजिक सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है जिसमें भूमध्यसागर में अमेरिका तथा इजरायल के नौमनिक अभ्यास भी सम्मिलित है। किन्तु अमेरिका द्वारा साखदी अरब को "आवाक" वायुयानों के बेचे जाने का निणय इजरायल के हितों का विरोधी है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध अरब देशों को अपने साथ लाना चाहता है किन्तु अरबों के लिए प्रमुख चुनौती इजरायल में है सावियत संघ से नहीं। इसमें अमेरिका मित्र और इजरायल को ही अपने साथ रख पाया है।

मिश्र के राष्ट्रपति सादात की हत्या

■ अक्टूबर 1981 का मिश्र के राष्ट्रपति सादात की जब वे राष्ट्रीय समारोह के समय एक सैनिक परेड देख रहे थे, सेना में से ही कुछ लोगो ने अचानक हत्या कर दी जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण तथा अप्रत्याशित घटना थी।

लेबनानी मोर्चों पर नहीं हुई हैं और यह इजरायल से स्वयं के बूते पर सैनिक संपर्क छोड़ने की जोखिम नहीं उठा सकता। इस समय यह जरूरी है कि अरब देश मिलकर साठवीं शक्ति योजना जैसे सामान्य आधार पर एकमत हो।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात अधिवेशन में 56 गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा प्रस्तुत एक सोलह सूत्री प्रस्ताव का पारित किया गया जिसमें इजरायल को गोलन पहाड़िया अपने देश में मिलाने की आलोचना की गई। किंतु इसमें भी अमेरिका ने इजरायल का पक्ष लिया और इजरायल के विरुद्ध आधिकारिक राजनयिक प्रतिबंधों को अनुचित बतलाया। अमेरिकी प्रतिनिधि श्रीमती किक पट्रिक ने कहा कि "यदि इजरायल को संयुक्त राष्ट्र से निकालने का निर्णय किया तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं का दिए जाने वाले अनुदान में कमी भी कर देगा और यदि आवश्यक हुआ तो संयुक्त राष्ट्र मध्य से बाहर भी आ जाएगा।" इस प्रकार अमेरिका का इजरायल को विवशता तथा स्वायत्त समर्थन स्पष्ट है। इससे न केवल अरबों और इजरायल के मध्य तनाव में वृद्धि हुई है अपितु अमेरिका तथा अरब देशों के मध्य भी अविश्वास बढ़ा है।

साइनाई के सम्पूर्ण क्षेत्र की मित्र को वापसी

कप डेविड संपन्न और मित्र इजरायली संधियों के अनुसार इजरायल न मित्र का साइनाई का बचा हुआ क्षेत्र भी 25 अप्रैल 1982 का मित्र को वापिस लौटा दिया। मित्र और इजरायल के मध्यवर्ती सीमाओं में बहुराष्ट्रीय सेनाएँ रखे जाने का प्रस्ताव अवश्य है किंतु इजरायल की गोलन पहाड़िया का अपने देश में मिलाने जैसी वापसाहियों से यह स्पष्ट है कि अवध रूप से अधिग्रहण क्षेत्र को नियंत्रित रखने की इजरायल नीतियों में कोई कमी नहीं आई है। साइनाई की पूर्णतया प्राप्त करने के बाद मित्र की अरब नीति में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आना सम्भव लगता है। इजरायल ने पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी क्षेत्र में भी फिलीस्तीनिया के साथ दुष्प्रवहार किया है जिसके कारण वहाँ इजरायल विरोधी प्रदर्शनों हुए हैं। इजरायल अपनी बहुत सी बस्तियों की नई क्षेत्रों से हटाना भी नहीं चाहता तथा वहाँ वापस रहना चाहता है। ईरान ईरान युद्ध में जो कि लगभग 2 वर्ष में चल रहा है पश्चिम एशिया के वातावरण में परिवर्तन किए हैं और उसके कारण भी फिलीस्तीनी समस्या के समाधान में विलम्ब हो रहा है। इजरायल और अरबों के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है।

सादात इजरायल के साथ शांति स्थापित करने के निरंतर प्रयास कर रहे थे तथा इन प्रयासों में उनका बहुत सफलता मिली। वह इजरायल से साइनाई का क्षेत्र मित्र को वापस दिलाने में सफल हो पाए। 1973 से वह सोवियत संघ के प्रभाव को पश्चिमी एशिया में कम करना चाहते थे।

सादात की मृत्यु के बाद हुस्न मुबारक मित्र के नए राष्ट्रपति बन जाने के सम्पदबिह समझौते का सम्मान करते हुए सादात की नीतियों का अनुसरण करने की घोषणा की है किन्तु उनके विचार सादात से अलग हैं। उन्होंने न केवल इजरायल से संबंध रखने का प्रयास किया है अपितु अरब देशों और सोवियत संघ से सामान्य सम्बंध बनाने का संकेत दिया है।

गोलन पहाड़ी इजरायल द्वारा विलय

दिसम्बर 1981 में इजरायली प्रधानमंत्री मनाहिट बेगिन ने गोलन पहाड़ियों का अपने क्षेत्र में मिलाने का निर्णय किया। इजरायल के इस फैसले की 18 दिसम्बर 1981 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सबसे अधिक मतों की भत्सना की। अमेरिकी रक्षा मंत्री कास्पर बाइनबर्गर ने इजरायली कार्यवाही को उत्तेजक एवं अस्थिरताजनक बताया। उसके बाद अमेरिका ने इजरायल के साथ सम्पन्न अपने सामरिक समझौते को भी स्थगित कर दिया। किन्तु इजरायल संयुक्त राष्ट्र संघ के निंदा प्रस्ताव के बावजूद गोलन पहाड़ी को इजरायली सीमा में शामिल करने की कार्यवाहियों में लगा हुआ है। जनवरी 1982 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीरिया तथा अन्य अरब राष्ट्रों ने मांग की कि इजरायल के विरुद्ध आर्थिक तथा सैनिक प्रतिबंध लगाए जाएं। किन्तु प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अमेरिका ने इस प्रकार के प्रस्ताव को बौटा कर दिया।

इजरायल यह समझता है कि इस संसार में सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा के कारण और विशेषकर अरब संसार में अमेरिकी, तेलहिता में बढ़ि के कारण अमेरिका के लिए उसका विशेष महत्व है। इजरायल यह भी जानता है कि अमेरिका तथा शेष संसार का ध्यान इस समय पोलैंड की घटनाओं की ओर अधिक लगा हुआ है तथा ऐसे में उसकी अपनी सीमाओं के विस्तार का अवसर मिल ही जायेगा। वर्तमान समय में अरब देशों में पारस्परिक मतभेद भी बना हुआ है। इजरायल को इन कार्यवाहियों के बावजूद भी सोवियत संघ ने इजरायल से युद्ध की दशा में सीरिया को सहायता का आश्वासन नहीं दिया।

वर्तमान समय में मित्र और अरबों में भिन्नता कुछ कम अवश्य हुई है लेकिन सभी अरब देश मिलकर इजरायल के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करें यह निश्चित भविष्य में सम्भव प्रतीत नहीं होता। सीरियाई सनाए पहले से ही

लेबनानी मोर्चों पर लगी हुई हैं और यह इजरायल से स्वयं के त्ने पर सैनिक संचय छेड़न की जोखिम नहीं उठा सकता। इस समय यह जल्द ही है कि अरब देश मिलकर माउदी शांति याचना जैसे सामान्य आधार पर एकमत हो।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात अधिवेशन में 56 गुट निरपेक्ष दलों द्वारा प्रस्तुत एक सौलह सूत्री प्रस्ताव का पारित किया गया जिसमें इजरायल की गोलन पहाड़ियां अपने देश में मिलान की आलोचना की गई। किंतु इसमें भी अमेरिका ने इजरायल का पक्ष लिया और इजरायल के विरुद्ध आर्थिक तथा राजनैतिक प्रतिबंधों को अनुचित बताया। अमेरिकी प्रतिनिधि श्रीमती क्लिफ पैट्रिक ने कहा कि "यदि इजरायल को संयुक्त राष्ट्र से निकालने का निर्णय किया तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती कर देगा और यदि आवश्यक हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर भी आ जाएगा।" इस प्रकार अमेरिका का इजरायल की विवशता तथा स्वायत्तपूर्ण समर्थन स्पष्ट है। इससे न केवल अरबों और इजरायल के मध्य तनाव में वृद्धि हुई है अपितु अमेरिका तथा अरब देशों के मध्य भी अविश्वास बढ़ा है।

सार्डनाई के सम्पूर्ण क्षेत्र की मिश्र की वापिसी

कप उर्विड समझौते और मिश्र इजरायली सन्धि के अनुसार इजरायल न मिश्र का माइनाई का बचा हुआ क्षेत्र भी 25 अप्रैल 1982 को मिश्र को वापिस लौटा दिया। मिश्र और इजरायल के मध्यवर्ती सामानों में बहुराष्ट्रीय सेनाएँ रले जाने का प्रस्ताव अवश्य है किंतु इजरायल की गोलन पहाड़ियों का अपने देश में मिलान जैसी कायवाहिया से यह स्पष्ट है कि अवैध रूप में आधिकृत क्षेत्र का नियंत्रित रखने की इजरायली नीतियों में कोई कमी नहीं आई है। माइनाई का पूर्णतया प्राप्त करने के बाद मिश्र की अरब नीति में भी धीर-धीरे परिवर्तन आना सम्भव लगता है। इजरायल ने पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी क्षेत्र में भी फिलीस्तीनिया के साथ दुष्प्रवृत्ति किया है जिसके कारण वहाँ इजरायल विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। इजरायल अपनी बहुत सी बस्तियों को जहाँ क्षेत्रों से हटाना भी नहीं चाहता तथा वहाँ वापिस रहना चाहता है। ईरान ईराक युद्ध ने जो कि लगभग 2 वर्षों में चल रहा है पश्चिम एशिया के वातावरण में परिवर्तन किए हैं और उससे कारण भी फिलीस्तीनी समस्या के समाधान में बिना रुक रहा है। इजरायल और अरबों के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है।

पश्चिमी एशिया में अनसुलझी गुत्थियाँ

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् से ही पश्चिमी एशिया में तनाव बना हुआ है और चार बार सैनिक संधि और कई शान्ति योजनाओं के प्रस्तुति के बावजूद भी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो पाया है। आज भी इस क्षेत्र में प्रमुख अनसुलझी समस्याएँ और चुनौतियाँ निम्न हैं —

1. लाखों फिलिस्तीनी अरबों के लिए एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण राज्य का निर्माण (जिसके लिए इजरायल अभी तक सहमत नहीं है)।
2. यू० एल० ओ० की वातानुसार के सदर्भ में फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि माना जाना।
3. इजरायल द्वारा 1967 में अधिकृत जोडन नदी के पश्चिमी किनारे गजापट्टी और गोसन पहाड़ियों की जोडन और सीरिया को लौटाने की समस्या।
4. जेरमलम के नियन्त्रण का प्रश्न और उसके अरबों वाले हिस्से की इजरायली नियन्त्रण से मुक्त कराना।
5. इस क्षेत्र में महाशक्तियों का हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा जिससे समस्याओं का पूर्ण तथा स्थायी समाधान नहीं हो पाता जैसे कैम्प डेविड समझौता आशिक है।
6. इस क्षेत्र के राज्यों द्वारा एक दूसरे के अस्तित्व का मान्यता दिए जाने का प्रश्न क्योंकि अभी तक अधिकांश अरब राष्ट्र इजरायल को मान्यता ही नहीं देते। कट्टर पक्षी अरब देश अब भी इस मान्यता का विरोध करते हैं।

फारस की खाड़ी के 6 देशों ने खाड़ी सहयोग परिषद का निर्माण किया है। किन्तु बड़ी शक्तियों के प्रतिस्पर्धा और दबाव के कारण उसकी सफलता की परीक्षा भी बाकी है। फिलिस्तीनी स्वायत्तता के प्रश्न पर इजरायल और मिश्र के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि अरब देश एकजुट होकर कोई नीति अपनाएँ तो राष्ट्रपति रीगन के लिए उनकी मांगों की उपेक्षा करना बल्लि काम होगा। साउदी अरब की आठ सूत्री शान्ति योजना अरब इजरायली विवाद के समाधान की दिशा में एक प्रमुख सकारात्मक कदम है। किन्तु उसे सभी अरब देशों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया है। नवम्बर 1981 में मोरक्को के नगर में अरब सम्मेलन साउदी शान्ति योजना पर तीव्र मतभेदों के कारण कुछ ही घण्टों में समाप्त हो गया था।

इस सदर्भ में अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनाव प्रमुख बाधा है। यदि दोनों महाशक्तियाँ इस समस्या का समाधान करें तो उचित परिणाम

निकल सकते हैं। इस प्रकार की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन अभी तो दिखाई नहीं देता है।

पश्चिमी यूरोपीय देश विशेषतः फ्रांस और जर्मनी भी अब शांति बातचीत में पी० एल० ओ० को महत्व देने लगे हैं, जबकि इजरायल की हठधर्मी से मध्य पूर्व के इस क्षेत्र में शांति प्रयासों की विफलता एवं खतरनाक स्थिति को जारी रख सकती है जिसका ताजा उदाहरण है इजरायल द्वारा बेरूत पर लामहूक और लगातार बम वर्षा और विध्वंस लीला।

लेबनान

लेबनान संकट

लेबनान पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है जो भू-राजनैतिक दृष्टि से इजरायल व सीरिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएँ इन दोनों से मिलती हैं। लेबनान में दो प्रमुख समुदाय हैं ईसाई और मुस्लिम। लेबनान में न केवल आंतरिक तनाव और विरोध है अपितु लेबनान, इजरायल व अरबों के बीच विवाद के कारण भी तनाव का केन्द्र रहा है।

लेबनान पश्चिमी एशिया में इस प्रकार का राष्ट्र है जहाँ पर एक ओर फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के छापाकार अड्डे रहे हैं और दूसरी ओर ईसाई मजहब गुट जो इजरायल का समर्थक है। लेबनान में फिलिस्तीनियों की उपस्थिति को कमजोर बनाने और धीरे धीरे समाप्त करने के लिए इजरायल लेबनान पर पिछले कई वर्षों से आक्रमण करता आ रहा है। 1981 के अंतिम महीनों में लेबनान की धरती पर सीरिया और इजरायल की सेनाओं के बीच भी व्यापक झड़पें होती रही हैं। इजरायल बेरूत नगर की ओर जान वाली एक प्रमुख सड़क के क्षेत्रों पर सीरिया का प्रभाव समाप्त करना चाहता था और साथ ही दक्षिणी लेबनान में स्थित फिलिस्तीनी अड्डों को भी आक्रामक कार्यवाही द्वारा समाप्त करने का प्रयास करता रहा है। फिलिस्तीनिया ने इस आक्रमण का मुकाबला किया और पी० एल० ओ० की सफलता एवं महत्वपूर्ण तत्व है। लेबनान संकट में संयुक्त राष्ट्र सच न कई बार हस्तक्षेप किया है और सम्बन्धित पक्षों से युद्ध विराम की अपील करता रहा है। दिसम्बर 1981 में संयुक्त राष्ट्र सच के प्रयासों से लेबनान में युद्ध विराम कराया गया। लेकिन वहाँ तनाव का वातावरण अब भी बना हुआ है। इजरायल यहाँ पर स्थित फिलिस्तीनी छापाकार अड्डों को सहन नहीं कर सकता जबकि फिलिस्तीनियों के लिए यह अड्डे इजरायल पर दबाव डालने के लिए रणनीति की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इजरायल ने पी० एल० ओ० पर लगातार बार युद्ध विराम के

पश्चिमी एशिया में अनसुलझी मुत्तियाँ

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् स ही पश्चिमी एशिया में नयाय बना हुआ है और चार बार सैनिक संघर्ष और कई शान्ति याजनाओं के प्रस्तुति के बावजूद भी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाया है। आज भी इस क्षेत्र में प्रमुख अनसुलझी समस्याएँ और चुनौतियाँ निम्न हैं —

1. साओ फिलीस्तीनी अरबों के लिए एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण राज्य का निर्माण (जिसके लिए इजरायल अभी तक सहमत नहीं है)।
2. पी० एन० आ० की वार्तालाप के संदर्भ में फिलीस्तीनिया का प्रतिनिधि माना जाना।
3. इजरायल द्वारा 1967 में अद्यतन जोर्डन नदी के पश्चिमी किनारे गजापट्टी और गोलन पहाड़ियों को ज़ाबन और सीरिया को लौटाने की समस्या।
4. जेरुसलम के नियंत्रण का प्रश्न और उसके अरब वाले हिस्से को इजरायली नियंत्रण में भुक्त कराना।
5. इस क्षेत्र में महाशक्तियों का हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा जिससे समस्याओं का पूरा तथा स्थायी समाधान नहीं हो पाता उस कम्प्लेक्स संदर्भ को भागिक है।
6. इस क्षेत्र के राज्यों द्वारा एक दूसरे के अस्तित्व का मान्यता दिए जाने का प्रश्न क्योंकि अभी तक अधिकांश अरब राष्ट्र इजरायल का मान्यता ही नहीं देते। बहुत सी अरब देश अब भी इस मान्यता का विरोध करते हैं।

फारस की खाड़ी के 6 देशों ने खाड़ी सहयोग परिषद का निर्माण किया है। किन्तु बड़ी शक्तियों के प्रतिस्पर्धा और दबाव के कारण उसकी सफलता की परीक्षा भी याकी है। फिलीस्तीनी स्वायत्तता के प्रश्न पर इजरायल और मित्रों के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि अरब देश एकजुट होकर कोई नीति अपनाएँ तो राष्ट्रपति रीगन के लिए उनकी मांगों को उपेक्षा कर पाना कठिन काम होगा। साउदी अरब की आठ सूत्री शान्ति योजना अरब इजरायली विवाद के समाधान की दिशा में एक प्रमुख सकारात्मक कदम है। किन्तु उसे सभी अरब देशों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया है। नवम्बर 1981 में मोरक्को के नगर में अरब सम्मेलन साउदी शान्ति योजना पर तीव्र मतभेदों के कारण कुछ ही घण्टों में समाप्त हो गया था।

इस संदर्भ में अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनाव प्रमुख बाधा है। यदि दोनों महाशक्तियाँ इस समस्या का समाधान करें तो उचित परिणाम

निकल सकते हैं। इस प्रकार की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन अभी तो दिखाई नहीं देता है।

पश्चिमी यूरोपीय देश विशेषतः फ्रांस और जर्मनी भी अब शांति वार्ताओं में पी० एल० ओ० का महत्व देने लगे हैं, जबकि इजरायल की हठधर्मी से मध्य पूर्व के इस क्षेत्र में शांति प्रयासों की विफलता एक खतरनाक स्थिति को जारी रख सकती है जिसका ताजा उदाहरण है इजरायल द्वारा बेरुत पर लोमहर्षक और लगातार बम वर्षा और विध्वंस लीला।

लेबनान

लेबनान संकट

लेबनान पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है जो भू-राजनैतिक दृष्टि से इजरायल व सीरिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएँ इन दोनों से मिलती हैं। लेबनान में दो प्रमुख समुदाय हैं ईसाई और मुस्लिम। लेबनान में न केवल आंतरिक तनाव और विराध है अपितु लेबनान, इजरायल व अरबों के बीच विवाद के कारण भी तनाव का केंद्र रहा है।

लेबनान पश्चिमी एशिया में इस प्रकार का राष्ट्र है जहाँ पर एक ओर फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के छापामार अड्डे रहे हैं और दूसरी ओर ईसाई सशस्त्र गुट जो इजरायल का समर्थक है। लेबनान में फिलिस्तीनियों की उपस्थिति को कमजोर बनाने और धीरे धीरे समाप्त करने के लिए इजरायल लेबनान पर पिछले कई वर्षों से आक्रमण करता आ रहा है। 1981 के अंतिम महीनों में लेबनान की धरती पर सीरिया और इजरायल की सेनाओं के बीच भी व्यापक झड़पें होती रही हैं। इजरायल बेरुत नगर की ओर जान वाली एक प्रमुख सड़क के क्षेत्रों पर सीरिया का प्रभाव समाप्त करना चाहता था और साथ ही दक्षिणी लेबनान में स्थित फिलिस्तीनी अड्डों को भी आक्रमण कायम बाही द्वारा समाप्त करने का प्रयास करता रहा है। फिलिस्तीनियों ने इस आक्रमण का मुकाबला किया और पी० एल० ओ० की सफलता एक महत्वपूर्ण तत्व है। लेबनान संकट में संयुक्त राष्ट्र संधि ने कई बार हस्तक्षेप किया है और सम्बंधित पक्षों से युद्ध विराम की अपील करता रहा है। दिसम्बर 1981 में संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रयासों से लेबनान में युद्ध विराम कराया गया। लेकिन वहाँ तनाव का वातावरण अब भी बना हुआ है। इजरायल वहाँ पर स्थित फिलिस्तीनी छापामार अड्डों को सहन नहीं कर सकता जबकि फिलिस्तीनियों के लिए यह अड्डे इजरायल पर दबाव डालने के लिए रणनीति की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इजरायल ने पी० एल० ओ० पर सैकड़ों बार युद्ध विराम के

बम गिराये है। इजरायल के विदेश मंत्री येजक समीर के अनुसार इजरायल पी० एल० ओ० के आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है अथवा इजरायल और लेबनान के बीच संधि का कोई कारण नहीं है। इजरायल न यह भी बहाना किया है कि दक्षिणी लेबनान के क्षेत्रों में यह आक्रमण इसलिय आवश्यक हो गये थे कि फिलीस्तीनी मुक्ति मोर्चा युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं।

ईरान ईराक युद्ध और फारस की खाड़ी में नये तनाव

ईरान और ईराक मध्यपूर्व के दो प्रमुख देश हैं और इन दोनों देशों की ऐतिहासिक परम्पराओं से ही यह स्पष्ट है कि इनके बीच बहुत अधिक अंतर रहे है। ये दोनों देश प्रमुख इस्लामी देश हैं और रणनीति के आधार पर पश्चिमी एशिया में बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1950 से महाशक्तियों की राजनीति और शीत युद्ध एशिया महाद्वीप को भी प्रभावित करने लगे और ईरान अमेरिका द्वारा संचालित केन्द्रीय संधि मण्डल का सदस्य बना। ईराक भी अपने सामरिक महत्व के कारण बड़ी शक्तियों के आक्रमण का केंद्र रहा है। 1958 में राजतन्त्र के पतन के बाद लम्बे समय तक ईराक में सैनिक तानाशाही रही है। 1979 में जनरल अलबकर से सहामहुसैन ने कार्यभार सम्भाला और 22 जून, 1980 का असम्बली के चुनाव कराकर वहाँ के नागरिकों को प्रजातान्त्रिक अधिकारों के उपयोग का अवसर दिया।

ईरान प्राचीन काल से फारसी सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक दो महायुद्धों में ईरान को भी बड़ी शक्तियों की राजनीति का शिकार होना पड़ा। ईरान के भूतपूर्व शाह रजा पहलवी पश्चिमी शक्तियों की ओर झुकें हुए थे और उनके अमेरिका से बड़े घनिष्ठ सम्बंध थे जहाँ उन्होंने ईरान को आधुनिक हथियारों से युक्त बनाया वहीं दूसरी ओर ईराक की ईरान विरोधी गतिविधियों को भी सीमित करने का प्रयास किया।

ईरान में क्रांति

1978 से पहले भी ईरान में शाह के विरोध में कई आन्दोलन हुए थे और वहाँ कट्टरपंथियों और वामपंथियों दोनों ने ही शाह को सत्ता से हटाने के प्रयास किये थे। ईरान में जहाँ एक ओर शाह समयका और उनके समर्थियों ने सत्ता का लाभ उठाकर स्वयं को आधुनिक भौतिक साधना से सज्जित कर लिया वहीं दूसरी ओर आम जनता की हालत पिछड़ेपन की बन गयी। 1978 में ईरान में शाह का विरोध बहुत अधिक बढ़ गया और कट्टरपंथी इस्लामी नेता आयतुल्ला खुमेनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति की लहर उठी और शाह को मजबूरन सत्ता छोड़नी पड़ी। ईरान में अमेरिका विरोधी

उल्लंघन के आरोप लगाय है और सीरिया की धारणा है कि इजरायल जान बूझ कर लेबनान में हस्तक्षेप करता है और युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहा है। इजरायल ने मई 1982 के अंत में लेबनान पर फिर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये हैं और कई प्रमुख स्थानों पर वम्बारी की है। इजरायल ने केवल फिलिस्तीनी समस्या के प्रति हठधर्मिता का रूप अपना रहा है अपितु उसने सीरिया के गोलन पहाड़ियों के क्षेत्र को जिस पर उसने 1967 से अवैध रूप अधिकार कर रखा है अपने देश की भूमि के साथ मिलने का निणय किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेगिन इसे सोच समझ कर लिया गया निणय भी बतलाते हैं। इस निर्णय की न केवल सभी अरब देशों ने भत्सना की है अपितु इससे अरबों व इजरायल के बीच विवाद और गहरा हो गया है। लेबनान अरब इजरायल विवाद के कारण और फिलिस्तीनियों की स्वायत्तता के अनसुलझे प्रश्न के कारण विस्फोटक स्थिति में है और अस्थायी रूप से महा युद्ध विराम अवश्य हो जाता है किंतु समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता जा कि सीरिया के हस्तक्षेप के कारण बहुत अधिक जटिल बन गयी है। इससे लेबनान की सुरक्षा व आंतरिक स्थायित्व पर भी असर पड़ता है।

लंदन में इजरायली राजदूत की हत्या के बाद इजराइल में लेबनान स्थित फिलिस्तीनी अड्डों पर जून 1982 में पुनः आक्रमण किये हैं और उसने सकड़ों से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। इजरायल ब्रिटेन में अपने राजदूत की हत्या के लिए पी० एल० ओ० को उत्तरदायी मानता है जबकि फिलिस्तीनी इससे इन्कार करते हैं और इसे बहाना मानकर उसने बेरुत में नरसंहार जारी रखा है। इजराइल ने विश्व जनमत की पूर्ण उपेक्षा कर तथा अमरीका की शह पर यह भीषण नरसंहार जारी रखा है जिसने हजारों को बधिरबार कर दिया सकड़ों इमारतों और स्त्री, बच्चे पशु और बूढ़े सभी पर बम बरसाये हैं। यह एक अतयन्त दुर्भाग्य की बात रही है कि फिलिस्तीनी अमर यादवा ने अपना लेबनानी साथियों की मदद से अकेले ही इस राक्षसी शक्ति का बहुत दिलेरी और बहादुरी से सामना किया है जबकि अरब राष्ट्रों ने एक गृहीत घणित चुप्पी अपनाई। भारत की प्रधानमंत्री ने निरन्तर यहाँ और अमरीका में जहाँ जहाँ बगई उहोने इजरायल की घोर निंदा की है और अमरीका पर भी दापारापण किया कि वे चाहते तो इजरायल को रोक सकते थे। दुर्भाग्य की बात है कि सीरिया दक्षिण यमन और एक दो अरब राष्ट्रों को छोड़ कर किसी ने फिलिस्तीनियों के प्रति मदद का वात ता अलग उनक माथ खुले वृत्तद स्वर में सहानुभूति भी प्रकट नहीं की।

इजरायल ने जहाजरानी और टायर क्षेत्रों की बमबारी की है। फिलिस्तीनी ममाचार संस्था बाफा के अनुसार इजरायल ने बका और बास क्षेत्रों में भी

बम गिराये हैं। इरायल के विदेश मंत्री येजा समीर के अनुसार इजरायल पी० एल० आ० के जातवाद को समाप्त करना चाहता है अथवा इजरायल और लेबनान के बीच मध्य का कोई कारण नहीं है। इजरायल न यह भावना बिया है कि दक्षिणी सज्जा के क्षेत्र म यह आक्रमण इसलिय आवश्यक हो गया कि फिनीस्तोती मुक्ति मोचा युद्ध विराम का उल्लंघन करते रहे हैं।

ईरान ईराक युद्ध और फारस की खाड़ी में नये तनाव

ईरान और ईराक मध्यपूर्व के दो प्रमुख देश हैं और इन दोनों देशों की ऐतिहासिक परम्पराओं से ही यह स्पष्ट है कि इनके बीच बहुत अधिक अंतर रहे हैं। ये दोनों देश प्रमुख इस्लामी देश हैं और रणनीति के आधार पर पश्चिमी एशिया में बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1950 से महाशक्तिवादी राजनीति और शीत-युद्ध एशिया महाद्वीप को भी प्रभावित करने लगे और ईरान अमेरिका द्वारा मजबूत केन्द्रीय सशस्त्र संगठन का सदस्य बना। ईराक भी अपने सामरिक महत्व के कारण बड़ी शक्तियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। 1958 में राजतन्त्र के पतन के बाद लम्बे समय तक ईराक में सैनिक नानाशाही रही है। 1979 में जनरल अलबकर से सहामहुसैन उपाय भार सम्मान और 22 जून, 1980 का असम्बल के चुनाव बग़र वहाँ के नागरिकों का प्रजातान्त्रिक अधिकारों के उपयोग का अवसर दिया।

ईरान प्राचीन काल से फारसी सभ्यता का प्रमुख केन्द्र रहा है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक दो महायुद्धों में ईरान का भी बड़ी शक्तियों का राजनीति का शिकार होना पड़ा। ईरान के भूतपूर्व शाह रजा पहलवी पश्चिमी शक्तियों की ओर झुके हुए थे और उनके अमेरिका से बड़े घनिष्ठ सम्बन्ध थे जहाँ उन्होंने ईरान को आधुनिक हथियारों से युक्त बनाया वहीं दूसरी ओर ईराक की ईरान विरोधी गतिविधियों को भी सीमित करने का प्रयास किया।

ईरान में क्रांति

1978 से पहले भी ईरान में शाह के विरोध में कई आन्दोलन हुए थे और वहाँ कट्टरपंथियों और वामपंथियों दोनों ने ही शाह को सत्ता सँहटाने के प्रयास किये थे। ईरान में जहाँ एक ओर शाह समर्थकों और उनके समर्थकों ने सत्ता का लाभ उठाकर स्वयं को आधुनिक भौतिक साधना से सज्जित कर लिया वहाँ दूसरी ओर आम जनता की हालत पिछड़ेपन की बराबर थी। 1978 में ईरान में शाह का विरोध बहुत अधिक बढ़ गया और कट्टरपंथी इस्लामी नेता आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति की लहर उठी और शाह को मजबूरन सत्ता छोड़नी पड़ी। ईरान में अमेरिका विरोधी

भावनाएँ बहुत बढ़ गयी और 52 राजनीतिज्ञों को 444 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया।

ईरानी क्रांति के पश्चात् भी ईरान में हिंसा और हत्याया का दौर जारी रहा। ससद और इस्लामी नेताओं के घरा पर बम्ब फेंके गये और ईरान में अस्थिरता बनी रही। इस स्थिति का ईरान न फायदा उठाना चाहा और 22 सितम्बर, 1980 को ईरान ने ईरान के हवाई अड्डा पर आक्रमण करके दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। ईरान और ईराक 1973 से तेल बंट नीति के सद्म में बहुत महत्वपूर्ण है और मध्यपूर्व की राजनीति में भी उनका प्रमुख स्थान है। ईराक और ईरान के बीच पहले से ही ऐतिहासिक व भूमि सम्बन्धी मतभेद रहे हैं और उनका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। सितम्बर 1980 में स्पष्ट रूप से युद्ध ईराक द्वारा प्रारम्भ किया गया था और इसका तत्कालीन कारण था 1975 में ईरान के साथ किये गये समझौते का ईराक के नये राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जाना। इस समझौते द्वारा ईराक में शत-अल-अरब नामक भौगोलिक आधार पर महत्वपूर्ण जलमाग को ईरान के साथ बांट लेने की पेशकश स्वीकार की थी यद्यपि इससे पूर्व 1913 में किए गये एक समझौते के अनुसार शत अल अरब ईराक का माना गया था।

शत-अल-अरब विवाद

शत अल अरब का क्षेत्र दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से महत्व का है और 1979 में किये गये समझौते का ईराक अपमानजनक समझता था क्योंकि इसने द्वारा ईरान को खाड़ी में अपना वचस्व स्थापित करने में सफलता मिली थी। ईराक ने युद्ध प्रारम्भ करने से पहले ही शत अल अरब जलमाग पर अपना दावा किया था। पश्चिम के तेल आयात करने वाले देशों से सम्बन्धों के सद्म में भी इस क्षेत्र का महत्व है। ईराक ने अपने युद्ध उद्देश्यों में ईरान के ख़ुजेस्तान प्रांत को घेर लेने का भी प्रयास किया। ख़ुजेस्तान में ईराक को बड़ी लाभ हो सकते हैं, जो कुर्दिस्तान में ईरान को है। इस प्रांत की अधिकांश जनसंख्या सुन्नी मतावलम्बी मुसलमानों की है जो सदैव से ईरान के सत्ताधारियों द्वारा शोषित रह रहे हैं। ईराक के शासक शैर शिया लोगों का समयन प्राप्त करके ईरान में अधिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते थे।

ईरान ईराक, दोनों संघर्षरत देशों के पास न केवल विपुल मात्रा में तेल के भण्डार हैं अपितु दोनों के पास विशाल शस्त्रागार भी है। दोनों देशों को दाना महाशक्तियों से पहले ही मिला हुआ हथियारों का उपयोग करने का मौका मिल गया है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ में इस प्रकार परिवर्तन आया कि कैम्प डेविड समझौते के बाद अरब जगत का मिश्र पर प्रभाव समाप्त हो गया। ईरान

के पतन के बाद न केवल पश्चिमी एशिया में अपितु समस्त मुस्लिम जगत में एक बड़े नेता का अभाव सा प्रतीत होने लगा। ईरान के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे हैं इस क्षेत्र में अपनी धाक जमाने का प्रयास किया है। जोदन के शाह हुसैन ने ईराक का समर्थन किया है और ईराक ने सऊदी अरब कतार और अन्य खाड़ी के देशों से ईरानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सहायता को अपील की और उनका भी ऋण सहायतापूर्तिपूर्ण रहा। ईराक ने सोवियत संघ को भी अपन दृष्टिकोण से अवगत करा दिया और 1972 को ईराक-सोवियत मैत्री संधि के तहत उससे हथियारों की मांग की।

प्रारम्भ में ईरान कमजोर दिखाई देने के कारण व शाह के पतन के बाद अराजकता, अयातुल्ला खुमैनी की धार्मिक कट्टरता, बड़े बड़े सैनिक अधिकांशता को फासी और उनमें अविश्वास के कारण रक्षाक्षेत्र में अव्यवस्था और अमरिका से सम्बंध बहुत खराब होने के कारण विमानों और टैंकों के चालन के लिए पुर्जों और प्रशिक्षण का अभाव रहा। ईराक यह भी समझता था कि महाशक्तियों से सम्बंधों के संबंध में ईरान अकेला पड़ गया था और अरब देश या तो ईराक का साथ देंगे या तटस्थ रहेंगे।

धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव

ईरान और ईराक दोनों मुस्लिम देश होने हुए भी शिया और सुन्नी मतों की भिन्नता के कारण परस्पर विरोधी रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में हुई ईरानी क्रांति की क्रांति मानने से इन्कार कर दिया और उसे इस्लाम विरोधी फारसी नस्लवाद की सजा दी। उसने ईरान में खुमैनी विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। खुमैनी ने सद्दाम हुसैन के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि वह अमेरिकी एजेंट है। युद्ध के प्रारम्भ में ईराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अपने मसूखों को धार्मिक व ऐतिहासिक रूप देते हुए कहा कि 637 ई० के बर्दिनिया संधि की पुनरावृत्ति होना जा रही है। उस वक़्त अरब कबीलों ने फारस के शासक के टुकड़े लेकर मुक्ति प्राप्त की थी। सद्दाम हुसैन को युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में पश्चिमी समाचार पत्रों ने अरब जात का उदीयमान मितारा कहा था। प्रारम्भ में यह लगता था कि ईराक ईरान को पराजित कर देगा और मनचाह क्षेत्रों पर अधिकार कर लेगा। ईरानी सैनिक तब बाग़जो शेर मानित नहीं हुआ और वह भी गत दावों से ईराकी सेनाओं का मुकाबला कर रहा है। प्रारम्भ में ईराक ने युद्ध को निर्णायक दौर में पहुँचाने की कोशिश की लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। वह खुरमशहर बंदरगाह बेलफुल पर ही अधिकार कर पाया। ईरान ने भी

यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से गोला बारूक और अन्य सामान खरीदन का बंदोबस्त कर रखा है। ईरान और ईराक के बीच युद्ध के प्रारम्भ होते ही ईरान में भी एकता की भावना बढ़ी है।

ईरान-ईराक की सैन्य क्षमता

	ईरान	ईराक
क्षेत्रफल	1 73,259 वर्ग मील	6,36,293 वर्ग मील
जनसंख्या	1 31 10,000	3,5250,000
कुल सेना	2,42,250	2,40,000
थल सेना	2,00,00	1,50,000
वयु सैनिक	38,000	70,000
नौ सैनिक	4,250	20 000
लड़ाकू विमान	332	445
अन्य विमान	220	155
हेलिकाप्टर	276	084
टैंक	2,850	1,985
युद्ध पोत	17	20
अन्य नौ सैनिक पोत	19	15
रिजर्व तथा अन्य		
अधिशय शक्ति	79 800	4,75,000

(दिनमान 12-18 अक्टूबर 1980 से साभार)

युद्ध के प्रारम्भ में ईराक ने युद्ध धिराम की निम्न शर्तें रखी थीं

- 1 सम्पूर्ण शत अरब माग पर ईराकी प्रभुसत्ता की स्वीकार किया जाए (यद्यपि जलमार्गों पर प्रभुत्व की सीमा प्रायः मध्य रेखा ही मानी जाती है)।
- 2 मुसियान के पास 230 वर्ग मील क्षेत्र पर ईराक का अधिकार स्वीकार किया जाए क्योंकि ईराक अपना क्षेत्र मानता है।
- 3 होमुज जल दरमध्य के पास अलबूसर और धम्म द्वीपों की वापसी क्योंकि ये परम्परा से अरब शासकों के पास रहे हैं।

ईरान खुजिस्तानी ठिकानों पर कब्जा करके अपनी शर्तें मनवाना चाहता था जिसमें उसे सफलता नहीं मिल पाई।

ईराक द्वारा प्रस्तुत एव पक्षीय युद्ध विराम ईरान को मजूर नहीं हुआ। फारस की खाड़ी के अरब देश जिनमे को आपसी विवाद भी बहुत है खुलकर ईराक के समथन म नहीं है क्योंकि वे स्वयं युद्ध म पँसना नहीं चाहते हैं। आमान ने अपनी जमीन से ईराक की सेना को आवृमूमा द्वीप पर धूमना करन की स्वीकृति नहीं दी सहाक हुसन ने इस प्रकार का समथ जारी किया जा कि आसानी म समाप्त नहीं हो सकता। यद्यपि ईरान और ईराक के बहुत से तेल केन्द्रो से तेल निकलना बंद हो गया और अव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पडा है। ईरान गत एक वष से भी अधिक समय तक आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ता रहा है। उसका उद्देश्य रहा है कि ईराकी सेनाभा को आगे न बढ़न देना ईराकी शहरो पर बमबारी द्वारा उसकी अव्यवस्था को अधिक से अधिक हानि पहुँचाना और ईराक के जियाओं और कुर्दा को विद्रोह के लिए उत्तेजित करना।

युद्ध का लम्बा दौर और उसका प्रभाव

ईरान ईराक युद्ध यद्यपि ईराक द्वारा प्रारम्भ किया था लेकिन दोनों दश सधपरत रहे हैं। यह युद्ध दोनों देशो के लिए ही बहुत हानिकारक रहा है और दोनों देशो की अव्यवस्थाएँ तहस नहस हो गई हैं। ईरान मे महगाई 50% की दर से बढ़ रही है। प्रमुख तेल केन्द्र अबादान से तेल मिलना बंद हा गया है। ईराक के बंदरगाहो विजली घरों, परमाणुशोध केन्द्रो आदि का गहरी क्षति पहुँची है। खाड़ी युद्ध न केवल लम्बा बिचता चला गया है अपितु वह बीच बीच म धीरे भी पड़ता गया है। इस तरह के युद्ध के परिणाम दूरगामी हाते हैं। पुमैनी जिस अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक जाति का नारा द रहे थे, वह राष्ट्रवाद मे बदल गयी है और शत्रु मे रक्षात्मक शक्ति का आधार बन गई है। भीतर के अत्तो म दूर तक बमबारी का प्रभाव यह पडा है कि युद्ध के मैदान म कोई भी जीते दोना इतन कमजोर हो जाएगे कि युद्ध बंद होन के बाद भी अस्थिरता और आर्थिक ममस्याएँ वषों तक बनी रहेंगी। यद्यपि प्रारम्भ म ईराक न युद्ध म बढ़त प्राप्त की किंतु 1982 मे प्रारम्भ म ईरान अपने छोए क्षेत्रा पर पुन कब्जा करन का प्रयाग कर रहा है। अब ईराकी सेनाभा पर ईरान का दबाव बढ़ता जा रहा है और ईराक की स्थिति कमजोर दिखाई देन लगी है।

अयातुल्ला खुमैनी अपन बूते पर जनेने ही प्रतिक्रम परिस्थितियों से जुझ रह हैं। ईरान न ईशकियों को पुजिस्तान म जहाँ का तहाँ पँनाए रखन म भी सफलता प्राप्त की। शरदकालीन वषा के बाद यह क्षेत्र दल दल मे बदल जाना है, जिमसे ईराक के लिए इम मौमम म ममस्याएँ उत्पन होंगी हैं।

महाशक्तियों का मौन

अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियाँ ने इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की घोषणा प्रारम्भ में ही कर दी थी क्योंकि वह सीमित विकल्पों के कारण हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यद्यपि अमेरिका ने साउदी अरब ओमन कुवैत आदि खाड़ी के देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। सोवियत संघ ने सीरिया के साथ 20 वर्षीय शांति और मैत्री की संधि पर हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति जाहिर कर दी है और अफगानिस्तान पर उसका कब्जा मजबूत हुआ है किंतु सोवियत संघ अपने विकल्प सीमित करना नहीं चाहता। दोनों ही देश (ईरान ईराक) भौगोलिक दृष्टि से सोवियत संघ के समीप हैं और ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाएँ तीव्र हैं। सोवियत संघ की नजर इस क्षेत्र पर अवश्य है कि वहाँ अब क्या होता है और अमेरिका अब कौन सी चाल चलता है। महाशक्तियों का हित इस बात में निहित है कि तेल क्षेत्रों में किसी एक ही महाशक्ति का नियंत्रण स्थापित न हो जाए।

अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों का इन तेल क्षेत्रों की बहुत अधिक चिंता है। 1974 के तेल संकट में अमेरिकी रक्षा विभाग और तेल कम्पनियाँ ऐसा वातावरण बनाए हुए हैं कि पश्चिमी एशिया के तेल क्षेत्रों पर ही अमेरिकी अस्तित्व और प्रभाव टिका हुआ है लेकिन अमेरिका युद्ध में फँसकर उन क्षेत्रों अपना कब्जा नहीं कर सकता। तेल की चिंता के नाम पर अमेरिका फारस की खाड़ी और अरब सागर में अड़ड़े विकसित कर रहा है, और रुस भी पीछे नहीं है। उसकी पनडुब्बियाँ और जहाज इस क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिका का तात्कालिक हित था होमुज जलमार्ग को खुला रखना क्योंकि लाखों पीपल तेल जो पश्चिमी देशों को मँपलाई किया जाता है, इसी मार्ग से गुजरता है। खुर्मेनी ने यह जलमार्ग अवरुद्ध नहीं करने की घोषणा कर दी थी। खाड़ी युद्ध में तो अमेरिका और रुस दोनों सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे युद्ध को ज्यादा व्यापक नहीं करना चाहते, लेकिन दोनों देशों के नौसैनिक, कूटनीतिक, व्यापारिक और तेल हित इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस युद्ध से व्यवहार में सोवियत संघ को लाभ हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की समस्या से दुनिया का ध्यान थोड़ा हटा हुआ है। रुस को ईराक को हथियार बेचने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। ईरान में यद्यपि अस्थिरता है तथापि या तो उसे भी रुस की ओर झुकना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ अमेरिका विरोधी भावनाएँ तीव्र हैं या ईरान को अमेरिका से अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि कर दी है। राष्ट्रपति रीगन ने सम्पूर्ण विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के भाग के रूप में खाड़ी क्षेत्र में भी अघाट

जमाया है। त्वरित गति से भेजी जा सकने वाली सेना रख जाने की भी योजना है। डियोगोसिया में अपने नौसैनिक अड्डे को भी अमेरिका विस्तृत कर रहा है।

सोवियत संघ भौगोलिक रूप से खाड़ी क्षेत्र के अधिक करीब है और अफगानिस्तान में उसकी उपस्थिति के कारण उसकी अमेरिका से यहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा है। अमेरिका की सैनिक बढत से इस क्षेत्र में न केवल तनाव में वृद्धि होनी है अपितु शीत युद्ध दक्षिणी पश्चिमी एशिया में लड़ा जा रहा है। सोवियत संघ यहाँ क्षेत्रीय संघर्षों में अमेरिकी उत्साह को रोकना चाहता है।

हाल ही में ऐसी खबर मिली है कि इजरायल ईरान को हथियार दे रहा है। इससे न केवल ईरान की हिम्मत बढ़ी है अपितु ईराक पर दबाव भी बढ़ा है और इरान द्वारा ईराकी सत्ताओं का खदेड़ने के कारण ईराक युद्ध विराम के लिए भी तैयार हो सकता है।

खाड़ी युद्ध के समाप्त कराने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

अक्टूबर 1980 से ही ईरान और ईराक के बीच चल रहा युद्ध का समाप्त कराने के प्रयास भी हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस बारे में चर्चा हुई है। इस्लामी देशों के सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष गणराज्यों द्वारा भी युद्ध को समाप्त कराने के प्रयास किए गए हैं किन्तु वे फलदायी न हो पाए। गुटनिरपेक्ष देशों के एक शांति प्रस्ताव के अनुसार युद्ध बंद करने का ईराकी सेनाएं 1975 के अल्जीरिया सम्मेलन के द्वारा निर्धारित सीमा तक लौट जाएं लेकिन वास्तविक सीमा निर्धारण का कार्य दोनों देश निरकर रहे। ईराक ने ईरान से अपनी सेनाएं तब तक हटाने से इन्कार कर दिया था जब तक कि अरब जलमार्ग पर उसके कानूनी अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती।

इस्लामी सम्मेलन ने भी युद्ध बंद करने के लिए मध्यस्थता का प्रयत्न किया। जून 1982 में भी 43 देशों के इस्लामी सम्मेलन में मध्यस्थों ने खाड़ी युद्ध को बंद करने का निर्वाह किया। पवित्र माह के प्रारम्भ तक युद्ध बंद नहीं हुआ। सत्रहवें सम्मेलन की 9 मध्यस्थों ने 19 दिनांकों में सितम्बर 1980 में ईराक द्वारा युद्ध प्रारम्भ करने से ईरान और ईराक दोनों के बीच समझौते पर विचार किया गया।

स्तीनी समस्या से हटता है अपितु युद्ध के कारण उनके बीच फूट भी बनी रहती है। ईरान की बढ़ती हुई जवाबी आक्रामक कायवाहियों के कारण अब ईराक पर भी दबाव बढ़ने लगा है। यदि ईराक सम्पूर्ण ईरानी क्षेत्रों से हट जाता है तो युद्ध विराम की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है।

ईरान-ईराक युद्ध के परिणाम

यद्यपि लगभग दो वर्ष से चला आ रहा खाड़ी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है प्रारम्भ में उसमें ईराक सशक्त लगता था और आज ईरान अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में सफल हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों से खाड़ी युद्ध में युद्ध विराम भी हो सकता है किन्तु इस संघर्ष के बहुत से महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं जिनमें अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा के लिए नकारात्मक ही हैं। इस युद्ध के प्रमुख परिणाम हैं —

- 1 फारस की खाड़ी के क्षेत्र में तनाव में तीव्र वृद्धि।
- 2 ईरान ईराक युद्ध के कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कुप्रभाव।
- 3 दोनों प्रमुख तेल निर्यातक देशों में तेल के उत्पादन में निरंतर कमी होना।
- 4 खाड़ी क्षेत्र में महाशक्तियों की युद्ध में तटस्थता के बावजूद भी महाशक्ति प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि।
- 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के चाटर का उल्लंघन और उसकी मध्यस्थता का उल्लंघन।
- 6 अरब देशों में तनाव और फूट की प्रोत्साहन जिससे अरब इजरायली समस्या के संदर्भ में भी अरब एकता पर बुरा असर पड़ा।
- 7 फिलीस्तीनी स्वायत्तता की समस्या खाड़ी युद्ध के कारण कुछ सीमा तक न केवल पीछे ढकेल दी गई है बल्कि इसने इजरायल को सैनिकों में बढकर आक्रमण करने को बढावा दिया है।
- 8 ईरान ईराक द्वारा पारस्परिक तेल ठिकाना पर बमबारी के कारण तेल उत्पादन में भारी कमी हुई है जिससे विकासशील देशों को इनसे तेल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

ईरान ईराक युद्ध की समाप्ति तभी सम्भव है जबकि दोनों देश पारस्परिक घृणा और विरोध का बम बरे तथा एक दूसरे की जमीन पर व्यर्थ के दावें बन्द करें और ईराक ईरान की भूमि से अपनी सनाए हथान के लिए सहमति हो।

कम्पूचिया की समस्या

दक्षिणी-पूर्वी एशिया में वियतनाम, कम्पूचिया, लाओस हिंद चीन के राष्ट्र कहलाते हैं। दूसरे महायुद्ध के पश्चात इस क्षेत्र के देश यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। सन् 1954 में हिंदचीन के बारे में जिनेवा समझौता किया गया, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने वियतनाम में लम्बी साम्राज्यवादी सैनिक दखलबाजी की और इसमें चीन और सोवियत संघ उत्तरी वियतनाम और कम्पूचिया की मदद करते रहे। 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका को वहाँ से सौटना पड़ा। इससे पूर्व किये गये 1973 के युद्ध विराम को बाद में भंग कर दिया गया और अन्त में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की विजय के साथ वियतनाम का पुनः एकीकरण हो गया।

किंतु हिंदचीन के क्षेत्र में चीन और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा हुई है। 1976 से कम्पूचिया में चीन द्वारा समर्थित सरकार थी। खेमरुक के समूह के नेतृत्व में कम्पूचिया का शासन चलाया जा रहा था। 1978 तक कम्पूचिया में पोलपोट की सरकार और पार्टी अपने वामपंथी भटकाव के कारण बहुत बदनाम हो गयी थी,

पोलपोट का पतन और वियतनामी हस्तक्षेप

कम्पूचिया में पोलपोट सरकार की दमन की नीति निरकुशता के कारण विरोध बढ़ता गया और वियतनाम को बाध्य होकर पोलपोट विरोधियों को मदद आरम्भ करना पड़ा। जनवरी 1979 में कम्पूचिया के कई भागों पर पोलपोट विरोधियों का नियंत्रण हो गया। वियतनाम ने कम्पूचिया में सैनिक हस्तक्षेप करके समानांतर सरकार स्थापित करवाई।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष कम्पूचिया में दा सरकार का विचार आया। सितम्बर, 1979 में गुटनिरपेक्ष देशों के हवाना शिखर सम्मेलन में इस

प्रश्न का कोई समाधान नहीं हो पाया और दशा में पोलपोट और हेम समरिन को सरकारों में बिसे भायता दी जाए, यह विवाद बना हुआ था और कम्पूचिया के स्थान को रिक्त छोड़ दिया गया।

कम्पूचिया में वियतनामी सैनिक हस्तक्षेप का संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी विरोध हुआ, और कई प्रस्तावों द्वारा यह मांग की गई कि कम्पूचिया से विदेशी सैनिकों को हटाया जाए और वहाँ जाता की स्वीकार सरकार स्थापित की जाए।

कम्पूचिया में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में हवाना में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई और फरवरी 1981 में नई दिल्ली गुटनिरपेक्ष विदेशी मंत्री सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कम्पूचिया से सभी विदेशी सेनाएँ हटायी जाएँ, और किसी देश के आंतरिक मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप अनुचित है।

चीन वियतनाम संधि

दक्षिणी पूर्वी एशिया में न केवल चीन और सोवियत संघ के हिता में टक़ाव है, अपितु चीन वियतनाम को सोवियत विस्तारवाद में सहायक मानता है। चीन का मत है कि इस बड़ा चौधरी है और वियतनाम इस क्षेत्र में महायुक्त चौधरी है। कम्पूचिया की पोलपोट सरकार को गिराया जाना और वहाँ वियतनाम का सैनिक हस्तक्षेप चीन के लिये असहनीय था। चीन के साम्यवादी दल के अध्यक्ष लेंग के अनुसार 'चीन वियतनाम को सबक सिखाना चाहता है।' अतः 17 फरवरी 1979 को चीन ने वियतनाम पर सैनिक आक्रमण कर दिया। चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष का एक कारण सीमा विवाद बताया जाता है। चीन और वियतनाम में सैनिक संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों देशों के हजारों सैनिक हताहत हुए, किन्तु चीन वियतनाम का कम्पूचिया से निकालने में सफल नहीं हो पाया। चीन ने वियतनाम पर यह भी आरोप लगाया कि वह हिंद चीन के देशों का एक संघ स्थापित करना चाहता और स्वयं उसमें अपना आधिपत्य जमाना चाहता है।

वियतनाम पर चीनी आक्रमण भी कम्पूचिया की समस्या से घनिष्ठ रूप से सम्बंधित है क्योंकि कम्पूचिया वियतनाम के हस्तक्षेप के बाद चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया। वियतनाम युद्ध में चीन ने स्वयं ही मार्च 1979 के प्रथम सप्ताह में युद्ध विराम घोषित कर दिया। दोनों देशों के बीच वार्ताओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। वियतनाम की सेनाएँ कम्पूचिया में अभी भी विद्यमान हैं। वियतनाम और चीन में तनाव बना हुआ है। अमेरिका और चीन कम्पूचिया की पोलपोट सरकार का भायता देते रह रहे हैं, अप्रैल 1976

तब वह कम्पूचिया में सत्ता में रही है, जबकि भारत सहित कई देशों ने हेंग सेमरिन सरकार को भायता दी है।

कम्पूचिया में हेंग सेमरिन सरकार ने 1981 में निर्वाचन भी कराए और पुनः सत्ता प्राप्त की किन्तु उसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। खेमर रूग समूह के लोग वियतनाम समर्थित सरकार के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाही करते रहे हैं फिर भी वियतनाम की मदद से कम्पूचिया में नई सरकार टिकी हुई है।

लाओस और वियतनाम के सोवियत संघ से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं और कम्पूचिया की स्थिति के बारे में तनाव बना हुआ है।

जून 1981 में कम्पूचिया पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया, किन्तु इस सम्मेलन में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के सगठन और चीन के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। एशियन के देश यह चाहते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया एक तटस्थ क्षेत्र रहे और वहाँ पर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव उत्पन्न न हो। कई देशों ने यह सुझाव दिया कि कम्पूचिया में सभी प्रमुख समूहों की मिलीजुली सरकार स्थापित हो। वियतनाम ने इस सम्मेलन में रुचि नहीं दिखाई। चीन यह चाहता है कि कम्पूचिया में किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव बना रहे। इस सम्मेलन द्वारा कम्पूचिया की समस्या के समाधान के लिये विशेष स्पष्ट सुझाव नहीं दिये।

नवम्बर 1981 में हेंग सेमरिन सरकार का विरोध करने वाले तीन दल 1 राजकुमार सिंहनुख के दल, 2 खेमर रूग और 3 पालपाट के ऐंग सेसे समूह में इस बात पर भी सहमत हुई कि वियतनाम समर्थित सरकार का मिलजुल कर मुकाबला किया जाय और आवश्यक हो तो निर्वासित सरकार स्थापित की जाए।

कम्पूचिया की समस्या का अभी भी कोई समाधान नहीं हो पाया है दक्षिणी पूर्वी एशिया में सावियत संघ और चीन द्वारा अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के प्रयत्न तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। वियतनाम, अमेरिका युद्ध समाप्त होने के बाद चीन का चिन्ता यह है कि कहीं अमेरिका के इस क्षेत्र से हटने से उत्पन्न शक्तिता को सावियत संघ अपनी उपस्थिति द्वारा न भर सके। इसलिये चीन यह भी चाहता है कि अमेरिका इस क्षेत्र से न हटे। अमेरिका और चीन का नया गठजोड़ दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनक जटिलताएँ उत्पन्न करेगा। सोवियत संघ और चीन के सामरिक चिन्तन में दक्षिणी पूर्वी एशिया का कितना महत्व है यह उनके द्वारा एक-दूसरे के प्रभाव का रक्षण के लिए अपनाया

गय विभिन्न दावपेचा से स्पष्ट है। एक ओर सोवियत संघ इस क्षेत्र के देशों से मित्रता संधियाँ करके चीन को चारों ओर अपनी सक्रिय सैनिक गतिविधियों के घेरे में जकड़ना चाहता है वहीं दूसरी ओर चीन इस को यूरोपीय देशों के साथ इस क्षेत्र से बाहर देखना चाहता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रभाव क्षेत्र कायम करने की दिशा में चीन का अधिक लाभ हो सकता है क्योंकि उसकी यहाँ भौगोलिक निकटता है और बहुत से चीनी लोग इन देशों में अब भी रहते हैं।

कम्पूचिया की समस्या का समाधान अभी सम्भव है जबकि इस क्षेत्र के देश आपसी क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करें और बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का दूर करने के लिये प्रयास करें।

आशियन के पांच सदस्य देश - थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया और फिलीपीन व्यवहार में अमेरिका समर्थक है और वियतनाम, लाओस तथा कम्पूचिया की नई सरकार सोवियत संघ समर्थक है।

दक्षिणी पूर्वी एशिया में नये तनाव

कम्पूचिया वियतनाम चीन, सोवियत संघ के पारस्परिक सम्बंधों में 1976 के बाद बहुत परिवर्तन आया है और चीन सोवियत संघ का प्रभाव दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा है। चीन ने सोवियत प्रवेश के खतरे का अंदाजा लगाकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से सम्बंध सुधारन के प्रयास किए हैं।

वियतनाम की स्वतंत्रता तथा एकीकरण के बाद सोवियत संघ के समक्ष चीन उसका विश्वास प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। इसीलिए वह कम्पूचिया को अपने प्रभाव में बनाए रखना चाहता था, कि तुपोलपोट सरकार की निरकुश और आतंकवादी नीतियों के कारण उसे भी हटना पड़ा।

कम्पूचिया की समस्या और भारत

भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के साथ घनिष्ठ सम्बंध बन रहे हैं। भारत और इन देशों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक और सभी प्रकार के सम्बंध हैं। भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाता रहा है और उसने पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिये बल प्रयोग का विरोध किया है। भारत की इस नीति के सदम में ही भूतपूर्व विदेशमन्त्री वाजपेयी की चीन यात्रा के समय वियतनाम पर चीनी आक्रमण को देखा जा सकता है। चीन वियतनाम पर चीनी पहले ही बना चुका था और श्री ५ की अपनी योजना को छोटकर

वापिस लौटना पड़ा। कम्पूचिया समस्या के सम्बन्ध में प्रारम्भ में ही भारत ने हतजार करने और स्थिति स्पष्ट होना तक रुकने की नीति अपनाई, किंतु जब हंगसेमरिन सरकार का कम्पूचिया के अधिकांश भागों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया, तब 1980 में भारत सरकार ने हंग सेमरिन सरकार को कूटनीतिक मायता प्रदान की। यद्यपि भारत सरकार की इस नीति को रूस के प्रभाव से उत्पन्न बताया जाता है।

अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों ने हंग सेमरिन सरकार को मायता प्रदान नहीं की है। वियतनाम की कम्पूचिया से सैनिक वापसी का भारत को धुलकर समायन करना चाहिए, अथवा भारत की विदेशनीति की स्वतन्त्रता कम प्रतीत होती है। कम्पूचिया की समस्या के समाधान के साधन में भारत को अधिक सक्रिय भूमिका अपनानी चाहिये।

अमेरिका ने वियतनाम पर चीनी आक्रमण के समय यह वक्तव्य दिया, (कम्पूचिया से वियतनामी सेना और वियतनाम में चीनी सेनाएँ वापस बुलाई जाय)। कम्पूचिया की समस्या के समाधान के निम्न यह भी उपयोगी हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सच के निरीक्षण में वहाँ स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करवाये जाएँ, और वहाँ अहस्तक्षेप के सिद्धांत का व्यवहार में लागू किया जाए। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की, जिनमें कम्पूचिया भी सम्मिलित है, समस्याएँ बड़ी विकट और जटिल हैं। जब तक वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, और अथ शक्तियों पर निर्भर हैं, जब तक उनके लिए बाहरी हस्तक्षेप का खतरा बना रहेगा।

- 1 आर्थिक आराम निभरता
- 2 क्षेत्रीय सहयोग
- 3 बाहरी हस्तक्षेप
- 4 आंतरिक सरचना में प्रजातन्त्रवाद और

5 गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन—वे मूल मन्त्र हैं जिनके आधार पर न केवल कम्पूचिया की समस्या का समाधान हो सकता है, अपितु दक्षिणी पूर्वी एशिया में तनाव कम किया जा सकता है और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा को इस क्षेत्र में सीमित किया जा सकता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के बीच अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की स्पर्धा सामरिक है और चाहे कोई भी अपना प्रभुत्व जमाने में सफलता प्राप्त करे, हानि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की स्वयं की ही है।

रगभेद का कलक और नामोचिया की समस्या

एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में मत्त तीन चार शताब्दियों से यूरोप की

साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियों का अधिकार रहा है, किंतु बीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के जागरण और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए हैं किंतु अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका के भाग में वहाँ पर सदियों से रहने वाले गोरे लोगो द्वारा वहाँ के मूल निवासियों के विरुद्ध जातीय भेदभाव और रंगभेद की नीति अपनायी जाती रही है। दक्षिणी रोडेशिया जिसे अब जिम्बावे कहा जाता है तो गत 20 वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद अल्पसंख्यक गोरो के शासन को समाप्त करने में सफल रहा है। 1980 में वहाँ बहुमत का शासन स्थापित हो गया और जनता के बहुमत द्वारा निर्वाचित देशभक्ति मोर्चे के नेता राबर्ट मुगाबे प्रधान मंत्री बन।

किंतु दक्षिणी अफ्रीका में उपनिवेशवाद अब भी समाप्त नहीं हुआ है यद्यपि अंगोला, जिम्बावे, मोजाम्बीक के मुक्ति मोर्चे अपने देशों को स्वतंत्र कराने में सफल रहे हैं तथापि नामीबिया (दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका) की स्वतंत्रता का सपना साकार नहीं हो पाया है। नामीबिया पर दक्षिणी अफ्रीका का उपनिवेशवादी शासन है। नामीबिया का क्षेत्रफल फ्रांस और इटली को मिलाकर भी अधिक है। नामीबिया पर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही दक्षिणी अफ्रीका का अधिकार रहा है। राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद नामीबिया में डेटे के रूप में दक्षिणी अफ्रीका के पास था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के दिसम्बर 1946 में नामीबिया का दक्षिणी अफ्रीका के साथ विलय करने का प्रायश्चित्त महासभा ने अस्वीकार कर दिया और इस संरक्षित प्रदेश बनाने पर जोर दिया जिस दक्षिणी अफ्रीका ने स्वीकार नहीं किया है और नामीबिया पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। 1966 में एक प्रस्ताव पारित कर संयुक्त राष्ट्र संघ ने नामीबिया पर दक्षिणी अफ्रीका का साम्राज्य समाप्त कर दिया। कुछ देशों ने दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक नादेबंदी की भी माँग की थी। अफ्रीकी राज्यों का मगडन (आ० ए० यू०) ने दक्षिणी अफ्रीका से नामीबिया का पूर्णतया स्वनयन कराने की माँग करता रहा है। 1968 में नामिब रंगिस्तान के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका नाम नामीबिया कर दिया। 1967 में इस प्रदेश के प्रशासन हेतु नियुक्त परिषद को दक्षिणी अफ्रीका ने मान्यता नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा के कारण 30 जनवरी 1970 को सुरक्षा परिषद ने दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित सभी कार्यों का अवधि घोषित कर लिया और सभी सदस्य राज्यों से दक्षिणी अफ्रीका से किसी भी प्रकार का सम्पर्क न रखने को कहा।

श्वेत और अश्वेत जातियों के बीच सम्बन्ध की समस्या भी वहाँ बड़ी गंभीर है। वहाँ श्वेत लोग कम संख्या में हैं किंतु उनकी वाले मूल निवासियों

से अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं। दक्षिणी अफ्रीका में बानूज के माध्यम से जानीय पर्यावासन या भेदभाव की नीति को निरन्तर चलाया जा रहा है। जान गुय का मत है कि 'यदि श्वेत और अश्वेत साथ साथ रहना सीख लेते हैं तो अफ्रीका बच जायगा। यदि नहीं तो यह अव्यवस्था गृह युद्ध और सामन्तवाद या साम्यवाद की भेंट चढ़ जायगा।'

स्वापो द्वारा स्वतन्त्र सघष

गन 20 वर्षों से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी जनसंगठन अपन दण की स्वतंत्रता और प्रभुता के लिए निरन्तर सघष कर रहा है। 1974 में समुवन राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर दक्षिणी अफ्रीका को नामीबिया में नियंत्रण हटाने की माग की। स्वापो प्रारम्भ में ही दक्षिणी अफ्रीका की उपनिवेशवादी धोरणों पर कारा प्रवृत्तियों के विरुद्ध लड़ता रहा है। इसने अपन समस्याओं को हथियार चलान का प्रशिक्षण दिया है और सरकारी सेनाओं से यह मुकाबला करता रहा है। स्वापो के कई जानिकारी, युवा नेताओं जैसे स्टीव नीको आदि का दमन और पुनिस द्वारा की जा वाली हत्याओं का शिकार होना पड़ा है। स्वापो छापामार प्रणाली से भी सघष करती है और इसे अफ्रीकी एगता संगठन तथा इसके पड़ोसी अफ्रीकी देशों का समर्थन प्राप्त होता रहा है। इसक वर्तमान नेता साय नाजुमा है जो नामीबिया में दक्षिणी अफ्रीका में पूर्णतः हट जान की माग कर रह है। अब स्वापो का नामीबिया का प्रतिनिधि माना जाता है। स्वापो को स्वाधीन नामीबिया का नवी शामक माना जात है। 1913 में समुवन राष्ट्र सघष भी स्वापो को नामीबिया का वास्तविक प्रतिनिधि स्वीकार किया है और उसके नेता साम नजुमा के विचार भी सुन गये। आज भी जहाँ एक ओर मुलह वार्ता द्वारा नामीबिया की स्वतंत्रता प्रयास चल रह है वहीं दक्षिणी अमेरीका की दमनकारी और अडिगल नीति के कारण स्वापो को सघष का रास्ता भी अपनाना पड़ता है।

पश्चिमी सम्पर्क गुट स्वायत्तता का साधक या बाधक

दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में सौविमल सघष की वढती हुई गतिविधियों का प्रभाव के कारण पश्चिमी देश चिन्तित हैं। 1975 में अगोला की स्वतंत्रता समय क्यूबा के सैनिकों की उपस्थिति इस महाद्वीप में महाशक्तियों की स्पर्धा की तीव्र चलन के लिए प्रर्याप्त रही। पांच पश्चिमी देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा) ने एक सम्पर्क गुट का गठन किया। देशों ने नामीबिया की स्वायत्तता के सम्बन्ध में दक्षिणी अफ्रीकी पर

स भी दातचित की। समस्या के समाधान के लिए उहान एक योजना प्रस्तुत का इमम —

- 1 युद्ध विराम (दक्षिणी अफ्रीकी सेनाओं और स्वापो के बीच) ।
- 2 संयुक्त राष्ट्र की दख रैय म स्वतंत्र चुनाव ।
- 3 नामीबिया और अंगोला के बीच विसं-यीकृत क्षेत्र तथा
- 4 विस यीकृत क्षेत्र म संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तनात किय जान का प्रावधान था ।

इस प्रस्ताव का दक्षिणी अफ्रीका सहित सभी देशा न स्वीकार कर लिया किंतु जइ चुनाव कराने का समय आया तो दक्षिणी अफ्रीका मुकर गया । अमेरिका का रीगन प्रशासन अव्यक्त रूप से दक्षिणी अफ्रीका के प्रति सहानु-भूति रखता है और नामीबिया पर चार्ता म वहा के अय सगठना (पश्चिम ममयक) को महत्व देता है । स्वापो ने नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए अपना सघप जारी रखन की घोषणा की है और वह किसी भी प्रकार के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए भी तैयार है । यदि दक्षिणी अफ्रीका अपनी उपनिवेशवादी और दमनकारी नीतिया स बाज नही आता तो उसे अफ्रीका के अय देशों द्वारा बहिष्कार और विरोध का भी सामना करना पड़ेगा । किंतु इस प्रकार क विरोध को ता वह दशाब्दियो से दखता आ रहा है ।

नामीबिया प्राकृतिक सम्पदा का भण्डार

दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया म रणनीति सम्बन्धी और आर्थिक व्यापारिक हित है नामीबिया म अपार खनिज सम्पदा है । विश्व म हीरो का 16% तथा यूरेनियम का तीन प्रतिशत उत्पादन नामीबिया मे होता है । सोना, तांबा जस्ता और तेल भी वहा भारी मात्रा म उपलब्ध होता है । दक्षिणी अफ्रीका प्राकृतिक सपदा और उद्योग के लिए कच्चे माल से सम्पन्न इस क्षेत्र को छाडना नही चाहता । वहा पश्चिमी देशो के भी आर्थिक हिन हैं । ब्रिटन, अमेरिका आदि की बहुत सी निजी कम्पनिया दक्षिणी अफ्रीका से व्यापार वनाय हुए है और लाभ कमा रही है । रीगन प्रशासन दक्षिणी अफ्रीका म स्वापो के प्रति उपेक्षा बरत रहा है क्योंकि वह नही चाहता कि आजादी के बाद स्वापो के नतृ व म नामीबिया गुटनिरपक्ष हो जाये अथवा इस रणनीति और व्यापार क सदम म महत्वपूर्ण क्षेत्र म सोवियत सघ और उसके सहयोगिया का प्रभाव बढ जाय । यद्यपि आज उपनिवेशवाद का समय समाप्त हा चला है और संयुक्त राष्ट्र न विभिन्न मंचो पर उसके विरुद्ध आवाज भी उठाई है उमके बावजूद भी वडे दश अपने आर्थिक लाभ के लिए और राजनीतिक, सामरिक एव सैनिक दष्टि से इन छोट क्षेत्रो के प्रति नवउपनिवेशवादी और

नव साम्राज्यवादी नीतिया अपना रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका भी यहाँ जहाँ तक हो सके अपनी प्रभुता बनाये रखन का बहाना ढूँढ रहा है यद्यपि वह ज्यादा लम्बे समय तक यहाँ अपना साम्राज्य बनाये रखन में सफल नहीं हो सकता।

अगोला पर दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण

जहाँ एक ओर दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में दमन और आतंकवाद की नीति अपना रहा है वहीं उसने 1981 में भी तथा मई 1982 में अगोला पर सैनिक आक्रमण किए हैं। वह अगोला पर आरोप लगाता है कि वहाँ स्वापा के छापामार अड्डे हैं और अगोला स्वापो के लोगो को समर्थन एवं सरक्षण देता है। वास्तविकता यह है कि वह अपने पड़ोस में मार्क्सवादी या वामपंथी सरकार को स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार के आक्रमण के पीछे अमेरिका जसी महाशक्तियों की सहमति प्रतीत होती है क्योंकि वह रणनीति की दृष्टि से अफ्रीका के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सोवियत विस्तारवाद का खुला विरोध कर रहा है। प्रिटोरिया (दक्षिणी अफ्रीका) अगोला पर आक्रमण कर पड़ोस के नामीबिया समर्थक देशों में आतंक फैलाने में सफल नहीं हो पाया है। स्वापा द्वारा नामीबिया की स्वतंत्रता के उद्देश्य से संघर्ष सतत जारी है।

नामीबिया की व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्व की वाल्विस खाड़ी पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने नामीबिया की ही प्रभुता स्वीकार की है और इस सम्बन्ध में 1980 में ही एक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। किंतु दक्षिणी अफ्रीका इसे अपने प्रभुत्व में बनाये रखना चाहता है जो कि अनुचित है। वाल्विस की खाड़ी नामीबिया की अर्थ-व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः इसे दक्षिणी अफ्रीका के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जा सकता। इस खाड़ी का नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद उसके लिए सामरिक और व्यापारिक महत्व और भी बढ़ जायगा।

पश्चिमी सम्पर्क गुट के देशों द्वारा पाँच वर्ष के प्रयास के बावजूद भी नामीबिया के बारे में समझौता नहीं हो पाया है। दक्षिण अफ्रीका से समझौते के लिए बातें जारी हैं किंतु नामीबिया की स्वतंत्रता में दक्षिण अफ्रीका विलम्ब ही कर रहा है। नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका की लगभग एक लाख सैनिकों मौजूद हैं।

नामीबिया में अर्धध निर्वाचन

जहाँ एक ओर नामीबिया की स्वतन्त्रता के लिए बातें चल रही थी वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने नामीबिया में 1977 में निर्वाचन कराये और वहाँ अपनी एक कठपुतली सदन बनवायी और तरण गले गुट के द्वारा वहाँ

शासन चला रही है। दिसम्बर 1977 में आयोजित इन चुनावों का स्वापो ने बहिष्कार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन चुनावों को अवधित लाया और उनकी आलोचना की क्योंकि यह निर्वाचन निष्पक्ष परिवेक्षक की देखरेख में नहीं कराये गये। तरण होने समूह को और उसे मर्मघत छोटे छोटे गुटा को दक्षिण अफ्रीका स्वापो के विकल्प के रूप में रखना चाहता है। किन्तु इसे जन समर्थन प्राप्त नहीं है। गत 22 वर्षों में स्वापो ने नामीबिया की जनता में तीव्र राष्ट्रीय जाग्रति और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएँ उत्पन्न की हैं। नामीबिया के लोग दमनकारी और नवउपनिवेशवादी दक्षिण अफ्रीकी सत्ता से परिचित हैं और वे उचित राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों में अंतर जानते हैं। अब वहाँ की सरकार जन आंदोलन को दबाने के लिए नग्न बल का प्रयोग कर रही है। किन्तु उतना ही विरोध रंग भेदवादी सरकार के विरुद्ध बढ़ता जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका की सेना द्वारा स्वापो का समर्थन करने वाले लोगों के घर जला दिए जाते हैं। हत्याएँ की जाती हैं उनके भवानों व फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है गिरफ्तारियाँ, यातनाएँ और नजरबंदी वहाँ आम बात हो गयी है। किन्तु इस सब प्रकार के दमन के बाद भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जारी है। मई 1982 में अंगोला पर दक्षिणी अफ्रीका आक्रमण के बाद स्वापो ने अपना संघर्ष न केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रखा है अपितु वह देश के केंद्रीय भाग में भी अपनी गतिविधियाँ देश के मध्यवर्ती भागों तक फैला रही है जहाँ कि उपनिवेशवादी गोरे रहते हैं। इसमें तस्मेह का जिला ओटेयर आदि स्थान सम्मिलित हैं। नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका की सेना के कमाण्डर जनरल लायड ने यह घोषणा की है कि वर्तमान परिस्थितियों में सेना स्वापो की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। निरंतर यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी उपनिवेशवादियों का नामीबिया में अपनी उपस्थिति की कीमत चुकानी पड़ रही है। दक्षिण अफ्रीका की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वापो की स्वतंत्रता संग्राम में विजय निश्चित है और इसका प्रभाव दक्षिण अफ्रीका की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस भी दक्षिण अफ्रीका में अल्पमत के शासन की समाप्ति और अपार्टाईड व क्लक को मिटाने के लिए सक्रिय है।

दक्षिण अफ्रीका रोगन प्रशासन जैसे पश्चिमी समर्थकों की अग्रतन्त्र मदद से नामीबिया की स्वतंत्रता में बाधा बहुत विलम्ब अवश्य कर सकेगा है किन्तु उसे रोक नहीं सकता। नामीबिया का न केवल अफ्रीका व अग्रवर्ती राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है अपितु स्वापो का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। भारत भी नामीबिया की स्वतंत्रता का समर्थक है भारत

प्रारम्भ से ही अफ्रीका में रंग भेद की नीति और उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में रंग-भेद का विरोध किया और सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया। भारत ने स्वायत्त को कूटनीतिक मायता प्रदान की है और उस नामीबिया का एक मात्र प्रतिनिधि मानता है। नामीबिया को भारत भौतिक-नतिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान कर रहा है।



